



# ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार

सैन्य विद्रोह के बाद भारतीय लोकवित्त के  
पुनर्निर्माण काल के प्रमुख चरित्र तथा विचार

सव्यसाची भट्टाचार्य

M

दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड

नई दिल्ली वॉर्ल्ड कलकत्ता मद्रास

समस्त विश्व में सहयोगी कंपनियां

© भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

अनुवाद : श्रीकांत मिश्र

प्रथम हिंदी संस्करण १९७६ ई.

भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त कागज  
इस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है।

मूल्य : 32.00

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रवर्तित

प्रस० जी० वसानी द्वारा दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
के लिए प्रकाशित तथा प्रगति प्रिंटर्स, दिल्ली 110032 में मुद्रित।

S. Bhattacharya : British Raj Ke Vittiya Adhar

## माता-पिता को

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम् प्रजासु ।  
यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवमकल्पमस्तु ॥





# भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की ओर से

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में एक है शोध की उपलब्धियों को उस पाठक वर्ग तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं में इतिहास संबंधी रचनाएं तैयार तथा प्रकाशित करें। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किंतु भारतीय पाठकवर्ग का यह छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भा० इ० अ० प० ने कुछ गौरव ग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की निर्यात पद्धतियों पर आधृत और इतिहास की समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

प्रस्तुत पुस्तक का विषय ब्रिटेन की वित्तीय नीति है, जिसमें 1857 की सैनिक क्रांति के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों और विचारधाराओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। विभिन्न हित समूहों, नीति निर्माताओं तथा प्रतिद्वंद्वी संगठनों का भी विवरण दिया गया है। ब्रिटेन की इस नीति के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमत तैयार हुआ था। इस प्रकार इस पुस्तक से हमें वह पृष्ठभूमि प्राप्त होती है जो 12वीं शताब्दी के सातवें दशक से प्रारंभ होने वाले आर्थिक राष्ट्रवाद को समझने के लिए आवश्यक है।

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए अनुवादक श्रीकान्त मिश्र, डा० नरेंद्रप्रसाद वर्मा तथा अन्य स्त्री. सहयोगियों के प्रति, हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

28 फरवरी 1976

नई दिल्ली

रामशरण शर्मा

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद



मैं बहुत सारे व्यक्तियों के प्रति आभारी हूँ। उनका स्मरण करते हुए मुझे हर्ष होता है। मेरे लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए० त्रिपाठी के प्रति पूरी तरह आभार प्रकट कर पाना कठिन है, जिन्होंने मेरे प्रथम शोध प्रयास का निर्देशन किया है। मैं डाक्टर एन० के० सिन्हा, भूतपूर्व आमुतोप प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर नीहाररंजन रे, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी को, उनके द्वारा दिए गए परामर्श और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

अपने गुरुजनों, सहयोगियों तथा विद्यार्थियों के प्रति बौद्धिक ऋणभार की आभारोक्ति केवल सामान्य रूप से ही की जा सकती है। मुझे विशेष रूप से प्रोफेसर एस० पी० सरकार का उल्लेख करना चाहिए जिन्होंने उस समय भी, जब मैं प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता में बी०ए० का ही छात्र था, मुझे सुनने की इच्छा उदारतापूर्वक दिखाई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० विपनचन्द्र, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के डा० यरुन डे तथा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डा० एस० गोपाल ने इस रचना से संबंध विषयों पर व्यक्तिगत और कभी-कभी सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने का कष्ट उठाया है। इन सभी के प्रति और कलकत्ता, दिल्ली तथा आक्सफोर्ड के अन्य बहुत सारे व्यक्तियों के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। परंतु भूलो और छुटियों के लिए मैं अकेला ही उत्तरदायी हूँ।

मैं इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी को, उनके द्वारा शोध कार्य और शोध प्रबंध के प्रकाशनार्थ दी गई सहायता के लिए; शिकागो विश्वविद्यालय की कमेटी आफ साउथ एशिया स्टडीज को प्रकाशन हेतु दी गई सहायता के लिए और उसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग को 1968-69 में प्रेरणादायी वातावरण (और अध्यापन कार्य से मुक्त एक सत्र) प्रदान करने के लिए; और डा० रेमण्ड कार तथा आक्सफोर्ड की प्रबंध समिति के सदस्यों को हैरिसन फेलोशिप के लिए मेरा चुनाव करने के निमित्त धन्यवाद देता हूँ।

मैं श्री एच० आर० सान्याल के प्रति जिन्होंने कुछ सांख्यिकीय सारणियों की जांच करने तथा भारत में मेरी अनुपस्थिति में पुस्तक का प्रूफ पढ़ने की अनुकंपा की। पाद टिप्पणियों में उल्लिखित पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के प्रति उस सामग्री के प्रयोग की अनुमति देने के लिए जिसे पहले मैंने लेखों के रूप में प्रकाशित कराया था; श्रीमती पोलाइन हावर आफ मारपैथ, नॉर्थवरल्ड के प्रति सर चार्ल्स ट्रैवीलियन के निजी कागजात



# सांख्यिकीय परिशिष्ट में सारणियों की सूची

- 1.1 लोक राजस्व : भारत सरकार के समग्र सकल राजस्व के प्रतिशत रूप में प्रमुख मर्दें : काल 1858-59 से 1871-72 ।
- 1.2 लोक व्यय : भारत सरकार के समग्र सकल व्यय के प्रतिशत रूप में प्रमुख मर्दें : काल 1863-64 से 1871-72 ।
- 1.3 भारत सरकार का भारत और इंग्लैंड में सकल राजस्व और व्यय : 1858-59 से 1871-72 तक ।
2. भारत सरकार के प्रमुख और इंग्लैंड में सकल राजस्व और प्राप्तियां (1857-58 से 1872-73 तक) : प्रमुख मर्दें ।
3. अफीम राजस्व : औसत कीमत, शुल्क दर तथा व्यापार की मात्रा 1857-72 ।
4. प्रमुख प्रांतों प्रेसीडेंसियों में सकल मालगुजारी : 1856-57 से 1870-71 तक ।
5. नमक से प्राप्त सकल राजस्व : आयात शुल्क, अंतर्देशीय सीमा शुल्क, तथा विक्रय मूल्य 1856-57 से 1871-72 तक ।
6. विदेशी व्यापार और सीमा शुल्क : आयात एवं निर्यात के सरकारी मूल्य तथा कुल सीमा शुल्क राजस्व 1857-58 से 1871-72 तक ।
- 7.1 कुछ मुख्य निर्यातों के सरकारी मूल्य : 1860-61 तथा 1870-71 ।
- 7.2 कुछ मुख्य आयातों के सरकारी मूल्य : 1860-61 तथा 1870-71 ।
- 8.1 मूती लच्छों, धागों और सूत के आयात 1857-58 से 1871-72 तक ।
- 8.2 मूती वस्त्रों के आयात : सरकारी मूल्य तथा सीमा शुल्क 1857-58 से 1870-71 ।
9. भारत सरकार के प्रमुख प्रांतों प्रेसीडेंसियों के सकल राजस्व और प्राप्तियां 1858-59 से 1871-72 तक ।
10. भारत सरकार का प्रमुख प्रांतों प्रेसीडेंसियों में सकल व्यय 1858-59 से 1871-72 तक ।
11. भारत सरकार का भारत व इंग्लैंड में सकल व्यय : प्रमुख मर्दें : 1863-64 से 1872-73 तक ।
- 12.1 लोक निर्माण विभाग में व्यय की प्रमुख मर्दें : लोक निर्माण 'साधारण' 1857-58 से 1871-72 तक ।
- 12.2 प्रमुख प्रांतों प्रेसीडेंसियों में लोक निर्माण (साधारण) पर व्यय : भारत में कुल व्यय के प्रतिशत रूप में ।

13. लोक निर्माण विभाग में व्यय की प्रमुख मदें : रेल तथा 'असाधारण' लोक निर्माण कार्य ।
14. 'साधारण' लोक निर्माण कार्यों पर प्रमुख प्रातों प्रेसीडेंसियों में व्यय, 1857-58 से 1871-72 तक ।
15. सैन्य व्यय का विस्तृत विवरण, काल 1865-66, 1869-70 तथा 1871-72 ।
- 16.1 ब्रिटिश भारत में नियोजित सैनिकों की संख्या, 1858-59 से 1869-70 तक ।
- 16.2 प्रत्येक प्रेसीडेंसी में नियोजित सैनिकों की संख्या, यूरोपीय तथा हिंदुस्तानी, 1858-59 से 1871-72 तक ।
17. प्रत्येक प्रेसीडेंसी में सेना पर सकल व्यय तथा इंग्लैंड में भुगतान, 1863-64 से 1871-72 तक ।
18. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत के अपरिशोधित लोकश्रृण की राशि, 1858-59 से 1872-73 तक ।
19. प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) कंपनियों को भुगतान किया गया वार्षिक व्याज, 1860-61 से 1871-72 तक ।
20. भारत सरकार के इंग्लैंड में शुद्ध भुगतान : मुख्य मदें और भुगतान की रीति, 1860-61 से 1871-72 तक ।
- 21.1 शिक्षा पर व्यय, 1857-58 से 1871-72 तक ।
- 21.2 शिक्षा पर व्यय : प्रमुख प्रातों प्रेसीडेंसियों में : सरकारी व्यय (कालम-क) और सभी सार्वजनिक तथा निजी स्रोतों से कुल व्यय (कालम-ख), 1858-59 से 1871-72 तक ।

## शब्द संक्षेप

लेखा शाखा	: लेखा शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण ।
कृषि, राजस्व व वाणिज्य कार्यविवरण	: कृषि, राजस्व तथा वाणिज्य विभाग संबंधी गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कार्यविवरण ।
डी० एन० वी०	: 'डिविजनरी आफ नेशनल बायोमेट्री' (लंदन)
इक० एच० आर०	: 'इकानामिक हिस्ट्री रिव्यू' ।
ई० एच० आर०	: 'इंग्लिश हिस्ट्रारिकल रिव्यू' ।
एलिंगन कागजात	: जेम्स ब्रूस, एलिंगन के आठवें अल (1811-63), भारत के गवर्नर जनरल (1862-63) के कागजात (पांडुलिपियां-यूरोप, एफ० 83, इंडिया आफिस लाइब्रेरी)
व्यय शाखा	: व्यय शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण ।
वित्त प्रेषण	: वित्त संबंधी प्रेषण, भारत सरकार से भारत मंत्री को ।
वित्त कार्यविवरण	: वित्त विभाग संबंधी गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कार्य-विवरण ।
पृथक राजस्व वित्त गृह कार्यविवरण	: पृथक राजस्व शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण । गृह विभाग संबंधी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कार्य-विवरण ।
गृह प्रेषण	: गृह विभाग प्रेषण, लोक शाखा, भारत सरकार भारत मंत्री ।
गृह राजस्व कार्यविवरण	: गृह विभाग कार्यविवरण, राजस्व शाखा ।
गृह पृथक राजस्व कार्य-विवरण	: गृह विभाग कार्यविवरण, पृथक राजस्व शाखा ।
जे० इक० एच० के० डब्ल्यू०	: 'जर्नल आफ इकानामिक हिस्ट्री' । 'कैप्ट विद', सपरिपद गवर्नर जनरल की कार्यवाही से संबंधित फाइलों में संलग्न अतिरिक्त कागजातों पर अभिलेखागार का संकेतन है ।
लारेंस कागजात	: सर जान लारेंस, प्रथम बरन लारेंस (1811-79), भारत का गवर्नर जनरल लारेंस (1864-69) के कागजात (पांडुलिपिया, यूरोप एफ० 90, इंडिया आफिस लाइब्रेरी) ।
विधान परिपद कार्यविवरण (सारांश)	: भारतीय विधान परिपद का कार्यविवरण सारांश (नई सीरीज) ।



- विधान परिषद विवरण : भारतीय विधान परिषद का कार्यविवरण (पुरानी भीरोज)  
 अवकाश व पेंशन : अवकाश व पेंशन शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण ।
- मेयो कागजात : रिचर्ड बोर्क, मेयो का छठा अल (1822-72), भारत का  
 गवर्नर जनरल (1869-72) (पता 7490, केंब्रिज विश्व-  
 विद्यालय पुस्तकालय) ।
- मैन्य प्रेषण : मैन्य प्रेषण, भारत सरकार भारत मंत्री ।
- मैन्य विभाग कार्यविवरण : सपरिषद गवर्नर जनरल का मैन्य विभाग संबंधी कार्यविवरण ।
- प्रकीर्ण शाखा : प्रकीर्ण शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण ।
- एम० एम० पी० आर० : भारत एंड मंडीरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट (मंसदीय कागजात) ।
- पी० पी० एच० सी० : मंसदीय कागजात (हार्डर्स-थोर्क कोमर्स) ।
- पी० पी० एच० एल० : मंसदीय कागजात (हार्डर्स-थोर्क कोमर्स) ।
- लोक शाखा : लोक शाखा, गृह विभाग कार्यविवरण ।
- निर्माण कार्यविवरण : निर्माण कार्यविवरण, भारत सरकार भारत मंत्री ।
- राजस्व कार्यविवरण : राजस्व शाखा, गृह विभाग कार्यविवरण ।
- राजस्व प्रेषण : राजस्व प्रेषण, भारत सरकार भारत मंत्री ।
- रेल प्रेषण : रेल विभाग प्रेषण, भारत सरकार, भारत मंत्री ।
- हिंदुस्तानी प्रेस रिपोर्ट : हिंदुस्तानी प्रेस के मसौदा में रिपोर्ट (भारतीय राष्ट्रीय अभि-  
 लेखागार) ।
- पृथक राजस्व : पृथक राजस्व शाखा, वित्त । गृह विभाग कार्यविवरण ।
- हिंदुस्तानी समाचार उद्धरण : हिंदुस्तानी भाषाओं के समाचार पत्रों से उद्धरण (भारतीय  
 राष्ट्रीय अभिलेखागार) ।
- ट्रैवीलियन कागजात : सर चार्ल्स ट्रैवीलियन (1807-86) के पत्र, मद्रास का  
 गवर्नर, 1859-60, और गवर्नर जनरल की परिषद का  
 वित्तीय मामलों का सदस्य, 1862-65 (माइक्रोफिल्म, बोड-  
 लियन लाइब्रेरी, आक्सफोर्ड) ।
- बुड कागजात : सर चार्ल्स बुड प्रथम विस्काउंट हैलीफाक्स (1800-85),  
 भारत मंत्री 1859-66, (पाडुलिपिया यूरोप एफ० 78,  
 इंडिया आफिस लाइब्रेरी) ।
- शब्द संक्षेपो तथा टिप्पणियों के पूरे स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ ग्रंथ सूची को देखिए ।

## अनुक्रम

प्रस्तावना	1
मितव्ययतापरक कुशलता की दिशा में	64
वित्तीय नियंत्रण प्रणाली	89
व्यय की प्रवृत्ति	130
राजस्व की मदें : नीति संबंधी कुछ प्रश्न	178
समृद्धि का लोला रूपक	238
अनुक्रमणिका	335



## प्रस्तावना

भारतीय साम्राज्य के व्यापक वित्तीय संगठन में बहुत से छोटे-छोटे अधिकारियों में से एक अधिकारी चार्ल्स लैम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में जब वह नौकरी करता था तब एक बार उसने डेविड वूय की 'टेबल्स आव सिपल इंटरेस्ट' नामक पुस्तक की, जिसे वह लगभग प्रतिदिन प्रयोग में लाता रहा होगा, समीक्षा की। उसने लिखा कि 'इस पुस्तक में उन सामान्य पुस्तकों से अलग एक खास प्रकार की दिलचस्पी अंत तक बनी रहती है जिनका अवलोकन करना हमारे भाग्य में बड़ा है।' लेखकों को बहुधा अपनी कृति के विषय में भ्रम रहता है, फिर भी यह समझना कि यह रचना आम पुस्तकों का अपवाद होगी और पाठकों की रुचि अंत तक बनाए रखेगी, व्यावहारिक दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं है। इसके अलावा उस नीरस विषय में पाठकों को घसीट ले जाना, जोकि लेखक ने उनके लिए निर्धारित किया है, कोई विशेष बड़ाई की बात भी नहीं है। अस्तु इस प्रस्तावना का उद्देश्य पाठक की इस कृति के विस्तार क्षेत्र का परिचय देना मात्र है। प्रथम अध्याय का भी उद्देश्य यही है। इसमें काल विशेष के प्रमुख पात्रों का परिचय पाठकों को देने के साथ-साथ इस अवधि की विशिष्ट समस्याओं की रूपरेखा भी निर्धारित की गई है।

भारतीय लोकवित्त का अध्ययन उस महान उथल-पुथल की समाप्ति से प्रारंभ होता है जिसे सैन्य-विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अध्ययन प्रारंभ करने के लिए 1858 का वर्ष सुविधाजनक है। सैन्य विद्रोह द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण उस समय नीति का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया था। इसी समय वित्तीय शक्ति का स्थान परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण सस्यागत परिवर्तन, जिनके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, हो रहे थे। (संस्थागत ढांचे के पुनर्गठन पर दूसरे अध्याय में और प्रधान नीति विषयक समस्याओं पर तीसरे और चौथे अध्यायों में विचार किया गया है।) 1872 को दो भिन्न अवस्थाओं का संघि वर्ष माना जा सकता है। इसके अनेक कारण हैं: पारचात्य यूरोप की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में और विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन में 1873 से 1896 की अवधि में भारी मंदी का प्रकोप; चांदी की अंतरराष्ट्रीय कीमत और स्टलिंग के साथ रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन; 1871-72 में भारतीय वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण होना; 1872 में मेयो का (जो इस कथानक के प्रधान पात्रों में से है) प्रशासन समाप्त होना; और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है पुनर्निर्माण की प्रेरक शक्ति का समापन—जो उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक की

विशेषता थी। इस प्रकार 1858 से 1872 तक की अवधि में एक निश्चित संगति के दर्शन होते हैं। हमने इसी अल्प परंतु निर्णायक महत्व की अवधि के गहन अध्ययन का निर्णय किया है। इस और आगे के अनेक अध्यायों में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है कि ब्रिटिश राज के विकास की दृष्टि से इस काल का वित्तीय इतिहास क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक एक साम्राज्य के वित्तीय संगठन के विषय में है। यह सर्वविदित है कि लोकवित्त का स्थान राजनीतिविज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच की सीमा पर है। अध्ययन के इस क्षेत्र में यदि हम शुद्ध राजनीतिक विधिक या प्रशासनिक इतिहास की औपचारिक विधिवादिता (नियम-कायदा) का ही अध्ययन करें अथवा राजनीतिक संदर्भ से कटे शुद्ध आर्थिक इतिहास मात्र में ही अपने को लगाए रखें तो संभवतः यह उपयोगी नहीं हो सकता। सरकार की साम्राज्यिक व्यवस्था के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण विधिवादी रहा है। सिविल सेवा (सिविल सर्विस) में रहने वाले व्यक्तियों तथा विधि-शास्त्रियों ने इस दिशा में पथप्रदर्शक का कार्य किया है। इन लोगों ने औपचारिक तथा विधिक ढांचे की व्याख्या की है। इन्होंने जानबूझ कर अपने अध्ययन को यही रूप ब्यो दिया यह स्वतः स्पष्ट है। परंतु बाद के लोगों ने भी, जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, जब इस परंपरा को अपनाया तो इससे उन अनेक प्रश्नों की उपेक्षा करने की प्रेरणा मिलती है जिनके उत्तर विधि तथा अधिनियमों के अध्ययन, सांविधानिक उत्तरदायित्वों एवं कार्यों के विश्लेषण, तथा औपचारिक सरकारी तंत्र के अंगों के इतिहास मात्र से नहीं दिए जा सकते। उदाहरण के लिए, वित्तीय नीतिनिर्धारण की प्रक्रिया में उन लोगों के अतिरिक्त, जिन पर नीतिनिर्धारण का औपचारिक उत्तरदायित्व होता था, अन्य अनेक व्यक्ति भाग लेते थे। बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का उत्तरदायित्व यद्यपि थोड़े से लोगों पर डाला जाता था, तथापि इन बहुत सारे व्यक्तियों में से कुछ लोग निर्णय लेने के अधिकारी व्यक्तियों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते थे। ऐसे अनेक गुट थे जो उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते रहते थे जिनके पास निर्णय लेने का अधिकार हुआ करता था। इनमें से कुछ गुटों को दबाव डालने में सफलता मिली और इस प्रकार इन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। कुछ ऐसे भी गुट थे जो अपने उद्देश्य में असफल रहे, परंतु उन्होंने अधिकारियों को रजामंद करने और उन पर दबाव डालने का कार्य जारी रखा। एक दूसरे को प्रभावित करने वाली इस गतिशील प्रक्रिया, तथा उन अनेकानेक विचारों और दबावों को, जिनसे निर्णयों तथा कार्यवाहियों की रीति-नीति निर्धारित होती थी, केवल सत्ता के औपचारिक ढांचे के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। विधिवादी दृष्टिकोण की अपर्याप्तता भी उस समय इतनी ही स्पष्ट हो जाती है जब हम कानूनों और विनियमों में किसी स्पष्ट परिवर्तन के बिना ही प्रशासनिक पदानुक्रम (हाइरार्की) में एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्रमशः निर्णय लेने के अधिकार के स्थानांतरण पर विचार करते हैं। संचार प्रणाली की प्रगति का प्रभाव इस दृष्टि से अच्छा उदाहरण है। भारतीय तार व्यवस्था के प्रारंभ (1854), यूरोप के साथ स्थल मार्ग से केविल द्वारा संबंध स्थापित होने (1868), समय की वचत

करने वाले स्वेज मार्ग के खुलने (1869) और अंत में समुद्री केबिल पड़ जाने (1970) से इंग्लैंड के साथ ही नहीं भारत के अंदर भी संचार व्यवस्था की गति तेज हो गई। इससे भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का और प्रांतीय सरकारों पर भारत सरकार का नियंत्रण बढ गया और यही प्रवृत्ति प्रशासन में सबसे नीचे स्तर तक व्याप्त हो गई। और भी, धीरे-धीरे वित्तीय नियंत्रण को कड़ा कर देने मात्र से केंद्रीय अथवा सर्वोच्च सरकार (उस समय केंद्रीय सरकार को यही कहा जाता था) के लिए प्रांतीय (अथवा अधीनस्थ) सरकारों के निर्णय लेने की शक्तियों में कमी कर पाना संभव था। जैसा कि सर चार्ल्स ट्रेवीलियन ने कहा है : 'केंद्रीय सरकार ने वित्तीय केंद्रीकरण की नीति का पालन करते हुए प्रायः अदृश्य रूप से ब्रिटिश भारत के संविधान में 'आधार भूत परिवर्तन किए।' 'चूँकि सरकार के सभी तत्वों में वित्त सबसे सबल होता है, इसलिए यह सहज ही अन्य सभी तत्वों को आत्मसात कर लेता और उन्हें दूसरा रूप दे देता है।'<sup>2</sup> यदि हम परंपरागत विधिक दृष्टिकोण ही अपनाते हैं तो विविध प्रक्रियाओं जैसे... दबाव गुटों के प्रभाव, नवीन संचार प्रणाली के परिणामस्वरूप सत्ता के केंद्र में स्थानांतरण अथवा सरकारी यंत्र के अंगीभूत तत्वों के बीच औपचारिक विधिक संबंधों से भिन्न वास्तविक संबंधों में परिवर्तनों का विश्लेषण संभव नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था के निरूपण का प्रयास औपचारिक विधिक ढाँचे से प्रारंभ तो अवश्य होना चाहिए (अध्याय 2 में वित्तीय शक्तियों के संबंध में इस ढाँचे का अध्ययन किया गया है) परंतु उसी के साथ समाप्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र अपनी चालू अवस्था में अपने आकारगत ढाँचे के बाहर भी अनेक तत्वों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थित होता है। इस स्थिति का विश्लेषण करने में हमने कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया है जिनकी परिभाषा देना आवश्यक है।

नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) शब्द का प्रयोग पूर्ण रूप से अनिंदात्मक अर्थ में किया गया है। इसके लिए एक वैकल्पिक शब्द सिविल सेवा (सिविल सर्विस) हो सकता है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। बाद में, ब्रिटिश सिविल सेवा के संगठन पर चार्ल्स ट्रेवीलियन यथा नार्थकोट की रिपोर्ट (1858) के प्रकाशन के बाद यह इंग्लैंड में काफी प्रचलित हो चला। यहाँ पर नौकरशाही शब्द इसलिए अधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि भारत में 'सिविल सेवा' का अर्थ प्रायः भारतीय सिविल सेवा लगाया जाता था। मूल रूप से भारतीय 'सिविल सेवा' में कंपनी के वे ही संविदाबद्ध (कावेनेंटेड) कर्मचारी आते थे जो गैरसैनिक होते थे, जबकि नौकरशाही शब्द व्यापक है और इसकी परिभाषा में सरकारी पदाधिकारियों का संपूर्ण वर्ग आ जाता है जिसमें भारतीय सिविल सेवा के संविदाबद्ध कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

हितवद्ध गुट (इंटरेस्ट ग्रुप) शब्द व्यक्तियों के उन समूहों के लिए प्रयोग किया गया है जिनका पास समस्याओं के संदर्भ में एक जैसा हित हो और जो स्वार्थ के आधार पर कल्पित अथवा वास्तविक समुदाय के रूप में संघटित हों। तात्पर्य यह है कि विशिष्ट समस्याओं पर गुट के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक जैसी होनी चाहिए

और सभी समान रूप से उनकी संतुष्टि के इच्छुक हों। हमारी दिलचस्पी इन गुटों के आंतरिक संगठन के बारे में इतनी नहीं है जितनी कि उस प्रक्रिया के विषय में है जिसके द्वारा ये हितवद्ध गुट अपने वर्ग के उद्देश्य के अनुरूप निर्णय पाने के लिए उन व्यक्तियों पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते थे जिनके पास कानून के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार था। कोई भी वर्ग जो इस प्रकार सरकार पर दबाव डालता है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह परोक्ष रूप से निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जो कार्यवाही की दिशा और नौकरशाही के सदस्यों द्वारा निर्णयों की क्रियान्वयन की प्रणाली निश्चित करती है। हमारे शब्दों में, हमारी दिलचस्पी उन गुटों के द्वारा डाले जाने वाले प्रभावों में है जिनकी पहुँच सरकार तक थी। हमारे इस अध्ययन का विषय केवल उन्हीं वर्गों तक सीमित है जिनकी रुचि सरकार की आधिक और विशेष रूप से वित्तीय नीतियों में थी। इस संदर्भ में सत्ता (पावर) और प्रभाव (इंफ्लुएंस) शब्दों में, अंतर करना आवश्यक है। हम सत्ता शब्द का प्रयोग सरकार में निर्णय करने की औपचारिक विधिक शक्ति के लिए कर सकते हैं। प्रभाव शब्द उस सत्ता को प्रभावित करने की सामर्थ्य (परामर्श, अनुमति, अथवा चालाकी द्वारा) की ओर संकेत करता है।

अनेक वर्ग जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस प्रकार के वर्गों को 'हितवद्ध गुट समूह' (इंटरैस्ट कंस्टेलेशन्स) कहा जा सकता है। मेयो, आरगाइल, अथवा टूवीलियन ने इसी अर्थ में रेल उद्योग से संबंधित हितों अथवा फास व्यवसाय से संबद्ध हितों की चर्चा की है।<sup>3</sup> यहाँ हमारी अधिक दिलचस्पी उन्हीं संगठित हितवद्ध समूहों में है जो काफी स्पष्ट रूप से बोधगम्य हैं क्योंकि हितवद्ध गुट समूहों की भाँति बृहत् समष्टि के संबंध में साधारणीकरण कर सकना तो सहज है परंतु उनका परीक्षण कठिन है। यह दावा करना व्यर्थ है कि हितवद्ध गुटों का प्रभाव मापा जा सकता है। परंतु गुटों के विभिन्न भेदों, उनकी कार्य प्रणालियों एवं उद्देश्यों तथा उनके पारस्परिक सघर्षों तथा संपर्कों का अध्ययन उपयोगिता हो सकता है।<sup>4</sup> औपचारिक ढंग से संगठित दबाव गुट मोटे तौर पर दो प्रकार के थे।<sup>5</sup> प्रथम तो वे गुट थे जो भलीभाँति और सुचारु रूप से संगठित थे। इनमें से प्रत्येक गुट आधिक हितों और इन हितों से संबद्ध विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की दृष्टि से समरूप (एक जैसा) होता था। दूसरे प्रकार के दबाव गुट मोटे तौर पर दो प्रकार के दबाव गुट अपेक्षाकृत विषमरूप होते थे तथापि औपचारिक संगठन अथवा समुदाय के रूप में वे संगठित थे और प्रायः सामान्य नीतिनिर्देशन करते थे क्योंकि गुट की विषमरूपता के चलते किसी आर्थिक गुट विशेष के हितों का पक्ष लेने की प्रवृत्ति नहीं रह पाती थी। पहले प्रकार के गुटों की रचना और उनके व्यवहार में कुछ समानता थी। दूसरी श्रेणी में आने वाले गुटों में विषमता थी और वे एक दूसरे को निभाने के उद्देश्य से बने हुए अप्रिय संगठनों की भाँति थे। इस प्रकार के गुटों में आने वाले सभी तत्वों के दीर्घकालीन हित-उद्देश्य अनिवार्य रूप से एक ही नहीं थे। विश्लेषणात्मक दृष्टि से हितों में समानता, संगठन और दृढ़ता के स्तर तथा उद्देश्यों की विशिष्टता के आधार पर इन दोनों प्रकार के गुटों में भेद कर सकना संभव है। एक तीसरे प्रकार का तत्व

कराची के अन्य दो चेंबर बहुत छोटी सस्थाएं थे और कलकत्ता की ही भांति इनके सभी पदाधिकारी यूरोपीय ही थे। जैसा कि आगे स्पष्ट होगा, चेंबर्स आव कामर्स की दिलचस्पी मुख्य रूप से टैरिफ, सीमा शुल्क मूल्यांकन देश में वस्तुओं के स्थानांतरण पर अंतर्देशीय शुल्क, व्यावसायिक कर जैसे मोहतरफा और व्यापार करने के लिए अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) शुल्क, आयकर, तथा बागान उद्यमों को प्रभावित करने वाले भूमिव्यवस्था संबंधी सरकारी नीति में होती थी। छोटे व्यवसायियों ने दि कलकत्ता टेबर्स एसोसिएशन, 1830 में बनाया। इन लोगों के प्रयोजन बंगाल चेंबर आव कामर्स की तुलना में बहुत सीमित थे और ये केवल अपने ऊपर लागू होने वाले करों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। इस संघ ने भूमि से प्राप्त होने वाली आय अथवा अचल संपत्ति तथा निष्क्रिय पूँजी पर भारी करों की मांग की थी जिससे व्यापार पर करों का बोझ कम करना संभव हो सके। विशेष रूप से 1859-61 की अवधि में दि इंडिगो प्लाटर्स एसोसिएशन आव बंगाल, कुर्ग के कहवा बागान मालिकों और असम के चाय बागान मालिकों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहा था। उन्होंने उस समय तक अपने अलग सच नहीं बनाए थे, तथापि वे इतने सगठित अवश्य थे कि संयुक्त रूप से स्मरणपत्र भेज सके। इन्होंने भूमि संबंधी विनियमों में परिवर्तन की मांग की थी जिससे प्राप्त मालगुजारी की अदायगी करने वालों को पूर्ण स्वामित्व सहित भूमि का पट्टा प्राप्त हो सके।<sup>9</sup> इनकी कार्यवाही से ब्रिटेन में भारत मंत्रों के कार्यालय पर मेनचेस्टर के काटन स्प्लाइ एसोसिएशन का दबाव बढ़ चला। यह एसोसिएशन उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक से ही भारत से कच्ची कपास की आपूर्ति में वृद्धि के प्रोत्साहन का आग्रह भारत सरकार से कर रहा था। यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो मेनचेस्टर के सूती मिल मालिकों की दृष्टि से उस समय बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गई जब अमरीकी गृह युद्ध के कारण कपास की आपूर्ति में भारी कमी हो गई थी। भारत सरकार के इस एसोसिएशन ने जो उपाय सुझाए थे उनमें भूमि संबंधी विनियमों में परिवर्तन की मांग की थी ताकि पूँजीपतियों के लिए कपास बागानों का विकास कर सकना संभव हो जाए। एसोसिएशन ने भारत सरकार से कपास का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से बंदरगाहों तक सड़कों का निर्माण करने, कपास की खेती वाली भूमि को मालगुजारी से मुक्त करने, कपास निर्यात के लिए बंदरगाहों पर सुविधाओं के विकास में धन लगाने, कच्ची कपास में मिलावट रोकने के लिए कानून बनाने, और सामान्य रूप से भारत में इंग्लैंड की अतिरिक्त पूँजी और मुक्त उद्यम के निवेश का मार्ग सुगम करने में सहायता देने का आग्रह किया।<sup>10</sup> इस एसोसिएशन को मेनचेस्टर चेंबर आव कामर्स और उन अनेक मसद सदस्यों का समर्थन मिला हुआ था जिनके हित सूती वस्त्र उद्योग जुड़े हुए थे। इसने दबाव गुट के रूप में सभी प्रकार की मंमव युक्तियों का प्रयोग किया। इसने 1857, जुलाई, 1859; अप्रैल, 1860 में कोर्ट आव डायरेक्टर्स तथा भारत मंत्रों को स्मरणपत्र दिए, फरवरी, 1859 तथा अक्तूबर, 1861 में भारत कार्यालय (इंडिया आफिस) को प्रतिनिधि मंडल भेजे। मंघ की पत्रिका 'दि काटन गप्पाई रिपोर्टर' के द्वारा समाचार पत्रों में प्रचार किया गया। मंसद सदस्यों को मसद के गोप्टी तथा में प्रभावित करने का प्रयास किया और अप्रैल 1860, मई, 1861 में गवर्नर



जनरल के पास प्रतिवेदन भेजे ।<sup>11</sup> जहां तक भारत सरकार का संबंध था ग्लासगो, लीड्स, डंडी इत्यादि के चेंबर आव कामर्स अपेक्षाकृत कम सक्रिय थे, फिर भी भारतीय सीमा शुल्कों के संबंध में मेनचेस्टर के चेंबर की भांति ही ये भी चिंतित थे ।

दि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी इसी प्रकार का हितवद्ध सघ था । इस विचार से वे लोग शायद असहमत हो जो जमींदारों के हितों के संरक्षक एवं हिमायती होने के कारण उसकी भूमिका की ओर से अपनी दृष्टि खामोशी से हटा लेते हैं । इस एसोसिएशन को प्रायः राष्ट्रवाद का छद्म प्रदान कर दिया जाता है और यदि यह स्वीकार भी किया जाता है कि इसके प्रयोजन और इसका व्यवहार स्वार्थ पर आधारित थे तो भी यह कहकर इस पक्ष को अनदेखा कर दिया जाता है कि यह उच्च प्रतिमानों से यदाकदा होने वाली भूल-चूक है । दि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1837 में स्थापित उस जमींदार एसोसिएशन आफ बंगाल का वराज था जिसका नाम बाद में लैंडहोल्डर्स सोसायटी पड़ा । लैंडहोल्डर्स सोसायटी ने उदार भाव से अनन्यता (सर्वंधी सिद्धांतों) को अस्वीकार कर सदस्यता के लिए एकमात्र शर्त इस देश में, भूमिहित होना निर्धारित की ।<sup>12</sup> 1843 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसायटी के साथ इसके एकीकरण से 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई । जमींदार वर्ग के हितों के प्रतिनिधि इस एसोसिएशन को भारत भ्रमण पर आए हुए एक अंग्रेज पत्रकार ने बड़े ही सारगर्भित ढंग से संगठित स्वार्थपरता का नमूना बताया था ।<sup>13</sup> सरकार इस एसोसिएशन को जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में यथेष्ट महत्व देती थी और इसके अनेक सदस्य विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए थे । इन मनोनीत सदस्यों में प्रसन्न कुमार टैगोर भी थे जो उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में इसके प्रधान नेताओं में से थे । इन्होंने 1860 में आयकर विवरणी प्रारूप समीति की सदस्यता दी गई थी ।<sup>14</sup> जिसके अध्यक्ष रिचर्ड टैपिल थे, एसोसिएशन के सभी सदस्य जमींदार नहीं थे, कुछ सदस्य व्यापारी और व्यवसायी भी थे, परंतु इसका हार्द संपन्न जमींदार वर्ग था और जिन लोगों को शिशिर कुमार घोष की तरह आशा थी कि धीरे-धीरे शिक्षित व्यक्तियों, मध्यम वर्ग और व्यवसायियों के सघ में सम्मिलित हो जाने से जमींदार वर्ग का अल्पमत हो जाएगा, अंततः उनका यह भ्रम दूर हो गया । भ्रम दूर होने का परिणाम यह हुआ कि मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक जनतात्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए 1876 में प्रतिद्वंद्वी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई ।<sup>15</sup> वित्तीय नीति से संबंधित मामलों पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विचारों में वर्गीय हितों के प्रति काफी झुकाव था । 1860 में इस एसोसिएशन के सदस्यों ने जमींदारों की आय पर प्रत्यक्ष कराधान का इस आधार पर विरोध किया कि इससे 1793 के स्थाई वदोवस्त का उल्लंघन होता है ।<sup>16</sup> 1861 में इन्होंने सरकार से नमककर बढ़ाने का आग्रह किया । इसका भार प्रधान रूप से निर्धन वर्ग के ऊपर था यह बात इस एसोसिएशन के सदस्यों को कम से कम आपत्तिजनक लगी । एसोसिएशन को आशा थी कि नमककर से अधिक आय प्राप्त होने पर सरकार के लिए उच्च आय वाले वर्गों को आयकर के उत्पीड़न से मुक्ति दे पाना संभव होगा ।<sup>17</sup> 1871 में इन्होंने सड़क उपकर तथा शिक्षा उपकर सरीखे स्थानीय उपकरों से एकत्रित

घनराशि से किए जाने वाले स्थानीय सुधारों में रोड़े अटकाए और पुनः स्याई वंदोवस्त की दुहाई दी।<sup>18</sup> 1868 में जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने सरकार की वित्तीय नीति पर परामर्श देने के लिए योग्य भारतीयों और भद्र अंग्रेजों की सलाहकार समिति के गठन की इच्छा प्रकट की तो सपरिषद गवर्नर जनरल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार की सस्था केवल थोड़े से वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिनका एक ही स्वार्थ है कि वे अपने ऊपर कराधान न होने दें।<sup>19</sup>

इन हितवद्ध गुटों के विपरीत दूसरे प्रकार के गुट अधिक व्यापक आधार पर संगठित और विषमरूप थे और वे अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हितों के लिए कार्य करते थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया रीफार्म सोसायटी, चावे एसोसिएशन इत्यादि सभ्यतः इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। नौरोजी के प्रभाव में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र में एक बंसी लावी बन गया था जैसी कि उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के उत्तरार्द्ध में भारतीयों के लिए सभ्य थी। नौरोजी ने इस एसोसिएशन के कार्यों के बारे में सोचा था कि यह लंदन में भारतीयों के हितों की देखभाल एवं रक्षा करेगा, उन्हें आवश्यक सूचनाएं देगा और इन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से कर सकने के लिए साधन एकत्रित करेगा। इसमें इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्र और वे अंग्रेज (1868 में इनकी संख्या कुल सदस्य संख्या की बीस प्रतिशत थी) सम्मिलित हुए जो भारत में कार्य कर चुके थे। इसकी सदस्यता, और विशेषकर इसके सदस्यों में ऐसे भारतीय युवकों की उपस्थिति, जिनके कलकत्ता और बंबई के साथ कम से कम अस्याई रूप से तो संबंध शिथिल ही थे तथा साथ ही इसके कार्यस्थल ने कुछ समय के लिए इसे सार्वजनिक हितों एवं सामान्य रूप से भारतीयों के कल्याण के रक्षक की भूमिका अदा करने में सहायता पहुंचाई।<sup>20</sup> लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गोष्ठियों में इबास वेल सरीखे उदारवादियों ने साम्राज्यिक नीति के आधार के रूप में विश्वास के महत्व पर दृढ़ता के साथ जोर दिया था। सर चार्ल्स ट्रेवीलियन ने भारत के साम्राज्यिक स्वामियों एवं शिक्षकों द्वारा इस देश को बिना हानि पहुंचाए ही इसे छोड़ जाने की भावी संभावना पर अटकलबाजी की थी। और तो और घनघोर सत्तावादी बार्टल फ्रेर ने भारतीय लोकमत पर अपने विचार व्यक्त किए थे।<sup>21</sup> जर्नल आव दी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में प्रकाशित एसोसिएशन के कार्य विवरण तथा भारत मंत्री और संसदीय प्रवर समितियों आदिको दिए गए स्मरणपत्रों से पता चलता है कि इस एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों को वित्तीय समस्याओं की अच्छी जानकारी थी। उनके कुछ विचार तो काफी प्रगतिशील थे। उन्होंने चालू राजस्व से लोक निर्माण पर व्यय करने की तत्कालीन प्रचलित रीति के स्थान पर ऋण की और ऋण शोधन निधि (सिंकिंग फंड) की उचित व्यवस्था के लिए वकालत की, और नौरोजी द्वारा की गई हिमायत से, विशेषतः 1870 में एसोसिएशन के सामने पड़े गए उनके लेख 'वाट्स एंड मीस आव इंडिया' से यह विषय सार्वजनिक बहस के एक नए ऊँचे स्तर पर पहुंच गया।<sup>22</sup> फिर भी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक प्रकार से स्वदेश से बाहर विस्मृत अवस्था में ही था और उसकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंबई (1869 में स्थापित) के नाम से ज्ञात एकमात्र भारतीय शाखा

की भूमिका विचित्र रूप से प्रभावहीन रही। केवल भारतीय राजस्व के संबंध में संसदीय प्रवर समिति की नियुक्ति के अवसर पर बंबई शाखा ने अपनी याचिका (अर्जी) 1871 में ब्रिटेन के भारत कार्यालय संबंधी खर्चों (होम चार्ज) के विषय में जाच की भूमिका तैयार करने की दिशा में थोड़ा सा प्रयास किया था।<sup>23</sup> इस सस्था और बंबई एसोसिएशन के बीच जिसने लगभग इसी समय और इसी संबंध में याचिका प्रस्तुत की थी भ्रम नहीं होना चाहिए।<sup>24</sup> बंबई एसोसिएशन में बंबई के तीन प्रमुख संप्रदाय पारसी, गुजराती, महाराष्ट्रीय सम्मिलित थे। इसने आर० जी० मंडारकर और सोराबजी सपूरजी वंगाली जैसे अनेक विख्यात व्यावसायिक व्यक्तियों को आकर्षित किया। इनमें से बहुत सारे ब्रिजित एल्फिंस्टन कालेज के छात्र रह चुके थे। इसे नाथभाई, मंगलदास और जमशेदजी जीजीभाई जैसे व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। बंबई एसोसिएशन की दिलचस्पी मुख्य रूप से स्थानीय मामलों में थी। यह लोकनिर्माण कार्यों को श्रेष्ठता और उनमें किफायत-शारी का पक्षपाती था। 1871 में इसने गृह कर तथा चुगी का विरोध किया और कलकत्ता तथा दूसरे स्थानों पर विधानपरिषदों में सुधार और सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश सुकर बनाने की मांग की।<sup>25</sup> यह आश्चर्य की बात है कि भारतीय वित्त से संबंधित अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर एसोसिएशन चुप्पी साधे था। संभवतः ऐसा इसलिए हुआ होगा कि व्यापारी वर्ग ने चेंबर आव कामर्स को (जिसमें बंगाल चेंबर आव कामर्स की तुलना में भारतीयों का प्रतिनिधित्व अधिक प्रबल था) इन मामलों के लिए अधिक प्रभावशाली सस्था समझा हो।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में ऐसे विचार धीरे-धीरे निश्चित रूप ले रहे थे जिनमें आर्थिक राष्ट्रवाद का सारा तत्व आ जाता है (इस संबंध में अध्याय पांच में विवेचना की गई है)। अनेक स्थानीय संघ जैसे, बावे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, अनुनय और दबाव की रीतियां सीख रहे थे। इस संदर्भ में नौरोजी की स्थिति विशेष थी, क्योंकि इंग्लैंड में अपनाए गए इन तरीकों से उनका व्यक्तिगत परिचय था और उनका कार्यस्थल लंदन होने से उन्हें स्थिति का लाभ भी प्राप्त था। उन्होंने भारतीय वित्त विषयक संसदीय प्रवर समिति से 1871 में कहा था कि 'भारत सरकार पर अंग्रेजी हित इस प्रकार का दबाव डालते हैं कि जब तक संसद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती और अपने वादों के अनुसार भारतीयों के प्रति न्याय पर जोर नहीं देती तब तक इस संबंध में कोई आशा नहीं की जा सकती।' <sup>26</sup> इस प्रकार के दबाव से लड़ने के लिए नौरोजी मैदान में उतरे थे मगर उन अधिकारियों तक उनकी पहुंच नहीं थी जिन्हें उन्होंने शासनतंत्र में निर्णय लेने वाला मस्तिष्क और निर्णय को कार्यरूप देने वाला हाथ कहा जाता है। संभवतया उन्होंने प्रचार के असर को अधिक महत्वपूर्ण मान लेने की भूल की थी। उनकी भूल यह भी रही कि उन्होंने आशा की थी कि न्याय के बारे में प्रचलित ब्रिटिश धारणा की रक्षा के लिए संसद भारत सरकार को डांट कर उसी प्रकार हस्तक्षेप करेगी जैसे बालवाड़ी (नर्सरी) में परिचारिका उदंड छात्र पर रोकथाम लगाती है। परंतु नौरोजी ने समस्या प्रस्तुत करने तथा पक्ष समर्थन में जनमत और सहानुभूति तैयार करने के लिए उस समय जो भी रीतियां अपनाईं जा

सकती थी उन सभी का प्रयोग किया। इस संबंध में उन्हें अंग्रेजी हितों ने ही रास्ता दिखाया था। 'इंडिया इट्स गवर्नमेंट अंडर ब्यूरोक्रेसी' के लेखक तथा 'रीफार्म ट्रेक्ट सीरीज' के प्रकाशक जान डिकिंसन द्वारा 1853 में स्थापित इंडिया रीफार्म सोसायटी के प्रयत्नों से इंग्लैंड में तैयार किए गए वैचारिक वातावरण से नौरोजी को सहायता मिली।<sup>27</sup> कुछ लोकोपकारी उद्देश्यों ने भी उत्साही लोगों को आकर्षित किया। उदाहरणार्थ, उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में भारत सरकार की अफीम उत्पादन और व्यापार में भागीदारों के विरोध में आंदोलन की ओर लोगों का ध्यान गया। इस आंदोलन का परिणाम अंततः यह हुआ कि 1874 में अफीम के व्यापार पर रोक लगवाने के लिए एक सोसायटी की स्थापना हुई।<sup>28</sup>

जनतांत्रिक व्यवस्था की अनिश्चित एकतन्त्रात्मक व्यवस्था में दबाव गुटों द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों की व्यापकता सीमित होती थी। सरकार के अंगों तक पहुंचने का आम माध्यम याचिका (अर्जी) अथवा स्मरणपत्र होता था। ऐसा लगता है कि एक परंपरा सी बन रही थी कि भारत में स्मरणपत्र पहले नीचे स्तर के सरकारी अधिकारियों (जैसे—प्रांतीय राजस्व बोर्ड के सचिव अथवा भारतीय वित्त विभाग के सचिव) को भेजा जाता था। संभवतः इसका उद्देश्य स्थिति का पता लगाना रहता होगा। तत्पश्चात् स्मरणपत्र सरकार के ऊंचे अधिकारियों (जैसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद) और अंत में भारत मंत्री के पास भेजा जाता था। दूसरी ओर, इंग्लैंड में कार्य करने वाले दबाव गुट सीधे भारत मंत्री के पास पहुंचते थे जो सपरिषद गवर्नर जनरल (गवर्नर जनरल इन काउंसिल) को सदेश भेजता था। परंतु इंग्लैंड में कार्य करने वाले हितवद्ध गुटों के सामने यह विकल्प भी था कि वे अपने सतोष के लिए भारत सरकार के साथ सीधी कार्यवाही कर सकते थे। अतः लंदन में अपने प्रयत्नों से संतुष्ट न होकर काटन सप्ताई एसोसिएशन ने सपरिषद गवर्नर जनरल के साथ सीधा पत्र व्यवहार किया।<sup>29</sup> कुछेक भारतीय सधों और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने लंदन में भारत मंत्री के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया था। इसी प्रकार 1870 में जब संसदीय प्रवर समिति (सलेक्ट कमेटी) की नियुक्ति आसन्न दिखाई देने लगी तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और वावे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अपील के आखिरी न्यायालय में पहुंचे।<sup>30</sup> नौरोजी का अनुभव था कि पिरामिड रूपी शासनतंत्र के शीर्ष इंडिया आफिस और ससद में निकटता के कारण इंग्लैंड के दबाव गुटों की अनिश्चित अधिक सुविधा थी।

स्मरणपत्र का प्रभाव उस समय अधिक पड़ता था जब अनेक गुट अथवा संघ मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करते थे। ब्रिटिश दबाव गुटों से भिन्न भारतीय मध्य प्रधान रूप से स्वानीय गुट होते थे और मंगलछिंद वगैरे कार्यवाही कर पाने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिए, हम ब्रिटिश दबाव गुटों के एक छोटे से आंदोलन पर विचार करें। यह आंदोलन घांरे पर लगाए गए मुक्त में कमी करने के लिए चलाया गया था। दिसंबर 1860 में लंदन की उन 42 कमी ने आंदोलन प्रारंभ किया जो भारत से घांरे का आयात करती थी (आयात मुख्यतः यूरोपीय देशों को फिर से निर्यात करने के उद्देश्य से किए जाते थे)। उन्होंने भारत मंत्री को एक स्मरणपत्र भेजा जिसमें लिखा गया था कि

भारतीय निर्यात शुल्क से उनके व्यापार को हानि होती है। दो माह के भीतर ही बंगाल चेंबर आव कामर्स भी इस संघर्ष में सम्मिलित हो गया। बंगाल चेंबर के दो माह बाद बंबई चेंबर आव कामर्स ने निर्यात शुल्क पर अपना विरोध पत्र दिया। मद्रास चेंबर आव कामर्स की प्रतिक्रिया कुछ देर से हुई, परंतु इसने सरकार को तीन स्मरणपत्र भेजकर अपने विलंब की दृष्टिपूर्ति की। कराची चेंबर आव कामर्स अपेक्षाकृत पिछड़ी अवस्था में था और अप्रैल, 1862 तक आंदोलन में सम्मिलित होने में असमर्थ रहा। मामले को गर्म रखने के लिए व्यक्तिगत व्यापारिक फर्मों ने (उदाहरणार्थ, सिंध के शोरा उत्पादकों और कलकत्ते की निर्यातकर्मी ब्रिटिश फर्मों) ने मिलकर संयुक्त रूप से समय-समय पर कुछ और भी स्मरणपत्र भेजे। इस लगातार सामूहिक प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि 1865 में शुल्क कम कर दिया गया। 1866 में इसमें पुनः कमी की गई।<sup>31</sup> उस समय तक भारतीय संगठनों के द्वारा इस प्रकार का संगठित प्रयास संभव नहीं था।

नीति निर्धारकों के पास पहुंचने की एक अन्य रीति यह थी कि भारत सरकार के उच्चपदस्थ सदस्यों अथवा भारत मंत्री के पास प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। उदाहरणार्थ, सीमा शुल्क मूल्यांकन प्रणाली से असंतुष्ट बंगाल चेंबर आव कामर्स गवर्नर जनरल की परिषद के वित्त सदस्य को उस प्रतिनिधि मंडल (अक्टूबर, 1860) से बातचीत करने के लिए राजी करने में सफल हो सका जिसे कलकत्ता, मद्रास, बंबई और मेनचेस्टर के चेंबरों द्वारा प्रस्तुत विविध स्मरणपत्रों में की गई शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करना था।<sup>32</sup> काटन सप्लाई एसोसिएशन ने 1859 और 1862 के बीच अनेक अवसरों पर भारत मंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे। भारत को प्रस्थान करने से कुछ ही समय पहले वित्त सदस्य विल्सन और लैंग ने मेनचेस्टर के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की थी।<sup>33</sup> भारतीय व्यापारियों के इस प्रकार के प्रतिनिधि मंडलों के उदाहरण बहुत थोड़े मिलते हैं। (1860 में कलकत्ता के मारवाड़ी व्यापारी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में बंगाल सरकार के सेक्रेटेरियट से यह आग्रह करने के उद्देश्य से मिले थे कि सरकार इस बात पर विचार करे कि आयकर निर्धारकों द्वारा की जाने वाली जाच से यदि यह प्रकट हो जाता है कि व्यापार में कितना घन उसका अपना और कितना दूसरे का है तो इससे अनेक मारवाड़ी कोठियों की व्यापारिक ख्याति को हानि होगी)।<sup>34</sup> स्पष्टतया अपनी शिकायतें रखने की इस रीति का प्रयोग जितनी बार अंग्रेजों ने किया उतनी बार भारतीय नहीं कर सके। संभवतः आमने-सामने की भेंट से कोई लाभ भी नहीं होता था। जब हम ब्रिटिश सिविल सेवा अधिकारियों और पराधीन प्रजाति के बीच बढ़ती हुई सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नजर नहीं आती।

जो लोग अपनी शिकायतें रखने और न्याय पाने के लिए विनम्र भाव से दिए जाने वाले स्मरणपत्रों और याचिकाओं (अर्जियों) को अपर्याप्त समझते थे उनके सामने एक तीसरा रास्ता भी था कि वे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करें। कुछ दबाव गुटों के निजी प्रचार साधन थे। इनका उद्देश्य काटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा निकाली जाने वाली 'काटन सप्लाई रिपोर्टर' नामक पत्रिका की भांति या तो बहुत अधिक विशिष्ट अथवा सीमित होता था, या फिर प्रचार के ये साधन पूर्ण समाचार पत्र होते थे जैसे कि

'हिंदू पेट्रिट' जिसे एक बोर्ड आव ट्रस्टीज चलाता था जिस में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों का दबदबा अधिक था।<sup>35</sup> इतना अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने पर भी समाचारपत्रों का प्रयोग प्रचार के लिए किया जा सकता था। भारत का यूरोपीय वाणिज्यिक समाज 'इंगलिशमैन' अथवा 'पायनियर' जैसे समाचारपत्रों का उपयोग प्रायः इसी प्रकार करता था। इसी प्रकार बंबई की 'रास्तगोपतार' नामक एक प्रमुख पारसी पत्रिका का प्रयोग नौरोजी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के उनके सहयोगियों ने प्रचार कार्य के लिए किया। भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचारपत्रों की उभयमुखता एक प्रासंगिक दिलचस्पी की बात है। ये समाचारपत्र अपने लेखों में उत्तेजनात्मक और समझौताकारी हथों में संगति-सी बैठते रहते हैं। संभवतः ऐसा इसलिए था कि ये पत्रिकाएँ एक नहीं दो प्रकार के पाठकों के लिए हुआ करती थी। ये दो प्रकार के पाठकगण पराधीन वर्ग के प्रबुद्ध सदस्य और शासक वर्ग के सहानुभूतिशील सदस्य थे। इस श्रेणी में आने वाली पत्रकारिता की इस विशेषता की ओर किसी का ध्यान न जाए ऐसा हो नहीं सकता।

संसद में लाब्बी की रीति एक ऐसी कला थी जिससे भारतीय परिचित होने लगे थे। सभी प्रकार की लाब्बी का उद्देश्य प्रत्यक्ष स्वार्थ नहीं था। ब्रिटिश संसद सदस्यों ने लोक-कल्याण के लिए कार्य करने वाले अनेक नागरिक गुटों को अपना समर्थन दिया था। इसी श्रेणी में आने वाली एक लाब्बी अफीम विरोधी गुट था। प्रति वर्ष कम उपस्थिति वाले सदन में कुछ संसद सदस्य भारत मंत्री के वित्तीय विवरण पर टिप्पणी करने के लिए खड़े होते और भारत सरकार की भागीदारी में होने वाले अफीम के व्यापार की नैतिक दृष्टि से निन्दनीय प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करते। कर्नल साइक्स, आर० एन० फाउलर, सर डब्ल्यू० लासन, स्टीफन केव तथा एम० फाउलर कुछ संसद सदस्य थे जो अफीम विरोधी लाब्बी में आते थे।<sup>36</sup> संसद में की जाने वाली एक अन्य प्रकार की लाब्बी वाणिज्यिक हितवद्ध गुटों की ओर से होती थी। इंडिड में किसी भी हितवद्ध गुट की लाब्बी (जैसे सूती यस्त्र उद्योग के हितों के समर्थक संसद सदस्य जे० बी० स्मिथ तथा टी० वेजल और उनके सहायक वाटसन, फ्राफोर्ड और कुछ दूसरे लोग) भारतीयों की तुलना में बहुत अधिक सशक्त थी। यद्यपि स्वार्थ पर आधारित संबंधों की तुलना में सहानुभूति के बंधन सामान्यतया शिथिल होते हैं, फिर भी संसद में भारतीयों के कुछ ऐसे हमदर्द सदस्य थे जो भारत मंत्री और भारत सरकार के लिए अनुविधाजनक स्थिति उत्पन्न कर देते थे। डिजरायली तथा स्टेफोर्ड नोर्थकोट को लिखे गए अपने पत्रों में मेयो ने तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि इन भारतीय शिकायतवाज उग्र लोगों की यह सहज प्रवृत्ति है कि वे भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावों और अल्पज्ञ भारतीय राज-नेताओं का समर्थन करते हैं।<sup>37</sup> इन्होंने काफी समय से मन में भरा गुबार उस समय निकाला जब भारतीय वित्त के संबंध में संसद की प्रवर समिति की नियुक्ति की गई। इंडिया आफिस से आरमाइन ने लिखा कि यह एक उबाऊ परंतु उसने इसे अनिवार्य बुराई मानकर अपने आपको मनुष्ट कर लिया था।<sup>38</sup> वित्त मदस्य रिचर्ड टैपिल ने (मेयो तथा आरमाइन की भांति ही निम्नी पत्रों में) श्री एफ० द्वारा पूछे गए प्रश्नों की ओर निंदा करते हुए लिखा कि 'ये प्रश्न तो थे ही नहीं, वे तो भारत सरकार पर

अप्रत्यक्ष रूप से किए गए प्रहार थे।<sup>39</sup> टैपिल ने जिस आलोचक को निंदक के रूप में चुन रखा था वह संभवतः हेनरी फास्ट था जो कैंब्रिज विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर (1863-84) और ब्राइटन से चुना गया संसद सदस्य (1865 और 1868 में चुना गया) था। वह न केवल भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के रूप में विख्यात था, बल्कि यों कहिए कि वह इसके लिए लगभग कुख्यात था। वह हेनरी हिडमैन के परामर्शदाताओं में था जो ट्रिनिटी में उसका शिष्य रह चुका था। हेनरी हिडमैन (जेम्स मेडस तथा नौरोजी की रचनाओं से प्रभावित होकर) भारतीय हितों का एक अनन्य समर्थक बन गया था।<sup>40</sup> यद्यपि संसद द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता अथवा किसी भारत हितोंपी संसद सदस्य के अत्यधिक उत्साह पर कलकत्ता स्थित राज-भवन (गवर्नमेंट हाउस) अथवा इंडिया आफिस में कोई उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया की संभावना नहीं होती थी, तथापि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बाये एसोसिएशन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस प्रकार के अवसरों का उत्सुकतापूर्वक लाभ उठाते थे। नौरोजी को प्रवर समिति के सामने भारतीय वित्त पर अपनी आलोचना रखने का जो अवसर प्रदान किया गया, उसके आधार पर उसकी स्थिति विरोधी प्रवक्ता के रूप में लगभग वैध मान ली गई। जब भारतीय वित्त के संवध में 1871 में संसदीय प्रवर समिति नियुक्त हुई तो इन संस्थाओं द्वारा भेजे गए स्मरण पत्रों से स्पष्ट है कि ये संसदीय जाच को शिकायत-प्रकाश में लाने का एक माध्यम मानती थी। नौरोजी ने प्रवर समिति के सामने अपने वक्तव्य में कहा था कि साम्राज्य की इस महान संसद का नियंत्रण उन अनेक वुराहों को रोक सकेगा जिन्हें भारत सरकार में उत्तरदायित्व की भावना से मुक्ति के कारण प्रोत्साहन मिलता है।<sup>41</sup> यह जाच ब्रिटिश जनता और संसद को जानकारी कराने का अद्वितीय अवसर थी। यह कह सकना कठिन है कि इन संघों के नौरोजी जैसे सदस्य वास्तव में यह विश्वास करते थे कि भारतीयों के साथ होने वाले अन्यायों को समाप्त करने के लिए तत्पर संसद और भारत के बीच जानकारी की कमी को दूर करने भर से कोई चमत्कार हो जाने वाला था। यह सत्य है कि इस प्रकार के सहज कथन और इनके साथ-साथ अंग्रेजों के राष्ट्रीय चरित्र के विषय में अस्पष्ट साधारणीकरण काफी प्रचलन में थे। न्याय की भावना आदि का प्रायः उल्लेख किया जाता था। परंतु यह फैशन मात्र, राजनीति के खेल की एक कला, एक तरीका और एक भाषा थी जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझी जाती थी।

अंत में, किसी दवाय गुट और भारत सरकार के मध्य सलाह और विचारों के आदान-प्रदान का एक अन्य माध्यम विधानपरिषद तथा सरकार द्वारा नियुक्त समितियों आदि में गुट का प्रतिनिधित्व होता था। चैंबर्स आव कामर्स तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों को विधानपरिषद में मनोनीत किया गया। एस० एन० बुलन (बंगाल चेंबर आव कामर्स का अध्यक्ष) को सीमा शुल्क मूल्यांकन पुनरीक्षण समिति (1860) में।<sup>42</sup> प्रसन्न कुमार टेंगोर (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) को आयकर पत्रक में संशोधन समिति (1860) में<sup>43</sup> और जे० ए० क्राफोर्ड (बंगाल चेंबर आव कामर्स)<sup>44</sup> को 1866 की टैरिफ समिति के सदस्य रूप में शामिल किया गया। सरकार द्वारा प्रमुख

गुटों के प्रयत्नाओं के रूप में गैर सरकारी व्यक्तियों के सतर्कतापूर्वक चुनाव के ये तथा कुछ अन्य उदाहरण सरकार की इन गुटों के साथ संपर्क रखने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। विधान परिषद की शक्तियाँ इतनी सीमित थीं और इन समितियों के कार्य इतने कम महत्वपूर्ण थे कि इन संस्थाओं के साथ गैर सरकारी व्यक्तियों के औपचारिक संबंध से केवल एक ही लाभ था कि संबंध बने रहने के अलावा एक दूसरे के विचारों के बारे में जानकारी बनी रहती थी। हमने एक अन्य स्थान पर विधानपरिषद में मनोनीत गैर सरकारी भारतीय सदस्यों में जमींदार अभिजात वर्ग की प्रधानता के कारण पेशेवर शहरी मध्यम वर्ग में उत्पन्न असंतोष का उल्लेख किया है।<sup>45</sup> चूंकि विधानपरिषद की बहसों के मोटे-मोटे विवरण समाचार पत्रों में आ ही जाते थे, और चूंकि ये कार्यविवरण आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, अतः इतिहासकारों ने विधानपरिषद की कार्यवाही की ओर विशेष ध्यान दिया है। परंतु इस बात के पक्ष में विशेष प्रमाण नहीं है कि नीति निर्धारण पर परिषद की बहसों का कोई प्रभाव पड़ता था।

स्मरणपत्र, प्रतिनिधि मंडल, समाचारपत्रों द्वारा प्रचार, ससद में लाइवी और विधानपरिषद अथवा सरकारी समितियों में प्रतिनिधित्व दबाव गुटों और सरकार के बीच संपर्क के महत्वपूर्ण माध्यम थे। परंतु अनौपचारिक संबंधों के द्वारा निर्णय को प्रभावित करने की संभावना छोड़ी नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, प्रशासन के नीचे के स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों पर यूरोपीय व्यापारियों का कुछ प्रभाव था। 1860 में कलकत्ता में सीमा शुल्क निर्धारण प्रणाली के बारे में जांच करते हुए एशले ईडन को सीमा शुल्क अधिकारियों और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों में साठ-गाठ का सदेह हुआ था।<sup>46</sup> सीमा शुल्क दरों का निर्धारण बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित दरों के बीच में समझौते द्वारा ही हुआ था। ईडन ने पाया कि व्यापार की उन सभी वस्तुओं का अवमूल्यमान हुआ था जिनमें अधिक प्रभावशाली व्यापारियों की दितचस्पी थी।<sup>47</sup> इस बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह का भ्रष्टाचार व्यापक था। कम से कम सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों से यह ज्ञात नहीं की जा सकती थी कि वे किसी से इस प्रकार की साठ-गाठ करेंगे। परंतु क्या वे भारत में अंग्रेज जाति के सामाजिक दबाव से मुक्त थे? इस प्रश्न का उत्तर काफी महत्वपूर्ण है।

ऐसा लगता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय लोगों और भारतीयों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ने लगी। इससे भारतीयों की यूरोपियनों तक पहुंच अधिक सरल न रही। दूसरी ओर यूरोपियनों के संपर्क का दायरा सकुचित हो जाने से वे अपने ही छोटे से समाज के सदस्यों के दबाव में अधिक आ गए। प्रवाह के साथ तैरने वालों को तो अधिक दबाव मालूम नहीं पड़ता, परंतु जो धारा के विपरीत जाते हैं उन्हें इस दबाव की शक्ति का पता चलता है। एंग्लो इंडियन समाज की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जेम्स सर चार्ल्स ट्रेवीलियन तथा मेयो ने निर्णय लिए तो उन्हें इसी प्रकार का अनुभव हुआ था। ट्रेवीलियन ने देखा कि किरायेदार बरतने के उसके प्रयत्नों में सेवा भावना और संघ भावना बाधक थी।<sup>48</sup> उसके सामने ऐसे मामले आए जिनमें लोगो



ने प्रधान रूप से भ्रातृ भाव से प्रेरित होकर अपने पद से स्वयं अपने और मित्रों के लिए अनुचित लाभ उठाए थे।<sup>49</sup> जब उसने अपने 1865 के वजट में अन्य वस्तुओं के अति-रिक्त चाय, कहवा तथा जूट पर निर्यात कर लगाने का प्रस्ताव रखा तो वह व्यापार में लगे हुए यूरोपियनों का कोपभाजन बना। एंग्लो इंडियन समाचारपत्रों ने समझा कि वह वागान मालिकों के हितों के विरुद्ध था,<sup>50</sup> और जैसा कि फ्रीड आंव इंडिया ने लिखा कि उसे वाणिज्य और व्यापारी वर्ग के साथ सक्रिय सहानुभूति नहीं थी।<sup>51</sup> भारत मंत्री ने नए निर्यात करों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। भारत सरकार अपने द्वारा ही पराजित अधिनियम की संशुद्ध धाराएं रद्द करने को वाध्य हुई, और वर्ष समाप्त होने से पहले ही ट्रंबोलियन का स्थान ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड से डब्ल्यू० एन० मंसी आ गया।<sup>52</sup> मेयो का मामला अधिक मनोरंजक है क्योंकि उसे नौकरशाही और सेना के ही भीतरी दबावों से संघर्ष करना पड़ा था। जब उसने सेना पर व्यय में कमी करने का प्रयत्न किया तो उसका अपने ही कमांडर इन चीफ से संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से टिप्पणियों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में सेनाध्यक्ष ने फेबियन दावपेच इस्तेमाल किए (निर्णय न होने देने के लिए उसने सबधित कागजात अपने पास रोक लिए), उसने अपने शत्रु पर अप्रत्यक्ष वार भी किया (भारत मंत्री और उसकी परिपद के सदस्यों के साथ सीधा पत्र व्यवहार करके), और पूरी तरह भात देने के लिए सेना सबधी मामलों के सदस्य ने तो धुलकर प्रतिकारात्मक वार किया (उसने सेना पर व्यय में कमी न करने और अर्सेनिक व्यय में कमी करने का प्रस्ताव रखा)।<sup>53</sup> सेना के रसद विभाग और बैरक निर्माण पर व्यय में कमी करने के लिए मेयो को पूरा लाछन मिला<sup>54</sup> परंतु उसने दृढ़ निश्चय के साथ मोटी तनख्वाह पाने वाले दायित्वहीन सैनिक पदाधिकारियों<sup>55</sup> और अपने उन सहयोगियों के साथ संघर्ष किया जो पहले मितव्ययता के लिए काफी जोरदार मांग कर रहे थे।<sup>56</sup> भारत मंत्री ने सेना पर व्यय में कमी को अस्वीकार कर दिया। अतः हारकर मेयो ने बड़ी कटुता के साथ लिखा : 'स्वार्थ को पराजित कर पाना कठिन है। जन सेवा का स्थान तो गौण है।'<sup>57</sup> इसी प्रकार की एकता 1870 में सिविल सेवा के अनुबंधित (कावेनेटेड) अधिकारियों ने दिखलाई थी जब उन्होंने ऊंची पेशनों के लिए आंदोलन चलाया था। संघ भावना से प्रभावित होकर गवर्नर जनरल और उसकी परिपद ने भारत मंत्री को इनके मामले पर अपनी सिफारिश की। इस मामले में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों पर यह दबाव कारगर सिद्ध नहीं हुआ। और कुछ भी हो, अर्थाभाव के कारण पेशनें बढ़ाई नहीं जा सकी। आरगाइल ने स्पष्ट रूप से एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा था कि गवर्नर जनरल की परिपद में विधि सदस्य और गवर्नर जनरल को छोड़कर सभी व्यक्ति सिविल सेवा के व्यक्ति हैं और उनका इस मामले के साथ व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है।<sup>58</sup> आरगाइल के मतानुसार साम्राज्य में ही नहीं, संभवतः विश्व भर में दूसरी सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों की तुलना में भारतीय सिविल सेवा में अधिकारियों के वेतन अधिक थे।<sup>59</sup> सेवा निवृत्ति के बाद ऊंचे भत्तों और अधिक सुविधाओं के लिए सरकारी अधिकारियों के आवेदनपत्र की अस्वीकृति संबंधी विज्ञप्ति की भाषा से अधिकारियों के रुष्ट हो जाने के भय के कारण मेयो ने आरगाइल से आग्रह किया था

कि विज्ञप्ति को प्रकट न किया जाए।<sup>61</sup> मामला शांतिपूर्वक रह कर दिया गया। ये घटनाएँ इस बात की ओर संकेत करती हैं कि प्रशासन और सेना में भी कुछ स्थितियों में उसी प्रकार के व्यवहार का डर उभर कर आता था जैसा कि बाहर के हितवद्ध गुटों में होता था और भ्रातृ भाव, सघ भावना और स्वदेशवासियों के प्रति सहानुभूति महत्व-हीन तत्व नहीं थे। तथापि नीति निर्धारण सबंधी सामाजिक दबाव के बारे में और अधिक साधारणीकरण करने से पहले हमें सिविल सेवा अधिकारियों की पृष्ठभूमि, भारत में यूरोपीय समुदाय के अन्य लोगों के साथ इनके संबंधों, उनके पूँजी निवेशों, तथा उनके हितों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सरकारी निर्णयों के प्रति इनके दृष्टिकोण की गहरी जानकारी आवश्यक है। परंतु यह ठीक ही है कि सामाजिक दबाव निर्णयों को प्रभावित करने का एक माध्यम था और इसे सामूहिक परंपरागत समझदारी आचरण के स्वीकृत प्रतिमान तथा पारस्परिक प्रत्याशाओं से उत्पन्न होने वाली अनिवार्यताओं से बल मिलता था।

सामाजिक दबाव सहानुभूति पाने के लिए डाला जाता था। सत्तावादी प्रणाली में यदि दबाव गुटों की भागें पूरी नहीं की जाती थी तो उनमें से अधिकांश अनुशास्ति (संकशन) का प्रयोग करने में असमर्थ होते थे। संभवतया मेनचेस्टर चेबर आव कामर्स अथवा काटन सप्लआई एसोसिएशन जैसी सशक्त संस्थाएं भारत मंत्री के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती थी। शायद इसी प्रकार भारत में चेबर आव कामर्स भी उपद्रव कर सकते थे। परंतु साधारणतया दबाव गुट अधिक से अधिक समझा-बुझा सकते थे, अनुरोध कर सकते थे अपना मामला रख सकते थे, और परामर्श दे सकते थे। इस दृष्टि से सहानुभूति पाना काफी महत्वपूर्ण था। विदेशी शासन के कारण देशी गुटों की कुछ खास असमर्थताएँ थीं। इन असमर्थताओं में दोनों प्रजातियों के बीच सामाजिक दूरी भी कम महत्व नहीं रखती थी। वस्तुतः इसी से भारतीय हितों की तुलना में ब्रिटिश हितों को अत्यधिक सुविधा मिली हुई थी।

ऊपर दबाव गुटों की किस्मों और कार्यपद्धतियों के विषय में जो कुछ कहा गया है उससे इनके कुछ लक्षण प्रकट होने के साथ-साथ इनके कार्यकलाप भी पृथक् हो जाते हैं। यहाँ सभी संगठनों और मंडलों की सूची तैयार करना और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन करना लाभप्रद नहीं होगा। राष्ट्रीय राजनीति के इतिहासकारों ने इस दिशा में काफी कार्य किया है। हमारी दिलचस्पी सरकार और दबाव गुटों के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया और लोकवित्त की निर्णय प्रतिक्रिया पर पड़ने वाले इनके प्रभावों में अधिक है। हित-समरूपता की भाँसा, गुट के रूप में संगठन तथा एकीकरण के अंश, तथा उद्देश्यों की विशिष्टता के आधार पर हमने गुटों के दो भेद किए हैं। पहली किस्म के गुट हैं—चेबर आव कामर्स, भूस्वामी (जमींदार) संघ, बागान मालिक संघ, व्यापारी गुट आदि, और दूसरी किस्म के गुट हैं—अग्रराजनीतिक संघ (प्रोटो पालिटिक्स एसोसिएशन), परोपकारी विचार गुट, मुधारवादी उत्साही वर्ग आदि। इनके अलावा असंगठित और अस्थाई गुट भी थे, जो अपेक्षाकृत मूक और असंगठित जनसमुदाय की प्रतिक्रिया प्रकट करते थे और ऐसा लगना है कि इस प्रकार के लोग अनायास ही कभी-कभी एकत्र हो जाते थे, भारी

संख्या में याचिका (अर्जी) पर हस्ताक्षर करते थे अथवा प्रतिनिधि मंडल भेजते थे, परंतु इनके इन सब कार्यों से दबाव गुट नहीं बनता था। व्यवस्था में सफलतापूर्वक कार्य करने अथवा राजनीति के इस खेल में कामयाबी हासिल करने की दृष्टि से प्रथम स्थान पहली किस्म के, द्वितीय स्थान दूसरे प्रकार के और अंतिम स्थान अव्यवस्थित गुटों का था। इसके विपरीत, व्यवस्था के खतरे की आशका के पहलू से विचार करने पर इन गुटों का क्रम ठीक उलटा हो जाता है। पहले प्रकार के गुट दबाव डालने की कला में दक्ष थे। दूसरी श्रेणी में आने वाले गुट अभी कार्य संपादन, भारी परिश्रम के साथ स्मरणपत्र तैयार करके भेजना, लांबी करना और सामान्यतया उपद्रव करना सीख रहे थे। साधारण लोग जिन्हें मेयो ने मूक बहुतेरे कहा है<sup>61</sup> इस कला में अकुशल थे। उनकी शिकायतें तथा मांगें बंगाल के नील विद्रोह तथा दक्षिण की बगावत की भांति बड़े विद्रोहों के रूप में प्रकट होती थी। (बंगाल में नील विद्रोह में सम्मिलित होने वाले किसानों को थोड़े से जमींदारों और ग्रामीण समाज के बाहर कलकत्ता के शिक्षित मुख्तारों, पत्रकारों और मिशनरियों का समर्थन मिला था।<sup>62</sup> इसी प्रकार दक्षिण के किसानों को मालगुजारी में वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन में पूना सार्वजनिक सभा की सहानुभूति प्राप्त थी जिसने किसानों की शिकायतों के संबंध में जाच की व्यवस्था की थी।<sup>63</sup> परंतु 1859 में बंगाल में और 1875 में दक्षिण में जो भी विद्रोह हुए वे पुरानी अनिर्णीत शिकायतों के फलस्वरूप स्वतः प्रवर्तित विस्फोट थे और उनका नेतृत्व दबाव गुटों के दाव पेच में कुशल शहरी व शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में नहीं था। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नील उत्पातों से संबंधित अभिलेखों में गांवों के जिन मुखियों अथवा मंडलों के नाम नेताओं के रूप में मिलते हैं वे इतने अधिक हैं कि प्रत्येक का उल्लेख कर पाना कठिन है... किसी भी गांव में जो नेता उत्पन्न हो गए, उनका अत्यधिक प्रभाव अविश्वसनीय अल्प समय में पास पड़ोस के अनेक गांवों में हो गया, परंतु यह प्रभाव नष्ट भी उतनी ही शीघ्रता से हो गया।<sup>64</sup> दक्षिण के किसानों की याचिकाओं से वहां के उपद्रवों की पूर्व सूचना मिल गई थी। इन याचिकाओं में एक याचिका विशिष्ट थी जो जुलाई 1873 में ईदापुर गांव की एक सभा में तैयार की गई थी, जिस पर थोड़े ही समय में 2,694 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो गए थे जिससे यह काफी प्रभावशाली बन गई थी। 1875 के उपद्रव आत्मस्फूर्त थे और वे उस प्रकार के संगठित आंदोलन से भिन्न थे जैसा कि पूना सार्वजनिक सभा ने सोचा था।<sup>65</sup> बंगाल और दक्षिण के आंदोलनों के वैधानिक हस्तक्षेप के रूप में कुछ सारपूर्ण परिणाम निकले। सरकार ने किसानों की शिकायतों की ओर ध्यान दिया। परंतु बंगाल और दक्षिण के किसानों ने जो कुछ भी किया वह उच्च वर्गीय दबाव गुटों के परिष्कृत दाव पेचों के नियमों के विरुद्ध था।)

ब्रिटिश दबाव गुटों की भारतीयों की तुलना में निर्णय अधिकारियों पर सामाजिक दबाव डालकर उन्हें प्रभावित करने की क्षमता न केवल अधिक थी, बल्कि उन्हें और भी सुविधाएं मिली हुई थी। ब्रिटेन में सरकारी अधिकारियों के साथ उनके सीधे संपर्क निर्णायक सिद्ध हुए। 1875-79 की अवधि में भारत मंत्री द्वारा मेनचेस्टर के माल पर आयात शुल्क हटाने के लिए किए गए हस्तक्षेप (और बाद में भारतीय सूती वस्त्रों का मूल्य

मेनचेस्टर के मूल्य के बराबर करने के उद्देश्य से उन पर उत्पादन शुल्क लगाकर किए गए हस्तक्षेप) ने पक्षपात के नाटकीय प्रदर्शन के रूप में जनसाधारण का ध्यान आकर्षित किया। अठारहवीं शताब्दी के सातवें दशक में सूती वस्त्रों और जूट के माल पर निर्यात शुल्कों में कमी करने के प्रश्न पर इंडिया आफिश का हस्तक्षेप कम नाटकीय होते हुए भी कम प्रभावोत्पादक नहीं था। प्रतियोगी भारतीय गुटों की तुलना में ब्रिटिश हित बढ़ गुटों की सुमंगलित कार्यवाही की सामर्थ्य काफी अधिक थी। भारतीय गुटों की असमर्थता का कारण अनुभव की कमी और नए प्रकार से साव्यीय के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रपंचपूर्ण कला का अभाव भी था। ब्रिटिश हितवद्ध गुटों की इस श्रेष्ठता से इसकी सफलता का आंशिक (आंशिक इसलिए कि और भी अधिक महत्वपूर्ण कारण थे) स्पष्टीकरण हो जाता है। उदाहरण के लिए, काटन सप्टाई एमोसिएशन तथा बागान मालिक संघों को 1862 में भूमि संबंधी नियमों में परिवर्तन करवाने में सफलता मिली थी। डंडी चेंबर आफ कामर्स जो 1869 में जूट के तैयार माल पर आयात शुल्क हटवाना चाहता था, 1870 में यह उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सका। उन्नीसवीं शताब्दी के पाचवें दशक में निजी पूंजी लगाने वालों को रेलों में पूंजी लगाने पर चाहे लाभ हो या न हो, राज्य से निश्चित ब्याज की गारंटी पाने में सफलता अवश्य मिली थी। मेनचेस्टर के सूती वस्त्र उत्पादकों को उनके माल पर लगने वाले आयात शुल्क में 1862 और 1863 में कमी करवाने में, और फिर 1869 में इसे पूरी तरह से हटवाने में सफलता मिली।<sup>67</sup> 1870 में बंगाल में जूट मिलों के मालिक जिनमें अधिकांश स्कॉटलैंड निवासी थे, डंडी चेंबर आफ कामर्स से पराजित हो गए। (यह स्मरणीय है कि इनमें प्रतियोगिता मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बाजारों में थी।) शोरे पर निर्यात शुल्क में कमी करवा पाने के लिए इसके उत्पादकों और निर्यातकों को पांच वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था। (हालांकि शोरे का व्यापार तो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो रहा था, क्योंकि यूरोप में शोरे के कृत्रिम उत्पादन तकनीक ने इसके पुनर्निर्यात व्यापार को नष्ट कर दिया था।) परंतु अधिकांश मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया स्वोकारात्मक और अविलंब होती थी। सरकार को प्रभावित करने में मेनचेस्टर की सफलता ने तो इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया है, परंतु भारत में ब्रिटिश हितवद्ध गुट कम प्रभावशाली नहीं थे। कुछ निर्णयों को प्रभावित करने में बंगाल चेंबर आफ कामर्स की सफलता का रेकार्ड आश्चर्यजनक है। अप्रैल, 1859 में चेंबर ने ऊंचे टैरिफ शुल्कों पर विरोध प्रकट किया (टैरिफ शुल्क सैन्य विद्रोह के कारण असाधारण सरकारी खर्चों का परिणाम थे) और फरवरी, 1860 में विल्सन ने अनेक निर्यात शुल्क (जूट, तन, फ्लैक्स, खाल, ऊन आदि पर निर्यात शुल्क) हटा दिए।<sup>68</sup> अगस्त, 1860 में मेनचेस्टर, बंबई तथा मद्रास के चेंबर आफ कामर्स के समर्थन पर बंगाल चेंबर आफ कामर्स ने सीमा शुल्क मूल्यांकन में संशोधन की मांग की और अक्टूबर, 1860 में सरकार ने मूल्यांकन में संशोधन करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी जिसका एक सदस्य बंगाल चेंबर का प्रतिनिधि भी था।<sup>69</sup> फरवरी 1861 में बंगाल चेंबर ने शोरे के निर्यातकर्ताओं की इस मांग का समर्थन किया कि निर्यात शुल्क में कमी की जानी चाहिए और

मार्च, 1865 में यह कमी (दो रुपये प्रति मन से एक रुपया प्रति मन) कर दी गई।<sup>70</sup> अप्रैल, 1865 में बंगाल चेंबर आफ कामर्स ने ट्रैवीलियन द्वारा प्रस्तावित चाय, कहवा, जूट खाल, ऊन आदि पर नए आयात शुल्कों की निंदा की। मई, 1865 में भारत मंत्री ने इन शुल्कों के संबंध में स्वीकृति देने से इकार कर दिया और जून में भारत सरकार ने इन्हें निरस्त (रिपील) कर दिया।<sup>71</sup> फरवरी, 1866 में बंगाल चेंबर ने शोरे पर निर्यात शुल्क में और अधिक कमी करने की माग की और उसी वर्ष इसमें और अधिक कमी कर दी गई (एक रुपये प्रति मन के स्थान पर मूल्यानुसार 3 प्रतिशत)।<sup>72</sup> नवंबर, 1867 में चेंबर ने सीमा शुल्क मूल्यांकन में और विशेष रूप से सूती वस्तुओं के बारे में संशोधन चाहा और फरवरी 1868 में मूल्यांकन में संशोधन करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई (सूती वस्त्रों के मूल्यांकन में 15 प्रतिशत की कमी कर दी गई)।<sup>73</sup> दो मामलों में बंगाल चेंबर आफ कामर्स को उतनी अधिक सफलता नहीं मिली। मार्च, 1867 में चेंबर ने छाद्यान्त व्यापारियों के निर्यात शुल्क में कमी के लिए चलाए गए आंदोलन का समर्थन किया,<sup>74</sup> परंतु जनवरी, 1873 तक गेहूं पर शुल्क हटाया नहीं गया। इसके अलावा चेंबर द्वारा प्रत्यक्ष करों का विरोध एक हारे हुए मामले की बकालत थी, क्योंकि सरकार आय के एक बड़े सभावित स्रोत को पूरी तरह से छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी।<sup>75</sup>

यद्यपि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील ब्रिटिश और भारतीय दबाव गुटों में से किसी का भी परिणाम पर पूरा नियंत्रण नहीं था, फिर भी कुल मिलाकर ब्रिटिश हितवद्ध गुटों को अक्सर थोड़े समय ही में सफलता मिल जाती थी। यह हम पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उक्त कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि ब्रिटिश दबाव गुट जो चाहते थे, सदैव करवा ही लेते थे। आखिरकार सरकार के सामने भी महत्वपूर्ण सीमाएं थी। ब्रिटिश हितवद्ध गुटों द्वारा की जाने वाली मांगों के अलावा स्वयं व्यवस्था की मांगें भी तो थी। साम्राज्यवादी व्यवस्था को भी तो बनाए रखना आवश्यक था। उसकी वैधता और सुरक्षा, उसके वित्तीय सामर्थ्य और अपने आपको बनाए रख सकने की क्षमता को संकट में नहीं डाला जा सकता था। अतएव व्यवस्था की आवश्यकताओं से विविध बंधन उत्पन्न हुए थे। एक तो करों में रियायत, सीमा शुल्कों के निरस्तीकरण, आयकर की समाप्ति आदि की माग, ब्रिटिश हितों के द्वारा कितने ही जोरदार शब्दों में और आग्रहपूर्ण ढंग से क्यों न उठाई गई हो, सरकार इन पर संपूर्ण वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर ही विचार कर सकती थी। यदि सरकार के लिए संभव होता था तो रियायतें दी जाती थीं, अन्यथा चेंबर आफ कामर्स तथा वेतन भोगियों के लिए अप्रिय आयकर के मामले में सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं था। इस विषय पर अथवा सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क के मामले में चेंबर आफ कामर्स को सरकार के नकारात्मक उत्तर का सारांश यह था कि सरकार के लिए यदि इन करों को हटा सकना संभव होगा तो इन्हें हटा दिया जाएगा, परंतु सरकार ऐसा कर पाने में असमर्थ है। इस प्रकार के वादे किए गए कि जैसे ही मौका मिलेगा, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। परंतु दबाव गुटों को इससे पूरा संतोष नहीं हुआ। व्यापारी ही नहीं, प्रत्येक करदाता अपने ही जीवन काल में राहत चाहता था, जबकि सरकार जो अपनी

वित्तीय स्थिरता को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, धीमी प्रगति से संतुष्ट थी (उदाहरणार्थ, धीरे-धीरे प्रगति से ही लगभग पूर्ण रूप से अबाध व्यापार 1882 में संभव हो सका)। परंतु जिसे हम संबद्ध अवधि कह सकते हैं, वह आखिरकार सरकार के लिए भी अधिक थी।

द्वितीय सरकार जनसाधारण में अपने विषय में प्रचलित धारणाओं के बारे में बिल्कुल उदासीन नहीं थी। वार्टन फ़ेरे ने सरकार को जनसाधारण की भावना समझने की सलाह दी थी। मेयो ने भी देखा था कि भारतीयों में वित्तीय मामलों के बारे में काफी चेतना आ रही है। और तो और परंपरागत रूप से शांत मद्रास में (राज बोर्ड आफ रेवेन्यू) को यह लगने लगा था कि 'प्रजा में से अधिकाधिक लोग सरकार के निर्णयों का सूक्ष्म परीक्षण करने के अलावा उस पर काफी समझदारी के साथ बहस भी करने लगे हैं।' <sup>16</sup> वित्तीय मंकाट के समय विल्सन ने ब्रिटिश फर्मों के द्वारा यूरोप के महान औद्योगिक देशों को जूट, कपास आदि कच्चे पदार्थों के निर्यात पर शुल्क हटाने का प्रतिवाद किया था (1860)। लैंग ने बड़े ही उत्साह के साथ मूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में कमी की न्यायोचित ठहराया था (1861-1862)। इन दोनों उदाहरणों से यह बात जाहिर होती है कि सदस्य केवल अपने प्रत्यक्ष श्रोताओं अर्थात् विधान परिषद के सरकारी और आज्ञापरायण मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों को ही संबोधित नहीं करते थे। ये वस्तुतः ब्रिटिश हितवद्ध गुटों को दी जाने वाली रियायतों को जनसाधारण के सामने न्यायोचित ठहराने के प्रयत्न थे। ट्रैवीलियन के अनुसार 'सरकार में लोगों की आस्था के लिए उसकी ख्याति' बनाए रखना उपयोगी था। <sup>17</sup> वायसरॉयों और सदस्यों के बीच पत्र व्यवहार में इस बात के अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि सरकार इस बात का ध्यान रखती थी कि जनसाधारण उसके बारे में क्या सोचता है। उन सभी निर्णयों पर जो लोकप्रिय नहीं होते थे अथवा उस सूचना पर जिस पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती थी व्यक्तिगत पत्र व्यवहार में विचार विमर्श होता था। आयात शुल्कों में कमी के लिए बूड का आग्रह और विशेष रूप से उसकी भारतीय मूती वस्त्रों के बारे में शुल्क योजना जिसका उद्देश्य भारतीय माल का मूल्य ब्रिटिश मूती वस्त्रों के मूल्य के बराबर करना था (भारतीय मूती वस्त्रों पर उत्पादक शुल्क अथवा भारत में मूल तैयार करने वाली मिलों पर विशिष्ट कर) केवल एलिगन और वार्टन फ़ेरे को छोड़कर सभी के लिए गोपनीय थी। <sup>18</sup> देशी जुलाहा विषयक कागजात (उदाहरणार्थ घरेलू वस्त्र उद्योग के विषय में ट्रैवीलियन द्वारा एकत्रित सूचना आगे देलिये) को सीमित वितरण के लिए गोपनीयता के उद्देश्य से उतनी ही सावधानी के साथ छपा गया था जितनी वजह छापने के समय अपनाई जाती है। ट्रैवीलियन ने बूड को यह विश्वास दिलाया कि गवर्नर जनरल की परिषद और इंडिया आफिस को देने के लिए दर्जन से भी कम प्रतियां छापी गई हैं और इनके अतिरिक्त ट्रंमंड जोर भारत में कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें देख भी नहीं सकेगा। <sup>19</sup> और भी 1862 में स्थाई बंदोस्त सानू करने के संबंध में व्यापक रूप से ज्ञात सरकारी फैसले को बदलने का निर्णय फ्रेंचवॉन, आरगाइल, लारेंस तथा मेयो ने अपने गोपनीय पत्र व्यवहार में विचार विमर्श द्वारा किया था; और 1871 तक नई नीति को मार्गजनिन रूप से

स्वीकार नहीं किया गया था।<sup>80</sup> जनता की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार की चिंता के ये कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि चार्ल्स बुड के साथ ट्रेवीलियन के निजी पत्र व्यवहार<sup>81</sup> से स्पष्ट है सरकार की यह चिंता सैन्य विद्रोह के बाद के वर्षों में अधिक थी। बाद में भी यह चिंता सरकार की वित्तीय नीति पर जिसका अधिकाधिक आलोचनात्मक दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षण होने लगा था प्रतिवध का कार्य करती रही।

एक तीसरे प्रकार की सीमा इस तथ्य से निर्धारित होती है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साम्राज्य को एक उपव्यवस्था के रूप में विश्वव्यापी साम्राज्य का अंशमात्र समझ लिया था और भारत सरकार से साम्राज्यिक हितों की पूर्ति के लिए त्याग का आग्रह किया गया था। अतः इस उपव्यवस्था ने अपने अल्प स्रोतों के मुकाबले की गई भारी मांगों से अपने आपको बचाने का यथासंभव प्रयत्न किया। उदाहरणार्थ ब्रिटिश सेना विभाग (वार आफिस) तथा नौ सेना विभाग (एडमिरल्टी) ने भारत सरकार पर भारी खर्च थोप दिए थे। भारत सरकार ने उन्हें कम करवाने अथवा उनसे पूरी तरह बचने का प्रयास किया था। प्रतिरक्षा मंत्री कार्डवेल का तर्क था कि भारत से ऐसी ब्रिटिश सेना का खर्च वसूल करना न्यायोचित है जिसे रिजर्व माना जा सकता है और आपात्काल में भारत सरकार जिसका प्रयोग खुद कर सकती है। सेना विभाग ने भारत के बाहर ब्रिटिश सेना के अभियानों पर होने वाले व्यय को भारत और ब्रिटेन के बीच में असमान रूप से बांटा और न्यायोचित भी ठहराया।<sup>82</sup> आरगाइल ने यह स्वीकार किया कि भारत पर लादे गए खर्चों में कुछ तो वास्तव में अत्यधिक है। फिर भी, उनसे दृढ़तापूर्वक कहा कि युद्ध संबंधी खर्चों का मामला केवल भारतीय न होकर साम्राज्यिक है और कभी भी इस बारे में निर्णय केवल भारतीय आवश्यकताओं को आधार मानकर नहीं हो सकता।<sup>83</sup> भारत सरकार इंडिया आफिस के माध्यम से सेना विभाग (वार आफिस) के साथ बातचीत द्वारा इस उगाही में कमी नहीं करवा सकी। न्याय अथवा ईमानदारी की अस्वीकृति के प्रति लारेंस ने विरोध किया और मेयो ने आशंका व्यक्त की थी कि 'यहां पर (भारत में) ऐसा असंतोष उत्पन्न हो सकता है जिसे शांत कर पाना कठिन होगा।' परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।<sup>84</sup> भारत सरकार को हिंद महासागर में सामान्य नौ सैनिक प्रतिरक्षा के लिए मनमाने ढंग से निर्धारित राशि ब्रिटेन के नौ सेना विभाग को अदा करनी होती थी। उसने इस स्थिति का दृढ़तापूर्वक विरोध प्रकट करते हुए मामले को उठाया। लारेंस ने लिखा था कि 'भेरा विचार है कि यह ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वह (इंग्लैंड) वाणिज्य से मिलने वाले लाभों के बदले में निवाहता है...'। मेयो ने इस व्यवस्था को बहुत स्पष्ट व संक्षिप्त भाषा में 'एक अत्यधिक तज्ज्ञानक डकैती का कार्य' कहा।<sup>85</sup> भारत सरकार के हितों की रक्षा के ये तथा कुछ अन्य दृष्टांत कभी-कभी भारत के संरक्षकों की निष्पक्षता एवं महानता के उदाहरण के तौर पर पेश किए जाते हैं। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, भारत सरकार के अधिकारियों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे अपनी सरकार की आय पर की जाने वाली बाहरी मांगों में कमी करवाने का प्रयत्न करें (यद्यपि इस मामले में वे असफल रहे)। प्रांतीय सरकारों तथा प्रशासनिक विभागों का भी ठीक यही रवैया था जो केंद्रीय

(या उच्चतम) सरकार के साधनों से यथासंभव बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते थे।<sup>86</sup> उपव्यवस्था को उसके साधनों से वंचित करने पर उसकी प्रतिक्रिया का सामान्य रूप यही होना था।

वित्तीय सामर्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता, जनसाधारण द्वारा सरकारी नीतियों की छानबीन की स्थिति में नेकनीयती की ख्याति सुरक्षित रखने की जरूरत और अपने साधन-स्रोतों में दूसरों का हस्तक्षेप रोकने की आवश्यकता जैसी बुनियादी जरूरतों के अलावा कुछ अन्य सगत और असंगत दोनों ही प्रकार के घटक थे जिनसे ब्रिटेन और ब्रिटिश नागरिकों के हितों को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के निर्णय निर्धारित होते थे।

पहले हम असंगत तत्वों पर विचार करेंगे। हम यह तर्क दे चुके हैं कि निर्णय अधिकारियों तक अपनी सामाजिक पहुंच और उन पर सामाजिक दबाव डाल सकने की सामर्थ्य के कारण ब्रिटिश हितवर्ध गुटों के लिए शासकों की सहानुभूति पाना सहज था। परंतु यदि उपर्युक्त बात में सचाई है तो यह भी सत्य है कि सरकार के ऊंचे अधिकारियों में ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनकी कलकत्ते के अंग्रेज जूट-व्यापारियों अथवा बंबई के चमड़ा-व्यापारियों में विशेष दिलचस्पी नहीं थी और वे इनसे कुछ दूर ही रहना चाहते थे। मेयो जैसे अभिजातवर्गीय लोग भारत में रहने वाले गैर-सरकारी यूरोपियों को हेय दृष्टि से देखते थे। व्यापार एवं उद्योगों में लगे हुए यूरोपीय इनी श्रेणी में आते थे। मेयो ने इनके विषय में लिखा है कि 'ये लोग यहाँ पर काले लोगों से यथामभव रूपमा एँठने के लिए आते हैं...मुझे इस वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और इन्हें यह मालूम है।' <sup>87</sup> ऐसा विश्वास किया जाता है कि सर पार्लमं ट्वेन्टीलिथन और भारत में निवास करने वाले ब्रिटिश व्यापारी वर्ग में पारस्परिक सहानुभूति का अभाव था। वित्त सदस्यों में केवल विल्सन ही ऐसा था जो टोप-उत्पादन बहुत मामूली, ना व्यवसाय कर चुका था। हम व्यवसाय को उन दिनों कितने हीन भाव से देखा जाता था यह उस समय के व्यर्थों तथा राजनीतिक कार्टूनों में दिग्ललाई पड़ता है। (इस पुस्तक में हम प्रकार के दो कार्टून सम्मिलित किए गए हैं।) एलिंग ने व्यंग्य का पुट देकर लिखा कि प्रथम दो वित्त-सदस्य जेम्स रिड्मन और सेमुअल लैंग (त्रिगुण कुछ संबंध रैन-उत्तमों से था), मध्यवर्गीय सटोरिये व्यवसायी समाज के थे।<sup>88</sup> ज्ञान सारंग के अनिश्चित सभी वाचस्पत्य अभिजात वर्गीय थे और यह नियम सा हो था कि दस वर्ग के लोग व्यापारियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। फिर भी, भारत में ब्रिटिश व्यापार तथा उद्यम की उपयोगिता एवं महत्त्व के विषय में उनके विचार सामान्य ज्ञान पर आधारित होते थे। भारतीय सिविन सेवा अपने श्रेष्ठ वर्गीय गौरव के वास्तव, अपनी परंपराओं और सामाजिक रचना की दृष्टि से ब्रिटेन सेवा की भांति ऊँची धेनी में नहीं आती थी। भारतीय सिविन सेवा के अनेक लोग, जिन्हें जी० ओ० ट्वेन्टीलिथन कास्टीमन माना जाता था, मंत्रवतः व्यापार को अभिजात वर्ग में गुनगुन देन दृष्टि से नहीं देखते थे। हिंदी भी मामूली में ऐसा नहीं लगता कि मेकेंटेरिफ्ट अथवा रूडिआ स्टारिम में पूराबद्ध ज्ञान प्रबल था कि अधिपतिय व्यापारियों को अस्वादिता



वृद्धा की भांति संदेह की दृष्टि से देखते थे और यह समझते थे कि वे सभी उससे अप्रत्याशित ढंग से अवैध पक्षपात पाने के लिए कोई पड्यंत्र कर रहे हैं।<sup>89</sup> महज अधिकारियों के दंभ के कारण व्यापारी वर्ग कभी हतोत्साहित नहीं हुआ और यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय भावना की अपील के (हमारे सम्राट के मुकुट का सबसे सुंदर रत्न... यह दूर तक विस्तृत साम्राज्य... सूर्यास्त कभी नहीं होता... आदि के) आश्चर्यजनक परिणाम निकले हैं।

नीकरशाही की अकर्मण्यता, सरकारी मशीनरी की शाही धीमी गति, विभागीय दृष्टिकोण की पवित्रता और एक साधारण सरकारी कर्मचारी में इस पवित्रता से हटने की अनिच्छा उन व्यापारियों के रास्ते में बाधाएं थी जो अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यावधि की समाप्ति जैसी महत्वपूर्ण घटना के साथ सैन्य विद्रोह जैसे संकट का संयोग हो जाने पर ही सरकार अपनी परंपरागत लीक से हट सकी। छठें दशक में विल्सन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा निर्धारित नीतियां कार्यान्वित की गईं और सर्वोच्च नीति निर्धारक अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारियों तक, सभी के लिए, नीति-विषयक कुछ धारणाएं लगभग निर्विवाद सूक्तियां बन गईं। ये धारणाएं जो सामूहिक रूप से विभागीय दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध थीं, एक विशेष प्रकार के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित थीं। इस विषय की विवेचना आगे की गई है।

उपर्युक्त सीमाओं के भीतर, किसी भी हितवद्ध गुट द्वारा डाला जाने वाला दबाव निर्णायक होता था। गुट की सफलता इस बात पर निर्भर होती थी कि उपर्युक्त रीतियों को कितने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया गया है और क्या सरकार को उसकी समग्र वित्तीय स्थिति, (संतुलित बजट अथवा शोधनक्षमता को उस समय असाधारण महत्व दिया जाता था), ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों की नीति, विभागीय दृष्टिकोण आदि के द्वारा, निर्धारित सीमाओं तक, दबाया जा सका है या नहीं। सभी हितवद्ध गुट सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में समान रूप से सफल नहीं हो पाते थे। यह कहा जा सकता है कि वर्मा के अंग्रेज खाद्यान्न व्यापारियों (वे 1867 में खाद्यान्नों पर शुल्क में कमी करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें 1873 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी) या भारत से इंग्लैंड को शोरे का निर्यात फिर वहां से उसका पुनर्निर्यात करने वाली ब्रिटिश फर्मों (शुल्क में कमी के लिए इनका आंदोलन 1860 में प्रारंभ हुआ था और उसे पांच वर्ष बाद भी आंशिक सफलता ही मिली) की तुलना में डडी या मैनचेस्टर के हित अधिक प्रभावशाली थे। खाद्यान्न अथवा शोरे का व्यापार करने वाली फर्में छोटी थीं और इन्हें थोड़ा सा ही लाभ प्राप्त था। ये जो रियायतें चाहते थे उन्हें ये चेंबर आफ कामर्स के समर्थन से ही प्राप्त कर सके।

अतः निर्णयकर्ता अधिकारी सभी ब्रिटिश हितवद्ध गुटों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे। यहां पर इस बात पर जोर देना सार्थक होगा कि हर समय और हर राजवित्तीय (फिस्कल) मामले पर सभी ब्रिटिश दबाव गुटों के हित पूरी तरह से एक से नहीं थे। प्रत्येक गुट लगभग सभी लोगों का समर्थन पाने के लिए अपने वर्गीय हित को

राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत करता था। किन्तु कम से कम, अल्पकालीन दृष्टिकोण से, ऐसे दावों को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करना या हितों की एकरूपता का अनुमान लगाना बेमानी होगा। यह उस समय स्पष्ट हो जाता है जब हम उदाहरण के लिए डंडी के जूट उत्पादकों (जिन्होंने जूट-माल पर आयात कर को हटाने की मांग की थी और जो पूरी भी हुई थी), और बंगाल के जूट मिल मालिकों, मैनचेस्टर के सूती वस्त्र उत्पादकों और वस्त्र उद्योग में काम आने वाली मशीनों के ब्रिटिश निर्यात कर्ताओं अथवा ब्रिटिश व्यापारियों की प्रशासन व्यय कम करने की मांग (जिससे कर भार में कमी हो) और नौकरशाही द्वारा इसके विरोध पर विचार करते हैं। हम अगले पृष्ठों में देखेंगे कि किस प्रकार ये परस्पर विरोधी दवाव, स्वार्थों का सम्मिलन और सामंजस्य तथा जनमत और निर्णयकर्ता अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए प्रतियोगी अभियान एक अत्यधिक पेचीदा तस्वीर पेश करते हैं। जो लोग हितों में एकरूपता मानकर चलते हैं वे उपर्युक्त जटिलता की उपेक्षा करते हैं। साथ ही वे निर्णय प्रक्रिया के असंगत तत्वों को पर्याप्त महत्व देने में असमर्थ रहते हैं और निर्णय अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंधों को हल्का मान लेते हैं।

हम यह तर्क दे चुके हैं कि (क) लोक वित्त संबंधी मामलों पर निर्णय प्रक्रिया में अनेक हितवद्ध गुट भाग लेते थे और प्रत्येक गुट अपने लिए अधिक से अधिक अनुकूल (उदाहरणार्थ, पूंजी लगाने वाले राज्य द्वारा व्याज की गारंटी के विषय में आश्वासन; व्यापारी सड़कों, बंदरगाहों तथा दूसरी आर्थिक उपरिबन्ध पूंजी का विकास; बागानों तथा खानों के मालिक भूमि संबंधी अनुकूल अधिनियम पारित करवाना; शहर के पेशेवर लोग सरकारी सहायता पर आधारित शिक्षा; व्यापारी और भूस्वामी विधान-परिपद में संस्थागत प्रतिनिधित्व के रूप में निर्णयकर्ता अधिकारियों तक पहुँचना, आदि चाहते थे), अथवा कम से कम प्रतिकूल निर्णयों के लिए प्रयत्न करता था (उदाहरणार्थ, भूस्वामी कृषि और आय कर पर कर में कमी, व्यापारी व्यापारिक कर जैसे—लाइसेंस कर में कमी, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता टैरिफ शुल्कों में कमी, बागान मालिक भूमि संबंधी प्रतिबंधात्मक कानूनों में ढील और सामान्य करदाता सरकारी खर्च में कमी चाहते थे)। (ख) दवाव गुटों और निर्णय अधिकारियों की परस्परक्रिया के परिणाम विभिन्न प्रतिस्पर्धी, सहयोगी और विरोधी गुटों द्वारा डाले गए परस्पर विरोधी दवावों, दवाव गुट विशेष और सरकार के बीच विशिष्ट संबंध से अलग कतिपय प्रतिबंधों तथा कुछ असंगत तत्वों जैसे—सामाजिक दम, स्थिर विचार और व्यक्तिगत निर्णयकर्ता अधिकारों की निजी प्रवृत्तियों पर निर्भर होते थे। (ग) अतः परिणाम की सही-सही भविष्यवाणी निर्णय-

अनुकूल निर्णय पाने की संभावना ब्रिटिश हितवद्ध गुटों (जिन्हें अन्य अच्छी मुविधाओं के अलावा शासन-तंत्र के पिरामिड के शीर्षस्थ इंडिया आफिस तथा संसद के साथ सीधे संबंधों, निर्णय अधिकारियों तक सामाजिक पहुँच और सामाजिक दवाव डाल सकने की सामर्थ्य, लाभोद्योग की कला से परिचय, तथा गुट के पारस्परिक स्तर के अलावा गुटके

भीतरी स्तर पर अधिक सामंजस्य के लाभ प्राप्त थे) के बारे में अधिक होती थी। दवाव गुटों की राजनीति परिष्कृत व जटिल थी और इस दृष्टि से उपर्युक्त कथन की बोझिल सत्यता दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस मान्यता के आधार पर कि सरकार के उद्देश्य महान थे (बुरे उद्देश्य की मान्यता भी संभव है), वजट भाषणों मारल एंड मँटीरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, संसद की वार्षिक वित्तीय समीक्षा, आदि में नीति विषयक वक्तव्यों से नीति का स्वरूप तय करना अधिक सरल और शायद अधिक सुविधाजनक होगा। आयोजित कार्यवाही के साथ संपादित कार्यवाही के लिए नीति शब्द के प्रयोग से नीति विषयक धारणा और व्यावहारिक नीति में भेद कर पाना कठिन हो जाता है। परंतु वास्तव में नीति की ठीक रूपरेखा उसी समय निर्धारित हो सकती है जब हम किसी महान उद्देश्य की मान्यता को स्वीकार न करें और अलग-अलग बिखरे हुए वास्तविक निर्णयों और कार्यों के आधार पर एक ढांचा तैयार कर लें। इसके लिए हमें निर्णयों का अध्ययन उनके प्रासंगिक आधार पर करना होगा और निर्णयकर्ता अधिकारियों तथा दूसरे लोगों के बीच पहली दृष्टि में थकाऊ और गौण लगने वाली उस परस्परक्रिया की ओर ध्यान देना होगा जिसके द्वारा निर्णय होते हैं या यों कहिए कि नीति का स्वरूप निश्चित होता है। जो लोग नीति संबंधी धारणाओं पर ही ध्यान देते हैं वे इस तथ्य को भुला बैठते हैं कि द्वितीय गुटों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ-साथ इस बात से भी इकार नहीं किया जा सकता कि नीतियों की अविच्छिन्नता तथा निर्णयकर्ता अधिकारियों की प्रतिप्रिया के स्वरूप में स्थिरता की पूरी व्याख्या उस समय तक नहीं हो सकती जब तक हम इन अधिकारियों की नीति विषयक धारणाओं, इनके द्वारा आवतन प्रयोग में लाए जाने वाले राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, इसके विचार करने के ढंग और दृष्टिकोण तथा संपूर्ण साम्राज्य की विचारधारा पर ध्यान नहीं दें। यहां हम अपने को साम्राज्यिक विचारधारा के उस अंश तक ही सीमित रखेंगे जो वित्तीय नीति के निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष रूप से सगत है।

जिन अर्थशास्त्रियों ने भारत में वित्तीय नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है उनमें जेम्स विल्सन अग्रणी है जो इस देश का प्रथम वित्त सदस्य था, आज उसे प्रधानतः लंदन से प्रकाशित होने वाले दि इकानोमिस्ट के संस्थापक-संपादक के रूप में स्मरण किया जाता है। अर्थशास्त्र की विविध पुस्तकों के लेखक के रूप में उसकी साधारण ख्याति है। उसके ही समकालीन लोगों में से कार्ल मार्क्स ने उसे ऊंचे स्तर का सरकारी अर्थशास्त्री कहकर उसकी स्थिति का सही-सही मूल्यांकन किया है।<sup>10</sup> जिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें से शुपीटर तथा केनक्रास भी हैं, इसकी रचनाओं की ओर ध्यान दिया है उन्होंने इसके आर्थिक विश्लेषण में विशेष मौलिकता नहीं पाई है।<sup>11</sup> उसका अर्थविज्ञान में योगदान नाममात्र का था, परंतु जैसा कि उसका दामाद वाल्टर बेजहाट उसके विषय में कहता है वह एक महान विश्वासोत्पादक अर्थात् एक प्रतिभाशाली प्रचारक था।<sup>12</sup> इस क्षमता के साथ-साथ राजनीतिक अर्थविज्ञान के व्यावहारिक महत्व के विषय में अपनी समझ के कारण अनेक दुरुह सिद्धांतशास्त्रियों से वह आगे निकल गया था। (उदाहरणार्थ,

सुरक्षा ही थी। यदि शस्त्र का बार-बार सहारा लिए बिना भी अधिकांश शासित व्यक्तियों की स्वीकृति और थोड़े से लोगों का सक्रिय सहयोग पा सकना संभव रहा हो तब भी ब्रिटिश शासन का बुनियादी आधार सेना ही थी। सैनिक व्यय को न्यूनतम रखना एक ऐसा आदर्श था जिसका पालन इंग्लैंड में तो हो सकता था परंतु भारत में कृपणता की नीति का पालन करते हुए सेना को कमजोर बना देना भूल थी। भारत में एक बड़ी यूरोपीय सेना रखने की आवश्यकता सैन्य विद्रोह के अनुभव से अच्छी तरह स्पष्ट हो गई थी। इस प्रकार की सेना का खर्च भारतीय करदाता पर लादा जा सकता था जिसे भारत के बाहर रिजर्व सेना के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। यदि आवश्यकता होती थी तो भारतीय सेना दूसरे स्थानों पर भेजे जाने के लिए उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार की व्यवस्था के राजनीतिक लाभ बहुत अधिक थे। इससे इंग्लैंड एशिया और अफ्रीका में अपने शत्रुओं को डराने में समर्थ हो गया था। साथ ही, इससे इंग्लैंड में करदाताओं को राहत भी मिल सकी थी। (अध्याय 3, देखिए)। जब मैथो ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सैनिक व्यय में कटौती का प्रस्ताव रखा था तो भारत मंत्री ने इस व्यवस्था के विशिष्ट स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि सैनिक व्यय का स्तर केवल भारत की तत्कालिक आवश्यकताओं के मंदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता।<sup>100</sup> सातवें दशक के उत्तरार्द्ध में प्रसिद्ध अंग्रेज उग्र राजनीतिज्ञ जोजफे (रिट्रेचमेट) ह्यूम के भतीजे कर्नल ह्यूम की अध्यक्षता में सैनिक वित्त आयोग ने सेना पर व्यय में भारी कमी की थी, परंतु इसका उद्देश्य मुख्य रूप से देशी भारतीय सेना के आकार को कम करना था जिससे इसके और भारत स्थित ब्रिटिश सेना के बीच सुरक्षित अनुपात रखा जा सके।<sup>101</sup>

द्वितीय, यह भी अनुभव किया गया कि भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य द्वारा दी जाने वाली गारंटी अथवा किसी अन्य रूप में आर्थिक सहायता देकर पूजी-निवेश को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। जिसे सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम कहा गया है उसका सबसे अधिक जाना-माना उदाहरण पूजी निवेशकों को व्याज गारंटी की संविदा के आधार पर भारतीय रेलों का निर्माण है। लगभग सभी पूजी निवेशक अंग्रेज थे। 1870 में 51,890 अंशधारियों में लगभग 0.6 प्रतिशत भारतीय थे और कुल पूजी निवेश में इनका भाग 1 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक था।<sup>102</sup> इस व्यवस्था के बारे में जो कुछ अन्यत्र (अध्याय 3 में) कहा गया है, हमें उसके बारे में यहाँ अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को रेलों के विकास का जो अनुभव हुआ उसने उसे अन्य देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था के बारे में सतर्क बना दिया। 5 प्रतिशत व्याज की सरकारी गारंटी के आधार पर 10 लाख पाँड की पूजी से मद्रास में स्थापित एक सिंचाई कंपनी एक उल्लेखनीय अपवाद थी। इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब मेनचेस्टर काटन स्प्लार्ड एसोसिएशन सरकार पर इन बातों के लिए दबाव डाल रहा था कि वह भारत में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की फासतू पूजी और निजी उद्यम को लोक निर्माण कार्य का विकास करने दे।<sup>103</sup> 1870 तक सरकार व्याज की गारंटी से हटने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक के प्रारम्भिक वर्षों में सरकार अपने न्यायोचित कार्यों का अतिक्रमण किए बिना व्यापारी को अविलंब सहायता देने के लिए तत्पर थी।<sup>104</sup> दशक की समाप्ति के आसपास

व्याज की गारंटी के दोषों से अवगत होकर, सरकार दावा कर रही थी कि निजी उद्यम के क्षेत्र में अगुआई करना प्रायः सरकार का कर्तव्य हो सकता है।<sup>107</sup> फिर भी इस प्रकार की भूमिका सरकार ने केवल चाय उद्योग में ही अदा की। अधिकांश प्रारंभिक लागत राज्य की थी और जोखिम भी उसी ने उठाया। जब यह उद्योग सुरक्षित दिखाई देने लगा तो इसे अंग्रेज वागान मालिकों ने ले लिया।<sup>108</sup> (सैन्य-विद्रोह से पहले की अवधि में लोहे व इस्पात उद्योग में इस प्रकार कुछ इक्के-दुक्के असफल प्रयास हुए थे)।<sup>109</sup> सब बातों को देखते हुए लगता है कि सरकार का भुकाव उद्यमी की भूमिका अदा करने के स्थान पर, परोक्ष रूप से व्यापारी को सहायता देने की ओर था।

यह अप्रत्यक्ष सहायता मुख्य रूप से आधारभूत आर्थिक उपरिव्यय पूँजी के विकास के रूप में थी। एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सरकार की इस भूमिका पर जे० एस० मिल ने जोर दिया है।<sup>110</sup> जेम्स विल्सन का विचार था कि कपास, जूट, ऊन तथा यूरोप के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार का प्रधान कर्तव्य लोक निर्माण कार्य तथा सड़कों का विकास करना था।<sup>111</sup> छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में कपास क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर था। रेलवे कंपनियों के प्रवर्तकों ने भी कपास का उत्पादन करने वाले जिलों तक रेल निर्माण के महत्व पर बल दिया। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा भारत मंत्री को अपने स्मरणपत्रों में काटन सप्लाई एसोसिएशन ने कच्चे पदार्थों के निर्यात में सुविधा की दृष्टि से लोक निर्माण कार्यों, सड़कों, बंदरगाहों आदि पर पूँजी निवेश में वृद्धि की माग की।<sup>112</sup> अमरीकी गृह युद्धकाल में कपास दुर्भिक्ष के कारण यह आग्रह अधिक जल्दुरी हो गया। परंतु मेनचेस्टर सकट जब गभीरतम स्थिति में था उस समय इंडिया आफिस का भारत सरकार को काफी जोरदार सुझाव था कि भारत में वाणिज्यिक उद्योगों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सिंचाई, कपास क्षेत्र में सड़कों अथवा अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय की मात्रा इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होनी चाहिए कि व्यय की पूरी राशि बाद में निकल आएगी।<sup>113</sup> 1863 से 1866 तक की अवधि में बंबई प्रेसीडेंसी को, जो कपास की प्रधान उत्पादक थी, लोक निर्माण पर कुल सामान्य पूँजी निवेशों का 24 प्रतिशत भाग मिला था, जबकि बंगाल प्रेसीडेंसी का भाग 17 प्रतिशत और मद्रास प्रेसीडेंसी का 13.9 प्रतिशत था। बंबई में 1863 से 1872 तक की अवधि में औसत सामान्य लोक निर्माण व्यय 79 रुपये प्रति वर्गमील था। पश्चिमोत्तर प्रांतों, बंगाल और मद्रास की राशियां क्रमशः 78 रुपये, 34 रुपये और 45 रुपये प्रति वर्गमील थी।<sup>114</sup> 1865 में अमरीका से कपास की पुनः आपूर्ति (सप्लाई) और उड़ीसा के दुर्भिक्ष के अनुभव के आधार पर बंबई प्रेसीडेंसी के साथ तरजीही सलूक और सिंचाई सुविधाओं की तुलना में भीतरी प्रदेश को रेलों से मिलाने वाली सड़कों को प्राथमिकता देने की नीति बदल दी गई। परंतु ब्रिटिश सरकार के अधिकारी अलाभकर लोक निर्माण कार्यों को सहायता देने के लिए अतिच्छुक् थे। उनका यह रवैया आर्थिक उपरिव्यय में सार्वजनिक पूँजी निवेश पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध बना रहा। अलाभकर लोक निर्माण कार्यों से तात्पर्य उन परियोजनाओं से था जिन पर व्यय की गई पूँजी का व्याज भी आय से पूरा नहीं हो पाता था (अध्याय 3)।

सुरक्षा ही थी। यदि शस्त्र का बार-बार सहारा लिए बिना भी अधिकांश शासित व्यक्तियों की स्वीकृति और थोड़े से लोगों का सक्रिय सहयोग पा सकना संभव रहा हो तब भी ब्रिटिश शासन का बुनियादी आधार सेना ही थी। सैनिक व्यय को न्यूनतम रखना एक ऐसा आदर्श था जिसका पालन इंग्लैंड में तो हो सकता था परंतु भारत में कृपणता की नीति का पालन करते हुए सेना को कमजोर बना देना भूल थी। भारत में एक बड़ी यूरोपीय सेना रखने की आवश्यकता सैन्य विद्रोह के अनुभव से अच्छी तरह स्पष्ट हो गई थी। इस प्रकार की सेना का खर्च भारतीय करदाता पर लादा जा सकता था जिसे भारत के बाहर रिजर्व सेना के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। यदि आवश्यकता होती थी तो भारतीय सेना दूसरे स्थानों पर भेजे जाने के लिए उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार की व्यवस्था के राजनीतिक लाभ बहुत अधिक थे। इससे इंग्लैंड एशिया और अफ्रीका में अपने शत्रुओं को डराने में समर्थ हो गया था। साथ ही, इससे इंग्लैंड में करदाताओं को राहत भी मिल सकी थी। (अध्याय 3, देखिए)। जब मैनो ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सैनिक व्यय में कटौती का प्रस्ताव रखा था तो भारत मंत्री ने इस व्यवस्था के विशिष्ट स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि सैनिक व्यय का स्तर केवल भारत की तात्कालिक आवश्यकताओं के मंदमं में निर्धारित नहीं किया जा सकता।<sup>102</sup> सातवें दशक के उत्तरार्द्ध में प्रसिद्ध अंग्रेज उग्र राजनीतिज्ञ जोजफ़े (रिट्टेंबेर्ग) ह्यूम के भतीजे कर्नल ह्यूम की अध्यक्षता में सैनिक वित्त आयोग ने सेना पर व्यय में भारी कमी की थी, परंतु इसका उद्देश्य मुख्य रूप से देशी भारतीय सेना के आकार को कम करना था जिससे इसके और भारत स्थित ब्रिटिश सेना के बीच सुरक्षित अनुपात रखा जा सके।<sup>103</sup>

द्वितीय, यह भी अनुभव किया गया कि भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य द्वारा दी जाने वाली गारंटी अथवा किसी अन्य रूप में आर्थिक सहायता देकर पूजी-निवेश को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। जिसे सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम कहा गया है उसका सबसे अधिक जाना-माना उदाहरण पूजी निवेशकों को व्याज गारंटी की संविदा के आधार पर भारतीय रेलों का निर्माण है। लगभग सभी पूजी निवेशक अंग्रेज थे। 1870 में 51,890 अशर्धारियों में लगभग 0.6 प्रतिशत भारतीय थे और कुल पूजी निवेश में इनका भाग 1 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक था।<sup>104</sup> इस व्यवस्था के बारे में जो कुछ अन्यत्र (अध्याय 3 में) कहा गया है, हमें उसके बारे में यहाँ अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को रेलों के विकास का जो अनुभव हुआ उसने उसे अन्य देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था के बारे में सतर्क बना दिया। 5 प्रतिशत व्याज की सरकारी गारंटी के आधार पर 10 लाख पौंड की पूजी से मद्रास में स्थापित एक सिचाई कंपनी एक उल्लेखनीय अपवाद थी। इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब मेनचेस्टर काटन सप्लाय एसोसिएशन सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि वह भारत में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की कालतू पूजी और निजी उद्यम को लोक निर्माण कार्य का विकास करने दे।<sup>105</sup> 1870 तक सरकार व्याज की गारंटी से हटने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में सरकार अपने न्यायोचित कार्यों का अतिप्रमण किए बिना व्यापारी को ज़रिअव सहायता देने के लिए तत्पर थी।<sup>106</sup> दशक की समाप्ति के आगपाव

ब्याज की गारंटी के दोषों से अवगत होकर, सरकार दावा कर रही थी कि निजी उद्यम के क्षेत्र में अगुआई करना प्रायः सरकार का कर्तव्य ही सकता है।<sup>107</sup> फिर भी इस प्रकार की भूमिका सरकार ने केवल चाय उद्योग में ही अदा की। अधिकांश प्रारंभिक लागत राज्य की थी और जोखिम भी उसी ने उठाया। जब यह उद्योग सुरक्षित दिखाई देने लगा तो इसे अंग्रेज वागान मालिकों ने ले लिया।<sup>108</sup> (सैन्य-चिद्रोह से पहले की अवधि में लोहे व इस्पात उद्योग में इस प्रकार कुछ इक्के-दुक्के असफल प्रयास हुए थे)।<sup>109</sup> सब बातों को देखते हुए लगता है कि सरकार का भुकाव उद्यमी की भूमिका अदा करने के स्थान पर, परोक्ष रूप से व्यापारी को सहायता देने की ओर था।

यह अप्रत्यक्ष सहायता मुख्य रूप से आधारभूत आर्थिक उपरिव्यय पूँजी के विकास के रूप में थी। एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सरकार की इस भूमिका पर जे० एस० मिल ने जोर दिया है।<sup>110</sup> जेम्स विल्सन का विचार था कि कपास, जूट, ऊन तथा यूरोप के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार का प्रधान कर्तव्य लोक निर्माण कार्य तथा सड़कों का विकास करना था।<sup>111</sup> छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में कपास क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर था। रेलवे कंपनियों के प्रवर्तकों ने भी कपास का उत्पादन करने वाले जिलों तक रेल निर्माण के महत्व पर बल दिया। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा भारत मंत्री को अपने स्मरणपत्रों में फाटन सप्लाइ एसोसिएशन ने कच्चे पदार्थों के निर्यात में सुविधा की दृष्टि से लोक निर्माण कार्यों, सड़कों, बंदरगाहों आदि पर पूँजी निवेश में वृद्धि की मांग की।<sup>112</sup> अमरीकी गृह युद्धकाल में कपास दुर्भिक्ष के कारण यह आग्रह अधिक ज़रूरी हो गया। परंतु मेनचेस्टर संकट जब गंभीरतम स्थिति में था उस समय इंडिया आफिस का भारत सरकार को काफी जोरदार सुझाव था कि भारत में वाणिज्यिक उद्योगों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सिचाई, कपास क्षेत्र में सड़कों अथवा अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय की मात्रा इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होनी चाहिए कि व्यय की पूरी राशि वाद में निकल आएगी।<sup>113</sup> 1863 से 1866 तक की अवधि में बंबई प्रेसीडेंसी को, जो कपास की प्रधान उत्पादक थी, लोक निर्माण पर कुल सामान्य पूँजी निवेशों का 24 प्रतिशत भाग मिला था, जबकि बंगाल प्रेसीडेंसी का भाग 17 प्रतिशत और मद्रास प्रेसीडेंसी का 13.9 प्रतिशत था। बंबई में 1863 से 1872 तक की अवधि में औसत सामान्य लोक निर्माण व्यय 79 रुपये प्रति वर्गमील था। पश्चिमोत्तर प्रांतों, बंगाल और मद्रास की राशिया क्रमशः 78 रुपये, 34 रुपये और 45 रुपये प्रति वर्गमील थी।<sup>114</sup> 1865 में अमरीका से कपास की पुनः आपूर्ति (सप्लाइ) और उड़ीसा के दुर्भिक्ष के अनुभव के आधार पर बंबई प्रेसीडेंसी के साथ तरजीही सलूक और सिचाई सुविधाओं की तुलना में भीतरी प्रदेश को रेलों से मिलाने वाली सड़कों को प्राथमिकता देने की नीति बदल दी गई। परंतु ब्रिटिश सरकार के अधिकारी अलाभकर लोक निर्माण कार्यों को सहायता देने के लिए अनिच्छुक थे। उनका यह रवैया आर्थिक उपरिव्यय में सार्वजनिक पूँजी निवेश पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध बना रहा। अलाभकर लोक निर्माण कार्यों से तात्पर्य उन परियोजनाओं से था जिन पर व्यय की गई पूँजी का ब्याज भी आय से पूरा नहीं हो पाता था (अध्याय 3)।

चतुर्थ, यह विश्वास किया जाता था कि भारत कच्चे पदार्थों के आपूर्ति कर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके इसके लिए सरकार को अपनी सामर्थ्य भर संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। कच्चे पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देना स्वदेशी साधनों को सुधारने का सर्वश्रेष्ठ उपाय था (विल्सन)। कृषि भारत का मुख्य उद्योग होना चाहिए (ट्रिवीलियन तथा उन कच्चे पदार्थों के बदले में, जिनमें भारत को विशिष्ट लाभ प्राप्त है, तैयार माल (यूरोप) का विनिमय (बगाल चेंबर आफ कामर्स) उपनिवेश तथा शासक देश के मध्य आदर्श श्रम विभाजन था।<sup>115</sup> विल्सन ने चाय तथा कढ़वे के साथ-साथ जो यूरोपीय मालिकों के वागानों की पैदावारें थीं, कच्ची कपास, जूट, सन, ऊन, खाल, लकड़ी आदि को निर्यात मुक्त से मुक्त रखकर भावी नीति के लिए दिशा निर्धारित की। इस प्रस्ताव से कि भारत की आर्थिक भूमिका कच्चे पदार्थों के आपूर्ति-कर्ता के रूप में ही थी, एक उपप्रस्ताव निकलता था कि भारत में कच्चे पदार्थों के दोहन के लिए आवश्यक पूंजीगत माल का आयात बिना किसी बाधा के होना चाहिए। 1845 और उसके बाद पानी के जहाजों के पेटों (हल) के लिए प्लेट लोहा, कृषि (मुख्य रूप से वागान कृषि के लिए), खनन रेल उपकरण के लिए मशीनें बिना किसी सीमा शुल्क के आयात की गईं। मेनचेस्टर में इसे भी शका की दृष्टि से देखा गया। वहां के उत्पादकों का मत था कि भारत सरकार इस देश में मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर गलती कर रही है, क्योंकि यहां का स्वाभाविक व्यवसाय तो कच्चे पदार्थों का उत्पादन ही है।<sup>116</sup> इस प्रस्ताव के साथ कि भारत की भूमिका ब्रिटेन को कच्चा पदार्थ देने की ही है, कुछ उन्माही व्यक्तियों ने एक अन्य उपप्रस्ताव जोड़ दिया। वह यह था कि ब्रिटेन को भारत का औपनिवेशीकरण कर डालना चाहिए। बेकफोल्ड की आर्ट्स आफ कालोनाइजेशन (औपनिवेशीकरण की कला 1849) ने ब्रिटेन से उत्तरी अमरीका और आस्ट्रेलिया को पूंजी तथा श्रम के देशांतरण की सुविधाएं देकर वहां की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की असीम संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। एडवर्ड वैंस्ट ने भी भारत में ऐसे ही औपनिवेशीकरण का समर्थन किया था। इस विषय पर उसकी पुस्तक का शीर्षक ही उसके कार्यक्रम को संक्षेप में बता देता है : ब्रिटिश भारत को प्रवास; समुक्त स्टॉक कंपनियों और संपन्न प्रवासियों के लिए लाभप्रद पूंजी निवेश के अवसर, उद्यमी और होशियार लोगों के लिए रोजगार, कपास, रेशम, चीनी, चावल, तंबाकू, नील तथा अन्य उष्णकटिबंधीय उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति; तैयार माल के लिए बढ़ती हुई मांग ... (1857)। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में इस औपनिवेशीकरण के विचार के कुछ प्रस्तावक थे। यह बहुत संभव है कि इससे वागान मालिकों द्वारा बेकार भूमि को पूर्ण स्वामित्व पट्टेदारी पर दिलाने की व्यवस्था करने के लिए भूमि संबंधी अधिनियमों में परिवर्तन संबंधी मामले को बल मिला हो। परंतु इस प्रकार की आशा व्यवहार में भ्रमपूर्ण सिद्ध हुई कि यहां पर यूरोप के लोग भारी संख्या में आकर बसेंगे। वैंस्ट का उस देश के विषय में अधिक ज्ञान ही नहीं था जहां पर वह चाहता था कि उसके देशवासी जाकर बसें। इसके अलावा जैसा कि मैरीबेल ने बेकफोल्ड की योजना की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया है कि उपनिवेशों का विकास अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं था और देशांतरण



तथा निवेश की कृत्रिम सहायता की तुलना में लाभप्रदता का अधिक महत्व था।<sup>117</sup>

साम्राज्य में पूरक विकास की नव वाणिज्यवादी (निजो मर्केंटायलिस्ट) धारणा और कच्चे पदार्थों के उत्पादन में भारत की तुलनात्मक लाभ पर जोर दिए जाने की स्थिति में, इस देश में निर्माण उद्योगों की संभावनाओं के विषय में अत्यधिक चिंता की आशा नहीं की जा सकती थी। परंतु परंपरागत वस्तुओं के उत्पादनों के विषय में क्या विचार था? अपशकुनी 'अनीद्योगीकरण' का प्रश्न पौराणिक पिशाच की भांति यदा-कदा ही सामने आता था। केवल उस एकमात्र वित्त सदस्य के लिए, जिसने स्वदेशी उद्योग के द्वारे में जांच की थी, यह प्रश्न पूर्ण रूप से कल्पित नहीं था। बंगाल चेंबर आफ कामर्स के आग्रह पर यह जांच ट्रैवेलियन ने करवाई थी। 1862 से 1864 तक मेनचेस्टर के सूती वस्त्रों की मांग में अस्थायी कमी हो गई थी। मांग में कमी के कारण थे—अमरीकी गृहयुद्ध के समय इंग्लैंड के वस्त्र की कीमतों में थोड़ी-सी वृद्धि, सूती वस्त्रों का सन तथा ऊन के बने हुए वस्त्रों द्वारा प्रतिस्थापन, उपलब्ध पूंजी को इस उद्योग से निकालकर अधिक लाभप्रद कपास निर्यात के सट्टे में लगाना, और भारतीय मुद्रा बाजार में पूंजी की अस्थायी तंगी।<sup>118</sup> बंगाल चेंबर की यह आशंका समझ में आती थी कि मेनचेस्टर से आने वाले माल की तुलना में आयातित कपास से कपड़ा कम लागत पर तैयार होता था।<sup>119</sup> ट्रैवेलियन द्वारा की गई जांच का क्षेत्र अवध, पश्चिमोत्तर, मध्य प्रांत और बंगाल के जिला स्तर तक सीमित था। जांच से स्पष्ट हुआ कि मांग में कमी उपर्युक्त कारणों से ही थी, और अमरीकी गृहयुद्ध के बाद कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाने से भारतीय बुनकरों के हाथ से घरेलू बाजार निकल रहा था। ट्रैवेलियन ने सर चार्ल्स वुड को सूचना दी थी कि कपास की कीमत में वृद्धि (इस तथ्य के साथ-साथ कि काफी बड़े भंडारों के कारण इंग्लैंड के कपड़े की कीमत में थोड़ी सी ही वृद्धि हुई है) से भारतीय बुनकरों की परेशानी बहुत बढ़ गई है "और बहुत सारे बुनकरों पर तो गंभीर विपत्ति टूट पड़ी है।"<sup>120</sup> कपास की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय बुनकरों को अपने काम में कमी करनी पड़ी और बहुत सारे स्थानों पर तो उन्हीं सूती वस्त्रों का उत्पादन ही छोड़ना पड़ा।<sup>121</sup> परंतु यह भारतीय समाज की स्वस्थ प्रगतिशील अवस्था ही थी कि संकट गंभीर होने पर भी, बाहरी सहायता के बिना भी उसका सामना कर लिया गया। ऐसा इस कारण हो सका कि प्रथम बुनकर सूती वस्त्रों के उत्पादन होने के साथ-साथ कृषक भी थे, और दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि श्रम की मांग सामान्यरूप से पर्याप्त थी। और अंत में, यह उल्लेखनीय है कि बुनकरों की बढ़ी संख्या (जैसा कि सर्वविदित है, बुनकर बढ़ी संख्या में शहरों में बसे होने के साथ-साथ देश के प्रत्येक गांव में फैले हुए थे) पर इस दवाव का एक लाभकारी परिणाम यह निकला कि इन लोगों द्वारा उद्योगों को छोड़कर कृषि व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया तेज हो गई जो समान रूप से भारत और इंग्लैंड दोनों ही के हित में थी...।<sup>122</sup> ट्रैवेलियन द्वारा जांच के निष्कर्ष निस्संदेह निर्णायक नहीं थे। घरेलू उद्योग में आश्चर्यजनक लोच के दर्शन हुए। तथापि इस जांच के निष्कर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थे कि इस काल से संबंधित घरेलू उद्योगों के द्वारे में केवल यही एक व्यवस्थित जांच थी। ट्रैवेलियन के विचार से उद्योगों

का जो पतन हो रहा था, सभी लोगों ने उसे वाछनीय प्रक्रिया का अनिवार्य समापन नहीं माना है। एक दशक के बाद एथले ईडन ने इसके परिणामों को एक भिन्न पहलू से देखा है। उसने लिखा है, जनाधिक्य द्वारा संभावित सामाजिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए यदि हमें किसी बात पर औरों की तुलना में अधिक ध्यान देना है तो वह यह कि औद्योगिक उत्पादन करने वाला वर्ग पैदा किया जाना चाहिए और भूमि पर जितने लोग ठीक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसी तुलना में जनसंख्या का भार दुगुना हो गया है और यह कम होना चाहिए।<sup>123</sup> तथापि प्रशासन में ईडन के सहयोगियों की दृष्टि में उसकी यह चिंता एक प्यारी सनक थी और ट्रेवीलियन की जाच को उसके सहयोगी वाछित प्रशासनिक सेवा के बाहर एक अतिरिक्त कार्य मानते थे। इस समस्या ने उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश तक विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। परंतु दुर्भिक्ष आयोगों की रिपोर्टों तथा राष्ट्रवादी इतिहासकारों की रचनाओं ने इस समस्या का यदि पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नहीं तो कम से कम इसका सिंहावलोकन करने के लिए लोगों को विवश कर दिया।

सामान्य सरकारी अधिकारियों की व्यावहारिकता और सैद्धांतिक तर्क के प्रति विमुखता लगभग अनुभूति जैसी थी और ये भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) से संबंधित साहित्य में निश्चित रूप से गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी थी। इंग्लैंड से भेजे गए वित्त सदस्यों और विशेष रूप से विल्सन, लैंग तथा मैसी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों और सिद्धांतों के भंडार से काफी प्रेरणा ग्रहण की। अतः व्यापारी वर्गों पर विशिष्ट करों को न्यायोचित ठहराने के लिए लाभ सिद्धांत को आधार बनाया गया। निस्संदेह सभी वर्गों को लाभ हुआ है... परंतु पूजीपति और व्यापारी वर्गों को विशेष लाभ प्रदान किया गया है और इनके लाभ की तुलना में दूसरे वर्गों का लाभ कुछ भी नहीं है।<sup>124</sup> यह लाइसेंस कर के समर्थन में दिया जाने वाला तर्क था। इसके आधार पर ब्रिटिश शासन से लाभान्वित वर्गों को इन लाभों की लागत में न्यायोचित अंशदान के लिए वाध्य किया जा सकता था। यह ठीक है कि इस तर्क को, कि प्रजा को राज्य के कार्यों से मिलने वाले लाभों के आधार पर ही कराधान होना चाहिए, अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों के अलावा ह्यूम्स तथा ग्रीक्स का समर्थन प्राप्त था। परंतु व्यवहार में यह बहुत कम अपनाया गया, क्योंकि तत्कालीन अर्थशास्त्रियों और विशेष रूप से जे० एस० मिल ने हित या लाभ के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था।<sup>125</sup> एडम स्मिथ के क्षमता सिद्धांत को रिकार्ड तथा जे० एस० मिल का समर्थन प्राप्त था। संभवतः मिल के प्रभाव के कारण ही विल्सन तथा लैंग ने लाभ सिद्धांत के साथ-साथ क्षमता सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। स्याई बंदोवस्त के क्षेत्र में जमींदारों के विरुद्ध क्षमता सिद्धांत एक सुविधाजनक अस्त्र था। ये जमींदार 1783 के विनियम 1 की गलत व्याख्या के आधार पर अनुचित छूट का लाभ उठा रहे थे यद्यपि वे अच्छी तरह से कर देने की क्षमता रखते थे। स्टाफ कर पर वहम में लाभ सिद्धांत और लागत दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लागत दृष्टिकोण के अनुसार प्रजा को राज्य के द्वारा संपन्न की जाने वाली सेवाओं के लिए लागत के आधार पर अंशदान करना चाहिए। विल्सन का तर्क था कि

वाणिज्यिक कानूनों, न्यायालयों आदि के प्रशासन की लागत का भार व्यापारियों तथा बैंकरो को वहन करना चाहिए।<sup>126</sup> इसके आधार पर वाणिज्यिक संव्यवहार (आदान-प्रदान) से संबंधित दस्तावेजों पर विशेष स्टाम्प शुल्क को न्यायोचित माना गया। सभी न्यायिक तथा विधिक कागजात पर सामान्य स्टाम्प शुल्क के संबंध में भी उपर्युक्त तर्क दिया गया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि मुकदमा लड़ने वाले को न्याय प्रशासन की लागत का कम से कम एक अंश तो देना ही होता था। (सामान्य स्टाम्प शुल्क को इस आधार पर भी उचित ठहराया गया था कि इससे अनावश्यक मुकदमेवाजी कम होती है।)

जो भी हो, न तो लाभ सिद्धांत और न ही क्षमता सिद्धांत का कोई व्यावहारिक महत्व था। यदि किसी भी विचार का कुछ इस प्रकार का महत्व था तो वह आर्थिक उदारवाद में निहित समानता का सिद्धांत था। कराधान के संदर्भ में इसका अर्थ था कि इसके द्वारा आय और संपत्ति के सापेक्ष वितरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अतः आरोही कराधान की कोई गुंजाइश नहीं थी। विल्सन ने लिखा था कि लोगों की स्थिति में समानता लाना सरकार का कार्य नहीं है।<sup>127</sup> यद्यपि जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री आफ इंडिया में एक अज्ञात अवतरण द्वारा यह माना है कि बेंथमवादी आय की ह्रासमान उपयोगिता संबंधी सिद्धांत के आधार पर आरोही कराधान को न्यायोचित ठहराया जा सकता है, तथापि जे० एस० तथा लोकवित्त के सिद्धांतों के परंपरानिष्ठ प्रतिपादकों ने ऐसे कराधान का घोर विरोध किया। इनका तर्क था कि आरोही कर उद्योग और अर्थव्यवस्था पर कर होगा... अर्थात् यह अपने पड़ोसियों से अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम और बचत करने वाले व्यक्तियों पर दंड होगा।<sup>128</sup> फिर भी जे० एस० मिल ने भी अर्जित आय और भूमि के मूल्यों में अनर्जित वृद्धि में भेद करने की आवश्यकता को स्वीकार किया था और मृत्यु कर का समर्थन किया था। परंतु आय स्रोत के आधार पर भेद के सिद्धांत को विल्सन और उसके उत्तराधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। बंगाल चैबर आफ कामर्स तथा कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन का तर्क था कि भूसंपत्ति से आय की तुलना में उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय पर कराधान को दर नीची होनी चाहिए।<sup>129</sup> कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन ने अपने तर्क के समर्थन में जे० एस० मिल का उल्लेख किया, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि सरकार ने अंतिम रूप से प्राप्त अर्जित आय और पूँजी से होने वाली आय, भूमि में मूल्यों में वृद्धि इत्यादि में कोई अंतर नहीं माना था, फिर भी किसी गुट विशेष के साथ भेदभाव न करने का सिद्धांत व्यापार तथा व्यावसायिक आय पर लाइसेंस कर के विरुद्ध एक प्रबल तर्क के रूप में धीरे-धीरे ही स्वीकार किया गया था। 1860 में ऊँची आय वाले वर्गों पर कर की दर थोड़ी सी अधिक करने का अधिनियम बनाया गया। परंतु विल्सन ने इसका सावधानी के साथ स्पष्टीकरण दिया कि यह आरोही कराधान के सिद्धांत की स्वीकृति नहीं वरन् निम्न आय वर्गों पर, जिन्हें लाइसेंस कर तथा आय कर दोनों ही देने थे, इन करों के दोहरे प्रभाव को रोकने का प्रयास था।<sup>130</sup>

कुल आय में इन प्रत्यक्ष करों का योगदान नगण्य अनुपात में था। इस अवधि में

यह 5 प्रतिशत से कभी भी अधिक नहीं था। सरकार की आय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत मालगुजारी और अफीम से होने वाली आय थे। इनका सरकार की आय में भाग क्रमशः 40 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक था। अफीम से प्राप्त होने वाली आय का एक भाग बंबई से निर्यात होने वाली अफीम पर शुल्क के रूप में प्राप्त होता था। यह अफीम मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के बाहर मध्य भारत की देशी रियासतों में पैदा की जाती थी। शेष भाग बंगाल की अफीम की विक्री से प्राप्त होता था जिस पर एकमात्र सरकार का एकाधिकार था। इस अप्रचलित किस्म के एकाधिकार पर अबाध व्यापार की दृष्टि से ही नहीं लोकोपकारी तथा नैतिक पहलू से भी ऐतराज होना स्वाभाविक था।<sup>131</sup> सरकार ने इन दोनों ही तर्कों को अस्वीकार करने में, और अपना एकाधिकार बनाए रखने में विशेष व्यावहारिकता दिखाई। मेयो ने इस संबंध में लिखा है कि हमने विचार विशेष के लिए अनेक भूले की है, परंतु मुझे आशा है कि इस प्रकार का भूर्खतापूर्ण आधरण (एवमेव; अफीम पर एकाधिकार का परित्याग) हम नहीं करेंगे।<sup>132</sup> अफीम विरोधी आदर्शवादी सरकार के अफीम पर अपना एकाधिकार रखने के इरादे को प्रभावित करने में असफल रहे।

जिसे कर भार कहा जाता था उसकी गणना में अफीम से आय और मालगुजारी को सरकार सम्मिलित नहीं करती थी। अफीम को अलग रखना ठीक था, परंतु राष्ट्रवादी प्रवृत्ताओं ने भूकर को अलग रखने के औचित्य के बारे में जोरदार ढग से शंका व्यक्त की। सरकारी मत था कि मालगुजारी कर नहीं है। इस परिभाषात्मक समस्या को इतना अधिक महत्व देना कुछ लोगों को अस्पष्ट हो सकता है। उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रभाव के आधार पर यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। परंतु जे० स्ट्रेची उस समय निश्चय ही इस सिद्धांत से प्रभावित था जबकि उसने लिखा था, अति प्राचीन काल में भारत में सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यवहार में भी राज्य की अधिकांश संपत्ति भूमि के रूप में ही रही है और सरकार के लिए जितना लगान ले सकना संभव और समीचीन रहा है उतना लिया गया है। भारत में मालगुजारी भूमि पर लगाने का केवल यही अंश है।<sup>133</sup> इस कथन की ऐतिहासिक कथन के रूप में सदिग्धता पर जोर देना अथवा भाषाशैली की विशिष्टता और विचार के उद्गम की खोज करना अर्थहीन है। प्रश्न यह है कि उस काल में जब कि उपयोगितावाद का प्रभाव घट रहा था, इस प्रकार की आस्था क्यों थी और सरकारी सिद्धांतों में मालगुजारी की लगान के अंश तथा गैर कर स्रोत के रूप में परिभाषा क्यों महत्वपूर्ण बन गई थी। इस संबंध में रिकार्डों अथवा मिल के प्रति निष्ठा के अतिरिक्त भी कुछ और बात थी। इस प्रकार सरकार ने भूमि से आय को बढ़ा पाना संभव व समीचीन दोनों ही पाया और उसने देश के कुछ संपन्न तथा अच्छे कराधान की संभावना वाले क्षेत्रों से करों के रूप में उस आय को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जो इन प्रदेशों में उसने मालगुजारी का स्थाई बंदोबस्त होने पर छोड़ दी थी। विलसन द्वारा लगाया जाने वाला आय कर जमींदारों पर कराधान का पहला प्रयास था। उसने कराधान से छूट के लिए जमींदारों के बहानों को अस्वीकार कर दिया।<sup>134</sup> यदि मालगुजारी की कर के रूप में परिभाषा की जाती तो स्थाई बंदोबस्त की ब्याख्या इस प्रकार हो

सकती थी कि जिसका अर्थ मालगुजारी देने वाले व्यक्तियों को और अधिक कराधान से स्थाई छूट होती है (जैसे, आय कर, सबक उपकर, शिक्षा उपकर इत्यादि से छूट)। अस्तु, सरकार ने मालगुजारी की लगान के बंश तथा आय के गैर कर स्रोत के रूप में परिभाषा पर जोर दिया। इसके अलावा, इस प्रकार की परिभाषा के आधार पर सरकार मालगुजारी को तथाकथित कर भार के अनुमानों से अलग रख सकी। अफीम से प्राप्त होने वाली आय के साथ-साथ इसे भी अलग रखने पर प्रति व्यक्ति कर भार उस कर भार का आधा प्रतीत होता था जो इन्हें सम्मिलित रखने पर होता था। निश्चय ही, ऐसा लगता था कि अधिकांश व्यक्ति कोई कर ही नहीं देते हैं। उनका सरकारी आय में एकमात्र योगदान जिसे कर कहा जा सकता था, उनके द्वारा नमक पर दिया जाने वाला शुल्क था। यही सरकारी मत था और एंग्लो इंडियन प्रेस ने इसका कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्रचार किया था।

हमारे इस दावे की कि उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में उपयोगितावाद में पतन हो रहा था, कुछ सीमाएं हैं। केनिंग ने उत्तर भारत की सामाजिक व्यवस्था में भूस्वामी अभिजात-वर्ग को प्राप्त परंपरागत स्थान पुनः दिलाने तथा सैन्य विद्रोह के बाद समाज सुधार की विस्फोटक विधायी नियमों को छिन्न-भिन्न करने के अनुदार दृढ़ निश्चय की नीति प्रारंभ की जिससे एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। इसकी विशेषता सरकार की सीमित अहस्तक्षेपी नीति थी। जे० एस० मिल ने<sup>125</sup> मालगुजारी के क्षेत्र में बड, प्रिगिल तथा थामसन द्वारा समर्थित उपयोगितावादी नीति से हटकर जमींदारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया की ठीक-ठीक व्याख्या की है। मिल ने इस प्रतिक्रिया के बारे में अपने प्रभाव-शाली मित्रो एच० एस० मेने तथा डब्ल्यू० टी० थाटर्न को चेतावनी दी थी और अपनी बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उसने इसके सैद्धांतिक आशय की उतनी अधिक विवेचना नहीं की जितनी इसके आशंकित व्यावहारिक परिणामों की। मिल ने कहा कि जमींदारों के साथ मालगुजारी के संबंध में स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था दीर्घकाल में सरकार के लिए बुरा सौदा सिद्ध होगी। परंतु 1862 तक सरकार इस संबंध में प्रतिज्ञा-बद्ध हो चुकी थी। 1862 में सर चार्ल्स वुड ने यह निर्णय किया कि जितनी जल्दी संभव होगा अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में स्थाई बंदोबस्त लागू किया जाएगा। सरकार जिन कारणों से इस निर्णय से धीरे-धीरे मुकर गई उनकी अध्याय 4 में विवेचना की गई है। जहां तक इस निर्णय का प्रश्न है इसके बारे में यह तर्क किया जा सकता है कि इस पर उपयोगितावाद के पक्ष व विपक्ष में सैद्धांतिक तर्कों का कोई प्रभाव नहीं था। स्थाई बंदोबस्त के विरोधियों ने यद्यपि लगान के उपयोगितावादी सिद्धांत का सहारा लिया था (उदाहरणार्थ सर जान स्ट्रैची),<sup>126</sup> तथापि सरकार ने स्थाई बंदोबस्त का विस्तार इस कारण से नहीं रोका। इसके कारण थे चांदी की कीमत में गिरावट और भूमि के मूल्यों में लगातार वृद्धि जिन पर उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में चार्ल्स वुड तथा स्थाई बंदोबस्त के समर्थकों का ध्यान नहीं गया था। इनके अलावा एक अन्य कारण यह भी था कि सरकार को कराधान की ऐसी प्रणाली का निर्माण करने में कठिनाई हो रही थी जिसके द्वारा वह भूमि आय में होने वाली वृद्धि में अपने हिस्से का

दावा छोड़ देने से होने वाली हानि पूरी कर सके। उपयोगितावादी दर्शन को आधार बनाना और प्रशासकों द्वारा उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में मालगुजारी नीति की व्याख्या करना ठीक नहीं है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से विचारधारा के प्रभाव में अतिव्याप्ति का दोष आ जाता है, यह निर्णयकर्ताओं की स्वस्थ व्यावहारिकता को कम महत्व देता है और वित्तीय ढाँचे एवं संपूर्ण आर्थिक दृश्य की उपेक्षा करता है। स्थाई बंदोबस्त के प्रश्न पर यद्यपि विचारधाराओं में संघर्ष इस दृष्टि से बहुत मनोरंजक था कि इसके द्वारा उपयोगितावाद का एक बैकल्पिक सामाजिक दर्शन से मुकाबला हुआ। चार्ल्स वुड तथा एस० लैंग के लिए जो स्थाई बंदोबस्त के विस्तार के समय क्रमशः इंडिया आफिस तथा वित्त विभाग के प्रधान थे, यह उपयोगितावादी सामाजिक दृष्टि का विकल्प था। इसका अर्थ 'एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नींव डालना था, संभवतः जिसकी सरलता के साथ व्यवस्था तो नहीं हो सकती थी, परंतु जिसमें सम्पत्ता और प्रगति की दृष्टि से आवश्यक तत्वों के बाहुल्य के साथ-साथ विविधता भी थी। इस ममाज में भूमि से संबद्ध मध्यम वर्ग का क्रमिक विकास भी हो सकता था।'<sup>137</sup> सरकार के प्रति निश्चित रूप से निष्ठावान कुलीन जमींदार वर्ग के विकास की संभावना स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति थी। व्यवहार में स्थाई बंदोबस्त की योजना को पहले स्थगित किया गया और बाद में इसका परित्याग कर दिया गया। परंतु यह अहस्तक्षेपी नीति विषयक दृष्टिकोण पर उपयोगितावाद की विजय न होकर उन कठोर आर्थिक परिवर्तनों (विषय के बाजारों में चादी की कीमतों में गिरावट तथा भारत में भूमि के मूल्यों में वृद्धि) के प्रति नीति-निर्धारकों की विमुख व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम थी जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था।

सैन्य विद्रोह से उपयोगितावादियों की सुखद कल्पनाओं और निष्प्रभ अमूर्त धारणाओं में आस्था को धक्का लगा। सैन्य विद्रोह से विजित देश में शासक प्रजाति की भूमिका के संघर्ष में दहशतपूर्ण अहसास और व्यापक चेतना का उदय हुआ। अप्रकट प्रजातीवाद (रेशलिज्म) उभर कर आया। सैन्य विद्रोह जान लारेंस के शब्दों में प्रायः प्रजातियों के बीच युद्ध माना गया था और इसके बाद की अवधि में प्रजातीय भावनाएं प्रबल हो गई थी।<sup>138</sup> इसके द्वारा न केवल शासित एवं शासक प्रजातियों के बीच एक सामाजिक दीवार अथवा यो कहिए कि एक सामाजिक दूरी बन गई जो दबाव गुटों की कार्यवाहियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, वरन् इसने प्रजातीय सिद्धांतों को भी जन्म दिया। सत्तावाद के समर्थन में उसका ही पुट लिए हुए एक प्रजातिवादी स्पष्ट वक्तव्य गवर्नर जनरल की परिषद में विधिसदस्य (1869-72) जे० फिट्ज जेम्स स्टीफन के लेखों में मिलता है। लिबर्टी, ईक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी में स्टीफन ने नीची प्रजाति के ऊपर बिना किसी कानून के शासन करने वाली सर्व सत्तावादी नीकरशाही के दृष्टिकोण में निहित विचार प्रकट किए हैं। ये विचार हैं कि लोगों में मौलिक असमानता होती है, विजयी प्रजाति श्रेष्ठ है, विजयी प्रजाति के लोगों के द्वारा निरंकुश सरकार की आवश्यकता है इत्यादि।<sup>139</sup> इस प्रकार का सर्व सत्तावाद भेदांतिक दृष्टि से उपयोगितावाद में निहित उसके ही एक तरफ का विस्तार था और ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक

प्रजाति पर दूसरी प्रजाति के साम्राज्यिक शासन का औचित्य प्रतिपादन करता था। साम्राज्यिक सदेश के प्रसारण में ग्रेटर ब्रिटेन (1868) का लेखक सर चार्ल्स डिल्के स्टीफन की तुलना में कहीं अधिक सफल था। उसके द्वारा गढ़ा गया मोबिन्ग्यू का प्रजातीय असमानता का विचार, डार्विन की भ्रष्ट ढंग से की गई व्याख्या, और संपूर्ण भूमंडल पर एंग्लो-सैक्सन प्रजाति के एकत्व की सुंदर कल्पना बहुत लोगों तक पहुंची। डिल्के का विचार था कि भारत आश्रित राज्यों में ऐसा राज्य था जिसे ब्रिटिश शासन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए था। गवर्नर जनरल की परिपद में विधि सदस्य सर हेनरी मेन (1862-69) द्वारा किए गए पुरातन समाजों के अध्ययन और उसके द्वारा प्रतिपादित नियम दूसरे ही बौद्धिक घरातल पर अधिष्ठित थे। भारतीय समाज के विकास में बाधाओं पर उसके विचारों की अलग-अलग व्याख्याएं की गई हैं। भारतीय एवं यूरोपीय लोगों की एक ही आर्य परंपरा पर मेन के विचार भारतीय आत्म सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक औपधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते थे। साथ ही उसका भारतीय शाखा की गतिहीनता का सिद्धांत शासित प्रजाति की निंदा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था। दि इकानामिस्ट से संबद्ध वाल्टर बेजहाट तथा अर्थशास्त्री टी० ई० सी० लेजली मेन की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे।<sup>140</sup> लेजली (जो ट्रिनिटी कालिज, डबलिन में मेन का विद्यार्थी रहा था) ने जर्मनी के इतिहासवादी अर्थशास्त्रियों की भांति ही गैर-पाश्चात्य अर्थव्यवस्थाओं की विशिष्टता पर जोर दिया। बेजहाट उस चेतना के लिए मेन के प्रति आभारी था जिसे वह सामाजिक विकास की प्राक् आर्थिक अवस्था कहता था। आर्थिक नीति निर्धारण के संबंध में इसका अर्थ स्पष्ट था कि विकसित पाश्चात्य समाजों के लिए अनुकूल आर्थिक सिद्धांत पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं हो सकते। भारत के लिए विशिष्ट नुसखा कुछ भी रहा हो, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि पाश्चात्य समाजों में सरकार की निर्धारित भूमिका की तुलना में ब्रिटिश भारतीय सरकार की भूमिका कहीं अधिक विस्तृत थी। जान स्ट्रैची स्टीफन के कथन का अनुमोदन करते हुए उसे उद्धृत करता है कि भारत में ब्रिटेन की भूमिका एक युद्धरत सभ्यता की भूमिका थी। स्ट्रैची ने जिस समय यह लिखा था चूंकि भारत के प्रति हमारा यह परम कर्तव्य है इसलिए हम यहां अपना शासन बनाए रखना चाहते हैं, वह इसमें निहित व्यंग्योक्ति से अनभिज्ञ था।<sup>141</sup> आरगाइल ने भी जब यह कहा था कि 'भारत में अपने शासन की रक्षा करना वहां के लोगों के प्रति हमारे प्रथम कर्तव्यों में से है' तो इस मनो-रजक धिरोधामास की अभिव्यक्ति में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई थी।<sup>142</sup> जिन्होंने साम्राज्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया था उनके लिए भारत पर इंग्लैंड का शासन करने का अधिकार और कर्तव्य विवाद का विषय नहीं था।

परंतु समुद्र में घात लगाकर बैठा राक्षस जैसे सिर उठाता है उसी प्रकार यदाकदा शंका उठ खड़ी होती थी। ट्रैवीलियन ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या भारत को उस समय के लिए तैयार किया जा रहा है जबकि यहां से इसके स्वामी एवं शिक्षक इसे छोड़कर चले जाएंगे।<sup>143</sup> काम्ते के वस्तुनिष्ठावादी शिष्य रिचर्ड काफ्रेव ने यह प्रश्न किया था कि यूरोप के लिए सामाजिक विकास के संबंध में प्रजाति की धारणा पर आधारित दृष्टिकोण

अपनाना तथा भारत की सभ्यता को नीचे स्तर की मानना और उस पर थोड़ी सी भी सहानुभूति न रखने वाली सरकार घोष देना क्या अविवेकपूर्ण नहीं है ? <sup>143</sup> जेम्स विल्सन का प्रश्न था कि क्या इंग्लैंड ने इस समस्या का सामना सच्चाई के साथ किया है कि भारत पर ब्रिटेन का शासन स्याई रूप से रहना है या इस देश को स्वशासन के लिए धीरे-धीरे तैयार करना है ? <sup>144</sup> अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार की शंकाएं भारत में खुलेआम प्रकट नहीं की जाती थी। एक अवसर पर यह सार्वजनिक मामला बन गया था। यह अवसर था तत्कालीन मद्रास विद्रोह जबकि मद्रास का गवर्नर चार्ल्स ट्रैवीलियन 1860 के बजट और वित्तीय केंद्रीकरण की नीति पर अपना असंतोष व्यक्त कर बैठा था। ट्रैवीलियन के उद्देश्य या कारण मिले-जुले थे। अशतः यह उसकी स्वस्थ प्रशासनिक समझदारी थी... कलकत्ता स्थित सरकार केंद्रीकरण के दोषों को देख सके, इससे बहुत पहले ही उसने अत्यधिक केंद्रीकरण के जोखिमों को समझ लिया था और विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाए थे। अशतः यह उसकी व्यवहार कुशलता में कमी, लोक सेवा के प्रति निर्भीक बोध, और विवादप्रिय स्वभाव था। वह बहस करने में पटु था और इसमें अपनी कुशलता के प्रदर्शन की प्रवृत्ति उसकी प्रधान दुर्बलता थी। अशत मद्रास विस्फोट फ्रैंक आफ इंडिया की भाषा में स्थानीयता की भावना अर्थात् मद्रास और बंबई के नागरिकों में ईर्ष्यापूर्ण स्वतंत्रता की भावना का लक्षण थी। <sup>145</sup> प्रशासनिक व्यवहार्यता पर मतभेद, सरकारी अफसरों में विवाद के लिए उत्साह या प्रांतीय ईर्ष्याएं पहले न हों ऐसी बात नहीं थी, परंतु इनसे कभी ऐसा तूफान खड़ा नहीं हुआ था जैसा कि ट्रैवीलियन के सामने खड़ा हो गया। जिस कारण से ट्रैवीलियन की निंदा हुई, और उसे सेवा से मुक्त करके इंग्लैंड बुला लिया गया, वह यह था कि उसने आधारभूत मामलों पर संदेह व्यक्त किया था। उसने लिखा था कि 'भारत में लोकप्रिय विधानसभा के स्वरूप तथा नीति-नीति की अच्छी नकल कर ली गई है, फिर भी इस समय हम स्थानीय हितों के प्रति-निधित्व से, पहले की तुलना में, कहीं अधिक दूर हैं।' <sup>146</sup> ट्रैवीलियन ने विरोध प्रकट करते हुए यह भी कहा था कि सरकार ब्रिटिश वित्तीय ढांचे को प्रतिरोपित तो कर रही थी, परंतु इस व्यवस्था की एक आधारभूत शर्त कि करदाताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूरी नहीं होती थी। वास्तविक प्रतिनिधि व्यवस्था के अभाव में लोकमत से ही सरकार पर नियंत्रण की आशा की जा सकती थी। परंतु भारत में ब्रिटिश समुदाय के मत को ही लोकमत समझने की गलती की गई थी। इस देश में यूरोपीय लोगों के उपभोग की वस्तुओं पर शुल्क को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने और हमारे घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल को सीमा शुल्क से मुक्त करने से बजट शासक वर्ग में काफी लोकप्रिय हुआ था, और जिसे लोकमत कहा जाता था यह उसका प्रतिनिधि मत था। ट्रैवीलियन ने वर्ग विधान की जो आलोचना की थी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। भारत मंत्री से शिकायत करते हुए सपरिषद गवर्नर जनरल ने विशेष रूप से उपर्युक्त उद्धरण को छोट कर उसे आपत्तिजनक तथा खतरनाक बतलाया। ट्रैवीलियन का दूसरा अधम्य अपराध यह था कि उसने सरकार की इज्जत कम की। मद्रास के गवर्नर ने भारतीय वित्तीय नीति पर अपने आलोचनात्मक विचारों को प्रकट कर दिया था और



इस संबंध में बहस में भारतीयों को सम्मिलित कर लिया था। सपरिपद गवर्नर जनरल कैनिंग ने लिखा कि 'मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हम अपने आपको अमोघ बनाए रखेंगे, परंतु हम असंदिग्धता बनाए रखने का यथासाध्य प्रयास करेंगे।'<sup>148</sup> भारत में विकसित सरकार की कार्य प्रणाली में इज्जत के विचार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शासित प्रजाति और प्राच्य मस्तिष्क के संबंध में रुढ़िगत धारणा, आघातपूर्ण सैन्य विद्रोह के अनुभव से उत्पन्न असुरक्षा की भावना, ब्रिटिश प्रशासकों और स्वाभाविक रूप से संपर्क में आने वाले अधीनस्थ अथवा विनयपूर्ण भारतीयों के मध्य संबंध की प्रकृति इनमें से कुछ भी इस इज्जत की जड़ में रहा हो, ब्रिटिश नौकरशाही सरकार को मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को परम महत्व प्रदान करती थी। उसको लगा कि ट्रेवीलियन को वापस इंग्लैंड बुला लेने से वह लज्जित होने से बच सकी और उसकी इज्जत बनी रही।

इज्जत की पूजा के अतिरिक्त सरकार की कार्य प्रणाली में प्राच्य मस्तिष्क से संबंधित एक अन्य तत्व संभवतः रुढ़िवादी धारणाओं में खोजा जा सकता है। सैन्य विद्रोह के बाद इस विचार को अधिक मान्यता प्राप्त हुई कि स्थिरता के हित में समाज के स्वाभाविक नेता भूस्वामी अभिजात वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। यह विचार ऐसा नहीं है कि किसी अनुभव पर आधारित न हो। अभिजात वर्ग का पुनर्स्थापना का विषय इस कृति के क्षेत्र के बाहर है।<sup>149</sup> परंतु इस नीति से संबंधित एक पहलू प्रासंगिक है। भारतीय विधान परिपद के प्रारंभ (1862 से 1872 तक) इसमें सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक भारतीय सदस्य जमींदारों के हितों का प्रतिनिधि था और इनमें से अधिकांश अभिजात वर्गीय थे। कुल 12 मनोनीत सदस्यों में से 3 राज्यों (पटियाला, जयपुर और रायपुर) के शासक, 5 राजा, महाराजा अथवा नवाब का खिताब प्राप्त जमींदार (विजयनगरम, किशनकोट, बंदवान, बलरामपुर और ढाका) और शेष जागीरदार, तालुकदार एवं जमींदार (देवनारायण सिंह, दिनकर राव, प्रसन्नकुमार टैगोर, देवराजसिंह) थे। विधान परिपद के गैर सरकारी सदस्यों से परामर्श करना औपचारिक व्यवस्था माना था। परिपद की बैठक नियमित रूप से नहीं होती थी। उदाहरणार्थ, पहले दस वर्षों में (1862-71) प्रतिवर्ष औसतन 29 बैठकें हुईं।<sup>150</sup> इन बैठकों में से लगभग एक तिहाई में कोई भी भारतीय सदस्य उपस्थित नहीं था। अनेक बार जब वे उपस्थित भी होते थे तो परिपद के कार्य विवरण पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भूमिका नहीं के बराबर होती थी। फिर भी भूस्वामी अभिजात वर्ग के सदस्यों के मनोनयन से यह स्पष्ट था कि सरकार इस वर्ग को कितना महत्व देती थी। प्रसन्नकुमार टैगोर वकील होने के नाते और पुरानी विधान परिपद में क्लर्क रहने की दृष्टि से पूरी तरह से इस श्रेणी में नहीं आते थे, परंतु उन्होंने बंगाल में जमींदारों की संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया था। वे (बंगाल में) जमींदार भी थे। इसी प्रकार दिनकर राव भी जमींदार थे (आगरे में) परंतु विधान परिपद में गौरवपूर्ण स्थान पाने का अतिरिक्त उनका दावा इस बात पर भी आधारित था कि उन्होंने सैन्य विद्रोह के समय ब्रिटिश राज की पूरी निष्ठा के साथ सहायता की थी। 1868 में परिपद के सदस्य के रूप में मनोनीत बलरामपुर के महाराजा अवध के ब्रिटिश

इंडियन एसोसिएशन के 20 वर्षों तक (1862-82) अध्यक्ष थे। यह तालुकदारों का संघ था जिसकी राय सरकार (मुख्य रूप से प्रांतीय विषयों पर) लिया करती थी। इस संघ का कार्यालय केंनिंग द्वारा संघ को दिए गए कैसरबाग महल में था और 1876 में सरकार के साथ इसका संबंध इतना घनिष्ठ हो गया था कि सरकार ने मालगुजारी के साथ-साथ तालुकदारों से इस एसोसिएशन का चंदा वसूल करने का कार्य भी अपने ऊपर ले लिया था।<sup>151</sup> भूस्वामी अभिजात वर्ग और उसके संघों की सरकार द्वारा पक्षधरता से शहरी, शिक्षित और व्यावसायिक वर्गों को प्रसन्नता नहीं हुई। हिंदू पैट्रिअट ने भी, जो वस्तुतः ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख पत्र था, लिखा था कि शिक्षित वर्गों की नियमित रूप से उपेक्षा की जाती है और राजा-महाराजा... उसी तरह ब्रिटिश महारानी की भारतीय प्रजा के प्रतिनिधि नहीं है जिस प्रकार लुई नेपोलियन अब्बा विक्टर एमेनुअल इंग्लैंड के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।<sup>152</sup> (यह 1870-71 की स्थिति है जब प्रसन्नकुमार टेंगोर की मृत्यु के दो वर्ष बाद परिषद के सदस्यों में कोई भी बंगाली नहीं था और इसकी बैठकों में शरीक होने वाले एकमात्र भारतीय जयपुर के महाराजा थे।) अगले दशक में इस संबंध में लोगों का रोष बढ़ गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम दो अधिवेशनों में वर्गीय हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मांग उठाई गई क्योंकि नेतागण जैसा कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा है, इस बात के लिए उत्सुक थे कि परिषद में सभी प्रभावशाली हितों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले।<sup>153</sup> 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से यह मांग आंशिक रूप से पूरी हो गई।

ब्रिटिश साम्राज्य की विचारधारा पर इतिहासकारों ने पर्याप्त ध्यान दिया है। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद इसके विघटन के विषय में हाल की अनेक रचनाओं में विचारों (न्यासधारिता, पितृवाद, उपयोगितावाद, आदि) पर जो जोर दिखाई देता है उससे त्रुटिहीन धारणा की कल्पित कथा का निर्माण हुआ है, मानो साम्राज्यिक नीतियां बर्क, बेथम या मिल की अमूर्त आत्माओं द्वारा पैदा हुई हों। यह भावी इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन के लिए दिलचस्पी का विषय होनी चाहिए। साम्राज्यिक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में समानांतर प्रवृत्तियां और हितवद्ध गुटों के स्थान पर विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति से जो अटकलवाजी का क्रम चलता है, उस पर हम यहां विचार नहीं करेंगे। लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि ये प्रवृत्तियां आज भी मौजूद हैं। अतः हितवद्ध गुटों की भूमिका पर जोर देने पर दो प्रकार से ऐतराज किया जा सकता है—प्रथम तो इसे ब्रिटिश नीतियों का अनुचित लक्षण चित्रण कहा जा सकता है (ब्रिटिश हितवद्ध गुटों के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के आधार पर), अथवा दूसरी ओर इसे भारतीय राष्ट्रवादियों की अव्यक्त निंदा माना जा सकता है (उनके आदर्शों एवं संक्षयों की अनुदार व्याख्या के आधार पर)।

जिस काल का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है उसमें भारतीय अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभा नहीं सके जबकि ब्रिटिश हितवद्ध गुट इस दिशा में उनसे कहीं आगे निकल गए थे। फिर भी, उनके प्रकट रूप से निष्फल लगने वाले प्रयत्नों से जैसे कि जनमत तैयार करने, संघ बनाने, शिक्षावर्तों का प्रचार करने, आदि से, राष्ट्रीय

राजनीतिक दल के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके साथ ही साथ बहुधा परस्पर विरोधी वर्गीय हितों से ऊपर उठकर एक विचारधारा सामने आई जो कालांतर में आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुई। जमींदारों एवं शहरी मध्यम वर्ग के आद्य-राजनीतिक संघों के उद्देश्यों व कार्यवाहियों में तथा उस व्यवस्था के भीतर, जिसमें ब्रिटिश राज के साथ सहयोग और उसके आदेशों का पालन ही होता था, वर्गीय आर्थिक हितों पर जोर देने का अर्थ यह नहीं कि उपर्युक्त प्रवृत्तियों को अस्वीकार किया जाता है। हम इस विषय पर अध्याय पांच में पुनः विचार करेंगे। जहाँ तक ब्रिटिश हितवद्ध गुटों का प्रश्न है, हम नीति निर्धारकों पर प्रतिबंधों का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। इन प्रतिबंधों के कारण दबाव गुटों के लिए सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिशा में ले जा पाना संभव नहीं था। यह स्पष्ट है कि व्यापारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग जैसे भूतपूर्व उपनिवेशवादी, उद्धत राष्ट्रवादी देशभक्त, लोकहितपी उत्साही व्यक्ति, पत्रकार, सुसमाचारक, आदि को भी उपनिवेशवाद से संबंधित समस्याओं में दिलचस्पी थी। यह पहले ही नहीं मान लेना चाहिए कि औपनिवेशिक अधीनस्थ राज्यों के प्रति ब्रिटेन की नीति के विषय में इन सभी गुटों के मत में अखंड एकरूपता थी। वह भाव जिसे टेनिसन ने साम्राज्य का स्वर कहा है सट्टेबाज साम्राज्यवादियों की देन नहीं है। यह भी मान लेना ठीक नहीं होगा कि अल्पकाल में सभी व्यावसायिक हितों में सर्वव्यापी समरूपता थी और प्रायः व्यवसायी गुट अल्पकालीन बातों को ध्यान में रखकर ही आचरण करते थे।<sup>154</sup> हमें हितवद्ध गुटों की भूमिका और विशेष रूप से व्यापारिक हितों की भूमिका का सही-सही मूल्यांकन करने के लिए उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अंत में एक और बात महत्व की है कि इन हितवद्ध गुटों की भूमिका पर विचार अलग से न करके ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशों में विस्तार के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। ब्रिटिश हितवद्ध गुटों की भूमिका को अधिक महत्व देने पर इस संबंध में यह ऐतराज उठाया जा सकता है कि ब्रिटेन द्वारा विदेशों में पूंजीनिवेश के भौगोलिक वितरण से यह सिद्ध नहीं होता है कि भारत में अपना साम्राज्य बनाए रखने में उसके भारी आर्थिक हित थे। विदेशों में ब्रिटेन के कुल पूंजीनिवेशों की तुलना में भारत ही नहीं सम्पूर्ण साम्राज्य में भी उसके निवेश बहुत थोड़े थे। अस्तु, साम्राज्यिक नीति निर्धारण में आर्थिक हित महत्वपूर्ण नहीं थे। आर्थिक साम्राज्यवाद के सिद्धांत के आलोचकों की इसे पहले से ही स्पष्ट प्रतिक्रिया को एक खास विचारधारा का व्युत्पन्न तत्त्व मानकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हो भी, तो भी इस मत पर आनुभविक रीति द्वारा विचार तो होना ही चाहिए। इस दिशा में सर जार्ज पैश के प्रयास (1911) के तत्काल बाद सी० के० हाव्सन (1914) और एल० एच० जेम्स (1924) ने कार्य किया था और तब से ब्रिटिश पूंजी के निर्यात के परिमाणानुक्रमिक अध्ययन की दिशा में तीन महत्वपूर्ण प्रयत्न ए० एच० इम्ला (1958), ए० के० केर्नकास (1958) और मैन्यू साइमन व हार्वे सेगल ने (1961) किए हैं। अब इस बात से सुनिश्चित प्रमाण उपलब्ध है कि ब्रिटेन द्वारा विदेशों में किए गए पूंजीनिवेशों का बहुत बड़ा भाग साम्राज्य के बाहर स्वतंत्र देशों में था।<sup>155</sup> इस क्षेत्र में नवीनतम और सबसे अधिक प्रभावशाली जांच साइमन

(1967) की है। इसने 1865 से 1914 तक की अवधि में ब्रिटेन द्वारा विदेशों में किए गए नए संविभागीय (पोर्टफोलियो) पूंजीनिवेशों के भौगोलिक एवं उद्योगवार वितरण से संबंधित व्यापक आंकड़ों का विश्लेषण किया है जो कम्प्यूटर की सहायता के बिना संभव ही नहीं हो सकता था। उसकी जांच का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि ब्रिटेन द्वारा विदेशों में किए गए पूंजीनिवेशों में से लगभग 40 प्रतिशत तो साम्राज्य के भीतर थे और 59 प्रतिशत स्वतंत्र देशों में। उत्तरी व दक्षिणी अमरीकी महाद्वीपों का अंश सर्वाधिक था (क्रमशः 34 प्रतिशत व 17 प्रतिशत)। एशिया तथा अफ्रीका का भाग अपेक्षाकृत कम था। मैन्यू साइमन के अनुमान के अनुसार ब्रिटेन द्वारा यूरोप के बाहर किए जाने वाले निवेशों में 68 प्रतिशत शीतोष्ण प्रदेश में नए बसे क्षेत्रों में थे। 1865 से 1873 की अवधि में ब्रिटेन के साम्राज्य के भीतर संविभागीय निवेश का वार्षिक औसत 98 लाख पौंड था जबकि स्वतंत्र प्रदेशों में औसत 3 करोड़ 49 लाख पौंड के लगभग था। (1874 से साम्राज्य के भीतर होने वाले निवेशों में वृद्धि हुई और 1885 में जब ये सर्वाधिक थे तो उस समय इनका कुल निवेश में भाग 67 प्रतिशत था। इसके बाद इनमें पुनः कमी हुई और 1890 में ये कुल निवेश के 25 प्रतिशत रह गए। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में आस्ट्रेलिया के खनन उद्योग में गरमबाजारी के समय एक बार इनमें फिर से वृद्धि हुई और 1903 में इनका अनुपात 59 प्रतिशत हो गया जो इस अवधि में सर्वाधिक था।)<sup>156</sup>

ब्रिटेन से विश्व के विविध भागों को पूंजी का प्रवाह विभिन्न अल्प अवधियों में भारी मात्रा में हुआ है। ब्रिटेन से भारत में पूंजी का भारी आयात 1865 से पहले हुआ था और इसी वर्ष से साइमन का अध्ययन प्रारंभ होता है। एल० एच० जैक्स के अनुसार 1857 से 1865 के बीच में ब्रिटिश पूंजी का भारत को बड़े पैमाने पर निर्यात हुआ... 1870 तक लगभग 7 करोड़ 50 लाख पौंड का पूंजीनिवेश रेलों में हुआ। अंग्रेजों के हाथ में जो स्टॉक पहले से ही था, उसके अतिरिक्त भारतीय ऋण के 5 करोड़ 50 लाख पौंड भी उनके हाथ आ गए। अनुमान है कि चाय बागान, जूट मिलों, बैंकों (अंशों और निक्षेपों दोनों ही रूप में), नौपरिवहन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 2 करोड़ पौंड की पूंजी निजी आधार पर लगाई गई।<sup>157</sup> इस प्रकार जैक्स ने अपने आंकड़ों का, (जैक्स फाइले) जिन्हें साइमन ने भी प्रयोग किया है, सार प्रस्तुत किया है। अधिकांश शोधकर्ताओं ने जिनमें सी० के० हाक्सन और केर्नकास भी हैं, अ... '870 के बाद

तथापि निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि ब्रिटिश पूजी की प्रवृत्ति नवीन विश्व और साम्राज्य के बाहर के देशों में प्रवाहित होने की थी। यही पैश के अध्ययन (1911) का भी निष्कर्ष था। भारत और श्रीलंका में 36 करोड़ 50 लाख पौंड, आस्ट्रेलिया में 38 करोड़ पौंड तथा दक्षिण अफ्रीका में 35 करोड़ 10 लाख पौंड के पूजीनिवेशों की तुलना में इंग्लैंड द्वारा नवीन विश्व में किए गए निवेशों का मूल्य 164 करोड़ 70 लाख पौंड था (इनमें से कनाडा में किए गए निवेशों की राशि 37 करोड़ 20 लाख पौंड थी।)<sup>159</sup>

आर्थिक साम्राज्यवाद के सिद्धांत के आलोचकों ने निवेशों के भौगोलिक वितरण से संबंधित आंकड़ों का काफी प्रयोग किया है। संभवतः संसार के कुछ भागों में विधिवत साम्राज्य की स्थापना बिल्कुल अनावश्यक हो गई थी, और औपचारिक साम्राज्यवाद भी यदि अधिक नहीं तो समान रूप से लाभकारी था। परंतु निवेशों के वितरण के स्वरूप के आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जाना युक्तिसंगत है कि पूजीनिवेश की प्रेरणा साम्राज्य की विधिवत स्थापना का कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं करती? यह कोई आसान प्रश्न नहीं है। यह कहना एक बात है कि साम्राज्य पूजीनिवेश की दृष्टि से कम आकर्षक क्षेत्र सिद्ध हुआ और यह कहना कि साम्राज्य को पूजीनिवेशों की दृष्टि से कभी आकर्षक समझा ही नहीं गया और इस दृष्टि से ये कभी साम्राज्य की स्थापना की प्रेरक शक्ति थे ही नहीं, बिल्कुल दूसरी बात है। प्रथम तो न तो व्यवसायियों और न ही नीति-निर्धारकों के पास परवर्ती इतिहासकारों की पश्च दृष्टि थी। यह तथ्य कि किन्हीं निर्दिष्ट क्रियाओं का (उदाहरणार्थ, आत्महत्या के प्रयास का) वांछित फल नहीं निकला, (आत्महत्या का प्रयास सफल नहीं हुआ), ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं जिससे सिद्ध हो कि क्रिया हुई ही नहीं थी (अन्यथा कोई भी आत्महत्या बंढनीय नहीं होगी)। केवल साम्राज्य के भीतर ही निवेशों का होना इस दावे के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐतिहासिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि साम्राज्य के बाहर निवेशों के लिए अवसर अधिकाधिक आकर्षक सिद्ध हुए। हमें निवेशकों पर इस संबंध में अलौकिक पूर्वज्ञान का आरोप लगाना आवश्यक नहीं है। ऐसा संभव है कि जो जानकारी उस समय मिल सकती थी उस तक भी यथार्थ में निवेशकों और साम्राज्य निर्माताओं की पहुंच न रही हो। सूचना की मात्रा से स्पष्टतः निवेश संबंधी निर्णय निर्धारित होते हैं। अधूरी सूचना के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। निवेश, कच्चे माल की प्राप्ति आदि की दृष्टि से तथाकथित उपयुक्त देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं भी निश्चित की जा सकती हैं। परंतु इन निर्णयों में पूरी जानकारी हो जाने पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। (यह ठीक है कि हर समय इस प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता।) आज भी अल्प विकसित देशों में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में सूचना कम ही है और गत शताब्दी में तो यह और भी कम थी। ऐसी स्थिति में व्यक्तिनिष्ठ तत्वों जैसे विस्तृत बाजारों के बारे में दिवास्वप्न, तथाकथित व्यावसायिक अन्तर्बोध, स्वार्थी गुटों द्वारा दिए गए नारों को स्वीकार करने की तत्परता, लाभप्रद अवसरों के बारे में इच्छाजनित धारणाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। एशियाई अधीनस्थ प्रदेशों के बारे में

इनमें से अनेक प्रत्याशाएँ भ्रामक सिद्ध हुई हैं और फिर पूँजी अन्यत्र चली गई है। परंतु जब तक यह भ्रम रहा है, साम्राज्य को बनाए रखने की इच्छा बलवती होती गई। यद्यपि इस बात का अहसास बढ़ रहा था कि ब्रिटिश पूँजी के लिए इसके कार्यक्षेत्र पर विधिवत नियंत्रण का होना आवश्यक नहीं फिर भी इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता था कि दूसरे देशों के अधीनस्थ प्रदेशों में ब्रिटिश पूँजीनिवेश में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। औपनिवेशिक अधीनस्थ देशों में शासक देश के अतिरिक्त अन्य देशों से पूँजी का प्रवाह निर्बाध नहीं था। ब्रिटेन के अन्य देशों में मंडिभागीय निवेशों के केवल 1 प्रतिशत दूसरों के अधीनस्थ देशों में थे (जैसे जर्मन-अफ्रीका तथा डच-इंडोनेशिया में)।<sup>160</sup> अस्तु, विधिवत स्थापित साम्राज्य का नकारात्मक पहलू से कुछ महत्व था। अंत में, प्रश्न उठता है कि क्या हम उन ब्रिटिश भारतीय हितवद्ध गुटों के प्रभाव का अतिरंजन कर रहे हैं जिनके हाथ में विदेशों में लंबी ब्रिटिश पूँजी का थोड़ा-सा भाग ही था? किसी भी हितवद्ध गुट का प्रभाव उसके पूँजीनिवेशों, कुल बिक्री आदि के अनुपात से अधिक हो सकता है। भले ही किसी भी साम्राज्यवादी देश के कुल विदेशी पूँजीनिवेशों में से एक छोटा अनुपात, ही अधीनस्थ देश या उपनिवेश में लगाया जाए और भले ही व्यवसायी वर्ग के बहुत थोड़े ही लोग उपनिवेश में दिलचस्पी रखते हों, फिर भी इन निवेशकों अथवा व्यवसायियों की सरकार की उपनिवेश संबंधी नीति में रुचि इसलिए कम नहीं हो जाएगी कि अधि-संख्यक पूँजीपतियों या व्यवसायियों के ध्यान में कुछ और ही स्वार्थ है। थोड़े से हितवद्ध गुटों के उत्साहपूर्ण प्रयत्नों के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। न तो भारत में सक्रिय हितवद्ध गुटों का प्रभाव इंग्लैंड के भारत में पूँजीनिवेश के उसके समस्त विश्व में निवेश के अनुपात से सहसंबंधित था और और नहीं नीति निर्धारक इस अनुपात के आधार पर हितवद्ध गुटों के दबाव को निर्णायक रूप से पता करते हैं, फिर भी यह सहज प्रस्ताव इस तर्क में निहित है कि साम्राज्य में भारत जैसे अधीनस्थ क्षेत्रों में पूँजीनिवेश की मात्रा थोड़ी होने से यह सिद्ध होता है कि साम्राज्य के नीति निर्धारण में पूँजीनिवेश का महत्व अधिक नहीं था।

1865 से 1914 तक विदेशों में ब्रिटेन के नवीन मंडिभागीय पूँजी निवेशों के क्षेत्रीय वितरण से स्पष्ट है कि परिवहन, लोकोपयोगी सेवाओं तथा लोक निर्माण कार्यों में भारी पूँजी लगाई गई। सामाजिक उपरिव्यय पूँजी में निवेश कुल निवेश का 69 प्रतिशत (रेलो में लगी 41 प्रतिशत पूँजी सहित), कृषि और खनन उद्योगों में 12 प्रतिशत तथा निर्माण उद्योगों में 4 प्रतिशत से भी कम था। साइमन का निष्कर्ष है कि इस तरह उन मुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाता था जिनसे प्राथमिक श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले राष्ट्रों के द्वारा यूरोप को अपने फ्राजिल बिकाऊ माल का निर्यात कर सकने के सामर्थ्य में वृद्धि हो।<sup>161</sup> मेकफरसन तथा थोर्नर ने भारत में रेलों में निवेश से संबंधित अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि मैनचेस्टर के सूती वस्त्र उद्योग के मालिकों ने रेलों के विकास का उत्साह के साथ समर्थन किया था। इस समर्थन के कारणों में कच्चे माल की आपूर्ति की प्रत्याशा एक महत्वपूर्ण कारण थी।<sup>162</sup> मैनचेस्टर के उद्योगपतियों की भारत से कपास की आपूर्ति बनाए रखने के बारे में उत्सुकता विशेष रूप से अमरीकी

गृह युद्ध के साथ काफी बढ़ गई थी। किंतु उन्नीसवीं शताब्दी के पाचवें दशक में ही काटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन की अमरीकी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से साम्राज्य के भीतर ही कपास की आपूर्ति विकसित करने का प्रयत्न कर रहा था। (भारत की संभावनाओं के विषय में जानकारी की स्थिति कितनी असंतोषजनक थी यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग सरकारी हस्तक्षेप के लिए आंदोलन कर रहे थे उनकी कपास की आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में जबरदस्त प्रत्याशाएँ थी लेकिन उन्होंने कुछ साधारण तथ्यों जैसे छोटे रेशे वाली भारतीय कपास के तकनीकी गुणों की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे ही भारतीय कपास से संबंधित समस्याओं का पता चला और अमरीका से 1864-65 में आपूर्ति पुनः चालू हो गई यह आंदोलन समाप्त हो गया।) प्रथम दो वित्त सदस्यों विस्सन तथा लैंग द्वारा कच्चे पदार्थों द्वारा आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका पर दिए गए चल और आगे भी इस नीति के पालन के विषय में ऊपर लिखा गया है। 1860 से 1870 के मध्य तक कपास निर्यात (सरकारी मूल्य) में ढाई गुनी, कच्चे जूट में छः गुनी और खालों में तीन गुनी वृद्धि हुई। 1860-61 के कुल निर्यात में वस्त्र निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल (कपास, जूट, रेशम तथा ऊन) का भाग 28 प्रतिशत था। 1870-71 में यह 43 प्रतिशत से अधिक हो गया।<sup>163</sup> रेल व सड़क निर्माण संबंधी नीति तथा सीमा शुल्क नीति दोनों ही पर कच्चे माल के निर्यातों को विकसित करने की आशंका की स्पष्ट छाप है, जो यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होता है कि यह पूँजी निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र खोज पाने की इच्छा से कहीं अधिक बलवती थी। ऐसा नहीं लगता कि नीति निर्धारकों को भारत में ब्रिटिश निवेशों के स्वरूप के बारे में विशेष दिलचस्पी थी। निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण वागान उद्यमों, खनन एवं कृषि उद्योगों तथा रेलों में भारी मात्रा में पूँजी निवेश अथवा रेलों में निवेश प्रेरक प्रभावों (सहसंबंध) का अभाव (रेलों के विकास के लिए आवश्यक मशीनों पर भारी मात्रा में व्यय इंग्लैंड में ही किया गया) कुछ ऐसे तथ्य थे जिनमें नीति निर्धारकों की रुचि नहीं थी। साम्राज्य के भीतर अनुपूरक विकास के संबंध में नव वाणिज्यवादी दृष्टिकोण के होते हुए नीति निर्धारकों से इसी बात की आशा भी की जा सकती थी। विधान परिषद में जिस दिन वजट पेश किया जाता था उस दिन वित्त सदस्य तथा चेंबर आफ कामर्स का प्रतिनिधि रस्मी तौर पर यह कह कर एक दूसरे को बधाई देते थे कि ब्रिटिश पूँजी के साथ-साथ भारत में अभिकर्ता गृहो (एजेसी हाउसेज) के द्वारा जुटाई गई अग्रेजों के स्वामित्व में चल पूँजी से भारत का विकास हो रहा है।

सरकार की भूमिका यथासंभव निष्क्रिय मानी गई थी। आवश्यक होने पर यह भूमिका सक्रिय हो सकती थी, परंतु इसकी आवश्यकता कभी ही पड़ती थी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन का आर्थिक नेतृत्व निर्विवाद था और ब्रिटिश वित्तीय तथा व्यापारिक हितों के सहायतार्थ हस्तक्षेप की आवश्यकता विरले ही पड़ती थी। 1870 से पहले की अवधि में विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश नीति अवाध व्यापार का साम्राज्यवाद के नाम से ज्ञात है। संक्षेप में यह नीति इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है—यदि संभव हो तो शासन की सहायता के लिए बिना ही व्यापार किया जाना चाहिए, परंतु यदि

आवश्यकता हो तो व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित किया जा सकता है (कारलाइल से क्षमायाचना पूर्वक) या फिर गालाघर तथा रीबिंसन इस नीति को इन शब्दों में बतलाते हैं : 'जब संभव हो अनौपचारिक नियंत्रण के साथ व्यापार किया जाए और जब आवश्यक हो तो व्यापार के लिए शासन तंत्र की सहायता ली जाए।'<sup>164</sup> विदेश में सशर्त राजनीतिक हस्तक्षेपवाद की यह नीति भारत में ब्रिटिश नीति जैसी ही थी। अधिक उपयुक्त शब्दों के अभाव में इस नीति को भेदमूलक हस्तक्षेपवाद कहा गया है। जहाँ एक ओर सरकार ने कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, जैसे कि सामाजिक उपरिब्यय पूँजी के विकास पर व्यय का सीमा निर्धारण, आरोही पुनर्वितरणीय कराधान से बचाव, घरेलू उद्योगों को टैरिफ संरक्षण न देना, आवर्ती दुर्भिक्ष की स्थितियों में भी खाद्यान्नों के स्थानान्तरण के संबंध में हस्तक्षेप न करना, औद्योगिक क्षेत्र में कोई रचनात्मक भूमिका निभाने के विषय में अनिच्छा दिखाना, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य क्षेत्रों में इसने अहस्तक्षेपी, नीति के सीधे व संकीर्ण मार्ग से अपने को हटा लिया और निजी पूँजी निवेशों को आर्थिक सहायता या गारंटी दी, वागानो में निवेश को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि संबंधी अधिनियमों में संशोधन किए, कपास तथा दूसरे कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए असाधारण प्रेरणाएं दी और कच्चे माल के निर्यात के पक्ष में आर्थिक उपरिब्यय पूँजी व परिवहन सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहन दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के छोटे दशक में अधिकांश ब्रिटिश हितवद्ध गुट जिनमें काटन सप्लाई एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण अपवाद था, केवल इतना चाहते थे कि सरकार सही किस्म की हस्तक्षेपी नीति का पालन करे और इसके अतिरिक्त कुछ भी न करे।

1870 के बाद की अवधि में साम्राज्य के बाहर राजनीतिक हस्तक्षेप और वाणिज्यिक विस्तार के बीच का संबंध भारी विवाद का विषय रहा है। साम्राज्यवाद की हास्यवादी समीक्षा के विरुद्ध कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग साधारण रूप से अनेक बातें कहते थे जो प्रायः निर्विवाद हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता था कि सबका एक ही मूल्य वाले स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं में से आक्रामक ध्वनि आती है (उदाहरणार्थ, पी० टी० बायर का मत है कि राजनीतिक उप-निवेशवाद की तथाकथित शोषणकारी प्रकृति व्यापक रूप से इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि विकसित देशों के बुद्धिजीवियों के मन में उस समाज के प्रति रोष रहता है जो उन्हें वह महत्ता और शक्ति प्रदान नहीं करता जिसके लिए वे अपने को योग्य समझते हैं। ये व्यक्ति अल्प विकसित देशों में रोष का अर्थशास्त्र स्वीकार करने की तत्परता का पूरा लाभ उठाते हैं।)<sup>165</sup> इतिहास लेखन में इस प्रतिक्रिया का एक परिणाम यह हुआ कि एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई थी कि साम्राज्यिक इतिहास में आर्थिक कारणों के स्थान पर केवल राजनीतिक कारणों पर जोर दिया जाता है। यह एक प्रश्न बना हुआ है कि फोल्डहाउस या गालाघर, रीबिंसन और डेनी ने 1870 के बाद साम्राज्य के लिए सघर्षों को यूरोप में नवीन राजनयिक रीति और राजनीतिक सुरक्षा के लिए प्रयत्न के रूप में व्याख्या देकर क्या व्यापारिक हितों के महत्व को कम नहीं समझा है ?<sup>166</sup> डी० सी० एम०



प्लैंट के अभी हाल के एक अध्ययन (1968) के अनुसार ब्रिटिश नीति निर्धारण में वित्तीय एवं व्यापारिक हितों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। उसके ही शब्दों में : '1815 से 1914 तक ब्रिटिश विदेशी नीति में जिस स्थिरता एवं सूत्रबद्ध के दर्शन होते हैं वह परंपरागत राजनय से कही जागे है। ब्रिटिश नीति के दो तत्व थे : राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था करना, तथा विश्व के बाजारों में ब्रिटेन द्वारा व्यापार के न्यायोचित एवं समान अवसरों को बनाए रखना।'<sup>167</sup> यह कहा गया है कि ये दोनों तत्व औद्योगीकरण में विशेषीकरण की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की गहनता, औद्योगिक देश की अपने यहां अनुपलब्ध साधनों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके कच्चे माल तथा बाजारों तक पहुंच बनाकर आर्थिक विकास के जोखिम को यथासंभव कम करने की ताकिक आवश्यकता के कारण घनिष्ठ रूप से संबद्ध है।<sup>168</sup>

यह संक्षिप्त सर्वेक्षण सतही तो है, फिर भी यह उस विषय के पृष्ठपट का कार्य कर सकता है, जिसे इस अध्ययन में केंद्र स्थान प्रदान किया गया है। डीन स्विफ्ट लिखता है कि जिस प्रकार भूगोलविद अफ्रीका के नक्शों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए हाथियों की आकृति बना देते हैं उसी प्रकार भारत के इतिहासकारों को भी यह सरल युक्ति आकर्षक लगी है। उन्नीसवीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास की परंपरागत स्वीकृत व्याख्या के पुनर्परीक्षण की दिशा में हाल में हुई प्रगति से हमारे ज्ञान में अनक रिक्तियां अब स्पष्ट हो चली हैं। इस संबंध में कुछ जाने-माने उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है— अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 1881 के बाद की अवधि के औद्योगीकरण से संबंधित जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) आकड़े अविश्वसनीय हैं, विदेशों में ब्रिटिश पूंजी निवेशों के बारे में अध्ययनों के परिणामस्वरूप 1871 के बाद की अवधि में ब्रिटेन से अधीनस्थ देशों की पूंजी प्रवाह से संबंधित पुरानी धारणाएं पूरी तरह से बदल गई हैं, परंपरागत वस्त्र उद्योग के विनाश से संबंधित व्यापक रूप से मान्य विचारधारा के बारे में सदेह प्रकट किया गया है, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में आधारभूत आर्थिक संरचना में किए निवेशों के स्वरूप एवं महत्व के साथ-साथ विदेशी व्यापार और घरेलू अर्थव्यवस्था के मध्य होने वाली परस्पर क्रिया पर पुनर्विचार हो रहा है।<sup>169</sup> जिन समस्याओं पर हमने विचार किया है वे कभी-कभी हमें उभर्युक्त प्रश्नों पर पहुंचा देती हैं, परंतु इन सभी पर गहराई में जाकर विचार करना न तो आवश्यक है और न ही संभव। आजकल कुछ प्रचलित विवाद (उदाहरणार्थ, परंपरागत घरेलू उद्योगों के पतन से संबंधित सामान्य रूप से स्वीकृत विचारों की समीक्षा) आनुमानिक परिकल्पनात्मक स्तर पर चलाए गए हैं। जब तक आनुभाषिक प्रमाण नहीं मिलते तब तक इन्हें अनिर्णीत प्रश्न माना जाना चाहिए। यह कहना अनावश्यक है कि इस अध्ययन का उद्देश्य 1858 से 1872 तक का भारत का पिस्तुत आर्थिक इतिहास प्रस्तुत करना नहीं है।

अतः, हम अपने दृष्टिकोण और अध्ययन की रीति के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे। हितवद्ध गुटों और निर्णयकर्ताओं के बीच अंतर्क्रिया के विषय में हमारे निष्कर्ष जैसे, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी गुटों के परस्पर दबाव, निर्णयकर्ताओं पर नियमित प्रतिबंध, निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अविवेकी तत्व एवं झुकाव, अनि-



आजकल प्रयोग किए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जिन्होंने निर्णय प्रक्रियाओं के अध्ययन किए हैं। इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि अनेक पाठकों के लिए अपरिचित विशिष्ट शब्दावली से बोझिल बनाए बिना ही किसी भी निर्णय (उदाहरण के लिए, स्थाई वंदोवस्त के क्षेत्र को विस्तृत न करने का निर्णय) का सीधा-सादा ऐतिहासिक विवेचन क्यों न प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया के विस्तृत वर्णन में अनेक महत्वहीन घटनाएँ अनावश्यक प्रतीत हुई हैं। निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण के अपने लाभ हैं, परंतु इस जाच का यही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। अध्याय दो में विधिवत स्थापित ढाँचे की व्याख्या की गई है। इस प्रारंभिक अध्याय में औपचारिक विधिक ढाँचे के बाहर निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटकों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। इन घटकों का अधिक विस्तार के साथ अध्ययन और विशेष रूप से, भारत और इंग्लैंड में हितवद्ध गुटों की भूमिका की जाच के द्वारा संभवतः सरकार की साम्राज्यिक व्यवस्था के कार्यान्वयन, परस्पर विरोधी हितवद्ध वर्ग समूहों, और उस युक्ति को अधिक गहराई के साथ समझा जा सकता है जिसके द्वारा विदेशी राज को स्वीकृति मिलने के साथ-साथ उसकी स्थिरता में वृद्धि हुई।

अंत में यह कहना शायद अनावश्यक ही है जैसा कि मैं नहीं कहता है : 'हम, मैं से कोई भी निष्पक्ष सत्यों के अलौकिक शून्य में नहीं खड़ा है।'<sup>11</sup> किसी भी भारतीय के लिए, जब वह उन विदेशियों की भावनाओं एवं दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करता है जिन्होंने भारत पर शासन किया है, तो 'उसकी अपनी अनुभूति और विदेशी शासकों की अनुभूति में अंतर' पर काबू पाना सहज नहीं होता। जब वह भारत के लोगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करता है तो उसके लिए अपने निर्णय से व्यक्तिनिष्ठ तत्व को अलग रख पाना आसान नहीं होता। वस्तुनिष्ठता की इन संभव सीमाओं से पूरी तरह मुक्त होने का दावा करना व्यर्थ है। परंतु पाठक के लिए यह निर्णय कर पाना संभव होना चाहिए कि दिया गया तर्क वस्तुनिष्ठ प्रमाण के नियमानुसार प्रयोग द्वारा उचित सिद्ध होता है या नहीं। यहाँ पर उठाए गए कुछ नए प्रश्न भारतीय साम्राज्य के राज-नीतिक अर्थशास्त्र (हमने जानबूझ कर इस अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया है) के अध्ययन के लिए सामान्य रूप से प्रासंगिक महत्व के हैं। इनमें से कुछ के उत्तर अब भी निर्णायक रूप से नहीं दिए जा सकते। हम आशा करते हैं कि यह कृति इन प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगी।

## संदर्भ

1. चार्ल्स लैम ने यह समीक्षा संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा से अवकाश ग्रहण करने के लगभग पांच वर्ष पहले बूख की 'टेबल ऑफ सिपल इस्टर्स्ट' (लंदन, 1818) की जिल्द के साथ वाले कोरे पन्नों पर लिखी थी। पाहुनिषि यूरो० सी० 128, इंडिया आफिश लाइब्रेरी, एम० सी० सदन, द्वारा इंडिया आफिश लाइब्रेरी (लंदन, 1967) पृ० 19 पर उद्धृत।

2. वित्त विभाग में गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कार्य विवरण, दिसंबर 1860, सख्या 2, चार्ल्स ट्रैवीलियन का नोट, 12, मई 1869 1)
3. उदाहरणार्थ देखिए चार्ल्स ट्रैवीलियन से चार्ल्स बुड को पत्र 12 अक्तूबर, 1864, ट्रैवीलियन कागजात, पत्र-पत्री जिल्द 44 (ट्रैवीलियन तीस शब्दों में अस्वीकार करता है कि वह 'वागान हितों' का विरोधी था), आरगाइल से मेयो को, 12 फरवरी, 1869, मेयो कागजात, बडल 47, सख्या 7 (आरगाइल मेयो को रेल योजना को इस समय बहुत अधिक गोपनीय रखने की सलाह देता है। इस समय बहुत अधिक गोपनीय शब्दों के नीचे मोटी रेखाएं छोपी गई हैं। आरगाइल द्वारा मेयो को यह सलाह इसलिए दी गई थी कि रेलवे-हित भयभीत न हों); मेयो से आरगाइल को पत्र, 9 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, सख्या 300 (मेयो ने भारत में यूरोपीय ध्यावसायिक समुदाय के विषय में लिखा है) ध्यावसायिक हितों (तथा अन्य हितों जिनका उल्लेख आगे किया गया है) के बारे में इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख प्रायः भारत-प्रतियोगी, गवर्नर जनरलों तथा सदस्यों के निजी पत्र-व्यवहार में मिलते हैं न कि उनके द्वारा लिखे गए सरकारी पत्रों में। इस सतर्कता के विविध कारणों में एक कारण यह था कि विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की जनता से छिपाना आवश्यक था। यह सोचने की ही बात है कि यदि भारत में रहने वाले इनके ही देशवासियों को उदाहरण के लिए मेयो की उनके प्रति घृणा (वे यहां पर काले लोगों के गोपण द्वारा ध्यासभव धन एकत्र करने के लिए आते हैं—मेयो ने यह भारत में रहने वाले गैर सरकारी यूरोपियनों के विषय में लिखा था) अथवा ट्रैवीलियन की चिड़चिड़ाहट (यदि मेनचेस्टर का चेबर आफ कामर्स मुझे यह बता सके कि हम उसके लिए और अधिक क्या कर सकते थे, तो मैं उसका अनुगृहीत होऊंगा) मालूम होती तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, मेयो से आरगाइल को, 9 नवंबर, 1870, पूर्व उद्धृत; ट्रैवीलियन से बुड को, 23 मई, 1863, ट्रैवीलियन कागजात, पत्र-पत्री जिल्द 42।
4. हमारी दिलचस्पी उपयोगी साधनों में है। सिद्धांतशास्त्रियों की भांति हमें अर्थगत विवादों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दबाव मुटो अथवा हितबद्ध मुटो के बारे में अनुभववाचित अध्ययन केवल पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रणालियों तक सीमित हैं। जतः इनके आधार पर निर्धारित सिद्धांत एशिया के पराधीन व गैर लोकतंत्रीय देशों के बारे में सगत नहीं भी हो सकते। एच० डब्ल्यू० एहरमान(स०) 'इंटरैस्ट ग्रुप्स आन फोर काटौनैट्स' (पिद्सबर्ग, 1958) एक मनोरंजक तुलनात्मक दृष्टि प्रदान करता है और डेविड बी० टूमन, 'दि गवर्नमेंट्स प्रासेस' (न्यूयार्क, 1951) ए० एफ० बेंटले के 'दि प्रासेस आफ गवर्नमेंट' (शिकागो, 1908) के प्रकाशन के समय से प्रगति वा सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। और भी देखिए, हेरी एकर्टीन, 'प्रेशर ग्रुप पालिटिक्स' (स्टैनफोर्ड, 1960)। दबाव मुटो की भूमिका और सरकारी निर्णय प्रणालियों के बारे में हाल में किए गए उन सभी अध्ययनों की सूची देना अनावश्यक हो नहीं असंभव भी होना जिनसे आधुनिक और, विशेष रूप से समकालीन, इतिहास के विषय में दृष्टि मिलती है। अकेले वैदेशिक नीति के क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया पर लिखे गए लेखों (1954 में आर० सी० स्नाइडर, एच० डब्ल्यू० ब्रक तथा बी० संपिन के लेख 'डिसेजिन मेकिंग ऐज अप्रोच टु दि स्टोरी आफ इंटरनेशनल पालिटिक्स' के प्रकाशन के समय से। देखिए 'फारेन पालिसी डिसेजिन मेकिंग' फ्री प्रेस आफ भेनको, 1962) की सख्या इतनी है कि बहुत बड़ी संरचना तैयार हो

जाएगी। इनमें से कुछ इतिहासकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं (उदाहरणार्थ, आर० जे० सी० बटोव, 'जापान्स डिसेंजन टु सरेंडर' स्टैनफोर्ड, 1965)। हमने दबाव गूट शब्द प्रयोग किया है। अनेक ब्रिटिश लेखक लाबी शब्द पसंद करते हैं। इतिहासकारों की शब्दावली में हाल में नए शब्द जुड़े हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन तत्त्वों एवं प्रक्रमों की ओर पहले कोई ध्यान नहीं दिया है।

5. हमने वर्गीकरण की कोई भी बनी-बनाई पद्धति प्रयोग नहीं की है। यदि हमारे आकड़ों को बोधगम्य क्रम से रखा जाए तो लगने लगता है कि उस समय कुछ विशेष प्रकार के एक दूसरे से भिन्न दबाव गूट थे।
6. गृह राजस्व कार्य विवरण, 6 सितंबर, 1860, सख्या 15 (पश्चिम विभाग) नाडियाद, जिला कैरा के निवासियों के द्वारा याचिका (अर्जी), 15 जून, 1860। वही पृ० 158, नीचे देखें (बंबई याचिका)।
7. बंगाल बायरेक्टरी (कलकत्ता, 1858), बंगाल चेंबर आफ कामर्स, टाइम्स के बंगाल चेंबर आफ कामर्स के इतिहास में प्रशासनिक ध्वनि और अनेक विषयों पर जानबूझ कर मौन के बावजूद भी काफी उपयोगी सामग्री है। यह बंबई और कराची के चेंबर आफ कामर्स द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक विवरणों के बारे में भी सत्य है।
8. गृह राजस्व कार्य विवरण, अप्रैल, 1867, सख्या 20, भारत मंत्री को कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन के मास्टर, समिति और सदस्यों द्वारा याचिका (अर्जी), 22 अप्रैल, 1867, सख्या 35, बायमराय को याचिका, 15 मार्च, 1867।
9. पी० पी० एच० एल० 1863, जिसमें 22, पत्र (कार्ड) 87, पृ० 160-62। स्मरण-पत्र लैंडहोल्डर्स एंड कमर्शल् एसोसिएशन से, 31 मई, 1861; इंडियो प्लांटर्स एसोसिएशन से, 20 नवंबर, 1860, काफी प्लांटर्स आफ कुर्ग से 25 जून, 1862; सूरसीपुर टी कंपनी कछार संचालकों से 6 फरवरी, 1861।
10. स्मरण-पत्र काटन सप्लाई एसोसिएशन से ईस्ट इंडिया कोर्ट आफ बायरेक्टर्स को 1857 में; भारत मंत्री को 26 जुलाई, 1859 को; भारत सरकार को 3 अप्रैल, 1860 को; आइसक वाट्स 'दि ओरिजिन एंड प्रोग्रेस आफ काटन सप्लाई एसोसिएशन' (मेनचेस्टर 1851) पृ० 119, 125, 131, इस प्रश्न में बहुत सारे प्रलेखों (डाकुमेंट्स) का संकलन है। आगे से इस प्रश्न को केवल वाट्स के नाम से संबोधित किया जाएगा।
11. काटन सप्लाई एसोसिएशन के कुछ क्रियाकलापों के लिए देखें एस० भट्टाचार्य 'लेक्चर इन इंडिया', 'इंडियन इकॉनामिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू', जनवरी, 1968, पृ० 1-22।
12. रीफार्मर 14 नवंबर, 1937; बी० बी० भनूमदार, 'इंडियन पोलिटिकल एसोसिएशन एंड रीफार्म आफ लॉजिस्तेचर' 1818-1917—(कलकत्ता, 1965) पृ० 24 पर उद्धृत।
13. जेम्स स्टलेज, 'ब्रिटिश रूल एंड नेटिव ओपीनिमन इन इंडिया' (लंदन, 1878) पृ० 219-20।
14. देखें अध्याय चार।
15. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 'ए नेशन इन मेकिंग' (लंदन, 1925) पृ० 40।
16. देखें अध्याय चार।
17. वित्त-कार्य-विवरण जून, 1861, लेखा सख्या 61, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता

के सदस्यों से गवर्नर जनरल को, 5 जून, 1861।

18. सड़क उपकर (सेत) विधेयक के संघ में 'हिंदू पैट्रियट' की टिप्पणी 5, 12 तथा 19 जून, 1871, बही 6 फरवरी, 1871; 23 जनवरी, 1871; 10 जुलाई, 1871 'बमीदारी पर सिधा और सड़क उपकरणों के विषय में।
- 19 भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सध्या 86, 3 अप्रैल, 1868।
20. 'जनेल बाक दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' जिल्द 1, सध्या 1, 1867।
21. देखें अध्याय 1, 2, 5।
22. देखें अध्याय 3, 5।
23. देखें अध्याय 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बर्बई शाखा से याचिका, (अर्जी), 'जनेल बाक दि ई० आई० ए०' जिल्द 5, खंड 2, 1871 पृ० 130-32।
- 24 देखें अध्याय 3।
25. पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, परिशिष्ट पृ० 511, बर्बई एसोसिएशन तथा बर्बई प्रेसीडेंसी के मूल निवासियों द्वारा प्रतिवेदन (1871)। स्थाई करो के बारे में पृ० 86 पर देखें; बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धृत, पृ० 68-73। एनिल सीत, 'दि एमरजेंस आफ इंडियन नेशनलिज्म' (कैम्ब्रिज, 1968) पृ० 229-31।
26. बी० नौरोजी, 'एपीजेर्ज एंड राइजिंग आफ दादाभाई नौरोजी' (मद्रास, 1908) पृ० 172, परिशिष्ट 'डी, स्टेटमेंट टु दि सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फार्मलेंस, 1871'।
27. जे० बिचिन (1815-76) 'काटन एंड ग्रेज्ज इन ब्रिस्टन इंडिया' (1851) 'धार नाट रेंटोर्ड' (1864), 'गवर्नमेंट आफ इंडिया अंडर ए म्यूरोक्रेमी' (1853) आदि प्रथम प्रकाशित किए; इनने सैन्य विद्रोह के बाद भारतीयों को क्षमा प्रदान करने की बग़ावत की पी और यह उनके प्रति सहानुभूतिमूलक था।
28. देखें अध्याय 5।
29. भारत सरकार को काटन सप्लाय एसोसिएशन से स्मरण-पत्र 3 अप्रैल, 1860, बादत पूर्वोद्धृत, पृ० 139। गृह राजस्व कार्य विवरण 6 जुलाई, 1861, सध्या 7, मंत्री, सी० एम० ए० से मंत्री, भारत सरकार को 15 मई, 1861। बही 9 दिसंबर, 1861, सध्या 2, ठीक बही 3 मितुबर, 1861।
30. देखें अध्याय 3, 5। वित्त कार्य विवरण जुलाई, 1868, पृथक राजस्व सध्या 14, भारत मंत्री की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा विनम्र स्मरण-पत्र, 31 मई, 1869।
- 31 देखें अध्याय 4। गृह पृथक राजस्व मार्च, 1861, सध्या 6 एच० इन्सू० जे० बुड, सचिव, बंगाल पेंडर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 23 फरवरी, 1861; सध्या 7, सी० बुड को संसद के डेबरेज बडमें तथा अन्य 41 फर्मा से, 15 दिसंबर, 1860; सध्या 7 (ए), जो० मेइमिस्त्रि, अध्यक्ष, ई० आई० एसोसिएशन से सी० बुड को, 14 दिसंबर, 1860। गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण, अप्रैल, 1862, सध्या 25, सचिव। बर्बई पेंडर आफ कामर्स में गोमा गुम्फ-इन्सिस्टर को 21 मई, 1861। बही, कराची पेंडर आफ कामर्स के सचिव से पत्र। बही, अप्रैल, 1862, सध्या 28, अध्यक्ष, मद्रास पेंडर आफ कामर्स से सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू, फोर्ट सेंट जॉर्ज, 8 मई, 1861; बही सध्या 42, सचिव, मद्रास पेंडर आफ कामर्स से सचिव,

भारत सरकार को, 28 जनवरी, 1862। यही सन्ख्या 45, मद्रास चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 9 अगस्त, 1862। यही 20 सितंबर, 1862, सन्ख्या S, बंबई के गवर्नर को निध के मोरे के उत्पादकों और व्यापारियों को सचिका, मई, 1862। यही 5 मार्च, 1861, सन्ख्या S, कलकत्ता की सैमर्स बोर्डे, क्लिबर्न एंड कपनी तथा चार अन्य फर्मों से सचिव, भारत सरकार को, 1 मार्च, 1861।

32. अगस्त 1860 में एच० डब्ल्यू० जे० गृह, मजी, बंगाल चेंबर आफ कामर्स ने सेक्रेटरीयट से भेद करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजत था कउन किया था। गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण, 1 अक्टूबर, 1860, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 27 अगस्त, 1860। गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण, 27 जुलाई, 1860, सन्ख्या 26, डब्ल्यू० एच० केर, अध्यक्ष, मद्रास चेंबर आफ कामर्स से सचिव, छोटे सेट जार्ज की सरकार को, 30 जून, 1860; यही सन्ख्या 10, सचिव, बंबई सरकार से सचिव, भारत सरकार को, 14 मई, 1860। और भी, गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण, 1 अक्टूबर 1860, सन्ख्या 1, 2 व 6 चेंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों को टैरिफ समिति में देने के संबंध में। बंबई और मद्रास के चेंबरों ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजे, उन्होंने बंगाल चेंबर आफ कामर्स से संबंध मुलम को ही अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया जिसे सरकार ने टैरिफ समिति का सदस्य मनोनीत किया।
33. 'एनुअल रिपोर्ट आफ काउन् सप्लआई एमोनिगेशन' सन्ख्या 5, 23 सितंबर, 1862। यही संख्या 2, 1859। पादम पूर्वोद्धृत पृ० 119 और जाने।
34. देखें अध्याय चार। गृह राजस्व कार्य विवरण 20 अक्टूबर, 1860, सन्ख्या 42, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, भारत सरकार को, 2 अक्टूबर, 1860।
35. सी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धृत पृ० 37। ए० सी० पूर्वोद्धृत पृ० 204। 'काउन् सप्लआई रिपोर्ट' के प्रत्येक अंक में मुख्य-मूल् पर सबसे ऊपर छाया रहता था। 'कमाल का कितो भी राजनीति से कोई संबंध नहीं है' तथापि कूटनीतिपूर्ण राजनीति उसका एक प्रमुख भाग था। लकाभायर के 'कमाल के दुश्मि' के समय मेनवेस्टर के सूत्री वरत उत्साहक और कमाल विवेका भारी सन्ख्या में काउन् सप्लआई एमोनिगेशन के सदस्य बन गए थे। काउन् सप्लआई रिपोर्ट इनके जाने प्रचार का साधन था।
36. हाउस आफ कामर्स में भाषण कर्नल साइमस द्वारा (29 जून, 1865), किर्की द्वारा (27 जुलाई, 1868), आर० एन० फाउलर द्वारा (3 अगस्त, 1869; 5 अगस्त, 1870), 'सर डब्ल्यू० लासन (3 अगस्त, 1869), रटीफन केन (24 फरवरी, 1871), 'काउन्सिलर स्टेट-मैट्र' रिप्लेटेड काम हवाईन पालिमापेटरी डिबेट्स' (कलकत्ता 1872) पृ० 634, 790, 794, 868, 886, 956, 969, 990, 997।
37. मेयो से बिजरायली को 9 मई, 1871, मेयो कामजात, बंडल 43, संख्या 100; मेयो से नोर्व-कोट को, 16 नवंबर, 1870, मेयो कामजात बंडल 41 संख्या 315।
38. आरगाइन से मेयो को, 16 दिसंबर, 1870, मेयो कामजात, बंडल 48, संख्या 34।
39. आर० टैपिल से ओ० टी० बर्न को 25 जुलाई, 1871, मेयो कामजात, बंडल 61, (सन्ख्या नहीं दी गई है)।
40. देखें अध्याय 5। सी० एन० बी०, XVIII, पृ० 225। हेनरी हिथीन, 'द रिफार्म'।

एन ऐडवेंचरस लाइफ,' (लंदन, 1911), पृ० 169, 174-75 ।

41. सी० नोरोजी पूर्वोद्धृत परिशिष्ट बी, 'स्टेटमेंट टु दि सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनेंस, 1871,' पृ० 173 ।
42. गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण सितंबर, 1860, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का प्रस्ताव 29 सितंबर, 1860 । कुलन बंगाल चेंबर आफ कामर्स का अध्यक्ष था । गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण सख्या 6, सचिव, चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 24 सितंबर, 1860 ।
43. गृह राजस्व कार्य विवरण सितंबर 23, 1860, सख्या 39 । गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा प्रस्ताव, वही अक्टूबर 20, 1860, सख्या 35 जायकर पत्रक में सशोधन के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट ।
44. वित्त कार्यविवरण जनवरी 1867, रिपोर्ट आफ कमेटी आन कस्टम्स टैरिफ भारत सरकार के वित्त सचिव को प्रेषित, 7 जनवरी, 1867 ।
45. देखें अध्याय 5 ।
46. गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण 7 जुलाई, 1860 सख्या 7, ए० ईडन । राजस्व बोर्ड सचिव, बंगाल सरकार को, 10 मार्च, 1860 ।
47. पूर्वोक्त स्थल ।
48. चार्ल्स ट्रेवीलियन से चार्ल्स वुड को, 13 जून, 1860, ट्रेवीलियन कागजात ।
49. चार्ल्स ट्रेवीलियन से चार्ल्स वुड को, 4 मार्च, 1863, ट्रेवीलियन कागजात ।
50. ट्रेवीलियन से वुड को, 12 अक्टूबर, 1864, ट्रेवीलियन कागजात ।
51. देखें 'क्रॉड आफ इंडिया' 14 अप्रैल, 1864; 22 सितंबर, 1864, 6 अप्रैल, 1865, 18 मई, 1865 ।
52. वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1865, पृथक राजस्व सख्या 35, भारत सरकार को बंगाल चेंबर आफ कामर्स द्वारा स्मरणपत्र 10 अप्रैल, 1865 । वही, जून 1865, सख्या 244, वित्त सचिव, भारत सरकार से सीमाशुल्क कलक्टर को, 21 जून, 1865 । भारतमन्त्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण, सख्या 114, 9 मई, 1865 ।
53. देखें अध्याय 1 ।
54. मेयो से आर्बुथनोट को 10 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 17 ।
55. मेयो से आरगाइल को, 17 अक्टूबर, 1869, मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 285 ।
56. मेयो से आरगाइल को, 17 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 20 ।
57. पूर्वोक्त स्थल ।
58. देखें अध्याय 3 ।
59. आरगाइल से मेयो को, 11 अप्रैल, 1871, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 5 ।
60. भारत मन्त्री से भारत सरकार को, 10 फरवरी, 1871, वित्त प्रेषण, सख्या 52 ।
61. देखें अध्याय 4 ।
62. मेयो से आरगाइल को, 9 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, सख्या 300 ।
63. स्नेपर सी० क्लिंग, 'दि न्यू म्यूटिना : इंडिगो इस्टिरेटमेंट इन बंगाल 1859-62'



(फिलाडेल्फिया, 1966) अध्याय 4 पत्र 38 ।

64. रविन्दर कुमार, 'दि डेकन राइट्स आफ 1875', 'जनरल आफ एशियन स्टडीज', XXIV, संख्या 4, अगस्त, 1965, पृ० 613-35 ।
65. डी० क्लिग पूर्वोद्धृत, पृ० 97-8 ।
66. बर० कुमार, पूर्वोक्त स्थल ।
67. काटन सप्टाई एसोसिएशन तथा भूमि सवखी अधिनियमों के विषय में देखें अध्याय 4, जूट के तैयार मात पर आयात-मुल्क के विषय में देखें अध्याय 4 न्याय की गारंटी देकर निर्माण की गई रेलों के सवख में देखें अध्याय 3 तथा डी० थोर्नर, 'इनवेस्टमेंट इन एपायर' (फिलाडेल्फिया, 1950) पृ० 119-167; सूती वस्त्रों पर आयात मुल्क के विषय में देखें अध्याय 4 और ए० रेडफोर्ड, 'मेनचेस्टर मचट्स एंड फारेन ट्रेड' (मेनचेस्टर, 1956), पृ० 25 और आगे ।
68. ऊंची टैरिफ दरों के विरोध में बंगाल चेंबर आफ कामर्स ने एक मसौदा का आयोजन किया था । सम्भवतः केनिंग को ब्रिटोहियो का धमादान की नीति के विरुद्ध ब्रिटिश समुदाय में रोष के कारण व्यापारियों को सभा में जनसाधारण को खाने में सफलता मिली । गृह (लोक) मन्त्र्याएं, 15 अप्रैल, 1859 । सख्या 10, कर्मकला याचिका (अर्जी), दिनांक 5 अप्रैल, 1859 ब्रिटेन की टैरिफ नीति पर इस अध्याय में आगे विचार किया गया है ।
69. गृह पुष्क राजस्व कार्यविवरण, 1 अक्टूबर, 1860, एच० डब्ल्यू० जे० बुड, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 27 अगस्त, 1860 । मेनचेस्टर स्मरण-पत्र के बारे में भारत सरकार को बता दिया गया था, गृह पुष्क राजस्व कार्यविवरण 7 जुलाई, 1860, सख्या 14, भारत मन्त्री से भारत सरकार को, 17 मई, 1860 । गृह पुष्क राजस्व कार्यविवरण 27 जुलाई, 1860, सख्या 26, डब्ल्यू० जे० फेक, अध्यक्ष, मद्रास चेंबर आफ कामर्स से सचिव, फोर्ट सेंट जार्ज की सरकार को, 30 जून, 1860 । वही सख्या 10, सचिव, बंबई सरकार से सचिव, भारत सरकार को, 14 मई, 1860 ।
70. गृह पुष्क राजस्व कार्यविवरण, मार्च 1861, सख्या 6, एच० डब्ल्यू० जे० बुड, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 23 फरवरी, 1861, देखें अध्याय 4 ।
71. वित्त कार्यविवरण पुष्क राजस्व अप्रैल, 1865, सख्या 35, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से गवर्नर जनरल को स्मरण-पत्र, 10 अप्रैल, 1865 । भारत मन्त्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण, सख्या 114, 9 मई, 1865 । वित्त कार्यविवरण पुष्क राजस्व जून 1865, सख्या 244, वित्त सचिव, भारत सरकार से बंगाल, मद्रास, बंबई और ब्रिटिश बर्मा की सरकारों को, 29 जून 1865 । देखिए अध्याय 4 ।
72. वित्त कार्यविवरण मार्च, 1866, सख्या 77, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 26 फरवरी, 1866 ।
73. वित्त कार्यविवरण सख्या 73, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, भारत सरकार को, 21 नवंबर, 1867 । बंबई चेंबर ने बंगाल चेंबर के इस दावे का समर्थन किया कि टैरिफ मूल्यों और बाजार कीमतों में भारी अंतर है । बहुत संभव है कि अमरीकी गृह-युद्ध के समाप्त होने के बाद कीमतें गिर गई थी और चेंबर आफ कामर्स द्वारा शिकायत के लिए आधार थे ।

वित्त कार्यविवरण, पूषक राजस्व फरवरी, 1868, सध्या 76, सचिव, बर्बई चेंबर आफ कामर्स से सचिव, बर्बई सरकार को, 22 अक्तूबर, 1867। फरवरी, 1868 में नियुक्त मर्मित ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल में दी जिसमें कहा गया था कि इन मर्मव बाजार कोमत और टैरिफ मूल्यों में छोड़ा ही अंतर है और इसलिए पुनर्मूल्यन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए (वित्त कार्यविवरण पूषक राजस्व, फरवरी, 1868, सध्या 90 तथा अप्रैल, 1868, सध्या 29)। मार्च, 1869 में टैरिफ मूल्यन में संशोधन किया गया। भारत सरकार को आशा थी कि 'इन छूट से व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा' जिससे वित्तीय त्याग में कुछ कमी हो सकेगी' (भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, 240, 20 मितवर, 1869)।

74. देखें अध्याय 4।

75. गृह राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 1867, सध्या 7, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, गृह विभाग, 22 मार्च, 1867, देखें अध्याय 4।

76. बी० फेर 'दि मीन्स आफ एमटॉनिश पब्लिक ओपीनियन इन इंडिया' 'जर्नल आफ ई० आई० ए०' 1871, जिल्द 5, खंड 4, पृ० 102-72। मेयो से डब्ल्यू० आर्चबिशप, 15 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बडल 42, सध्या 68। वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1868, सध्या 48, सचिव, राजस्व बोर्ड से मुख्य सचिव, फोर्ट सेंट जाम्स, 27 जनवरी, 1868।

77. ट्रैवीलियन का कहना था कि सरकार द्वारा अतिरिक्त कराधान की शक्ति उमरी ईमानदारी की व्याप्ति पर निर्भर होती है। अतः उमने आयकर हटाने का आग्रह किया, जो मूल रूप से अल्प काल के लिए आपात्कालीन उपाय के रूप में लगाया गया था। ट्रैवीलियन से एल्लिन को, 11 अप्रैल, 1863, एल्लिन कागजात, 1, भाग 2, जिल्द 23।

78. बुड ने भारत में आयातीत तैयार माल पर शुल्क में कमी का सुझाव दिया था। उसका सकेत मूल तैयार करने वाली फैक्ट्रियों पर सतुलन की दृष्टि से लगाए जाने वाले उत्पादन-शुल्क की ओर था। उसका यह भी विचार था कि भारतीय सूती बस्तों पर उत्पादन शुल्क (एक्साइज द्यूदी) लगाया जाना चाहिए। सी० बुड से एल्लिन को, 3 मार्च, 1862, बुड कागजात, 10, पृ० 62, ठीक वही, 25 जून 1862, वही, पृ० 310, बुड से फेर को, 2 अप्रैल, 1863, वही, 12 पृ० 170। ऐसा लगता है कि उसकी राय में भारतीय आयात शुल्कों से प्रभावित होने वाले हितों को सतुष्ट करने का सबसे अच्छा ढंग यही था कि मूल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर विशिष्ट शुल्क लगाया जाए।

79. सी० ट्रैवीलियन से सी० बुड को, 23 मई, 1863, ट्रैवीलियन कागजात।

80. देखें अध्याय 4।

81. देखें अध्याय 4। विल्सन की मृत्यु के 70 वर्ष बाद उनके निजी पत्रों को उनकी पुत्री ने प्रकाशित किया, ई० आई० बैरिंगटन, 'दि गवेंट आफ आल' (लंदन, 1927); देखें केनिंग से विल्सन को पत्र, 131 जनवरी, 1860, 10 फरवरी, 1860, 18 मार्च, 1860, बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत II, पृ० 223-24, 225-27, 274-75।

82. देखें अध्याय 3।

83. आरगाइन से मेयो को, 4 नवंबर, 1869, मेयो कागजात, बडल 47।

84. वित्त कार्यविवरण लेखा शाखा फरवरी, 1868, सध्या 57, गवर्नर जनरल द्वारा मेयो० 20

- जनवरी, 1868। मेयो से एच० डुरड को, 24 अप्रैल, 1870, मेयो कागजात, बंडल 39, संख्या 105।
85. वित्त कार्यविवरण लेखा शाखा फरवरी, 1868, संख्या 57, गवर्नर जनरल का मेमो, 20 जनवरी, 1868। मेयो से आरगाइल को 6 अप्रैल, 1870, मेयो कागजात, बंडल 39, संख्या 100।
86. देखें अध्याय 2।
87. मेयो से आरगाइल को, 9 नवंबर, 1870, वही बंडल 4, संख्या 300।
88. एल्गिन से सी० बूड को, 14 मई, 1862, एल्गिन कागजात, अनुभाग 1, भाग 1, पत्र-पत्रों, जिल्द 1, पृ० 13, उद्धृत गोपाल द्वारा, पूर्वोद्धृत पृ० 53।
89. इन शब्दों में सेलिमबरी ने एक ठेठ फारेन आफिस अवर-मचिव के व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त किया था, लेडी ब्लैडलन सेलिम, 'साइफ जाफ राबर्ट, मारकम आफ सेलिमबरी' (लन्दन, 1931), III, पृ० 216। उद्धृत सी० सी० एम० प्लाट द्वारा, 'फाइनल ट्रेड एंड पालिटिक्स - ब्रिटिश फारेन पालिसी' 1815-1914 (जॉक्सफोर्ड, 1968) पृ० XX, प्लाट ने नीति-निर्धारण के सदर्भ में नौकरशाही की सामाजिक रचना के बारे में दिलचस्प बातें कही हैं।
90. कार्ल मार्क्स, 'कैपिटल' (डोना टोर द्वारा संपादन), जिल्द 1, पृ० 213।
91. ए० के० केनक्रास, 'होम एंड फारेन इनवैस्टमेंट 1870-1913' (केंब्रिज, 1953), पृ० 244 केनक्रास को विल्सन के 'मौद्रिक सिद्धांत में आधुनिक उत्थ' दिखाई देता है। शुपीटर विल्सन का प्रसंगवश उल्लेख करते हुए उनके बारे में लिखता है कि 'वह उन लोगों में था जो विश्लेषण के इतिहास में बुरी तरह असफल हुए हैं।' जे० ए० शुपीटर, 'हिस्ट्री आफ इकानामिक एनेलिसिस' (लंदन, 1961) पृ० 726। विल्सन के आधारभूत आर्थिक विचारों का विस्तृत विश्लेषण राबर्ट लिक के 'इंग्लिश वियरीज आफ इकानामिक फलक्यूएशन' 1815-1848 (न्यूयार्क, 1959) में मिलता है। और भी देखिए एल्बर बूड, 'इंग्लिश वियरीज आफ सेंट्रल बैंकिंग 1819-1858' (केंब्रिज, मैसाचुसेट्स 1939)।
92. डब्ल्यू० बेजहाट 'मैमायर आफ दि राइट आनरेबल जेम्स विल्सन' (1860), मिसेज रमल, बैरिंगटन, 'दि वर्क्स एंड साइफ आफ वाल्टर बेजहाट' (लंदन, 1955), जिल्द III पृ० 213।
93. सर एडवर्ड वैंस्ट की भारत में जीवन-वृत्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं है। रिकार्डों ने अपने प्रिंमिपल्स के आमुख में लगान के सही सिद्धांत के विषय में वैंस्ट के योगदान को स्वीकार किया है। देखें सी० एन० बी० L X, पृ० 329, और शुपीटर, पूर्वोद्धृत, पृ० 586।
94. 'दि इकानामिस्ट,' 7 अप्रैल, 1860।
95. रिचर्ड टैपिल, 'मैन एंड ईवेट्स आफ माई टाइम इन इंडिया' (लंदन, 1882), ई० आई० बैरिंगटन द्वारा उद्धृत अपनी पुस्तक 'दि वर्क्स एंड साइफ आफ वाल्टर बेजहाट' (लंदन, 1915) जिल्द 10, पृ० 337।
96. सी० ट्रेवीलियन से टी० पाइक्रोफ्ट को, 25 फरवरी, 1860, ट्रेवीलियन कागजात।
97. मैं इस काल में प्रचलित आर्थिक विचारों—विशेष रूप से ब्लैडलन के वित्त संबंधी सिद्धांतों, की शुपीटर द्वारा अच्छी व्यवस्था के लिए उसके प्रति आभारी हूँ। शुपीटर, पूर्वोद्धृत, पृ० 402-5।

98. देखें अध्याय 2।
99. देखें अध्याय 4।
100. वही।
101. वही।
102. आरणाइल से मेयो को, 4 नवंबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 47।
103. सैन्य-व्यय सबंधी नीति का विवेचन आगे अध्याय III, अनुच्छेद I और II में किया गया है।
104. 'रिपोर्ट ऑन दि वकिंग आफ इंडियन रेलवेज (1875)' पृ० 15; यद्यपि भारतीय बस-धारियों के भाग की बहुत प्रशंसा की गई है तथापि इन स्रोत के बारे में अनुमान बहुत ही कान-चलाऊ है, आरणाइल ने मेयो को एक पत्र में लिखा था कि 1869 में रेलों में लगी हुई पूंजी में भारतीयों का भाग 1/80 था, पत्र 12 फरवरी, 1859, मेयो कागजात, बंडल 47, सख्या 7।
105. काटन सप्लाई एसोसिएशन से चार्ल्स वुड को स्मरण-पत्र 26 जुलाई, 1859। वाट्स पूर्वोद्धृत पृ० 125, सिचाई कंपनी ने तुंगभद्रा नदी से एक नहर खोदने में अपनी समस्त पूंजी व्यय कर दी और 1866 से सरकारी ऋणों पर निर्भर हो गई। एक अन्य कंपनी दि ईस्ट इंडिया इर्रिगेशन कंपनी इसी प्रकार सरकार से समय-समय पर मिलने वाले ऋणों पर उस समय तक निर्भर थी जब तक कि उसे सरकार द्वारा ले नहीं लिया गया (1868)। इस कंपनी को सरकार द्वारा निश्चित व्याज देने की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। एम० एम० पी० आर०, 1873-74, जार्ज बेजली इंडियन पालिटि (लंदन, 1868) पृ० 411-12।
106. राजस्व कार्यविवरण 28 फरवरी, 1861, सख्या 26, गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा प्रस्ताव, 28 फरवरी, 1861।
107. वित्त कार्यविवरण जुलाई, 1871, सख्या 83, भारत सरकार से भारत मंत्री को, सख्या 40, 6 अप्रैल 1870।
108. एच० ए० एड्रोबस क अनुसार सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि चाय का उत्पादन विपण्य (बिकाऊ) वस्तु के रूप में हो सकता है। तत्पश्चात् वाणिज्यिक आधार पर उसका उत्पादन करने के लिए यह चाय को निजी उद्यम के लिए छोड़ देना चाहती थी। 'ए हिस्ट्री आफ दि आसाम कंपनी,' (एडिनबरा, 1957)।
109. एम० जी० रानाडे, 'आइरन इंडस्ट्री—मार्गनिंगर जट्टेड्स' (1892); एम० के० सेन, 'स्टील इज इंडस्ट्रियल पालिसी एंड डेवलपमेंट' (कलकत्ता, 1964) पृ० 104-13।
110. देखें अध्याय 1।
111. जे० विल्सन से डब्ल्यू० वेजहार्ट को, 4 जुलाई, 1860 ई० बैरिगटन 'दि सवेंट आफ आस' (लंदन, 1927), बिल्ड II, पृ० 252।
112. 1857 में काटन सप्लाई एसोसिएशन से ईस्ट इंडिया कोर्ट आफ डायरेक्टर्स को स्मरण-पत्र वाट्स पूर्वोद्धृत पृ० 119, सर चार्ल्स वुड को 26 जुलाई, 1859, वहीं पृ० 125; भारत सरकार को, 3 अप्रैल, 1860, वही पृ० 131।
113. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 115, 16 जुलाई, 1863।
114. देखें अध्याय 5।
115. विल्सन का बजट वक्तव्य, विधान-परिषद विवरण (पुरानी सीरीज) जिल्ड 6, 1860;

ट्रिवीलियन का दस्तव्य, विधान-परिषद् कार्यविवरण (नई सीरीज) 1863, जिल्द II, पृष्ठ 82; गृह पृथक् राजस्व कार्यविवरण 31 मार्च, 1862, सख्या 7, डब्ल्यू० एस० फिट्जविलियम, अध्यक्ष, बंगाल चेंबर आफ कामर्स सपरिषद् गवर्नर जनरल (गवर्नर जनरल इन काउंसिल) को 27 मार्च, 1862।

116. 'मेनचेस्टर गार्जियन' 1 फरवरी 1861, भारतीय मामलों के विषय में 'मेनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स' द्वारा बुलाए गए सम्मेलन की रिपोर्ट। इस सम्मेलन में सूची वस्तु पर भारतीय आयात-शुल्क की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया था।
117. एच० मेरीवेल (1806-74) कैंब्रिज में राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर (1937-46), उपनिवेशों के लिए स्थाई ज्वर-सचिव (1948 से) तथा 'लैन्सर्स आन कोलोनाइजेशन' (1841) का लेखक था; 1859 में उसे स्थानांतरित कर इंडिया आफिस भेज दिया गया, वह बेनफोल्ड (1796-1862) से, जो बहुत सारे पेपलेटों का लेखक और औपनिवेशीकरण जाबोलन का नेता था, कम प्रभावशाली था।
118. राजस्व कार्यविवरण जून, 1864, सख्या 23, जी० एम० वैंटन, सचिव, सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू, एन० डब्ल्यू पी०, से एन० डब्ल्यू० पी० सरकार को, 16 मार्च, 1864।
119. राजस्व कार्यविवरण, 1 दिसंबर, 1863, सख्या 2।
120. सी० ट्रिवीलियन से बुड को 4 मार्च (1863) ट्रिवीलियन कागजात।
121. सी० ट्रिवीलियन से एल्यिन को, 21 फरवरी 1863, ट्रिवीलियन कागजात।
122. सी० ट्रिवीलियन से बुड को, 4 मार्च, 1863, ट्रिवीलियन कागजात।
123. देखें अध्याय 5।
124. वही।
125. जे० एस० मिल 'प्रिंसिपल्स आफ पोलिटिकल इकानामी' (1848) एशले का संस्करण V, II, 2।
126. देखें अध्याय 5।
127. देखें अध्याय 4।
128. जेम्स मिल, 'हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया' (संपादक एच० एस० विल्सन, चौथा संस्करण) जिल्द II, पृ० 293, गुल्लार मिर्डाल द्वारा 'पोलिटिकल ऐसीमेट इन दि डेवलपमेंट आफ इकानामिक थिअरी' (लंदन 1955) पृष्ठ 242, जे० एस० मिल, पुनर्मुद्रित, V, II, 3।
129. देखें अध्याय 4। गृह राजस्व कार्यविवरण अप्रैल, 1867, सख्या 7, सचिव बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, गृह विभाग को, 22 मार्च, 1867। वही सख्या 20, कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन के मास्टर, समिति और सदस्यों से भारत मंत्री को याचिका (अर्जी), 22 अप्रैल, 1867। गृह राजस्व कार्यविवरण, मार्च, 1867, सख्या 35, कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन से बापसराय को याचिका, 15 मार्च, 1867।
130. देखें अध्याय 4।
131. देखें अध्याय 5।
132. मेयो से बार्टल फेर को, 3 जून, 1870, मेयो कागजात, बहल 39, सख्या 156।
133. जे० स्ट्रैचो का स्मरण-पत्र, 1874, पी० पी० एच० सी० 1874, पृष्ठ 326, पृ० 16-17।

134. देखें अध्याय 4 ।
135. जे० एस० मिल से डब्ल्यू० टी० मोनटन को, 28 जनवरी, 1862, मिल से एच० एम० मे को 1 जनवरी, 1869; 'दि सैटस ऑफ जान स्टुअर्ट मिल' (संपादक एच० एम० आर हलियट लंदन, 1910), जिल्द I, पृ० 258, जिल्द II, पृ० 169 ।
136. विधान-परिषद कार्यविवरण ('नई सीरीज'), VII, पृष्ठ 432 ।
137. गृह राजस्व कार्य विवरण सितंबर, 1862, सध्या 29, मेमो० एस० लैंग द्वारा, 7 अगस्त 1862 : भारत मंत्री से भारत सरकार को, 'राजस्व प्रपण सध्या 14, 9 जुलाई, 1862 ।
138. लारेसे से डलहौजी को, 16 जून 1858, आर० बासवयं स्मिथ द्वारा 'साइफ ऑफ लार्से' (लंदन, 1901) जिल्द II में उद्धृत, पृष्ठ 196 । तुलसीय टी० आर० मंडकाफ, 'आपटरमै ऑफ दि म्यूटिनी' (प्रिंसटन, 1965) अध्याय 8, इस पुस्तक में तत्कालीन राजनीतिक विचार और विशेष रूप से प्रजातिवादी मित्रता का ज्ञानप्रद व आलोचनात्मक सर्वेक्षण मिलता है और भी देखिए रिचर्ड कोबनर एच एच० डी० मिमड्ट, 'इंपीरियलिज्म : दि स्टोरी एंड सिम्लिफिकेड ऑफ ए पोलिटिकल वर्ड 1840-1960' (कैंब्रिज, 1964) अध्याय 4 और 5 ।
139. लैंग्ली स्टीफन, लार्क ऑफ जे० एक० स्टीफन (लंदन, 1895) पृष्ठ 243, जे० एक० स्टीफन का दि टाइम्स को पत्र, 1 मार्च, 1883; उद्धृत मंडकाफ की पूर्वोद्धृत पुस्तक में, पृ० 318 देखें अध्याय 1 ।
140. देखें अध्याय 1 ।
141. जे० रट्टी, इंडिया (लंदन, 1888), पृ० 360 ।
142. पृ० 1868-79, LV, लोकसेवा में भारतीयों को लेने के विषय पर कागजात, पृ० 7 ।
143. सी० ट्रेवीलियन का भाषण, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक का कार्यविवरण, 7 मार्च, 1871, 'जर्नल ऑफ दि ई० आई० ए०,' जिल्द 5, भाग 2, सध्या 92, पृ० 108 और भाग 3, सध्या 100, पृ० 108 ।
144. रिचर्ड कासेब (1818-1899) एक विवादप्रिय व्यक्ति था । वह आपस्त कान्ते और बाथलेमी सेट हिलेरी का मित्र और लंदन में प्रत्यक्षवादी समाज (पाजिटिविस्ट सोसाइटी) का संस्थापक था (1855), सैन्य विद्रोह के तत्काल बाद प्रकाशित भारत के संबंध में उसकी पुस्तक का और मेरा ध्यान बर्नार्ड पोर्टर के ग्रंथ क्रिटिक्लिज ऑफ एपायर (मेकमिलन, 1968) ने आकर्षित किया था ।
145. दि इकॉनॉमिस्ट, 26 सितंबर, 1857, XV, 1062; डी० आर० मंडकाफ, 327 ।
146. एस० भट्टाचार्य ट्रेवीलियन, विस्सन, केनिंग एंड दि फाउंडेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल पालिसी बंगाल : पास्ट एंड प्रजेंट, जिल्द LXXX, 1961, पृ० 65-73 ।
147. सी० ट्रेवीलियन द्वारा मेमो०, 20 मार्च, 1860, पी० पी० एच० सी०, जिल्द 49 पृ० 112-21 ।
148. केनिंग से जे० विस्सन को, 24 जुलाई, 1860, ई० आई० बी०, II, 301 ।
149. टी० आर० मंडकाफ, पूर्वोद्धृत अध्याय 6 व 7 ।
150. बी० बी० मन्मदार, पूर्वोद्धृत, पृ० 318-36 ।
151. मंडकाफ, पूर्वोद्धृत, पृ० 160-62 ।
152. हिंदू रेंडिचट 21 फरवरी, 1870, 10 अप्रैल, 1871 ।

153. देखें अध्याय 5 ।

154. जो लोग भारत में ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के हितों के बारे में अतिरिक्त भाषा में सहज साधारणोक्ति करते हैं वे प्रायः अतिम बात की ओर ध्यान नहीं देते । यह उल्लेखनीय है कि कार्ल मार्क्स ने भारतीय साम्राज्य के विषय में ऐसा नहीं किया और उसने व्यक्तियों को मिलने वाले लाभों पर जोर दिया है । देखें मार्क्स, 'ब्रिटिश इनकम इन इंडिया, न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून, 21 सितंबर, 1857, आन कोलोनिअलिज्म (मास्को, 1867) । भारतीय वार्षिक राष्ट्रवाद के बारे में देखिए विरन चंद्र, पूर्वोद्धृत, अध्याय 1 ।

155. जी० पैग 'ग्रेट ब्रिटेन इनवेस्टमेंट्स इन अदर लैंड्स' जर्नल आफ दि रायल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, LXXIV, 1909, पृ० 456-80; 'ग्रेट ब्रिटेन कैपिटल इनवेस्टमेंट्स इन इंडो-विजुअल कंट्रीज एंड फारेन इंडस्ट्रीज,' वही, LXXXIV, 1911, पृ० 167-200 । सी० के० हाव्सन, 'दि एनमपोर्ट्स आफ कैपिटल (न्यूयार्क, 1914), सीलैंड एच० जेम्स, दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल टु 1875 (न्यूयार्क, 1927), (मैंने बाद के संस्करण, 1938 संस्करण का उपयोग किया है) । ए० के० केनकास, 'होम एंड फारेन इनवेस्टमेंट 1870-1913 (कैम्ब्रिज, 1958) । एच० सैंगल व एम० साइमन 'ब्रिटिश फारेन कैपिटल इन्पूज', 1865-94 जे० इ० एच०, दिसंबर, 1961, पृ० 567-81 । एम० साइमन 'दि पैटर्न आफ न्यू ब्रिटिश पोर्ट-फोलियो फारेन इनवेस्टमेंट 1865-1914' संपादक ए० आर० हाल, दि एक्सपोर्ट्स आफ कैपिटल फ्रॉम ब्रिटेन 1870-1914 (संस्करण, 1968) पृ० 15-44 । और भी आर० नर्त्स, 'पैटर्न्स आफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट' (स्टाकहोम, 1959), इतिहास लेखन की पुरानी परंपरा में एक कृति जो पूर्ण रूप से प्रासंगिक न होते हुए भी बहुत दिलचस्प है, आर० पेयर्स 'इकानामिक फैक्टर्स इन दि हिस्ट्री आफ दि एंपायर, दि हिस्टोरियस बिजनेस एंड अदर ऐंसेज (आक्सफोर्ड, 1961) ।

156. एम० साइमन पूर्वोद्धृत पृ० 28-30 ।

157. जेम्स, पूर्वोद्धृत 207, 225 ।

158. ए० आर० हाल, संपादक, दि एक्सपोर्ट्स आफ कैपिटल फ्रॉम ब्रिटेन 1870-1914, (संस्करण, 1968) पृ० 13 ।

159. जी० पैग, पूर्वोद्धृत, (1911) ।

160. एम० साइमन पूर्वोद्धृत, पृ० 23-25 ।

161. वही, पृ० 26 ।

162. जे० डब्ल्यू मैकफार्लैंड 'इनवेस्टमेंट इन इंडियन रेलवेज 1845-1875' इ० एच० आर०, VIII, एन० एस्०, 1955, पृ० 177-86 । डेनियल थोर्नर इनवेस्टमेंट इन एंपायर . ब्रिटिश एंड स्टीम शिपिंग एंटरप्राइज इन इंडिया 1825-49 (फिलाडेल्फिया, 1950) ।

163. देखें परिशिष्ट ।

164. जे० गालेघर व आर० इ० राबिंसन 'दि इंपीरियलिज्म आफ फ्री ट्रेड' इ० एच० आर०, VI, संख्या 1, 1953 । इस विषय पर हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं : पी हार्नेट्टी इंपीरियलिज्म एंड फ्री ट्रेड, सकाशायर एंड दि इंडियन काउंटन इयूटीज 1859-62; इ० एच० आर०, जिल्ड 18, एन० एस्०, 1965-66 और ए० ई० मूर इंपीरियलिज्म एंड फ्री ट्रेड





एतिहासिक ब्रिटिशों के उत्तरी भारत (अप्रकाशित) अध्ययन से उन्नीसवीं शताब्दी के परवर्ती काल में सिन्धु के विकास के बारे में नए तथ्य प्रकट होने की संभावना है। उत्तर उन्नीसवीं शताब्दी में मृत्युओं में परिवर्तन के विषय में ए० घोष और के० मुकुर्जी की कृतियों का उल्लेख इस पुस्तक में अन्यत्र किया गया है।

170. चार्ल्स वुड ने एल्मिन (25 जून, 1862, वुड कागजात, 10, पृ० 170) और फेर (2 अप्रैल, 1863, वुड कागजात, पृ० 12, 170) को अपने पक्षों में भारत में सूत तैयार करने वाली कंपनियों पर एक कर और उत्पादित सूती वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। जब सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि उसके लिए मेनचेस्टर के माल पर से आयात शुल्क कम कर पाना अथवा उसे हटा सकना संभव नहीं है तो अतः 1895 में भारतीय सूती वस्त्रों पर प्रतिरोधक (काउंटर वैलिंग) उत्पादन शुल्क लगाए गए। यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन शुल्क केवल मध्यम श्रेणी के वस्त्र पर जो मेनचेस्टर के माल से प्रति-योगिता करता था, लगाया गया था। प्रत्यक्ष करों के विषय में देखें अध्याय 4 और जे० पी० तियोनी, पूर्वोद्धृत; सैन्य व्यय के विषय में देखें अध्याय 3, बिना किसी आर्थिक उत्तरदायित्व के भारत में ब्रिटिश सेना रखने के लाभों के संबंध में देखें राबिन्सन, गालेघर, और डेनी पूर्वोद्धृत, पृ० 13। आइज़क वाट की पुस्तक 'दि आरिजिन एंड प्रोग्रेस आफ् दि काउन् सप्लाई एमोसिएशन' (मेनचेस्टर, 1871) में मेनचेस्टर के व्यापारियों और मिल मालिकों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से साम्राज्य के भीतर ही कपास के आपूर्ति स्रोत विकसित करने के प्रयत्नों का वर्णन मिलता है, देखें अध्याय 4।
171. कार्ल मैन्हीम, एसेज आन दि सोशियोलॉजी आफ् नालिज, संपादक पी कैस्केमेट्टी (लंदन, 1952) पृ० 148। निस्संदेह मैन्हीम का विश्वास था कि बुद्धिजीवी के लिए सैद्धांतिक ज्ञान से अपने आपको मुक्त कर पाना संभव है तथा ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। शूपीटर ने कही पर इसे 'मैन्हीम का रक्षा यंत्र कहा है। जिसे सामाजिक आत्मबोध की समस्या कहते हैं, उसके लिए देखें ओस्कार लुगागे, पोलिटिकल इकॉनामी (धारसा, 1963), अध्याय 7।

पालिसी इन इंडिया 1853-54 इक० एच० आर० XVII, एन० एम०, 1964-65 ।

165. पी० टी० नायर 'दि इकनामिक्स आफ रिजेंटमेट : कोलोनिअलिज्म एंड अडरडेवलपमेट जर्नल आफ कटोपेरेरी हिस्ट्री', जिल्द 4, सफ्या 1, जनवरी 1969, पृ० 51-72 ।
166. डी० के० फोल्डहाऊस 'इपीरियलिज्म : एन हिस्टोरियोग्राफीकल रिवीजन' 'इक० एच० आर०, जिल्द 14, एन० एम० सफ्या 2, 1961, पृ० 187-209, 'दि थिअरी आफ कैपीटलिस्ट इपीरियलिज्म (सदन, 1957) पृ० XIII-XIX, 187-94 । आर० ई० रोबिंसन, जे० ए० गालेघर व ए० डेनो, अफ्रीका एंड दि विक्टोरियन्स (सदन, 1961) पृ० 462 और आगे ।
167. डी० सी० एम० प्लाट, फाइनेंस, ट्रेड, एंड पोसिटिव्स इन ब्रिटिश फारेन पालिसी 1815-1915 (आक्सफोर्ड, 1968) पृ० 367 ।
168. साइमन कुजनेट्स, इकनामिक प्रोप एंड स्ट्रक्चर (सदन, 1966) पृ० 50-51 । कुजनेट्स का यह तर्क है कि जिन देशों में तेजी के साथ विकास हुआ है उनमें कुछ बाध्यकर तत्व बहा की विस्तारक एवं उत्साही प्रवृत्तियों के कारण हैं । अन्य तत्वों में आधारभूत तत्व यह है कि जब भी उम क्षेत्र का विस्तार होता है, जिस पर उस देश के आर्थिक स्रोतों का बाहरी स्रोतों, विशेषकर प्राकृतिक अथवा कुछ अन्य स्रोतों के साथ उपयुक्त अनुपात में प्रयोग कर पाना संभव होता है तो प्रति इकाई उत्पादन का स्तर ऊंचा उठने और आर्थिक विकास संबंधी जोखिम कम होने की संभावना रहती है । आर्थिक विकास एक जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है । व्यक्तिगत फर्म की दृष्टि से इसका अर्थ ऐसी प्रतिबद्धता हो सकता है जिसे वह सहज ही पूरा कर पाने में असमर्थ हो और देश के पहलू से इस प्रक्रिया में ऐसे विक्षेपीकरण और उन साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है जो देश की सीमा के भीतर उपलब्ध न हों । किसी भी तेजी के साथ विकासशील देश के नेता राज्य की शक्ति की सहायता से अपने देश की सीमा के बाहर कच्चे माल अथवा बाजार की पक्की व्यवस्था कर इस प्रकार के जोखिमों को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं । आर्थिक विकास के सिद्धांत पर एक लेख में कुजनेट्स की उपर्युक्त उक्ति निश्चय ही व्यापक अर्थ में है । विशिष्ट रूप से ब्रिटेन के संदर्भ में प्लाट का कहना है ' 'वैदेशिक नीति का प्रधान कार्य सदैव ही राष्ट्रीय सुरक्षा था । परंतु बाजारों तक पहुंच और इन बाजारों में व्याप पाना इंग्लैंड की दृष्टि से ऐसा हित था जिसका स्थान प्राथमिकता की दृष्टि से राष्ट्रीय व साम्राज्यिक सीमाओं की रक्षा के ठीक बाद में होने के साथ-साथ उससे घनिष्ठ रूप से संबद्ध भी था । ' प्लाट, पूर्वोक्त स्थल । इस बात पर वे लोग प्रायः ध्यान नहीं देते जो राजनीतिक तत्वों को अलग से देखते हैं । दूसरी ओर, साम्राज्यिक विस्तार जैसी जटिल समस्या का केवल बाजार, कच्चे माल, पूंजी निवेश के लिए अवसर इत्यादि की आवश्यकता के रूप में विश्लेषण करना भी समान रूप से व्यर्थ प्रयास है । ।
169. डेनियल एंड एलिस थोर्नर 'वी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया 1881-1931' लेड एंड लेबर इन इंडिया (नवंबर, 1962) । एम० डी० मौरिस 'टुवर्ड ए रिइटरप्रिडेशन-आफ नाइटीय सेचुरी इंडियन इकनामिक हिस्ट्री' जे० इक० एच०, 23 (1963) पृ० 606-18 । के० एन० चौधरी, इंडियाज इंटरेनशनल इकनामी इन दि नाइटीय सेचुरी : एन हिस्टोरिकल सर्वे 'माइनिंग एंड मैन स्टडीज', II, 1, (1968) पृ० 31-50 । एम० के० धाराराज 'पब्लिक इन-वेस्टमेट इन इंडिया 1868-1914', इंडियन इकनामिक रिव्यू, II, 4, (1955) । डा०

एतिहासिक दृष्टिकोण के उत्तरी भारत (अप्रकाशित) अध्ययन से उन्नीसवीं शताब्दी के परवर्ती काल में सिंचाई के विकास के बारे में नए तथ्य प्रकट होने की संभावना है। उत्तर उन्नीसवीं शताब्दी में मूल्यों में परिवर्तन के विषय में ए० घोष और के० मुकुर्जी की कृतियों का उल्लेख इस पुस्तक में अन्यत्र किया गया है।

170. चास्सॅ वुड ने एस्मिन (25 जून, 1862, वुड कागजात, 10, पृ० 170) और फ्रें (2 अप्रैल, 1863, वुड कागजात, पृ० 12, 170) को अपने पक्षों में भारत में सूत तैयार करने वाली कैंक्ट्रियों पर एक कर और उत्पादित सूती वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। जब सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि उसके लिए मेनचेस्टर के माल पर से आयात शुल्क कम कर पाना अथवा उसे हटा सकना संभव नहीं है तो अतः 1895 में भारतीय सूती वस्त्रों पर प्रतिरोधक (काउंटर वैलिंग) उत्पादन शुल्क लगाए गए। यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन शुल्क केवल मध्यम श्रेणी के वस्त्र पर जो मेनचेस्टर के माल से प्रति-योगिता करता था, लगाया गया था। प्रत्यक्ष करों के विषय में देखें अध्याय 4 और जे० पी० नियोगी, पूर्वोद्धृत; सैन्य व्यय के विषय में देखें अध्याय 3; बिना किसी आर्थिक उत्तरदायित्व के भारत में ब्रिटिश सेना रखने के साधनों के संबंध में देखें राबिन्सन, गालेघर, और डेनी पूर्वोद्धृत, पृ० 13। आइजक बाट की पुस्तक 'दि आरिजिन एंड प्रोग्रेस आफ् दि काउंटर सप्लाई एसोसिएशन' (मेनचेस्टर, 1871) में मेनचेस्टर के व्यापारियों और मिल मालिकों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से साम्राज्य के भीतर ही कपास के आपूर्ति स्रोत विकसित करने के प्रयत्नों का वर्णन मिलता है, देखें अध्याय 4।

171. कार्ल मैन्हीम, एसेज आन दि सोशियोलॉजी आफ् नेशनलिज्म, संपादक पी कैस्केमेटी (लंदन, 1952) पृ० 148। निस्संदेह मैन्हीम का विश्वास था कि बुद्धिजीवी के लिए सैद्धांतिक भ्रांति से अपने आपको मुक्त कर पाना संभव है तथा ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। शूपीटर ने कही पर इसे 'मैन्हीम का रक्षा यंत्र कहा है। जिसे सामाजिक आत्मबोध की समस्या कहते हैं, उसके लिए देखें ओस्कार लांगे, पोलिटिकल इकॉनॉमी (बारसा, 1963), अध्याय 7।

## मितव्ययतापरक

### कुशलता की दिशा में

भारतीय साम्राज्य के राजस्व-प्रवध के विषय में लिख पाना सहज नहीं है। भारतीय साम्राज्य पर शासन करने वाली सरकार की नीतियों के विषय में इतना अधिक लिखा जा चुका है कि एक अन्य प्रयास अनावश्यक माना जा सकता है। फिर भी इस विषय पर अगर और निरंतर बढ़ते हुए साहित्य के सतक विचार्यों से यह छिपा नहीं रह सकता कि इस साहित्य में अभी भी अनेक रिक्तियाँ हैं। अध्ययन के जिन कुछेक क्षेत्रों में बहुत कार्य हो चुके है, उनमें काम करने पर सीमांत उपलब्धि हासमान हो सकती है, परन्तु अब भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन में कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि ब्रिटिश भारत के लोकवित्त के इतिहास की ओर वांछित ध्यान क्यों नहीं दिया गया। प्रायः अस्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर आधारित पृथक-पृथक असंख्य प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों की मारफ्त वित्तीय नीति की प्रगति का अध्ययन कठिन कार्य है। इस कार्य की ओर बहुत थोड़े लोगों ने रुचि दिखाई है। इसके अलावा अनेक तथ्य, एंग्लोइंडियन दफ्तरी भाषा में यह कहा जाएगा कि उपलब्ध नहीं थे। बहुत सारे आंकड़े जो अब अभिलेखागार में उपलब्ध हैं और निर्णयकर्ता अनेक उच्चाधिकारियों के निजी कागजात कुछ समय पहले तक प्राप्य नहीं थे। इन लोगों के विरल और कभी-कभी भ्रामक सांवाञ्जनिक वक्तव्यों और भारतीय राजस्व के मात्र ढाँचा संबंधी अल्प परिमाणामक आंकड़ों का अपर्याप्त आधार बनता था जिससे केवल विवाद-प्रिय लोगों तथा नौकरशाहों को ही सतोष हो सकता था, जो यथार्थ की खोज में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे जितनी कि बिब में। अपूर्ण ज्ञान की धुंध में, जिसमें कभी-कभी आत्मप्रवंचना का मिश्रण भी होता था, अध अस्वीकृति अथवा दिनयपूर्ण स्वीकृति दो ऐसे दृष्टिकोण थे जो प्रायः साथ-साथ देखे जा सकते थे, परन्तु कभी-कभी उनमें विरोध भी होता था। साम्राज्य और उसकी वित्तीय प्रणाली के आलोचकों और समर्थकों दोनों को ही जिस प्रकार प्रेक्षकों की प्रतिक्रिया ने खतरनाक ढंग से प्रभावित किया है और आगे भी कर सकती है, उसे विद्वानों की वस्तुनिष्ठता जिस पर उन्हें काफी गर्व होता है, समाप्त हो जाती है और वे एक दूसरी महत्वपूर्ण भूल कर बैठते हैं। इस क्षेत्र में अस्पष्ट एवं दुर्बोध हो जाना बहुत सरल किंतु जोखिम भरा है। यदि ऐतिहासिक अनुभव सरल और सगत नहीं है, और यदि आनुभविक तथ्यों की जटिलता भयावह और निराशाजनक है, तो यह हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति इस परिकल्पना का आश्रय लेने लगे कि घटना-क्रम अस्तव्यस्तता एवं सभ्रम की घेतरतीव प्रक्रिया है जिसमें अप्रत्याशित

घटनाओं से बाधा पड़ती है और जिसकी अव्यवस्था कभी-कभी कुछ महापुरुषों की प्रतिभा द्वारा कम हो जाती है। इस विचारधारा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि इतिहासकार किसी निश्चित प्रवृत्ति को खोज करता है तो वह कर्तव्य विमुख होता है। इस विचारधारा का आकर्षण कुछ संदिग्ध है और हमें इस संवध में आगे उस समय विचार करना होगा जब इसके द्वारा या तो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकेंगे अथवा कुछ प्रश्न उठाए ही नहीं जा सकेंगे।

भारत में ब्रिटिश वित्तीय नीति की व्याख्या से संबंधित समस्या के प्रति ये विभिन्न प्रतिक्रियाएं सौ वर्ष पहले भी देखी जा सकती थी। सैन्य विद्रोह के बाद के दशक में लोकवित्त की समस्याओं पर जन साधारण ने इतना ध्यान दिया जितना पहले कभी नहीं दिया था। सैन्य विद्रोह के वित्तीय परिणाम संभवतः उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि राजनीतिक और प्रशासनिक सैन्य विद्रोह ने वित्तीय संकट को जन्म दिया। सेना, सैन्य पुलिस, नई सैनिक भर्ती और पुलिस व सैनिक लोक निर्माण पर वार्षिक व्यय 13.2 करोड़ रुपये (1856-57) से 17.2 करोड़ रुपये (1857-58) और फिर 24.7 करोड़ रुपये (1858-59) हो गया। इसी अवधि में भारत सरकार के ऋणों में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सैन्य विद्रोह से अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट में घाटा रहा। वित्त मंत्री ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि चांसलर आफ एक्सचेंजर राबर्ट लोथी 'ऐसा जंतु है जिसे आधिक्य मिलना ही चाहिए।' इस उक्ति से बजट संतुलित रखने की चिंता जो ग्लैंडस्टोन युग की विशेषता थी, सही-सही प्रकट होती है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो स्पष्ट है कि सैन्य विद्रोह के बाद के वर्षों में भारत सरकार की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक थी। यथार्थ में वित्तीय संतुलन जैसा कि उसे प्रायः कहा जाता था, भारतीय साधनों पर असामान्य मांगों के कारण सदैव अनिश्चितता की स्थिति में रहा था। इस तथ्य पर ध्यान देना काफी सूचनाप्रद है कि सैन्य विद्रोह से पहले साम्राज्य विस्तार का काल लगभग वही काल है जिसमें भारत सरकार के बजट घाटे के थे। 1814-19 की अवधि में बजट घाटे के थे। और यही नेपाल युद्ध और मराठा युद्ध का काल था। इसी प्रकार 1823-28 की अवधि में पहला बर्मा युद्ध और भरतपुर की घेराबंदी हुई, 1838-48 की अवधि में अफगान युद्ध, सिंध एवं ग्वालियर युद्ध तथा सिक्खों के साथ युद्ध हुए और 1853-55 द्वितीय बर्मा युद्ध का काल था। सैन्य विद्रोह के दौरान और बाद में सैनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि से संकट उत्पन्न हो गया। स्थिति पर टिप्पणी करते हुए जेम्स विल्सन ने, जिससे सैन्य विद्रोह के उपरांत उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्या के समाधान की आशा की गई थी, कहा कि 'आपतकाल में ही सुधार कर सकना संभव होता है। इस समय ऐसी ही आपतकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब वे सुधार एवं परिवर्तन किए जा सकते हैं जो पहले नहीं हुए हैं।'¹

जेम्स विल्सन (1805-60), जो एक ऊनी वस्त्र निर्माता का पुत्र था, सोलह वर्ष की आयु से ही व्यवसाय में लगा हुआ था। उसने 1844 में सफल व्यावसायिक जीवन-वृत्ति से अवकाश ग्रहण किया और फिर 1847 से 1857 तक वह वेस्टवरी और 1857 से 1859 तक डेवनपोर्ट से संसद सदस्य (एम० पी०) रहा। जब वह बोर्ड आफ कंट्रोल

का संयुक्त सचिव (ज्वाइंट सेक्रेटरी) (1848-52) था तो उसे भारतीय मामलों का थोड़ा-सा अनुभव हुआ। संयोग से इसी समय उसने भारत में रेलों के निर्माण के संगठन में महत्वपूर्ण भाग लिया। जब वह ट्रेंजरी का फाइनेंस सेक्रेटरी (1853-58) तथा बोर्ड आफ ट्रेड का वाइस प्रेसीडेंट (1859) था तब उसे वित्तीय मामलों से संबंधित उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उसे वाणिज्यिक मामलों के व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ सम-कालीन आर्थिक सिद्धांत की अच्छी समझ थी। वास्तव में इंग्लैंड में उसकी ख्याति लंदन के प्रसिद्ध इकानोमिस्ट के (1843) योग्य सस्थापक-संपादक के रूप में थी और उसे प्रधानतः इसी के लिए स्मरण किया जाता था। इस पत्र की स्थापना कोवडन की सहायता से 'अबाध व्यापार आंदोलन को बौद्धिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।'<sup>2</sup> कार्न ला विवाद पर इन्प्लुएंस आफ दि कार्नसाज नामक पंप्लेट के अतिरिक्त विल्सन ने करेंसी समस्या पर भी प्लक्चुरेशस आफ करेंसी तथा कंपीटल, करेंसी एंड बैंकिंग (1847) नामक लेखों में ध्यान दिया।<sup>3</sup> तथाकथित बैंकिंग विचारधारा को (बैंकिंग स्कूल) का सदस्य होने के कारण विल्सन ने इकानोमिस्ट<sup>4</sup> में करेंसी विचारधारा (करेंसी स्कूल) की आलोचना की थी। विल्सन 1844 के बैंकिंग ऐक्ट का आलोचक था, परंतु बाद में उसने इसे अपनी भारतीय पत्र-मुद्रा संबंधी योजना की रूपरेखा के रूप में प्रयोग किया।<sup>5</sup> सर सी० वुड के आग्रह पर विल्सन ने गवर्नर जनरल की परिपद में वित्तीय सदस्य का पद स्वीकार कर लिया। उसने परिपद की सदस्यता 29 नवंबर 1859 को ग्रहण की। 11 अगस्त 1860 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने इसी अल्प समय में भारतीय वित्त व्यवस्था के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। वित्तीय मामलों से संबंधित उसके अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। उसकी वजह और आयकर संबंधी योजनाएं उसके इंग्लैंड के अनुभवों पर आधारित थी।<sup>6</sup> विल्सन पर अनेक लोगों ने जिनमें सर सी० ट्रेवीलियन भी था, यह आरोप लगाया है कि वह बहुत अधिक सिद्धांतवादी था और उसने भारतीय परिस्थितियों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी।<sup>7</sup> किंतु विल्सन का जीवनी लेखक बेजहाट लिखता है कि विल्सन को आशका थी कि 'अधिकांश सभ्य देशों में मान्य प्रशासन विज्ञान की भारत में अवहेलना होगी... यद्यपि लोगों को धीरे-धीरे अर्थ विज्ञान के रास्ते पर ले ही जाना था तो भी यह उनके ऐतिहासिक पूर्वचरित से उत्पन्न विचारों तथा भावनाओं का बहुत लिहाज करना चाहता था।'<sup>8</sup> उसके व्यक्तित्व की इस दूसरी विशेषता का एक उदाहरण यह है कि उसने इस विचार-धारा की पुष्टि के लिए विशेष प्रयास किया कि आयकर मनु संहिता में सहितावद्ध हिंदू-विधि के अनुरूप है।<sup>9</sup> उसके संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए ट्रेवीलियन ने कहा है कि 'विल्सन ने नवीन भारतीय वित्तव्यवस्था की नींव डाली थी।'<sup>10</sup> उसे भारत में लोगों का पूरी तरह विश्वास प्राप्त था।<sup>11</sup> इंग्लैंड में उसके प्रति आस्था का सबसे अधिक विश्वासीत्पादक प्रमाण उसकी मृत्यु के बाद मिला। प्रमाण यह था कि जैसे ही उसकी मृत्यु का समाचार इंग्लैंड पहुंचा भारत निधि की कीमते तत्काल गिर गई।<sup>12</sup>

हेनरी वार्टिल फेर (1815-84) ने विल्सन की मृत्यु के बाद छः मास से अधिक

समय तक गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यवाहक वित्त सदस्य का कार्य किया। फ़ेर की शिक्षा हेलीबरी में हुई थी। वह एक योग्य आई० सी० एस० अफसर था और उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य के रूप में (1859-62) हुई। बाद में वह बंबई का गवर्नर (1862-67) बनाया गया।<sup>13</sup> विल्सन ने मृत्युशय्या पर से फ़ेर को 'उसके अधूरे कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर पूरा करने का आग्रह किया था।'<sup>14</sup> फ़ेर के अनुसार विल्सन की योजनाएं बड़ी लंबी-चौड़ी थीं और वह अनुभव करता था कि 'उन्हें पूरा करना किसी भी एक मनुष्य के बल के बाहर की बात है।'<sup>15</sup> उसके विचार से 'यदि हड़बड़ी नहीं की जाती तो गति को तेज़ रखा जा सकता था।'<sup>16</sup> सैद्धांतिक योजनाओं में उसे नौकरशाहों की तरह अविश्वास था और उसकी आस्था कठिन परिश्रम और 'कोल्हू के बल की भांति उपयोगी काम' में थी। उसने बुद्ध को लिखा था कि 'अपने को उलझन से बचाने के लिए आप लेखे और सैकड़ों बारीकियों के साथ नियमित रूप से अच्छा प्रबंध ही चाहते हैं।'<sup>17</sup> फ़ेर के इस विचार की ओर ध्यान देना सार्थक होगा, क्योंकि यह भारत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों के प्रति नौकरशाही के विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो यहां पर ब्रिटिश विचारों और सत्ताओं को लाना चाहते थे। नवीनता के प्रति नौकरशाही के निष्क्रिय विरोध का ही यह परिणाम हुआ कि आधुनीकरण की अनेक प्रेरक शक्तियां असफल तथा व्यर्थ सिद्ध हुईं।

विल्सन के उत्तराधिकारी सेमुअल लैंग (1812-97) के पास यद्यपि विल्सन जैसी वित्त संबंधी राजनीतिमत्ता नहीं थी फिर भी वह वित्त सदस्य के रूप में असफल नहीं रहा। उसके बोर्ड आफ़ ट्रेड संबंधी अनुभव और रेलों के प्रबंध से संबंधित व्यावहारिक अनुभव उपयोगी थे। इसके अलावा वह 1852 से 1857 तक और फिर 1859 में पार्लियामेंट का भी सदस्य रहा था।<sup>18</sup> लैंग इस दृष्टि से भाग्यशाली था कि उसके कार्यकाल के प्रथम वर्ष (1861-62) में बजट में बहुत थोड़ा घाटा हुआ। उसने 1862-63 का भी बजट तैयार किया था। 1862 के अंत में वह भारत से वापस चला गया। उस वर्ष बजट में 18 लाख पांडा का आधिक्य था। बजट में यह आधिक्य प्रधानतः अफीम से भारी आय और सैनिक वित्त आयोग के द्वारा व्यय में कटौती के कारण था। टैरिफ़ में कमी करने के कारण लैंग व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय था।<sup>19</sup> उसका भारतमन्त्री से अनेक बार झगड़ा हुआ। इस संबंध में हम आगे स्पष्ट करेंगे।

चार्ल्स ऐडवर्ड ट्रेवीनियन (1807-88) की भी शिक्षा हेलीबरी में हुई थी। उसने बहुत लिखा है। संभवतः गवर्नर जनरल की परिषद के वित्त सदस्यों में वह सबसे अधिक प्रतिभा मंजून था, यद्यपि कुछ अन्य लोग वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों के रूप में अधिक योग्य सिद्ध हुए। लोगों का विश्वास था कि वह मनबहुलाय के लिए अधिकृत रिपोर्टों को पढ़ा करता था। मकाले ने उसे 'वास्तविक प्रतिभा से मंजून व्यक्ति' माना है—'वह 100<sup>०</sup> पूर्वी देशांतर के किसी भी व्यक्ति के लिए चुरा आदमी नहीं था।' भारत में राजसेवा के सफल कार्यकाल (1826-40) के बाद जब वह इंग्लैंड लौटा तो 1840 से 1857 तक ट्रेजरी का असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा।<sup>20</sup> इंग्लैंड में सिविल सेवा की भर्ती की प्रणाली से संबंधित जांच कार्य में वह नॉर्थकोट का सहयोगी था।

जिस समय वह मद्रास का गवर्नर (1859-60) था उसका वित्तीय शक्तियों के केंद्रीकरण के प्रश्न पर विल्सन के साथ झगडा हो गया। जब वह वित्त सदस्य (1862-65) था तो प्रायः उसका भारतमंत्री के साथ मतभेद रहता था और एक बार तो उसके वजट और कर संबंधी प्रस्तावों को पूरी तरह बदल दिया गया। 1864 में फ्रेंड आफ इंडिया ने लिखा था कि ट्रेंवीलियन को 'वाणिज्य और व्यापारिक समुदाय के प्रति सक्रिय सहानुभूति नहीं थी।' <sup>21</sup> 1865 में जब ट्रेंवीलियन ने चाय और जूट सहित कच्चे माल पर निर्यात शुल्क का प्रस्ताव रखा तो समस्त व्यापारिक समुदाय उसके विरुद्ध हो गया। <sup>22</sup>

डब्ल्यू० एन० मैसी (1809-81) ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। वह 1855 से 1863 तक संसद सदस्य रहा था। उसकी संसदीय राजनीति (पार्लियामेंट में) में भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी। <sup>23</sup> वह 1865 में भारत आया। हम आगे स्पष्ट करेंगे कि मैसी के समय में (1865 से 1868 तक) वजटों में लगातार घाटा चला। उसे सामान्य योग्यता का व्यक्ति माना जाता था और लोग उसे अकर्मण्य एवं निरुद्यमी समझते थे। <sup>24</sup>

उसका उत्तराधिकारी रिचर्ड टैपिल (1826-1902) भारतीय सिविल सेवा से आया था वित्त मंत्री के रूप में ऐसा योग्य नहीं था जिसकी ओर ध्यान जाए। 1860 में वह विल्सन का सहायक नियुक्त हुआ था। उसने विल्सन को मेरा स्वामी कह कर संबोधित किया है। कालांतर में उसे एक योग्य प्रशासक के रूप में ख्याति मिली। <sup>25</sup> वह दीर्घ काल तक (1868-74) वित्त सदस्य रहा। वह गवर्नर जनरल मेयो के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर सका। <sup>26</sup> टैपिल ने मेयो की वित्तीय विकेंद्रीकरण की योजना को समर्थन नहीं दिया और मेयो को टैपिल द्वारा की गई आय कर व्यवस्था दोषपूर्ण लगी। टैपिल की इस व्यवस्था का बहुत विरोध तथा आलोचना हुई थी। <sup>27</sup> जुलाई 1870 में मेयो ने आरगाइल को लिखा था, 'मुझे विश्वास नहीं है कि यह (टैपिल) विश्व की दृष्टि में वह स्थान पा सकेगा जो इस प्रकार के साम्राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मंत्री को मिलना चाहिए'... 'क्योंकि उसके पास न तो वित्तीय मामलों का वैसा ज्ञान है और न ही समस्याओं के समाधान हेतु उपाय खोजने की सामर्थ्य है जो परिपद की परामर्श देने के लिए उसके पास होनी ही चाहिए'... <sup>28</sup> मेयो ने टैपिल से छुटकारा पाने के उद्देश्य से उसे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव रखा था। <sup>29</sup> आरगाइल टैपिल को मद्रास की गवर्नरी देना चाहता था। <sup>30</sup> परंतु टैपिल का स्थान ग्रहण करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सका। आरगाइल के विचार से इस पद के लिए भारतीय सिविल सेवा का कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं था। उसने स्टेफर्ड नार्थकोट को वित्त सदस्य का पद स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया, परंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली, <sup>31</sup> तथा परिपद और समाचार पत्रों में निरंतर आलोचना के बावजूद टैपिल गवर्नर जनरल की परिपद में वित्त सदस्य बना रहा।

वित्त संबंधी विषयों के बारे में जान स्ट्रैची (1823-1907) मेयो के विश्वासपात्र





सरकारी सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद) लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी और वित्तीय मामलों में उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित थी। भारत मंत्री का भारत सरकार पर पूर्ण वित्तीय नियंत्रण था। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1885 द्वारा सपरिषद भारत मंत्री के हाथ में वित्तीय नियंत्रण और इसकी छानबीन का काम सिमट आया था। इंग्लैंड और भारत के बीच संचार व्यवस्था में जैसे ही सुधार हुआ भारतमंत्री ने शासन पर अपने नियंत्रण को और अधिक कस दिया। (संचार तकनीक और शक्ति वितरण एवं प्रयोग में संबंध और इसके फलस्वरूप, विशेष रूप से, जिला अधिकारी की शक्तियों में कमी और भारत सरकार पर गृह अधिकारियों के नियंत्रण में वृद्धि ऐसी समस्या है जिसका विस्तार के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए) 1858 के अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए वह प्रत्येक वर्ष पार्लियामेंट में वित्तीय स्थिति पर वक्तव्य देता था, परंतु इन वक्तव्यों पर शायद ही कभी ध्यान दिया गया हो।

बिस्मार्क की प्रिय भाषा में आर्थिक कार्यकुशलता पर जोर देने का भी अर्थ यही था कि भारत में वित्तीय शक्तियों के केंद्रीयकरण के कुछ न कुछ उपाय किए जाने चाहिए। 1858 से 1861 तक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति रही और इस मामले को लेकर ट्रैवीलियन तथा बिस्मार्क में मिश्रित हो गई। उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में विकेंद्रीकरण की विविध योजनाओं पर विचार किया गया। सेमुअल लैंग, डब्ल्यू० एम० मैसी तथा कर्नल आर० स्ट्रैची ने विविध योजनाओं के प्रस्ताव रखे। परंतु गवर्नर जनरल लारेस विकेंद्रीकरण का कट्टर विरोधी था, और 1867 में विकेंद्रीकरण की सभी योजनाएं ताक पर रख दी गईं। मेयो ने विकेंद्रीकरण के विचार को पुनर्जीवित किया। उसका विश्वास था कि वित्त के विकेंद्रीकरण के द्वारा (क) सर्वोच्च सरकार और प्रांतीय सरकारों के संबंधों में सुधार होगा, (ख) स्थानीय सुधार यथासंभव स्थानीय कराधान द्वारा किए जा सकेंगे, (ग) सर्वोच्च सरकार के लिए उन व्ययों से छुटकारा पाना संभव होगा जिन्हें केवल स्थानीय सरकारें ही प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित कर सकती हैं, तथा (घ) सरकार के लिए स्थानीय एवं म्युनिसिपल स्तर पर प्रशासन के उत्तरदायित्वों को भारतीयों के साथ बांटना संभव होगा और इससे यहाँ के लोगों को उपयोगी राजनीतिक प्रशिक्षण मिल सकेगा। 1871-72 में मेयो की वित्तीय हस्तांतरण योजना को लागू कर दिया गया। यद्यपि मेयो की योजना में बहुत सारे दोष थे, तथापि भारत के वित्तीय इतिहास में यह एक युगांतरकारी घटना थी।

अस्तु, सगठनात्मक स्तर पर आर्थिक कार्यकुशलता के लिए प्रयत्न किया गया, हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली। सरकार की स्थिति संपन्न नहीं थी। वास्तविकता यह है कि 1862-64, 1865-66 तथा 1870-72 के वर्षों को छोड़कर इस अध्ययन की अवधि के अन्य सभी वित्तीय वर्षों के तलपट (बैलेंस-शीट) से घाटे ही प्रकट होते हैं। आम पक्ष में मालगुजारी और अफीम सबसे अधिक महत्वपूर्ण मदें थी। कुल आय में मालगुजारी का भाग 40 प्रतिशत से अधिक और अफीम का 15 प्रतिशत से अधिक था। वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर तीन थे : औसतन कुल आय में नमक कर का योगदान 10 प्रतिशत, उत्पादन शुल्क का भाग 5 प्रतिशत और सीमा शुल्क से प्राप्ति 5 से

9 प्रतिशत तक थी। आय पर कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियां कुल आय का नगण्य भाग थी। आय की अनेक मदें (स्टाप, टकसाल, पोस्टऑफिस, तार, लोक-निर्माण, कोर्ट फीस आदि) ऐसी थीं जिनकी प्रकृति सरकार के अनुसार विशिष्ट लाभ-राजस्व की थी। व्यय पक्ष में, सेना तथा लोक निर्माण पर होने वाले व्यय कुल व्यय के क्रमशः लगभग 33 और 15 प्रतिशत थे। कुल व्यय का एक-तिहाई से अधिक इंग्लैंड तथा भारत में प्रशासन पर किया जाने वाला व्यय होता था। व्याज के रूप में भुगतान कुल समस्त व्यय का 10 प्रतिशत था।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक सरकार की भूधृति नीति (लैंड टेन्योर पालिसी) का स्वरूप निश्चित हो गया था। भूराजस्व (मालगुजारी) प्रशासन और नीति संबंधी महत्वपूर्ण विवाद तथा प्रयोग अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के बाद के वर्षों में और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के प्रारंभिक वर्षों में हुए थे। एकमात्र महत्वपूर्ण मामला जो तय नहीं हो सका था, वह स्थाई बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त के क्षेत्रों में लागू करने का प्रश्न था। इसके अतिरिक्त मालगुजारी के परिशोधन तथा बेकार भूमि की बिक्री से संबंधित कुछ अन्य समस्याएं भी थीं। 1862 में मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया गया। जिन प्रयोजनों एवं उद्देश्यों ने सरकार को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया उनमें से कुछ उल्लेखनीय प्रयोजन थे—रैयत की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना (यह कर्नल बर्डे स्मिथ का सुझाव था), संपत्ति के पूर्ण सृजन द्वारा सरकार के प्रति लोगों के मन में निष्ठा उत्पन्न करने की इच्छा, भूमि में पूंजी के निवेश को हतोत्साहित करने वाले तत्वों को समाप्त करने की इच्छा। यद्यपि स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था तथापि अधिकारी इस प्रकार के बंदोबस्त के लाभों के बारे में पुनर्विचार करने लगे थे। छठे दशक के मध्य से स्थाई बंदोबस्त में आस्था कम होने लगी थी। यह अनुभव किया गया कि मालगुजारी का स्थाई रूप से निर्धारण सरकार के लिए घाटे का सौदा रहेगा। सरकार के लिए कृषि संपत्ति (ऐसी संपत्ति जिसके विषय में मान्यता थी कि वह स्थाई बंदोबस्त द्वारा उत्पन्न होगी) पर कर लगाने के लिए कराधान की व्यवस्था विकसित कर पाना और स्थाई बंदोबस्त हो जाने पर आय की हानि को अन्य स्रोतों से पूरा कर पाना कठिन था। भूमि की कीमत में तेजी के साथ वृद्धि और रुपये के मूल्य में ह्रास ने भी सरकार को हतोत्साहित किया। सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत उत्सुक थी। अतः पहले स्थाई बंदोबस्त की दिशा में निर्णय स्थगित कर दिया गया और 1883 में स्थाई बंदोबस्त को और अधिक क्षेत्रों में लागू करने का विचार विधिवत त्याग दिया गया।

मालगुजारी के बाद आय की मदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अफीम थी। फसल की अप्रत्याशित स्थिति और बाजार में अनिश्चितता के कारण अफीम से होने वाली आय में घटा-वृद्धि की प्रवृत्ति के बावजूद हमारे अध्ययन की अवधि में इस स्रोत से आय में अनवरत वृद्धि हुई है। जब छठे दशक में चीन में अफीम का उत्पादन तेजी से बढ़ा तो वहां के बाजार में प्रतियोगिता का थोड़ा भय हो गया था, परंतु इससे अफीम से होने वाली आय पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि भारत सरकार का मालवे की अफीम (जिस

पर बंबई में पारगमन शुल्क लिया जाता था) के उत्पादन से कोई संबंध नहीं था, तथापि बंगाल के प्रेसीडेंसी में अफीम के उत्पादन से सरकार का घनिष्ठ संबंध था। अफीम-व्यापार से सरकार के संबंधों के विरोध में इंग्लैंड में आंदोलन चला, परंतु भारत सरकार के लिए अफीम से होने वाली आय को छोड़ सकना संभव नहीं था। अतः उसने अफीम विरोधी समाज द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

भारत सरकार की सीमा शुल्क नीति (टैरिफ नीति) भारत और इंग्लैंड के बीच श्रम विभाजन पर आधारित लगती है। इस व्यवस्था में भारत को कच्चे माल की आपूर्ति और इंग्लैंड को औद्योगिक उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी थी। यह एक विवादरहित तथ्य था कि सीमा शुल्कों का स्वरूप संरक्षणारमक नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन के उत्पादक वर्ग भारतीय सीमा शुल्क नीति पर विशेष ध्यान रखते थे। यह समझ में आने वाली बात है। क्योंकि, उदाहरण के लिए, लकड़ायर अपने वस्त्रों के कुल उत्पादन का एक-तिहाई भारत को निर्यात करता था। वित्तीय कारणों से ब्रिटिश आयातों पर सभी आयात शुल्कों को समाप्त कर सकना संभव नहीं था, परंतु उन्हें यथासंभव नीचा रखा गया था। भारतीय कच्चे माल पर निर्यात-शुल्क नीचे रखे गए थे। 1860-61 में भारत के 28.1 प्रतिशत निर्यात वस्तुओं के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में (मूत, सिल्क, ऊन एवं जूट) थे। 1870-71 में इनका भाग बढ़ कर 43.3 प्रतिशत हो गया। 1860-61 में कुल आयात में सूती वस्तुओं का भाग 39.63 प्रतिशत था। 1870-71 में सूती वस्तुओं का भाग बढ़ कर 49.82 प्रतिशत हो गया।

नमक शुल्क जो वस्तुतः सबसे कम आय वाले वर्गों पर व्यक्ति कर (पोल टैक्स) था, सरकार की आय का ऐसा स्रोत था जिसमें वरावर वृद्धि हो रही थी। शुल्क की दरों को धीरे-धीरे ऊंचा उठाया गया। इस नीति को इस आधार पर युक्तिसंगत ठहराया गया कि पूरे भारत में शुल्क की दरों को समान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है जिससे अततः देश के भीतर सीमा शुल्क अवरोधों को हटा सकना संभव होगा। आय-कर तथा अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष कर अधिक आय वाले वर्गों पर लगाए गए थे, परन्तु वे प्रत्याशित आय जुटा पाने में असफल रहे।

भारत सरकार के खर्चों में अनवरत वृद्धि हो रही थी। ऐसा आंशिक रूप से समस्त भारत में कीमतों और मजदूरियों में होने वाली वृद्धि के कारण और आंशिक रूप से श्रेष्ठ प्रशासन के लिए मांग के फलस्वरूप था। कुछ मदों में (जैसे, विधि एवं न्याय) पर बढ़ा हुआ खर्च न्यायसंगत था। परंतु शिक्षा व लोक स्वास्थ्य पर व्यय बहुत थोड़ा था। भारत और विशेष रूप से इंग्लैंड में लिए गए ऋणों के व्याज का भार सरकार पर काफी था। असैनिक (सिविल) खर्चों तथा व्याज के भार में कमी करने के लिए समय-समय पर अनियमित ढंग से प्रयास किए गए। ये प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं हो सके। गृह खर्चों में (होम चार्ज) में भी कमी नहीं की जा सकी। विशेष रूप से गारंटी प्राप्त रेल कंपनियों को दिए जाने वाले व्याज, इंग्लैंड में प्राप्त ऋणों पर व्याज, तथा भारत स्थित ब्रिटिश सेना की सेवाओं के लिए भुगतान को नियंत्रित कर पाना कठिन था।

सेना पर व्यय समस्त व्यय का एक-तिहाई था। सैन्य विद्रोह के बाद जैसे ही

सामान्य स्थिति पुनः स्थापित हुई, सरकार ने सेना पर व्यय में कमी करना प्रारंभ कर दिया। परंतु सरकार के लिए सेना को उस न्यूनतम संस्था के नीचे ले जा पाना संभव नहीं हो सका जो उसकी दृष्टि में 1857 जैसी उथल-पुथल की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक थी। भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओं पर व्यय, भर्ती, प्रशिक्षण तथा इंग्लैंड से भारत आने-जाने के खर्च, भारतीय बैरकों में यूरोपीय जीवन स्तर बनाए रखने के लिए व्यय, सेवा निवृत्ति पर पेंशन आदि के खर्च भारत सरकार ने उठाए। भारत सरकार का दावा था कि युद्ध कार्यालय भारत स्थित ब्रिटिश सेना की सेवाओं के लिए अनुचित रूप से अधिक राशि वसूल कर रहा है। परंतु ब्रिटिश सेना के प्रभावी तथा अप्रभावी खर्चों में कमी नहीं की जा सकी। भारत सरकार के लिए भी उस स्थिति से मुक्त पाना संभव नहीं हो सका जो उसने ब्रिटिश सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एकीकरण के समय स्वीकार की थी। इसके अतिरिक्त, इंग्लैंड के लिए भारत के खर्च पर रखी गई सेना (देशी भारतीय सेना सहित) एक रिजर्व सेना थी जिसकी आवश्यकता पड़ने पर भारत की सीमा के बाहर कारंबाई में प्रयोग किया जा सकता था। भारत में ब्रिटेन के दासन और भारत के बाहर उसके प्रभाव का मुख्य आधार भारत स्थित सेना ही थी।

सरकारी पूंजी और सरकार से भारी सहायता प्राप्त निजी पूंजी निवेशों के द्वारा परिवहन एवं संचार का विकास और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। परिवहन व्यवस्था के विकास, बाहरी किफायतों में वृद्धि और अन्यान्य सहूलियतों के विस्तार से आर्थिक विकास को मिलने वाली प्रेरणा आशा से कम रही। लोक निर्माण नीति की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पड़ी। जैसे, लोक निर्माण (अलाभकर निर्माण कार्यों) के लिए पूंजी की व्यवस्था ऋणों के द्वारा नहीं की गई जिससे पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं जुटाए जा सके। लोक निर्माण के लिए उपलब्ध साधनों का बहुत बड़ा भाग सेना के लिए बैरकों के निर्माण जैसे गैर विकास कार्यों के लिए किया गया। भारत में रेलों के विकास के लिए जिन शर्तों पर ब्रिटिश पूंजी को प्राप्त किया गया, उसके कारण भारत के ऊपर गारंटीयुदा ब्याज के रूप में भारी बोझ पड़ा।

इससे पहले कि हम अपनी इस साधारण-सी रूपरेखा के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तार के साथ वर्णन करें, हमारे लिए यह उपयोगी होगा कि हम थोड़ा रोक कर भारत के आर्थिक जीवन में सरकार की भूमिका के प्रश्न पर नीति निर्धारकों के दृष्टिकोण में दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को देखने का प्रयत्न करें।

इस संबंध में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि सैन्य विद्रोह के कारण भारत के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन हो गया था। सर जार्ज ट्रेवीलियन ने यह महसूस किया था कि 'भारत के प्रति अंग्रेजों की मनःस्थिति' बह नहीं थी जो 1857 की राजनीतिक उथल-पुथल से पहले थी।<sup>40</sup> सर चार्ल्स ट्रेवीलियन एक पुराना ऐंग्लो-इंडियन था। उसने 1863 में खेद प्रकट करते हुए कहा कि 'सिविल सेवा के सदस्य' अवांछनीय रूप से 'स्वदेश की ओर उन्मुख हैं।' उसने इस स्थिति के जो कारण बताए,

वे है संचार के द्रुत साधनों का विकास तथा छुट्टी संबंधी नए नियम।<sup>41</sup> एक अन्य पुराना अनुभवों व्यक्ति चार्टल फोर लिखता है कि 'अंग्रेजों की चाहे वे भारत में काफी समय से रह रहे हो, अथवा नए आए हों भारतीयों के प्रति सहानुभूति यदि विद्वेष में नहीं तो सामान्य रूप से घृणा में निश्चय ही बदल गई है; और उनमें यहाँ रहने, अथवा भारत की चिन्ता करने की प्रवृत्ति नहीं है। वे समस्याओं को भारतीय पहनू से न देख कर किसी भी अन्य पहलू से देखने के लिए तैयार हैं...'।<sup>42</sup> इसके अलावा 'भारत अंग्रेज युवकों के लिए कुबेर का खजाना नहीं रह गया था। अब यह पूँजी निवेश और व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन रहा था।'<sup>43</sup>

भारत को 'विकसित करने' का महान प्रयास सैन्य विद्रोह के परवर्ती काल का मुख्य लक्षण था। जिस किसी भी परियोजना में इस बात का विश्वास होता था कि भारत को पूँजी निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है उसमें लोगों की दिलचस्पी हो जाती थी और कभी-कभी उसे सरकार का समर्थन भी मिलता था। जेम्स विल्सन का दावा था कि भारत विकास काल की दहलीज पर खड़ा हुआ है। यह तथ्य 'वाद के वर्षों में हमारे घरेलू तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार में तेजी के साथ विकास, चाय बागान, कोयला खान, अंतर्देशीय जहाजरानी से संबंधित सार्वजनिक कंपनियों में पूँजी के भारी निवेश, लोगों की सुधरी हुई स्थिति, कृषि उत्पादन और उसके मूल्य में वृद्धि, मजदूरी की दर में वृद्धि, सड़क, नदी तथा नहर यातायात में वृद्धि...' आदि से स्पष्ट था।<sup>44</sup> सैन्य विद्रोह के बाद दो दशकों के भीतर भारत में ब्रिटिश पूँजी निवेश की राशि अभूतपूर्व थी।<sup>45</sup> 1861-64 में कपास व्यवसाय में गरम बाजारी, क्रीमियन युद्ध और अमरीकी गृह युद्ध के समय भारतीय कच्चे माल के बाजारों में विस्तार, स्वेज नहर के खुल जाने, रेल व्यवस्था के विकास आदि ने व्यापार तथा वाणिज्य को, विशेष रूप से भारत के पश्चिमी भाग में, प्रोत्साहन दिया।<sup>46</sup> इस प्रक्रिया में ब्रिटिश व्यापारी की भूमिका स्वभावतः निर्णायक थी। 'उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में मेनचेस्टर के उद्योगपतियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। जहाँ उनका पहले साम्राज्य निर्माण से अलग रहने और दूसरे देशों में हस्तक्षेप न करने में विश्वास था, वहाँ बाद में उनकी उत्साहपूर्ण औपनिवेशिक एवं विदेशी नीति में आस्था जाग गई।' <sup>47</sup> औपनिवेशिक व्यापार में यह नई दिलचस्पी कुछ तो 1870 के बाद अनेक देशों में संरक्षणात्मक टैरिफ लगाए जाने से विदेशी बाजार सकुचित होने के कारण<sup>48</sup> और कुछ 1857 के बाद भारत पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाने के फलस्वरूप थी। जब भी इंग्लैंड के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक हितों ने चाहा तो अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धांत में संशोधन किए गए और भारत सरकार निश्चित रूप से व्यावहारिक नीति का पालन करते हुए लोक नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रायः अहस्तक्षेपी नीति के कठिन और सख्त पथ से हटती रही।<sup>49</sup>

एक ओर ब्रिटिश वाणिज्यिक समाज भारत में अपने आर्थिक हितों के विषय में अधिक जागरूक हो गया था और दूसरी ओर इसी समय भारत के प्रति उत्तरदायित्व के सबंध में ब्रिटेन में भी नई चेतना जगी। भारतीय राजस्व पर फासट और हिंडमैन की

रचनाओं ने गुरु के भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत प्रभावित किया था।<sup>50</sup> डिकिंसन ने यथार्थ को रहस्यपूर्ण बनाने की उस व्यवस्था का भंडाफोड़ करने का प्रयास किया जिसके द्वारा भारतीय नोकरशाही, भारतीय मामलों के बारे में, इंग्लैंड के लोगों को अज्ञान में रखती थी।<sup>51</sup> 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आवर फाइनेशियल रिलेशन विद इंडिया' में मेजर विंगेड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्रिटिश्मानीति 'उस देश के लोगों के कल्याण के लिए विमुक्त स्वार्थरहित एवं परोपकारी दृष्टिकोण के द्वारा निर्धारित नहीं होती।'<sup>52</sup> विंगेड, मेजर एवान्स वेल<sup>53</sup> और राबर्ट नाइट<sup>54</sup> ने भारत सरकार की आय के गैर भारतीय उद्देश्यों के लिए व्यय और तथाकथित संपत्ति विकास से सबद्ध तथ्यों का उद्घाटन किया है। हंटर तथा वार्टन फ़ोर जैसे भूतपूर्व अनुभवी अफसरों ने इंग्लैंड के लोगों को चेतावनी दी थी कि सरकार की आय और साधनों के अपव्यय के प्रति भारत में रोप बढ़ रहा है।<sup>55</sup>

उस काल में प्रचलित लोक वित्त का सिद्धांत, जो इंग्लैंड में ग्लैंडस्टन के नाम से जुड़ा हुआ था, आर्थिक उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित था।<sup>56</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वित्तदाताओं के लिए केवल राजस्व के लिए कराधान एक अविवाद्य तथ्य था। इनके अनुसार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं था। उनका यह भी उद्देश्य था कि लोक व्यय कम रहे और राजस्व इस प्रकार जुट जाए कि निजी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप को किसी प्रकार की हानि न हो और, इस सब के ऊपर, बजट संतुलित होना चाहिए। सरकार की आय उसके व्यय से अधिक रहनी चाहिए और ऋण से यथासंभव बचना चाहिए। भारत के नीति निर्धारक लोक वित्त के इन रुढ़िवादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सके।

सभी जानते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी में अहस्तक्षेपी नीति के प्रभुत्व से भारत सरकार की नीति काफी प्रभावित हुई। भारत के आर्थिक विकास संबंधी एक प्रमुख विचारपत्र के अनुसार तो 'बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक अहस्तक्षेपी नीति का ही पालन किया गया।'<sup>57</sup> अभी हाल में यह बात कुछ जोर देकर कही गई है कि '1858 में कंपनी का शासन समाप्त होने के साथ ही अहस्तक्षेपी नीति का युग वास्तव में प्रारंभ होता है।' 'यह उग्र अहस्तक्षेपी नीति का काल था।'<sup>58</sup> एक अन्य इतिहासकार ने तो ब्रिटिश राज्य को 'रात्रि-प्रहरी-राज्य' कह कर उसकी विक्षेपता प्रकट की है।<sup>59</sup> और अधिक उदाहरण देना सरल किंतु अर्थहीन है। अहस्तक्षेपी नीति शब्द स्पष्ट रूप से घिसी-पिटी पिष्टोक्ति बन गया है। आज जबकि राज्य के कार्यों का क्षेत्र बहुत बड़ गया है, उस समय उन्नीसवीं शताब्दी की अहस्तक्षेपी नीति के श्रेष्ठतम युग के रूप में देखना शायद स्वाभाविक ही है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं का अनौद्योगीकरण संबंधी दावा इसी पर आधारित था। उनका तर्क था कि सरकार के उदासीनतावाद से उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय उद्योगों का अधिक तेजी के साथ पतन हुआ। कुछ भी हो, भारत के सदर्भ में अहस्तक्षेपी नीति की धारणा का सूक्ष्म परीक्षण करना और, फिर कुछ अन्य प्रश्न उठाना सार्थक होगा।

इस बात को कभी-कभी ठीक प्रकार से समझा नहीं जाता कि भारत सरकार

‘भारत में अंग्रेज युद्धरत सभ्यता के प्रतिनिधि है।’<sup>66</sup> सर जान स्ट्रैची ने लिखा है कि सर फिट्ज जेम्स स्टीफन के शब्द ‘हमारे द्वारा प्रवर्तित सिद्धांतों’ के पीछे निहित भावना को स्पष्ट करते हैं। एरिक स्टोनस ने बतलाया है कि स्टीफन और स्ट्रैची ठेठ नई पीढ़ी के प्रशासक थे, जिनमें उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सभ्यता के प्रसार संबंधी मिशन की सुसमाचारी संकल्पना के साथ कार्यकुशलता के लिए उपयोगितावादी उत्साह का सम्मिलन था।<sup>67</sup> कर्तव्य की यह संकल्पना जेम्स मिल के उपयोगितावाद में अंतर्निहित सत्तावादी तत्व पर जोर देती थी और इसने कार्यकुशलता संबंधी ऐसे आदर्शों को जन्म दिया जिसे ऐसे राज्य में ही हासिल किया जा सकता है जिसमें नौकरशाही का प्रभुत्व हो। कर्तव्य की इस कल्पना में भारत को अधिशासित प्रदेश बना दिया और यहां पर रुढ़िवादी उदार अहस्तक्षेपवाद की प्रासंगिकता नहीं रही। सर जान स्ट्रैची का कथन है कि ‘जिन कार्यों की हम अपने जैसे देशों की सरकारों से अपेक्षा करते हैं, भारत सरकार के कार्य उससे कहीं अधिक हैं।’<sup>68</sup> कानूनरहित नीची प्रजातियों के शासकों तथा प्रायः कमोवेश काम करने की में विश्वास रखने वाले आलसी बुद्धिहीनों के स्वामियों के भारी उत्तरदायित्व होते हैं।<sup>69</sup> कभी-कभी उत्तरदायित्व के प्रति उनकी चेतना उनके धार्मिक उत्साह के साथ घुल-मिल जाती है। यह एनन के शब्दों से स्पष्ट है। वह लिखता है ‘इस संसार में केवल हम ही ईश्वर के प्रति उन लोगों के लिए उत्तरदाई हैं जिन्हें उसने हमारे संरक्षण में रखा है।’<sup>70</sup> कभी-कभी उत्तरदायित्व की कल्पना अपेक्षा-कृत अधिक लौकिक माप में की जाती थी और यह प्रजाति श्रेष्ठता की धारणा के अनुरूप होती थी।

किपलिंग का अपने देशवासियों को उपदेश था ‘श्वेत मानव का उत्तरदायित्व संभालो’। ऐसे बंदरगाहों और सड़कों का जहां तुम जा भी नहीं सकते, अपने जीवन से निर्माण करो; और अपनी मृत्यु से उन पर एक अमिट छाप छोड़ दो।’<sup>71</sup> उत्तरदायित्व की संकल्पना राज्य के कार्यों के विषय में नकारात्मक कल्पना के विपरीत थी जिसे उपहास में रात्रि-प्रहरी-राज्य का विचार कहा गया है। इंग्लैंड में राज्य के नियंत्रण के प्रति काफी घृणा थी, परंतु भारत में वैज्ञानिक वैधमवादी प्रशासक तथा सत्तावादी टोरी सज्जनों में स्वाभाविक सहयोग पूरी तरह संभव था।<sup>72</sup>

भारत में नीति निर्धारण के ऊपर अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धांत के प्रभाव को अधिक आंक सक्ता संभव है। नौकरशाही का सोचने का ढंग यदि कुछ था तो वह व्यावहारिक था और वह पश्चिम के ऐतिहासिक अनुभव अथवा आर्थिक विचारधारा से प्रेरित सरकारी नीति के विविध प्रतिमानों को प्रासंगिकता को सदेह की दृष्टि से देखता था। जैसा कि हम आगे देखेंगे नीति निर्धारकों की कुछ विशिष्ट समस्याओं के प्रति प्रतिक्रियाओं के पैटर्न से प्रकट होता है कि वे प्रायः आर्थिक उदारवाद के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांतों का यथार्थ में खंडन नहीं करते थे तो उनकी अवहेलना अवश्य करते थे। आर्थिक नीति के सिद्धांतों की खोज अमूर्त सिद्धांतों के क्षेत्र के बाहर कंपनियों के शेयरों के वास्तविक स्तर, व्याज व लाभांशों, ससदीय लाब्डी तथा चैंबर्स आफ कामर्स के दायरों में होनी चाहिए। जिस काल का हम यहां अध्ययन कर रहे हैं, भारत में इस अवधि में



अहस्तक्षेप नीति के नाम से जानी जाने वाली नीति का उद्देश्य ब्रिटिश माल के लिए भारतीय बाजार को खोलना, कच्चे मालों की आपूर्ति बढ़ाना और पूँजी निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना था और इनकी प्राप्ति के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जिस प्रकार हुआ वह वाणिज्यवाद की याद दिलाता है।<sup>173</sup>

यदि भारत में सरकार द्वारा सपन्न किए जाने वाले कार्यों के विस्तार पर विचार किया जाता है तो ब्रेबनर की भाँति ही इस प्रकार के साधारणीकरण के लिए इच्छा हो सकती है कि यदि ब्रिटेन में अहस्तक्षेपी नीति मियक थी तो वह भारत में कम मियक नहीं थी।<sup>174</sup> अनेक बाहरी किरायातशारी बरतने के लिए आधारभूत आर्थिक संरचना में पूँजी निवेश का पेटन; रेल तथा सिंचाई कपनियों में राज्य द्वारा ब्याज की गारंटी के आधार पर पूँजी निवेश, कपास आदि कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए असाधारण उपाय; भारत में यूरोप के लोगों द्वारा निवेश और उनके आवास में बाधक भूमि संबंधी अधिनियमों में मंशोधन, भारत में यूरोपीय उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए पथप्रदर्शक परियोजनाओं का लोक वित्त द्वारा पोषण ऐसी बातों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन्हें ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार भारत में विवेकपूर्ण हस्तक्षेपवाद कहा जा सकता है।

हमें सरकारी कार्यों के ऐसे कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें आर्थिक उदारवाद की पुरानी शुद्धता को बनाए रखा गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के परवर्ती वर्षों के टैरिफ विवाद में शिशु उद्योग वाले तर्कों का खंडन करने के लिए अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धांतों का आश्रय लिया गया था।<sup>175</sup> भारत जिस समय दुर्भिक्षों के चक्र से गुजर रहा था, उस समय सरकार ने खाद्यान्नों के स्थानांतरण में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।<sup>176</sup> अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत के आधार पर आरोही कराधान को अपनाया नहीं गया। इस समय में तर्क यह था कि 'लोगों' की स्थितियों में समता लाना वित्तीय व्यवस्था से संबंधित कार्यों का अंग नहीं है।<sup>177</sup> अहस्तक्षेपी नीति पर आधारित लोक वित्त के सिद्धांतों के कारण आधारभूत आर्थिक संरचना के विकास से संबंधित विविध प्रकार के व्यय में बाधा रहती थी।<sup>178</sup> सरकार के न्यायसम्मत कार्यों की दृढ़ परिकल्पना के कारण कभी-कभी सरकार के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रचनात्मक कार्य कर पाना संभव नहीं होता था।<sup>179</sup> वस्तुतः ये तथ्य इतने जाने-माने हैं कि उन पर किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सरकार की हस्तक्षेपवादी और अहस्तक्षेपवादी नीतियों में जिनका सरकार साथ-साथ पालन करती थी कोई आधारभूत अंतर्विरोध है।

ऐसा लगता है कि सरकारी हस्तक्षेप की समर्थनकारी और विरोधी प्रतिक्रियाओं का अंतर्विरोध वास्तविक न होकर ऊपरी है। उदाहरण के लिए यह प्रायः स्वीकार किया जाता है कि सभी निहित स्वार्थों में मेनचेस्टर के मूनी वस्त्र उद्योग हितों का स्थान केंद्रीय था। आगे हम देखेंगे कि मेनचेस्टर के मूनी वस्त्र उद्योग को कपास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अहस्तक्षेपवादी नीति की अवहेलना अनुचित नहीं मानी गई। इसी के साथ-साथ भारत के घरेलू कपास उद्योग को टैरिफ संरक्षण न देने के

मामले में अहस्तक्षेपी नीति को कड़ाई के साथ लागू किया गया। इन दोनों बातों में ऊपरी अमंगति के बावजूद दोनों ही नीतियाँ एक ही प्रकार के हितों की दृष्टि से उपयोगी थीं। विविध विचारों की अंतर्क्रिया और सरकार की नीति में लोच के कारण स्थिति बहुत जटिल है। अहस्तक्षेपी नीति का लेवल होने पर हमें इस जटिलता की उपेक्षा करने का साहस होता है। यदि किसी सरल लेवल की ही आवश्यकता है तो संभवतः स्थिति की परिभाषा अहस्तक्षेपी नीति शब्द की तुलना में भेदमूलक हस्तक्षेपवाद के द्वारा अधिक सही हो सकेगी।

जे० ए० शुपीटर के अनुसार यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में 'आर्थिक उदारवाद में इतना अधिक हेर-फेर किया गया कि कभी-कभी तो इससे उसके अपने सिद्धांतों का ही अप्रकट रूप से परित्याग हो गया।' <sup>80</sup> इंग्लैंड में निर्धनों को दी जाने वाली सहायता से संबद्ध व्यवस्था के आधुनिकीकरण, फैक्ट्रियो और जन-स्वास्थ्य के नियम, नगर-समाजवाद के प्रयोगों, सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली के संगठन आदि के कारण घोषित अहस्तक्षेपवाद के बावजूद सरकारी कार्यकलाप का क्षेत्र विस्तृत हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजीवाद के अभ्युदय के कारण ही अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धांतों से हटा गया था जबकि भारत में पिछड़ी अर्थ व्यवस्था और उसके क्षोषण की समस्याओं के कारण ऐसा हुआ। यह तर्क देना युक्तिसंगत होगा कि अपने भारतीय अनुभव के कारण अहस्तक्षेपी नीति में ब्रिटिश लोक जनो की आस्था समाप्त हो गई, और इस प्रकार कम से कम उन नीतियों के प्रति जिनके द्वारा सरकारी कार्यों का विस्तार होता था, उनकी घृणा कम हो गई। यूरोप के सिद्धांतवादियों के प्रभाव के अलावा संभवतः 'भारत सरकार की व्यावसायिक क्रियाओं से ही इंग्लैंड में समष्टिवाद को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला।' <sup>81</sup> यह भलीभांति स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम कुछ दशकों में यूरोप में इंग्लैंड तक में जिसे डायसी अहस्तक्षेपी नीति का स्वाभाविक स्थल मानता है इस नीति का महत्व कम हो रहा था। <sup>82</sup>

जिस समय जर्मनी के ऐतिहासिक विचारधारा वाले अर्थशास्त्री अहस्तक्षेपी नीति सिद्धांत अथवा मिथवाद (जर्मनी में अहस्तक्षेपी नीति सिद्धांत को मिथवाद उपनाम प्रदान किया गया था) <sup>83</sup> पर प्रहार कर रहे थे, उस समय इंग्लैंड में भी परंपरागत अहस्तक्षेपवाद के विरुद्ध एक वैचारिक धारा चल रही थी। यूनिवर्सिटी कालिज, लंदन के राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जे० ई० कर्नीज ने 1870 में अपने प्रारंभिक व्याख्यान में कहा था कि 'अहस्तक्षेपी नीति सिद्धांत सार्वजनिक मामलों में बाधा एवं कंठक बन गया है।' <sup>84</sup> सिद्धांतिक आधार पर भी वह इस मत का विरोधी था कि संपूर्ण राजनीतिक अर्थशास्त्र का सार अहस्तक्षेपी नीति है। <sup>85</sup> इसी समय इस विचार को कि पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों में क्रियाशील सिद्धांत उन देशों के लिए अनुपयुक्त थे जो ऐतिहासिक विकास में पिछड़ गए थे, अधिकाधिक मान्यता मिल रही थी। वेजहाट तथा लैजली की रचनाओं में सर हेनरी मेन के पुरातन समाज एवं समुदायों के अध्ययनों का प्रभाव देखा जा सकता है। <sup>86</sup> वाल्टर वेजहाट ने जोरदार ढंग से कहा था कि 'भारत उन देशों में से है जिनकी सभ्यताओं का विकास अवरोध हो गया है।' <sup>87</sup> यहाँ का समाज

धीरे-धीरे 'प्राक् आर्थिक अवस्था से उस समय विकसित हुआ था जब राजनीतिक अर्थ-शास्त्र की मान्यताओं का अस्तित्व ही नहीं था और जब इसके नियमों का पालन अनर्थकारी भी हो सकता था।'<sup>88</sup> थामस लैजली के अनुसार प्रारंभिक क्लासिकी अर्थशास्त्रियों की सामान्य एवं निगमनिक रीतियों पर निर्भरता ठीक नहीं थी।<sup>89</sup> रोशर के प्रभाव से<sup>90</sup> लैजली ने सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में आर्थिक ढांचे से संबंधित अंतर के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया।<sup>91</sup> विचार करने का यह ढंग संभवतः पाश्चात्य तथा गैर पाश्चात्य ऐतिहासिक अनुभव एवं सामाजिक स्थिति में अंतर से संबंधित चेतना का परिणाम था। आर्थिक विश्लेषण में ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादकों ने इस धारणा को बहुत स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर लिया था कि आर्थिक सिद्धांत सभी कालों और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस प्रकार उन्होंने अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धांत को जड़ खोदी। इस जर्मन विचारधारा को विशेष रूप से उसके अहस्तक्षेपी नीति पर तीखे प्रहार के लिए ही स्मरण किया जाता है। परंतु दो जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट तथा कार्ल मार्क्स आर्थिक हितों के आधार पर अहस्तक्षेपी नीति दर्शन की व्याख्या की दिशा में बहुत आगे चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में 1853 में मार्क्स ने लिखा कि कुलीन तृतीय शासकों को भारत के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की कि भारत में कृषि कार्य 'पूर्ण प्रतियोगिता के ब्रिटिश सिद्धांत, अहस्तक्षेपी नीति तथा स्वच्छंदता के अनुसार नहीं चल सकता था।'<sup>92</sup> 'जैसे-जैसे भारतीय बाजारों पर (ब्रिटिश) औद्योगिक हितों की निर्भरता बढ़ती गई, वैसे-वैसे ही शासक वर्ग ने भारत में नई उत्पादक शक्तियों के विकास की आवश्यकता को समझा।'<sup>93</sup> अतः जहां शासक वर्ग का कंपनी के शासन काल में भारत की प्रगति में अल्पकालिक तथा आपवादिक हित था, वही इसके विपरीत औद्योगिक हित, जिन्हें मार्क्स ने मिलवाद कहा है, भारत को विकसित करने और अन्य देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक थे।<sup>94</sup> मुक्त व्यापार के पक्ष में अहस्तक्षेपी नीति तर्कों की फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा की गई आलोचना बहुत जानी मानी है और ऐसा लगता है कि उसने भारतीय मंत्रालयवादियों को और विशेष रूप से एम० जी० रानाडे को काफी प्रभावित किया है।<sup>95</sup> एक औद्योगिक देश द्वारा अपने उपनिवेश पर मुक्त व्यापार को थोपने का प्रयत्न, वास्तव में उस सीढ़ी को हटाने के प्रयास की भांति है, जिस पर होकर वह स्वयं ऊपर उठा है ताकि अन्य देश उसी सीढ़ी के द्वारा उसका अनुगमन न कर सकें। इस संबंध में अधिक संदेह नहीं किया जा सकता कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के विकास के लिए राजकीय हस्तक्षेप को लिस्ट द्वारा दिए गए समर्थन और जर्मनी में सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति की सफलता का भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की आर्थिक विचारधारा पर प्रभाव पड़ा था।

जिस काल का हम यहां अध्ययन कर रहे हैं उसमें भारतीय वित्त नीति से संबंधित विवादों में भाग लेने वाले व्यक्ति प्रायः अस्पष्ट प्रयोजनों एवं हितों को तर्कसंगत बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों अथवा राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने पिसे-पिटे शब्दों को बहुधा ले लिया करते थे। हितों और विचारों में मध्य के बीच अदिल अतन्त्रिया का

अध्ययन करते हुए हमारे सामने अनेक समस्याएं आती हैं। हितवद्ध समूहों को पहचान पाना कठिन कार्य है। कुछ हितवद्ध गुट विधिवत संगठित किए गए थे और इसलिए उन्हें सहज ही पहचाना जा सकता था (उदाहरणार्थ, ब्रिटेन तथा भारत में चेंबर आफ कामर्स, या मेनचेस्टर काटन सप्लाय एसोसिएशन), परंतु बहुतों का गठन विधिवत नहीं हुआ था और उनको पहचान सकना कठिन था। हितवद्ध गुटों तथा वित्तीय नीति से संबंधित मामलों पर निर्णयों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर पाना सदैव संभव नहीं है। कभी-कभी तो कोई संबंध होता ही नहीं था और कभी ऐसे भी अवसर आए जब अभिजात वर्गीय शासकों (जैसे कैनिंग और मेयो) तथा इनकी ही प्रजाति के भारत में व्यापारिक समुदाय में परस्पर सहानुभूति के अभाव के कारण भारी कटुता रही। यह भी मान लेना भूल होगी कि सभी के हित एक ही जैसे थे हालांकि प्रत्येक हितवद्ध गुट अधिक लोगों तक पहुंचने और उन्हें सन्तुष्ट कर अपने समर्थन में भारी लोकमत तैयार करने के लिए अपने वर्गीय हित को 'राष्ट्रीय हित' के रूप में प्रस्तुत करता था। आगे आने वाले पृष्ठों में बार-बार यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार ऊंची आय वाले वर्गों ने जिनमें जमींदार और व्यापारी भी थे, सरकार से जनसाधारण पर करो (उदाहरणार्थ, नमक कर) को बढ़ाने का आग्रह किया जिससे अभिजात वर्गों को कर-भार (विशेष रूप से आयकर जिसका भार अपेक्षाकृत ऊंची आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता था) से मुक्ति मिल सके; किस प्रकार भारत में रहने वाला ब्रिटिश व्यापारी समुदाय सरकारी व्यय को घटाने पर जोर देता था जिससे उस पर कर-भार में कमी हो सके जबकि ब्रिटिश नौकरशाह तथा सैनिक अधिकारी व्यय में कमी के विरुद्ध थे और उन्होंने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अपना प्रतिफल बढ़ाने का प्रयास किया; किस प्रकार भारतीय व्यापारी और व्यावसायिक वर्गों को इस घात पर रोष था कि उनकी अर्जित 'जीवन-आय' पर कर की वही दर थी जो संपत्ति (विशेष रूप से स्याई बंदोवस्त के अंतर्गत जमींदारों की संपत्ति) से प्राप्त अनर्जित आय पर थी; और किस प्रकार प्रांतीय ईर्ष्या के कारण कुशल केंद्रीय नियंत्रण में बाधा उपस्थित हुई। कभी-कभी हितों में अंतर अस्याई और ऊपरी किस्म के होते थे और इसलिए अंत में उनका समाधान निकल आता था। ब्रिटिश व्यापारियों तथा नौकरशाहों का कुछ समस्या पर मतभेद हो सकता है परंतु साम्राज्य को बनाए रखने तथा इससे संबंधित खर्चों के प्रश्न पर अथवा दूसरों का साम्राज्य स्थापित करने का अवसर देने की समस्या पर गहरा मतभेद नहीं था। हितों में इस प्रकार की भिन्नता और आधारभूत संघर्षों में, जिनकी ओर दादाभाई नौरोजी ने ध्यान आकर्षित किया था, भेद करना आवश्यक है। हितवद्ध गुटों के प्रतिनिधि अपना प्रभाव डालने में सफल हो सकते थे यदि वे इस दिशा में विधिवत प्रयास करते। परंतु प्रभावशाली बनने के लिए आवश्यक नियम नौरोजी के 'सघटको' के विपरीत थे। नीति-निर्धारक एक हद तक, आंतरिक हितवद्ध गुटों से प्रतिक्रियाशील थे। प्रतिक्रिया क्या होगी यह डाले जाने वाले दबाव, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के दृष्टिकोण, प्रचलित लोकाचारों, तथा अन्य अनेक कारणों जैसे निर्णयकर्ता अधिकारियों की व्यक्तिगत अभिरुचियों (यद्यपि अतिम घटक सीमांत व असाधारण स्थितियों में ही निर्णायक होता था) आदि पर निर्भर होती

थी। निर्णय अधिकारियों की सीमाएं गमग्र वित्तीय स्थिति पर निर्भर होती थीं जो यह निर्धारित करती थी कि रियायतें दी जा सकेंगी अथवा नहीं, लोकमत पर निर्णयों का प्रभाव क्या होगा, परंपरागत रास्ते से सरकार न हटे इसकी ओर नौकरशाही का भुगव, आदि। हमारा उद्देश्य उन नियमों का अध्ययन है जिनका इस प्रक्रिया में पालन किया गया।

## संदर्भ

1. विल्सन से वुड को, 11 जुलाई, 1859, बैरिंगटन, II, 171। 'इंडियनरी आफ नेशनल बायोग्राफी', जिल्द 21, पृ० 571-73। सी० ई० बर्कनहेड, 'इंडियनरी आफ इंडियन बायोग्राफी' (सदन, 1906) पृ० 456। वास्टर बेजहाट, 'लिटरेरी स्टडीज' (सदन 1879) जिल्द 1, परिशिष्ट। 'लोम्बार्ड स्ट्रीट' का मैट्रक बेजहाट विल्सन का दामाद था और उसके बाद 'इकानामिस्ट' का संपादक बना था।
2. विलियम डी० ब्रैम्प, 'दि मेनचेस्टर स्कूल आफ इकानामिक्स', (स्टेनफोर्ड, 1960) पृ० 13।
3. ए० के० केर्नक्रास, 'होम एंड फोरेन इन्वेस्टमेंट' 1870-1913 (कैम्ब्रिज, 1953) पृ० 244। राबर्ट लिंक, 'इग्निश मिजरीज आफ इकानामिक एक्सचुएशंस' 1815-48 (म्यूयार्क, 1959)। जे० एम० केंस, 'इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस' (सदन, 1913) पृ० 38।
4. देखिए एस्मर वुड, 'इग्निश मिजरीज आफ सेंट्रल बैंकिंग' 1819-1858 (कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स 1939)।
5. पत्र मुद्रा के समर्थ में भारत मंत्री के प्रेषण पर जे० विल्सन का मेमो० दिनांक 25 दिसंबर, 1859। वित्त कार्य विवरण जनवरी, 1860। लेखा माया, सत्या 1।
6. जे० विल्सन से लार्ड कैनिंग को 25 अगस्त, 1859, ई० बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत, पृ० 181-83।
7. देखें, भागे अध्याय 2।
8. डब्ल्यू० बेजहाट, पूर्वोद्धृत, पृ० 400-401।
9. जेम्स विल्सन, 'फाइनेंसियल स्टेटमेंट' (कलकत्ता, 1860) पृ० 9। वी० जी० काले, 'डान आफ माडर्न फाइनेंस इन इंडिया' (पूना, 1922) पृ० 87-89 पर विल्सन के मत के समर्थन में मनु 7, 128, 130 और गौतम 10, 24-30 से उद्धरण।
10. सी० ट्रैवोलियन से सी० वुड को, प्रतिलिपि डब्ल्यू० बेजहाट को प्रेषित, 2 दिसंबर, 1862। ई० बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत, II, पृ० 259।
11. 'फंड आफ इंडिया', 2 फरवरी, 1860, 1 मार्च, 1860, 23 अगस्त, 1860। 'बंगाल हुरकार' (एड दी इंडिया गजट) 21 फरवरी, 1860, 23 फरवरी, 1860। 'टाइम्स आफ इंडिया', 25 दिसंबर, 1863। राबर्ट नाइट का विचार था कि विल्सन से बहुत गहरी भूलें हुईं जैसे, भारतीय ऋण की साम्राज्य द्वारा गारंटी का विरोध, भारत के लिए स्वर्ण मुद्रा की असंयोजित, मर्षा वित्तीय कठिनाइयों के समाधान के लिए आय कर को अधिक उपाय मानकर उसमें आस्था रखना। 'दि इंडियन इकानामिस्ट' 10 मार्च, 1870, पृ० 231।

12. 'फैंड आफ इंडिया', 25 अक्टूबर, 1860 ।
13. सी० ई० बकलेट, पूर्वोद्धृत, पृ० 156 ।
14. बी० फेर से मेजर एफ० मैरियट को 11 अगस्त, 1860, माटिन्यू, पूर्वोद्धृत I, पृ० 312 ।
15. बी० फेर से सी० बुड को, 23 नवंबर, 1860, माटिन्यू, पूर्वोद्धृत I, पृ० 313 ।
16. बी० फेर से मर जी० ब्लाक को, 9 मई, 1860, माटिन्यू, पूर्वोद्धृत I, पृ० 308 ।
17. बी० फेर से सी० बुड को, 23 नवंबर, 1860, माटिन्यू, पूर्वोद्धृत I, पृ० 313 ।
18. 'डी० एन० बी०' जिल्द 22 (परिशिष्ट) पृ० 948-50 । रेल आयोग का मसौदा (1845); लंदन, ब्राइटन एंड साउथ कोस्ट रेलवे कंपनी का घेपरमैन और प्रबंध संचालक । ट्रेंजरी (वित्त मन्त्रालय) का फाइनेशियल सेक्रेटरी (1860) । 1861 में उस पर एक छोटा सा कलक लगा था । उस पर हैमिल्टन एंड टोरटो रेलवे कंपनी (कनाडा) के साथ साठ-गाठ के मौशों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था । आरोप ग्राह्य गलत था और सिद्ध नहीं हो सका 'फैंड आफ इंडिया' 11 अप्रैल, 1861 ।
19. 'फैंड आफ इंडिया' 1 जनवरी, 1863, 17 अप्रैल, 1862 । जब लैंग ने बुड के साथ बार-बार झगड़ों के कारण त्यागपत्र दे दिया तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए कानकता के अप्रेज व्यापारियों ने एक सभा की थी । 'फैंड आफ इंडिया', 11 मितवर 1862 ।
20. 'डी० एन० बी०' जिल्द 19, पृ० 1135-36 । ई० ह्यूजेज सर चार्ल्स ट्रैवीनियन एंड सिविल सर्विस रीफार्म 'ई० एच० आर०', 1949 भाग 1 व 2, पृ० 53, 206 । टी० बी० मैकाले से टी० एफ० एलिस को, 15 दिसंबर, 1834 । जी० एम० ट्रैवीनियन पूर्वोद्धृत, पृ० 23 ।
21. 'फैंड आफ इंडिया', 14 अप्रैल, 1864, वही 22 मितवर, 1864 ।
22. 'फैंड आफ इंडिया' 6 अप्रैल, 1865, 27 अप्रैल, 1865, 18 मई, 1865 ।
23. 'डी० एन० बी०' जिल्द 13, पृ० 7 । 'डी० एन० बी०' में एक महत्वपूर्ण भूल है जिसके अनुसार वह सालफोर्ड के स्थान पर 1863 तक बैठता रहा । 1863 में उसने भारत सरकार में वित्त सचिव के रूप में सेमुअल लैंग का स्थान ग्रहण किया और इस पद पर उसने 1868 तक कार्य किया । वास्तव में लैंग का उत्तराधिकारी ट्रैवीनियन था न कि मैगी और मैगी 1865 में परिपद का सदस्य बना था न कि 1863 में ।
24. 'दि इंग्लिशमैन' 11 अप्रैल, 1866 । 'फैंड आफ इंडिया' (29 मार्च, 1866) ने उसे विश्वस्त व्यक्ति माना है जो प्रतिभाशाली नहीं था ।
25. सी० ई० बकलेट पूर्वोद्धृत, पृ० 418 । टैपिल, 'दि स्टोरी आफ माई साइक', I, पृ० 199 ।
26. देखें ओ० टी० बर्नी, 'ए प्यू सेंटमें' (जिमना, 1877) पृ० 159 । बर्नी कहता है कि मेयो उनके (टैपिल के) सतही गुणों को समझता था और जान स्टुडो तथा विल गविय चैपमैन पर अधिक निर्भर रहता था । मेयो ने अपनी बर्गीयता (दिनांक 12 अक्टूबर, 1868) में इच्छा प्रकट की थी कि उनके निजी पत्र व्यवहार में ऐसी कोई भी चीज प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए, जो किसी भी औचित्य व्यक्ति को आघात पहुंचाए, अथवा नाराज करे । (वही, पृ० 4) अतः यह स्वामाधिक है कि हटर द्वारा लिखी गई मेयो की जीवनी में मेयो और टैपिल के दुर्भाग्यपूर्ण मर्यादों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है ।

27. मेयो से आरगाइल को 22 मार्च, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सध्या 81 ।
28. मेयो से आरगाइल को 14 जुलाई, 1870, मेयो कागजात, बडल 40, सध्या 202 ।
29. पूर्वोक्त स्थल ।
30. आरगाइल से मेयो, 1 नवंबर, 1871, मेयो कागजात, बडल 49, जिल्द 19 ।
31. पूर्वोक्त स्थल ।
32. मेयो से आरगाइल को 14 जुलाई, 1870, मेयो कागजात, बडल 40, सध्या 202 ।
33. 'दि इग्लिशमैन', 6 जुलाई, 1870 ।
34. सी० ई० बकलैंड, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 407 ।
35. कर्नेल आर० स्ट्रैची ने 1836 में सबसे इजीप्टियन में नौकरी शुरू की थी; 1862 में लोक निर्माण विभाग में सचिव के पद पर उसकी नियुक्ति हुई और 1866 में इस्पेक्टर जनरल आफ इरीगेशन के रूप में । सी० ई० बकलैंड, पूर्वोद्धृत, पृ० 407 ।
36. वित्त कार्य विवरण, अक्तूबर, 1867, लेखा शाखा सध्या 23 । कर्नेल आर० स्ट्रैची का नोट 17 अगस्त, 1867 । देखें अध्याय 2, अनुच्छेद दो ।
37. मेयो से डब्ल्यू० ग्रै को, 20 अगस्त, 1869, मेयो कागजात, बडल 36, सध्या 205 ।
38. मेयो से सी० फेर को, 6 दिसंबर, 1869, मेयो कागजात, बडल 37, सध्या 345 ।
39. मेयो से विस्काउंट हिलीफैम, 4 अक्तूबर, 1869, मेयो कागजात, बडल 37, सध्या 270 ।
40. सर जी० ट्रेवीलियन, 'दि कपटिशन घाला' (सदन, 1895 : प्रथम सत्राकरण 1864) पृ० 238 ।
41. वित्त कार्य विवरण मार्च, 1864, अवकाश और पेंशन, सध्या 33 सर सी० ई० ट्रेवीलियन का नोट 28 अक्तूबर, 1863 ।
42. सी० फेर से सी० बुड को 10 अप्रैल, 1861 । संपूर्ण पत्र काफी दिलचस्प है । मार्टिन्यू पूर्वोद्धृत जिल्द 1, पृ० 336-41 ।
43. टी० जे० होडेन बर्नो, 'दि कपनी एंड दि नाउन', (सदन, 1866 पृ० 239) ।
44. भारत सरकार में भारत मंत्री को, वित्त सध्या 144, 29 जून, 1860 । यह मगीरा लगभग निश्चिन्त रूप से स्वयं जेम्स विल्सन ने तैयार किया था । प्राकृत्य (मगीरा) के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके सपु हस्ताक्षर हैं ।
45. एम० एच० जेफन, 'भाइसेजन आफ ब्रिटिश बॅंकिंग टु', 1875 (म्युपार्स, 1927) । जॉर्ज पैम 'बैंक ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन अंडर वेइंग जर्नल' आफ दि रायल स्टैंडिटीकल सोसाइटी' जिल्द 52, मिनबर, 1909, पृ० 465-80, और 'बैंक ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडोविजुअल प्रोपर्टीज एंड कोरेन कंट्रीज' जे० आर० एम० एम० जिल्द 54, जनवरी, 1911, पृ० 167-87 ।
46. देखें अध्याय 4 आगे । सी० ई० वाशा, 'एंडोवमेंटियल बॅंकेट इन दि बोर्गे' गिटी (बर्डी, 1910) पृ० 1-26 । 'ग्लोबे' आफ दि रायल कमीशन ऑन दि मोन्ट पेन ऑफ बोर्गे', (बर्डी, 1869) पृ० 8-14 ।
47. जी० बी० हर्ज 'दि मेनबेटर पार्लियामेंट' 1750-1912 (सदन, 1912) पृ० 75 ।
48. वही, पृ० 79 ।
49. सी० आर० डे, 'एंडोवमेंट इकायर्स एंड इन्स पेमेंट इन दि बोर्गे ऑन इकायर्स ऑफ इकायर्स',

- 1600-1900 (आन्सफोर्ड, 1934) पृ० 177 । सव्यसाची भट्टाचार्य 'लेमे फेअरे इन दि इंडिया' 'इंडियन इकानामिक सोशल हिस्ट्री रिव्यू', जिल्द 2, सख्या 1 । 1 जनवरी, 1965, पृ० 1-22 ।
- 50 हेनरी फासट, 'इंडियन फाइनेंस', (लंदन, 1880) । एच० एम० हिडमैन, 'दि बैंकरप्सी आफ इंडिया' (लंदन, 1886) ।
- 51, जे० डिक्सन, 'इंडिया : इट्स गवर्नमेंट अंडर एब्यूरोक्रेसी', (लंदन, 1853) । वह इंडिया रीफार्म सोसाइटी (1853) जिमने इंडियन रीफार्म ट्रैक्ट्स का प्रकाशन किया था, का सस्थापक था । देखें ई० बैल (सपादक) 'सास्ट कांसिल्स आफ एन अननोन कामिलर, जान डिक्सन' (लंदन, 1877) पृ० 13-14 ।
52. मेजर विनेट, 'अवर फाइनेशियल रिलेशन विद इंडिया', (लंदन, 1859) ।
- 53 मेजर ई० बैल 'ट्रस्ट ऐज दि बेसिस आफ इंपीरियल पालिसी' 'जनल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', जिल्द 6, पृ० 145-75 । (यह लेख 18 जून, 1872 के दिन ई० आई० ए० की एक गोष्ठी में पढ़ा गया था) ।
54. आर० नाइट, इंडिया : 'ए रिब्यू आफ इंग्लैंड्स फाइनेशियल रिलेशन देअर विद' (लंदन, 1868) 'नाइट इंडियन इकानामिस्ट' तथा 'टाइम्स आफ इंडिया', का सस्थापक था ।
55. डब्ल्यू० डब्ल्यू० इटर, 'सम आल्सैक्ट्स आफ इंडियन फाइनेंस', 12 दिसंबर, 1879 के दिन बनिधम चेंबर आफ कामर्स में भाषण (1880) ।
- 56 सी० आर० फे, 'ग्रेट ब्रिटेन फ्राम एंडम स्मिथ टु दि प्रजेंट डे', (लंदन, 1932), पृ० 74-78 । जे० ए० शुपीटर, 'हिस्ट्री आफ इकानामिक एनेलिसिस' (न्यूयार्क, 1954) पृ० 402-5 ।
57. डी० आर० गाडगिल, 'दि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आफ इंडिया' (ओ० यू० पी० 1945), पृ० 205 । प्राथमिक अवधि में (प्रथम विश्व युद्ध तक) राज्य का दृष्टिकोण पूरी तरह अहस्तक्षेपी हो था । (पृ० 323) ।
58. बी० बी० मिश्र, 'दि इंडियन मिडिल क्लासेज देअर ग्रोथ इन माडर्न टाइम्स' (लंदन, 1961) पृ० 214-359 ।
59. मारिस डी० मारिस, 'टुवर्ड्स ए रिइटरप्रेटेशन आफ नाइटीथ सेंचुरी इंडियन इकानामिक हिस्ट्री' 'जनल आफ इकानामिक हिस्ट्री', जिल्द 23, 1963 । 'ब्रिटिश राज अपने आपको रात्रि प्रहरी की निष्क्रिय भूमिका में देखता था ।' (पृ० 615) । वह बार-बार राज्य की रात्रि प्रहरी नीतियों (पृ० 616) और सरकार के रात्रि-प्रहरी उद्देश्यों (पृ० 611), का उल्लेख करता है ।
60. जे० एस० मिल 'प्रिंसिपल्स आफ पोलिटिकल इकानामी', 1848 में पहली बार प्रकाशित (लंदन, 1902), पुस्तक 5, पृ० 590-91 । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मिल एक पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था की समाधारण स्थिति की व्याख्या करता है । 'उमने क्वासिकी अर्थशास्त्र में सशोधन किए हैं, परंतु वह हम धारणा से विमुख नहीं हुआ कि आर्थिक मामलों में सरकारी निरीक्षण व नियंत्रण से व्यक्तिगत उद्यम श्रेष्ठ है ।' जार्ज डी० बीजर्स, 'ब्रिटिश एटोच्यूट्स टुवर्ड्स इंडिया 1784-1885 (ओ० यू० पी० 1961) पृ० 286 । मिर्जाल के अनुसार मिल आर्थिक उदारवाद में संकट को स्पष्ट करता है । गुन्नार मिर्जाल, 'दि पोलिटिकल एलीमेंट इन दि डेवलपमेंट इकानामिक बिजनेस' कैम्ब्रिज मैमानूस्क्रिप्ट्स 1961) पृ० 127 और आगे ।
61. देखें जे० एम० मिल, 'रिजिजेंटेटिव गवर्नमेंट', पहली बार प्रकाशित 1861 (लंदन, 1912)



पृ० 190-211 ।

- 62 जोजफ स्पेगलर, 'जोन स्टुअर्ट इकानामिक डेवलपमेंट' बट एफ० होत्रलिट्ज (संपादक) 'थिथरीज आफ इकानामिक प्रोब', (1960), पृ० 144 यत्न-तत्त्व ।
- 63 वेंथम और मैकुला के राज्य सवधी विचारों के विवेचन के लिए देखें लायनल रोबिंस, 'दि थिथरी आफ इकानामिक पालिसी इन इंग्लिश कनामिकल पोलिटिक्स इकानामी', (लंदन, 1961) पृ० 39 और आगे ।
- 64 अहमदशेरी नोति का सिद्धांत कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह विश्वसनीय है, परंतु कुछ अन्य क्षेत्रों में वह विलकुल लागू नहीं होता, और हर मौके पर उसका उल्लेख करना तोते की रट जैसी लगती है किमी राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक की नोति जैसी नहीं । ड्रीटाइन आन दी मक्सीशन टु प्रापर्टी बेकैट बाई डेप (1848) पृ० 156 । रोबिंस, पूर्वोद्धृत, पृ० 39 ।
- 65 जान स्ट्रैची, 'इडिया इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस' (लंदन, 1903), पृ० 209 ।
- 66 जे० एफ० स्टीफन का 'दि टाइम्स' को पत्र, 1 मार्च, 1883, जे० स्ट्रैची के 'इडिया . इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस' (लंदन, 1903) में पृ० 209 पर उद्धृत ।
- 67 ऐरिक स्टोसम, 'दि इंग्लिश यूटीलिटेरियस एंड इडिया' (आक्सफोर्ड, 1959), अध्याय 4, यत्न तत्त्व ।
- 68 जे० स्ट्रैची, पूर्वोद्धृत पृ० 209 ।
- 69 कडवाई किपलिंग, 'रिसीशनल' और 'दि ईवन', 'कलैक्टड वर्स आफ किपलिंग' (लंदन, 1912), पृ० 325, 422 ।
- 70 ऐनन, 'हाउ थी टैक्स इडिया' (लंदन, 1857) पृ० 37 ।
71. आर० किपलिंग, 'दि प्लाइडमैस बर्डन' (1899) पूर्वोद्धृत, पृ० 320 । टी० एस० इलियट ने किपलिंग पर एक अनुबोधक लेख में स्पष्ट किया है कि किपलिंग 'किमी ऐसे तत्व के अस्तित्व के बारे में चेतना प्रगटित करना चाह रहा था जिसके विषय में उसे ऐसा लगता था कि अधिकांश लोगों में अपर्याप्त जानकारी है । निश्चय ही यह गौरव के प्रति चेतना थी, परंतु उससे भी कहीं अधिक यह उत्तरदायित्व के बारे में चेतना थी ।' 'ए ब्यापस आफ किपलिंग वर्स' (लंदन, 1944) पृ० 25 ।
- 72 जी० एम० यंग, 'विक्टोरियन इंग्लैंड : पीपल आफ एन एज' (लंदन, 1960) पृ० 54 ।
73. फ्रेडरिक विलेयर भौट, 'इकानामिक लिबरलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट' (बर्क, 1960), पृ० 126 । ऐनी एफ० हेक्शर, 'मर्कैटडॉमिज्म', ई० एफ० सीडरलड संस्करण (लंदन, 1955), जिल्ड 2, पृ० 338 । वाणिज्यवाद का लक्षण उपनिवेश और शासक देश के मध्य नियंत्रित बाजार का एक ऐसा संवध था जो व्यापार की शक्तों की उपनिवेश के विरुद्ध और शासक देश के पक्ष में कर देता था । व्यापार के द्वारा बाण का लक्षण आधुनिक साम्राज्यवाद में भी विद्यमान है 'मारिस हाउ, पोलिटिकल इकानामी एंड नैपिटलिज्म (लंदन, 1960) पृ० 229 ।
- 74 जे० थी० ब्रेनर, 'लेस्ते केअरे एंड स्टेट इंटरवेंशनलिज्म इन नाइट्रीज सेबुरी ब्रिटेन', 'जर्नल आफ इकानामिक हिस्ट्री', 1948, जिल्ड 7, पृ० 59 । ब्रेनर स्पष्ट करता है कि हंगेरी में नए उद्यमकर्ताओं ने राज्य से नई स्वतंत्रताओं के साथ-साथ नई सेवाएं भी प्राप्त कीं । अहमदशेरी नोति 'एक राजनीति एवं आर्थिक मिशन' अथवा 'एक भारी भी जिसे नए रिज्म के उद्यमकर्ताओं

ने सामंती कुलीनतन्त्र के विरुद्ध अपनी राजनीतिक व आर्थिक लड़ाई में इस्तेमाल किया था ।'

75. कही-कही खडन-मडन की लुटि के बावजूद बार० मो० दत्त के उत्कृष्ट ग्रंथ 'इकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया इन विस्टोरियन एज' (लंदन, 1903) में टैरिफ नीति का सबसे अधिक विस्तृत विश्लेषण मिलता है ।
76. देखें बी० एम० भ्राटिया, 'फंमोस इन इंडिया' (बर्नई, 1966) पृ० 105-108, 182-83 ।
77. विधान परिषद में जेम्स विल्सन का भाषण, 14 अप्रैल, 1860, विधान परिषद कार्यविवरण 1860 (पुरानो सीरीज, जिल्द 6) पृ० 376 ।
78. एम० डी० मोरिस पूर्वोद्धृत, पृ० 615-16, देखें अध्याय 3 आगे ।
79. एस० के० सेन, 'स्टडीज, इन इन्स्टिट्यूशनल पालिसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया' (कलकत्ता, 1964) । 'अहस्तक्षेपी नीति के कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक पूंजीनिवेश में तगी' (पृ० 158) अध्याय 8, यत्र-तत्र ।
80. जे० ए० शुपीटर, 'हिस्ट्री आफ इकानामिक एनेलिसिस' (न्यूयार्क, 1959) पृ० 761 ।
81. सिल्वर एच० जेम्स 'दि माइपेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल' (लंदन, 1938) पृ० 230-31 ।
82. ए० बी० डायसी, 'लैबर्स आन दी रिलेशन बिटवीन ला एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड इयूरिंग दि नाइटीज सेचुरी' (लंदन, 1962) पृ० 175 ।
83. 'रात्रि प्रहरी' राज्य के विषय में लतीफे के लिए जर्मन जिम्मेदार नहीं है । ऐसा लगता है कि रात्रि प्रहरी की उपमा लैजली ने बी बी और कार्लाइल ने 'सिपाही सहित अराजकता' शब्दों के आधार पर अहस्तक्षेपी नीति का उपहास किया था ।
84. जे० ई० कैरनीज, 'ऐमेज इन पोलिटिकल इकानामी : बिजिटिकल एंड ऐप्लाइड' (लंदन, 1873) । भाषण का शीर्षक 'पोलिटिकल इकानामी एंड सेसे फेअर', पृ० 252 ।
85. वही पृ० 188 । कैरनीज ने आयरलैंड में कृषि सबंधों में बिघाई हरतक्षेप के विरुद्ध अहस्तक्षेपी नीति पर आधारित कूटनीतिक तर्कों की निंदा की है । 'वही' पृ० 202, 'पोलिटिकल इकानामी एंड लैड' पर लेख (फोर्टनाइटली रिव्यू, जनवरी, 1870) यह लेख रॉबर्ट नाइट की पत्रिका 'दि इंडियन इकानामिस्ट' में फिर प्रकाशित हुआ था (जुलाई, 1874) ।
86. दोनों ही मेन के प्रति काफी आभार प्रकाशित करते हैं । डब्ल्यू० वेजहाट 'फिजिक्स एंड पालिटिक्स आर पाट आन दि ऐप्लिकेशन आफ दि प्रिंसिपल्स आफ नेचुरल सिंलैक्शन एंड इन हैरि-टैम टु पोलिटिकल सोसाइटी' (लंदन, 1872) पृ० 12, 22 । टी० ई० सी० लैजली, 'ऐसेज इन पोलिटिकल इकानामी' (डबलिन, 1888) पृ० 93 । लैजली के मतानुसार मेन की 'एशेंट ला एंड विलेज कम्युनिटीज इन दि ईस्ट एंड वेस्ट' के विषय में कृतिया अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी । लैजली ट्रिनिटी कालिज, डबलिन में मेन का विचारार्थ रहा था ।
87. डब्ल्यू० वेजहाट, पूर्वोद्धृत, पृ० 54 ।
88. वही, पृ० 11 ।
89. टी० ई० सी० लैजली, पूर्वोद्धृत 189 ।
90. वही पृ० 175 तुलनीय 'दि हिस्ट्री आफ जर्मन पोलिटिकल इकानामी' (फोर्टनाइटली रिव्यू, जुलाई, 1875 से पुनः मुद्रित) ।
91. वही, पृ० 83 ।

92. के० माक्सं 'ब्रिटिश रुस इन इंडिया' 'न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून' 25 जून, 1853। 'दि फर्स्ट इंडियन वार आफ इन्डिपेंडेंस' (मास्को, तिथि नहीं) पृ० 17।
93. के० माक्सं, 'दि ईस्ट इंडिया कंपनी इट्स हिस्ट्री एंड रिजल्ट्स' एन० यू० डी० टी०, 11 जुलाई/1863 प्रबोद्धत, पृ० 30।
94. के० माक्सं प्रबोद्धत, पृ० 34, 36।
95. पी० जे० जायीरदार, 'स्टडीज इन दि सोशल थाट आफ एम० जी० रानाडे, पृ० 123।

## वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

भारत सरकार की वित्तीय-प्रशासन प्रणाली बेतरतीब ढंग से 'हाथो-हाथ विकसित' होती गई। इस प्रणाली का युक्तिकरण तथा अनेक संस्थागत परिवर्तनों का प्रवर्तन कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की उपलब्धि था जिन्होंने सैन्य-विद्रोह के ठीक बाद के दशक में इस कार्य में अपने आपको लगाया था। सैन्य-विद्रोह द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट से ऐसा आघात लगा कि इस कार्य की ओर ध्यान गया। और 1858 में सत्ता के हस्तांतरण से संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए अवसर मिला। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने और विकासमान प्रणाली को समझने के लिए संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों या भारत सरकार के कानूनों की जांच कर लेना पर्याप्त नहीं है। हमें यह मालूम करने के लिए कि वित्तीय शक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता था, इस प्रणाली के क्रियान्वयन पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए।

हम भारत मंत्री की शक्तियों (अनुच्छेद I) और भारतीय वित्त मंत्री, जिसे उस समय वित्त सदस्य कहते थे, के कार्यों (अनुच्छेद II) का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के बाद वित्तीय मामलों पर विधान मंडल की तुलना में कार्याग अर्थात् सपरिषद गवर्नर जनरल की स्थिति पर (अनुच्छेद III) विचार करना होगा। वित्त-विभाग (अनुच्छेद IV) और बजट-प्रणाली (अनुच्छेद V) के विकास के संश्लेषित वित्तीय निरीक्षण और नियंत्रण की व्यापक प्रणाली की व्यवस्था हो गई। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण की नीति के विश्लेषण (अनुच्छेद VI) के साथ ही उत्तर-सैन्य-विद्रोह कालीन पुनर्निर्माण के अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली के विकास का हमारा यह अध्ययन पूर्ण हो जाता है।

### I

1858 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार वित्तीय मामलों में संवीक्षण (छानबीन) और नियंत्रण का अधिकार भारत मंत्री के हाथ में रखा गया। इससे भारत मंत्री को भारत सरकार के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण मिल गया। आरगाइल ने मेयो को एक अपने व्यक्तिगत पत्र में लिखा था कि वित्त एक 'व्यापक विषय है और इसके द्वारा प्रत्येक विभाग तक पहुंचा जा सकता है।'<sup>1</sup> गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1858 की धारा XLI के शब्दों में, 'भारत के राजस्व से किए जाने वाले व्यय पर चाहे वह भारत में हो या अन्यत्र, भारत मंत्री का नियंत्रण रहेगा, और इस राजस्व से अथवा इस अधिनियम

की बढ़ती संपरिपद भारत मंत्री के कब्जे में आने वाली किमी संपत्ति के किसी भी भाग का अनुदान या विनियोग संपरिपद काउंसिल की बैठक में बहुमत द्वारा सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।' इसके अलावा धारा 53 के अनुसार यह आवश्यक था कि जो वित्त वर्ष अभी पूरा हुआ है उसके ठीक पूर्व के वर्ष के आय-व्यय के व्योरो सहित पिछले वर्ष का अद्यतन प्राक्कलन सदन में प्रस्तुत किया जाए। भारत मंत्री का यह भी उत्तरदायित्व था कि वह भारत की आय से चुकाए जाने वाले ऋणों और दायित्वों के प्राक्कलन भी सदन में पेश करे।<sup>2</sup>

इंडिया आफिस में कठोर नियंत्रण की परंपरा मंत्रवतः कुछ इस भावस्मिक कारण से थी कि पहला भारत मंत्री सर चार्ल्स वुड बना जो, जैसा कि डलहौजी ने अपने एक वैयक्तिक पत्र में लिखा है, बेचैन और दस्तुंदाज प्रकृति का था।<sup>3</sup> वह 1858 के नए अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले वित्तीय नियंत्रण एवं निरीक्षण के अपने अधिकारों के विषय में विशेष रूप से दृढ़ था। यदि संपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा भारत मंत्री को बराबर सूचना देते रहने और संवीक्षण हेतु लेखों व प्राक्कलनों को इंडिया आफिस भेजने में असावधानी होती थी तो भारत मंत्री द्वारा कड़ी फटकार पड़ती थी। उदाहरणार्थ, 26 मार्च, 1860 के प्रेषण में वुड ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि 'आपकी सरकार द्वारा जो सूचना मेरे पास भेजी गई है वह इस देश के ही सार्वजनिक समाचार पत्रों के संपादकों तथा व्यक्तियों को मिलने वाली जानकारी से कहीं पुरानी है... यह सरकार की ऐसी भूल है जो भविष्य में दुबारा नहीं होनी चाहिए।' 12 जनवरी और 26 मई के वित्तीय प्रेषणों में भी इसी प्रकार की शिकायतें की गई थी।<sup>4</sup> प्रथम वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने वैयक्तिक पत्र-व्यवहार के द्वारा वुड के साथ संपर्क रखने का प्रयत्न किया था और कॉनिंग ने भारत मंत्री को यह विश्वास दिला रखा था कि बिना उसकी पूर्ण सम्मति के वित्तीय उपकरण 'कानून नहीं बनेंगे'।<sup>5</sup> विल्सन के उत्तराधिकारी सेमुअल लैंग को इंडिया आफिस को वित्तीय प्राक्कलन न भेजने और कलकत्ता गजट में भारत मंत्री के पास भेजे गए प्राक्कलनों से भिन्न प्राक्कलन प्रकाशित करने के लिए कड़ी फटकार मिली थी।<sup>6</sup> भारत मंत्री ने आदेश दिया था कि संसद के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए लेखों तथा प्राक्कलनों में भारत मंत्री को पूर्ण सूचना दिए बिना कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए।<sup>7</sup>

भारत और इंग्लैंड के बीच संचार के साधनों में सुधार हो जाने पर भारत मंत्री का शासन की बागडोर पर नियंत्रण और अधिक कठोर हो गया। भारत मंत्री ने 17 मार्च, 1864 के प्रेषण में वेतन वृद्धि व गृह अधिकारियों को पहले सूचना दिए बिना पद सृजन को रोकते हुए कहा कि भारत सरकार और इंग्लैंड के बीच संचार व्यवस्था अधिक तेज हो जाने से अब इस संबंध में स्वीकृति के लिए पहले से कम महत्वपूर्ण कारण रह गया है।<sup>8</sup> संपरिपद गवर्नर जनरल की ओर से तर्क दिया गया था कि नए नियम (जिसके द्वारा भारत सरकार को नए पद सृजित करने अथवा वेतन बढ़ाने से रोका गया था) के अनुसार विधान द्वारा नए पद के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने से इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा निर्धारित विधान मंडल की शक्तियों को अवैध ढंग में सीमित कर दिया गया

है।<sup>10</sup> किंतु भारत मंत्री ने ठीक ही स्पष्ट किया कि इंडियन काउंसिल एक्ट की 22वीं धारा के अंतर्गत भारतीय विधान मंडल को ऐसे कानून बनाने से स्पष्ट रूप में रोका गया है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट (21 तथा 22, विक० सी० 106) के किन्हीं भी उपबन्धों को प्रभावित करते हैं। इससे वित्तीय मामलों पर भारत मंत्री का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। 'इस प्रतिबंध से स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि सपरिषद गवर्नर जनरल को कानून बनाने के संबंध में जो शक्तियाँ दी गई थी वे व्यापक होते हुए भी, जहाँ तक राजस्व संबंधी शक्ति के प्रयोग का सवाल था, भारत मंत्री के नियंत्रण में रहते हुए प्रयोग की जाती थी।'<sup>11</sup> भारत सरकार को आशंका थी कि पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने में जो समय लगेगा उससे होने वाली देरी सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगी। परंतु भारत मंत्री का विचार था यदि भारत सरकार व्यय संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर डालती है तो भारत मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों के लिए उन्हें अस्वीकार कर पाना कठिन होगा। इससे भारत सरकार की कार्यवाही की अस्वीकृति का संकेत मिलेगा।<sup>12</sup> कुछ भी हो, स्थलीय केबल (1868) स्वेज नहर (1869) तथा समुद्री केबल (1870) के रूप में संचार व्यवस्था के विकास से भारत के वित्तीय मामलों पर भारत मंत्री का नियंत्रण बढ़ गया। मेयो तथा आरगाइल प्रायः तार से बात कर लेते थे।<sup>13</sup>

यद्यपि सिद्धांत रूप में वित्तीय निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत मंत्री को ही मिला हुआ था, तथापि उसकी परिषद तथा ससद वित्तीय नीति पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकी। 1858 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत मंत्री को कुछ मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर देने की शक्ति प्राप्त हो गई थी परंतु संपत्ति से आय के विनियोग, मुद्रा की प्राप्ति के लिए प्रतिभूतियों के निर्गमन, अनुबंधों, वेतन-दर में परिवर्तन आदि के विषय में वह ऐसा नहीं कर सकता था। 1869 में सर सी० वुड के उत्तराधिकारी लार्ड फ्रेनबोर्न ने परिषद की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव रखा। उसके विचार से परिषद व्यय के संबंध में अपनी शक्ति के आधार पर भारत मंत्री के विरुद्ध भी सामान्य-नीति को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकार का दावा कर सकती थी।<sup>14</sup> यद्यपि परिषद की शक्तियों में पुनः कमी नहीं की गई, तथापि 1869 के विधान (32 तथा 33 विक० भी० 97) द्वारा जब भारत मंत्री को इंडिया काउंसिल में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करने का अधिकार मिला तो उसके हाथ अधिक मजबूत हुए। परिषद के सदस्यों का कार्य काल 'सदाचरण काल' के बजाय दस वर्ष कर दिया गया। सर सी० वुड ने अपने अनुभव से समझा कि इंडिया काउंसिल 'किसी भी देश की सरकार द्वारा कभी भी खोजे गए यंत्रों में सबसे अधिक दुर्बलतम यंत्र था।'<sup>15</sup> वुड का कथन है कि परिषद से आशा की गई थी कि वह 'समस्त भारत के विषय में एकत्रित ज्ञान' के आधार पर भारत मंत्री को सहायता देगी।<sup>16</sup> परंतु असैनिक तथा सैनिक सेवाओं से निवृत्त व्यक्तियों ने जो भी अनुभव प्राप्त किया था और उनके जो विचार थे, वे सभी शीघ्र ही पुराने हो गए।<sup>17</sup> एक बार व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को परिषद में लाने की दृष्टि से प्रस्ताव रखा गया कि व्यावसायिक वर्ष के कुछ सदस्य और कुछ असैनिक अधिकारियों को 'सीधा जिले से' परिषद में लाया जाना चाहिए, परंतु यह

प्रस्ताव अस्वीकार हो गया।<sup>18</sup> परिपद के अधिकांश सदस्य भारतीय वित्त की तकनीकी वारीकियों को समझ पाने में असमर्थ थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया आफिस के वित्त-विभाग का सचिव भारत मंत्री का वित्तीय मामलों पर सबसे प्रमुख सलाहकार होता था। फिर भी, भारत मंत्री की दृष्टि से परिपद आवरण की भांति उपयोगी थी। प्रायः भारत मंत्री अपने आपको परिपद रूपी शिखंडी की आड़ में कर लेता था। नार्थ-कोट ने जान सारेंस को लिखा था कि 'मुझे लगता है कि मैं आदम की भांति हूँ जो अपनी समस्त भूलों को होवा पर मढ़ने के लिए तत्पर है। मैं परिपद रूपी होवा के दिए हुए फल खा गया हूँ'।<sup>19</sup>

1858 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के उपबन्धों का पालन करने के उद्देश्य से हर साल भारत मंत्री संसद में वित्त-विवरण रखता था परंतु प्रायः अधिवेशन के अंत में रखे जाने वाले इन विवरणों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था और कुछ थोड़े से सदस्य ही जानकारी के आधार पर आलोचना कर पाने में समर्थ होते थे।<sup>20</sup> इसके विपक्ष में सामान्य रूप से लोगों को पता था और भारतीय मामलों की इस उपेक्षा के लिए यहाँ के समाचार पत्रों में प्रायः आलोचनात्मक टीका-टिप्पणी होती थी।<sup>21</sup> यद्यपि भारतीय मामलों की ओर सामान्यतः अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था (सैन्य-विद्रोह जैसे संकट के मौकों को छोड़कर), लेकिन संसद में कुछ ऐसे गुट थे जो भारत की आर्थिक और वित्तीय नीति में विशेष रुचि रखते थे। इस प्रकार का एक गुट सूती-वस्त्र उद्योग के हितों के प्रति उदार संसद सदस्यों (काटन एम० पीज) का था जो भारत से कपास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत मंत्री के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव डालते थे। यह गुट विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका से गृह-युद्ध काल में कपास की आपूर्ति रुक जाने के कारण लंकाशायर में कपास के अभाव के समय सक्रिय था।<sup>22</sup> कुछ संसद सदस्य अफीम विरोधी आंदोलन से संबंधित थे जो अधिकारियों को अफीम का व्यापार (आय की दृष्टि से इस स्रोत का महत्व मालगुजारी के बाद ही था) बढ़ाने के लिए रजामंद करने तथा उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे।<sup>23</sup> यह भी लोकविदित है कि व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव गुट भारत सरकार की टैरिफ नीति पर ध्यान रखते थे।<sup>24</sup>

कंपनी के शासन काल में भारतीय मामलों का समय-समय पर पुनर्विलोकन होता रहता था। 1870 में भारतीय वित्त के ऐसे ही पुनर्विलोकन का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में गवर्नर जनरल और भारत-मंत्री के बीच का पत्र-व्यवहार बहुत मनोरंजक है क्योंकि इससे इस बात का संकेत मिलता है कि मेयो निश्चित रूप से मंसदीय जाच के विरोध में था और आरगाइल को इस संबंध में कोई उत्साह नहीं था। मेयो को आशंका थी कि भारतीय वित्त के संबंध में प्रस्तावित प्रवर समिति से भारत की जनता की यह धारणा बनेगी कि भारत सरकार को राजा और इंग्लैंड की सरकार का विश्वास प्राप्त नहीं है। उसने कहा था कि 'अज्ञान और दुर्भाव की उत्पत्ति को निगलने के लिए संदेन में शेर का मुँह खोलने से—पुरानी भ्रातियों और नई गलतियों के बचाव से कोई लाभ नहीं होगा।'<sup>25</sup> मेयो का विचार था कि संसद सदस्यों द्वारा की गई जाच से कोई परिणाम

नहीं निकलेगा क्योंकि वे भारत की तत्कालीन स्थिति से पूर्ण अनभिज्ञ थे। 'लंदन में ऐसे कलाप्रेमी भारतीय राजनीति के मर्मज्ञों और पुराने एंग्लो इंडियनों की भीड़ लगी है जो पन्द्रह-बीस वर्ष पुराने भारत को ही जानते हैं। उनके पास ऐसी तीलिया है जिनमें से नब्बे प्रतिशत बहुत पहले ही जल चुकी है। आशंका इस बात की है कि ये पुनः न सुलगाई जाए।' <sup>26</sup> मेयो जांच के विस्तार-क्षेत्र को सीमित रखना चाहता था। उसने आर-गाइल को लिखा था कि 'मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि यदि इसका (संसद की प्रवर समिति का) कोई परिणाम निकलना है तो वह अच्छा नहीं होगा... मुझे आशा है कि आप जांच को कुछ विशेष मामलों के स्पष्टीकरण तक ही सीमित कर सकेंगे।' <sup>27</sup> मेयो को डर था कि भारत सरकार अपना बचाव कर पाने में सफल नहीं होगी, विशेषकर इस कारण से भी कि उसके वित्तीय-मुद्धारसफल नहीं हुए थे। <sup>28</sup> प्रवर समिति की कार्यवाही को देखकर वित्त-सदस्य टैपिल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उसके कुछ प्रमुख सदस्य और विशेष रूप से प्रोफेसर एफ० फासट भारत सरकार के प्रति पूर्वग्रह रखते थे। <sup>29</sup> परंतु भारत मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रवर समिति यद्यपि 'एक मुसीबत' है, फिर भी उसकी अपनी उपयोगिता है। उसने मेयो को लिखा था कि 'मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि आपको एक संसदीय समिति पर एनराज है। भारत सरकार ने सदैव ही उनका विरोध किया है और यह उनके लिए स्वाभाविक ही है। परंतु जैसा आपको विदित है, पुराने जमाने में भी शासन-पत्र (चाटर्स) के प्रत्येक नवीकरण के समय ये जांच अनिवार्य रूप से होती थीं और यह अस्वाभाविक नहीं है कि नवीन शासन में संसद भारतीय मामलों पर अपने विचारों को रखने के लिए अवसर चाहे। व्यक्तिगत रूप से तो इस प्रकार की समिति यहां पर हम सभी के लिए एक मुसीबत ही है।' <sup>30</sup> ऐसा लगता है कि गवर्नर जनरल, भारत मंत्री तथा वित्त सदस्य सभी संसदीय जांच के बारे में अधिक उत्साही नहीं थे। भारत सरकार ऐसे लोगो से जिन्हें मेयो ने डिजरायली को अपने एक पत्र में 'भारतीय शिकायतवाज' कहा है, डरती थी। इन शिकायतवाजों में 'अतिवादी थे जिनकी भारत सरकार के प्रतिकूल सभी प्रस्तावों का समर्थन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी।' <sup>31</sup> संसद का हस्तक्षेप ऐसा लगता है कि एक मुसीबत तो थी ही, साथ ही इससे साम्राज्य के मरक्षकों के मस्तिष्क में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती थी।

## II

अब हम भारत में चालू व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे। उत्तर मैन्य-विद्रोह काल में गवर्नर जनरल की परिपद में वित्त-सदस्य वित्तीय व्यवस्था का कर्णधार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिपद में जेम्स विल्सन के शामिल होने से पहले कोई भी सदस्य वित्त-विभाग का कार्यभारी नहीं होता था। उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में प्रचलित व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए रिचर्ड टैपिल लिखता है, 'उन दिनों में आज की भांति (1880 में) गवर्नर जनरल तथा उसकी परिपद के सदस्यों के बीच काम का विभाजन बहुत थोड़ा या बिल्कुल ही नहीं था। आज की व्यवस्था में तो भारत सरकार



कुछ-कुछ ब्रिटिश मन्त्रि परिषद की भांति ही काम करती है। उस समय वित्त में सरकार के किसी एक सदस्य का सर्वध्वज न होकर सभी सदस्यों का सर्वध्वज समान रूप से था।<sup>32</sup> जब जेम्स विल्सन से सर चार्ल्स वुड ने भारत जाकर गवर्नर जनरल की परिषद में एक रिक्त स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया तो उसे विश्वास दिलाया गया कि उसका पद 'भारत के वित्त मंत्री, (चायतर आफ एक्सचेंजर) का होगा।'<sup>33</sup> शासकीय रूप से उसका ओहदा गवर्नर जनरल की परिषद में 'चौथे साधारण सदस्य' का था। वह सामान्यतः 'वित्तीय-सदस्य' के रूप में जाना जाता था और उसे मौकरगाही विरामिद में 'कानूनी विषयों के सदस्य' तथा 'मैनिफेस्ट मामलों के सदस्य' के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त था।

कैनिंग के निर्देशन में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में काम के बंटवारे के लिए सविभागीय व्यवस्था का विकास हुआ।<sup>34</sup> 1860 के इंडियन काउंसिल एक्ट की धारा 8 के आधार पर गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। वित्त सदस्य की नियुक्ति विशिष्टीकरण और कार्यों के बंटवारे की दिशा में कदम था। वित्त संबंधी तकनीकी वारीकियों का विशेषज्ञ होने के कारण वित्त सदस्य की परिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक सुविधाजनक स्थिति प्राप्त थी। विशेष रूप से उन वित्त सदस्यों (जैसे कि जेम्स विल्सन तथा मेमुअल लैंग) को जो इंग्लैंड से भेजे गए थे, सिविल सेवा से पदोन्नति प्राप्त कर वायसराय की परिषद का सदस्य बनने वाले लोगों की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त होता था। 1870 में भारत मंत्री आरगाइन ने लिखा था 'यदि इंग्लैंड में कोई अच्छा सार्वजनिक व्यक्ति उपलब्ध हो तो इस (वित्त सदस्य के) पद पर उस की नियुक्ति के अनेक लाभ हैं। सिविल-सेवा का कोई भी व्यक्ति अपनी ही श्रेणी के दूसरे व्यक्तियों की ईर्ष्या से बच नहीं पाता है, जबकि इंग्लैंड से जाने वाले व्यक्ति को भारतीय सिविल-सेवा से आने वाले व्यक्ति की तुलना में यूरोपीय तथा भारतवासी दोनों ही लोग, अधिक आदर की दृष्टि से देखते हैं।'<sup>35</sup> जेम्स विल्सन को मिली असाधारण सफलता से यह धारणा बन गई कि इंग्लैंड से भेजे जाने वाले व्यक्ति विशेष रूप से यदि उनके पास विल्सन की भांति राजकीय का अनुभव हो तो वे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 'गृह अधिकारियों' ने अनुभव किया कि भारतीय वित्त संगठन के लिए 'एक ऐसे नए व्यक्ति की आवश्यकता है जो ब्रिटिश राजकीय के दृष्टिकोण से भारतीय-वित्त पर विचार करे...'।<sup>36</sup> तथापि भारत में सिविल-सेवा के लोगों में प्रचलित मत इंग्लैंड से आने वाले 'बाहरी व्यक्तियों' की वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के विरुद्ध था। उदाहरण के लिए सर बार्टल फ़ोर का विचार था कि वित्त मंत्रियों के इंग्लैंड से जायात करने का प्रयास करना निरर्थक था, 'इसकी लागत की तुलना में लाभ कम है; क्योंकि जो भी व्यक्ति यहां आता है वह सोचता कि रोमन वाणिज्य दूत की भांति उसे एक ही वर्ष में या अधिक से अधिक दो-तीन वर्षों में ख्याति प्राप्त करनी है और वह अपने पूर्वाधिकारियों की नीति का ईमानदारी के साथ पालन करने से ही सन्तुष्ट नहीं होगा।'<sup>37</sup> बार्टल फ़ोर ने सर चार्ल्स वुड को लिखा था कि भारत को 'वित्त संबंधी

मर्मज्ञता के 'चमत्कारों' के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर नहीं देखना चाहिए। ठेठ भारतीय सिविल-सेवा के व्यक्ति की भांति वार्टल फ्रेर' कहता है कि भारत सरकार के वित्त विभाग के लिए केवल कठोर परिश्रम, व 'अधिक उपयोगी चाकरी' और 'सैकड़ों छोटी-छोटी बातों में अच्छे प्रबंध' की आवश्यकता है।<sup>38</sup> यही भारत की सिविलियन पार्टी का मत था। 'हिंदू पेट्रिअट' ने, जो प्रबुद्ध भारतीय लोकमत को अभिव्यक्त करता था, सिविलियन पार्टी की प्रतारणा करते हुए कहा, 'हमें वित्त मंत्री के पद के लिए वित्त-मर्मज्ञ की आवश्यकता है, न कि ऐसे 'व्यक्ति की जो केवल प्रशासक हो और भारतीय सिविल-सेवा से आने वाले व्यक्ति कितने ही कुशल प्रशासक क्यों न हों वे साधारणतया वित्त-मर्मज्ञ नहीं होते।'<sup>39</sup> 'हिंदू पेट्रिअट' ने भारत के वित्त-प्रबंध का उत्तरदायित्व सिविल-सेवा में आने वाले व्यक्तियों को सौंपने की पुरानी नीति की निंदा की, क्योंकि ये व्यक्ति 'नासमझ और अप्रगतिशील' रहे हैं (यथावत) और इन पर नवीन ब्रिटिश विचारों का स्वस्थ प्रभाव न होने के कारण ये वित्त सबधी कठिन समस्याओं का ठीक समाधान खोजने में असमर्थ रहे हैं।<sup>40</sup> कुछ भी हो, वित्तीय मामलों के अंग्रेज विशेषज्ञों (जैसे एस० लैंग) तथा सार्वजनिक व्यक्तियों (ज० विल्सन)<sup>41</sup> की सेवाएं प्राप्त कर पाना कठिन था, अतः वायसराय की परिपद में रिक्त स्थानों की पूर्ति उन सिविल-सेवा अधिकारियों से की गई जिन्हें इंग्लैंड (जैसे सर सी० ट्रेवीलियन) तथा भारत (सर आर० टैपिल) में वित्त संबंधी अनुभव प्राप्त था।

प्रस्तुत अध्ययन की कलाविधि में जिस व्यवस्था का विकास हुआ वह कुछ बातों में ब्रिटिश मंत्रि परिपद की व्यवस्था की भांति थी। प्रथम भारतीय वित्त सदस्य की नियुक्ति की हाउस आफ कामंस में घोषणा करते हुए सर चार्ल्स ब्रुड ने कहा था कि वित्त-सदस्य 'गवर्नर जनरल का अतरंग मित्र नहीं होगा और वह अकेला ही देश के विन के लिए उत्तरदाई नहीं होगा। वह गवर्नर जनरल की परिपद का सदस्य होगा और वह वित्त विभाग का कार्य सभालेगा, परंतु गवर्नर जनरल और उसकी परिपद उसके कार्यों के लिए उत्तरदाई होंगे क्योंकि वह उनकी स्वीकृति तथा सहमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता।'<sup>42</sup> भारत मंत्री ने सपरिपद गवर्नर जनरल को अपने प्रेषणों में वित्त सदस्य की स्थिति और उसके उत्तरदायित्वों की सीमाएं सतर्कतापूर्वक समझाईं। भारत मंत्री ने लिखा कि परिपद के चौथे साधारण सदस्य का कार्य 'आपके समक्ष विचार और निर्णय के लिए वित्तीय उपायों के बारे में अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव रखना होगा' श्री विल्सन केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जो परिपद के अन्य सदस्यों को प्राप्त है और आपकी सरकार द्वारा किए गए सभी निश्चयों के लिए आपको ही उत्तरदाई ठहराया जाएगा।<sup>43</sup> वित्त विवरण अथवा वित्त सदस्य के वजट भाषण में समूची सरकारी नीति का वर्णन होना चाहिए। भारत मंत्री ने एक अन्य प्रेषण में लिखा 'यद्यपि यह तो असंभव है कि आपकी सरकार को आपकी परिपद के सदस्य (वित्त सदस्य) के सभी कार्यों के लिए उत्तरदाई ठहराया जाए, तथापि वित्त-विवरण की प्रमुख बातों में सरकारी विचारधारा का विवरण भी अवश्य होना चाहिए, और भारत सरकार वित्त सदस्य द्वारा तैयार किए गए विवरणों तथा प्रस्तावों के लिए उत्तरदाई होगी, क्योंकि

इन मामलों में वह सरकार के अंग के रूप में ही कार्य करता और वक्तव्य देता है।<sup>44</sup>

‘मंत्रि परिषद के नियमों’ के अनुसार परिषद के सदस्यों को ‘मंत्री परिषद की गोपनीय बातें प्रकट करने का अधिकार नहीं था। वे परिषद द्वारा निर्णीत विषयों के संबंध में मतभेदों पर खुलेआम विचार-विनिमय नहीं कर सकते थे। एक बार मैनिक मामलों के सदस्य सर विलियम मैन्सफील्ड को मेयो ने सार्वजनिक रूप से ऐसे वक्तव्य देने पर गुप्त रूप से फटकारा था जिससे 1866-69 के बजट पर परिषद में गंभीर मतभेद का पता लग गया था।<sup>45</sup> मैन्सफील्ड इस बात से दुखी था कि परिषद के सदस्यों को ‘सार्वजनिक रूप से उन बातों का समर्थन करना आवश्यक था जिन्हें गुप्त बैठकों में वे निश्चित रूप से अस्वीकार करते थे और उनका विरोध करते थे।’<sup>46</sup> परंतु उसने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि परिषद में होने वाली बहस को बाहर नहीं लाना चाहिए और उसने उन वित्तीय उपायों का विधान परिषद में समर्थन किया तथा उनके पक्ष में मत दिया जिनका कार्यकारी परिषद में उसने विरोध किया था।<sup>47</sup> परिषद में सर्वसम्मति वाछनीय थी और लगभग हमेशा हो भी जाती थी। भारत मंत्री को भेजे जाने वाले प्रेषणों पर परिषद के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते थे। यदि कोई सदस्य सहमत नहीं होता था तो उसे अपनी विसम्मति-टिप्पणी लिख कर ही संतुष्ट हो जाना पड़ता था। इस संदर्भ में ‘कुछ करने की उमंग जिसे वे अपने मत को लिपिबद्ध कराना चाहते थे’ (जिससे मेयो के धैर्य की परीक्षा हुई) समझी जा सकती है।<sup>48</sup> कार्यवृत्त लिखने की आदत सैन्य-विद्रोह के पहले से चली आ रही थी। उस समय सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच अधिकांश विचार विनिमय कार्यवृत्त तथा नोट लिख कर होता था जो काले संदूकों में धीरे-धीरे घूमते रहते थे और जिनके गंभीर अनुशीलन के साथ-साथ उन पर टिप्पणी होती थी जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था।<sup>49</sup> एक बार भारत मंत्री नोर्थकोट ने यह प्रस्ताव रखा था कि परिषद में मतभेद से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए परिषद की तुलना में गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ा दी जानी चाहिए। नोर्थकोट ने गवर्नर जनरल जान लारेंस को अपने एक व्यक्तिगत पत्र में लिखा था कि ‘गवर्नर जनरल को अधिक स्वतंत्र स्थिति प्रदान करने की मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है और मैं चाहता हूँ कि वह अपनी परिषद के सदस्यों को मनोनीत करे तथा जब उपयुक्त समझे उनके मत की अवहेलना भी कर सके और प्रेषणों पर उसी के हस्ताक्षर हो (न कि संपूर्ण परिषद के)।’<sup>50</sup> तथापि नोर्थकोट को अपना यह विचार छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे पता लगा कि हाउस आफ कामंस में प्रचलित मत इस पक्ष में नहीं था कि गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ दी जाए।<sup>51</sup>

### III -

1853 के एक्ट (16 तथा 17 विक्ट० सी० 95) के अंतर्गत विधान परिषद अपना कार्य इस प्रकार करती थी जो ऊपरी तौर से किसी भी ससदीय सस्था की कार्य-विधियों से मिलता-जुलता था।<sup>52</sup> न केवल सभी विषयों पर विधान परिषद के सदस्यों को मत देने का अधिकार था, बल्कि विधान परिषद के कार्य वितरण जनसाधारण के

सामने पेश किए जाते थे और उन्हें प्रकाशित भी किया जाता था। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को मैन्यु विद्रोह द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट पर नियंत्रण पाने के लिए जो कराधान संबंधी विविध उपाय करने पड़े थे उन्हें विधान परिषद के सामने रखना पड़ा था। विधान परिषद के 1859-60 के कार्य विवरण से स्पष्ट है कि जब इस वर्ष में आय कर संबंधी विविध प्रस्तावों पर बहस हुई तो विधान परिषद के अनुभवी सरकारी सदस्य इस स्थिति में थे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की आलोचना कर सकें और उन्हें प्रभावित भी कर सकें।<sup>53</sup> विधान परिषद के सामने पहला बजट 18 फरवरी, 1960 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बार्टल फ़ोर के अनुसार इस बात ने, और 'कराधान की आवश्यकता ने' 'उसके कार्य विवरण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।'<sup>54</sup> विधान परिषद की भूमिका के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। सर चार्ल्स वुड का मत था कि विधान परिषद ने वह भूमिका अपना ली थी जो उसको सौंपी नहीं गई थी। वह मार्वाजनिक बहस के लिए एक मंच बन रही थी और वह कार्यकारी के कार्यों की जांच करने के लिए बहुत इच्छुक थी।<sup>55</sup> उसके विरोधियों का मत था कि विधान परिषद उपयोगी कार्य कर रही थी। उदाहरण के लिए सर बार्टल फ़ोर ने वुड को लिखा था 'लार्ड डलहौजी ने परिषद को विचार विमर्श सभा का रूप दिया था और 1857 के संघर्ष विद्रोह ने उसके लिए नए कर लगाना आवश्यक कर दिया। परिणामतः भारत सरकार के लिए पहले से अधिक कठिनाई हो गई है, परंतु परिणाम कुछ भी हो, मेरा विचार यह है कि अब पीछे हटना असंभव है और अब मुझे कानून बनने से पहले होने वाले इस प्रकार के विचार विमर्श के बिना करों के बढ़ाने में भारी खतरा दिखाई देता है।'<sup>56</sup> तथापि, सर चार्ल्स वुड ने स्पष्ट किया कि विधान-परिषद (1853 के एक्ट के अनुसार) में भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके ही शब्दों में, 'मैं इस संभावना से कि भारतीय प्रजा (शासितों) के लिए भारत में बसने वाले अंग्रेज (यथावत) कानून बनाएंगे, निश्चित नहीं हूँ ...'<sup>57</sup>

1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट (24 व 25 विक्ट० सी० 67) के द्वारा विधान-परिषद की शक्तियों में परिवर्तन हुआ। परिषद में गैर सरकारी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और यद्यपि इस विषय में वैधानिक व्यवस्था तो नहीं की गई थी, तथापि हाउस आफ कामंस में यह आश्वासन दिया गया था कि गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा।<sup>58</sup> कोई भी नया उपाय जो सरकारी राजस्व या ऋण को प्रभावित करता था उसके लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होती थी (धारा 19)। तकनीकी तौर पर विधान परिषद में बजट पर बहस नहीं हो सकती थी क्योंकि परिषद की शक्तियां केवल विधि निर्माण तक ही सीमित थी (निस्संदेह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्तावों पर विचार हो सकता था)। फिर भी 1861 से 1872 की अवधि में प्रति वर्ष वित्त संबंधी वक्तव्य विधान-परिषद में दिए गए, क्योंकि हर वर्ष नए वित्त संबंधी विधान की आवश्यकता होती थी। अतः नवीन कराधान-विधेयकों के पेश होने के समय परिषद में वित्त के पुनर्विलोकन या बजट पर वक्तव्य और थोड़े से विचार विमर्श के लिए अवसर मिल जाता

था। जब किसी नए वित्तीय विधान की आवश्यकता नहीं होती थी (जैसे 1873-76 की अवधि में) तो परिपद में वित्त मंत्री वक्तव्य के स्थान पर सरकार भारत के बजट में वित्त-विवरण प्रकाशित करती थी। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट (55 व 56 विक्ट० सी० 14) पास होने तक विधान परिपद को वार्षिक वित्त विवरण पर बहस करने तथा उसके संबंध में प्रश्न करने का अधिकार नहीं था।<sup>59</sup>

भारतीय जनता के एकमात्र मुखर और सुलभ हुए विचारों वाले शिक्षित मध्यम वर्ग की ओर से ऐसी व्यवस्था की मांग की गई जिसमें विधान परिपद के माध्यम से लोक वित्त के ऊपर कुछ तो सार्वजनिक नियंत्रण हो। जैसा कि हम आगे देखेंगे, प्रमुख 'स्वदेशी' अखबार तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाएं तत्कालीन व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट थी।<sup>60</sup> सर चार्ल्स ट्रेवीलियन के शब्दों में यह व्यवस्था 'लोकप्रिय विधान सभा के बाह्य रूप एवं कार्यविधियों की बनावटी नकल' मात्र थी और इसमें भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था।<sup>61</sup> तथापि भारत सरकार संतुष्ट थी कि तत्कालीन व्यवस्था कुशल प्रशासन की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त थी। 1867 में भारत मंत्री ने सपरिपद गवर्नर जनरल को लिखा था 'जो व्यवस्था वार्षिक बजट (परिपद में) पेश करते समय से धीरे-धीरे कायम हो गई है वह सामान्य बुद्धि, सुविधा तथा देश की परिस्थितियों पर आधारित है।'<sup>62</sup> विधान परिपद से, जिसके सदस्यों में अनुभवी अफसर, गैर अफसर, यूरोपीय व्यापारी और भारतीय अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मनोनीत सदस्य होते थे, आग्रह किया जाता था कि उसके पास भेजे गए प्रस्ताव सरकार की जिम्मेदारी पर, और उसके द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर कि आपूर्तियां वास्तव में आवश्यक हो थी, अपेक्षाकृत अल्प विचार विमर्श के बाद ही स्वीकार कर लिए जाए। सरकार का विचार था कि तत्कालीन परिस्थितियों में विधायी संस्था की स्वीकृति प्राप्त करने की यह सबसे कुशल रीति थी। भारत सरकार को 'इसमें प्रायः भारी अमुविधा हो सकती थी, यदि बजट प्रणाली में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कानून कार्य-संचालन के नियमों के अंतर्गत कर दिया जाता।' भारत जैसे बड़े देश में सरकारी कामों में कुछ देरी अनिवार्य थी। परंतु यदि सामान्य विधिकरण के लिए निर्धारित सभी नियमों के पालन को राजस्व-विधान के निर्माण के लिए भी आवश्यक कर दिया जाता है तो और अधिक विलंब आवश्यक हो जाएगा और नए करो से वित्तीय साधनों का संग्रह कुछ महीनों के लिए स्थगित हो जाएगा जिसके परिणाम वार्षिक बजट प्रणाली के लिए वास्तव में घातक होंगे।'<sup>63</sup> 'स्वदेशी' समाचार पत्र तथा समुदाय (इस संबंध में) राजनीतिक अधिकारों की बात करते थे, जबकि नौकरशाही के दिमाग के लिए यह केवल प्रशासनिक सुविधा का प्रश्न था।

#### IV

1843 में स्थापित वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी प्रारंभ में भारत सरकार का मुख्य वित्त सचिव चीफ फाइनेंसियल सेक्रेटरी होता था। प्रारंभ में इस विभाग का अधिकांश कार्य व्यय नियंत्रण से संबंधित था जबकि राजस्व संग्रह शाखा में बहुत सारे

वित्तीय क्रिया कलाप का प्रभारी गृह विभाग था। सितंबर, 1859 में सर चार्ल्स वुड ने गुप्त रूप से गवर्नर जनरल को प्रचलित व्यवस्था पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। उसने लिखा था, 'राजस्व संबंधी कार्य जैसे, करों का निर्धारण तथा संग्रह, जहां तक भारत सरकार द्वारा संपन्न एवं नियंत्रित होता है, एक सचिव (गृह सचिव) द्वारा किया जाता है और वही संबंधित बातों को गवर्नर जनरल के सामने रखता है, जबकि वित्त-विभाग जिसके पास सारे राजस्व की प्राप्ति के बाद उसके नियंत्रण तथा दिशा निर्धारण का उत्तरदायित्व है, एक अन्य सचिव (वित्त सचिव) के द्वारा संचालित होता है और यही सचिव विभागीय बातों को गवर्नर जनरल के सामने रखता है।'<sup>64</sup> भारत मंत्री का मत था कि यह प्रणाली इंग्लैंड में प्रचलित वैसी ही प्रणाली से कम कुशल थी जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि साधनों को भी जुटाना उसी विभाग का उत्तरदायित्व है जो व्यय पर नियंत्रण रखता है। 1859 के अंत में जब जेम्स विल्सन ने वित्त विभाग संभाला तो उस समय कैनिंग उसकी परिपद और भारत मंत्री गृह तथा वित्त विभागों<sup>65</sup> को एक में मिलाने की योजना पर विचार विमर्श कर रहे थे। कैनिंग द्वारा अपनी परिपद में प्रारंभ की गई 'विभाग प्रणाली' (पोर्टफोलियो सिस्टम) के कारण स्वाभाविक रूप से कार्यों का अधिक व्यवस्थित बंटवारा और वित्त संबंधी कार्य का विल्सन के विभाग में केंद्रीकरण हो गया। मार्च, 1861 में स्टाम्प तथा सीमा शुल्क से संबंधित सभी कार्य गृह विभाग से वित्त विभाग को दे दिए गए।<sup>66</sup> अल्प समय को छोड़ कर (मार्च, 1862 से अक्टूबर, 1863 तक जब प्रशासनिक सुविधा के कारण इन शाखाओं पर गृह सचिव का नियंत्रण बना रहने दिया गया था)<sup>67</sup> राजस्व की इन शाखाओं पर वित्त विभाग का नियंत्रण था।<sup>68</sup> अक्टूबर, 1863 में राजस्व की नमक, अफीम तथा आवकारी शाखाएं भी गृह विभाग से लेकर वित्त विभाग को सौंप दी गईं।<sup>69</sup> अस्तु, चार्ल्स वुड का यह उद्देश्य बहुत सीमा तक पूरा हो गया कि आय का निर्धारण, संग्रह तथा व्यय एक ही विभाग के नियंत्रण में होना चाहिए।

वित्त विभाग ने अन्य विभागों पर व्यय के सबंध में कठोर नियंत्रण रखा। उत्तर सैन्य विद्रोह काल में सेना में से छठमी के समय सैन्य विभाग का व्यय सैन्य वित्त आयोग (जून, 1859 में नियुक्त) के निरीक्षण में था,<sup>70</sup> जिसे बाद में सैन्य वित्त विभाग (जून, 1860) में बदल दिया गया और अंत में समाप्त ही कर दिया गया (अप्रैल 1864)। इसने सेना में कमी करने का उपयोगी कार्य किया था परंतु सैन्य विभाग में लेखा परीक्षण एवं नियंत्रण का एक पृथक और स्वतंत्र विभाग रखना सार्थक नहीं था।<sup>71</sup> सैन्य विभाग के अकाउंटेंट जनरल को जो कंट्रोलर जनरल आफ मिलिटरी एक्सपेंडिचर कहलाता था, सैन्य वित्त विभाग का कार्य सौंपा गया।<sup>72</sup> सेना पर व्यय के प्राक्कलन की तैयारी का निरीक्षण कंट्रोलर जनरल करता था। ये प्राक्कलन अंत में वित्त विभाग के सामने रखे जाते थे। स्थाई रूप से प्राधिकृत व्यय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, किंतु अस्थायी आकस्मिक व्ययों की काफी छानबीन की जाती थी और वयं विशेष में सैन्य विभाग द्वारा व्यय के प्राक्कलन पूर्व अनुमति के बिना नहीं बढ़ाए जा सकते थे।<sup>73</sup> गृह विभाग में न्यायिक, विधायी, पुलिस, राजस्व, नौसेना, शिक्षा, गिरजाघरों

संबंधी, डाक तथा अन्य शाखाओं द्वारा व्यय की संवीक्षा वित्त विभाग द्वारा की जाती थी।<sup>14</sup> प्रशासन की इन सभी और अन्य शाखाओं में वेतन क्रमों में संशोधन तथा नए पदों के सृजन के लिए सभी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने होते थे और इस विभाग से होकर ये प्रस्ताव भारत मंत्री के पास पहुंचते थे।<sup>15</sup> लोक निर्माण विभाग में जिसकी स्थापना डलहौजी ने 1854 में की थी, वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था विशेष रूप से विस्तृत थी। यदि सिचाई एवं लोक निर्माण कार्यों में एक निश्चित राशि से अधिक व्यय आवश्यक होता था तो उसके लिए प्रेसीडेंसी लोक निर्माण विभागों को केंद्रीय लोक निर्माण एवं वित्त विभागों के पास भेजे गए बजट प्रावकलनों के आधार पर पूर्वं अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होता था। फोर्ब्स नाइटिंगेल के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अधिकारियों में 'स्वच्छता संबंधी चेतना' आने से उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में सैनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जो सैनिक निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, उस पर वित्त विभाग का नियंत्रण था। केवल रेलों के निर्माण में वित्त विभाग का नियंत्रण ढीला था और रेल कंपनियों के साथ संयुक्त परामर्श की प्रणाली के द्वारा व्यय में कमी करने के उसके प्रयत्न असफल रहे।<sup>16</sup> लोक निर्माण, गृह और मैन्य विभागों के अतिरिक्त इस संबंध में जिस विभाग का उल्लेख किया जाना चाहिए, वह राजस्व, कृषि एवं वाणिज्य विभाग है। इस विभाग की स्थापना जून, 1871 में कृषि को प्रोत्साहन देने, खनिज संपत्ति के दोहन, तथा 'औद्योगिक ज्ञान के प्रसारण' के लिए की गई थी।<sup>17</sup> माल-गुजारी सर्वेक्षण बंदोबस्त, कृषि एवं व्यापार सबधी आंकड़ों, वन आदि से संबंधित कार्य इस विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए। 1872 के बाद राजस्व विभाग की कुछ शाखाएं भी इस विभाग को दे दी गईं।

वित्त विभाग की विविध व कठोर कार्यों के कुशलतापूर्वक संपादन के लिए योग्य तथा समर्थ कर्मचारियों की आवश्यकता थी। ये सहज ही उपलब्ध नहीं थे। 1857 में सेवा में एक पृथक वित्तीय शाखा बनाई गई। इस शाखा में वे ही अनुबंधित (कावेनेटेंड) अफसर नियुक्त किए गए जो एक परीक्षा पास कर सके जिसके विषय थे, बहीखाता, राज-कोष का प्रबंध, तथा भारतीय राजस्व प्रणाली के मिश्रित। मई, 1862 में वित्त विभाग की सेवा के लिए युवकों की प्रशिक्षण देने के लिए एक परिवीक्ष्यमाण (प्रोवेशनर) अफसरों का वर्ग बनाया गया। इसी समय वित्तीय मामलों के सदस्य एस० लैंग ने घोषित किया कि अनुबंधित अफसरों तथा गैर अनुबंधित अफसरों में आगे कोई भेद नहीं किया जाएगा और पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर होगी।<sup>18</sup>

भारत में तरुण अफसरों की प्रशिक्षण देने की योजना असफल रही और भारत मंत्री से यह आग्रह किया गया कि वह सिविल सेवा आयोगों की सहायता से भारतीय वित्त सेवा में नियुक्ति के लिए यहीखाते के काम में प्रवीण युवकों की इंग्लैंड में भर्ती करे।<sup>19</sup> भारत मंत्री को भारत जाने के लिए उत्तमक पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी लोगों की भर्ती में कठिनाई हुई। जनः उमने गवर्नर जनरल से अनुरोध किया कि वह भारत में ही इस कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों की गोज करे।<sup>20</sup> ब्रिटिश राजकोष के एक अफसर श्री फीस्टर वित्त विभाग के मन्नाहकार बनकर एक विशेष मिशन पर भारत

आए थे। उनके अनुसार ब्रिटिश राजकोष द्वारा दिए जाने वाले ऊँचे पारिश्रमिक के कारण इंग्लैंड में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति लोक सेवा में चले जाते थे और भारत में नीचे वेतनमान पर्याप्त रूप से आकर्षक नहीं थे। 'अनुभव से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक वेतन नीचा निर्धारित करने से होने वाली बचत के दोष ये हैं कि केवल व्यापारियों के दफ्तरों में अस्वीकृत और सरकारी पेंशन के अलावा दूसरे प्रकार से जीविकोपार्जन में अयोग्य व्यक्तियों के वर्गों को ही राज्य के वित्तीय व्यवसाय के संपादन का उत्तरदायित्व दे दिया गया है।'<sup>81</sup> परंतु चार्ल्स ट्रेवीलियन (जो इंग्लैंड में प्रसिद्ध ट्रेवीलियन नोर्थ-कोट सुधारों के समय से सिविल सेवा में भर्ती के विषय पर विशेषज्ञ माना जाता था) वेतनमान में संशोधन करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति सदैव ही घाटे के पास रहती थी और ऐसी स्थिति में सरकार के लिए वित्त विभाग में खर्च बढ़ा पाना संभव नहीं था।<sup>82</sup>

वित्त विभाग में सुधार करने के लिए यह भी सुझाव दिया गया था कि भारी संख्या में अनुबंधित अफसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए।<sup>83</sup> 1862 से वित्त विभाग में वित्त सचिव तथा अकाउंटेंट जनरल केवल दो ही अनुबंधित अफसर थे अतः जिम्मेदारी के अनेक पद गैर अनुबंधित अफसरों को दिए गए। वित्त विभाग में थोड़े ही अनुबंधित अफसर आना चाहते थे क्योंकि दूसरे विभागों की तुलना में इस विभाग में पदोन्नति और अधिक पारिश्रमिक के अवसर कम ही थे।<sup>84</sup> 1865 में वित्त सचिव ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि विभाग की अकुशलता का एक कारण यह है कि ऊँचे पदों पर गैर अनुबंधित अफसर हैं 'जिनकी आयु कुछ नया सीख सकने की दृष्टि से अधिक है' और जो मातृहता में दीर्घकाल तक कार्य करने से 'दूसरों पर सही प्रभाव डाल सकने की दृष्टि से अनुपयुक्त हो गए हैं।'<sup>85</sup> सर चार्ल्स ट्रेवीलियन ने इस मत पर आपत्ति की। उसने स्पष्ट किया कि 1862 से पहले जब विभाग में कई अनुबंधित कर्मचारी थे तो कार्य-कुशलता का स्तर ऊँचा नहीं था। उसका विचार था कि गैर अनुबंधित अफसरों को शिक्षा दी जा सकती है और वे अनुबंधित अफसरों से इस दृष्टि से भिन्न हैं कि प्रायः वित्त विभाग में ही बने रहते हैं जहाँ उनकी पदोन्नति की संभावना अन्य स्थानों से अधिक है। कुछ भी हो, सरकार के लिए वित्त विभाग में भारी संख्या में अनुबंधित अफसरों की नियुक्ति कर पाना संभव नहीं था।<sup>86</sup>

वित्त विभाग में अकुशलता के मुख्य कारण यह थे कि अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग की शिक्षा अपर्याप्त थी और उनका पारिश्रमिक कम था और सिविल सेवा के अफसरों के पास यद्यपि शिक्षा तो काफी अच्छी थी तथापि वे विशेष रूप से वित्त प्रबंध के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। जिस प्रकार के कर्मचारी ब्रिटिश राजकोष के पास थे वैसे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पदोन्नति की संभावनाएं वित्त विभाग में नहीं थी। इंग्लैंड से विल्सन के आने के दस वर्ष बाद 1869 में भी यह अनुभव किया जाता था कि विभाग 'कर्मचारियों की दृष्टि से अशक्त' है।<sup>87</sup> सैन्य अथवा प्रशासनिक सेवाओं के समान कुशल वित्तीय सेवा के विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी थी।



## V

सैन्य विद्रोह के बाद संस्थागत नव प्रवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बजट प्रणाली थी। 1860-61 के वित्तीय वर्ष तक का साम्राज्यिक आय-व्यय का वार्षिक बजट न होने के कारण वित्तीय वर्ष में अलग-अलग समयों पर तैयार किए जाने वाले 'प्रत्याशित प्राक्कलनों' 'खाका प्राक्कलनों' तथा 'नियमित प्राक्कलनों' की जटिल पद्धति के द्वारा विविध व्ययों तथा भावी आवश्यकताओं का पता लगाना होता था।<sup>88</sup> वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से ढाई माह पहले प्रत्याशित प्राक्कलन स्थानीय लेखाकारों द्वारा सर्वोच्च सरकार के पास जाते थे। इन प्राक्कलनों में तुलना की दृष्टि से समानांतर कालों में पिछले दो वर्षों की प्राप्तियां और खर्च दिए रहते थे। वित्तीय वर्ष के चार माह बीत जाने पर 'खाका प्राक्कलन' तब तक के संशोधनों सहित स्थानीय लेखाकारों द्वारा भेजे होते थे। तीन माह और बीत जाने पर 'नियमित प्राक्कलन' भेजे जाते थे। इनमें पहले छः महीनों की वार्षिक प्राप्तियां और व्यय, जो उस समय तक मालूम होते थे, और वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए प्राक्कलन दिखाए जाते थे। प्रत्येक प्रेसीडेंसी अथवा प्रांत में स्थानीय लेखाकार प्रत्येक असेनिक, सैनिक, लोक निर्माण, आदि विभागों के व्यय अधिकारियों से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में मासिक या साप्ताहिक विवरणी प्राप्त करता था। प्रत्याशित, खाका तथा नियमित प्राक्कलनों के अतिरिक्त भारत सरकार के पास स्थानीय लेखाकारों से रोकड़ शेष की मासिक विवरणियां भी आती थीं। घन राशि के आवंटन के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा प्राक्कलित या वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों की तुलना कर (विभिन्न विभागों की) आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता था। वास्तविक व्यय का लेखा परीक्षण विभाग द्वारा व्यापक लेखा परीक्षण किया जाता था। व्यय प्रायः दो भागों में विभक्त किए जाते थे, स्थिर व्यय (जैसे, लोक ऋण पर ब्याज, असेनिक अव्यवस्था एवं वेतन, सेना पर व्यय आदि) तथा अस्थिर व्यय जिनमें परिवर्तन होते रहते थे (जैसे, स्टोर की लागत, बट्टा, आकस्मिक व्यय, आदि)। यह नियम था कि किसी भी विभाग के द्वारा बिना विशिष्ट मंजूरी के कोई भी स्थिर व्यय नहीं किया जा सकता। परिवर्ती व्यय सामान्य रूप से प्रमाणित नियमों के अनुसार अथवा विशिष्ट मंजूरी के द्वारा ही किए जा सकते थे। विभागीय अफसरों के लिए अनुमानों में स्वीकृत कुल राशियों के भीतर ही व्यय करना होता था। इस सीमा के भीतर ही उन्हें, अभाव की स्थिति में भी, विशिष्ट अनुदान को किसी अन्य बात पर व्यय करने के लिए बहुत थोड़ी स्वतंत्रता दी गई थी।<sup>89</sup>

जेम्स विल्सन को अपने आपको इस जटिल तथा अनोखी वित्तीय व्यवस्था से अवगत कराना पड़ा। विल्सन ने बेजह्राद को लिखा था कि 'भारत का वित्त विभाग एक विशाल यंत्र है और इसके सामने इंग्लैंड का अर्थ-विभाग जटिलता, विविधता, तथा कार्य व्यापार के बिंदुओं में दूरी की दृष्टि से कुछ भी नहीं है।'<sup>90</sup> हम जटिल यंत्र का वैज्ञानिक पुनर्गठन उम्मा प्रधान कार्य था। 7 अप्रैल, 1860 को भारत सरकार ने बजट

पद्धति अपनाने का निश्चय किया था। इससे पहले 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन ने विधान परिषद में प्रारंभिक प्राक्कलन के आधार पर बजट विवरण पेश किया। विल्सन को इस प्रकार भारत में बजट प्रणाली का प्रवर्तक माना जा सकता है। तथापि मई, 1859 में सर चार्ल्स टूबीलियन ने भारत के लिए बजट प्रणाली की एक योजना तैयार कर विल्सन से पहले ही इस दिशा में पहल की थी।<sup>91</sup>

7 अप्रैल, 1860 के प्रस्ताव में यथासंभव इंग्लैंड जैसी प्रणाली के प्रवर्तन की सिफारिश की गई थी। इस प्रणाली का संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया गया था, 'प्रत्येक शासकीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले सर्वोच्च सरकार को आगामी वर्ष में साम्राज्य की प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्यय के सतर्कतापूर्वक तैयार किए गए प्राक्कलनों की आवश्यकता होगी। विभिन्न लक्ष्यों पर उनकी निष्पत्ति के लिए आवश्यक साधनों और स्रोतों के सदर्थ में विचार कर; प्रस्तावित व्ययों की पिछले वर्षों के व्ययों से तुलना कर; विभिन्न कार्यपालक सरकारी एवं विभागाध्यक्षों की सिफारिशों पर विचार कर सर्वोच्च सरकार सेवा की प्रत्येक शाखा और प्रत्येक शाखा की विविध मदों के लिए निश्चित राशियों का आवंटन करेगी। विभिन्न कार्यपालक सरकारों तथा विभागों पर उपर्युक्त विनियोग अधिनियम के आधार पर स्वीकृत धनराशियों के उचित उपयोग का उत्तरदायित्व होगा।'<sup>92</sup>

प्रस्ताव में इस प्रकार की प्रणाली के वर्तमान पद्धति की तुलना में लाभ स्पष्ट किए गए थे। सर्वप्रथम, इस प्रणाली में आगामी वर्ष में प्रत्याशित आय तथा होने वाले व्यय के पूरे पुनर्विलोकन की व्यवस्था थी। 'वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही जब पुनर्विलोकन होता है तो यह पूर्वज्ञान का पुनर्विलोकन होता है न कि अनुभव का क्योंकि पुनर्विलोकन अधिकारी उन योजनाओं का निर्णायक होता है जो अभी पूरी होकर तथ्य नहीं बन सकी है।' द्वितीय, नई प्रणाली में व्ययों का समय-समय पर संधीक्षण होगा, और प्रत्याशित व्यय राशि की तुलना में इस प्रकार के व्यय के लिए साधन और स्रोत की व्यवस्था की रीतियों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार भविष्य की आय और व्यय में अपेक्षाकृत अच्छा मतुलन आ सकेगा। इसके अलावा, नई प्रणाली के द्वारा व्यवस्थित लेखा परीक्षण तथा लेखा प्रणाली की आधारशिला रखी गई। प्रत्येक कार्यपालक सरकार तथा प्रत्येक विभाग के नाम साम्राज्यिक बजट द्वारा स्वीकृत राशि जमा कर दी जाएगी और उसके आधार पर सर्वोच्च सरकार के वित्त विभाग द्वारा वास्तव में दी गई राशि नाम में डाल दी जाएगी। व्यय विशिष्ट स्वीकृतियों में अधिक नहीं होगा। अस्तु, इस व्यवस्था के द्वारा सामान्यतः 'आर्थिक कार्य कुशलता' में वृद्धि अर्थात् कफायत होगी।<sup>93</sup>

चूंकि नई प्रणाली को एक साथ लागू कर सकना संभव नहीं था, अतः यह निश्चय किया गया कि इसे 1860-61 के वित्तीय वर्ष में आंशिक रूप से लागू किया जाए (जबकि कुछ समय के लिए वर्तमान गंगठन तथा रीतियों को बनाए रखा जाए) जिससे 1861-62 के वित्तीय वर्ष तक यह पूरी तरह व्यवहार में लाई जा सके। बजट प्रणाली से संबद्ध अनेक वित्तीय सुधार (उदाहरणार्थ, केन्द्रीय रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, साम्राज्यिक लेखा परीक्षण विभाग का पुनर्गठन, प्रत्याशित, रूपरेखीय, तथा नियमित अनुमानों के फार्मों के

स्थान पर बजट फार्मों के प्रयोग के लिए इनको तैयार करना)<sup>91</sup> विल्सन के जीवन काल में पूरे नहीं हो सके। बजट प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन के लिए आधारभूत प्रशासनिक संरचना तैयार करने का कार्य लैंग तथा टूवीलियन पर पड़ा जो विल्सन के उत्तराधिकारी थे।

इंग्लैंड की लेखा पद्धति तथा लेखा परीक्षण प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उन्हें यहां पर लागू करने की एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इसके सदस्य थे ई० ड्रमंड (भारत का अकाउंटेंट जनरल), सी० एच० लॉसिंगटन (भारत सरकार का वित्त सचिव), और रिचर्ड टैपिल (सिविल सेवा से इसे विल्सन के निजी सचिव के रूप में काम करने का अनुभव होने के कारण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था)<sup>92</sup> समिति ने मिफारिश की कि वित्त संबंधी कार्य दो विभागों में बांटे जाने चाहिए—प्रथम, लेखा तथा लेखा परीक्षण विभाग जिसमें दो भिन्न वर्ग के अफसर होने चाहिए। इनमें एक वर्ग का कार्य केवल व्ययों का निरीक्षण और दूसरे का केवल लेखे का निरीक्षण करना होना चाहिए। अकाउंटेंट जनरल आफ इंडिया ही आडिटर जनरल भी होना चाहिए और इस प्रकार वित्तीय सेवा के दोनों पक्षों में एकता स्थापित हो जाएगी।<sup>93</sup> 1860 की बजट समिति द्वारा विनियोग लेखा परीक्षण की रीति संबंधी एक आधारभूत महत्व का सुधार किया गया। भारत में 1860 से पहले की प्रणाली में प्रधान दोष यह था कि वर्ग विशेष के प्रत्येक सेवा के लिए विशिष्ट स्वीकृतियों के बजट प्राक्कलन नहीं होते थे। विल्सन ने पुरानी प्रणाली के स्थान पर बजट प्रणाली को प्रारंभ कर, जिसका उद्घाटन 18 फरवरी, 1860 के बजट वक्तव्य में साथ हुआ था, उपर्युक्त दोष को दूर कर दिया। परंतु प्रत्याक्षित व्यय विवरण (अर्थात् बजट) के साथ-साथ वास्तविक व्यय की प्राक्कलित व्यय से तुलना कर सकने के लिए भी व्यवस्था विकसित करनी थी जिससे वास्तविक व्यय प्राक्कलन से अधिक न होने पाए और सेवा की प्रत्येक शाखा को आवंटित राशि किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में न लाई जाए। व्यय की माहवार प्रगति (सेवा की अलग-अलग शाखाओं में और समग्र प्रशासन में) पता लगा सकने के लिए इंग्लैंड की व्यवस्था की रूपरेखा के आधार पर विनियोग लेखा परीक्षण प्रारंभ किया गया।<sup>94</sup> बजट समिति के सुझावों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें लागू किया। नई प्रणाली में अकाउंटेंट एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया के पास मातहत लेखाकारों तथा लेखा परीक्षकों से सेवा की प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय का मासिक सारांश आता था जो अंतिम विनियोग लेखा परीक्षण के बाद समस्त भारत में व्यय पर मासिक रिपोर्ट के रूप में वित्त विभाग के पास भेजा जाता था।<sup>95</sup>

बजट समिति का प्रस्ताव था कि धनराशि के विशिष्ट विनियोग का क्षेत्र (1) सेवा के वर्गों, (2) वर्ग विशेष में प्रत्येक विभाग द्वारा व्यय की मदों, तथा (3) प्रत्येक विभाग में प्रत्येक अनुभाग द्वारा व्यय की मदों तक विस्तृत होगा। भारत मंत्री ने सेवा की प्रत्येक शाखा द्वारा व्यय की विस्तार के साथ दी गई मदों तक विनियोग विस्तार के औचित्य के प्रति संदेह प्रकट किया। उसका विचार था कि व्यय की छोटी मदों के ऊपर

धनराशि के व्यय के बारे में कुछ स्वतंत्रता दी जा सकती है।<sup>99</sup> भारत मंत्री की सलाह के अनुसार ही विशिष्ट विनियोग उपयुक्त पहली दो श्रेणियों (सेवा की शाखाओं और प्रत्येक वर्ग के विभाग की व्यय की मदें) तक ही सीमित रखा गया और उसे और अधिक विस्तृत मदों में नहीं तोड़ा गया।<sup>100</sup> बजट समिति द्वारा तैयार किए गए बजट तथा अनुमानों के फार्म इस सिद्धांत के अनुरूप थे।<sup>101</sup>

एक अन्य समस्या पर जो प्रकट रूप से कम महत्व की थी, हमारे इस अध्ययन के काल में काफी ध्यान दिया गया। समस्या यह थी कि वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होना चाहिए? 1865 तक वित्तीय वर्ष 1 मई से प्रारंभ होता था।<sup>102</sup> अधिकारी इस बात से अवगत थे कि भारत में यह भावना बन गई थी कि चूंकि भारतीय लेखे प्रायः मसद के सत्रात में पेश किए जाते हैं इसलिए किसी भी सदन में 'इस महान साम्राज्य के मामलों पर इनके महत्व के अनुरूप लोगों की दिलचस्पी नहीं बन पाती'।<sup>103</sup> अतः यह वांछनीय समझा गया कि वित्तीय वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया जाए जिससे भारतीय लेखे संसद के सत्र के शुरू में ही पेश हो सकें। भारतीय लेखा जांच आयोग (7 सितंबर, 1864) की सिफारिशों के अनुसार 1866-67 से वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने लगा।<sup>104</sup> वित्तीय वर्ष और भी पहले, यदि संभव हो सके तो 1 जनवरी से, प्रारंभ करने के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया<sup>105</sup>, परंतु यह भारत में फसल काटने के समय (जो राजस्व संग्रह से संबंधित थे) की दृष्टि से असुविधाजनक था।<sup>106</sup>

विल्सन तथा बजट समिति के प्रयत्नों से वार्षिक बजट प्रणाली बिना किसी अड़चन के प्रारंभ की जा सकी। तथापि बजट स्वीकृतियों की सीमा में ही व्ययों को रखना और भविष्य में व्ययों के लिए सही प्राक्कलन तैयार करना कठिन कार्य था। प्रारंभ में लेखा परीक्षकों तथा लेखाकारों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय प्राक्कलनों और वास्तविक व्ययों में भारी अंतर पाए गए।<sup>107</sup> अधीनस्थ सरकारें बहुधा अपनी भावी आवश्यकताओं के बारे में प्राक्कलन समय पर नहीं भेजती थी, अतः भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन कुछ-कुछ अटकलवाजी जैसे ही होते थे।<sup>108</sup> प्राक्कलन से अधिक खर्च को हतोत्साहित किया जाता था और सामान्यतः आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं होता था।<sup>109</sup> 'साम्राज्य की वित्तीय स्थिति और लोक सेवा की न्यायोचित आवश्यकताओं को देखते हुए' जो बजट आवंटन किए जाते थे उनके ऊपर धनराशि की स्वीकृति के लिए सामान्यतः कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था।<sup>110</sup> बजट में स्वीकृत अनुदान यदि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक व्यय नहीं हो पाते थे तो उन्हें निश्चय ही समाप्त मान लिया जाता था।<sup>111</sup>

1864 में भारतीय लेखा जांच आयोग द्वारा लेखा पद्धति में कुछ छोटी-मोटी बातों में सुधार किए गए। आयोग के सदस्य थे फास्टर तथा व्हिफन। इनमें पहला असिस्टेंट वे मास्टर जनरल तथा दूसरा इंग्लैंड के युद्ध विभाग का डिप्टी अकाउंटेंट जनरल था। भारत में पुरानी लेखा पद्धति 'बहीखाते की वाणिज्यिक पद्धति' पर आधारित थी और 'इसका उद्देश्य वाणिज्यिक अर्थ में सरकार की लाभ-हानि पता करना था'।<sup>112</sup> इस प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से सर चार्ल्स टूबीलियन ने भारत मंत्री से कुछ अंग्रेज

अफसरों की सेवाओं को प्राप्त करने का आग्रह किया। ग्लेड्स्टन तथा सर जार्ज ल्युइस से परामर्श कर ट्रैवीलियन ने फास्टर तथा व्हिफिन को धुना।<sup>113</sup> फास्टर तथा व्हिफिन ने अपने मुआयने (1864-65) में भारतीय लेखाओं को ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर सुधारने के अनेक सुझाव दिए। वित्तीय प्रशासन संबंधी छोटी-मोटी बातों के विषय में उनके सुझावों से वित्त विभाग की कुशलता में सुधार हुआ।<sup>114</sup>

हमारे सिंहावलोकन की अवधि में बजट प्रणाली के प्रारंभ तथा लेखा परीक्षण एवं लेखा प्रणाली को नया रूप देने से नवीन वित्तीय प्रणाली का आधार तैयार हो गया। और, कोई कारण नहीं है कि मेयो द्वारा नई प्रणाली के संस्थापकों की प्रशंसा के प्रति असहमति प्रकट की जाए। मेयो ने कहा था : 'हमारी वित्त व्यवस्था का उत्तर-दायित्व जिन लोगों पर डाला गया था वे बहुत विपन्न स्थिति में एक श्रेष्ठ व समर्थ प्रणाली को यद्यपि वह काफी जटिल थी, अपनाने के कठिन कार्य में संलग्न थे। उन्हें बिना किसी बुनियाद से वित्त प्रशासन की प्रणाली विकसित करनी थी।'<sup>115</sup> ऐसी परिस्थितियों में उन्हें कमाल की सफलता प्राप्त हुई।

## VI

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निर्धारित कार्य में केंद्रीय या सर्वोच्च सरकार तथा स्थानीय या अधीनस्थ सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 1858 से 1861 तक वित्तीय नियंत्रण की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की दिशा में थी। 1862 तथा 1868 के मध्य वित्त के विकेंद्रीकरण के विचार को काफी स्वीकृति मिली और इस संबंध में कई योजनाएँ तैयार की गईं यद्यपि इन योजनाओं में से कोई भी पूरी तरह संतोषजनक न थी। तृतीय अवस्था में 1869 से 1872 तक वित्त के विकेंद्रीकरण की योजना मेयो द्वारा तैयार कर लागू की गई। इस कार्य में जान स्ट्रैची ने उसकी योग्यतापूर्वक सहायता की।

सैन्य विद्रोह के समय सर्वोच्च सरकार की तुलना में स्थानीय सरकारों (दंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी की गवर्नरी भी शामिल है) की मातृहृती की स्थिति स्पष्ट थी। संसद के विधान द्वारा 'स्थानीय' अथवा प्रांतीय सरकारों को बिना सपरिपद गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के नए पद बनाने अथवा वेतन या उपदान (ग्रैंज्युटी) देने का अधिकार नहीं था।<sup>116</sup> यह सिद्धांत बना हुआ था कि सर्वोच्च सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्थानीय कर्मचारियों की संस्था, उनके पदों अथवा वेतनमानों में परिवर्तन नहीं किए जा सकते थे।<sup>117</sup> तथापि जब विल्सन भारत आया तो उसने पाया कि 'सर्वोच्च और अधीनस्थ सरकारों में सुनिश्चित एवं स्पष्ट संबंध नहीं है और अधीनस्थ सरकारें अपने अधिकारों के अतिक्रमण का और सर्वोच्च सरकार अपने अधिकारों को बनाए रखने का प्रयत्न करती है जिससे वित्तीय प्रशासन में काफी अटिस्तता है।'<sup>118</sup> स्थानीय और सर्वोच्च सरकारों के बीच संबंध अमंतीपजनक थे क्योंकि सर्वोच्च सरकार को व्यय संबंधी छोटी से छोटी बात पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। परंतु, चूंकि बजट प्रणाली नहीं थी और लेखा परीक्षण तथा लेखा पद्धति कमजोर थी, अतः सपरिपद

गवर्नर जनरल के लिए प्रभावी ढंग से वित्तीय नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग कर पाना संभव नहीं था। प्रांतीय सरकारों की वित्तीय शक्तियों का विस्तार तथा सीमाएं भी ठीक से परिभाषित नहीं थी। अस्तु, भारत सरकार पर ऐसे कार्य का भार था जिसे करने के लिए उसके पास साधन नहीं थे और स्थानीय सरकारों को जिनके पास कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं था, अपव्यय रोक कर बचत करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी।

जेम्स विल्सन का उद्देश्य सर्वोच्च सरकार के वित्तीय नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाना था। बजट प्रणाली से, जिसका 1860 के प्रारंभ में उद्घाटन हुआ था, विशिष्ट स्वीकृतियों (सेवा की प्रत्येक शाखा और प्रत्येक शाखा की हर छोटी से छोटी मदों के लिए) की व्यवस्था हो गई और यह भी निश्चित हो गया कि स्थानीय सरकारें सपरिपद गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति के बिना निर्धारित राशि से अधिक व्यय नहीं करेंगी। इस सिद्धांत को बजट समिति ने अधिक विस्तार के साथ प्रतिपादित किया। विनियोग लेखा परीक्षण की रीति तथा नवीन लेखा पद्धति ने व्यय के ऊपर सर्वोच्च सरकार का नियंत्रण अधिक दृढ़ कर दिया। जिस नियम के अंतर्गत स्थानीय सरकारें वेतन क्रम में परिवर्तन तथा स्थाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकती थी उस पर पुनर्विचार किया गया, लेकिन विभाग के भीतर ही व्ययों के वितरण में मामूली परिवर्तन कर सकने की स्वीकृति इस घात पर दी गई कि जब भी ऐसा किया जाए तो सर्वोच्च सरकार को इस संबंध में तत्काल सूचना दी जाए।<sup>119</sup> 1861 में इंडियन फाउंटिस एक्ट द्वारा बंबई तथा मद्रास सरकारों को विधि निर्माण का वह अधिकार पुनः मिल गया जो उनसे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा छीन लिया गया था। परंतु प्रांतीय विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की बिना पूर्ण स्वीकृति के भारत के लोक रूढ़ि, सीमा शुल्क, सर्वोच्च सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर, करंसी, बिल, नोट आदि को प्रभावित करने वाले कानून या अधिनियम बनाने अथवा उन पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया गया था।<sup>120</sup> इस प्रकार 1860-61 में विल्सन द्वारा बनाए गए वित्तीय तंत्र से सज्जित होकर भारत सरकार अधीनस्थ सरकारों को वित्तीय दृष्टि से नियंत्रित करने लगी। भारत सरकार प्रकट रूप से वित्तीय केंद्रीकरण की नीति से प्रतिबद्ध नहीं थी। परंतु वित्तीय नियंत्रण की कड़ाई को अधीनस्थ सरकारों ने इसी रूप में लिया, जिन्हें संभवतः पहली बार दृढ़ एवं कुशल केंद्रीय नियंत्रण की कठोरता का अनुभव हुआ था। जेम्स विल्सन की ध्याति 'केंद्रीकरण के प्रतिपादक' के रूप में ही थी।<sup>121</sup>

मद्रास का गवर्नर सर चार्ल्स ट्रैवीलियन केंद्रीकरण की नीति का कड़ा विरोधी था। ट्रैवीलियन का विचार था कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अत्यधिक केंद्रीकरण अवांछनीय है। 1853 में भारतीय राज्य क्षेत्रों पर बनी प्रवर समिति के सामने अपने साक्ष्य में ट्रैवीलियन ने वित्तीय मामलों में, केंद्रीय सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण अधीन, प्रेसीडेंसियों को उचित स्वतंत्रता एवं आत्म निर्णय का अधिकार देने के पक्ष में तर्क दिए थे। 1859 में यद्यपि उसने स्वीकार किया कि प्रांतीय सरकारें बजट आबंटन से अधिक व्यय नहीं कर सकतीं, तथापि उसने एक बार पुनः इन सरकारों को आत्मनिर्णय का थोड़ा सा अधिकार देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वह हर छोटी बड़ी मद के लिए

विशिष्ट स्वीकृति का विरोधी था जिसके कारण अधीनस्थ सरकारों को 'अपमानजनक अनिवार्यता का सामना करना होता था, क्योंकि उन्हें जब भी कोई नया व्यय, यह कितना ही नगण्य क्यों न हो, करना होता था, तभी एक अलग आवेदन पत्र कलकत्ता भेजना होता था।'<sup>122</sup>

12 मई, 1860 के अपने नोट में भारतीय रेवेन्यू प्रणाली की विविधताओं और एक ही केंद्र से दूर-दूर के प्रदेशों पर शासन कर सकने की कठिनाई को स्पष्ट करते हुए उसने अपने मत का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया: 'यह एकीकरण न होकर असंगत कार्यों का अध्वबस्थित ढेर मात्र है। यह सिर में रत्नसंकुलता की ओर अन्य अंगों में पक्षाघात जैसी स्थिति है।'<sup>123</sup>

ये एतराज प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किए गए थे। ट्रिबीलियन ने इससे आगे बढ़कर संवैधानिक पहलू का भी उल्लेख किया था। उसने प्रश्न उठाया कि 'क्या प्रेसीडेंट (अर्थात् सपरिषद गवर्नर जनरल) के लिए स्थानीय सरकारों से बिना कोई सलाह मशविरा किए हुए ही कोई प्रस्ताव अचानक प्रख्यापित कर ब्रिटिश भारत के सविधान में मूलभूत परिवर्तन करना, जैसा कि अभी हुआ है, उचित है?' जिम समय तक भारत मंत्री ने प्रत्येक प्रेसीडेसी में विधान परिषद के निर्माण और अपना कार्य करने के बारे में उसे स्वतंत्रता देने के विषय में सरकार के इरादे की घोषणा की तब तक विल्सन ने थोड़ा सा केंद्रीकरण कर दिया था जिससे प्रांतीय सरकारों की केंद्रीय सरकार पर निर्भरता बढ़नी स्वाभाविक थी। इसका कारण यह है कि वित्तीय केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सभी प्रभावकारी सत्ता केंद्रीय सरकार के हाथ में है। ट्रिबीलियन के ही शब्दों में, 'चूंकि सरकार के सभी तत्वों में वित्त, सबसे अधिक सबल है, इसलिए अन्य सभी तत्वों का इसमें आत्मसात हो जाना और इसके ही अनुरूप ढल जाना स्वाभाविक है... एंग्लो इंडियन सरकारों के गठन के महत्वपूर्ण प्रश्न को वित्त प्रबंध की महत्वहीन घटना मानकर चुपचाप नहीं निपटाया जाना चाहिए।'<sup>124</sup>

सर चार्ल्स ट्रिबीलियन द्वारा उठाए गए प्रश्न यद्यपि महत्वपूर्ण थे तथापि उसने अपने पक्ष के समर्थन में जिस प्रकार से तर्क दिए तथा गोपनीय सरकारी कागजात प्रकाशित किए, और उसके 'विद्रोह' से जो उत्पात शुरू हो गया उनसे उसकी भूल सिद्ध हो गई। उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न को सकीर्ण ईर्ष्या की अभिव्यक्ति समझ लिया गया। गवर्नर जनरल ने 'वर्गीय सिद्धांतों एवं दावों' को अस्वीकार कर दिया। लार्ड कैनिंग जेम्स विल्सन के साथ संपूर्ण रूप से सहमत था। उसने विल्सन को लिखा, 'भारत में समस्त वित्त को एक ही केंद्रीय नियंत्रण में लाने के लिए आप जो कुछ भी कहते हैं, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ।'<sup>125</sup> उसका पक्का इरादा था जिसे स्पष्ट करते हुए उसने एक अन्य पत्र में विल्सन को लिखा था कि 'मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं भूलों से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकूंगा, परंतु मैं विवाद को यथासाध्य रोकने का प्रयत्न करूंगा।'<sup>126</sup> सर चार्ल्स वुड ने ट्रिबीलियन के कार्यों की ओर, विशेषकर, सरकारी कार्यवृत्त के प्रकाशन को 'पूर्ण रूप से विद्रोही' कार्य बतलाकर, निंदा की।<sup>127</sup> ट्रिबीलियन को इंग्लैंड वापस बुला लिए जाने पर यह विवाद कुछ समय के लिए समाप्त हो गया।

1861 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की एक योजना सेमुअल लैंग द्वारा, जो गवर्नर जनरल की परिषद में वित्त सदस्य के पद पर वित्सन का उत्तराधिकारी था, तैयार की गई थी। साम्राज्य के प्रत्येक भाग में लोक निर्माण के क्षेत्र में कार्य और लोक निर्माण कार्यों पर व्यय संबंधी छोटी-छोटी बातों में केंद्र द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की वांछनीयता काफी अनुभव की गई। भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग से संबंधित सचिव ने 'देश में वित्त के प्रांतीयकरण' की सिफारिश की थी और लैंग ने प्रांतीय सरकारों को भेजे गए गोपनीय परिपत्र में इस उद्देश्य के लिए अपनी योजना की रूपरेखा भेजी थी।<sup>128</sup> लैंग ने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण कार्यों के विकास के अतिरिक्त भी विकेंद्रीकरण के लाभ होंगे। प्रांतीय सरकारों को अपने नियंत्रण की मर्दों में बचत करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और इससे 'स्थानीय स्वावलंबन की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।' 1860-61 के नियमित प्राक्कलनों से मार्च, 1861 तक स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार अपनी आय से 6 करोड़ रुपये अधिक व्यय कर रही थी।<sup>129</sup> इसका एक ही समाधान था कि नमक कर में तत्काल वृद्धि की जाए और प्रांतीय सरकारों को लोक निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदानों में कमी की जाए। इस कमी से लोक निर्माण कार्यों के विकास में काफी बाधा आनी थी। अतः, स्थानीय कराधान के लिए कुछ विषय प्रांतीय सरकारों को दे देने का प्रस्ताव रखा गया जिससे स्थानीय लोक निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय अनुदानों में कुछ कमी हो तो उसे पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ आय प्राप्त की जा सके। इस प्रकार लैंग के प्रस्ताव के मुख्य प्रयोजनों में एक प्रयोजन यह भी था कि सर्वोच्च सरकार के वित्त पर लोक निर्माण के भारी खर्चों में कमी करके भार को थोड़ा हल्का किया जाए और इस भार के एक अंश को प्रांतीय सरकारों पर डाल दिया जाए। यद्यपि प्रांतीय सरकारों को नए प्रांतीय करों से धन सग्रह की योजनाएं तैयार करने में बहुत कठिनाइयां हुईं फिर भी लैंग की योजना के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल नहीं थी।<sup>130</sup> परंतु योजना को तत्काल लागू नहीं किया गया। भारत सरकार ने उस समय तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जब तक कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना न हो। 1862-63 में व्यय पर आय का आधिक्य 1.8 करोड़ रुपये था। अगले वर्ष थोड़ा सा ही आधिक्य रहा। इसलिए थोड़े समय के लिए कुछ खर्चों को प्रांतीय सरकारों पर डालने के उपाय को स्थगित कर दिया गया।

1866 में वित्त सदस्य डब्ल्यू० एन० मैसी ने इस योजना को पुनर्जीवित किया। 1866-67 में भारत सरकार का व्यय उसकी आय से 2.5 करोड़ रुपये अधिक था। अगले दो वर्षों में लगभग 1.6 करोड़ रुपये और 4.14 करोड़ रुपये के घाटे थे। इस संकट में भारत सरकार ने एक बार पुनः विकेंद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जिससे प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च सरकार के साथ वित्तीय भार को उठाने में भागीदार रह सकें। दो योजनाएं तैयार की गईं। प्रथम योजना डब्ल्यू० एन० मैसी ने तैयार की थी जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि प्रांतीय सरकारों पर कुछ व्ययों की मर्दों का उत्तरदायित्व डाला जाएगा (जो तब तक साम्राज्यिक आय से किए जाते थे) और इसके लिए वे स्थानीय



करों के द्वारा आय की व्यवस्था करेंगी और इस संबंध में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। दूसरी योजना 1867 में कर्नल आर० स्ट्रैची द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित थी। इसमें न केवल कुछ व्यय की मदों बल्कि कुछ आय की मदों के भी हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा गया था।

पहली योजना व्यय की कुछ मदों, उदाहरणार्थ : शिक्षा, पुलिस, जेल, लोक निर्माण से बचने का उपाय मात्र थी और इस प्रकार इसका उद्देश्य साम्राज्यिक व्यय में 1.2 करोड़ रुपये की कमी करना था।<sup>121</sup> बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेसिल बीडन ने स्पष्ट किया कि जहां स्थानीय सुधार करने के लिए स्थानीय कराधान वांछनीय है वहां साम्राज्यिक वित्त पर भार में कमी लाने के लिए स्थानीय कराधान स्थानीय सरकारों के बीच लोकप्रिय होने की संभावना नहीं है।<sup>122</sup> बंबई से सर बार्टल फ्रैने ने अपने सामान्य स्पष्टवादी ढंग से मैसी को लिखा कि वह इस शर्त पर व्यय की मदों के हस्तांतरण के लिए सहमत होगा कि आय की मदों का भी हस्तांतरण हो। उसके ही शब्दों में : 'परंतु उस समय बात दूसरी होगी जब उत्तरदायित्व का हस्तांतरण इस प्रकार बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए न केवल साम्राज्यिक कराधान के किसी भी अंश का हस्तांतरण किए बिना कर दिया जाए, बरन यह भी आदेश हो कि घनराशि जो अब तक स्थानीय कार्यों के लिए उपयोग में आती थी, उसका प्रयोग अब साम्राज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाए।'<sup>123</sup> पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ई० ड्रमंड तथा मद्रास के गवर्नर डब्ल्यू टी० डेनिसन का कहना था कि मैसी योजना में बिना भारत की स्थिति पर विचार किए हुए ही इंग्लैंड की स्थानीय वित्त प्रणाली को अपना लिया गया है।<sup>124</sup> पंजाब तथा मध्य प्रांत की सरकारों को छोड़ कर सभी स्थानीय सरकारें उन सभी व्ययों के लिए, जो अब तक साम्राज्यिक आय से किए जाते थे, स्थानीय कर लगाने के लिए अनिच्छुक थीं। सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री के सामने यह स्वीकार किया कि 'यदि अधिक कड़ा शब्द प्रयोग न किया जाए' तो व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों के हस्तांतरण के बिना खर्चों के हस्तांतरण पर 'लगभग सर्वत्र हिच-किचाहट है।'<sup>125</sup> अतः मैसी की योजना को वापस ले लिया गया और अगले वर्ष सरकार ने एक नई योजना प्रस्तुत की।

दूसरी योजना लोक निर्माण विभाग से संबद्ध कर्नल आर० स्ट्रैची ने तैयार की थी। मैसी ने विकेंद्रीकरण की योजना केवल साम्राज्यिक सरकार के भार को थोड़ा कम करने के उद्देश्य से तैयार की थी।<sup>126</sup> स्ट्रैची ने बिना इस बात का ध्यान दिए हुए ही कि भारत सरकार साम्राज्यिक आय से अपने खर्चों को पूरा कर सकेगी या नहीं, विकेंद्रीकरण की वांछनीयता के कारणों को स्पष्ट किया। (क) प्रांतीय और सर्वोच्च सरकारों के मध्य तत्कालीन वित्तीय संबंध प्रांतीय सरकारों के लिए 'हतोत्साहित करने वाले' हैं। 'लोक आय का वितरण विकृत होकर छीना-भ्रष्टाई जैसी चीज बन जाता है जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होती है और औचित्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।'<sup>127</sup> स्थानीय सरकारें साम्राज्यिक आय में से यथासंभव अधिक अंश पाने के लिए शोर मचाती हैं, साम्राज्यिक आय बढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती और

प्रांतीय स्तर पर मितव्ययता बरतने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती। वित्त के विकेंद्रीकरण से उनमें कुछ जिम्मेदारी की भावना आएगी क्योंकि उन पर ही कुछ विशिष्ट खर्चों के लिए साधनों की व्यवस्था बरने का उत्तरदायित्व होगा। (ख) प्रांतीय तथा सर्वोच्च सरकारों के मध्य सद्भावपूर्ण संबंधों के लिए थोड़ा सा विकेंद्रीकरण वाछनीय था। प्रांतीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले छोटे-बड़े व्ययों में सर्वोच्च सरकार द्वारा लगातार हस्तक्षेप तथा इस हस्तक्षेप के प्रति स्थानीय सरकारों की अप्रसन्नता से दोनों के बीच झगड़ा होता था।<sup>138</sup> यह सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग में होता था जिसमें स्ट्रुची काम करता था।<sup>139</sup> (ग) अंत में स्ट्रुची ने 'उन हितों के विस्तार में होने वाले असाधारण परिवर्तनों की ओर' ध्यान आकर्षित किया 'जिनसे पिछले 10-15 वर्षों में भारत सरकार का संपर्क रहा था।' सरकार के कार्य क्षेत्र में विस्तार तथा आय और व्यय में भारी वृद्धि से केंद्रीय नियंत्रण की पुरानी व्यवस्था अप्रचलित हो गई।

स्ट्रुची ने लिखा है कि 'मुझे कल्पना करनी चाहिए कि केंद्रीय अधिकारी की वित्तीय स्थिति सामान्य रूप से समुक्त राज्य की केंद्रीय सरकार की भांति मात्राओं को आत्मसात करने की होनी चाहिए, परंतु निस्संदेह उसके पास पृथक् स्थानीय प्रशासन के वित्त के ऊपर सामान्य ढंग के निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार भी होना चाहिए'।<sup>140</sup> स्ट्रुची का प्रस्ताव था कि प्रारंभ में व्यय की कुछ मदें (विधि एवं न्याय, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, लेखन सामग्री तथा मुद्रण) तथा साम्राज्यिक आय के कुछ स्रोत प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।<sup>141</sup> प्रांतीय सरकारें इन हस्तांतरित खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं ही उत्तरदाई होगी। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय कर लगा कर अतिरिक्त आय की जा सकती है। यह आशा की गई थी कि भविष्य में खर्चों की हस्तांतरित मदों से बढ़ने वाले व्यय को आय की हस्तांतरित मदों और अतिरिक्त स्थानीय करों से पूरा किया जा सकेगा। मैसी ने स्पष्ट किया कि हस्तांतरित व्यय तथा आय की राशियां लगभग समान हैं।<sup>142</sup> योजना की इस विशेषता के कारण प्रांतीय सरकारों ने इस पर अपनी सहमति दे दी जबकि मैसी की पहली योजना (आय के एक अंश के हस्तांतरण के बिना ही खर्चों का हस्तांतरण) के विषय में वे उत्साहित नहीं थे। मद्रास सरकार को छोड़कर सभी स्थानीय सरकारों ने विकेंद्रीकरण योजना का स्वागत किया।<sup>143</sup> ऐसा लग रहा था कि विकेंद्रीकरण की बहुचर्चित योजना शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी।

परंतु गवर्नर जनरल, उसकी परिपद के सेना संबंधी मामलों के सदस्य, मद्रास के गवर्नर तथा कुछ अन्य अधिकारियों ने विकेंद्रीकरण योजना का कड़ा विरोध किया। उनके एतराजों का सार चार श्रेणियों में रखा जा सकता है : (क) इस बात की आशंका थी कि विकेंद्रीकरण के द्वारा भारत सरकार का नियंत्रण शिथिल हो जाएगा। यह नियंत्रण चाहे 'कष्टप्रद' ही क्यों न हो आवश्यक था। मेजर जनरल सर एम० एम० ड्यूरेड का विश्वास था कि वर्तमान प्रणाली कितनी ही अरुचिकर क्यों न हो 'विघटन' से श्रेष्ठ है।<sup>144</sup> (ख) एक अन्य एतराज यह था कि इस योजना को अपना लेने से भारतीय पंजी निवेशों में ब्रिटिश पूंजीपतियों के विश्वास में कमी हो जाएगी। साम्राज्य

के विकास के लिए फिर ब्रिटिश पूजी नहीं मिल सकेगी।<sup>114</sup> मद्रास के गवर्नर लार्ड नैपियर अब मॉन्टेस्ट्रन ने स्पष्ट किया कि इंग्लैंड के मुद्रा बाजार में (भारत की) सर्वोच्च सरकार की सार्वभौमिकता की मान्यता करीब-जरीब वही है जो फ्रांस या संयुक्त राज्य अमरीका की है। वित्त के 'संघीकरण' की स्थिति में यह मान्यता जोरों पर पड़ सकती है।<sup>115</sup> (ग) इस बात की आशंका थी कि प्रांतीय सरकारें साम्राज्यिक हितों की उपेक्षा करें। 'संपूर्ण साम्राज्य के वित्तीय स्रोतों का प्रबंध करने वाली और प्रांतीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा अच्छे परिकल्पना से कही ऊँचे बानून से अनुप्राणित' केंद्रीय सरकार द्वारा कठोर नियंत्रण की आवश्यकता थी।<sup>116</sup> लारेंस ने विकेंद्रीकरण के परिणामों का अंधकारपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया था। 'प्रत्येक स्थानीय सरकार तथा प्रशासन डेड चावल की गिचड़ी अलग-अलग पकाने लगेगी और हर वर्ष इनकी प्रणालियों में अंतर बढ़ता जाएगा।'<sup>117</sup> यदि सर्वोच्च सरकार अपने वित्तीय नियंत्रण को छोड़ देती है तो उसे अन्यत्र भी अपने नियंत्रण को छोड़ना पड़ेगा। लगभग प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय जब व्यवहार में लागू किया जाता है तो उसके वित्तीय उलझाव होते हैं और यदि स्थानीय सरकारों को इसके लिए स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं तो वे इन मामलों को केंद्रीय सरकार के पास ही नहीं भेजेंगे। (घ) अंत में, योजना के आलोचकों का कहना था कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली में वित्त का संघीकरण संयुक्त राज्य अमरीका की संघीय वित्त व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न था। संयुक्त राज्य अमरीका की भांति भारत में लोकतंत्रीय प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं थी जो प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रख सकती।<sup>118</sup> कर्दाताओं को इसमें अधिक अंतर नहीं पड़ता था कि केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। जैसा कि मद्रास के बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अर्धपूर्ण ढंग से कहा कि यह मान लेना गलत होगा। कि किसी भी कर की 'साम्राज्यिक' के स्थान पर 'स्थानीय' कह देने मात्र से वह लोगों की दृष्टि में कर नहीं रहेगा अथवा उसमें स्वीकृति अथवा आरोपण में सुविधा का कोई विशेष गुण उत्पन्न हो जाएगा।<sup>119</sup>

इन आधारों पर वित्त विकेंद्रीकरण की योजना अस्वीकृत कर दी गई। मद्रास के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की परिषद के सेना संबंधी मामलों के सदस्य के विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकी। यद्यपि स्थानीय सरकारों तथा परिषद सदस्यों का बहुमत इस योजना के पक्ष में था, तथापि गवर्नर जनरल ने स्ट्रेंची तथा मैसी द्वारा बनाई गई योजना लागू न करने का निर्णय कर लिया। गवर्नर जनरल लारेंस (जो संभवतः मैन्य विद्रोह के अनुभव से बहुत प्रभावित था) थोड़े से भी विकेंद्रीकरण को मान कर केंद्रीय सत्ता को दुर्बल करने के लिए अनिच्छुक था। जब तक 1870 में मेयो ने इस प्रश्न को फिर नहीं उठाया, तब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ।

1870 में मेयो ने सर एस० फिट्जजेराल्ड को लिखा था : 'मुझे आशा है कि अब वित्त के विकेंद्रीकरण की भयानक निंदा समाप्त हो जाएगी।'<sup>120</sup> वह नए प्रयोग के प्रति अर्हचि हो थी। मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति से पूर्णतया प्रतिबद्ध था लेकिन उसने 'स्थानीय वित्त' शब्द को अधिक पसंद किया क्योंकि उसका विचार था कि 'विकेंद्रीकरण' शब्द से नियंत्रण में क्षीयलता की ध्वनि है। अपने स्थानीय वित्त संबंधी उपाय

लागू कर देने के बाद उसने 1871 में लिखा कि 'हम यह नहीं मानते कि हमने वित्त का विकेंद्रीकरण किया है अथवा कुशल नियंत्रण का लेख मात्र भी परित्याग किया है...'<sup>152</sup>

अपने आगमन के कुछ ही महीनों में मेयो को समझ में आ गया कि विशुद्ध रूप से स्थानीय मामलों में भी सर्वोच्च सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक है।<sup>153</sup> दूसरी ओर प्रांतीय सरकारों ने, और विशेष रूप से बर्मी सरकार ने, 'नियंत्रण के विरुद्ध काफी अर्धयंत्र' और 'संघर्ष का शोचनीय झुकाव' दिखाए।<sup>154</sup> प्रांतीय सरकारों के अधिकारी 'इंग्लैंड में रहने वाले अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तथा बलबो में खीझ दिखाते और बड़बड़ाते थे।'<sup>155</sup> प्रांतीय सरकारों और सर्वोच्च सरकार में अच्छे संबंध नहीं थे। ऐसी स्थिति में मेयो ने 'टकराव को कम करने और आपसी भावनाओं में सुधार करने', प्रांतीय सरकारों को अधिक उत्तरदायित्व देने तथा पत्र व्यवहार में कमी करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस की।<sup>156</sup>

मेयो का विश्वास था कि इस प्रकार की योजना राजकोपीय दृष्टि से लाभदायक होगी। प्रांतीय अधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि 'लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार व्यवस्था अधिक सुविधापूर्वक होगी।' <sup>157</sup> मेयो ने नैपियर के नाम एक पत्र में वित्तीय हस्तांतरण पर सहमति के लिए उसे राजी करने के लिए लिखा : 'यह सभी को दिखाई देता है कि हमारी बड़ी हुई आवश्यकताओं के लिए कराधान में वृद्धि होनी चाहिए, और अच्छा यही होगा कि यह बड़ी हुई स्थानीय स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्थानीय अंशदान के रूप में प्राप्त हो, न कि साम्राज्यिक अंशदान के रूप में'।<sup>158</sup> इसके अलावा स्थानीय वित्त प्रणाली से मितव्ययता बढ़ेगी। मेयो का इरादा था कि स्थानीय सरकारों के लिए अपने बजटों का प्रकाशन तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों को सर्वोच्च सरकार के साथ-साथ प्रांतीय विधान परिषद (जहां पर इस प्रकार की परिषद का निर्माण हो गया था) के पास भेजना अनिवार्य कर दिया जाए।<sup>159</sup> मेयो ने फिट्जराल्ड को लिखा 'मेरा विचार है कि स्थानीय बजटों के प्रचार और लोगों में इस भावना के जागरण से कि वे अपनी ही धनराशि व्यय कर रहे हैं, नियंत्रण की स्थापना होगी जो गवर्नर जनरल द्वारा रखे जाने वाले निबंधन की अपेक्षा अधिक कड़ा होगा।' <sup>160</sup> सड़कों, छोटी इमारतों व जेलों के निर्माण, शिक्षा, पुलिस आदि व्यय की शाखाओं में अपव्यय हो रहा था और इसे स्थानीय सरकार के ब्रजवादा कोई अन्य सत्ता कुशलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकती थी।

राजनीतिक कारणों से भी स्थानीय वित्त की प्रजापति मंडेडिन प्रणाली की अपेक्षा श्रेष्ठ थी। मेयो के शब्दों में 'हमें इस देश की सरकार में यहां के निवासियों को अपना सहयोगी बना लेना चाहिए। हमने इसकी बहुत उम्मीद की है... यह समय की बात हो सकती है। जिस तरह अन्य देशों में स्थानीय शासन की समस्याओं का उद्गम और विकास सामान्यतः स्वशासन की शक्तियों के विकास में बढ़ावा दे सकता है, कि शासन हमें प्रशासन में सर्वश्रेष्ठ सहायता यहां के मूल निवासियों में ही मिलेगी... इससे जो भी शक्तियां हस्तांतरित की जा सकती हैं वे हमें स्थानीय अधिकारियों को देनी चाहिए'।

होगी और उन्हें उनके जिलों के प्रबंध के विषय में आदेश देने होंगे...<sup>161</sup> मेयो 'स्वदेशी स्वशासी पालिक संस्थाओं'<sup>162</sup> का निर्माण करना और 'स्थानीय वित्त के प्रबंध में' भारतीयों को 'अधिक हिस्सा' देना चाहता था।<sup>163</sup> स्थानीय शासन की नई रूपरेखा तैयार करने में समय लगना था, अतः तत्काल साम्राज्यिक विधान परिषद में जिस प्रकार बजट प्रस्तुत किया जाता था ठीक उसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों (जहां पर भी ये थीं) में वार्षिक विवरणों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की जा सकती थी।<sup>164</sup>

मौलिकता की दृष्टि से ये विचार असाधारण नहीं थे। विकेंद्रीकरण के लाभों पर लैंग, स्ट्रैची, मैसी तथा कुछ अन्य लोगों ने भी प्रकाश डाला था। परंतु जहां मेयो को सफलता मिली वहां अन्य लोग असफल रहे। मेयो को मालूम था कि सुधार के रास्ते में 'प्रांतीय ईर्ष्या तथा संकीर्ण विचारधारा' बाधक हैं।<sup>165</sup> उसने सरकार के सभी सर्वोच्च अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण अफसरों को अपने पक्ष में करने में बहुत सावधानी से काम लिया। वह काफी पत्र लिखता था और उसके निरंतर समझाने-बुझाने और दबाव डालने से सारा विरोध अंततः समाप्त हो गया। इसके द्वारा राईलैंड नैपियर आब मर्किस्ट्रन, सर फिट्जेराल्ड, सर डब्ल्यू० म्योर, सर बी० फोर, डब्ल्यू० आर्बुथनाट के साथ किए गए पत्र व्यवहार में अधिकांश, जिससे कुछ उद्धरण ऊपर दिए गए हैं, विकेंद्रीकरण के प्रश्न से ही संबंधित थे।

मेयो को अपनी परिषद के वित्त सदस्य सर आर० टैपिल से अधिक सहायता नहीं मिली। टैपिल ने 1868 में एक योजना तैयार की थी जिसमें उसने राज्य सरकार के छोटे-छोटे मामलों के बारे में सर्वोच्च सरकार के नियंत्रण को ढीला करने का प्रस्ताव रखा था और मद्रास तथा बंबई की सरकारों को बहुत थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाही थी।<sup>166</sup> मेयो ने आरगाइल को बतलाया था कि टैपिल की योजना 'के द्वारा वास्तव में नाम भर का परिवर्तन होना था न कि मर्यादा'।<sup>167</sup> मेयो टैपिल के सुझावों के आधार पर कार्य नहीं करना चाहता था और उसने इस मामले को कुछ समय के लिए स्थगित हो जाने दिया। 1870 में मेयो ने अपनी योजना तैयार की और परिषद में टैपिल द्वारा कड़े विरोध के बावजूद यह योजना, छोटे-मोटे सशोधनों के बाद, स्वीकार कर ली गई।<sup>168</sup>

मेयो की योजना को, जिसकी रूपरेखा उसने जून, 1870 के अपने कार्यवृत्त में दी थी, वित्त सचिव ने प्रांतीय सरकारों को अगस्त, 1870 में भेजे गए अपने परिपत्र में विस्तार के साथ स्पष्ट किया था। इसे 14 दिसम्बर, 1870 के सपरिषद गवर्नर जनरल के प्रस्ताव द्वारा अंतिम रूप देकर स्वीकार किया गया।<sup>169</sup> योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं: प्रशासन के कुछ विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिए गए थे विभाग थे: जेल, पुलिस, रजिस्ट्रीकरण, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं (चिकित्सा प्रतिष्ठानों को छोड़कर) मुद्रण, सड़क, असेनिक भवन, तथा प्रकीर्ण सार्वजनिक सुधार। इन सभी विषयों पर व्यय पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों की आय के स्रोत थे: (क) इन मदों से विभागीय प्राप्तियां, (ख) इन प्रांतीय सेवाओं के लिए वार्षिक साम्राज्यिक आय से स्थाई रूप से दिए जाने वाले निश्चित एक मुश्त राशियों में अनुदान, (ग) और

यदि कमी पड़े तो स्थानीय कराधान <sup>170</sup> साम्राज्यिक बजट में प्रांतीय सेवाओं के नाम से दिखाए जाने वाले आबंटन प्रांतीय सरकारों के अधिकार में होंगे और इनकी राशियाँ निश्चित होंगी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। प्रांतीय सरकारों पर कुछ शर्तें लगाई गई थी। ऐसी कुछ शर्तों का उद्देश्य था कि अपव्यय या धनराशि के अनुचित व्यय को रोकने की दृष्टि से लेखाओं तथा प्राक्कलनों की जाच और उनके प्रकाशन की निश्चित व्यवस्था। प्रांतीय सरकारों के लिए अपने वार्षिक प्राक्कलनों तथा लेखाओं को प्रांतीय गजटों में प्रकाशित करना और जिस प्रकार साम्राज्यिक बजट विधान परिषद में पेश किया जाता था उसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों (जहाँ पर ये सभाएँ थीं) में साम्राज्यिक बजट जैसा एक वित्त विवरण पेश करना आवश्यक था। प्रांतीय सरकारों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे भारत सरकार को वार्षिक लेखे व प्राक्कलन भेजेंगी। एक अन्य प्रकार की शर्तों के द्वारा सर्वोच्च सरकार के हाथ में सामान्य वित्तीय नियंत्रण का अधिकार सुरक्षित रखा गया। ऐसे सभी मामलों में, जिनका संबंध किसी भी श्रेणी में आने वाले अफसरों के वेतनमानों में परिवर्तन, 250 रुपये से अधिक वेतन के पदों के सृजन, अवकाश तथा भत्ते संबंधी साम्राज्यिक सेवा के नियमों में परिवर्तन तथा सार्वजनिक खजाने में मुद्रा के निवेश से होता था, सर्वोच्च सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत सरकार की सामान्य नीति से विचलन (प्रांतीय सरकारों का) अथवा शर्तों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए हस्तांतरित विषयों के प्रशासन और हस्तांतरित धनराशियों के संयंतरण में हस्तक्षेप कर सकने का अधिकार अपने पास रखा। प्रांतीय सरकारों ने इस व्यवस्था के बारे में अपनी स्वीकृतियाँ दे दी यद्यपि इस वास्तविकता के कारण कि साम्राज्यिक आय से आबंटन छोटे थे और न्याई रूप से निश्चित थे, उन्हें इसके संबंध में कुछ संदेह बने रहे।<sup>171</sup>

विकेंद्रित वित्त की योजना 1871-72 के वित्तीय वर्ष से व्यवहार में आ गई। अगले कुछ वर्षों के अनुभव से मेयो द्वारा तैयार की गई योजना के दोष प्रकट हो गए। प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित खर्चों को पूरा करने के लिए निश्चित राशियाँ आवंटित हुई थी। जैसे ही हस्तांतरित विभागों (विशेष रूप से शिक्षा, सड़कों, पुलिस, तथा सार्वजनिक सुधार) के खर्चों में वृद्धि हुई, प्रांतीय सरकारों के लिए व्ययों को पूरा कर पाना अधिकाधिक कठिन हो गया। अतः विकेंद्रीकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के लिए अपने व्यय में तो कमी कर पाया संभव हुआ, परंतु इससे स्थानीय सरकारों पर स्थानीय करो से अतिरिक्त आय प्राप्त करने का कठिन कार्य आ गया। मेयो का विश्वास था कि 'यदि लोग यह देख सकेंगे कि अतिरिक्त कराधान केवल उन्हीं के लाभ के लिए किया जा रहा है तो उनके 'एतराज कम होने लगेंगे'।<sup>172</sup> तथापि प्रांतीय सरकारों को ऐसे करो के स्रोत तलाश करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा जिनसे खजाने को पर्याप्त आय होती। लोकमत करो की संख्या बढ़ाने के विरुद्ध था। आरगाइन ने ठीक ही कहा था कि स्थानीय करो के साम्राज्यिक करो से अधिक लोकप्रिय होने की संभावना उस समय तक नहीं थी जब तक दोनों ही प्रकार के कर 'सरकार द्वारा लोगों की भावनाओं और उनके विचारों को समझे बिना लगाए जाए'।<sup>173</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि 1871-72 में

प्रस्तावित स्थानीय करों : जैसे बवई नगर में चुगी तथा गृह कर, बंगाल में मालगुजारी पर सड़क और शिक्षा उपकर (सेस) तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में विविध स्थानीय करों के विरुद्ध लोकमत की कड़ी प्रतिक्रिया हुई।<sup>1171</sup>

भारत सरकार की कुल आय के दसवें भाग से भी कम आय प्रांतीय सरकारों को दी गई। केंद्रीय और स्थानीय आयों में उचित अनुपात बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रांतीय सरकारों के मध्य धनराशि के वितरण में अनौचित्य से बहुत ईर्ष्या या मनोमालिन्य था। जब मद्रास के गवर्नर नैपियर ने इस संबंध में शिकायत की तो मेयो ने लिखा, 'यदि इस प्रश्न को मद्रास की ओर से उठाया गया है तो आपको निश्चय ही भारत में एक भी ऐसा प्रांत नहीं मिलेगा जो, अपने विचार से, अधिक धनराशि के लिए उतना ही अच्छा पक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ न हो जितना कि मद्रास द्वारा किया गया है। सभी प्रांत पूर्णतया मनुष्ट होकर अपने-अपने ढंग से यह दिखा सकेंगे कि अन्य प्रांतों को बहुत अधिक धन दिया जा रहा है।'<sup>1172</sup> यह सत्य था परंतु, साथ ही, यह भी यथार्थ था कि विभिन्न प्रांतों को आवंटन का वितरण पुराने लिखित प्रमाणों के आधार पर किया गया था न कि वर्तमान अथवा भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर।

इसके अलावा, प्रांतीय सरकारों को प्रशासन की वे शाखाएं : जैसे सामान्य प्रशासन, मालगुजारी तथा उत्पाद शुल्क : नहीं दी गईं जिनमें उनकी प्राथमिक रूप से दिलचस्पी थी। 'उनकी अपनी वर्तमान आय में पर्याप्त वृद्धि करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इस वृद्धि से केवल भारत सरकार का ही लाभ होना था।'<sup>1173</sup> सर चार्ल्स ट्रेवीलियन का विचार था कि मेयो योजना के प्रति यह निर्णायक आपत्ति थी। उसका कहनाय था कि स्थानीय सरकारों के कार्य दृढ़ता के साथ परिभाषित नहीं किए जा सके। परंतु भारत सरकार के पास साम्राज्यिक हितों को प्रभावित करने वाले कुछ कार्य थे। जिनका संघर्ष सेना, वैदेशिक संबंध, लोक ऋण, डाक सेवा, आदि विभागों से था। इन कार्यों का ठीक प्रकार से सीमांकन होना चाहिए था और इनमें वाणिज्य विनियोजन की राशि निर्धारित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार दोष कार्य और आय का दोष भाग प्रांतीय सरकारों के लिए बच रहता।<sup>1174</sup>

मेयो ने मान लिया था कि वित्त के विकेंद्रीकरण द्वारा स्वशासन में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और प्रांतीय एवं स्थानीय मंत्रियों में यूरोपीय लोगों के गंपर्न में आकर भारतीयों को स्वशासन की निप्पटार मिलेगी। भारत मंत्री की यह धारणा थी कि सरकार 'स्थानीय समुदायों की ओर से जो भी कदम उठाएगी उन पर स्थानीय लोगों की सामान्य रूप से सहमति प्राप्त कर लेगी।'<sup>1175</sup> वास्तव में 1871-72 के उपायों का अर्थ आय और व्यय की कुछ मदों का प्रांतीय सरकारों को हस्तान्तरण मात्र था। विकेंद्रीकरण के साथ नगरपालिकाओं तथा स्थानीय बोर्डों (नोबल बोर्डों) के माध्यम से वास्तविक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था नहीं हुई। 1871 नगरपालिकाओं में निर्वाचित तत्व नहीं थे। स्थानीय निकायों में मजबूरी महत्व बढ़ी मंथरा में होने दे।<sup>1176</sup> सर चार्ल्स ट्रेवीलियन ने स्पष्ट किया था कि वास्तविक विकेंद्रीकरण अंग में 'प्रतिनिधि प्रणाली' का रूप ले लेता है। 'अब यह उद्देश्य प्राप्त हो गया हो तो देश को जिना कोई हानि पहुंचाना, हुए शासकों

तथा शिक्षकों को चले जाने देना चाहिए।<sup>180</sup> इन शब्दों की दबी प्रतिध्वनि दबी हुई आवाज में भारतीयों के प्रतिनिधि गंगठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा पेश किए गए स्मरण पत्र में सुनाई पड़ती हैं।<sup>181</sup> स्मरण पत्र दाताओं का विचार था कि 'प्रत्येक प्रांत को एक संपूर्ण राज्य माना जाना चाहिए' और 'लोगों को प्रशासन में यथासंभव व्यावहारिक हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।' कुछ साम्राज्यिक खर्चों जैसे सेना, लोक ऋण तथा गृह खर्चों को पूरा कर लेने के बाद शेष आय प्रांतीय सरकारों के लिए छोड़ दी जानी चाहिए और केंद्रीय सरकार को केवल सामान्य निरीक्षण अपने पास रखना चाहिए। परंतु ऐंग्लो इंडियन तथा स्वदेशी समाचार पत्रों ने अधिक विकेंद्रीकरण के लिए हों-हल्ला मचाया।<sup>182</sup> ऐसा अनुभव किया गया कि मेयो योजना सही दिशा में उठाया गया कदम है, परंतु वह बहुत प्रगतिशील न थी। वह संघीकृत वित्त प्रणाली की दिशा में प्रगति की एक अवस्था मात्र थी। प्रतिनिधि प्रणाली जिसकी चर्चा ट्रैवीलियन ने की थी, साम्राज्य के अधिकांश प्रशासकों की दृष्टि से एक दूरस्थ सभावना थी। साम्राज्यवाद के मध्याह्न काल में ट्रैवीलियन जैसा व्यक्ति एक हल्की छाया मात्र था।

## संदर्भ

1. आरगाइन से मेयो को, 6 जनवरी, 1871। मेयो कागजात, बंडल 49, सख्या 1।
2. एच० डोडवेल के अनुमार 'संभवतः 1858, में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन भारत मंत्री के हाथ में वित्तीय शक्तियों का केंद्रीयकरण था। हेनरी डोडवेल, 'ए स्कैच आफ हिस्ट्री आफ इंडिया' 1858-1918' (सदन 1925), पृ० 32।
3. डलहौजी से जार्ज कूपर को, 23 सितंबर, 1854। 'जे० जी० ए० बेअर्ड (संपादक) 'ग्राइवेट लैटर्स आफ दि भारतवेम आफ डलहौजी' (सदन, 1910), पृ० 321।
4. भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त प्रेषण सख्या 43, 26 मार्च, 1860।
5. भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त प्रेषण सख्या 1, 12 जनवरी, 1860; सख्या 85, 26 मई 1860।
6. सर आर० मोटगोमरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब से लार्ड कैनिंग की त्रिसमे कैनिंग द्वारा सी० वुड को लिखे गए पत्र को उद्धृत किया गया था, 25 अप्रैल, 1860। ई० आई० वैरिंगटन 'सर्वेंट्स आफ आल' II, पृ० 26। जे० विल्सन से सी० वुड को 11 जुलाई, 1859, वही, पृ० 171। सी० वुड से जे० विल्सन को 26 मार्च, 1860, वही पृ० 238।
7. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 122, 2 अगस्त, 1861। भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 170, 23 सितंबर, 1861।
8. भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त प्रेषण सख्या 196, 16 दिसंबर, 1861।
9. वही, 63, 17 मार्च, 1864।
10. वही, 63, 26 मई, 1864।
11. वही, 227, 26 सितंबर 1864। सदस्य सी० ट्रैवीलियन ने एक अन्य बात उठाई थी कि



दूसरी औपनिवेशिक सरकारों पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। भारत मंत्री ने स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक सेवा के नियमों की धारा 346 और 367 द्वारा औपनिवेशिक सरकारों (जहां पर प्रतिनिधि विधान सभाएं नहीं थी) पर लगाए गए प्रतिबंध समान रूप से कठोर थे।

12. पूर्वोक्त स्थल।

13. तेज संचार व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ था कि प्रेस और व्यापारियों को जल्दी ही समाचार मिल जाते थे, जब कि बॉम्बे सरकारों संचार प्रणाली पीछे रह जाती थी। मेयो से आरगाहल को, 13 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बंडल 41, सख्या 311।

14. लार्ड केनवॉले 'हसाडे', तृतीय सौरीज, C x C iv, 1074, C X C iv, 700 उद्धृत, ए० बी० कीथ, 'ए कास्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया' (सदन, 1936) पृ० 168। सर सी० इल्वर्ट, 'दि गवर्नमेंट आफ इंडिया' (आक्सफोर्ड, 1922) पृ० 105।

15. सी० बूड से लार्ड कैनिंग को, 9 जनवरी, 1861। बूड कागजात, आई० ओ० एल० जिल्ड 6, पृ० 14 उद्धृत सी० एच० फिलिप्स (संपादक) 'दि एवोल्यूशन आफ इंडिया एंड पाकिस्तान' 1858-1947-सिलेक्ट डोक्यूमेंट्स' (सदन, 1962) पृ० 11-12।

16. सी० बूड से बी० फ्रेर को, 17 सितंबर, 1860। जे० माटियू, 'दि लाइफ एंड कारेस्पॉन्डेंस आफ सर बार्टन फ्रेर' (सदन, 1895), I पृ० 353।

17. यह कैनिंग और बार्टन फ्रेर का निश्चित मत था, जिन्हें किसी भी प्रकार अति उग्रवादी नहीं कहा जा सकता। बी० फ्रेर से सर मी० बूड को 22 अक्तूबर, 1860, वही, पृ० 355, लार्ड कैनिंग से सर सी० बूड को 24 अक्तूबर, 1860, पृ० 358।

18. मेयो से आरगाहल को 22 जुलाई, 1870। मेयो कागजात, बंडल 40 सख्या 208। मेयो ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यद्यपि यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, तथापि 'मेरा विचार है कि 25 वर्ष के अनुभवी जिला अधिकारी को, जिसका जीवन संघर्ष और ताजा कैरियर पर बीता है, सेलिक्टड गवर्नर्स और विभिन्न श्रेणियों में आने वाले भूतपूर्व प्रभावशाली व्यक्तियों के समकक्ष स्थान देना मानसिक दृष्टि से आघातपूर्ण होगा...'

19. एम० नोर्थकोट से जे० लारेंस को 9 फरवरी, 1868। लारेंस कागजात, भारत मंत्री से जे० लारेंस को जिल्ड, V सख्या 5।

20. हेनरी फामर, समद सदस्य, कैबिनेट विधिविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर, 'इंडियन फाइनेंस' (सदन, 1880) पृ० 115। भारतीय वित्त के विषय में मामाग्य समद सदस्य की अज्ञानता के बारे में देखें, मेयो से नोर्थकोट के नाम पत्र, 3 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बंडल 48 सख्या 61।

21. 'दिल्ल पैट्रिस्ट' (31 अगस्त, 1868) ने टिप्पणी की थी कि भारतीय वित्त के विषय में बहुत 'ग्रहमनमात्र' थी; 1868 के वित्त विवरण पर वहन के समर्थ समद के 630 सदस्यों में केवल 30 उपस्थित थे। 'इग्निशमेन' (3 अगस्त, 1870) ने घोषणा की कि चूंकि भारतीय वित्त से संबंधित प्रश्नों की समद में उपेक्षा होती है, अब भारत का शासन बही ॥ चलाना चाहिए। यह नारा कि 'भारत का शासन भारत से ही होना चाहिए' सदैव लोकप्रिय रहा है ('फ्रेंड्स आफ इंडिया', 11 मितंबर, 1862)।

22. देवें सव्यसाची भट्टाचार्य 'लेस्ले फेअरे इन इंडिया', 'दि इंडियन इकानामिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू' जिल्द 11 सख्या 1, जनवरी, 1965, पृ० 1-22 ।
23. देखें, आगे अध्याय 3 ।
24. वही ।
25. मेयो से एम० नोर्थकोट को, 16 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, सख्या 315 ।
26. पूर्वोक्त स्थल, भूतपूर्व एंग्लो इंडियन अपने नौकरों को 'कोई हैं' कहकर आवाज देते थे ।
27. मेयो ने आरगाइल को 18 जनवरी, 1871, मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 24 ।
28. मेयो से एम० नोर्थकोट को, 16 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, सख्या 315 ।
29. आर० टैपिल से ओ० टी० बर्नो को 25 जुलाई, 1871 मेयो कागजात, बडल 61 (सख्या नहीं दी है) । प्रवर समिति ने भारत सरकार के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछे गए प्रश्नों की भाषा 'उद्धृत व आपत्तिजनक थी थी एफ० (फासट) के सहायक प्रभु वास्तव में प्रभु न होकर भारत सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार थे ।'
30. आरगाइल से मेयो को, 16 दिसंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 48, सख्या 34 ।
31. मेयो से बी० डिजरायली को, 9 मई 1871, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 10 ।
32. रिचर्ड टैपिल, 'मैन एंड ईवेंट्स आफ माई टाइम इन इंडिया', (सदन, 1892) पृ० 187 ।
33. जे० विल्सन से एलिजा बिस्सन को, 21 जुलाई, 1859 और जे० विल्सन से लार्ड कैनिंग को 25 अगस्त, 1859, ई० बरिंगटन, पूर्वोद्धृत जिल्द 11, पृ० 181 ।
34. ए० बी० रूद्रा, 'दि वायमराय एंड गवर्नर जनरल आफ इंडिया' (ओ० यू० पी०, 1940) पृ० 64-65 ।
35. आरगाइल के अनुसार यह ग्लैडस्टन और सर चार्ल्स वुड (लार्ड हैलीफाक्स) का भी मत था । आरगाइल से मेयो को, 1 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडल 48, सख्या 26 ।
36. आरगाइल से मेयो को 1 नवंबर, 1871, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 19 ।
37. बी० फ्रे से लार्ड कैनिंग को, 11 जून, 1861 । माटिंग्यू, पूर्वोद्धृत, I, पृ० 326-27 । मेयो का भी यही मत था । 'मेरे विचार में इंग्लैंड से भेजे जाने वाले सदस्यों (एक को छोड़कर) को कोई विशेष सफलता नहीं मिली ।' मेयो से आरगाइल को, 14 जुलाई, 1870, मेयो कागजात, बडल 40, सख्या 202 ।
38. बी० फ्रे से सी० वुड को, 23 नवंबर, 1860, माटिंग्यू, पूर्वोद्धृत, I, पृ० 313 ।
39. 'हिंदू पेट्रिअट', 16 फरवरी, 1868, संपादकीय का शीर्षक था 'नया वित्त मंत्री ।'
40. 'पूर्वोक्त स्थल', 1872 में 'हिंदू पेट्रिअट' ने सुझाव दिया था कि किसी हिंदू को वित्तीय मामलों का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए । 'यदि आप चाहें तो लोगों के स्वभाव, उनके जीवन के ढंग तथा उनके पूर्वाग्रहों के विषय में पूर्ण जानकारी से अनुपयुक्त, असह्य व अनुत्पादक करो को समावना को रोका जा सकेगा ।' 'हिंदू पेट्रिअट' 16 दिसंबर, 1872 ।
41. आरगाइल से मेयो को, 1 नवंबर 1871, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 19 ।
42. 'हाउस आफ कामंस' में सी० वुड का भाषण, 9 अगस्त, 1859 । 'फाइनैशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टु इंडिया' रिप्रिंटेड फ्रॉम हार्ड्स पार्लियामेन्टरी डिबेट्स', पृ० 281 ।
43. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 96, 30 मितवरे, 1859 ।

44. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सध्या 83, 8 जून, 1862 ।
45. मेयो से सर डब्ल्यू० मैसफिल्ड को, 11 मार्च, 1869, मेयो कागजात, बडल 34, सध्या 89 ।
46. वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1868 । पृथक राजस्व सध्या 32, डब्ल्यू० आर० मैसफिल्ड द्वारा मेमो०, 28 अगस्त, 1868 ।
47. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1868, लेखा शाखा सध्या 82, डब्ल्यू० आर० मैसफिल्ड द्वारा मेमो० 5 अप्रैल, 1868 ।
48. मेयो से आरगाइल को, 9 जनवरी, 1871, मेयो कागजात, बडल 42, सध्या 13 ।
49. देखें, संपादकीय, शीर्षक 'दि काउंसिल बिकम्स द कैबिनेट फ्रेंड आफ इंडिया', 1 अगस्त, 1861 ।
50. एस० नोर्थकोट टु जे० लारेंस, 9 जनवरी, 1868, लारेंस कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द V, सध्या I ।
51. एस० नोर्थकोट टु जे० लारेंस, 9 फरवरी, 1868, लारेंस कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द V, सध्या 5 ।
52. सर कोर्टन हल्बर्ट, 'दि गवर्नमेंट आफ इंडिया', (लंदन, 1922), पृ० 90-92 ।
53. देखें आगे अध्याय 3 ।
54. बार्टल फेर से सर सी० वुड को 10 अप्रैल, 1861 । माटिन्सू, पूर्वोद्धृत 1, पृ० 336 ।
55. सर सी० वुड से बी० फेर को 9 जून, 1861 और 18 फरवरी, 1861 । माटिन्सू द्वारा उद्धृत, पूर्वोद्धृत, 1, पृ० 330-36 । विधान परिषद में मसूरा के राजकुमारों को अनुदान के विषय में हुई आलोचना से सरकार को लज्जापूर्ण उसभून का सामना करना पड़ा था । विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) जिल्द VI, 1860, पृ० 1343-1402 ।
56. बी० फेर से सी० वुड को 10 अप्रैल, 1861, माटिन्सू, पूर्वोद्धृत, I, 336 ।
57. सी० वुड से बी० फेर की 17 अगस्त, 1861, माटिन्सू, पूर्वोद्धृत, I, 343 ।
58. 'विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की सध्या को बढ़ाया गया । सध्या कम से कम छ और अधिक से अधिक बारह हो सकती थी और इनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा दो वर्ष के लिए की जाती थी । इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आगे गैर सरकारी अफसर अर्थात् ऐसे व्यक्ति होते थे जो राज्य की सैनिक अथवा सिविल सेवा में न हों ।' सी० हल्बर्ट, पूर्वोद्धृत, पृ० 100 ।
59. सी० हल्बर्ट, पूर्वोद्धृत, पृ० 107 ।
60. देखें 'लोकमत' से संपादित अध्याय । 'हिंदू पेट्रियट' 5 सितंबर, 1860, 6 मार्च, 1868, 6 अप्रैल, 1868, 21 फरवरी, 1870, 11 जुलाई, 1870, 10 अप्रैल, 1871 । 'सोम प्रकाश', 9 मार्च, 1868 । आर० एन० पी० (बंगाल) 1868, पृ० 107 । 'जामे जमशेद', 15 फरवरी, 1869, 10 मार्च, 1869 । आर० एन० पी० बंबई (1869) पृ० 94, 133 । वित्त कार्यविवरण जुलाई, 1860, सध्या 26 । सचिव, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से सचिव, बंगाल सरकार को 3 फरवरी, 1868 । 'वही', सध्या 35 । ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से भारत मंत्री को याचिका, 1 फरवरी, 1868 ।
61. सी० ईवोलियन द्वारा मेमो०, 20 मार्च, 1860, पी० पी० एच० सी० 1860, जिल्द 49, पृ०

112। यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रिबोलीयन इंडियन काउन्सिल एक्ट पारित होने से पहले की स्थिति के विषय में कह रहा है।

62. वित्त कार्यविवरण 1867। राजस्व सख्या 21, भारत सरकार से भारत मंत्री को 20 अप्रैल, 1867।
63. पूर्वोक्त स्थल।
64. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संख्या 96, 30 सितंबर 1859।
65. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण 26 नवंबर, 1859, भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त सख्या 33, 24 फरवरी, 1860।
66. गृह कार्यविवरण सार्वजनिक 11 मार्च, 1861, सख्या 55। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 11 मार्च, 1861।
67. गृह कार्यविवरण सार्वजनिक 11 मार्च, 1862 सख्या 7। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 11 मार्च, 1861।
68. गृह कार्यविवरण सार्वजनिक 6 नवंबर, 1863 सख्या 14—इसके द्वारा मार्च, 1862 के आदेश को रद्द किया गया और गृह विभाग के सचिव को आदेश दिया गया कि वह 'स्टाम्प' और 'सीमा शुल्क' शाखाओं को अपने नियंत्रण में लें।
69. पूर्वोक्त स्थल। नितंबर, 1864 तक कुछ प्रांतों पंजाब, अवध, मध्य प्रांत और ब्रिटिश बर्मा में ये परिवर्तन नहीं हुए। ठाकुर, तारपुर और मातगुजारी पहले की भांति गृह विभाग के नियंत्रण में बने रहे।
70. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 1, 8 जनवरी 1863, भारत सरकार से भारत मंत्री को, सैन्य विभाग प्रेषण सख्या 132, 19 मार्च, 1864।
71. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 156, 30 जून, 1864।
72. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 161, 30 जून, 1865।
63. गृह कार्यविवरण सार्वजनिक, दिसंबर, 1867 सख्या 78 सचिव, सैन्य विभाग, एच डब्ल्यू० नोरमन 20 सितंबर, 1867।
74. गृह कार्यविवरण सार्वजनिक, दिसंबर, 1867, सख्या 60। ई० सी० बेले, सचिव, गृह विभाग।
75. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 96, 15 अप्रैल, 1865।
76. गृह कार्यविवरण सार्वजनिक, दिसंबर, 1857 सख्या 62। कर्नल सी० एच० डिकिंस, सचिव, लोक निर्माण विभाग का नोट 21 नवंबर, 1867।
77. मेयो से आरगाहल को, 11 अप्रैल, 1870, मेयो कागजात, बडल 39, सख्या 100। ठीक वही 22 जुलाई, 1870, मेयो कागजात बडल 40, संख्या 208।
78. वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1865, व्यय सख्या 81। ई० एच० ललिंगटन, सचिव, वित्त विभाग का नोट, 18 फरवरी, 1865, फंड आफ इंडिया, 15 मई, 1862।
79. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 55, 20 मार्च, 1865। 1862-65 की अवधि में वित्त विभाग में केवल एक कर्मचारी की परिवर्तना पर नियुक्ति हुई। वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1865, व्यय सख्या 81। सचिव, विभाग का नोट 18 फरवरी, 1865।
80. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 141, 16 जून, 1865।

81. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1865, व्यय संख्या 82 । ई० एच० फास्टर का नोट, 20 फरवरी, 1865 ।
82. एडवर्ड ह्यूजेज. 'सर चार्ल्स ट्रेवीलियन एंड सिविल सर्विस रीफार्म्स' 1853-55 'दि इंग्लिश हिस्टोरिकल रिव्यू', जिल्द L XIV, 1949 खंड 1 पृ० 53, खंड 11 पृ० 206 । वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1865, व्यय संख्या 83, सी० ई० ट्रेवीलियन द्वारा मेमो०, 23 फरवरी, 1865 ।
83. वही, संख्या 81, ई० एच० लॉसिंगटन, सचिव, वित्त विभाग का नोट, 1865 ।
84. पूर्वोक्त स्थल ।
85. पूर्वोक्त स्थल ।
86. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1865, व्यय संख्या 83, सी० ई० ट्रेवीलियन द्वारा मेमो०, 23 फरवरी, 1865 ।
87. मेयो से बी० फ़ोर को, 6 दिसंबर 1869, मेयो कागजात, बंडल 27, संख्या 345, मेयो से आरणाइल को 2 अक्टूबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 37, संख्या 265 ।
88. वित्त कार्यविवरण, 17 अगस्त, 1860, लेखा शाखा संख्या 93 (ए) ।
89. पूर्वोक्त स्थल ।
90. जे० विल्सन से डब्ल्यू० बेजहाट को, 19 जुलाई, 1860, डब्ल्यू० बेजहाट द्वारा उद्धृत, 'सिटिरेरी स्टडीज' (सदन, 1879), जिल्द I, पृ० 401 । सैन्य विद्रोह द्वारा पुरानी प्रणाली की वित्तीय दुर्बलताएं प्रकट हो गई थीं । सैन्य विद्रोह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक अभिन्न एवं दूर-दर्शी पद्धति और अविव्य में व्यय के । विशेष रूप से सैन्य विभाग से संबंधित विश्वसनीय प्रावकलों के निर्माण में अधिक प्रगति नहीं हुई थी—फलतः उनमें (1860 से पहले के प्रावकलों में) उस स्थिति में जब कि व्यय की दर में निरंतर परिवर्तन हो रहे थे, सदैव ही झुटिया रहती थी । सैन्य विद्रोह द्वारा उत्पन्न गड़बड़ी में ये झुटिया और अधिक बढ़ गईं ।
91. वित्त कार्यविवरण दिसंबर, 1860, मद्रास के गवर्नर सी० ई० ट्रेवीलियन का मेमो०, 12 मई, 1860 । अपने 25 मई, 1859 तथा 13 जुलाई, 1859 के मेमो० में ट्रेवीलियन ने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश बजट प्रणाली भारतीय वित्त संगठन में अपनाई जानी चाहिए; ब्रिटिश वित्त विभाग में अपने लंबे अनुभव के कारण ट्रेवीलियन भी विल्सन की भांति वहां की वित्त प्रणाली से परिचित था ।
92. वित्त कार्यविवरण, 4 मई, 1860, संख्या 13 । वित्त विभाग में भारत सरकार का प्रस्ताव, 7 अप्रैल 1860 ।
93. वही ।
94. वही, वित्त कार्यविवरण, 4 मई, 1860, संख्या 14, अकाउंटेंट जनरल से वित्त विभाग के सचिव के नाम स्मरण पत्र ।
95. वित्त कार्यविवरण, 11 मई, 1860; संख्या 26 । भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 11 मई, 1860 ।
96. वित्त कार्यविवरण, 18 अगस्त, 1860, संख्या 93 (ए) । बजट समिति की रिपोर्टें 30 जुलाई, 1860 ।

97. पूर्वोक्त स्थल ।
98. वही । वित्त विभाग में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 18 अगस्त, 1860 । संपूर्ण भारत में लेखा परीक्षक प्रारंभिक विस्तृत लेखा परीक्षण और ऑडिटर जनरल अंतिम विनियोग लेखा परीक्षण करेंगे, स्थानीय लेखाकारों पर लेखाओं के मिलान और समायोजन का उत्तरदायित्व होने के साथ-साथ ऑडिटर जनरल को अंतिम लेखा परीक्षण के लिए विविध विवरण भेजने की जिम्मेदारी होगी । सिविल लेखा परीक्षक अपनी अपनी स्थानीय सरकारों के वेतनाधिकारी (पे मास्टर) भी होंगे और विभिन्न राजकोषों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन के हस्तांतरण का नियमन करेंगे । प्रत्येक वेतनाधिकारी वित्त विभाग के प्रति और प्रत्येक सवितरक अधिकारी अपना विभाग वेतन अधिकारी के प्रति उत्तरदाई होता था ।
99. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 140, 14 सितंबर, 1860 ।
100. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 208, अक्टूबर, 1860; भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त 52, 8 अप्रैल, 1861 ।
101. वित्त कार्यविवरण, 14 नवंबर 1860 । बजट समिति की रिपोर्टें (छठी), 27 अक्टूबर, 1860 । वित्त विभाग में भारत सरकार का प्रस्ताव, 15 नवंबर, 1860 । यद्यपि भारतीय लेखाओं के लिए प्राक्कसन फार्मों में परिवर्तन किए गए, तथापि भारत मंत्री के विरोध का कारण लेखे जिस रूप में पेश किए जाते थे, उसमें अधिक परिवर्तन नहीं किए जा सके । भारत मंत्री व्ययों के वर्गीकरण को यथासंभव पुराने ही रूप में बनाए रखना चाहता था जिससे कि पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना हो सके । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 171, 25 सितंबर, 1861 । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 68, 8 मई, 1862 और वित्त सख्या 31, 25 फरवरी, 1863 । गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल के लिए भारत मंत्री के पास लेखा भेजना आवश्यक था । 1860 से इस लेखा के अलावा सपरिषद गवर्नर जनरल भारत मंत्री के पास नियमित रूप से अपने प्रेषण में उन उपकरणों को स्पष्ट करता था जिनकी वजह से राजस्व और व्यय की अनुमति और वास्तविक राशियों में अंतर होता था । यह समद के सामने पेश किए जाने वाले लेखा सबधी विवरणों की भांति प्रकाशित नहीं किया जाता था । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 80, 4 अप्रैल, 1860 ।
102. एक विचारधारा के अनुसार यह सुविधाजनक था क्योंकि अप्रैल के अंत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आते ही नौ परिवहन का मौसम समाप्त हो जाता था ।
103. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 223, 27 सितंबर, 1870 ।
104. वही, 89, 19 अप्रैल, 1866 ।
105. वही, 154, 25 जून, 1868; भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 413, 14 जून, 1869, भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 87, 29 मार्च, 1870 ।
106. आरगाइल जब वित्तीय वर्ष को 'प्राकृतिक वर्ष' के अनुरूप बनाने की बात करता है तो सभवतः वह फसल काटने के समय के आधार पर निर्धारित होने वाले वर्ष की ओर संकेत करता है । आरगाइल से मेयो को, 9 अगस्त, 1870, मेयो कागजात, बंडल 48, संख्या 23 ।
107. वित्त कार्यविवरण जून, 1865 । लेखा शाखा सख्या 83 । वित्त विभाग, भारत सरकार से

आडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल आफ इंडिया तथा स्थानीय लेखाकारों के नाम पर पत्र, 9 जून, 1865 ।

108. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1869 । लेखा शाखा सख्या 14, ई० एच० लॉगिंग्टन, सचिव, वित्त विभाग से सभी अधीनस्थ सरकारों के महालेखाकारों को, 21 अक्टूबर, 1869 । यदि भारत सरकार को किसी स्थानीय सरकार के बजट प्राक्कलन, जिस वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाना होता था, उससे पिछले वर्ष की 1 जनवरी तक प्राप्त नहीं होने थे तो भारत सरकार का वित्त विभाग स्वयं उस स्थानीय सरकार के बजट प्राक्कलन तैयार करता था ।
109. स्थानीय महालेखाकार बजट आबटन से विचलन को रोकते थे और इसके विषय में उच्चतम सरकार को सूचना देते थे । वित्त कार्यविवरण, मई, 1869, लेखा शाखा, सख्या 55 । सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार से महालेखाकार को, 25 मई, 1869 ।
110. वित्त कार्यविवरण, मई, 1869, पूयक राजस्व सख्या 34, गवर्नर-जनरल आफ इंडिया से सभी स्थानीय सरकारों के प्रधानों को, 13 मई, 1869 ।
111. वित्त कार्यविवरण, मई, 1863, सख्या 15 । सचिव, वित्त विभाग से भारत सरकार के आडिटर जनरल को, 6 मई, 1863 ।
112. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल 1868, लेखा शाखा 26, कंप्यूटर जनरल आफ अकाउंट्स द्वारा पत्र, 25 मार्च, 1867 ।
113. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1863. प्रकीर्ण सख्या : सी० ई० टूंबीलियन द्वारा मेमो०, 11 फरवरी, 1863, भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त सख्या 32, 4 मार्च, 1863 । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 131, 25 जुलाई, 1863 ।
114. वित्त कार्यविवरण, मई, 1865, लेखा शाखा सख्या 113, वित्त विभाग में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 20 सितंबर, 1865 । वित्त कार्यविवरण, जून, 1865 । ध्वज सख्या 246 । एम० एच० फास्टर से सचिव, वित्त विभाग को, 27 मई, 1865 । 1866 में रेल विभाग में लेखा परीक्षण की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई । बंगाल, बर्मी तथा मद्रास में रेल विभाग के लेखा परीक्षण के लिए तीन रायल इंजीनियर अफसर तथा कुछ मातहत कर्मचारी नियुक्त किए गए । अंतिम लेखा परीक्षण केंद्रिय लोक निर्माण एवं वित्त विभाग द्वारा किया जाता था । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 215, 28 सितंबर, 1866 । रेल विभाग के लेख के संवध में विनियोजन लेखा परीक्षण का प्रारंभ 1867 में हुआ था । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 9, 8 जनवरी 1867 । मेयो को रेल विभाग में लेखा परीक्षण का सुधार करने की दिशा में अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली । भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त सख्या 75, 29 अप्रैल, 1871 ।
115. मेयो से वार्टल फॉर को, 6 दिसंबर, 1869, मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 345 ।
116. 3 व 4 वित्त IV, कैप 85, अनुच्छेद 59 ।
117. 1804 का विनियम, अनुच्छेद 23 ।
118. जे० विल्सन से डब्ल्यू० वेजहाट को, 19 जुलाई, 1860 । बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत, II, पृ० 303 ।
119. वित्त कार्यविवरण, 8 मई, 1861, सख्या 7; 23 जुलाई, 1861, सख्या 158, गृह कार्य-विवरण, 30, 1862, सार्वजनिक (बी) सख्या 211-13 ।

120. 24 व 25 वित्त० बंग० 67 अनुच्छेद 42 ।
121. 'वे.इ.आफ.इ.डिया' 2 मई, 1861 ।
122. वित्त कार्यविवरण, दिसंबर, 1860, पृ० 3089, गर गो० ई० ट्रिबोनियन द्वारा मेमो०, 13 जुलाई, 1859 ।
123. वित्त कार्यविवरण, दिसंबर, 1860, मेमो० आया सध्या, गर गो० ई० ट्रिबोनियन का मेमो०, 12 मई, 1860 ।
124. पूर्वोक्त स्थल ।
125. वैनिस मे जे० विमान को, 23 अगस्त, 1860, बैरिंगटन, पूर्वोक्त, जिल्द II, पृ० 263 ।
126. वैनिस मे जे० विमान को, 24 जुलाई, 1860, बैरिंगटन, पूर्वोक्त, जिल्द II, पृ० 301 ।
127. भारत मंत्री मे भारत सरकार को, वित्त सध्या 74, 10 मई, 1860 ।
128. वित्त कार्यविवरण, 16 मार्च, 1861, मेमो० आया सध्या 198-204 ।
129. वित्त कार्यविवरण, 16 मार्च, 1861, मेमो० आया सध्या 197, गो० एच० सॉमिंगटन, सचिव वित्त विभाग, भारत सरकार मे सचिव, बंगाल सरकार को, 16 मार्च, 1861 ।
130. पी० एन० बनर्जी, 'प्राविशियन पाइनेम इन इंडिया', (सं०, 1929) पृ० 23-27 । इस पुस्तक में जे० एन० टिन्ने द्वारा एंग्लिश प्रयोगों, 'हिस्ट्री आफ प्राविशियन अरेंजमेंट्स', (बंगलूरु, 1887) मे उद्धरण दिए गए हैं ।
131. वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1867, मेमो० आया सध्या 22 । इन्फ्यू० एन० मैगी से गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और चीफ कमिश्नरों को 21 फरवरी, 1866 ।
132. वही मेमो० आया सध्या 22, गो० सीडन से इन्फ्यू० एन० मैगी को, 8 मार्च, 1867 ।
133. वही सी० फेर, बंबई का गवर्नर, मेमो० दिनांक 15 नवंबर, 1866 ।
134. वही ई० डुमरे, पश्चिमीतर प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन्फ्यू० एन० मैगी को 8 मार्च, 1866 । इन्फ्यू० टी० डेनिसन, मद्रास का गवर्नर, का मेमो० 23 मार्च, 1866 ।
135. भारत सरकार मे भारत मंत्री को, वित्त सध्या 209, 19 मिनवर, 1867 ।
136. इन्फ्यू० एन० मैगी से जान सार्रेम को, 10 फरवरी, 1866, टीक वही, 12 फरवरी, 1866 । सार्रेम कागजात, परिपद के सदस्यों से पत्र, जिल्द 2, 1866, सध्या 8 और 8 (ए) ।
137. वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1867, मेमो० आया सध्या 23, कर्नेल आर० स्ट्रैची का नोट, 17 अगस्त, 1867 ।
138. इस प्रकार के मतभेदों का एक उदाहरण बंबई के गवर्नर सी० फेर और गवर्नर जनरल की परिपद के सदस्य सी० ट्रिबोनियन के बीच बंबई मे लोक निर्माण से संबंधित व्यय पर भागड़ा था । उस समय भारत मंत्री सी० वुड ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'मेरा विचार है कि भारत सरकार का वित्त पर कठोर 'सामान्य' नियंत्रण होना चाहिए' परंतु उसे हर कहीं छोटे-छोटे कार्यों में अपने आपको नहीं उपजा सेना चाहिए । सी० वुड से जे० सार्रेम को, 17 अक्तूबर, 1864 । सार्रेम कागजात, भारत मंत्री मे पत्र, जिल्द 1, सध्या 56 । तथापि तत्कालीन कानूनी प्रतिबंधों के होने हुए उच्चतम सरकार का निरंतर हस्तक्षेप आवश्यक था ।
139. गृह कार्यविवरण, दिसंबर, 1867 मार्चजर्नल सध्या 62, कर्नेल सी० एच० डिकिंस, सचिव, लोक निर्माण विभाग का नोट, 21, नवंबर, 1867 । नियमानुसार स्थानीय सरकार को व्यय



की छाटी ॥ छोटी मद के लिए सपरिपद गवर्नर जनरल की पूर्वं अनुमति लेनी होती थी। ये नियम बजट और लेखा परीक्षण को नई प्रणाली लागू करने से पहले बनाए गए थे और नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक थे, परंतु कालांतर में वे कटक बन गए।

140. वित्त कार्यविवरण, अक्टूबर, 1867, लेखा शाखा 23, कर्नेल आर० स्ट्रेंची का नोट, 17 अगस्त, 1867।
141. राजस्व से प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किया जाने वाला भाग था, मालगुजारी का सोलहवा हिस्सा, आय कर से प्राप्त का चौथा हिस्सा, और साइसेंस कर का चौथा हिस्सा। स्ट्रेंची योजना के अनुसार स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित खर्चों की राशि 76 लाख पौंड और हस्तांतरित राजस्व की राशि 88 लाख पौंड थी। इस प्रकार स्थानीय लोक निर्माण कार्यों के लिए लगभग 12 लाख पौंड बच रहते थे।
142. वित्त कार्यविवरण, अक्टूबर, 1867, लेखा शाखा सध्या 26, डब्ल्यू० एन० मैसी द्वारा मेमो० 17 अगस्त, 1867।
143. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1868, लेखा शाखा सध्या 36। चीफ कमिशनर मध्य प्रांत के सचिव से भारत सरकार के वित्त विभाग के सचिव को, 22 अक्टूबर, 1867। वही सध्या 39, पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यवृत्त 'भारत सरकार को संप्रेषित दिनांक 21 नवंबर, 1867। 'वही' सध्या 40, 44 व 45। ब्रिटिश इर्षा, अवध और पंजाब की सरकारों ॥ पत्र। अधिकांश स्थानीय सरकारों का विचार था कि योजना ठीक थी, परंतु अधिक आगे नहीं जाती थी।
144. वित्त कार्यविवरण, अक्टूबर, 1867, लेखा शाखा सध्या 74, एच० एम० ड्यूरेंड 7 अक्टूबर, 1867।
145. पूर्वोक्त स्थल।
146. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1868, लेखा शाखा सध्या 48, फोर्ड सेंट जार्ज के अध्यक्ष का मेमो०, 15 फरवरी, 1868।
147. पूर्वोक्त स्थल।
148. वित्त कार्यविवरण, अक्टूबर, 1867, लेखा शाखा सध्या 73, गवर्नर जनरल द्वारा मेमो० 27 सितंबर, 1867।
149. वित्त कार्यविवरण, अक्टूबर, लेखा शाखा सध्या 73, गवर्नर जनरल द्वारा मेमो०, 27 सितंबर, 1867।
150. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1868, लेखा शाखा सध्या 48, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सचिव ॥ फोर्ड सेंट जार्ज की सरकार के मुख्य सचिव को, 27 जनवरी, 1868।
151. मेयो से एस० पिट्ज़ेरेल्ड को, 20 अगस्त, 1870, मेयो कागजात, बंडल 40, सध्या 239।
152. मेयो से डब्ल्यू० आर्बुथनोट को, 15 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बंडल 42, सध्या 68।
153. वही, 13 सितंबर, 1868, मेयो कागजात, बंडल 33, सध्या 6।
154. मेयो से आरगाहल को, 31 जनवरी, 1869, मेयो कागजात, बंडल 34, सध्या 23।
155. मेयो से बी० फेर को, 6 फरवरी, 1869, मेयो कागजात, बंडल 37, सध्या 345।
156. मेयो से सर एम० पिट्ज़ेरेल्ड को, 1॥ नवंबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 37, सध्या 313।

157. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, लेखा शाखा सख्या 22, गवर्नर जनरल का मेमो०, 23 जून, 1870 ।
158. मेयो से लार्डर नेपियर आफ मॉकिस्टन को, 13 मार्च, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 74 ।
159. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, लेखा शाखा सख्या 22, गवर्नर जनरल का मेमो०, 23 जून, 1870 ।
160. मेयो से एच० फिट्जरेल्ड को, 5 जनवरी, 1870 को, मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 10 ।
161. मेमो मे एच० ड्यूरेड को, 29 अप्रैल, 1870, मेयो कागजात, बडल 39, सख्या 107 ।
162. पूर्वोक्त स्थल ।
163. मेयो से सर डब्ल्यू० म्योर को, 2 सितंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 40, सख्या 255 ।
164. पूर्वोक्त स्थल ।
165. मेयो से आरगाइल को, 10 अप्रैल, 1871, मेयो कागजात, बडल 43, सख्या 91 ।
166. टैपिल ने मुझाव दिया था (7 नवंबर, 1868 का कार्यवृत्त) कि मद्रास और बंबई की सरकारों को साम्राज्यिक खर्चों के प्रति अशदान को बचाकर इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाकी राजस्व और धन्यो के सवध में स्वतंत्रता दी जा सकती है । प्रतिष्ठानों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण शिथिल किया जाना था, परंतु ऊंचे वेतनों और सामान्य वेतनमानों के सवध में 'नियंत्रण' रहना था । वास्तव में योजना का उद्देश्य यही था कि प्रेसीडेसी सरकारों को राजस्व का छठा भाग दिया जाय (भारत सरकार के सामान्य नियंत्रण के साथ) और कुल राजस्व के छः समान हिस्सों में से पांच पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहे ।
167. मेयो से आरगाइल को, 1 फरवरी, 1869, मेयो कागजात, बडल 34, सख्या 24 ।
168. वही, 19 अगस्त, 1870, मेयो कागजात, बडल 40, सख्या 237 ।
169. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, लेखा शाखा सख्या 22, गवर्नर जनरल का मेमो० (23 जून, 1870) । वही, सख्या 25 और धागे । आर० चैपमैन, सचिव, वित्त विभाग से स्थानीय सरकारों को पत्र, 17 अगस्त, 1870 । वही, सख्या 48, गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा प्रस्ताव, 14 दिसंबर, 1870 । वही, सख्या 49, भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 265, 14 दिसंबर, 1870 । योजना तैयार करने में टैपिल और जान स्ट्रैची (रिचर्ड स्ट्रैची का भाई) की भूमिकाएं महत्वपूर्ण थीं । वही सख्या 20, टैपिल का मेमो०, 23 जून, 1870; वही सख्या 21, जे० स्ट्रैची का मेमो०, 15 जुलाई, 1870 ।
170. प्रारंभ में मेयो ने मुझाव दिया था (मेमो०, 23 जून, 1870) कि हस्तातरिक विभागों का खर्च पूरा करने के लिए उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व प्रांतीय सरकारों को हस्तातरिक कर दिया जाना चाहिए, परंतु बाद में यह विचार छोड़ दिया गया । 1871-72 के बाद प्रांतीय सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट से एक मुश्न दिया जाने वाला अनुदान 46,88,711 पौंड था । प्रांतीय सरकारों में इनका विभाजन इस प्रकार था : बंगाल, 11,68,592 पौंड; बंबई, 8,80,075 पौंड; मद्रास, 7,39,488 पौंड; पंजाब, 5,16,221 पौंड; पश्चिमोत्तर प्रांत, 6,40,792 पौंड; बर्मा, 2,75,332 पौंड; मध्य प्रांत, 2,61,263 पौंड; अवध, 2,06,948 पौंड । विभिन्न प्रांतों में पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1870-71 में इन्हीं सेवाओं पर व्यय के आधार पर

आवटन का अनुपात निर्धारित हुआ था। 1871-72 में इन सेवाओं के लिए कुल आवटन पिछले वर्ष में व्यय की तुलना में कम था। इस प्रकार साम्प्रदायिक राजस्व में 3,30,800 पौंड की बचत कर ली गई थी। वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, लेखा शाखा संख्या 48, भारत सरकार का प्रस्ताव, 14 दिसंबर, 1871।

171. मद्रास, बंबई और पश्चिमोत्तर प्रांत की सरकारों ने अधिक धनराशि के आवटन की आवश्यकता और भविष्य में बढ़ने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व कुछ निरंतर बढ़ती आय देने वाले स्रोतों के हस्तांतरण की माछनीयता के संबंध में आग्रह किया। वित्त कार्यविवरण जनवरी, 1871, लेखा शाखा संख्या 37, मचिव, फोर्ट सेंट जार्ज सरकार से सचिव, वित्त विभाग को. 27 मितंबर, 1870; वही, संख्या 40, बंबई के गवर्नर का मेमो, 1 अक्टूबर, 1870, वही, संख्या 33, सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार से सचिव, वित्त विभाग को 15 मितंबर, 1870। वही, संख्या 43, पंजाब के सेप्टिमेंट गवर्नर के मेमो०, 22 नवंबर, 1870 और 10 जून, 1870। फिर भी कुल मिलाकर योजना का प्रांतीय सरकारों ने हादिक स्वागत किया।
172. मेयो से नेपियर आफ मॉकस्टन को 4 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडल 42, संख्या 7।
173. आरगाइल से मेयो को, 3 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बडल 49, संख्या 5।
174. चूकि हमारा विषय प्रांतीय वित्त अध्ययन नहीं है इसलिए हमारे लिए स्थानीय करो के इतिहास में जाना आवश्यक नहीं है। चुगी शुल्क (मेयो से जे० स्ट्रैची को 20 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, संख्या 321) और गृह कर (देखें 'इंडियन इकॉनामिस्ट', 21 मितंबर, 1871) बंबई में अनोक्षप्रिय थे। 'टाइम्स आफ इंडिया' संपादक के नाम जे० एन० मिल का पत्र, 'इंडियन इकॉनामिस्ट' 21) अक्टूबर 1871, पृ० 63 में उद्धृत) बहुत दिलचस्प है, मिल का विचार था कि जहां गृह कर पूर्ण रूप से न्यायोचित था, वहां जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं पर चुगी शुल्क आपसितजनक था, 'यै यह तो नहीं कहता कि भारत जैसे देश में जहां उन करो को लगा पाना कठिन है जिनके लोग आदी नहीं हैं, वित्तीय आवश्यकता के मध्य भी इन्हें न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, परंतु मेरा यह निश्चित मत है कि यह परम सफ़ट की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। मासगुजारी पर शिक्षा और सड़क उपकर (सेम) को राजस्व के स्पाई बंदोबस्त की व्यवस्था का उत्लपन माना गया था (सड़क उपकर विधेयक के विषय में देखें, 'हिंदू पेडिअट', 5 जून, 12 जून और 19 जून, 1871, शिक्षा तथा सड़क उपकर लगाकर जमींदारों पर किए जाने वाले अन्याय के लिए देखें, वही, 23 जनवरी, 1871। 6 फरवरी, 1871, 10 जुलाई, 1871)। सरकारी मत के अनुसार सड़क उपकर के रूप में जमींदारों पर वही भार डाला गया था जिससे वे 1793 से बचते आ रहे थे। (देखें सर जी० कंफर्वेल, 'मेमोरीज आफ मार्टिन डेविडन कैरियर' लंदन 1893, जिल्द II, पृ० 210)। पश्चिमोत्तर प्रांत के विषय में देखें, वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, संख्या 47, एन० डब्ल्यू० पी० की स्थानीय कराधान समिति की रिपोर्ट, 12 नवंबर, 1870।
175. मेयो से नेपियर को, 4 जनवरी, 1871, मेयो कागजात, बडल 42, संख्या 7।
176. डब्ल्यू० एस० मेयर, 'मेमोरेण्डम आन दि फाइनेंसियल पावर्स आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया एंड प्राविशियल गवर्नमेंट्स, फार दि रायल कमीशन आन डिमेंट्रसाइजेशन' (थिम्पन, 1907),



आवटन का अनुपात निर्धारित हुआ था। 1871-72 में इन सेवाओं के लिए कुल आवंटन पिछले वर्ष में व्यय की तुलना में कम था। इस प्रकार साम्राज्यिक राजस्व में 3,30,800 पौंड की कमी हुई थी। वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, सेवा शाखा सख्या 48, भारत सरकार का प्रस्ताव, 14 दिसंबर, 1871।

171. मद्रास, बर्मा और पश्चिमोत्तर प्रांत की सरकारों ने अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता और भविष्य में बढ़ने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व कुछ निरंतर बढ़ती आय देने वाले स्रोतों के हस्तांतरण की वाछनीयता के संबंध में आप्रह किया। वित्त कार्यविवरण जनवरी, 1871, सेवा शाखा सख्या 37, सचिव, फोर्ट सेंट जार्ज सरकार से सचिव, वित्त विभाग को, 27 सितंबर, 1870; वही, सख्या 40, बर्मा के गवर्नर का मेमो, 1 अक्टूबर, 1870, वही, सख्या 33, सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार से सचिव, वित्त विभाग को 15 सितंबर, 1870। वही, सख्या 43, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मेमो०, 22 नवंबर, 1870 और 10 जून, 1870। फिर भी कुल मिलाकर योजना का प्रांतीय सरकारों ने हार्दिक स्वागत किया।
172. मेयो से नेपियर आफ मॉकिस्टन को 4 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 7।
173. आरगाइल से मेयो को, 3 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 5।
174. चूंकि हमारा विषय प्रांतीय वित्त अध्ययन नहीं है इसलिए हमारे लिए स्थानीय करो के इतिहास में जाना आवश्यक नहीं है। चुग्री शुल्क (मेयो से जे० स्ट्रैची को 20 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, सख्या 321) और गृह कर (देखें 'इंडियन इकानामिस्ट', 21 सितंबर, 1871) बर्मा में अलोकप्रिय थे। 'टाइम्स आफ इंडिया' संपादक के नाम जे० एम० मिल का पत्र, 'इंडियन इकानामिस्ट' 21 अक्टूबर 1871, पृ० 63 में उद्धृत) बहुत श्लिष्ट है; मिल का विचार था कि जहां गृह कर पूर्ण रूप से ग्यायोचित था, वहां जनमाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर चुगी शुल्क आपत्तिजनक था, 'यै यह तो नहीं कहता कि भारत जैसे देश में जहां उन करो को लगा पाना कठिन है जिनके लोग आदी नहीं हैं, वित्तीय आवश्यकता के समय भी इन्हें ग्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, परंतु मेरा यह निश्चित मत है कि यह परम सख्त की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। भातयुजारी पर शिक्षा और सड़क उपकरण (सेम) को राजस्व के स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था का उत्सर्जन माना गया था (सड़क उपकरण विधेयक के विषय में देखें, 'हिंदू पेट्रिअट', 5 जून, 12 जून और 19 जून, 1871, शिक्षा तथा सड़क उपकरण लगाकर जमींदारों पर किए जाने वाले अभ्यास के लिए देखें, वही, 23 जनवरी, 1871। 6 फरवरी, 1871, 10 जुलाई, 1871)। सरकारी मत के अनुसार सड़क उपकरण के रूप में जमींदारों पर वही भार डाला गया था जिससे वे 1793 से बचने में रहे थे। (देखें सर जी० कैंपबेल, 'मेमोरीज आफ मार्ड इंडियन कैरियर' लंदन 1893, जिल्द II, पृ० 210)। पश्चिमोत्तर प्रांत के विषय में देखें, वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1871, सख्या 47, एन० डब्ल्यू० पी० की स्थानीय कराधान समिति की रिपोर्ट, 12 नवंबर, 1870।
175. मेयो से नेपियर को, 4 जनवरी, 1871, मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 7।
176. डब्ल्यू० एम० मेयर, 'मेमोरेण्डम आन दि फाइनेंशियल पावरम् आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया एंड प्राइमरियल गवर्नमेंट्स, फॉर दि रायल कमीशन आन डिमेंट्रलाइजेशन' (शिमला, 1907),



## व्यय की प्रवृत्तियाँ

व्यय की मर्दों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मद सेना थी जिस पर उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में भारत सरकार के कुल व्यय का लगभग एक तिहाई होता था। सैन्य विद्रोह के बाद दो वर्षों में भारत में सेना में भारी वृद्धि हुई और सेना पर व्यय में भी समानुपातिक वृद्धि हुई। सातवें दशक में प्रतिरक्षा व्यय में कटौती और घटौती के कुछ छिटपुट प्रयत्न किए गए, परंतु सैन्य विद्रोह के अनुभव से (शासकों को) ऐसा मानसिक आघात पहुंचा था कि नौकरशाही के भीतर से ही सेना में छंटनी के विचार का कडा विरोध हुआ। लोक निर्माण कार्यों पर होनेवाला व्यय (कुल व्यय का लगभग 15 प्रतिशत) अंशतः साधारण निर्माण कार्यों पर होता था जो वर्ष में होने वाली आय से पूरा किया जाता था और अंशतः असाधारण निर्माण कार्यों पर होता था जिसके लिए वित्त की व्यवस्था ऋणों से की जाती थी।<sup>1</sup> सिविल प्रशासन के खर्च बजट में विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत शीर्षक थे। सर्वप्रथम, बजट तथा लेखों में सामान्य प्रशासन नामक शीर्षक व्यय रहता था जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी एवं विधान परिषद के सदस्यों, गवर्नरो, लेफ्टिनेंट गवर्नरो तथा चीफ कमिश्नरो, भारत सरकार के सचिवों, लेखा, व लेखा परीक्षण तथा करेंसी आदि विभागों के अधिकारियों के वेतन आते थे। इस शीर्षक पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 2 से 4 प्रतिशत तक होता था। द्वितीय में न्याय प्रशासन का व्यय था जिसमें न्यायालयों अथवा न्याय विभाग, जेल इत्यादि पर होने वाला खर्च मम्मिलित होता था। इसे विधि एवं न्याय नामक शीर्षक में दिखाया जाता था (कुल व्यय का लगभग 5 प्रतिशत)। तृतीय में सभी राजस्व संग्रह के माध्यमों जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा वन संरक्षण विभाग, बगाल तथा मालवा की अफीम एजेंसियां, नमक शुल्क लगाने के लिए अतर्देशीय सीमा शुल्क कर्मचारी, दस्तावेजों के पंजीकरण तथा स्टाम्प की बिक्री के लिए कर्मचारी, आय कर निर्धारण तथा संग्रह के लिए समय-समय पर भर्ती किए जाने वाले कर्मचारीगण पर होने वाले स्थापन खर्च आते थे जिन्हें एक में समूहबद्ध कर राजस्व संग्रह पर व्यय नामक शीर्षक में दिखाया जाता था।<sup>2</sup> इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय में काफी कमीवशी होती रहती थी, परंतु सामान्यतः यह कुल व्यय का 17 से 20 प्रतिशत तक रहता था। नागरिक प्रशासन संबंधी इन व्ययों के अलावा सेवा नियुक्ति तथा अनुकंपा भत्तों (जो सरकार के यूरोपीय तथा भारतीय कर्मचारियों को दिए जाते थे) और अवकाश भत्तों तथा अनुपस्थिति भत्तों पर जो (भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को दिए जाते थे) छठे दशक के एक सामान्य वर्ष में कुल व्यय का एक तिहाई में भी अधिक

व्यय होता था।<sup>3</sup> व्यय की अन्य मदों में एक महत्वपूर्ण मद था राजनीतिक एजेंसियाँ। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के व्यय आते थे जैसे देगी रियायतों में राजनीतिक एजेंसियों तथा रेजिडेंसियों के अनुरक्षण पर व्यय, सीमांत प्रदेशों में सेना रखने का व्यय, फारस तथा काबुल में वाणिज्यिक दूतावास पर खर्च, अदन में मैनिक अड्डा रखने की लागत (जिसमें ब्रिटिश सरकार भी हाथ बटाती थी), सीमांत प्रदेशों में जनजातियों के सरदारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता या गिश्त, आदि। व्याज प्रभार के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के दोषर धारकों को या जाने वाला लाभांश सम्मिलित कर लेने पर इस मद का प्रभार कुल व्यय का लगभग 10 प्रतिशत होता था। उन्नीसवीं शताब्दी में मौकर-शाही की विनिष्ट गद्दावली में गृह खर्च (होम चार्जेज) का अर्थ वास्तव में विदेशी खर्च अर्थात् इंग्लैंड में स्टैलिंग में किए जाने वाले खर्च से होता था। इस मद के अंतर्गत इंग्लैंड में लिए गए ऋणों पर व्याज, भारत के लिए स्टोर का व्यय, भारत स्थिति ब्रिटिश सेना की सेवाओं के लिए गृह खर्च, सेना के भारन, आने और इंग्लैंड वापस लौटने पर परिजहन व्यय, सेना के अधिकारियों की पेंशन तथा वापसी प्रभार और गारटी जुदा रेल कंपनियों को दिए जाने वाले व्याज आते थे। जब हम उत्तर गंग्ग विद्रोह काल में नीति मंथनी मामलों पर विचार करते हैं तो स्थिति के स्वरूप के बारे में इन मोटे-मोटे तथ्यों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा।

## I

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में सेना पर खर्चों का कुल व्यय के साथ औसत अनुपात 30 से 35 प्रतिशत तक था। अतः व्यय की मदों में सबसे बड़ी मद सेना थी। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी योजना में भारतीय सेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सेना पर व्यय संबंधी नीति केवल भारत की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित नहीं की गई थी। क्या प्रतिरक्षा पर भारी व्यय उचित था? क्या भारत सरकार की ब्रिटिश सरकार के साथ सेना संबंधी व्यवस्था भारत के राजस्व तथा संपत्ति को यहाँ से ले जाने का माध्यम थी? हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

सैन्य विद्रोह से स्वभावतः सेना पर भारत सरकार के व्यय में भारी वृद्धि हो गई। यह व्यय 11.49 करोड़ रुपये (1856-57) से बढ़ कर 15.57 करोड़ रुपये (1857-58) हो गया। वृद्धि की यह प्रवृत्ति 1858-59 (21 करोड़ रुपये) तथा 1859-60 (29.9 करोड़ रुपये) में जारी रही। एक बार जब सेना तथा पुलिस में स्थानीय भर्तों तथा सैन्य दलों को इंग्लैंड से भारत भेजने का कार्य शुरू हो गया तो उसे अकस्मात् रोक पाना सम्भव नहीं रहा।<sup>4</sup> भारत आने वाले सैनिकों की कुल संख्या 1859-60 में सर्वाधिक रही। 1857 में यूरोपीय सेना का भारतीय सेना के साथ अनुपात 1 : 6 था जो 1858-60 में बढ़कर लगभग 1 : 2 हो गया। ब्रिटेन में भारतीय सेना संबंधी खर्च (मिलिटरी होम चार्जेज) 3,40,000 पौंड 1856-57 से बढ़कर 18 लाख 20 हजार पौंड (1860-61) हो गया। सैन्य विद्रोह के बाद नीति के तौर पर सेना में यूरोपीय नस्ल के सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। गोलदाज फौज में जहाँ पहले मुख्य रूप से हिंदुस्तानी ही हुआ



करते थे वहा अब इसमें केवल यूरोपीय नस्ल के सैनिकों को ही रखा गया। सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही हिंदुस्तानी सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों पर अधिक खर्च होने के कारण प्रति सैनिक व्यय की दर में बहुत भारी वृद्धि होने लगी। 1859 में भारत मंत्री ने गवर्नर जनरल से सेना संबंधी व्यय पर सतर्कतापूर्वक ध्यान रखने का आग्रह किया, साथ ही सेना व्यवस्था तथा सैन्य भंडारों की आपूर्ति में कृपणता न करने के लिए भी कहा।<sup>5</sup> उसने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रणाली जारी रखने की नीति काफ़ी असंतोषजनक है।<sup>6</sup> सपरिपद गवर्नर जनरल ने वादा किया कि मौजूदा भारी युद्ध व्यय में जैसे ही और जिस निरापद सीमा तक कमी कर सकना संभव हुआ<sup>7</sup> वहाँ तक इसमें कटौती कर दी जाएगी। परंतु उसी समय कटौती करना असंभव था।<sup>8</sup> भारत मंत्री का विचार था कि चूंकि शांति पुनः स्थापित हो गई है, अतः हिंदुस्तानी सैन्य टुकड़ियों को समाप्त किया जा सकता है।<sup>9</sup> उसने यह भी सुझाव दिया कि हाल में भर्ती हुए पुर्तिस दल को वे कार्य सौंपे जा सकते हैं जो पहले हिंदुस्तानी सैन्य टुकड़ियों के पास थे और उनकी सख्या में तेजी के साथ कमी की जानी चाहिए।<sup>10</sup> इसके साथ-साथ उसने यह भी सुझाव दिया कि बैरको में पड़े कुछ अन्य रेजिमेंट यथाशीघ्र ब्रिटेन लौटा दिए जाने चाहिए।<sup>11</sup> भारत मंत्री भारत में पुनः वित्तीय संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से खर्चों में कमी करने के लिए उत्सुक था। उसने भारत सरकार को लिखा, जिस असाधारण मंकट से आप (भारत सरकार) अभी हाल में गुजर चुके हैं उसके लिए प्रत्येक छूट दी जानी चाहिए, और इस देश (भारत) को वित्त की आपूर्ति का निश्चित स्रोत ममज्ञ कर इसकी ओर देखने की मनोवृत्ति को काफ़ी जोरदार ढंग से नापसंद भी नहीं किया जा सकता।<sup>12</sup>

भारत मंत्री के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सैन्य व्यय में कमी प्रारंभ हुई। सैन्य वित्त आयोग ने जिसका अध्यक्ष कर्नल बालफोर था, 1859 में सेना पर व्यय में काटछाट प्रारंभ की। सैन्य भंडारों पर व्यय में कमी के लिए उसके द्वारा की गई, सिफारिशों से सेना रसद विभाग के खर्चों में कमी आई।<sup>13</sup> द्वितीय, हिंदुस्तानी फौज की संख्या 2,13,000 (1859-60) से घटाकर 1,84,000 (1860-61) कर दी गई।<sup>14</sup> भारत मंत्री ने हिंदुस्तानी सेना में कमी करने के लिए आग्रह किया। उसने लिखा हिंदुस्तानी सेना में कमी करके ही बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिकों के लिए साधनों की व्यवस्था हो सकेगी।<sup>15</sup> अतः हिंदुस्तानी मिपाहियों की संख्या में भारी कमी की गई और 1862-63 में उनकी संख्या 1,21,000 रह गई। यह स्वीकार किया गया कि भारत में यूरोपीय सैनिकों को सैन्य विद्रोह से पहले के उनके परंपरागत अनुपात से अधिक अनुपात में रखना एक राजनीतिक आवश्यकता थी, तथापि भारत मंत्री की इच्छा थी कि उनकी संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी हमारे उपनिवेशों की पूर्ण सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।<sup>16</sup> सर मी० वुड थमस ने कटौती की प्रगति से गतुष्ट नहीं था।<sup>17</sup> वास्तव में भारत सरकार ने व्यावहारिक कटौती की अपेक्षा अधिक की आशा दिलाई थी, परंतु धन में कटौती की प्रक्रिया धीमी रही।<sup>18</sup> इसके अलावा सेना संबंधी लेन की अव्यवस्था के कारण अनेक व्यय के खर्च अग्रकट बने रहे।<sup>19</sup> तथापि 1862-63 तक

यूरोपीय सैनिकों की संख्या घटाकर 76,000 कर दी गई। तात्पर्य यह कि पांच वर्षों (1858-59 से 1862-63 तक) में इनकी संख्या में लगभग 13 000 की कमी हुई।

कटौती के विविध उपायों से सेना पर व्यय, जो सैन्य विद्रोह के समय असाधारण रूप से बढ़ गया था, कम हो गया। 1858-60 में सेना पर व्यय 20.9 करोड़ रुपए था। 1863-64 तक यह घटाकर 14.5 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसका श्रेय सर सी० वुड और सैन्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कर्नल वालफोर को था जिसने बिना किसी समझौते की भावना के साथ व्यय में कमी करने का अलोकप्रिय कार्य अपने ऊपर ले लिया।<sup>20</sup> सैन्य वित्त आयोग (नियुक्ति जून, 1859 विकसित होकर हर दृष्टि से एक विभाग बन गया (जुलाई, 1860)। अप्रैल 1824 में इसे समाप्त कर दिया गया और सैन्य व्यय पर नियमित नियंत्रण सैन्य व्यय के कंट्रोलर जनरल को सौंप दिया गया।<sup>21</sup>

1864-65 से 1870-71 की अवधि में सेना पर व्यय लगभग 16 करोड़ रुपए के आस-पास स्थिर रहा। वायसरॉय पद पर लारेंस के कार्यकाल में सेना पर होने वाले व्यय में वृद्धि की थोड़ी सी प्रवृत्ति दिखाई दी। लारेंस ने सेना का व्यय कम रख पाने में कठिनाई अनुभव की।<sup>22</sup> सैन्य व्यय में वृद्धि आंशिक रूप से भूटान युद्ध के खर्चों और आंशिक रूप से कीमतों और मजदूरियों में सामान्य वृद्धि के कारण हुई।<sup>23</sup> भारत सरकार एक उभय संकट में फंसी हुई थी। भारत मंत्री क्रेनबोर्न ने इसे थोड़ी सेना अथवा अधिक कर के बीच चुनाव करने की समस्या कहा है।<sup>24</sup> लारेंस सेना पर व्यय में कमी करने के लिए उत्सुक था, परंतु वुड को जैसी आशंका थी, परिपद के सैन्य सदस्यों ने मितव्ययता के उपायों का विरोध किया।<sup>25</sup> कुशलता के नाम पर उन्होंने लारेंस के सामने ऐसे उपायों की सिफारिश रखी जिनसे खर्चों में वृद्धि हो।<sup>26</sup>

जनवरी, 1869 में भारत मंत्री ने गवर्नर जनरल का ध्यान पिछले पांच वर्षों में सैन्य व्यय में वृद्धि की ओर दिलाते हुए एक लंबा पत्र लिखा। पत्र में बतलाया गया था कि यूरोपीय सेना के प्रति व्यक्ति खर्च में काफी वृद्धि हो गई है, सेना के रसद विभाग में विशेष कमी नहीं हुई है, रिसाते में खर्च तथा कर्मचारियों (स्टाफ) नियुक्तियों तथा संगठन पर व्यय भार में वृद्धि हो गई है और आशा के विपरीत पुलिस की नई व्यवस्था से सेना पर व्यय में कमी नहीं हो सकी।<sup>27</sup> मेयो ने कटौती का कार्य अपने ऊपर ले लिया। उसने मैडहर्स्ट को लिखा था कि सैन्य खर्चों को 12 करोड़ रुपये तक कम कर पाना संभव है। वास्तव में यह वालफोर की भी सिफारिश थी यद्यपि कटौती संबंधी उसकी सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती थी।<sup>28</sup>

मेयो ने देखा कि भारत में सेना में आराम की नौकरी करने वाले अफसर, निरीक्षण अधिकारी जिनके पास या तो निरीक्षण के लिए बहुत थोड़ा या बिलकुल ही काम नहीं था, और कर्तव्यपरायण अफसर जिनके पास कोई भी काम नहीं था, बड़ी संख्या में हैं।<sup>29</sup> मेयो ने अनुभव किया कि सैन्य विद्रोह के समय से राजनीतिक वातावरण में काफी परिवर्तन हो गया है। उसने आरगाइल को लिखा कि, 'मुझे संदेह है कि इंडिया आफिस में भारत के सैन्य मामलों के क्षेत्र में होने वाले असाधारण परिवर्तन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है... सुगंठित पुलिस और जितनी ब्रिटिश सेना इस समय भारत

में है ठीक उतनी ही सेना दक्षिण भारत के लिए चाहिए।<sup>30</sup> किंतु राजनीतिक खतरा खास तौर से दक्षिण में नहीं था इसलिए हिंदुस्तानी सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैरक निर्माण रसद विभाग इत्यादि पर व्यय में कटौती के लिए समस्त लाइन में मेयो को मिला।<sup>31</sup> वह सैन्य खर्चों को कम कर पाने में सफल हो गया। परंतु जब उसने सैनिकों की संख्या में कमी करने का प्रस्ताव रखा तो उसे अनेक दिशाओं से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।<sup>32</sup>

मेयो ने 20 रेजिमेंट कम करने का क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। कटौती मुख्य रूप से मद्रास प्रेसीडेंसी की सेना में की गई। उसके कुछ परामर्शदाताओं (जैसे ड्यूरेड मैसफील्ड) का मत था कि मद्रास ही में कुछ और रेजिमेंटें खरम की जा सकती हैं।<sup>33</sup> मेयो का विचार था कि मद्रास की सेना कमजोर और अनुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं थी।<sup>34</sup> मद्रास प्रेसीडेंसी में रखी जाने वाली सेना उसकी आवश्यकताओं के मुताबिक पूर्णतया अनुपातहीन थी<sup>35</sup> और उसे समाप्त कर देना अधिक उपयुक्त था क्योंकि उसकी ब्रिटिश शासन की दृष्टि से विशेष उपयोगिता नहीं थी।<sup>36</sup> उसने इस बात का खंडन किया कि मद्रास की सेना के प्रति बंगाल में कोई द्वेष भावना है।<sup>37</sup> कर दाताओं पर भार डाल कर वहां ऐसी सेना रखना अन्यायपूर्ण था जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी।<sup>38</sup>

आरगाइल की इच्छा थी कि सैन्य विभाग की प्रशासनिक शाखाओं, सामान्य कर्मचारी वर्ग, रिसाला, रसद विभाग इत्यादि के व्यय में कटौती की जाए,<sup>39</sup> परंतु वह सैनिकों की संख्या में कमी नहीं करना चाहता था।<sup>40</sup> सेना में कमी करने के प्रस्ताव का अनेक अप्रत्याशित दिशाओं से विरोध हुआ। मेयो ने वार्टल फ़ोर को लिखा 'मैं मानता हूं कि मुझे इस बात पर हंसी आती है कि उन सभी क्षेत्र में, जहां व्यय में कमी करने के लिए सबसे अधिक होहल्ला था, वहां इस संबंध में जो कुछ किया गया है उसकी छोटी-छोटी बातों की आलोचना की मनोवृत्ति दिखाई देती है।'<sup>41</sup> मुझे यह सुनकर कुछ-कुछ निराशा हुई है कि 'कुछ लोग जो मितव्ययता की भाग जोरदार शब्दों में कर रहे थे और अनावश्यक खर्चों की निंदा कर रहे थे कटौतियों के बाद असहमति में सिर हिलाते हैं और कोई अन्य प्रस्ताव न रखते हुए भी उसके लिए जल्दबाजी, निर्दयतापूर्ण 'अनावश्यक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं।'<sup>42</sup> मैगडला के लार्ड नेपियर ने कटौती के प्रस्तावों का विरोध किया था। मेयो ने आरगाइल को क्षोभ के साथ लिखा कि 'लार्ड नेपियर समझता है कि यह उसका कर्तव्य है कि वह उन सभी प्रस्तावों का विरोध करे जिनसे घन के अपव्यय में कमी की जा सकती है।'<sup>43</sup> मेयो यह जानकर बहुत चिढ़ा कि नेपियर ने रंदन स्थित इंडिया काउंगिल के सदस्यों और आरगाइल को कुछ कागजात भेजे थे। घुसा विवाद टालने के लिए मेयो ने कागजी युद्ध नहीं चलाया और नेपियर अपनी अति-कर्तव्यनिष्ठा का लाभ उठा रहा था।<sup>44</sup> मेयो ने आरगाइल को शिकायत की कि सेनाध्यक्ष के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। सेनाध्यक्ष अर्सेहोयोग करता था और कटौती संबंधी निर्णय को रोके रहने के उद्देश्य से संबंधित कागजात को तीन माह तक अपने पास रखे रहा।<sup>45</sup> अंततोगत्वा भामना यहाँ तक बढ़ गया कि गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में सेनाध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही बार-बार के विस्फोट रक सके।<sup>46</sup> सेना के हिन्दी के

प्रतिनिधि सर एच० एम० ड्यूरेण्ड ने प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में प्रस्ताव रखा कि असैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए।<sup>44</sup> यह प्रस्ताव निस्संदेह गवर्नर जनरल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। गवर्नर जनरल ने स्पष्ट किया कि सैन्य व्यय वजट में सबसे बड़ी मद था।<sup>45</sup> मेयो चाहता था कि सेनाध्यक्ष को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया जाना चाहिए कि वित्त संबंधी मामलों में उसे न केवल भारत सरकार की अपितु राज्य की अपेक्षाओं के भी अधीन रहना है।<sup>46</sup>

सैन्य व्यय में कमी के विरोध में सेनाध्यक्ष अकेला नहीं था। स्वयं आरगाइल भी प्रस्तावित कटौती पर अपनी स्वीकृति देने के पक्ष में नहीं था।<sup>47</sup> कैब्रिज का ड्यूक काफी चिंतित था कि कहीं कटौती से सेना की कार्यक्षमता में बाधा न पड़े।<sup>48</sup> इंडिया काउंसिल के लगभग सभी सदस्य सेना की संख्या में कमी करने के विरुद्ध थे। सैन्य विद्रोह के बाद काफी कटौती संभव थी परंतु आरगाइल तथा उसकी परिपद के सदस्यों के विचार से और अधिक कटौती न तो सुरक्षित थी और न वांछनीय ही।<sup>49</sup> आरगाइल ने फरवरी, 1871 में मेयो को सूचना दी कि चूंकि इंडिया काउंसिल गवर्नर जनरल के प्रस्ताव का विरोध करती है इसलिए इस मामले पर मंत्री परिपद में विचार किया जाएगा।<sup>50</sup> मंत्री परिपद ने मेयो के विरुद्ध निर्णय दिया और तदनुसार आरगाइल ने सेना में कटौती से संबंधित भारत सरकार के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी।<sup>51</sup>

इस घटना की व्याख्या हमने कुछ विस्तार के साथ की है क्योंकि इससे सैन्य व्यय में कटौती के बीच आने वाली मुख्य बाधाएँ...विरोध रूप से गवर्नर जनरल की परिपद में सैन्य अधिकारियों का दबाव स्पष्ट हो जाती है। मेयो को आशंका थी कि उसकी कटौती योजना रद्द कर दी जाएगी। उसने 1870 में बड़ी कटुता के साथ आरगाइल को लिखा, स्वार्थ को पराजित कर सकना कठिन है। काफी अधिक पाने वाले अयोग्य व्यक्तियों को हमेशा ही बहुत सारे समर्थक मिल जाते हैं। लोक सेवा गौण है...और सदस्य खुलकर व्यय में ऐसी कमी का जो उचित होने के साथ-साथ सहज हो संभव है, समर्थन करने के स्थान पर जनता पर भार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं।<sup>52</sup> जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि मेयो इस बात का कायल था कि वित्तीय मामलों में सेनाध्यक्ष को गवर्नर जनरल तथा उसकी परिभाषा के मातहत रखा जाना चाहिए। इस संबंध में आरगाइल ने अपना मत मेयो को लिखे एक व्यक्तिगत पत्र (जिस पर गोपनीय शब्द लिखा था) में व्यक्त किया था, 'मेरी आशंका है कि आपका उद्देश्य परिपद में उस विशिष्ट प्रभाव को समाप्त करना है जो अनावश्यक सैन्य व्यय के पक्ष में है। आपका विचार है कि यह प्रभाव सेनाध्यक्ष में केंद्रित है...'<sup>53</sup> परंतु आरगाइल का विचार था कि भारत में सेनाध्यक्ष का स्थान, 'युद्ध मंत्री को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि यदि सेनाध्यक्ष सेना संबंधी किसी भी कार्यवाही का विरोध करता है तो बाधा डालने की उसकी शक्ति संभवतः परिपद के बाहर भी अधिक नहीं तो उतनी प्रबल तो होगी ही जितनी कि परिपद के भीतर है।'<sup>54</sup> आरगाइल ने आगे कहा कि 'चूंकि भारत में ब्रिटिश सेना पर व्यय सदैव ही सर्वाधिक रहना है, अतः हमें इससे विरोध रूप से संबंधित सैन्य अधिकारियों को अपने माथ रखने की सर्वोत्तम रीति का ध्यान रखना चाहिए।'<sup>55</sup>

सैन्य व्यय में कटौती संवन्धी 1869-71 के विवाद से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सैन्य अधिकारी जो सत्ता में थे (विशेष रूप से जो गवर्नर जनरल की परिपद के सदस्य थे) मितव्ययता संवन्धी उपायों में बाधा डाल रहे थे। साथ ही यह भी लगता है कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भारत में सेना में कमी करने के बारे में बहुत सतर्क थे। (यह सारेंस जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा बाधा डालने की नीति के विषय में शिकायत की थी)<sup>56</sup> का अनुभव था और यही अनुभव मेयो (जिसे इंडिया आफिस से भारी कटौती के प्रस्ताव पर अनिच्छा के साथ मामूली समर्थन मिला था) का भी था।<sup>57</sup> यह स्वाभाविक ही था क्योंकि भारतीय सेना की शक्ति के प्रश्न पर सदैव ही इंग्लैंड के व्यापक साम्राज्यिक हितों के संदर्भ में विचार होता था।<sup>58</sup>

## II

भारतीय तथा ब्रिटिश सरकारों के मध्य वित्तीय लेन-देन ब्रिटिश सरकार पर भारत सरकार की निर्भरता, ब्रिटिश सरकार को किए जानेवाले भुगतान, भारत में रखी जाने वाली ब्रिटिश सेना की जो लागत भारतीय करदाता को चुकानी पड़ती थी उसके अध्ययन से हमारे द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। प्रश्न है—क्या भारत ब्रिटिश सरकार के साथ तत्कालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन के व्यापक साम्राज्यिक हितों के लिए अपनी जेब से भुगतान कर रहा था?

ब्रिटिश सरकार के सेना विभाग तथा इंडिया आफिस के बीच हुए एक समझौते के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड नरेश की सेनाओं की सेवाओं के लिए भुगतान करती थी। सैन्य विद्रोह के वर्ष तक इंग्लैंड में भर्ती, प्रशिक्षण, डिपो व्यवस्था तथा बरक आवास पर होने वाले खर्च क्रमशः भारतीय और ब्रिटिश सगठनों में सैनिकों की संख्या और उनको दिए गए वेतन इत्यादि के अनुपात में बाँटे जाते थे।<sup>59</sup> सैन्य विद्रोह के समय भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओं के खर्च सहसा बढ़ गए। ब्रिटेन से और अधिक आने वाली सेना पर व्यय भारत सरकार की आय से किया गया। इस प्रकार भेजी गई सेना जिस समय से इंग्लैंड से चली तब से उसका पूरा खर्च भारत सरकार से लिया गया। भारत में स्थानीय सेवा के लिए एक पुष्क युरोपीय सेना रखने का भारत सरकार का अधिकार 1860 में निरस्त कर दिया गया।<sup>60</sup> 1861 के सेना समामेलन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार की सेना में स्थानीय युरोपीय सेनाओं का विलय कर दिया गया।<sup>61</sup> इसका परिणाम हुआ कि भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओं के खर्चों के लिए सेना विभाग को किए जाने वाले भुगतानों में स्थाई रूप से वृद्धि हो गई।

इन खर्चों का, जिन्हें नियमित खर्च (अर्थात् भारत स्थित इंग्लैंड की सेना का चालू खर्च) कहा जाता था, सर ए० टूलाक समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया जो इंडिया आफिस, सेना विभाग तथा खजाने (वित्त विभाग) के बीच लेखा संबंधी मामलों तय करने के लिए नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिश के अनुसार एक अतिरिक्त व्यवस्था पर सहमति हो गई जिसके अंतर्गत भारत सरकार को सभी प्रकार के प्रति 1,000 सैनिकों एवं अधिकारियों पर 10,000 पाउंड वार्षिक देना था। तात्पर्य यह है

कि प्रति व्यक्ति वार्षिक दर 10 पौड निर्धारित हुई। यह राशि 12 महीनों की उपस्थिति नामावली की औसत संख्या पर चुकाई जानी थी। इस भुगतान में भर्ती, और वस्त्र, शस्त्र, अन्य साज-सामान, तथा परिवहन की लागत को छोड़कर सेना के भारत आने के समय तक उसके भरण-पोषण का खर्च सम्मिलित था।<sup>62</sup> सर सी० वुड का विचार था कि ये खर्च अत्यधिक थे।<sup>63</sup> परंतु प्रारंभ में अंतरिम रूप से की गई व्यवस्था को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और वह व्यवहार में 1861-62 से 1869-70 तक बनी रही।

सेना विभाग इस समझौते से सन्तुष्ट न था। नए रंगरूट सैनिकों के भारत आने के लिए पोतारोहण तक की लागत तथा डिपो खर्चों में वृद्धि हो गई थी और सेना विभाग का दावा था कि प्रति व्यक्ति 10 पौड की दर से भुगतान भारत आने वाले सैनिकों के ऊपर किए जाने वाले व्यय के लिए पर्याप्त नहीं था। सेना विभाग ने माग की कि समझौते का आधार 10 रुपए प्रति व्यक्ति की कामचलाऊ औसत दर न होकर वास्तविक व्यय होना चाहिए। 1869 में सीकोंव समिति नियुक्त हुई जिसका काम समस्या की जांच कर प्रति व्यक्ति दर में सशोधन करना था।<sup>64</sup> नई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दरें तय हुईं : 136 पौड 13 शिलिंग 11 पैसे अश्वारोही सेना (रिसाला); 63 पौड 8 शिलिंग 5 पैसे पैदल सेना, 78 पौड 14 शिलिंग 8 पैसे शाही घुड़सवार गोलंदाज सेना, 59 पौड 2 शिलिंग 10 पैसे शाही गोलंदाज सेना, आरोहित; तथा 58 पौड 9 शिलिंग 3 पैसे शाही गोलंदाज सेना के लिए।

इंडिया आफिस का तर्क था कि प्रचलित व्यवस्था बहुत खर्चीली है और वास्तविक खर्चों में और अधिक वृद्धि करना भारत के साथ अन्याय होगा। 1861 के सेना समामेलन अधिनियम का उल्लेख करते हुए भारत मंत्री आरगाइल के ड्यूक ने लिखा, 'भारत में स्थानीय यूरोपीय सेना का समापन साम्राज्यिक नीति के विचार से आवश्यक उपाय था, परंतु यह संदेहास्पद है कि यदि यह पूरी तरह मालूम होता कि इसका भारत सरकार पर कितना अधिक अतिरिक्त भार पड़ेगा तो क्या यह उपाय सहज ही कर सकना संभव होता'।<sup>65</sup> भर्ती और प्रशिक्षण की प्रणाली अनावश्यक रूप से अपव्ययी थी और गृह डिपो में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी थे। आरगाइल ने इसे न तो 'नीतिकुशलता' और न ही 'व्यायपूर्ण' माना कि भारत की आय पर रंगरूटों की पूर्ति के लिए संगठन की लागत को थोप दिया जाए। यह संगठन भारत की आवश्यकता या उसकी आर्थिक क्षमता की अपेक्षा कही बढ़ा था।

ब्रिटिश सेना मंत्री कार्डेवेल का दावा था कि भारत सरकार पर डाले गए वास्तविक खर्च अन्यायपूर्ण न होकर बहुत मामूली थे। सेना विभाग ने तर्क दिया कि इंग्लैंड की सेना रिजर्व के रूप में कार्य करती है जिससे भारत सरकार आपात्कालीन स्थिति में कुमक मगा सकती है। रिजर्व सेना के रहने कारण भारत सरकार के लिए अपनी सेना में कमी कर पाना संभव हुआ है। कार्डेवेल के मतानुसार, 'इन उपलब्ध रिजर्व सेनाओं का अनुरक्षण ब्रिटिश सरकार की आय के वास्तविक व्यय में एक महत्वपूर्ण भद्र था जिसके पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व भारतीय राजस्व का है...'।<sup>66</sup> अतः नए रंगरूट भर्ती करने के संतर्क की लागत और रिजर्व में रहने वाले प्रशिक्षित सैनिकों के खर्चों

का आनुपातिक भाग देना भारत की जिम्मेदारी था।<sup>67</sup>

कार्डवेल के पत्र के उत्तर में भारत का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।<sup>68</sup> सेना परिपक्ष विभाग का दावा था कि भारत सरकार इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना में ही एक रिजर्व सेना तैयार रखती है जिसे भारत की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक ब्रिटिश प्रतिष्ठान अथवा संस्था, चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो यदि उससे भारत सरकार का व्यापारिक या रोजगार की दृष्टि से संबंध है तो उसकी लागत का एक भाग भारत पर धोपा जा सकता है। अमलियत यह है कि इंग्लैंड ने भारतीय सेनाओं को ही अपना रिजर्व ममत्ता दी। 'यह कहना अधिक ठीक है कि साम्राज्यिक सरकार भारत में वहाँ के राजस्व के धल पर अपनी सेना का उतना बड़ा भाग रखती है जो उसके विचार से वहाँ पर अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेना के इस भाग को साम्राज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वभावतः रिजर्व के रूप में लिया जाता है। यूरोपीय रेजिमेंट साम्राज्यिक युद्धों में भाग लेने के लिए समान रूप से भारत की प्रतिरक्षा सेना से अलग कर दिए गए हैं' और भारत की हिंदुस्तानी सेना का भी अनेक बार भारत के बाहर ऐसे युद्धों के लिए, जिनसे भारत का कोई संबंध नहीं था, प्रयोग किया गया है, जब कि इसके अनुरक्षण में साम्राज्यिक सरकार का कोई योगदान नहीं था।<sup>69</sup> केवल असाधारण सैन्य विद्रोह के मामले से, सेना विभाग के तर्क में कुछ सत्याभास होता था, परंतु उस समय ब्रिटिश सेना के खर्च का भार भारतीय सरकारों ने उठाया था। सेना विभाग के अनुसार इंग्लैंड में भर्ती और प्रशिक्षण की लागत अधिक हो गई थी। परंतु लागत में यह वृद्धि एक कृत्रिम खर्च की प्रणाली के कारण हुई थी जिसके आधार पर ऐसे व्ययों को भी सम्मिलित कर लिया गया था जिनका प्रशिक्षण की लागत से कोई संबंध नहीं था और जो पूर्ण रूप से इंग्लैंड की गृह रक्षक सेना के संगठन से संबंधित थे। इन व्ययों का भारत की आवश्यकताओं से भी कोई संबंध नहीं था। भारत सरकार ने आरगाइल के पास भेजे गए अपने प्रतिवेदन में यही बात रखी थी।<sup>69</sup>

गृह खर्चों के अंतर्गत आने वाली मदों में सैन्य खर्च प्रमुख थे। विभिन्न मदें निम्नलिखित थीं - भारत स्थित ब्रिटिश सेना के लिए ब्रिटिश सरकार को दी जाने वाली राशियाँ; सेना के यातायात पर खर्च, शस्त्रीकरण व्यय; इंग्लैंड में भर्ती पर व्यय तथा डिपी खर्च, एडिस्कोव स्थिति सैनिक कालेज के लिए प्रभार, अफसरों को छुट्टी और सेवा निवृत्ति वेतन तथा पेंशन।<sup>70</sup>

अब तक हम सेना के नियमित खर्चों पर विचार विमर्श करते रहे हैं। गैर नियमित खर्च अर्थात् सेवा निवृत्ति के बाद सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन भारतीय सैन्य वजट की एक बड़ी मद थी।<sup>71</sup> 1823 से पहले भारत स्थिति ब्रिटिश सेनाओं के लिए गैर नियमित खर्चों के निमित्त सेना विभाग को कोई भुगतान नहीं किया जाता था। 1823 के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गैर नियमित खर्चों के निमित्त 60,000 पाउंड की स्थिर राशि वार्षिक देने के लिए अपनी महमति दे दी। 1858 में इस समझौते में समायोजन करने के लिए सेना विभाग की ओर से माग की गई क्योंकि 1823 की तुलना में भारत

स्थित शाही सेना बढ़ गई थी।<sup>72</sup> 1859 में गैर नियमित खर्चों का अनुमान करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने निर्णय किया कि भारत स्थित 30,000 सेना के लिए 2,000,000 पौंड वार्षिक दिए जाना चाहिए।<sup>73</sup> समिति के इंडिया आफिस से संबंधित सदस्यों ने इस अनुमान को अत्यधिक समझकर अपनी असहमति प्रकट की। एक अन्य समिति नियुक्त की गई और उसने सिफारिश की (3 जनवरी, 1861) कि सभी प्रकार के फौजियों के लिए गैर नियमित खर्चों के निमित्त प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 3,500 पौंड वार्षिक का भुगतान होना चाहिए। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और मार्च, 1861 से पहले एक वर्ष के लिए, और फिर बाद में पांच वर्ष के लिए, व्यवहार में आ गया।<sup>74</sup> प्रारंभ में इसे अस्थायी व्यवस्था के रूप में रखने का इरादा था। सीकॉव समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा सेना विभाग को दिए जाने वाले गैर नियमित खर्चों का अपेक्षाकृत अधिक सही अनुमान 1870 में लागू किया गया। अप्रैल, 1870 से गैर नियमित खर्चों का अनुमान एक नए सिद्धांत के आधार पर होने लगा। यह सिद्धांत था '...स्वीकृत पेंशनो की राशि पता लगाकर उसमें से भारतीय हिस्से का पूजीकरण करना (जीवनांकिक सारणियों के आधार पर)। यह प्रणाली 1883 तक प्रचलन में रही।

कुल सैन्य व्यय को अलग-अलग कर देखने पर स्पष्ट होता है कि समस्त व्यय का पाचवा भाग इंग्लैंड में नियमित, गैर नियमित मदों तथा युद्ध सामग्री पर हुआ। इसका काफी बड़ा अनुपात प्रशासनिक कर्मचारियों तथा संगठन (रसद व्यवस्था, वैरको, चिकित्सा इत्यादि) पर व्यय किया गया; सामग्री पर होने वाला व्यय काफी बढ़ा था; और इंग्लैंड में गैर नियमित खर्च सदैव ही भारत में इस प्रकार के खर्चों से अधिक रहते थे।

भारतीय लेखे में व्यय की मदों में नौसेना का उल्लेख नहीं रहता था, क्योंकि 1862 के बाद से भारत की अपनी नौसेना नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना को 1862 में शाही भारतीय समुद्री वेड़े (रायल इंडियन मेरीन) नामक गैर लड़ाकू दल में परिवर्तित कर दी गई। इस पर भारतीय सागर में सेना के यातायात, प्रकाश स्तम्भ, समुद्री सर्वेक्षण इत्यादि का उत्तरदायित्व था। भारतीय लेखे में समुद्री खर्च अलग से दिखाए जाते थे। यह व्यय प्रति वर्ष आधे से एक करोड़ तक रहता था। सामान्य समुद्री प्रतिरक्षा का कार्य शाही नौसेना को सौंप दिया गया था। इस सेवा के लिए 1862 से 1869 तक नौसेना विभाग को कोई भुगतान नहीं किया गया, परंतु 1869 के बाद इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले छ' जलपोतों के खर्चों को पूरा करने के लिए 70,000 पौंड वार्षिक दिए गए। 'भारतीय प्रयोजन' पद को व्यापक अर्थ में लिखा गया और वस्तुतः शाही नौसेना के पोत हिंद महासागर में ब्रिटिश व्यापार की रक्षा करते थे। गवर्नर जनरल लारेंस ने 1868 में अपने एक कार्यवृत्त में लिखा था कि यदि इंग्लैंड भारत को समुद्र में संरक्षण प्रदान करता है तो इसके पीछे उसकी स्वार्थ दृष्टि है। उसके शब्दों में : 'यै समझता हू कि यह ऐसा कार्य है जिसे वह वाणिज्य से मिलने वाले वार्षिक लाभ के बदले जो दसियों लाख के होते हैं,.... (और) अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए करता है।'<sup>75</sup> मेयो ने नौ-सैनिक सहायता के लिए पोपे जाने वाले प्रभार के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए आर-ग्राइल को लिखा था, 'आशा है आप हमें साम्राज्यिक सरकार को प्रति वर्ष 70,000 पौंड



का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे...सच जिसे हम सभी समझते हैं यह है कि इस विषय में हमें पूरी तरह 'समाप्त' कर दिया गया है और यह एक घोर खुटेरेपन का कार्य है।'<sup>70</sup>

भारत की सीमा के बाहर भारतीय सेना का प्रयोग बिरले नहीं होता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत मंसद की स्वीकृति के बिना भारत सरकार की आय, देश की सीमा के बाहर, विदेशी आक्रमण को रोकने के अलावा किसी अन्य सैनिक कार्यवाही के खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं की जा सकती थी।<sup>71</sup> इससे भारत के हितों की थोड़ी रक्षा हुई। भारत की सीमा के बाहर सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप असाधारण खर्चों (जैसे अफसरो व सैनिकों को दिए जाने वाले सामान्य वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त प्रभार) का भार ब्रिटिश राजकोष ने उठाया। भारत सरकार इस सिद्धांत से पूर्णतया संतुष्ट नहीं थी। जब भी इंग्लैंड से भारत को सैनिक दस्ते भेजे जाते थे तो इन सैनिक दस्तों का समस्त वेतन और असाधारण खर्च भारत को उस समय से देने पड़ते थे जब से वे ब्रिटिश समुद्र तट छोड़ते थे। परंतु सामान्यतः भारत के बाहर फौजी कार्यवाही के क्षेत्र में भारतीय सेना से सामान्य खर्चों (जैसे, वेतन तथा भत्तों) का भुगतान ब्रिटिश राजकोष से नहीं किया जाता था। विदेशी युद्धों में प्रयोग किए जाने वाले भारतीय सैनिक दस्तों के सामान्य खर्चों का भुगतान ब्रिटिश राजकोष से न करने का कोई औचित्य नहीं था। 1872 में इंडिया आफिस से मंडूक सेना सचिव ने लिखा था 'यह निश्चित है कि ये सभी युद्ध साम्राज्यिक सरकार द्वारा थोपे गए थे और इन सभी के निर्धारक तत्व थे, ब्रिटिश वाणिज्यिक हित, ब्रिटिश व्यापारियों की शिकायत, ब्रिटिश नरेश की प्रतिष्ठा, इत्यादि।'<sup>72</sup> भारतीय सेना का प्रयोग चीन में 1842 तथा 1859-60 में, श्रीमिया में 1855 में, ईरान में 1856-57 में, न्यूजीलैंड में 1860 में, तथा अबीसीनिया में 1867 में किया गया था। 1878 में जब भारतीय सेना माल्टा भेजी गई तो यह पैरोडी बन गई : 'युद्ध नहीं हम करना चाहते, स्वयं न रणक्षेत्र में जाएं; पर साम्राज्यवाद जब बाध्य करे तो हिंदू सैनिक वहां पठाएँ।'<sup>73</sup>

1867 का अबीसीनिया युद्ध, जिसके कारण एक छोटा सा वित्तीय सकट उत्पन्न हो गया था, एक अच्छा उदाहरण था।<sup>74</sup> अबीसीनिया में भारतीय सेना के असाधारण खर्चों का भुगतान तो ब्रिटेन ने किया, परंतु सामान्य खर्च भारत ने ही किए। इस विषय पर गवर्नर जनरल लॉरेंस ने एक कमाल का कार्यवृत्त लिखा : 'इस युद्ध में भारत का कोई प्रत्यक्ष हित न था।...निस्संदेह इस निर्णय के समर्थन में पिछले उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या ये उदाहरण न्याय अथवा औचित्य पर आधारित हैं? क्या इंग्लैंड जब अपनी सेना भारत भेजता है तो वह इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? भारत ने केवल भारत स्थित ब्रिटिश सेना का खर्च देता है, अपितु सैनिकों की भर्ती और उन्हें कार्यक्षम रखने के लिए उनके भरण-पोषण पर आने वाले व्यय का भी भुगतान करता है। ब्रिटिश सेना के भारत और इंग्लैंड के बीच आने जाने का खर्च भी भारत देता है'<sup>75</sup>...यदि दूसरे देशों में सैन्य कार्यवाही में मंगल भारतीय सेना के सामान्य खर्च भारत से लेने का सिद्धांत नहीं बदला जाता

‘तो भारत के लोग यह सोच सकते हैं कि इंग्लैंड के लिए एक सिद्धांत और भारत के लिए दूसरा सिद्धांत अपनाया गया है और ये दोनों ही सिद्धांत भारत के प्रतिकूल हैं।’<sup>82</sup> इस प्रकार की भर्त्सना भारतीय राष्ट्रवादियों तक के लेखों में बिरले ही मिलेगी। लारेस की भांति मेयो भी इस बारे में भारतीयों के मन में उठने वाले विचारों के विषय में चिंतित था। उसने लिखा, ‘इससे यहां पर असतोष उत्पन्न होगा जिसे शांत कर पाना कठिन होगा और यह बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है।’<sup>83</sup>

1867 में मार्क्विस् आव सेलिसवरी ने कहा था कि भारत को ‘पूर्वी समुद्र में इंग्लैंड की बैरक’ नहीं समझा जाना चाहिए।<sup>84</sup> इतना सब होने पर भी व्यवहार में भारत स्थित सेना को रिजर्व सेना ही समझा जाता था। ब्रिटिश सेना भारत में रखी जाती थी और उसका खर्च भारत को देना होता था। सर चार्ल्स डिल्के के अनुसार ‘भारत सरकार के साथ की गई व्यवस्था के आधार पर इंग्लैंड के लिए भारतीय खर्चों पर उन 70,000 ब्रिटिश सैनिकों को रख पाना संभव था जो साम्राज्य पर सकट के समय उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकते थे।’<sup>85</sup> इस प्रकार भारत सरकार से सेना का खर्च लिया जा सकता था और साथ ही सरकार मसद द्वारा बनाए गए कानूनों के विधिक प्रतिबंधों तथा वित्तीय प्रतिबंधों से मुक्त थी।<sup>86</sup> अतः भारत के सैन्य वित्त के प्रश्नों पर निर्णय केवल भारतीय हितों को ध्यान में रखकर नहीं किए जाते थे। भारत की तात्कालिक स्थिति और आवश्यकताओं से अलग ‘सामान्य बातों’ को भी ध्यान में रखा जाता था।<sup>87</sup> 1874 में हाउस ऑफ कामन्स की भारतीय वित्त से संबंधित प्रवर समिति को ‘आभास हुआ कि कहीं-कहीं जो खर्च इंग्लैंड को करने चाहिए थे वे भारत के ऊपर थोप दिए गए हैं। तथापि इस समिति को अनेक साक्ष्यों ने आश्वासन दिलाया है कि ब्रिटिश सरकार के विभिन्न विभागों में यह भावना आम तौर पर व्याप्त है कि भारत पर कोई भी खर्च अनुचित ढंग से नहीं लादा जाना चाहिए।’<sup>88</sup> इंग्लैंड के शासक भारत के साथ हर मामले में अन्याय नहीं करते थे, परंतु जैसा गवर्नर जनरल लारेंस का कहना था, ‘इंग्लैंड में करदाताओं पर भार हलका करने के लिए उनके मन में एक स्वभाविक पूर्वग्रह’ था।<sup>89</sup> वे अपने साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न किए बिना सैन्य व्यय में कमी करना चाहते थे और सेना की भर्ती तथा उसके वित्त के बारे में इस सिद्धांत को सही मानते थे कि भारत के हित इंग्लैंड के व्यापक साम्राज्यिक हितों के सामने गौण हैं।

### III

भारत में रेलों का विकास भारत में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त उद्यम का दिव्यचमक उदाहरण है। 1849 में निर्धारित भविष्य की शर्तों के अंतर्गत भारत सरकार ने रेल कंपनियों को भूमि दी जिसके लिए उन्हें कोई मूल्य नहीं देना पड़ा।<sup>90</sup> सरकार ने समादत्त पूंजी (पेड अप कैपिटल) पर 99 वर्षों तक एक न्यूनतम व्याज जो प्रायः 5 प्रतिशत था, देने की गारंटी दी। कार्य संचालन, अनुरक्षण, तथा आरक्षित निधि के लिए राशि निकाल लेने के बाद बचे हुए आधिक्य को पहले चानू 5 प्रतिशत व्याज प्रभार चुकाने में लगाया जाना था (जिससे भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो

सके)। शेष राशि भारत सरकार (अग्रिम रूप में पहले दिए गए प्रत्याभूत (गारंटी शुदा ब्याज के पुनर्भुगतान के रूप में) और रेल कम्पनी के बीच बाटी जानी थी। जब भारत सरकार को उसके अग्रिम का पूरा भुगतान हो जाए तो पूरा लाभ रेल कम्पनी को ही जाना था। प्रत्येक रेल कम्पनी को रेलवे लाइन तथा कारखाने सरकार को समर्पित कर लगाई गई पूँजी के बदले में पूरी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार था। कोई भी कम्पनी 99 वर्ष के पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। 99 वर्ष का पट्टा समाप्त हो जाने के बाद रेलों और उनके कारखाने स्वाभाविक ढंग से सरकार की संपत्ति बन जाएंगे। सरकार को हस्तांतरण के संवध में उपर्युक्त अंतिम दो शर्तों परस्पर सगत नहीं थी। कोई भी कम्पनी मंविदा के साथ, जिसमें प्रत्याभूत ब्याज भी सम्मिलित था, 98 वर्षों तक उठा सकती थी। उसके बाद वह 99 वर्ष पूरे होने से पहले, जबकि नियमानुसार सरकार का रेलवे संपत्ति पर (बिना क्षतिपूर्ति के) स्वाभाविक ढंग से अधिकार हो जाना था, रेलवे लाइन सरकार को समर्पित कर पूरी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती थी। संक्षेप में, मंविदा के द्वारा रेल कम्पनियों को 5 प्रतिशत प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) साथ-साथ 'अलाभकर शिशु को राज्य के पास संभालने के लिए छोड़ देने' और अपना हाथ खींच लेने की स्वतंत्रता मिली हुई थी।<sup>91</sup>

यह बहुत ठीक कहा गया है कि यह सार्वजनिक जोखिम के आधार पर निजी उद्यम का एक उदाहरण था। भारत मंत्री आरगाइल के ड्यूक ने मेयो को लिखा कि 'प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) कम्पनियां निजी उद्यम का प्रतिनिधित्व नहीं करती।'<sup>92</sup> ये कम्पनियां केवल वित्तीय साधन जुटाने और खर्च करने वाली संस्थाएं मात्र थीं जबकि सारा का सारा उद्यम संबंधी जोखिम राज्य को उठाना था। 'यह महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड में अहस्तक्षेपी नीति का गढ़ मैनचेस्टर के उद्योगपति तथा ससद सदस्य भारत में रेलों के हामीदार (अंडरराइटर) के रूप में सरकारी हस्तक्षेप के प्रमुख समर्थकों में थे।'<sup>93</sup>

ऊपर से सब लगने वाला यह तर्क भी दिया जा सकता है कि प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) सविदाओं की शर्तें यद्यपि अनुकूल नहीं थीं, तथापि भारतीय अधिकारियों के सामने एकमात्र रास्ता यही था। डैनवर्स, चैजनी, तथा स्ट्रैची का मत यही था।<sup>94</sup> उनका कहना था संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के काम में लगाने से रेलों के लिए लगातार पूँजी की प्राप्ति तथा उसका उपयोग निश्चित था। यदि भारत सरकार स्वयं पूँजी जुटाने का कार्य करती तो विशेष रूप से उत्तर मैन्य विद्रोह काल में आर्थिक संकट के समय यह बहुत संभव था कि इस धनराशि का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर लिया जाता और रेलों के विकास में बाधा पड़ती। इसके अलावा पूँजी निवेश की दृष्टि से भारत नया क्षेत्र था और पूँजी निवेशकों की यह प्रत्याशा स्वाभाविक थी कि सरकार ब्याज की कुछ ऊंची दर की गारंटी दे और उनके भुगतान का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले।<sup>95</sup>

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत आने वाली ब्रिटिश पूँजी में रेलों का अंश महत्वपूर्ण था। अनुमान है कि 1854 से 1869 तक भारत में 15 करोड़ पौंड की ब्रिटिश पूँजी का निवेश हुआ। इसमें से लगभग आधी पूँजी रेलों में लगाई गई। 1858 से 1869

तक 7,01,10,000 पौड भारतीय रेलों पर व्यय किए गए।<sup>96</sup> इस प्रकार गारंटी प्रणाली निस्संदेह पूँजी को आकर्षित करते में सफल हुई।

परंतु गारंटी प्रणाली के स्पष्ट दोषों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। (क) 5 प्रतिशत प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) व्याज सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्क्युरिटीज) पर व्याज से। प्रतिशत अधिक था, अर्थात् यदि भारत सरकार चाहती तो नीची व्याज की दर पर ऋण ले सकती थी। इंग्लैंड भेजे गए व्याज से गृह खर्चों की राशि बढ गई और जैसे-जैसे एक के बाद दूसरे वर्ष रेलों में लगाई गई पूँजी में वृद्धि हुई वैसे-वैसे प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) व्याज के रूप में व्यय की राशि बढ़ती गई। भारत सरकार की इस स्थिति से उत्पन्न चिंता को कम करने के लिए भारत मंत्री ने स्पष्ट किया कि 'इस व्याज का स्वरूप निस्संदेह अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि अंततोगत्वा इसका सरकार को भुगतान मिलना ही है।'<sup>97</sup> जैसे ही रेलों का विकास कार्य पूरा हो जाएगा, यातायात से शुद्ध प्राप्ति बढ जाएगी और भारतीय राजस्व पर इस प्रभार में कमी हो जाएगी। तथापि पुनर्भुगतान का समय बहुत दूर था और प्रत्याभूत व्याज प्रभार का बोझ काफी था।

(ख) गारंटी शुदा मविदाओं के एक अन्य दोष के कारण भारत सरकार को भारी हानि हुई। मविदाओं में व्यवस्था थी कि रेलवे कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूँजी बैंक आय इंग्लैंड में भारत सरकार के गृह विभाग के खाते में जमा की जाएगी और कंपनियों के अभिकर्ता (ऐजेंट) भारत सरकार के खजाने से। शि० 10 पैसे प्रति रुपये की स्थिर दर से रुपये ले सकेंगे। परंतु हमारे इस सर्वेक्षण की अवधि में भारत सरकार तथा इंडियन आफिस के बीच लेखाओं का ममायोजन 2 शि० प्रति रुपये की दर से होता था। इस प्रकार रेलवे कंपनियों द्वारा भारतीय खजानों से निकाले जाने वाले रुपये पर 2 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से हानि हुई।<sup>98</sup> लेखे की इस हानि को विनिमय द्वारा हानि के रूप में दिखाया गया।<sup>99</sup> 1862-72 के दशक में इस हानि का औसत 1,42,000 पौड वार्षिक था।<sup>100</sup> 1861 में भारत मंत्री से गवर्नर जनरल ने आप्रह्न किया कि जब तक यह आपत्तिजनक धारा हटाई नहीं जाती तब तक मविदाओं का न तो नवीकरण किया जाए और न ही नई मविदाएँ की जाएँ।<sup>101</sup>

भारत सरकार का तर्क था कि विनिमय द्वारा हानि के रूप में प्रभार का बोझ चालू वर्ष के राजस्व पर नहीं डाला जाना चाहिए। वायसराय की परिपद का वित्त सदस्य मैदांतिफा आधार पर भारत की आय में से विनिमय द्वारा होने वाली हानि के भुगतान के विरोध में था।<sup>102</sup> परंतु भारत मंत्री गर सी० बुड ने जोर डाला कि यह प्रभार चालू राजस्व से ही निकाला जाना चाहिए।<sup>103</sup> बिना अधिकार के इस मद को 1861-62 के बजट से निकाल देने के लिए लैंग को कड़ी डाट-फटकार पड़ी। 'विनिमय द्वारा हानि' के रूप में प्रतिवर्ष आय की भारी हानि होती रही प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) व्याज तथा 'विनिमय द्वारा हानि' के अतिरिक्त भारत सरकार को रेलवे लाइनों के लिए भूमि तथा निरीक्षण का खर्च भी चुकाना पड़ा।

(ग) मविदा के अनुसार भारत में रेल कंपनियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा-परीक्षण संशुद्ध रूप से रेलवे अधिकारियों और सरकारी अफसरों द्वारा होना चाहिए

था। इस पुनर्विलोकन की व्यवस्था सरकार के हितों की रक्षा की दृष्टि से की गई थी। परंतु भारत मंत्री वुड ने भारत सरकार को आदेश दिया कि लेखा परीक्षण करते समय 'रेलवे कंपनियों के साथ आप उस उदार भावना के साथ व्यवहार करें जो इतने बड़े काम के नियंत्रण के लिए आवश्यक है'।<sup>101</sup> वास्तव में सरकार रेल कंपनियों के व्यय को नियंत्रित कर पाने में असफल रही। 1858 में कॉनिंग ने और 1861 में सर डब्ल्यू० डेनिस ने स्पष्ट किया कि (संभवतः रेलवे तथा सरकार के अधिकारियों के बीच उत्तरदायित्व के विभाजन के कारण) रेल कंपनियों के अपव्यय को रोका नहीं जा सका।<sup>102</sup> 1872 में प्रवर समिति के सामने अपने साक्ष्य में लार्ड लार्सेंस, सर आर्थर काटन, मेजर चेजनी, डब्ल्यू० एन० मैसी, विलियम थॉर्नटन तथा कुछ अन्य लोग इस एक बात पर पूर्ण सहमत थे कि भारत में रेलों के निर्माण की लागत असाधारण रूप से अधिक रही है।<sup>103</sup> आरगाइल ने मेयो को लिखा कि 'यह स्पष्ट है कि हम 5 प्रतिशत की जो गारंटी करते हैं इससे मितव्ययता की प्रवृत्ति जो निजी उद्यम के लाभों में से एक है, बहुत कुछ समाप्त हो जाती है'।<sup>104</sup> आरगाइल के ड्यूक ने इस प्रकार रोग का ठीक निदान कर लिया था। परंतु रेल संघर्षी मविदाओं के द्वारा स्थापित 'द्वंद्व शासन की असंगत प्रणाली' के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सका।<sup>105</sup>

(घ) रेल कंपनियों के साथ सरकार के संबंधों से उत्पन्न एक अन्य समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलों के निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार सामान्यतः किसी भी रेल कंपनी को उस अवस्था में भी अग्रिम देती रहती थी जब इसके द्वारा गृह-खजाने (होम ट्रेजरी) को भुगतान की गई राशि और इसके नाम जमा रकम से भी व्यय कहीं अधिक होता था। भारत मंत्री का यही आदेश था।<sup>106</sup> रेलवे कंपनियां बहुधा अपने द्वारा जमा की गई राशियों से अधिक रुपया निकाल लेती थी और भारत में सरकारी खजानों से हुई प्राप्तियों के बदले इंग्लैंड में तत्काल भुगतान नहीं कर पाती थी। इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उदाहरण के लिए, 1860 में भारत सरकार को रेलों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों में कमी करनी पड़ी जिससे कुछ रेलवे लाइनों को पूरा करने में विलंब हुआ।<sup>107</sup> चूंकि रेलवे कंपनियां भारत में उन्हें किए गए भुगतानों की राशि को चुकाने में असमर्थ रही अतः भारत मंत्री ने 30 लाख पौंड का ऋण जुटाने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त की।<sup>108</sup> फरवरी, 1861 में संकट गहरा हो गया और भारत सरकार द्वारा भारत मंत्री को चेतावनी दी गई कि सरकार रेल कंपनियों को भुगतान पूर्ण रूप से बंद कर सकती है।<sup>109</sup> 1861 में भारत मंत्री ने ऋण लेने के लिए संसद द्वारा पहले ही दी गई अनुमति का लाभ उठाना चाहा। इससे भारत सरकार को संकट पर नियंत्रण पाने में सहायता मिली।<sup>110</sup> रेलवे कंपनियों के अपने खाते में जमा राशि से अधिक रुपया निकालने के व्यवहार के कारण 1866-67 में सरकार पुनः कठिनाई में फंस गई। भारत में रोकड़-धेप बहुत कम थे और भारत मंत्री से अनुरोध किया गया कि वह रेल कंपनियों पर रकम चुकता करने के लिए और पूंजी खाते में उनके नाम राशि को बढ़ाने के लिए जोर दे।<sup>111</sup> 1866-67 में रेल कंपनियों को भारत में किए गए भुगतान इंग्लैंड में इनसे होने वाली प्राप्तियों से 26,12,000 पौंड अधिक थे।<sup>112</sup>

ये उम तथाकथित गारंटी प्रणाली के प्रमुख दोष थे जिसके अंतर्गत भारतीय रेलों का निर्माण हुआ था। इन दोषों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने- जो नीति अपनाई उसकी मुख्य बातें थी, (क) अपव्यय रोकने के लिए व्यय पर सरकारी नियंत्रण कड़ा किया गया; (ग) सरकार ने बिना किसी गारंटी के नई कंपनियों के द्वारा रेलवे लाइनों का निर्माण कराने का प्रयास किया और प्रचलित कंपनियों के साथ पुरानी संविदाओं में संशोधन करने का भी प्रयत्न किया; (ग) इसके अलावा सरकार ने अपने आप पूँजी जुटा कर अपने ही प्रबंध में सरकारी रेलों के निर्माण का निश्चय किया।

(क) रेलवे कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यय का लेखा परीक्षण सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। सर सी० ब्रुड के अनुसार पुनर्विलोकन की यह प्रक्रिया सरकार एवं अंशधारियों के हित का सबसे अच्छा बचाव है और इसमें अंशधारियों (शेयर होल्डरों) को तो किसी प्रकार की हानि होती ही नहीं है।<sup>117</sup> जब तक 1864 में अन्य छोटे-छोटे सुधारों के साथ लोक निर्माण विभाग के अकाउंटेंट जनरल के सुझाव पर विनियोजन लेखा परीक्षण को व्यवहार में नहीं लागू किया गया, तब तक यह निरीक्षण अधिक प्रभावपूर्ण नहीं था।<sup>118</sup> प्रत्येक रेलवे कंपनी के कार्यालय से संबद्ध सरकारी लेखा परीक्षक मूल वाजचरों के आधार पर लेखे की जाच करते थे। आय और व्यय के नियतकालिक लेखे तैयार किए जाते थे और उन्हें सरकार के पास भेजा जाता था।<sup>119</sup> आरगाइल ने मेयो को लेखा परीक्षण तथा लेखा प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ा कर गारंटीशुदा रेलवे लाइनों पर हानि रोकने की राय दी थी।<sup>120</sup> 1871 में भारत सरकार ने इस आशा से कि भारत मंत्री की स्वीकृति तो प्राप्त हो ही जाएगी, गारंटी-शुदा रेलों के लेखे के लिए लेखा परीक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की।<sup>121</sup> बाद में इसे भारत मंत्री की स्वीकृति मिल गई।<sup>122</sup>

रेलवे कंपनियों की अपने छातों में जमा राशियों से अधिक रूपया निकालने की प्रवृत्ति के कारण भारत सरकार कभी-कभी कठिन स्थिति में फँस जाती थी। भारत में रेलवे कंपनियों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों के वापस भुगतान में शीघ्रता के लिए भारत सरकार ने रेल कंपनियों द्वारा किए गए भुगतानों से ऊपर की अग्रिम राशियों पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का प्रस्ताव रखा।<sup>123</sup> भारत मंत्री नोर्थकोट ने स्वीकार किया कि चूँकि संविदाओं में इस प्रकार की अग्रिम राशियों की कोई व्यवस्था नहीं है अतः ब्याज का लेना न्योचित है। इस प्रकार की प्रभाय राशि भविष्य में रेलवे कंपनियों से वापस मिलने वाले प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) ब्याज के साथ जोड़ी जाने की व्यवस्था की जाएगी।<sup>124</sup> इसके साथ-साथ रेलवे कंपनियों को भी भारतीय खजानों में सरकार द्वारा अग्रिम राशियाँ दे देने के बाद बचने वाले उनके रोकड़ शेष पर ब्याज देना निश्चित हुआ।<sup>125</sup>

(ख) प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) ब्याज प्रणाली की समस्याओं से बचने के लिए भारत सरकार ने गारंटी रहित कुछ छोटी संभरक (फीडर) रेलवे लाइनों का निर्माण कराने का प्रयास किया।<sup>126</sup> परंतु यह देखा गया कि 100 पौंड प्रति मील रेलवे लाइन के हिसाब से अधिक सहायता देनी पड़ी और यह सहायता भी पूँजी आकर्षित करने के लिए

अपर्याप्त थी।<sup>127</sup> आखिरकार पुराने प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) व्याज संबंधी सविदाओं की भांति ही सुविधाएं देनी पड़ी। तथापि ये नई सविदाएं विशेष रूप से विनिमय दरो तथा व्यय पर सरकार के अपेक्षाकृत अच्छे नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय हितों के अनुकूल थे।<sup>128</sup>

प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) व्याज की सविदाओं में, जो 1849 और इसके बाद के वर्षों में की गईं, 1869 में संशोधन किए गए। भारत मंत्री आरगाइल ने रेलवे कंपनियों से एक संशोधित सविदा स्वीकार करने का आग्रह किया जिसके अनुसार भारत सरकार को अतिरिक्त शुद्ध लाभ का आधा भाग भविष्य में सदा मिलना था। उसने सोचा कि भारत सरकार की दृष्टि से यह अच्छा सौदा है अतः बदले में वह रेलवे कंपनियों को दो सुविधाएं देने के लिए तैयार हो गया। प्रथम प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) व्याज के निमित्त भारत सरकार द्वारा दो गईं अग्रिम राशियों का पूरा ऋण समाप्त कर दिया जाना था और कंपनी को यह ऋण नहीं चुकाना था। द्वितीय, आरगाइल ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार अगले 25 वर्षों में रेलवे लाइनों को नहीं खरीदेगी। अधिकांश रेलवे कंपनियों ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।<sup>129</sup> गवर्नर जनरल ने इस व्यवस्था पर अपनी सरकार का असंतोष व्यक्त करते हुए भारत मंत्री को लिखा।<sup>130</sup> मेयो ने आरगाइल से अपने एक निजी पत्र में शिकायत की, जिसमें उसने सरकारी पत्र व्यवहार की तुलना में अपने विचारों की अपेक्षाकृत अधिक खुले रूप में व्यक्त किया। उसने लिखा कि रेलवे कंपनियों के साथ हाल की व्यवस्था से 'न केवल हमारे करदाताओं पर अनावश्यक एवं भारी प्रभार आ जाएगा, बल्कि इससे भारी मात्रा में, ब्रिटिश पूंजी लगभग अनिश्चित काल के लिए भारत से बंध जाएगी'।<sup>131</sup> आरगाइल यद्यपि गारंटी प्रणाली के गंभीर दोषों से अनभिज्ञ नहीं था, तथापि उसका विचार था कि गारंटी प्रणाली का आंशिक रूप से बना रहना न्यायसंगत है।<sup>132</sup> उसे आशा थी कि जब रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यातायात से आय तथा शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी और इस लाभ के आधे भाग से भारत सरकार की उस हानि की क्षतिपूर्ति हो सकेगी जो, उसे रेलवे कंपनियों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि को छोड़ने से होगी।

(ग) गारंटी प्रणाली के बारे में भ्रम दूर हो जाने पर भारत सरकार ने उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक के अंतिम वर्षों में सरकारी रेल पथ प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय तक पहुंचने में सरकार ने काफी समय लगाया। यह नई दिशा में कार्य था। यह कोई अस्वाभाविक घात नहीं थी कि तत्कालीन लोककल्याणकारी विचारधारा के अगुआ लार्ड लारेंस ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। लैंग तथा फोर जैसे कुछ लोग थे जो रेलों के विकास के लिए सरकारी माध्यम की वनिस्वत निजी माध्यम को पसंद करते थे।<sup>133</sup> परंतु लोक निर्माण के बारे में माने गए विशेषज्ञों में से अधिकांश जैसे योर्नटन (इंडिया आफिस में लोक निर्माण विभाग का सर्वोच्च अधिकारी), चेजनी (लोक निर्माण विभाग का अकाउंटेंट जनरल), आ० स्ट्रैची (लोक निर्माण विभाग का सचिव) तथा लार्ड लारेंस निश्चित रूप से इस मत के थे कि सरकारी रेलपथ गारंटी व्यवस्था के अवगंत निर्मित रेलपथों से कहीं सस्ते-रहेगे और उनका

प्रशासन भी अच्छा रहेगा।<sup>131</sup> तथापि, प्रारंभ में इस विचार का कि 'रेलपथों के निर्माण में सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, विरोध था और लारेंस द्वारा 1867 में दिए गए सुझावों पर गृह अधिकारियों की अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं थी।<sup>132</sup> तत्कालीन भारत मंत्री नोर्थकोट प्रचलित व्यवस्था को बदलना नहीं चाहता था यद्यपि उसने स्वीकार किया कि अलाभकारी 'राजनीतिक' रेलवे लाइनों (अर्थात् जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थी) का निर्माण राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।<sup>133</sup> इसके कुछ समय बाद ही नोर्थकोट के पद पर आरगाइल और लारेंस के पद पर मेयो आए। सरकारी रेलपथों की योजना को आगे बढ़ाने में आरगाइल और मेयो में प्रतिस्पर्धा थी। आरगाइल ने मेयो को लिखा कि 'इस प्रणाली (गारंटी प्रणाली) के विरुद्ध जितने प्रबल मेरे विचार हैं उतने किसी दूसरे के नहीं हैं।' 'मैंने सरकार द्वारा सीधा निर्माण करने के प्रश्न को लारेंस द्वारा दिए गए समर्थन से बहुत पहले उठाया था...'।<sup>134</sup> आरगाइल ने सरकारी रेलपथों की अपनी योजना पर मतिपरिपद की स्वीकृति ले ली। मेयो भी विश्वास के साथ सरकारी निर्माण का समर्थन कर रहा था।<sup>135</sup> (उसने आरगाइल को लिखा) 'यह मान लेने के लिए कोई आधार नहीं है कि भारत सरकार उतना निर्माण कार्य नहीं कर सकती जिसके लिए पूंजी उपलब्ध हो सकती है और आय से व्याज दे सकना संभव है।<sup>136</sup> भारत सरकार ने शासकीय ढंग से पुनः सरकार द्वारा निर्माण का प्रश्न उठाया और इस बार उसकी दो रेलवे लाइनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति मिल गई।<sup>137</sup> सरकारी निर्माण के पक्ष में आरगाइल ने स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार किया था। (उसके शब्दों में) 'हम अपनी सीधी जमानत पर 4 प्रतिशत पर धन जुटा सकते हैं जबकि हम कंपनियों को 5 प्रतिशत की गारंटी देते हैं और इसके अलावा हम संभावित अतिरिक्त लाभ पर अपना दावा भी छोड़ देते हैं...' मैं देखना चाहता हूँ कि बड़ा रेल विभाग बनाया जाए, रेलपथों के निर्माण कार्य के लिए अलग से ऋण जुटाए जाएं, कुशल इंजीनियरों के दल के नियंत्रण में सविदा द्वारा धन का व्यय किया जाए और संचालकों आदि के द्वैध शासन को, जो केवल वही कार्य कर सकता है जो हम अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह करते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए।'<sup>138</sup> एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आरगाइल ने उठाई वह यह थी कि रेलवे कंपनियों द्वारा पूंजी जिस प्रकार जुटाई जाती थी, उससे केवल ब्रिटिश पूंजी का ही निवेश होता था और भारतीय पूंजी लगभग नहीं मिल पाती थी। (उसके ही शब्दों में) 'यदि हम भारत के मूल निवासियों को अपने ऋणों में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकें तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी। मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे लोक ऋण में इनका भाग अनवरत कम होता जा रहा है...' जहाँ तक रेलपथों के निमित्त लिए जाने वाले ऋणों का प्रश्न है 8 करोड़ के निवेश में हिंदुस्तानियों का भाग 10 लाख से अधिक नहीं है।<sup>139</sup> उसे आशा थी कि भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित ऋण की ओर भारतीय पूंजी आकृष्ट होगी। हाउस आफ लार्ड्स में अपने वित्त विवरण में आरगाइल ने कहा कि सरकारी माध्यम 'धन जुटाने और उसके व्यय की कम अपव्ययी रीति है।'<sup>140</sup> आरगाइल को जितना विरोध वास्तव में हुआ उससे कहीं अधिक विरोध की आशा थी। सरकारी रेलों के निर्माण संबंधी आयोजन



की प्रारंभिक अवस्था में उसने मेयो को इस संबंध में शांत रहने का सुझाव दिया था। (उसने लिखा 'इस समय इस मामले को बिल्कुल गोपनीय रखना ठीक रहेगा, क्योंकि इस प्रस्ताव से अनेक हित भयभीत हो उठेंगे।'<sup>144</sup>) परंतु उसकी कुशल युक्ति तथा एक व्यावहारिक उपाय के रूप में इस प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के कारण उसकी योजना सरलता से व्यवहार में आ सकी। अस्तु, अहस्तक्षेपी नीति का परित्याग कर दिया गया। 1872 में भारतीय वित्त के बारे में प्रवर समिति द्वारा जांच के समय किसी भी साक्षी ने रेल पथों के निर्माण में सरकार की सीधी भागीदारी के फायदों के विषय में शका प्रकट नहीं की।

क्षेत्रीय वित्तीयकरण, व्यापार की मात्रा में वृद्धि, उद्यम तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रोत्साहन, कीमत और मजदूरी पर प्रभाव, इत्यादि के रूप में रेलवे के विकास का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था। विलसन ने जो (इंडिया बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्य के रूप में तथा बाद में भारत में वित्त सदस्य के रूप में) रेलवे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने में सहायक था, घोषणा की कि 'इनके द्वारा जो लाभ मिलने चाहिए वे उससे कहीं अधिक हैं जो हमने अभी तक अनुभव किए हैं...'<sup>145</sup> जैसा कि हम देख चुके हैं कि वित्तीय दृष्टिकोण से गारंटी प्रणाली, जिसके अंतर्गत रेलों का निर्माण हुआ था, भारत सरकार को हानि देने वाला स्रोत थी। परंतु अधिकारी बर्गे जैसा कि हम स्पष्ट कर आए हैं तर्कसंत आशावाद के साथ उस समय की ओर दृष्टि लगाए थे, जबकि रेलवे से लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। यह आशा की जाती थी कि सरकार को लाभकारी रेलपथों से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार के लाभ होंगे। फ्रेनबोर्न ने जान लारेंस को लिखा था कि 'हर वर्ष इनमें (रेलवे में) अकारण विलंब हो रहा है। इसका प्रभाव यह है कि भविष्य का भारतीय वित्तदाता अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा बड़ी हुई आय से, जिसकी ओर खर्च में उत्तरोत्तर एवं अपरिहार्य वृद्धि पूरी करने के लिए उसकी दृष्टि होनी चाहिए, संक्षिप्त हो रहा है।'<sup>146</sup>

#### IV

1854 तक भारत में पृथक् लोक निर्माण विभाग नहीं था। लोक निर्माण और उसके अनुरक्षण के लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक सैन्य बोर्ड था जो निरीक्षण संस्था के रूप में कार्य करता था। यह व्यवस्था पर्याप्त थी क्योंकि अधिकांश लोक निर्माण पर व्यय यद्यपि बहुत थोड़ा होता था, तथापि यह सैन्य निर्माण के लिए किया जाता था। 1854 में डलहौजी के शासन काल में पृथक् लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। यही से परिवर्तन प्रारंभ हुआ। लोक निर्माण सैन्य बोर्ड के नियंत्रण से निकल जाने पर सिविल निर्माण अर्थात् असीनिक इमारत, सड़क, बाध, नहर तथा सिंचाई निर्माण की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया गया। 1849-50 में लोक निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि केवल 60 लाख रुपये थी। 1856-57 में लोकनिर्माण पर व्यय की राशि बढ़कर 2.25 करोड़ रुपये हो गई। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तगभग अपने संपूर्ण शासन काल में लोक निर्माण की उपेक्षा कर अंतिम तीन-चार वर्षों में इस दिशा में आकस्मिक ढंग से भारी कार्य किया।<sup>147</sup> कंपनी ने अपने उपनिवेश को ठीक उसी प्रकार समझा जैसे

कोई भी पूर्वी निरंकुश शासक अपनी रियासत को समझता था। कंपनी की दृष्टि में उप-निवेश विकसित करने के लिए न होकर शोषण करने के लिए होता था। पूर्वी निरंकुश शासक और कंपनी में एक ही आर्थिक अंतर था कि कंपनी रूपी यूरोपीय जमींदार अन्यत्रवासी था।<sup>148</sup>

सैन्य विद्रोह के समय उत्तरी भारत में रिकार्ड नष्ट हो जाने, प्रशासनिक नित्य-क्रम बिगड़ जाने, लेखे तैयार करने की ओर अपर्याप्त ध्यान दिए जाने के कारण 1857 और 1858 में लोक निर्माण पर होने वाले व्यय का सही अनुमान लगा सकना कठिन है। सैन्य विद्रोह के वर्ष और उसके तत्काल बाद की अवधि में असैनिक निर्माण परियोजनाओं में पूजी निवेश में भारी कमी कर दी गई। सातवें दशक में लोक निर्माण अनुदान धीरे-धीरे 1860-65 के औसत 4.3 करोड़ रुपये से बढ़कर दशक के उत्तरार्द्ध में 6.8 करोड़ रुपये हो गया। 1867-68 के बाद से लोक निर्माण पर आंशिक व्यय ऋणों से (जिन्हें 'साधारण व्यय' कहा जाता था) और दोप अंश सरकारी आय (जिन्हें 'साधारण व्यय' कहा जाता था) से किया जाता था। 1871-72 में लोक निर्माण पर प्रति व्यक्ति व्यय का काम-चलाऊ परिकलन संभव है क्योंकि इस वर्ष के लिए जनगणना पर आधारित जनानुसूची के कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। 'साधारण' लोक निर्माण पर प्रति व्यक्ति व्यय बंगाल (रु० 0.103), मद्रास (रु० 0.106) तथा पश्चिमोत्तर प्रांत (रु० 0.19) में बहुत कम था और पंजाब (रु० 0.34) तथा बंबई (रु० 0.53) में थोड़ा सा अधिक था।<sup>149</sup>

सरकार की लोक निर्माण नीति के विषय में राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं की मुख्य शिकायत यह थी कि गैर विकास व्यय में तो वृद्धि हो रही है और विकास के लिए व्यय किया जाने वाला राजस्व या तो स्थिर है या फिर घट रहा है। सरकार के राष्ट्रवादी अलोचकों ने मोटे और कामचलाऊ ढंग से सड़क, नहर, बाघ, एनीकट, बदरगाह इत्यादि पर हुए खर्च को विकास कार्यों पर व्यय माना है। इसके विपरीत सिविल इमारतों, जैसे अदालती इमारतें, जेल इत्यादि और सेना की बरतकें स्पष्टतः एक अलग श्रेणी में आती थी। हम आगे राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं के द्वारा गैर विकास व्यय के प्राक्कलनों के आधार पर इस की व्याख्या करेंगे। तथापि यह एक दिलचस्प बात है कि वायसराय तथा उसकी परिषद को भी इस बारे में संदेह था। भारत मंत्री को अपने एक प्रेषण में सपरिषद गवर्नर जनरल ने लिखा था कि छठे दशक के अंतिम वर्षों में हमारे सेना संबंधी निर्माण पर व्यय का अनुपात काफी बढ़ा है और यह व्यय ऐसा है जो राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से योग नहीं देता...।<sup>150</sup>

भारत की विस्तृत आवश्यकताओं को देखते हुए सड़क तथा सिंचाई निर्माण के लिए साधनों की अपर्याप्तता से एक ही सुझाव मिलता था कि राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए ऋण लिए जाने चाहिए। परंतु उन दिनों सरकार द्वारा ऋण लेने के विरुद्ध काफी पूर्वग्रह था। यह पूर्वग्रह सार्वजनिक और व्यक्तिगत उधार के बीच गलत समानता पर आधारित था। हेनरी फासट (जो कैब्रिज में राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर, और संसद सदस्य था तथा जिसकी रूढ़िवादी भावनाएं भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले पक्षधर के रूप में थी) का कथन विशिष्ट था, 'राज्य के साथ-साथ व्यक्ति के लिए भी सबसे बुरी

वात यह है कि वह अपने साधनों से अधिक व्यय करे और इस प्रकार अपने ऊपर ऋण का भार चढ़ा ले।<sup>151</sup> विक्टोरिया युग में रुढ़िवादी राजस्ववेत्ताओं का कहना था कि यदि सरकार ऋण लेने में ययासभव कमी नहीं करती तो 'सरकार के दिवालिपापन' का हीवा भयानक रूप से उपस्थित होगा।<sup>152</sup> लंदन मुद्रा बाजार में भारत सरकार जिन शर्तों पर ऋण ले सकती थी वे अनुकूल थीं और यदि ब्रिटिश सरकार की गारंटी होती तो शर्तें और भी अच्छी हो सकती थी। तर्क यह दिया गया कि जिस प्रकार किसी भी व्यापारिक इकाई अथवा व्यक्ति के लिए बाजार में अपना साख को प्रभावित किए बिना भारी मात्रा में ऋण लेना संभव नहीं है, उसी तरह सरकार के लिए भी इस प्रकार का जोखिम उठाए बिना भारी मात्रा में ऋण ले सकना संभव नहीं है। उस समय प्रचलित मत यह था कि सरकार को ऋण से ययासंभव वचना चाहिए। यदि ऋण लेना ही पड़े तो उनका केवल 'लाभकारी' सिंचाई निर्माण कार्यों के निमित्त प्रयोग होना चाहिए जिससे ध्याज की राशि निकाली जा सके।

यह दृष्टिकोण 1864-65 में भारत सरकार और भारत मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार से स्पष्ट है। अगस्त, 1864 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से सिंचाई-साधनों के निर्माण की ओर उससे कहीं अधिक ध्यान देने का आग्रह किया जितना उत्तर सैन्य-विद्रोह काल में, वित्त के अभाव के कारण संभव हो सका था। भारत मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह ऋण लेने के लिए भी तैयार रहे।<sup>153</sup> भारत सरकार ने चार या पांच करोड़ स्टर्लिंग का ऋण लेने की योजना प्रस्तुत की। यह संपूर्ण राशि कई वर्षों में प्राप्त की जानी थी और देश के विभिन्न भागों में सिंचाई परियोजनाओं के बीच वितरित होती थी।<sup>154</sup> इस योजना को भारत मंत्री की स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि इसमें प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर व्यय के सुनिश्चित प्रावकलन नहीं दिए गए थे और वस्तुतः यह सुझाव दिया गया था कि इंग्लैंड में भारी मात्रा में ऋण लेकर उन्हें भारत सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिए।<sup>155</sup> भारत मंत्री ने घोषणा की कि वह सिंचाई के छोटे निर्माण कार्यों के लिए जिन पर थोड़ा घन व्यय (30,000 पीड से कम) होना हो, अपनी स्वीकृति देने के लिए तत्पर है। अनुभव यह था कि सिंचाई की इन लघु परियोजनाओं से व्यय की गई राशि पर अच्छा प्रतिफल मिलता था। परंतु बड़ी परियोजनाएँ जिन्हें पूरा करने में कई वर्ष का समय लगता और जिन पर लागत भी अधिक आती, वित्तीय मामलों की पूरी जांच के बिना प्रारंभ नहीं की जानी थी। इस संबंध में भारत मंत्री ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत था कि 'सिंचाई के साधनों का निर्माण कार्य इस प्रकार से हो कि इनसे इतनी आय तो हो ही जाए जिससे इनके निर्माण पर व्यय की गई पूंजी पर दिए जाने वाले व्याज का भुगतान हो सके।' भारत की वर्तमान वित्तीय अवस्था में इन्हीं को ठीक से प्रारंभ किया जा सकता है। भारत मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार की यह सोचने में भूल थी कि सिंचाई के साधनों के निर्माण के लिए वित्तीय साधन जुटाने की समस्या का सरल समाधान ऋण लेना है। गृह अधिकारियों को कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक था जैसे व्याज प्रभार की मात्रा तथा लंदन मुद्रा बाजार की अवस्था। एक अनिश्चयात्मक टिप्पणी के साथ

अपने प्रेषण को भारत मंत्री ने इस प्रकार समाप्त किया, 'मैं यह कहने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं हूँ कि इस अपेक्षित व्यय के एक अंग के निमित्त साधनों की व्यवस्था करने के लिए और अधिक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। परंतु इस समय यह निर्धारित कर सकना हर प्रकार असंभव है कि अंततोगत्वा कितनी राशि ऋण के रूप में ली जा सकेगी अथवा इसकी आवश्यकता कब होगी। मैं निश्चित रूप से न तो यह समझता हूँ कि इस समय मेरे द्वारा कोई भारी ऋण लिया जाना युक्तिसंगत होगा, और न ही मैं यह घोषणा करने के लिए तैयार हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में मैं ऋण लूंगा...'।

ये उद्धरण सरकार द्वारा ऋण लेने के प्रश्न पर गृह अधिकारियों के अनिश्चयात्मक तथा आवश्यकता से अधिक सतर्क दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। 1865-66 के दुर्भिक्ष से, जो उडोसा में बहुत गंभीर था, भारी आकस्मिक आघात पहुँचा। भारत मंत्री फ्रेनबोर्न ने वायसराय जान लारेंस को लिखा कि 'मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस दुर्भिक्ष से अधिकांश लोगों की समझ में यह तथ्य आ गया होगा कि इन अधिकांश निर्माण कार्यों में विलंब का अर्थ भारी मध्या में लोगों के जीवन और उनकी उत्पादन शक्ति की समय-समय पर हानि है।' <sup>156</sup> 'फ्रेनबोर्न ने लारेंस से भारत को सिचाई की सुविधाएं प्रदान करने और लोक निर्माण विभाग में अपनी 'समग्र शक्ति लगा देने' के लिए कहा। सड़क तथा सैन्य निर्माण के मुकाबले सिचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी उतनी अधिक और तत्काल आवश्यकता नहीं है जितनी कि सिचाई की है। सरकार यूरोपीय सैनिकों के लिए बैरकों के निर्माण पर भारी धनराशि व्यय कर रही थी जबकि सिचाई निर्माण कार्यों के लिए घनाभाव था। फ्रेनबोर्न ने कहा कि 'भारी संख्या में लोगों के जीवन की तुलना में अथवा, अधिक से अधिक यदि यह भी मान लिया जाए कि कई वर्षों तक कोई दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा तो भी, भूमि पर खेती की अत्यावश्यक अनिवार्यताओं की तुलना में सैनिकों के आराम को प्राथमिकता देना अन्यायपूर्ण है।'।

1866 से गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। चूकि सिचाई का 'भारत की प्रगति के लिए भारी महत्व था', अतः अगस्त, 1866 में भारत मंत्री ने उत्पादक निर्माण कार्यों के निमित्त ऋण लेने के लिए तत्परता दिखाई। <sup>157</sup> 1867-68 में भारत सरकार ने लोक निर्माण पर व्यय के लिए ऋण लेने का प्रस्ताव रखा और इस पर इंडिया आफिस ने अपनी अविलंब स्वीकृति दे दी। <sup>158</sup> फ्रेनबोर्न ने समझा कि 'विकास का प्रतिस्थापन कर उधार से बचने के लिए प्रयास' की तुलना में सिचाई के साधनों के निर्माण के लिए ऋण लेना कहीं अधिक 'सच्ची बचत' है। <sup>159</sup>

भारत सरकार ने गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन का आभास पाकर प्रस्ताव रखा कि भविष्य में सिचाई के साधनों के निर्माण पर समस्त व्यय ऋणों से पूरा किया जाना चाहिए। भारत सरकार का प्रस्ताव था कि पुनरुत्पादी सिचाई परियोजनाओं पर होने वाला व्यय चालू आय-व्यय वाले वजट में नहीं दिखाया जाएगा। चूकि ये खर्च ऋण लेकर किए जाएंगे, अतः इन्हे पूंजीगत खर्चों के रूप में लिया जाएगा और केवल व्याज को वजट में दिखाया जाएगा। इसके अलावा सैनिकों के लिए बैरक, जेल, सड़क इत्यादि विशिष्ट लोक निर्माण कार्यों पर भारी व्यय को असाधारण प्रभार के नाम से

दिखाया जाएगा जिसका एक अंश राजस्व से और दूसरा ऋणों से पूरा किया जाएगा।<sup>160</sup>

भारत मंत्री इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका। उसका विचार था कि सिचाई के साधनों के निर्माण पर होने वाले व्यय को आय-व्यय लेख से हटाकर ऋण में दिखाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। उसने भारत सरकार को आदेश दिया कि वह सिचाई के साधनों के निर्माण पर होने वाले व्यय को अपने वार्षिक वित्तीय तलपट (बैलेंस शीट) में ट्रंक सड़कों, सैनिकों के लिए बैरकों इत्यादि पर 'असाधारण' प्रभारों के साथ ही 'असाधारण' प्रभार के रूप में दिखाए।<sup>161</sup> बाद में एक महत्वपूर्ण विषय पर क्रेनबोर्न का यह निर्णय उसके उत्तराधिकारी नोर्थकोट के द्वारा बदल दिया गया। नोर्थकोट का मत<sup>162</sup> था कि 'सामान्यतः उन निर्माण कार्यों को छोड़कर जिनके प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकने की आशा हो, सभी निर्माण कार्य 'साधारण' माने जाने चाहिए। तात्पर्य यह कि ये अपनी लागत पर ब्याज के बाद लाभ देने में समर्थ होने चाहिए...। चूंकि सैनिक बैरक सड़क, बांध और जेल लाभकारी श्रेणी में नहीं रखी जा सकती अतः ये सभी 'असाधारण' लोक निर्माण की श्रेणी से अलग कर दिए गए। इन निर्माण कार्यों (सैन्य निर्माण, सड़क, जेल इत्यादि) पर व्यय वार्षिक आय से ही करना आवश्यक कर दिया गया। केवल सिचाई के साधनों का निर्माण ऋण लेकर किया जा सकता था और इसे बजट में असाधारण लोक निर्माण के रूप में दिखाना था।<sup>163</sup>

अतः, अंत में यह निर्णय हुआ कि (क) 'असाधारण निर्माण कार्य' नामक श्रेणी में आने वाले 'पुनर्स्थापना' अथवा लाभकारी सिचाई के साधनों के निर्माण के लिए सरकार ऋण ले सकती है; (ख) और 'साधारण निर्माण' नामक श्रेणी में आने वाले अलाभकारी निर्माण जैसे, सैन्य निर्माण, सड़क, जेल, बांधों इत्यादि के लिए सरकार सामान्यतः ऋण नहीं ले सकती है। अलाभकारी निर्माण के निमित्त लिए जाने वाले ऋणों का एकमात्र उदाहरण 1867-68 का सैनिक बैरकों के निर्माण के लिए लिया गया 10 लाख पौंड का ऋण था।<sup>164</sup>

1867 में लोक निर्माण विभाग की नवीन स्थापित सिचाई शाखा के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कर्नेल रिचर्ड स्ट्रैची की नियुक्ति हुई।<sup>165</sup> उसके अनुरोध पर 1869 में भारत मंत्री के पास भारत सरकार ने अगले वर्षों में कम से कम 30 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय की एक योजना भेजी। यह संपूर्ण राशि ऋणों के द्वारा जुटाई जानी थी और सिचाई के साधनों के निर्माण पर व्यय की जानी थी।<sup>166</sup> यह वस्तुतः सामान्य प्रावकलन था क्योंकि गवर्नर जनरल मेयो अपनी सरकार को भारी ब्याज प्रभार से लज्जास्पद उत्पन्न में नहीं डालना चाहता था।<sup>167</sup> भारत मंत्री ने मेयो को सतर्क किया कि वह लागत और लाभप्रदता के आंकड़ों के बिना बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण प्रारंभ न करें।<sup>168</sup> आरगाइल नई सिचाई परियोजनाओं में बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता था, परंतु वह यह अवश्य चाहता था कि भारत सरकार तुलनात्मक रूप से कम खर्चों और लाभकारी निर्माण कार्य करे।<sup>169</sup> उसने मेयो को साधारण लोक निर्माण पर व्यय में कमी करने की राय दी, क्योंकि 'असाधारण' निर्माण पर व्यय में वृद्धि हो रही थी।<sup>170</sup> सरकार ने इस नीति का पालन किया यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि साधारण

लोक निर्माण पर व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात जो 1868-69 में 12.3 प्रतिशत था, 1869-70 में 10 प्रतिशत, 1870-71 में 8.2 प्रतिशत और 1871-72 में केवल 5.3 प्रतिशत रह गया।

लोक निर्माण विभाग में अपव्यय के कारण साधनों का अभाव बढ़ गया। 'दि फ्रैंड आफ इंडिया' में इस विभाग की तुलना ऐसे सड़े हुए नगर से की थी जो किसी प्रकार सुधार से बच गया था। हिंदुस्तानियों द्वारा निकाले जाने वाले देशी भाषाओं के समाचार पत्रों की शिकायत थी कि भारत सरकार और करदाताओं को अपने धन का उचित प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। आक्षेप यह था कि लोक निर्माण की धनराशि का बड़ा भाग अपव्यय के कारण नष्ट हो रहा है।<sup>171</sup> नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार, ठेकों के विवर्णन में भ्रष्टता तथा यूरोपीय इंजीनियरों द्वारा सापरवाही के साथ निरीक्षण के आरोप थे।<sup>172</sup> 1871 में जब ईस्ट इंडिया वित्त प्रवर समिति ने अपनी जांच प्रारंभ की तो समिति का ध्यान इस समस्या की ओर आकृषित करने के लिए बंबई एसोसिएशन की ओर से प्रतिवेदन दिए गए।<sup>173</sup> सातवें दशक की समाप्ति के आसपास अपव्यय रोकने के लिए जोरदार प्रयत्न किए गए। धन की अधिक बरबादी बिना पर्याप्त सर्वेक्षण तथा बिना आकड़े एकत्र किए ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर देने से होती थी।<sup>174</sup> सितम्बर, 1869 में एक प्रस्ताव में सपरिषद गवर्नर जनरल ने चिंता के साथ उल्लेख किया कि बिना स्वीकृति के अनियमित व्यय बढ़ गया है। सरकार ने अफसरों को आदेश दिया कि वे प्राक्कलनों की स्वीकृति के बिना अथवा पहले विनियोजन का प्रबंध किए बिना निर्माण कार्य प्रारंभ न करें।<sup>175</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में स्थापन खर्च इंग्लैंड की बनिस्वत चार-पाच गुना था। ऐसा मुख्यतः असेनिक निर्माण कार्यों के लिए ऊँचे वेतन पाने वाले सेना के अफसरों की नियुक्ति तथा निरीक्षणात्मक कार्यों के लिए, जिन्हें मातहत कर्मचारी भी कर सकते थे, यूरोपीय लोगों की नियुक्ति के कारण था।<sup>176</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में एक औसत वर्ष का स्थापन खर्च लोक निर्माण (साधारण) पर कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक था।

सैन्य विद्रोह के वर्ष से 1859-60 तक सैन्य निर्माण पर व्यय जो बैसे भी अधिक रहता था, असाधारण रूप से अधिक था। 1860 से 1865 तक औसत वार्षिक व्यय लगभग 0.72 करोड़ रुपये था जो अपेक्षाकृत कम था। दशक के उत्तरार्द्ध में सैन्य निर्माण पर औसत वार्षिक व्यय 1.59 करोड़ रुपये था। इस व्यय में आंशिक वृद्धि तो संपूर्ण भारत में सामरिक महत्व के स्थानों पर सेना की बैरकों के निर्माण से संबंधित योजना के कार्यान्वयन के कारण थी। सेना के स्वास्थ्य से संबंधित शाही आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1865 में यूरोपीय सैनिकों के लिए नई बैरकों का निर्माण करने का निश्चय किया।<sup>177</sup> सैन्य विद्रोह के बाद भारतीय सेना में भारी अनुपात में यूरोपीय सैनिकों को रखने के निर्णय (हिंदुस्तानी सैनिकों के द्वारा एक दूसरे विद्रोह के विरुद्ध रक्षोपाय की दृष्टि से) के फलस्वरूप उनके लिए नई बैरकों का निर्माण आवश्यक हो गया। उस समय सफाई की धुन के कारण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा का स्तर ऊँचा हो गया था



प्रश्न यह था कि 'क्या विशिष्ट एवं अस्थाई कराधान किया जाना चाहिए... अथवा भार अगली पीढ़ियों के साथ बांटा जाना चाहिए। दूसरा तरीका अपेक्षाकृत अच्छा था क्योंकि केवल सैन्य निर्माण से ही बजट में घाटा रहता था।'<sup>185</sup>

भारत सरकार ने एक अन्य सुझाव दिया। प्रस्ताव यह था कि सेना के लिए बैरक सहित सभी लोक निर्माण पर भारी व्यय को लेखे में 'असाधारण' प्रभार के नाम से दिखाया जाए और इन्हें पूजीगत प्रभार माना जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि असाधारण प्रभार को वार्षिक आय-व्यय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें रोकड़ धन के विवरण में अलग से ऋण के रूप में दिखाया जाना चाहिए।<sup>186</sup>

1867 में आखिरकार भारत मंत्री को 10 लाख पाँड का ऋण प्राप्त करने के लिए राजी किया गया। परंतु भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर कि अगले दो वर्षों में भी इतनी ही राशि के और ऋण लिए जाएं, फ्रेनबोर्न ने अपनी सरकार की ओर से कोई वचन नहीं दिया।<sup>187</sup> भारत मंत्री, फ्रेनबोर्न 'असाधारण प्रभार' को चालू लेखे से हटाकर ऋण में रखने के लिए भी सहमत हो गया। उसने यह भी मान लिया कि सेना के लिए बैरकों के निर्माण पर खर्च 'असाधारण प्रभार' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।<sup>188</sup>

तथापि बाद में इन दोनों ही निर्णयों में थोड़ा सा संशोधन किया गया। इंडिया आफिस में फ्रेनबोर्न के उत्तराधिकारी नोर्थकोट ने आदेश दिया कि सैन्य निर्माण कार्यों पर खर्च 'असाधारण' प्रभार की श्रेणी से निकाल दिए जाने चाहिए। केवल सिचाई के साधनों के निर्माण को चालू लेखे से हटाकर ऋण में रखना होगा। उसका मत था कि प्रत्येक वर्ष की आय से लोक निर्माण के लिए धन की व्यवस्था में अनुचित रूप से कमी करके बैरकों तथा अन्य अलाभकर निर्माण कार्यों पर व्यय को अलग करने का उद्देश्य भारत सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गलत धारणाओं को प्रोत्साहन देना था।<sup>189</sup> अतः भारत सरकार ने सैन्य निर्माण कार्यों (सड़क, बाघ इत्यादि) पर खर्चों को 'असाधारण प्रभार' की श्रेणी से 'साधारण प्रभार' (अर्थात् वे खर्च जो चालू आय से किए जाने चाहिए) की श्रेणी में रख दिया।<sup>190</sup> इसके अलावा भारत मंत्री के आदेश पर वित्त सदस्य डब्ल्यू. एन. मैसी ने भारत सरकार की ओर से घोषणा की कि बैरकों के निर्माण के लिए व्यय चालू आय से किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए और अधिक ऋण नहीं लिए जाएंगे।

गवर्नर जनरल की परिपद के अनेक सदस्यों ने जिनमें सेना संबंधी मामलों का सदस्य और सेनाध्यक्ष भी थे, नीति में उलटाव का विरोध किया। सर डब्ल्यू. आर. मैसफील्ड ने कहा कि अधिकारी समय के विपरीत चल रहे हैं क्योंकि यदि सैन्य निर्माण पर व्यय ऋण से न करके चालू आय से किया जाना है तो विकास पर व्यय में कमी करनी होगी। ऋण लेने के विषय में इंकार करके सरकार अप्रचलित नीति को पुनः अपना रही थी जिसका अर्थ निर्माण कार्यों में विलंब था।<sup>191</sup> मेजर जनरल एच. एम. ड्यूरेण्ड ने स्पष्ट किया कि नोर्थकोट के 'घोर पश्चयामी' निर्णय ने सरकार को अलोकप्रिय व्यवसाय कर की जिसे लाइसेंस अथवा सर्टिफिकेट कर कहा जाता था, बनाए रखने के लिए बाध्य किया। भारत सरकार ब्रिटिश पूंजी के स्वतंत्र एवं स्वस्थ प्रवाह को रोक



और सुख साधनों के बारे में आशाएं काफी बढ़ गई थीं। परंतु आधुनिक आधार पर सेना के लिए इमारतों का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना बहुत खर्चीला था। गृह अधिकारियों की ओर से तर्क दिया गया था कि 'इन उपायों को करने के लिए यदि सेना के कल्याण की स्वाभाविक इच्छा पर्याप्त कारण न हो तो भी यूरोपीय सैनिकों की कार्यक्षमता की अवस्था में वृद्धि से सरकार को जो आर्थिक लाभ होगा उससे इस बढ़े हुए खर्च को अच्छी तरह युक्तिसंगत सिद्ध किया जा सकता है।'<sup>178</sup> इन बैरकों के निर्माण की लागत का मूल प्राक्कलन 1 करोड़ पौंड था।<sup>179</sup> बाद में प्राक्कलन में संशोधन करके लागत बढ़ाकर 1 करोड़ 13 लाख 10 हजार पौंड कर दी गई। यह संपूर्ण व्यय पांच वर्षों (1865-66 से 1869-70) में किया जाना था।<sup>180</sup> यह उस सरकार पर काफी भार था जिसके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रायः साधन जुटा पाना कठिन होता था। सितंबर, 1868 में सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री को लिखा, 'यदि सैन्य निर्माण पर व्यय को निकाल दिया जाए तो अन्य साधारण लोक निर्माण जैसे सड़क, संचार साधन, सार्वजनिक इमारत इत्यादि पर व्यय में वृद्धि होने के स्थान पर उसमें भारी कमी हुई है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमें इन पर व्यय में कटौती करनी पड़ी है...'। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि व्यय की इस प्रवृत्ति से देश के सामान्य विकास में कोई योगदान नहीं मिला है।<sup>181</sup> इस तथ्य ने सरकार को आलोचना का काफी शिकार बना दिया। भारतीय समाचार पत्रों ने इस संबंध में शिकायत की कि यूरोपीय सैनिकों को आराम तथा विलासिता की सुविधाएं देने के लिए भारी धनराशि व्यय की जाती है जबकि लोकोपयोगी निर्माण के लिए धन का अभाव बनाए रखा जाता है।<sup>182</sup>

सरकार की आय का अपेक्षाकृत बड़ा अनुपात विकास कार्यों जैसे सड़क, नहर तथा लोकोपयोगी निर्माण पर लगाया जाना संभव हो सके; इस दृष्टि से सुझाव दिया गया कि सैन्य निर्माण पर व्यय को श्रृंखण लेकर पूरा किया जाए। यह प्रश्न कि क्या सैनिक बैरकों के निर्माण के लिए सरकार को श्रृंखण लेना चाहिए, गंभीर विवाद का विषय बन गया।

जनवरी, 1865 में भारत सरकार ने भारत मंत्री को एक गोपनीय पत्र में लिखा कि अर्सेनिक लोक निर्माण, तथा पुराने अर्सेनिक एवं सैन्य निर्माणों की देखभाल तथा मरम्मत और रेलों पर व्यय के ऊपर सैनिक बैरकों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय का भार असह्य है। कराधान में वृद्धि किए बिना चालू आय से इन सब के लिए व्यवस्था कर पाना अमंभव है। परंतु कराधान में वृद्धि से लोगों की संपन्नता एवं संतुष्टि में बाधा है।<sup>183</sup> और वर्तमान पीढ़ी पर इन निर्माण कार्यों का संपूर्ण भार डाल देना अन्यायपूर्ण है, जो भावी पीढ़ियों के लिए भी है।

भारत सरकार ने अनेक बार यह सुझाव दिया कि भारत मंत्री को श्रृंखण लेना चाहिए और सेना के लिए बैरकों की लागत का एक अंश श्रृंखण से और दोष चालू आय से पूरा करना चाहिए।<sup>184</sup> 1865-66 में तीन बार भारत मंत्री से सैन्य निर्माण के लिए लगातार तीन वर्षों तक वार्षिक श्रृंखण द्वारा 30 लाख पौंड जुटाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्न यह था कि 'क्या विशिष्ट एवं अस्थाई कराधान किया जाना चाहिए...' अथवा भार अगली पीढ़ियों के साथ बाँटा जाना चाहिए। दूसरा तरीका अपेक्षाकृत अच्छा था क्योंकि केवल सैन्य निर्माण से ही बजट में घाटा रहता था।<sup>185</sup>

भारत सरकार ने एक अन्य सुझाव दिया। प्रस्ताव यह था कि सेना के लिए बैरक सहित सभी लोक निर्माण पर भारी ध्यय को लेखे में 'असाधारण' प्रभार के नाम से दिखाया जाए और इन्हें पूँजीगत प्रभार माना जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि असाधारण प्रभार को वार्षिक आय-व्यय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें रोकड़ दोष के विवरण में अलग से ऋण के रूप में दिखाया जाना चाहिए।<sup>186</sup>

1867 में आखिरकार भारत मंत्री को 10 लाख पाँड का ऋण प्राप्त करने के लिए राजी किया गया। परंतु भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर कि अगले दो वर्षों में भी इतनी ही राशि के और ऋण लिए जाएं, फ्रेनबोर्न ने अपनी सरकार की ओर से कोई वचन नहीं दिया।<sup>187</sup> भारत मंत्री, फ्रेनबोर्न 'असाधारण प्रभार' को चालू लेखे से हटाकर ऋण में रखने के लिए भी सहमत हो गया। उसने यह भी मान लिया कि सेना के लिए बैरकों के निर्माण पर खर्च 'असाधारण प्रभार' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।<sup>188</sup>

तथापि बाद में इन दोनों ही निर्णयों में जोड़ा सा संशोधन किया गया। इंडिया आफिस में फ्रेनबोर्न के उत्तराधिकारी नोर्थकोट ने आदेश दिया कि सैन्य निर्माण कार्यों पर खर्च 'असाधारण' प्रभार की श्रेणी से निकाल दिए जाने चाहिए। केवल सिचाई के साधनों के निर्माण को चालू लेखे से हटाकर ऋण में रखना होगा। उसका मत था कि प्रत्येक वर्ष की आय से लोक निर्माण के लिए धन की व्यवस्था में अनुचित रूप से कमी करके बैरकों तथा अन्य अलाभकर निर्माण कार्यों पर व्यय को अलग करने का उद्देश्य भारत सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गलत धारणाओं को प्रोत्साहन देना था।<sup>189</sup> अतः भारत सरकार ने सैन्य निर्माण कार्यों (सड़क, बांध इत्यादि) पर खर्चों को 'असाधारण प्रभार' की श्रेणी से 'साधारण प्रभार' (अर्थात् वे खर्च जो चालू आय से किए जाने चाहिए) की श्रेणी में रख दिया।<sup>190</sup> इसके अलावा भारत मंत्री के आदेश पर वित्त सदस्य डब्ल्यू० एन० मैसी ने भारत सरकार की ओर से घोषणा की कि बैरकों के निर्माण के लिए व्यय चालू आय से किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए और अधिक ऋण नहीं लिए जाएंगे।

गवर्नर जनरल की परिपद के अनेक सदस्यों ने जिनमें सेना संबंधी मामलों का सदस्य और सेनाध्यक्ष भी थे, नीति में उलटाव का विरोध किया। सर डब्ल्यू० आर० मैसफील्ड ने कहा कि अधिकारी समय के विपरीत चल रहे हैं क्योंकि यदि सैन्य निर्माण पर ध्यय ऋण से न करके चालू आय से किया जाना है तो विकास पर व्यय में कमी करनी होगी। ऋण लेने के विषय में इंकार करके सरकार अप्रचलित नीति को पुनः अपना रही थी जिसका अर्थ निर्माण कार्य में विलंब था।<sup>191</sup> मेजर जनरल एच० एम० ड्यूरेण्ड ने स्पष्ट किया कि नोर्थकोट के 'घोर पश्चगामी' निर्णय ने सरकार को अलोकप्रिय व्यवसाय कर को जिसे लाइसेंस अथवा सर्टिफिकेट कर कहा जाता था, बनाए रखने के लिए बाध्य किया। भारत सरकार ब्रिटिश पूँजी के स्वतंत्र एवं स्वस्थ प्रवाह को रोक

और सुख साधनों के बारे में आशाएं काफी बढ़ गई थीं। परंतु आधुनिक आधार पर के लिए इमारतों का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना बहुत खर्चीला था। अधिकारियों की ओर से तर्क दिया गया था कि 'इन उपायों को करने के लिए यदि सैन्य-कल्याण की स्वाभाविक इच्छा पर्याप्त कारण न हो तो भी यूरोपीय सैनिकों की कार्यक्षमता की अवस्था में वृद्धि से सरकार को जो आर्थिक लाभ होगा उससे इस बढ़े हुए खर्च को अच्छी तरह युक्तिसंगत सिद्ध किया जा सकता है।<sup>179</sup> इन बैरकों के निर्माण की लागत का मूल प्राक्कलन 1 करोड़ पाँड था।<sup>179</sup> बाद में प्राक्कलन में संशोधन करके लागत बढ़ाकर 1 करोड़ 13 लाख 10 हजार पाँड कर दी गई। यह संपूर्ण व्यय पांच वर्षों (1865-66 से 1869-70) में किया जाना था।<sup>180</sup> यह उस सरकार पर काफी भार था जिसके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रायः साधन जुटा कठिन होता था। सितंबर, 1868 में सपरिपद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री को लिख 'यदि सैन्य निर्माण पर व्यय को निकाल दिया जाए तो अन्य साधारण लोक निर्माण सड़क, संचार साधन, सार्वजनिक इमारत इत्यादि पर व्यय में वृद्धि होने के स्थान पर उसमें भारी कमी हुई है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमें इन पर व्यय में घट करनी पड़ी है...'। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि व्यय की इस प्रवृत्ति के सामान्य विकास में कोई योगदान नहीं मिला है।<sup>181</sup> इस तथ्य ने सरकार को चिन्ता का काफी शिकार बना दिया। भारतीय समाचार पत्रों की कि यूरोपीय सैनिकों को आराम तथा विलासिता व धनराशि व्यय की जाती है जबकि लोकोपयोगी निर्माण रखा जाता है।<sup>182</sup>

अनुपस्थिति भत्ते सम्मिलित थे। जिस अवधि का हमने अध्ययन किया है उसमें असैनिक खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसका एक कारण जिसका हम पहले भी कई बार उल्लेख कर चुके हैं, भारत में कीमत और मजदूरी में सामान्य वृद्धि थी। दूसरा कारण प्रशासन में सुधार की मांग था। 'आधुनिक धारणाओं के अनुरूप महान सभ्य प्रशासन के 'सभी उपकरणों' की व्यवस्था करनी थी।<sup>197</sup> अतः एक ओर तो नए विभाग खोले गए, पुराने स्थापनों का विस्तार किया गया, सेवा की शाखाओं का पुनर्गठन एवं विकास किया गया और दूसरी ओर पुराने वेतनमानों में संशोधन किए गए, अफसरों (विशेष रूप से यूरोपीय अफसरों) की सुविधाएं बढ़ा दी गईं और कीमत तथा मजदूरी में वृद्धि के कारण अनेक नए पदों किए गए।

हिंदुस्तानी न्यायाधीशों तथा न्यायालयों में काम करने वाले मातहत हिंदुस्तानी अधिकारियों को बहुत थोड़ा वेतन मिलता था। औसत वेतन 250 रुपये वार्षिक से कम था और सबसे अधिक वेतन पाने वाले अफसरों को केवल 1800 रुपये प्रति वर्ष मिलता था। लारेंस के चायसराय काल में पहले बंगाल प्रेसीडेंसी में और फिर अन्य प्रांतों में न्यायिक सेवा में वेतनों में संशोधन हुआ। यह जान स्टूची की सहायता से (जिसने मामले की जांच कर वेतनों में वृद्धि की सिफारिश की थी) लारेंस द्वारा किए जाने वाले विविध उपायों में से एक था।<sup>198</sup> गैर अनुबंधित न्यायिक सेवाओं के वेतनों में वृद्धि से सभी गैर अनुबंधित कर्मचारियों के वेतनों में उसी प्रकार के संशोधन करने पड़े। समाचार पत्रों में इस प्रकार खबर थी कि मुद्रा की श्रय शक्ति में तेजी से कमी होने के कारण गैर अनुबंधित कर्मचारियों को भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है।<sup>199</sup> गैर अनुबंधित अफसरों ने सरकार को यह बताते हुए याचिका (अर्जी) भेजी कि योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की दृष्टि से वेतनमान तथा पेंशन कम है, विशेष रूप से उस समय जबकि भारत में लाभप्रद रोजगार के विविध क्षेत्र खुल रहे हैं।<sup>200</sup> सरकार इस बात से पूरी तरह परिचित थी कि वेतन का प्रश्न 'मजदूरी बाजार की वास्तविकताओं' के संदर्भ के बिना केवल पूर्वोदाहरणों के आधार पर तय नहीं हो सकता।<sup>201</sup> इस बात पर ध्यान दिया गया था कि अनेक योग्य अफसर सरकारी नौकरी छोड़कर वाणिज्यिक फर्मों तथा बैंकों में जा रहे थे।<sup>202</sup> यथार्थ में, 1863 से बंबई सरकार 200 रुपये से कम पाने वाले अफसरों को 'खाद्यान्न भत्ता' दे रही थी। जिसे आजकल महंगाई भत्ता कहा जाता है, संभवतः यह उसका सबसे पहला उदाहरण है।<sup>203</sup> 1865 से 1867 तक लगातार कई संशोधनों के द्वारा देश के लगभग सभी भागों में सिविल मातहत कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि हो गई।<sup>204</sup>

गैर अनुबंधित सिविल सेवाओं में भारी संख्या में यूरोपीय तथा यूरेशियाई लोग लगे हुए थे। ये पेंशन तथा अवकाश भत्ता मांगते थे जिससे सरकार का खर्च बहुत हो जाता था।<sup>205</sup> भारत मंत्री 'गैर अनुबंधित सेवा के विकास को जिसमें सभी ऊंचे पदों को अंग्रेजों ने हथिया लिया था' रोकना चाहता था। 1868 के एक सर्वेक्षण के अनुसार (सिविल प्रशासन में) सरकारी पदों पर 100 रुपये से अधिक पाने वाले भारतीयों की संख्या केवल 4,039 थी। इनमें से अधिकांश (3,898) को 500 रुपये अथवा उससे कम मिलता

उम समय ऐसा करती है जब ब्रिटिश कर भारत की सामान्य प्रगति को रोकती है... वा खोज में है।<sup>192</sup>

पूँजी सुरक्षित एवं लाभकारी निवेश के अवसर की स्ट्रैची और डब्ल्यू० एन० मैसी ने गवर्नर जनरल लारेंस, गृह सदस्य जानक्या। लारेंस का विचार था कि ऋण नोर्थकोट के निर्णय का समर्थन करने का प्रयास है।<sup>193</sup> जान स्ट्रैची इस मत से सहमत लेने के लिए बाध्य होना निस्संदेह बड़ी बुरी बात लिए सरकार उसी अवस्था में ऋण ले था। अलाभकारी निर्माणों जैसे बैरक इत्यादि को पूरा कर पाना असंभव हो अन्यथा सकती थी जब चालू वर्ष की आय से इन पर व्यय। ड्यूरेड तथा मीमफील्ड ने विसम्मति नहीं।<sup>194</sup> यह विचारधारा अंत में स्वीकार की गई। अनुसार वे उसी सरकार के सदस्य टिप्पणी लिखी, परंतु मंत्रि परिषद के सिद्धांतों के रोध प्रकट नहीं कर सकते थे।<sup>195</sup> होने के नाते भारत की जनता के सामने अपना वि. मैन्य निर्माण पर व्यय जहां तक संभव

संक्षेप में, भारत सरकार की नीति थी कि से अधिक ऋण न लिया जाए जिसके हो चालू वर्ष की आय से ही किया जाए और उ. न ऋण, चालू वर्ष की आय से ही इन बिना काम चला पाना संभव न हो। 1867-68 में नोर्थकोट क्रेनबोर्न की भांति इस खर्चों को पूरा करने के सिद्धांत से थोड़ा विचलन कि वह भारत सरकार को लाभकारी नियम को ढीला करने के लिए तत्पर नहीं था क्योंकि दे पाने में समर्थ रहेगे) के अलावा सिंचाई निर्माण कार्यों (जो लगाई गई पूँजी पर व्यय देने के लिए अनिच्छुक था। अतः, किसी अन्य बात के लिए ऋण लेने की अनुमति के लिए पूर्ण रूप से चालू वर्ष की आय 1868-69 से सरकार सैन्य निर्माण पर व्यय करने 1868 के प्रेषण में स्पष्ट किया है कि पर ही निर्भर रही। जैसा कि भारत सरकार ने कर तथा आय कर के रूप में विभिन्न इस स्थिति के कारण उसे लाइसेंस कर, सर्टिफिकेट डा था। इसी प्रेषण में परिषद गवर्नर प्रकार के प्रत्यक्ष कर लगाने के लिए विवश होना प. ऊपर से देखने पर यह लग सकता है जनरल ने असामान्य स्पष्टता के साथ लिखा था, भी उतना ही कर रहे हैं जितना पहले कि हम देश में सामान्य विकास करने के लिए अब छ वर्षों में सेना पर व्यय का अनुपात कभी कर रहे थे। परंतु वास्तव में... हाल के कु बढाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं बहुत बढ गया है। यह व्यय राष्ट्र की संपत्ति को है...।<sup>196</sup>

## V

दिखाई जाने वाली प्रमुख मद्दों का

इस अध्याय के प्रारंभ में लेख के व्यय पक्ष में खर्च भारत सरकार के कुल व्यय के पुनरीक्षण करते हुए हमने देखा था कि सेना पर लगभग 15 प्रतिशत थे। तात्पर्य यह है लगभग एक तिहाई और लोक निर्माण पर व्यय लर था। सिविल प्रशासन पर व्यय भी कि लगभग आधा व्यय सेना और लोक निर्माण प्रवृद्धित तथा गैर अनुवृद्धित सरकारी कुल व्यय का एक तिहाई था। इस श्रेणी में अनेक खर्च, 'विधि एवं न्याय' के अंतर्गत अफसरों के वेतन तथा स्थापना खर्च, राजस्व संग्रहों में राजनीतिक एजेंटों के खर्च, आने वाले व्यय; भारतीय रियासतों तथा हमारे देशवासियों को मिलने वाले अवकाश एवं सेवा निवृत्ति तथा अनुकंपा भत्ते; और यूरोपीय



या और संपूर्ण भारत में केवल 15 व्यक्ति ऐसे पदों पर थे जिनका वेतन 1,000 रुपए अथवा अधिक था।<sup>206</sup> इन आंकड़ों से एक हद तक भारत में नए शिक्षित मध्यम वर्ग का सरकार की रोजगार संबंधी नीति के प्रति रोष स्पष्ट हो जाता है। सरकार की रोजगार संबंधी नीति के आलोचक यह स्पष्ट करके कि ब्रिटिश प्रशासकों की नियुक्ति राज्य के लिए अत्यधिक महंगी पड़ रही थी, अपने मामले को अधिक पुष्ट बना रहे थे। सिविल अवकाश एवं अनुपस्थिति भत्ते नामक व्यय की मद केवल उन ब्रिटिश अर्थनिक अधिकारियों के कारण थी जिन्हें ऐसा कहा जाता था कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कुछ समय तक नौकरी कर लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड जाने की आवश्यकता पड़ती थी। 1863-64 में अवकाश भत्ते पर व्यय की राशि 72,000 पाँड थी जो कुछ समय में दुगुनी हो गई और दस वर्षों में 10 लाख पाँड के लगभग बढ़ गई।

सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर सेवा निवृत्ति एवं अनुकंपा भत्ते पाने वालों में, संख्या की दृष्टि से, भारतीयों की प्रधानता थी, परंतु अधिकांश धनराशि यूरोपीय लोगों को मिल रही थी। पेंशन निस्संदेह सेवा काल में वेतनमानों के अनुपात में दी जा रही थी। इस मद के अंतर्गत एक दशक (1863-64 से 1872-73 तक) में 5 लाख की वृद्धि असाधारण नहीं थी। संभवतः वृद्धि की मात्रा और भी अधिक रही होती यदि इंग्लैंड में अधि-गैर नियमित अर्थनिक व्यय में वृद्धि की

कठिन था जो उससे अपनी पेंशन में वृद्धि की माग कर रहे थे।<sup>214</sup>

समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैंनिंग के वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 1860 से मार्च, 1862 तक) के बाद आयोग ने व्यय की विविध मदों में कटौती की सिफारिश की जिससे लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटौतियाँ सरकार को मंजूर नहीं थी परंतु लगभग 1 करोड़ रुपये की कटौती तो संभव थी ही।<sup>215</sup> अफसर वर्ग के बीच कटौती संवन्धी उपाय अधिक लोकप्रिय नहीं थे।<sup>216</sup> 1869-70 में मेयो ने नागरिक खर्चों को कम करने का एक और प्रयत्न किया। उसने अनुभव किया कि 'किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध अभियान और 'स्वाधो', अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर प्रहार।'<sup>217</sup> अफसर वर्ग ने मितव्ययिता के उपायों का विरोध किया। सरकारी मत था कि यदि सरकार 'ब्रिटिश शासन के प्रति कर्तव्यों तथा शासन की आवश्यकताओं' की ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों में वृद्धि होना अपरिहार्य है।<sup>218</sup>

भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड में व्याज प्रभार कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक थे। ये खर्च विभिन्न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता था : (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा अस्थायी ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थायी ऋणों की श्रेणी में जनता को निर्गत राजकोष पत्र (ट्रेजरी बिल) अथवा कागजी मुद्रा रिजर्व आते थे। नियमानुसार राजकोष पत्र 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय पर नवीकरण होता था और कभी राजकोष पत्रों के धारकों को यह विकल्प होता था कि वे यदि चाहें तो उन्हें दूसरे शेषों में बदल लें। इस प्रकार अस्थायी ऋण का स्थायी ऋण में परिवर्तन हो जाता था।<sup>219</sup> विल्सन ने ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प और अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थायी स्वरूप के ऋणों में बदल लिया।<sup>220</sup> डाकघर नकदी पत्र तथा अनैतिक एवं सैनिक सेवा निधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण थे। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोष पत्रों के रूप में ऋण बहुत अधिक नहीं थे। अतः यहाँ पर हम मुख्य रूप से स्थायी ऋण पर ही विचार करेंगे।

लेखकों में स्थायी ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता था :

(1) साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋणों में सिंचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे। ये इसलिए उत्पादक ऋण कहलाते थे क्योंकि यह आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूँजी निवेश से आय (जल उपकरण, रेल से प्राप्तियाँ इत्यादि) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उधार लेकर निवेश की गई पूँजी पर व्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण' की श्रेणी में ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल में संचित अन्य ऋण थे।



कठिन था जो उससे अपनी पेशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे।<sup>214</sup>

समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैनिंग के वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 1860 से मार्च, 1862 तक) के बाद आयोग ने व्यय की विविध मदों में कटौती की सिफारिश की जिससे लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटौतियाँ सरकार को मंजूर नहीं थी परंतु लगभग 1 करोड़ रुपये की कटौती तो संभव थी ही।<sup>215</sup> अफसर वर्ग के बीच कटौती संबंधी उपाय अधिक लोकप्रिय नहीं थे।<sup>216</sup> 1869-70 में मेयो ने नागरिक खर्चों को कम करने का एक और प्रयत्न किया। उसने अनुभव किया कि 'किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध अभियान और 'स्वार्थों', अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर प्रहार।'<sup>217</sup> अफसर वर्ग ने मितव्ययिता के उपायों का विरोध किया। सरकारी मत था कि यदि सरकार 'ब्रिटिश शासन के प्रति कर्तव्यों तथा शासन की आवश्यकताओं' की ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों में वृद्धि होना अपरिहार्य है।<sup>218</sup>

भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड में व्याज प्रभार कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक थे। ये खर्च विभिन्न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता था : (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा अस्थायी ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थायी ऋणों की श्रेणी में जनता को निगंत राजकोप पत्र (ट्रेजरी बिल) अथवा कागजी मुद्रा रिजर्व आते थे। नियमानुसार राजकोप पत्र 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय पर नवीकरण होता था और कभी राजकोप पत्रों के धारकों को यह विकल्प होता था कि वे यदि चाहें तो उन्हें दूसरे शेयरों में बदल लें। इस प्रकार अस्थायी ऋण का स्थायी ऋण में परिवर्तन हो जाता था।<sup>219</sup> विस्तृत में ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प और अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थायी स्वरूप के ऋणों में बदल लिया।<sup>220</sup> डाकघर नकदी पत्र तथा अनैतिक एवं सैनिक सेवा निधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण थे। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोप पत्रों के रूप में ऋण बहुत अधिक नहीं थे। अतः यहाँ पर हम मुख्य रूप से स्थायी ऋण पर ही विचार करेंगे।

लेखकों में स्थायी ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता था : (1) साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋणों में सिंचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे। ये इसलिए उत्पादक ऋण कहलाते थे क्योंकि यह आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूँजी निवेश से आय (जल उपकरण, रेल से प्राप्तियाँ इत्यादि) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उधार लेकर निवेश की गई पूँजी पर व्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण' की श्रेणी में ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल में संचित अन्य ऋण थे।

कठिन था जो उससे अपनी पेंशन में वृद्धि की माग कर रहे थे।<sup>214</sup>

समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैनिंग के वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 1860 से मार्च, 1862 तक) के बाद आयोग ने व्यय की विविध मदों में कटौती की सिफारिश की जिससे लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटौतियाँ सरकार को मंजूर नहीं थी परन्तु लगभग 1 करोड़ रुपये की कटौती तो संभव थी ही।<sup>215</sup> अफसर वर्ग के बीच कटौती संबंधी उपाय अधिक लोकप्रिय नहीं थे।<sup>216</sup> 1869-70 में मेयो ने नागरिक खर्चों को कम करने का एक और प्रयत्न किया। उसने अनुभव किया कि 'किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपभ्रष्ट के विरुद्ध अभियान और 'स्वार्थों', अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से बेकार व्यक्तियों पर प्रहार।'<sup>217</sup> अफसर वर्ग ने मितव्ययिता के उपायों का विरोध किया। सरकारी मत था कि यदि सरकार 'ब्रिटिश शासन के प्रति कर्तव्यों तथा शासन की आवश्यकताओं' की ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों में वृद्धि होना अपरिहार्य है।<sup>218</sup>

भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड में व्याज प्रभार कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक थे। ये खर्च विभिन्न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता था : (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा अस्थायी ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थायी ऋणों की श्रेणी में जनता को निर्गत राजकोष पत्र (ट्रेजरी बिल) अथवा कांगजी मुद्रा रिजर्व आते थे। नियमानुसार राजकोष पत्र। धर्म से कम अवधि के लिए होते थे, परन्तु कभी-कभी इनका समय-समय पर नवीकरण होता था और कभी राजकोष पत्रों के धारकों को यह विकल्प होता था कि वे यदि चाहें तो उन्हें दूसरे शेयरों में बदल लें। इस प्रकार अस्थायी ऋण का स्थायी ऋण में परिवर्तन हो जाता था।<sup>219</sup> विल्सन ने ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प और अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थायी स्वरूप के ऋणों में बदल लिया।<sup>220</sup> डाकघर नकदी पत्र तथा अनैतिक एवं सैनिक सेवा निधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण थे। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोष पत्रों के रूप में ऋण बहुत अधिक नहीं थे। अतः यहाँ पर हम मुख्य रूप से स्थायी ऋण पर ही विचार करेंगे।

लेखकों में स्थायी ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता था : (1) साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋणों में सिंचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे। ये इसलिए उत्पादक ऋण कहलाते थे क्योंकि यह आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूँजी निवेश से आय (जल उपकर, रेल से प्राप्तियाँ इत्यादि) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उधार लेकर निवेश की गई पूँजी पर व्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण' की श्रेणी में ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल में संचित अन्य ऋण थे।

था और संपूर्ण भारत में केवल 15 व्यक्ति ऐसे पदों पर थे जिनका वेतन 1,000 रुपए अथवा अधिक था।<sup>206</sup> इन आंकड़ों से एक हद तक भारत में नए शिक्षित मध्यम वर्ग का सरकार की रोजगार संबंधी नीति के प्रति रोष स्पष्ट हो जाता है। सरकार की रोजगार संबंधी नीति के आलोचक यह स्पष्ट करके कि ब्रिटिश प्रशासकों की नियुक्ति राज्य के लिए अत्यधिक महंगी पड़ रही थी, अपने मामले को अधिक पुष्ट बना रहे थे। सिविल अवकाश एवं अनुपस्थिति भत्ते नामक व्यय की मद केवल उन ब्रिटिश अर्सेनिक अधिकारियों के कारण थी जिन्हें ऐसा कहा जाता था कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कुछ समय तक नौकरी कर लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड जाने की आवश्यकता पड़ती थी। 1863-64 में अवकाश भत्ते पर व्यय की राशि 72,000 पाँड थी जो कुछ समय में दुगुनी हो गई और दस वर्षों में 10 लाख पाँड के लगभग बढ़ गई।

सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर सेवा निवृत्ति एवं अनुकंपा भत्ते पाने वालों में, संख्या की दृष्टि से, भारतीयों की प्रधानता थी, परंतु अधिकांश धनराशि यूरोपीय लोगों को मिल रही थी। पेंशन निस्संदेह सेवा काल में वेतनमानों के अनुपात में दी जा रही थी। इस मद के अंतर्गत एक दशक (1863-64 से 1872-73 तक) में 5 लाख की वृद्धि असाधारण नहीं थी। संभवतः वृद्धि की मात्रा और भी अधिक रही होती यदि इंग्लैंड में अधिकारियों ने गैर नियमित अर्सेनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति का प्रबल विरोध न किया होता। 1868 में अनुबंधित सरकारी अफसरों ने तीन प्रेसीडेंसियों में एक आंदोलन प्रारंभ किया। भारत मंत्री को स्मरणपत्र भेजे गए जिनमें पेंशन बढ़ाने की मांग की गई।<sup>207</sup> इन स्मरणपत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों का अर्थ था कि 78,000 पाँड से 1,53,000 पाँड तक प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय किया जाए। भारत सरकार ने जो इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती थी पेंशन भत्तों में वृद्धि की सिफारिश की।<sup>208</sup> परंतु भारत मंत्री ने, जिसे अपनी परिपद का समर्थन प्राप्त था इस संबंध में व्यय में वृद्धि के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। भत्तों में वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं था।<sup>209</sup> उसने भारत सरकार को लिखा कि 'साम्राज्य में और संभवतः विश्व में कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जिसके साथ इतनी उदारता दिखाई जा रही हो।'<sup>210</sup> भारत मंत्री ने केवल एक रियायत दी कि सरकारी सेवा में जिन अनुबंधित अफसरों ने 25 वर्ष पूरे कर लिए थे और जो भारत में 21 वर्ष रह चुके थे, उन्हें सेवा से निवृत्त होने पर कम से कम 1,000 पाँड वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई।<sup>211</sup> मेयो को लिखे गए अपने निजी पत्रों में आरणाइल ने सिविल सेवा के अफसरों द्वारा अपनी सुविधाएं तथा पेंशन बढ़वाने के लिए किए गए आंदोलन पर अप्रसन्नता प्रकट की।<sup>212</sup> आरणाइल ने उन स्वार्थी प्रयोजनों की स्पष्ट रूप में निंदा की जिनके कारण भारत सरकार को अनुबंधित यूरोपीय अफसरों को अनेक सख्ती सुविधाएं देनी पड़ी। उसने मेयो को लिखा 'वायसराय, सेनाध्यक्ष तथा विधि-सदस्य के अलावा सरकार (अर्थात् गवर्नर जनरल की परिपद) का प्रत्येक सदस्य सिविल सेवा का अफसर है। ये सभी इस समस्या में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रखते हैं।'<sup>213</sup> इन सरकारी अफसरों में समूह भावना का असर होना स्वाभाविक था और गवर्नर जनरल के लिए संपूर्ण भारत में उन अपने अफसरों का विरोध कर पाना

कठिन था जो उससे अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे।<sup>214</sup>

समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैनिंग के वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 1860 से मार्च, 1862 तक) के बाद आयोग ने व्यय की विविध मदों में कटौती की सिफारिश की जिससे लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटौतियाँ सरकार को मंजूर नहीं थीं परंतु लगभग 1 करोड़ रुपये की कटौती तो संभव थी ही।<sup>215</sup> अफसर वर्ग के बीच कटौती संबंधी उपाय अधिक लोकप्रिय नहीं थे।<sup>216</sup> 1869-70 में मेयो ने नागरिक खर्चों को कम करने का एक और प्रयत्न किया। उसने अनुभव किया कि 'किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध अभियान और 'स्वार्थों', अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर प्रहार।'<sup>217</sup> अफसर वर्ग ने मितव्ययिता के उपायों का विरोध किया। सरकारी मत था कि यदि सरकार 'ब्रिटिश शासन के प्रति कर्तव्यों तथा शासन की आवश्यकताओं' की ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों में वृद्धि होना अपरिहार्य है।<sup>218</sup>

भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड में ब्याज प्रभार कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक थे। ये खर्च विभिन्न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता था : (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा अस्थायी ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थायी ऋणों की श्रेणी में जनता को निर्गत राजकोप पत्र (ट्रेजरी बिल) अथवा कागजी मुद्रा रिजर्व आते थे। नियमानुसार राजकोप पत्र 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय पर नवीकरण होता था और कभी राजकोप पत्रों के धारकों को यह विकल्प होता था कि वे यदि चाहें तो उन्हें दूसरे शेयरों में बदल लें। इस प्रकार अस्थायी ऋण का स्थायी ऋण में परिवर्तन हो जाता था।<sup>219</sup> विल्सन ने ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प और अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थायी स्वरूप के ऋणों में बदल लिया।<sup>220</sup> डाकघर नकदी पत्र तथा अनैतिक एवं सैनिक सेवा निधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण थे। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोप पत्रों के रूप में ऋण बहुत अधिक नहीं थे। अतः यहाँ पर हम मुख्य रूप से स्थायी ऋण पर ही विचार करेंगे।

लेखकों में स्थायी ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता था :

(1) साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋणों में सिंचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे। ये इसलिए उत्पादक ऋण कहलाते थे क्योंकि यह आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूजी निवेश से आय (जल उपकरण, रेल से प्राप्तियाँ इत्यादि) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उधार लेकर निवेश की गई पूजी पर ब्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण' की श्रेणी में ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल में संचित अन्य ऋण थे।

1856 में भारत का 'साधारण ऋण' 4 करोड़ 92 लाख पौंड था। 1858 के 'एक्ट फार दि चैंटर गवर्नमेंट आफ इंडिया' की धारा 42 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के पूंजी शेयर और कंपनी के क्षेत्रीय व दूरगरे ऋणों के माप-माप इंग्लैंड के मनी बंधपत्र (बांड) ऋण पत्र तथा अन्य ऋणों पर लाभार्थ भारत सरकार के राजस्व पर भार थे। मैन्स-विद्रोह काल में और उसके तत्काल बाद द्वा द्वय ऋण में बढ़ी तेजी के माप बृद्धि हुई। सरकार का इंग्लैंड और भारत में कुल मिलाकर ऋण 5 करोड़ 94 लाख पौंड (1857) से बढ़ कर 9 करोड़ 81 लाख पौंड (1860) हो गया।

वित्तन के आने के समय तक भारत सरकार मैन्स विद्रोह के कारण सेना पर, रक्षा से उत्पन्न वित्तीय संकट का सामना करने के लिए कोई वित्तीय नीति नहीं खोज पाई थी। वित्तन द्वारा प्रारंभ किए गए मुधारों का पूरा अंगर होने तक सरकार को अनेक बार ऋण लेना पड़ा। 1861-62 तक ऋण की राशि बढ़कर 10 करोड़ 75 लाख पौंड हो गई। 1863-64 में चार्ल्स ड्यूबोयसियन के प्रयत्नों से यह प्रवृत्ति रुकी। अप्रैल, 1864 में भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास ऋण का विवरण भेजकर बतलाया कि पिछले दो वर्षों में ऋण में 90 लाख पौंड की कमी हुई और यह मुख्यतः रोकड़ शेप में से हुई। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ बंधपत्र (बांड) (2,56,000 पौंड) चुका दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिभूति पर लिए गए ऋण वापस कर दिए गए (15 लाख पौंड) और लगभग 55 लाख पौंड के ऋण पत्रों की भी चुकोती हो गई। भारत में रोकड़ शेप और बेकार भूमि की बिक्री से मिली धनराशि से 11 लाख पौंड की सरकारी प्रतिभूतिया खरीदी गई थी। तंजौर ऋण, काश्मीर के राजा से लिए गए ऋण तथा अन्य अनेक दायित्व चुका दिए गए।<sup>222</sup> इसके अलावा, ऋण राशियों की मदों की जांच पड़ताल की गई और विविध न्यासनिधिया, सैनिक-अर्धसैनिक कर्मचारियों की जमा निधियां तथा भारत सरकार के पास जमा की गई स्थानीय निधिया विशिष्ट सार्वजनिक निधियों से पृथक् कर दी गई।<sup>223</sup> इस प्रकार ऋण कम और व्यवस्थित अनुपात में कर लिया गया। 1865-66 तक ऋण 9 करोड़ 80 लाख पौंड के लगभग स्थिर बना रहा। इस वर्ष के बाद यह बढ़ता गया और 1871-62 में इसकी राशि असाधारण रूप से अधिक होकर 12 करोड़ 17 पौंड हो गई। मेयो की सरकार इस प्रवृत्ति से बहुत चिंतित थी और उसने साधारण खर्च चालू आम से करने और उधार से बचने का दृढ़ निश्चय किया।<sup>224</sup> रिचर्ड टैपिल जिस समय इंग्लैंड में ठिका हुआ था, उस समय वह प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन के संपर्क में आया जिसने टैपिल को ऋण प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों के विषय में परामर्श दिया। उसकी ही सलाह पर टैपिल ने ऋण के एक भाग पर ब्याज में कमी कर दी। शेयरधारियों के सामने विकल्प रखा कि वे या तो अपना मूलधन वापस ले लें या ब्याज की नीची दर स्वीकार करें।<sup>225</sup> पुराने 5 वर्षीय ऋण पत्रों को सममूल्य पर भुगतान से कुछ अन्य ऋणों का परिशोधन हो गया।<sup>226</sup> टैपिल द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज पर लिए गए ऋणों की 4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋणों में सफलतापूर्वक बदलने से यह संकेत मिला कि सरकार की साल 'धीरे-धीरे उस बिंदु पर पहुंच रही थी जहां पर वह 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले ऋणों पर भरोसा कर सकती थी।'<sup>228</sup> बाद में सरकार 5 प्रतिशत ब्याज पर लिए

गए और भी ऋणों को 4 प्रतिशत व्याज वाले ऋणों में बदल पाने में सफल हुई। तथापि पुराने ऋणों का परिशोधन सरलता से नहीं हो सकता। मेयो और उसकी सरकार जो भी कुछ कर सकी वह यह था कि वे अनियंत्रणीय बड़े ऋण के सचय को जिसे मेयो 'सबसे बड़ा भारतीय खतरा' कहता था रोकने का प्रयास कर सके।<sup>227</sup>

अधिकारियों के परिकलन में व्याज प्रभार का बढ़ा बोझ था। वे लोक निर्माण कार्यों में पूजी निवेश से मिल सकने वाले उत्पादक परिणामों का पूरी तरह महत्व समझ ही नहीं सके। लोक ऋणों और निजी ऋणों के बीच झूठे सादृश्य पर आधारित पूर्वग्रह तथा 'सरकार के दिवालिया हो-जाने' का भय विकास के लिए भारी भात्ता में ऋण लेने में बाधाएं थी।<sup>228</sup> तथापि एक विचारधारा थी जो सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए सरकार द्वारा ऋण लेने का समर्थन करती थी। सर आर्थर काटन ने 1854 में लिखा था 'बृहत लोक निर्माण के लिए चालू आय से धन की कमी भी व्यवस्था नहीं हो सकती। निर्माण कार्य के लिए तब तक प्रतीक्षा करना जब तक कि आय में वृद्धि हो वस्तुतः गाड़ी को धोड़े के आगे जोतना है...लोक निर्माण कार्य के अलावा किसी अन्य प्रकार से आय में वृद्धि नहीं हो सकती।' <sup>229</sup> भारत में लोकमत सरकार द्वारा लोक निर्माण के विकास के लिए ऋण लेने के पक्ष में था। 'टाइम्स आफ इंडिया' ने लिखा कि ऋण के विरुद्ध पूर्वग्रह भारतीय वित्त के विनाश का कारण है।<sup>230</sup> 'इंडियन इकानामिस्ट' ने जोरदार ढंग से कहा था लोक निर्माण पर व्यय जितना अभी है, उसका तीन गुना होना चाहिए और इस व्यय की व्यवस्था अल्पकालीन ऋण लेकर की जानी चाहिए।<sup>231</sup> कुछ हिंदुस्तानियों के देशी भाषा में निकलने वाले समाचार पत्रों ने भी यही शोर मचाया।<sup>232</sup> 1871 में हाउस आफ कामंस के पास भेजे गए अपने स्मरण पत्र में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने माग की कि इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिए कि 'ऐसे देश में जिसके साधन तो सपन्न हैं परंतु पूजी का अत्यंत अभाव है, लोक निर्माण की लागत क्या अब भी चालू आय से चुकाई जानी चाहिए अथवा इसकी ऋण तथा निक्षेप निधि (सिकिंग फंड) की उपयुक्त प्रणाली द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए...' <sup>233</sup> 1870 में बंबई बैंक्स आफ कामर्स ने वायसराय को अपनी यह इच्छा प्रकट करते हुए लिखा कि 'स्याई स्वरूप के लोक निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था राजस्व पर भारितव्य और निश्चित तिथियों पर शोधनीय, अल्पकालीन ऋणों से की जा सकती है...' <sup>234</sup> टी० बी० जेफ्रीज ने अपने पैफलेट 'नेशनल क्रेडिट एंड पब्लिक वर्क्स' में 'राष्ट्रीय साख के मुक्त एवं युक्तिसंगत प्रयोग' का सुझाव दिया, क्योंकि 'चालू आय से लोक निर्माण का खर्च निकालने से वास्तव में नया निर्माण कार्य एक तरह से निषिद्ध हो जाता है...' <sup>235</sup> प्रथम भारतीय आर्थिक पत्रिका के संस्थापक रायट नाइट ने लोक ऋण के विरुद्ध पूर्वग्रह को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उसका तर्क था कि भारत सरकार को किसी भी ऐसे जमींदार की भांति, जिसके पास सुधार के लायक भू संपत्ति है, ऋण लेकर देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसी से आय में वृद्धि होगी जो व्यय के औचित्य को सिद्ध करेगी।<sup>236</sup>

अस्तु, लोक निर्माण के विकास के लिए ऋण लेने के पक्ष में काफी बड़ा लोकमत था। फिर भी सरकार की नीति उधार से यथासंभव बचने की थी। जब भी ऋण लेने के

पक्ष में निर्णय लिया जाता था तो भारत सरकार पर भारत मंत्री द्वारा अनेक शर्तें लगाई जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि ऋण लेकर जुटाई गई धनराशि का प्रयोग केवल लाभकारी निर्माण के लिए होना चाहिए। यह तर्क इस गलत सादृश्य पर आधारित था कि जिस प्रकार एक निजी व्यावसायिक इकाई उस समय तक ऋण नहीं ले सकती जब तक कि पूंजी निवेश उत्पादक न हो (अर्थात् लगाई गई पूंजी पर व्याज का भुगतान और ऋण परिशोधन संभव हो) सरकार को भी लाभकारी उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य बात के लिए ऋण नहीं लेना चाहिए।<sup>237</sup>

यह बात मान ली जानी चाहिए कि बड़े पैमाने पर उधार लेने के विरुद्ध कुछ सबल तर्क थे। भारत सरकार स्वदेश में ही ऋण लेने के स्थान पर विदेशी ऋणदाताओं से ऋण ले रही थी। विदेश में लिए गए ऋणों पर व्याज का भार बहुत अधिक था। इस प्रकार के उधार की प्रवृत्ति निरन्तर घरेलू उधार से भिन्न होती है जिसमें देश के भीतर ही ऋणदाताओं को व्याज का भुगतान किया जाता है। आरगाइल ने मेयो को 'हिंदुस्तानी पूंजीपतियों के पास पहुंचने' का उपदेश दिया। उसके शब्दों में, 'भारतीय लोक ऋण में भारत के मूल निवासियों की दिलचस्पी बढ़ाना मैं बड़े भारी राजनीतिक महत्व का मामला समझता हूँ...'।<sup>238</sup> लारेंस को भी चार्ल्स वुड ने यही सलाह दी थी।<sup>239</sup> परंतु भारत सरकार ने लंदन मुद्रा बाजार से ऋण लेना जारी रखा। मेयो ने एक कारण बताया कि सरकारी ऋणों में पैसे देने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या कम क्यों है। उसने भारत मंत्री को लिखा 'हमें यहां पर अभी ऋण नहीं मिल सकता। हिंदुस्तानी साहूकार अच्छी प्रतिभूति पर अपनी मुद्रा के बदले में 10, 15 अथवा 18 प्रतिशत व्याज की आशा करता है और यह उसे मिलता भी है... अतः, अभी काफी वर्षों तक हमें केवल 4 प्रतिशत व्याज देकर यूरोप से ही ऋण लेना चाहिए।'<sup>240</sup> इस संबंध में जिन अन्य कारणों का उल्लेख किया गया था वे थे: 'भारतीय ऋणों के लिए यूरोपीय पूंजीपतियों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा', हिंदुस्तानी पूंजीपतियों की 'भूमि पाने के लिए बढ़ती हुई लालसा' (विशेष रूप से बंगाल में) तथा पुराने सामंती वर्गों का पतन जिनके पास पहले निवेश धनराशि रहती थी और जो अब धनहीन हो गए थे।<sup>241</sup> भारत सरकार के अनुसार 'इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि हम यूरोपियों को जो शर्तें देते हैं उनसे हर तरह की बेहतर शर्तें देकर भी देशी पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहित कर सकें। मुद्रा बाजार की स्थिति पर (जो मौसम तथा कृषि की स्थिति पर निर्भर होती थी) भारत सरकार समय-समय पर भारत में ऋण लेती थी।'<sup>242</sup> परंतु भारत सरकार का धार-धार यही कहना था कि कुल मिलाकर लंदन मुद्रा बाजार में सुविधा के साथ ऋण लिए जा सकते थे।<sup>243</sup> 1867 में भारत में सिंचाई निर्माण के लिए एक धनराशि जुटाने के उद्देश्य से भारत की लघु वचतों के सग्रह के लिए एक मनोरंजक योजना सामने आई। बंबई सरकार ने 40-50 रुपये की छोटी-छोटी राशियां में ऋण लेने का प्रस्ताव रखा। इसमें शर्त यह थी कि धनराशियां जिते के खजानों में जमा की जाएंगी। यह कहा गया कि 'इस योजना का उद्देश्य सरकारी ऋणों के लाभ कृपकों तथा दूसरे वर्गों तक, जो वचतों को या तो मंचित किए रहते हैं या बहुत खराब प्रतिभूतियों के आधार पर इन्हें निजी ऋणियों को दे देते हैं, पहुंचाना है।'<sup>244</sup> इस

प्रस्ताव को भारत मंत्री ने अस्वीकार कर दिया जिसे बहुत छोटी-छोटी राशियों में लिए जाने वाले ऋणों के प्रवर्ध में औपचारिक कठिनाइयाँ दिखाई दी। इस प्रकार इस अकल्प-नाशील ढंग से लोक निर्माण के विकास के लिए निष्प्रिय लघु वचनों के प्रयोग की एक अच्छी योजना का गला घोट डाला।

## संदर्भ

1. देखें अनुच्छेद IV आगे।
2. प्रत्यक्ष करों के निर्धारक और सग्रहकर्ता अस्थाई होते थे और इनकी नियुक्ति उसी समय होती थी जबकि इनकी आवश्यकता पड़ती थी।
3. देखें परिशिष्ट।
4. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संध्या 144, 29 जून, 1860, ठीक वही वित्त संध्या 58, 19 अप्रैल, 1862, सशोधित प्राक्कलन जून, 1860।
5. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 6, 19 जनवरी, 1859।
6. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 9, 31, जनवरी, 1859।
7. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 28, 22 फरवरी, 1859।
8. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संध्या 57, 23 अप्रैल, 1859।
9. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 57, 15 जून, 1859।
10. भारत मंत्री से भारत सरकार को, सैन्य प्रेषण संध्या 352, 7 अक्टूबर 1859।
11. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 75, 1 अगस्त, 1859।
12. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 23, 16 मार्च, 1860।
13. वित्त कार्यविवरण अक्टूबर, 1861 संध्या 197, सैन्य वित्त विभाग से भारत सरकार के वित्त सचिव को, 22 अगस्त, 1861। वित्त कार्यविवरण, अगस्त, 1861, लेखा शाखा संध्या 1 सैन्य वित्त विभाग से भारत सरकार के वित्त सचिव को, 15 जून, 1861। वित्त कार्यविवरण, सितंबर, 1861। लेखा शाखा संध्या 168। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 19 सितंबर, 1861।
14. देखें परिशिष्ट।
15. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 136, 22 अगस्त, 1860। वित्त कार्यविवरण, अक्टूबर, 1861, लेखा शाखा संध्या 193, सैन्य वित्त विभाग से वित्त सचिव को, 8 अक्टूबर, 1861।
16. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 136, 22 अगस्त, 1860।
17. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संध्या 53, 8 अप्रैल, 1861; ठीक वही वित्त संध्या 85, 17 मई, 1861।
18. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संध्या 209 ए, 12 दिसंबर, 1861।
19. बी० फ़ैर से सी० ब्रुड को, 3 मई, 1860 मार्टिन्यू, पूर्वोद्धृत, बिल्ड I, पृ० 300 यदि यह



सुरी बात नहीं है तो कम से कम हास्यास्पद तो है ही कि सैन्य और पुलिस आयुक्तों के बीच ऐसे दलों का भेद खुला जिनके विषय में पहले रिपोर्टों को मान्य नहीं था और जिन्हें राजनीतिक अथवा न्यायिक धर्मों की रिपोर्टों में मद के अन्तर्गत छिपाया गया था।' बी० फ्रेड से जी० बर्कें को, 8 मई, 1861, वही पृ० 314।

20 फंड ऑफ इंडिया', 17 अप्रैल, 1862।

21 भारत सरकार से भारत मंत्री को सैन्य प्रेषण सध्या 132, 19 मार्च, 1864। भारत मंत्री का विचार था कि वित्त विभाग के बाहर सैन्य वित्त विभाग का होना असंगत था। भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सध्या 1, 8 जनवरी, 1863। सी० ई० ट्यूबोरोविचन ने वित्त विभाग में वित्तीय नियंत्रण के केंद्रीकरण की वाछनीयता को स्वीकार कर लिया था। वित्त बार्ड-विवरण, फरवरी, 1864, प्रकीर्ण सध्या 14, सी० ई० ट्यूबोरोविचन का मेमो० 18 मई, 1863।

22. देखें परिशिष्ट।

23. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सध्या 66, अप्रैल, 1865।

24. फ्रेडबोर्न से जे० सार्रेट को, 18 फरवरी, 1867, सार्रेट कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द IV, सध्या 7।

25 सी० बृड से जे० सार्रेट को, 9 दिसंबर, 1864, सार्रेट कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द I, सध्या 67।

26 जे० सार्रेट से फ्रेडबोर्न को, 10 सितंबर, 1866, सार्रेट कागजात, जे० सार्रेट से भारत मंत्री को पत्र, जिल्द, III, सध्या 34।

27. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सध्या 52, 26 जनवरी, 1869।

28 मेयो से सार्जेंट सैडहर्स्ट को, 28 मई, 1871। मेयो कागजात, बंडल 43, सध्या 117।

29 मेयो से आरगाइल को, 17 अक्टूबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 37, सध्या 285।

30 मेयो से आरगाइल को, 15 मार्च, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, सध्या 77।

31. मेयो से डब्ल्यू० आर्बुथनाट को, 10 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, सध्या 17।

32. मेयो से बी० फ्रेड को, 11 जनवरी, 1869, मेयो कागजात, बंडल 32, सध्या 15।

33. मेयो से डब्ल्यू० ए० आर्बुथनाट को 5 दिसंबर, 1869 मेयो कागजात, बंडल 37, सध्या 342।

34 मेयो से आरगाइल को, 7 दिसंबर, 1869, के पत्र में सलमान गृह विभाग के अवर सचिव का मेमो०, मेयो कागजात, बंडल 37, सध्या 346।

35 मेयो से डब्ल्यू० आर्बुथनाट को, 14 फरवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, सध्या 62।

36 वही।

37 मेयो से आरगाइल को, 20 मई, 1870, मेयो कागजात, बंडल 39, सध्या 132।

38. मेयो से डब्ल्यू० आर्बुथनाट को, 14 फरवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, सध्या 62।

38 ए-भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सध्या 72, 16 मार्च, 1871।

38. बी-आरगाइल से मेयो को, 9 दिसंबर, 1870, मेयो कागजात, बंडल 48, सध्या 33।

38 सी-मेयो से बी० फ्रेड को, 11 जनवरी, 1869, मेयो कागजात, बंडल 35, सध्या 15।

39. मेयो से आरगाइल को, 17 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, सध्या 20।

40. मेयो से आरगाइल को, 10 अप्रैल, 1871, मेयो कागजात, बंडल 43, संख्या 91 ।
41. मेयो ने आरगाइल को, 8 मई, 1871, बंडल 43, संख्या 97 । आरगाइल का विचार था कि नैपियर द्वारा सदन के साथ सीधा पत्र व्यवहार आपत्तिजनक नहीं था । आरगाइल से मेयो को, 9 जून, 1871, मेयो कागजात, बंडल 49, संख्या 13 ।
42. मेयो से आरगाइल को, 4 अक्तूबर, 1870, मेयो कागजात, बंडल 41, संख्या 282 ।
43. मेयो से आरगाइल को, 30 नवंबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 37, संख्या 335 ।
44. विल्ल कार्यविवरण, नवंबर, 1869, लेखा शाखा संख्या 45 । एच० एम० ड्यूरेड का मेमो०, 13 सितंबर, 1869 ।
45. वही संख्या 48, गवर्नर जनरल का मेमो०, 4 अक्तूबर, 1869 ।
46. मेयो से आरगाइल को, 30 नवंबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 37, संख्या 335 ।
47. आरगाइल से मेयो को, 10 फरवरी, 1871, मेयो कागजात, बंडल 49, संख्या 31 ।
48. मेयो से ड्यूक आफ कैम्ब्रिज को, 22 मार्च, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, संख्या 82 । मेयो ने यह पत्र ड्यूक आफ कैम्ब्रिज के 4 फरवरी, 1870 के नोट के उत्तर में लिखा था ।
49. आरगाइल से मेयो को, 10 फरवरी, 1871, मेयो कागजात, बंडल 49, संख्या 3 ।
50. आरगाइल से मेयो को, 11 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बंडल 49, संख्या 4 ।
51. आरगाइल से मेयो को, 3 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बंडल 49, संख्या 5 ।
52. मेयो से आरगाइल को, 17 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, संख्या 20 ।
53. आरगाइल से मेयो को, (गोपनीय), 26 अक्तूबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 47 ।
54. वही ।
55. वही ।
56. पी० पी० एच० सी० 1873, जिल्द 12, पत्रक 354, 4752, 4757, भारतीय वित्त के सबध में प्रवर समिति के सामने जे० लारेंट का साक्ष्य ।
57. मेयो ने दरअसल आरगाइल पर अपनी बात से मुकरने का आरोप लगाया था, मेयो से आरगाइल को, 10 अप्रैल, 1871, मेयो कागजात, बंडल 43, संख्या 91, ठीक वही, 9 जनवरी, 1871, बंडल 42, संख्या 13 ।
58. आरगाइल से मेयो को, 4 नवंबर, 1869, मेयो कागजात, बंडल 47 । 'जहाँ तक आपके सेना में कमी करने के प्रस्ताव का सबध है, उससे जो प्रश्न उठते हैं उनका सबध भारत से ही न होकर पूरे साम्राज्य से है 'मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि 'इन प्रश्नों का समाधान भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के ही संदर्भ में नहीं हो सकता ।'
59. पी० पी० एच० सी० 1896, जिल्द 16, सी० 8259, पृ० 285-308 । भारत में लोक व्यय से संबंधित शाही आयोग की रिपोर्ट का परिशिष्ट । 1824 में इंडिया आफिस, वार आफिस तथा ट्रेजरी के बीच भुगतान के सिद्धांतों का निर्धारण 1824 में हो गया था और वे 1860 तक प्रचलन में रहे ।
60. एक्ट 23 व 24, विक्ट सी० 100 ।
61. एक्ट 24 व 25, विक्ट० सी० 74 । ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की सेवा में स्थानांतरण का प्रबल प्रतिरोध किया था । इसे स्वेन सैन्य विद्रोह कहा गया है । देखें पी०

- पी० एच० सी० 1860, जिल्द 51, पत्रक 169, 196 I, 169 II ।
62. भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त सध्या 90, 31 मई, 1861 । इस पत्र में समझौते की शर्तें पूर्णरूप से स्पष्ट की गई हैं ।
63. पी० पी० एच० सी० 1896, जिल्द 16 पत्रक 8259, पृ० 297 ।
64. पी० पी० एच० सी० 1874, जिल्द 8, पत्रक 329, पृ० 226-27 । भारतीय वित्त के संघ में प्रवर समिति की चौथी रिपोर्ट का परिशिष्ट । सीकोव समिति ने सिफारिश की थी (रिपोर्टें, दिनांक 11 मार्च, 1869, 24 नवंबर, 1869, 28 फरवरी, 1870 और 12 अप्रैल, 1872) कि भारत सरकार को अधिक मात्रा में खर्चों का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को हिपो खर्चों और सैनिकों की भर्तियों से लेकर उनके पोतारोहण तक की लागत की अग्रिमता के कारण कुछ हानि हो रही है । परंतु इन सिफारिशों को सरकार लागू नहीं किया गया । इंडिया आफिस ने प्रस्तावित नई दरों का विरोध प्रकट किया । वही पृ० 230-43 ।
65. सैन्य सचिव, इंडिया आफिस को ओर से जे० पी० टाम से अवर सचिव, वार आफिस को 8 सितंबर, 1871 । पी० पी० एच० एल० 1874, जिल्द 8, पत्रक 329, पृ० 245 ।
66. सी० कैबेल, वार आफिस से उप भारत मंत्री, 14 अप्रैल, वही पृ० 248 ।
67. वही ।
68. टी० टी० पीयरर्स, सैन्य सचिव, इंडिया आफिस से अवर सचिव, वार आफिस को, 9 अगस्त, 1872 । वही पृ० 249-53 ।
69. भारत सरकार ने भारत मंत्री को, सैन्य प्रेषण सध्या 94, 15 मई, 1873 में स्पष्ट किया कि सैनिकों की भर्तियों के लिए खर्चों का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भुगतान (1859 में समाप्त होने वाले दस वर्षों में सभी प्रकार की सेना के लिए औसत 19 पौंड 14 शि० 10½ पैस या) उससे बहुत कम था जो 1873 में युद्ध मंत्री द्वारा वसूल किया गया (अबवारोही सेना के लिए 136 पौंड 13 शि० 11 पैस, पैदल सेना के लिए 63 पौंड 8 शि० 5 पैस; शाही अबवारोही गोलदाज सेना के लिए 78 पौंड 14 शि० 8 पैस; शाही गोलदाज सेना के लिए 58 पौंड 9 शि० 3 पैस) ।
70. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सध्या 110, 10 जुलाई, 1860 ।
71. देखें पी० पी० एच० सी० 1896, जिल्द 16, सी० 8259, पृ० 304 ।
72. पी० पी० एच० सी० 1862 जिल्द 16, पत्रक 165, पृ० 483 और आगे ।
73. टुलाक समिति (1859) ने 2 लाख पौंड की सिफारिश की थी । इसमें सेवामुक्त सैनिकों की पेंशन के लिए 1 लाख 60 हजार पौंड, घायल अफसरों की पेंशन के लिए 2,374 पौंड अवकाश प्राप्त अफसरों को पूरे वेतन अथवा सैन्य भत्तों के लिए 21,541 पौंड, तथा विधवाओं और बच्चों के लिए 15,369 पौंड की राशियां सम्मिलित थी, वही ।
74. एक्ट 25 व 26, विक्ट० मी० 27 । यद्यपि एक्ट मार्च, 1867 तक ही लागू था, तथापि व्यवहार में समझौते के अनुसार मार्च, 1870 तक कार्य होता रहा ।
75. वित्त कार्यनिर्वाह फरवरी, 1868, लेखा शाखा सध्या 57 । गवर्नर जनरल का मेमो०, 20 जनवरी, 1868 ।
76. मेयो मे आरगाइल को, 6 अप्रैल, 1870, मेयो कागजात, बंडल 39, संख्या 100 ।

77. एक्ट 21 व 22 विक्ट० सी० 106, अनुच्छेद 55 ।
78. टी० टी० पियर्स, सैन्य सचिव, इंडिया आफिस से अवसर सचिव, चार आफिस को, 9 अगस्त, 1872, पी० पी० एच० सी० 1874, जिल्द 8, पत्रक 329, पृ० 249 और आगे ।
79. 'आवसफोर्ड डिक्शनरी आफ कोटेशंस, 1941, पृ० 527 ।
80. अबीसीनिया अभियान के लिए भारत सरकार ने जो भारी मात्रा में अग्रिम राशियाँ प्रदान की उससे उसका रोकड़ शेष अत्यधिक कम हो गया (भारत सरकार से भारत मंत्री को तार, 25 अगस्त, 1867) । भारत मंत्री ने भारत सरकार से अपनी धूसूली (ड्राफ्ट) में कमी कर दी (भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 316, 31 अगस्त, 1867) । इंग्लैंड में भारत मंत्री ने 12 लाख पाँड का ऋण लिया (भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त 485, 24 नवंबर, 1868) । भारत सरकार ने शिकायत की कि 'ऐसे कार्य के लिए जिसका भारत सरकार से कोई संबंध न हो', एक वर्ष में 70 लाख पाँड देना बहुत कठिन है । (भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 332, 21 दिसंबर, 1868), । भारत में बहुत सारे ऋण लिए गए (भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 339, 31 दिसंबर, 1868) ।
81. वित्त कार्यविवरण, फरवरी, 1868, लेखा शाखा सख्या 57 । गवर्नर जनरल का मेमो०, 20 जनवरी, 1868 ।
82. पूर्वोक्त स्थल ।
83. मेयो से एच० ह्यूरेड को, 24 अप्रैल, 1870 मेयो कागजात, बंडल 39, सख्या 105 ।
84. 'हुमाई' सीसरी सीरीज C X C कालम 406, 28 नवंबर, आर० रोबिंसन द्वारा उद्धृत और अग्यत, पूर्वोद्धृत, पृ० 12 ।
85. सर सी० डिल्के, 'ग्रेटर ब्रिटेन', (लंदन, 1869) पृ० 470-74 ।
86. वित्तीय प्रतिबंध और म्यूटिनी एक्ट की धाराओं के लिए देखें भारत मंत्री से भारत सरकार को, सैन्य प्रण, सख्या 108, 17 मार्च, 1862 ।
87. वही ।
88. पी० पी० एच० सी० 1874, जिल्द 8, पत्रक 329, पृ० V ।
89. वित्त कार्यविवरण, फरवरी, 1868, लेखा शाखा सख्या 57, गवर्नर जनरल का मेमो०, 20 जनवरी, 1868 ।
90. 4 नवंबर, 1859 के, भारत मंत्री द्वारा प्रेषण (रेल विभाग पत्र सख्या 109) में रेल विभाग की सविदा की शर्तों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है । इसकी एक अच्छी क्लिपिंग लोक निर्माण विभाग के महालेखाकार जार्ज चेजनी की पुस्तक 'इंडियन पालिटी' (लंदन, 1868) में मिलती है । ईस्ट इंडिया कंपनी के टायरेक्टर्स और रेल कंपनियों के बीच 1849 तक समझौता संबंधी बातचीत के मध्य में देखें डेनियल थोर्नर की पुस्तक 'इनवेस्टमेंट इन एषायर' (फिना-डेल्फिया, 1950), पृ० 119-167 ।
91. डेनियल थोर्नर, पूर्वोद्धृत, पृ० 178 ।
92. आरगाइल से मेयो को, 12 फरवरी, 1869, मेयो कागजात, बंडल 47, सख्या 7 ।
93. डेनियल थोर्नर, पूर्वोक्त स्थल ।
94. पी० पी० एच० सी० 1872, जिल्द 8, पत्रक 327, पूर्वी भारत के लोक वित्त के संबंध में प्रवर

समिति की रिपोर्टें और कार्यविवरण। डेवसें (1861-63), चेजनी (2643-46), तथा आर० स्ट्रुंची (6882, 6887) के साध्य। आगे इसका उल्लेख 'वित्त प्रवर समिति' के नाम से किया गया है और सबधित पैराग्राफों को सख्याएँ कोष्ठक में दी गई हैं।

95. रेलों में पूँजी लगाने वाले निवेशक 'उससे कहीं अधिक व्याज बसूल कर पाने में सफल हुए जितना कि उन्हें भारत सरकार को सीधा ऋण देने पर मिल सकता था', जबकि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों में अंतर अति सूक्ष्म था।' एन० एच० जैक्स, 'पूर्वोद्धृत, पृ० 223।
96. एन० एच० जैक्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 225, 219।
97. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 136, 22 अगस्त, 1860।
98. पी० पी० एच० एल० 1872, जिल्द 8, पृष्ठ 327, वित्त प्रवर समिति। स्ट्रुंची (1836-41) द्वारा साध्य। जार्ज चेजनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 336। निस्संदेह, विनिमय दर भारत सरकार के लिए लाभ का स्रोत बन सकती थी। जदन स्थित कंपनियों को 'यातायात संबंधी प्राप्ति' से प्रति रुपया 2 पैसे का भारत सरकार को लाभ हो सकता था।
99. 'इंग्लैंड में रेल कंपनियों से मिलने वाली राशियाँ और भारत में उन्हें इन राशियों के 1 शि० 10 पैसे प्रति रुपये की दर से पुनर्निगम से होने वाली विनिमय हानि अब तक भारतीय राजस्व पर प्रभार के रूप में नहीं दिखाई गई है, परंतु भविष्य में इसे सभी प्राकृतिक और लेखों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।' भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 67, 26 अप्रैल, 1860।
100. देखें परिशिष्ट।
101. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, सख्या 63, 2 मई, 1861।
102. वही।
103. विधान परिषद के कार्यविवरण, 1864, जिल्द III (नई सीरीज) पृ० 219-20।
104. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 83, 9 जून, 1862।
105. भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण, सख्या 109, 4 नवंबर 1859।
106. एन० साग्याल, 'डैवलपमेंट आफ इंडियन रेलवेज', (कलकत्ता, 1903) पृ० 64।
107. पी० पी० एच० सी 1872, जिल्द 8, पृष्ठ 327। वित्त सबंधी प्रवर समिति, लार्ड लॉरेन (4589-92), ए काटन (8311), चेजनी (2622-25), डब्ल्यू० एन० मैसी (8866-67), थॉमसन (1781-82) के साध्य। कामकाज खर्च जैसे कि प्रारंभिक व्यय बहुत अधिक थे। 1872 में इंग्लैंड की रेलों में कामकाज खर्च सकल प्रवृत्तियों के 49 प्रतिशत और भारत में 54 प्रतिशत थे। इंग्लैंड में लगाई गई पूँजी पर शुद्ध आय 4.47 प्रतिशत और भारत में 3 प्रतिशत थी। जे० ए० रेंज 'रेलवेज इन दि यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, 1872' 'दि इरीपन इरानामिस्ट', 31 जनवरी, 1874।
108. आरगाइल से मेयो को, 12 फरवरी, 1869, मेयो कागजात, बंडल 47, सख्या 7।
109. 'फ्रैंड आफ इंडिया', 28 मई, 1863, लेख जिसका शीर्षक 'रेलवे एनार्की' है।
110. भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण सख्या 78, 10 अक्टूबर, 1860, इसके द्वारा भारत मंत्री के वित्त प्रेषण सख्या 110, दिनांक 10 जुलाई, 1860, में दिया गया आदेश निरस्त कर दिया गया। पुराने आदेश द्वारा जिस कंपनी ने अपने व्ययों में अधिक रुपया

से लिया था उसे भुगतान रोक देने की भारत सरकार को अनुमति दी गई थी।

111. वित्त कार्यविवरण, सितंबर, 1860, सख्या 42, भारत सरकार द्वारा टिप्पणी, 13 सितंबर, 1860।
112. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण, सख्या 205, 8 दिसंबर, 1860।
113. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, सख्या 16, 5 फरवरी, 1861।
114. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, सख्या 22, 2 फरवरी, 1861।
115. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, सख्या 199, 31 अगस्त, 1867।
116. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, सख्या 58, 18 फरवरी, 1867।
117. भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण, सख्या 109, 4 नवंबर, 1859।
118. वित्त कार्यविवरण, दिसंबर 1864, लेखा शाखा, सख्या 546, रेल विभाग के लेखों से संबंधित लेखा परीक्षण एवं नियंत्रण संबंधी कार्यविवरण।
119. वित्त कार्यविवरण, जून 1869, लेखा शाखा, सख्या 65, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 19 जून, 1869।
120. आरगाइल से मेयो को, 3 अगस्त 1869, मेयो कागजात, बंडल 47।
121. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 341, 13 दिसंबर, 1871।
122. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 41, 31 जनवरी 1872।
123. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 74, 8 मार्च, 1867। तुलनीय भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण सख्या 94, 17 नवंबर, 1860।
124. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 251, 24 जून, 1867।
125. भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त प्रेषण सख्या 17, 30 अप्रैल, 1866। भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 116, 23 अप्रैल, 1868। वित्त कार्यविवरण मार्च, 1868, लेखा शाखा सख्या 35, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 5 मार्च, 1868।
126. ईस्ट इंडिया ड्रामवे कंपनी तथा इंडियन नाव रेलवे कंपनी के लिए देखें एन० सायाल, पूर्वोद्धृत, पृ० 67।
127. भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण सख्या 18, 23 मार्च, 1867।
128. अबध रेलवे कंपनी और कर्नाटक रेलवे कंपनी के साथ नई सविदाओं में 2 मिलियन रुपया त्रिनिमय दर, बीस वर्ष बाद रेलों के राष्ट्रीयकरण के राज्य के अधिकार तथा प्राक्कलनों के सरकार द्वारा सूक्ष्म परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण सख्या 44, 11 जून, 1868।
129. ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ग्रेट इंडिया पेनिमुला रेलवे, बंबई बड़ोदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे; मद्रास, बंबई, सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे कंपनियों ने इसे स्वीकार कर लिया। देखें एन० सायाल, पूर्वोद्धृत, पृ० 67 और आगे।
130. भारत सरकार से भारत मंत्री को, रेल विभाग प्रेषण, सख्या 80, 12 अगस्त, 1870।
131. मेयो से आरगाइल को, 12 अगस्त, 1870, मेयो कागजात, बंडल 40, सख्या 229।
132. आरगाइल से मेयो को, 17 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 48, सख्या 1।
133. पी० पी० एच० सी० 1872, जिल्द 8, पृष्ठ 327, वित्त संबंधी प्रवर समिति के सामने एम०

- लेग का साध्य (7526-29)। आरगाइल लिखता है कि बार्टन फेर ने 'इस बारे में बहुत संदेह प्रकट किया था कि भारत सरकार उत्तरी तैजो से रेलों का निर्माण कर सकेगी जिस प्रकार कि प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) कंपनियों ने रेलों का विकास किया है।' आरगाइल से मेयो को, 19 नवंबर, 1869। मेयो कागजात, बडस 47। फेर जब बचई का गवर्नर था तो उसने त्रिजी उद्यमकर्ताओं को 'विधिकेतर' सहायता भी प्रदान की। एल० एच० जेम्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 216।
134. पी० पी० एच० सी० 1872, जिल्द 8, पत्रक 327, वित्त संबंधी प्रश्न, गमिति के सामने साध्य डब्ल्यू० थोर्नटन (3032 और आगे), स्ट्रैची (6380-81), जी० चेन्नई (2623)।
135. भारत सरकार से भारत मंत्री को, रेल विभाग प्रेषण संख्या 125, 3 दिसंबर, 1867, अनुत्तम गवर्नर जनरल सारेंस का मेमो०, दिनांक 16 अगस्त, 1867।
136. भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण, संख्या 5, 24 जनवरी, 1868।
137. आरगाइल से मेयो को, 17 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडस 48, संख्या 1।
138. वही।
139. मेयो से आरगाइल को, 21 दिसंबर, 1868, मेयो कागजात, बडस 37, संख्या 363।
140. भारत सरकार से भारत मंत्री को, रेल विभाग प्रेषण संख्या 24, 11 मार्च, 1869। भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण संख्या 42, 15 जुलाई, 1869।
141. आरगाइल से मेयो को, 12 फरवरी, 1869 मेयो कागजात, बडस 47, संख्या 7।
142. वही।
143. आरगाइल के ड्यूक का वित्त संबंधी वक्तव्य 23 जुलाई, 1869। 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिप्रिंटेड फ्राम हुआईंस पार्लियामेन्टरी डिबेट्स' (कलकत्ता, 1873), पृ० 810।
144. आरगाइल से मेयो को, 12 फरवरी, 1869, मेयो कागजात, बडस 47, संख्या 7।
145. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 144, 29 जून, 1860। प्रेषण का संपूर्ण मसौदा विल्सन ने तैयार किया था। उसने लिखा है 'मैं लगभग अकेले ही रेल व्यवस्था प्रारंभ करने में प्रेरक रहा हूँ।' जे० विल्सन से लार्ड कनिंग को, 25 अगस्त, 1859 (ई० बी० II पृ० 181)। विल्सन का इस संबंध में दावा अतिशयोक्तिपूर्ण है।
146. फ्रेनबोर्न से जे० सारेंस को, 3 नवंबर, 1866, सारेंस कागजात, भारत मंत्री से जे० सारेंस को पत्र, जिल्द III, संख्या 39।
147. स्ट्रैची, 'इंडिया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोब्लेम्स' (लंदन, 1911) पृ० 228-234। विलियम डी थोर्नटन, 'पब्लिक वर्क्स इन इंडिया' (लंदन, 1875)। सर, ए० काटन, 'पब्लिक वर्क्स इन इंडिया' (लंदन, 1854)।
148. एल० एच० जेम्स, 'दि माइग्रेशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटल' (लंदन, 1938), पृ० 208 : ईस्ट इंडिया कंपनी के रोस डी० मैंगल के एक वक्तव्य के अनुसार 1834 से 1848 के बीच कंपनी ने अपनी 2 करोड़ पाँड की वार्षिक आय में से केवल 14 लाख 34 हजार पाँड लोक-निर्माण पर व्यय किया (वही, पृ० 208)। 1858 में भाषण करते हुए जान ब्राइट ने कहा था कि अकेले मैनचेस्टर में वहाँ के निवासियों के लिए केवल पानी की व्यवस्था पर उससे बड़ी अधिक धन व्यय किया गया है जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1834 से 1858 के बीच चौदह वर्षों में संपूर्ण उपनिवेश में हर तरह के लोक निर्माण पर व्यय किया है। (जे० स्ट्रैची

द्वारा उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 233) ।

149. देखें परिशिष्ट ।
150. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 239, 18 सितंबर, 1868 ।
151. 'इंडियन फाइनेंस' (लंदन, 1880), पृ० 155 ।
152. देखें विवादात्मक पैफलेट, एल० सी० प्रोविन, 'इज इंडिया सोल्वेड' (लंदन, 1880), तथा डब्ल्यू० एम० योर्नबर्न, 'इंडिया सोल्वेड' (मद्रास 1880) । प्रोविन जिसकी दृष्टि प्रोफेसर फासट से अधिक साफ थी व्यक्ति और सरकार के स्थिति विवरणों में अंतर को देख सका । पूर्वोद्धृत, पृ० 13 ।
153. भारत मंत्री से भारत सरकार को, सार्वजनिक प्रेषण सख्या 39, 8 अगस्त, 1864 ।
154. भारत सरकार से भारत मंत्री को, लोकनिर्माण प्रेषण सख्या 29, 9 मार्च, 1865 । भारत सरकार से भारत मंत्री को, पृथक राजस्व प्रपक सख्या 13 और 14 दिनांक क्रमशः 7 व 8 अप्रैल, 1865 ।
155. भारत मंत्री से भारत सरकार को, 30 नवंबर, 1860, वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1866, व्यय शाखा 236 ।
156. कैनबोर्न से जे० लारेस को, 3 नवंबर, 1866, सार्वजनिक प्रेषण, भारत मंत्री से जे० लारेस को पत्र, गिल्ड III, संख्या 39 ।
157. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संख्या 200, 23 अगस्त, 1866 ।
158. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 210, 21 सितंबर, 1866 । भारत मंत्री ■ भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 263, 9 नवंबर, 1866 ।
159. कैनबोर्न से जे० लारेस को, 3 नवंबर, 1866, जे० लारेस कागजात, भारत मंत्री से जे० लारेस को पत्र, गिल्ड III, संख्या 39 ।
160. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 255, 20 दिसंबर, 1866 । यद्यपि अधिकारी सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों की लाभकारी प्रकृति पर जोर देते थे तथापि इनसे कहाँ तक लाभ होता है यह निर्धारित कर पाना असंभव था । उदाहरणार्थ, क्या सिंचाई, सुविधाओं के फलस्वरूप मालगुजारी में वृद्धि को लोक निर्माण में पूँजी निवेश के लाभ के रूप में दिखा सकना संभव था ? मद्रास में सिंचाई की व्यवस्था होने से पहले और उसके बाद की मालगुजारी के रूप में प्राप्तियों के अंतर को सिंचाई निर्माण कार्यों का लाभ माना गया । अतः मद्रास में सिंचाई निर्माण से लाभ की दर ऊँची थी । पश्चिमोत्तर प्रांत में केवल खेतों की सिंचाई से प्राप्त होने वाली राशि को ही सिंचाई निर्माणों के लाभ के रूप में दिखाया गया था । अतः लेख में सिंचाई से थोड़ा लाभ दिखाई देता था जबकि सरकार को मालगुजारी के रूप में लाभ हुआ था । (मह. कार्यविवरण, राजस्व, 28 मई, 1870, सख्या 15 (7) । कर्नल आर० स्ट्रैची की रिपोर्ट, दिनांक 2 सितंबर, 1869) । 1857-58 से 1862-63 के मध्य मद्रास के कुछ सिंचाई निर्माणों से पूँजी पर 4 प्रतिशत व्याज चुका देने के बाद 0.3 प्रतिशत से लेकर 29.9 प्रतिशत तक शुद्ध लाभ हुआ जबकि कुछ अन्य पर शुद्ध भार 0.3 प्रतिशत से लेकर 54.3 प्रतिशत तक था । परंतु कुल मिलाकर निर्माण कार्य लाभकारी थे । परंतु इसी अवधि में पश्चिमोत्तर प्रांत में काफी हानि हुई (भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण 266, 30 नवंबर, 1865) ।



161. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 79, 28 फरवरी 1867 । 1867-68 के बजट में सिंचाई निर्माण पर व्यय को चालू खाते से हटा कर ऋण खाते में दिखाया गया । (भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 73, 8 मार्च 1867) । भारत सरकार ने भारत मंत्री का 28 फरवरी 1867 का प्रेषण प्राप्त होने पर बजट विवरण बदल दिया (क) सिंचाई सबंधी निर्माण कार्य पर व्यय को 'ऋण' से हटा कर 'असाधारण खर्चों' में डाल दिया गया, (ख) इंडिया आफिस से आदेश आने पर जेलों के लिए अनुदान 'असाधारण खर्चों' में से घटा दिया गया । लेखा पद्धति में इस प्रकार के परिवर्तनों से भारतीय वित्त संबंधी आंकड़ों की तुलना कर पाना बहुत कठिन हो गया है ।
162. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 220, 14 जून, 1867 ।
163. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 288, 9 जुलाई, 1868 । आदेशानुसार भारत सरकार ने सैन्य निर्माण, संचार, सड़कघन और जेलों पर सभी खर्चों को 'साधारण व्यय' की श्रेणी में रखा था । अतः संपूर्ण ओझ वर्ष विशेष-के राजस्व पर ही पड़ जाता था । केवल सिंचाई और विशिष्ट निधि निर्माण 'असाधारण व्यय' की श्रेणी में रखे गए थे और इन पर व्यय को ऋणों से पूरा किया गया था । (भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण 283, 21 अक्टूबर, 1868, सख्या 013, 23 नवंबर, 1868)
164. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 72, 25 फरवरी 1867 ।
165. वित्त कार्यविवरण, जनवरी 1867, व्यय खाखा सख्या 193, लोक निर्माण विभाग में सपरिवर्तन गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्ताव, 22 जनवरी, 1867; सख्या 194, वित्त विभाग में प्रस्ताव, 31 जनवरी 1867 ।
166. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1869 । लेखा खाखा सख्या 15 । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 477, 23 दिसंबर, 1867 ।
167. मेयो को आरगाहल से, 16 मार्च, 1869, मेयो काबजात' बंडल 34, सख्या 102 ।
168. मेयो का भी यही मत था ।
169. यह निर्धारित कर पाना कठिन था कि सिंचाई निर्माण कार्य कहां तक लाभकारी था । देखें पाव टिप्पणी सख्या 160 ।
170. आरगाहल के मेयो को पत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1869 (बंडल 47, सख्या 7) और 17 जनवरी, 1870 (बंडल 48, सख्या 1) में उसके लोक निर्माण के विषय में विचार मौजूद हैं ।
171. 'फैंड आफ इंडिया,' 10 अक्टूबर, 1861 । वृत्त प्रवाण', 2 मई, 1868 (आर० एन० पी० बवई, 1868, पृ० 31) । 'हिंदू रीफार्मर,' 1 नवंबर, 1869 (आर० एन० पी० बवई, 1869 पृ० 554) । 'ज्ञान प्रकाश,' 15 नवंबर, 1869 (आर० एन० पी० बवई, 1869, पृ० 586) । वही 22 जून, 1868 (आर० एन० पी० बवई, 1868, पृ० 134, । 'आमाम मिहिर,' 28 मई, 1873 (आर० एन० पी० बगाल, दिनांक 14 जून, 1873) । 'समवाद पूर्णचंद्रोदय,' 11 जुलाई, 1868 (आर० एन० पी० बगाल, 1868, पृ० 147) । 'प्रवाण दूत,' 15 जुलाई 1868 ।
172. 'मोम प्रमाण,' 23 नवंबर, 1868 (आर० एन० पी० बगाल, 1868, पृ० 343), 'हिंदू रीफार्मर,'

- 1 दिसंबर, 1869 (आर० एन० पी० बवई, 1869, पृ० 604) । 'सडे रिव्यू', 6 मई, 1870 (आर० एन० पी० बवई, 1870, पृ० 134) । 'ज्ञान प्रकाश', 27 जुलाई, 1868 (आर० एन० पी० बवई, 1868, पृ० 211) ।
173. बंबई एगोसिएशन तथा बंबई प्रेसीडेंसी की ओर से प्रतिवेदन (1871) पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, परिशिष्ट पृ० 511 ।
174. मेयो से एच० वॉटल फेर को, 21 अगस्त, 1869, मेयो कागजात, बडल 36, संख्या 208 ।
175. वित्त कार्यविवरण, सितंबर, 1869 । मेया शाखा 54, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, लोक-निर्माण विभाग, 11 सितंबर 1869 ।
176. पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, वित्त संबंधी प्रवर समिति का कार्यविवरण, गेह्स का साक्ष्य (9968-71) । अलेक्जेंडर आर० बिनी, 'पब्लिक वर्क्स इन इंडिया - ए सैंटर एंड्रैड टु दि राइट ओनरेबल डब्ल्यू० ई० ग्लेहस्टन', 'एम० पी० एड अदर मेंबर्स आफ हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट' (लंदन, 1881) । बिनी जो भारतीय लोक निर्माण विभाग में एक कर्मचारी था कहता है कि जहा इंग्लैंड में भिविल इंजीनियोरिंग प्रभार निष्पन्न निर्माण कार्य के मूल्य का 5 से 6 प्रतिशत तक था, वहा भारत में स्थापन भव्य के रूप में 25 से 30 प्रतिशत तक खर्च किया जाता था ।
177. भारत सरकार से भारत मंत्री को, लोक निर्माण विभाग प्रेषण संख्या 67, दिनांक 30 जून, 1865; तथा संख्या 3, दिनांक 6 जनवरी, 1865 । भारत सरकार से भारत मंत्री को, लोक निर्माण विभाग (सैन्य) प्रेषण संख्या 34, दिनांक 17 मार्च, 1865, संख्या 52, दिनांक 11 मई, 1865, तथा संख्या 108, दिनांक 30 अगस्त, 1865 ।
178. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संख्या 252, 8 नवंबर, 1865 ।
179. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 10, 12 जनवरी, 1865 (गोपनीय) ।
180. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संख्या 252, 8 नवंबर, 1865 । इस मद के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्राक्कलित व्यय निम्नलिखित था
- |                        |
|------------------------|
| 1865-66—12,70,000 पाँड |
| 1866-67—20,00,000 पाँड |
| 1867-68—28,00,000 पाँड |
| 1868-69—28,00,000 पाँड |
| 1869-70—25,00,000 पाँड |
181. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 239, 18 सितंबर, 1868 ।
182. 'दि रास्त गोफ्तार' (बवई) ने ईर्ष्या भाव से लिखा कि यूरोपीय सैनिकों की बैरको पर व्यय अत्यधिक था ('रास्त गोफ्तार', 30 अक्टूबर, 1870, आर० एन० पी० बवई, 1870, पृ० 525) । इसे घोर 'अक्षपात' का उदाहरण बतलाया गया ('रास्त गोफ्तार', 24 अक्टूबर, 1869, आर० एन० पी० बवई, 1869, पृ० 543) । 'सोम प्रकाश', 7 नवंबर, 1864, आर० एन० पी० बगाल, 14 नवंबर, 1864 की रिपोर्टें) ।
183. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 10, 12 जनवरी, 1865 (गोपनीय) ।
184. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 210, 21 सितंबर, 1866 ।

185. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सध्या 258, 20 दिसंबर, 1866 ।
186. वही ।
187. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सध्या 72, 25 फरवरी, 1867 ।
188. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सध्या 79, 28 फरवरी, 1867 ।
189. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सध्या 228, 9 जुलाई, 1868 ।
190. भारत सरकार से भारत मंत्री, वित्त प्रेषण सध्या 283, 21 अक्टूबर, 1868 । अनुसार 1868-69 के बजट में परिवर्तन किया गया । बजट में मूल प्रायश्चित्त के अनुसार 2.4 करोड़ रुपये का अधिष्य था । वास्तव में बजट में उम खर्च 4.1 करोड़ रुपये का पाटा था । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सध्या 313, 30 नवंबर, 1868 ।
191. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1868, लेखा शाखा सध्या 88, इन्स्यू. आर. मैसफील्ड का मेमो., 14 मार्च, 1868 ।
192. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1858, लेखा शाखा 87, सर एच. एम. ड्यूरेड का मेमो., 13 मार्च, 1868 । और भी, ड्यूरेड का 23 मार्च, 1868 का मेमो., पूर्वोक्त स्थल, सध्या 91 । इसी रूपरेखा के आधार पर ड्यूरेड का 17 अगस्त, 1868 का मेमो. । वित्त कार्यविवरण सितंबर, 1868, लेखा शाखा सध्या 164 ।
193. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1868, लेखा शाखा 89, जे. सार्वेन का मेमो., 18 मार्च, 1868 ।
194. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1868, लेखा शाखा 90, जे. स्टुडी का मेमो. ।
195. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1868, लेखा शाखा 88, इन्स्यू. आर. मैसफील्ड का मेमो., 14 मार्च, 1869 ।
196. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सध्या 239, सितंबर, 1868 (आर. एन. पी. बगल, 1868, पृ. 253) । 'मुफीद-ए-आलम', 15 जुलाई, 1871 (एन. बी. एन., परिचमोत्तर प्रात, 1871, पृ. 401) । 'कुमकीणम एयेनायम,' 17 जुलाई, 1872 (रिपोर्ट धान समित प्रेम, दिनांक 31 जुलाई, 1872) । 'हिंदू पेडिअट,' 12 दिसंबर, 1880 और 21 फरवरी, 1870 ।
197. जे. स्टुडी, भारतीय लोक वित्त से संबंधित कुछ प्रश्नों के तबय में स्मरण पत्र । पी. पी. एच. सी. 1874, गिल्ड 47, पत्रक 326, पृ. 245 ।
198. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सध्या 7, 13 जनवरी, 1866, टीक वही, वित्त सध्या 37, 14 फरवरी, 1866 । गृह कार्यविवरण, 10 फरवरी, 1866, सध्या 1, 387 । जे. स्टुडी द्वारा स्मरण पत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1865 व 27 सितंबर, 1865, गवर्नर जनरल का मेमो., 7 अक्टूबर, 1865; इन्स्यू. एन. मेमो का मेमो., 29 दिसंबर, 1865 । भारत सरकार से भारत मंत्री को, न्यायिक प्रेषण सध्या 30, 4 जुलाई, 1863 ।
199. 'इंडियन डेली न्यूज' 27 फरवरी, 1866 । उसके अनुसार 8 वर्षों में जीवन निर्वाह के स्तर में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । वही 17 फरवरी, 1866 ।
200. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1865, पेंशन व प्रेचुटी, सध्या 90 । भारत सरकार के कुछ वर अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा वायमराय को विनम्र स्मरण पत्र, अगस्त, 1864 ।

201. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1865। व्यय प्रकीर्ण सख्या 415। सेनाध्यक्ष का मेमो०, 30 नवंबर, 1864।
202. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1865। पृथक् राजस्व संख्या 309। सचिव, बंबई सरकार से सचिव, भारत सरकार को, 7 जनवरी, 1865।
203. जुलाई, 1863 में बंबई सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने खाद्यान्न भत्ते की सिफारिश की थी। भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 22, 5 फरवरी, 1864। यद्यपि अतिरिक्त व्यय अनियमित था, तथापि अस्थाई उपाय के रूप में उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त 118, 16 मई, 1864। खाद्यान्न भत्ते 1867 तक दिए गए जबकि वेतनो में स्थाई रूप से वृद्धि की गई थी। वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1867। लेखा शाखा सख्या 109। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 30 अप्रैल, 1867।
204. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 74, 17 अप्रैल, 1865; वित्त सख्या 38, 14 फरवरी 1866, वित्त संख्या 43, 20 फरवरी, 1866, वित्त सख्या 160, 24 जुलाई, 1866, वित्त सख्या 96, 26 मार्च, 1867।
205. भारत सरकार से भारत मंत्री को, गृह (लोक शाखा) सख्या 37 व 42, दिनांक क्रमशः 8 और 15 जून 1861। भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 110, 4 अगस्त, 1882। भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 205, 8 दिसंबर, 1862।
206. गृह कार्यविवरण दिसंबर, 1868, लोक शाखा 66। इस विवरण में भारत सरकार को नौकरी में हिंदुस्तानी नियो की सख्या को दिखाया गया है।
207. वित्त कार्यविवरण, जून, 1870, पेंशन व प्रेचुटी, सख्या 67। बंगाल के अनुबंधित सरकारी अफसरों का ह्यूक आफ आरगाइल को स्मरणपत्र, वही सख्या 70 व 71। मद्रास और बंबई के अनुबंधित सरकारी अफसरों का सर एस० नोर्थकोट को स्मरण पत्र।
208. आरगाइल से मेमो को, 11 अप्रैल, 1871, मेमो कागजात बडल 49, सख्या 8।
209. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 155, 24 जून, 1870। ठीक वही वित्त सख्या 171, 14 जुलाई, 1874।
210. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 52, 10 फरवरी, 1871।
211. सदनानुसार अधिनियम बनाए गए। वित्त कार्यविवरण, 1871; पेंशन तथा प्रेचुटी, सख्या 17। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 31 मार्च, 1871। निवृत्ति भत्ता इंग्लैंड में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार दिया जाता था। वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1871। पेंशन तथा प्रेचुटी सख्या 61-62। बाद में जब रुपया स्टलिंग दर भारत के विपरीत हो गई तो सरकार को स्टलिंग में निर्धारित पेंशनो पर हानि हुई।
212. आरगाइल से मेमो को, 3 अप्रैल 1871, मेमो कागजात, बडल 49, संख्या 5।
213. आरगाइल से मेमो को, 11 अप्रैल 1871, मेमो कागजात, बडल 49, सख्या 8।
214. वही। मेमो का दावा था कि स्वहित द्वारा निर्णय प्रभावित नहीं था क्योंकि इस संबंध में परिपद के असैनिक सदस्यों ने न तो कोई टिप्पणी की थी और न ही कोई सिफारिश की थी। मेमो से आरगाइल को, 23 मार्च, 1871, मेमो कागजात, बडल 43, सख्या 110। इस दर से कि कही सरकारी अफसर पेंशनो में वृद्धि की अस्वीकृति के धारे में प्रेषण की ध्वनि से नाराज

न हो, मेयो ने आरगाइल से अनुरोध किया कि वह उसे प्रकट न करे। आरगाइल से मेयो को, 22 जून, 1871, मेयो कागजात, बडल 49, सध्या 14।

215. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल 15, 1862। प्रकीर्ण सध्या 25। अर्गनिक वित्त आयोग से वित्त सचिव, 20 मार्च, 1862।
216. 'फैंड आफ इंडिया' 8 मई, 1862; वही 26 फरवरी, 1863।
217. वित्त कार्यविवरण, नवंबर, 1869। लेखा शाखा 48. गवर्नर जनरल द्वारा स्मरण पत्र। 4 अक्तूबर, 1869। मेयो से आरगाइल को, 9 जनवरी 1871। मेयो कागजात, बडल 42, सध्या 13।
218. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सध्या 144, 29 जून, 1860।
219. वित्त कार्यविवरण, मई 1860, सध्या 21, वित्तीय विज्ञप्ति, 27 अप्रैल, 1860; 23, जे० विस्तन से भारत मंत्री, 28 अप्रैल, 1860।
220. वही, सध्या 25, वित्तीय विज्ञप्ति, 10 मई, 1860।
221. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 53, 9 अप्रैल, 1864। भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त 14, 9 जुलाई, 1862, और भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त 116, 16 सितंबर, 1863।
222. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 62, 22 मई, 1863।
223. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 240, 20 सितंबर, 1869। ठीक वही, वित्त 258, 11 अक्तूबर, 1869।
224. आर० ट्रेपिल, 'दि स्टोरी आफ माई लाइफ' (सदन, 1866) जिल्द I, पृ० 201, 208।
225. वित्त कार्यविवरण दिसंबर, 1871, सध्या 38। भारत सरकार की विज्ञप्ति, 20 दिसंबर, 1871।
226. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त (गोपनीय) सध्या 130, 16 जून, 1871।
227. मेयो से आरगाइल को, 27 मई, 1870, मेयो कागजात, बडल 39, सध्या 141।
228. देखें IV ऊपर।
229. ए० काटन, 'पब्लिक वर्क्स इन इंडिया' (सदन, 1854), पृ० 52-53। और भी देखें, पृ० 25-29 और 49-52।
230. 'टाइम्स आफ इंडिया,' 9 मई, 1863।
231. इंडियन इकानामिस्ट, 11 जुलाई, 1870। केवल 'दि फैंड आफ इंडिया' ने ही बड़े पैमाने पर उधार लेने के लिए सरकार की निंदा की थी। देखें संपादकीय 4 दिसंबर, 1865, 11 मार्च 1869।
232. 'रास्त गोप्तार,' 11 सितंबर, 1870, आर० एन० पी० (बवई) 1870, पृ० 443; वही, 9 अक्तूबर, 1870; आर० एन० पी० (बवई), 1870, पृ० 491। 'सोम प्रकाश,' 30 जुलाई, 1866; आर० एन० पी० (बंगाल) दिनांक 9 अगस्त, 1866।
233. हाउस आफ कामन्स में पेश की गई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की याचिका, (अर्दी), 17 फरवरी, 1871, 'जनरल, आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,' जिल्द V, 1871, खंड II, पृ० 128-29।
234. वित्त कार्यविवरण, मई, 1870। पृथक राजस्व सध्या 83, बवई चेंबर आफ कामन्स से लार्ड

मेयो को, 18 अप्रैल, 1870 ।

235. टी० जेफरीज, 'नेशनल क्रेडिट एंड पब्लिक वर्ग' (नाराची, 1871), II पृ० 14 ।
236. धी० नाइट, 'दि फाइनेंसियल स्टेटमेंट दैट शुड हैव बीन डिस्मिस्ड एंड वाज नाट' (बवई, 1870) अज्ञात नाम से प्रकाशित, पृ० 42 । नाइट 'इंडियन इकानामिस्ट' का सस्थापक संपादक था ।
237. आरगाइन से मेयो को, 12 मार्च, 1869, मेयो कागजात, बडल 47 ।
238. हैलीफाक्स (सी० वुड) से जे० लारेंस को, 10 मार्च, 1866, लारेंस कागजात, भारत मंत्री से जे० लारेंस को पत्र, जिल्द III, सख्या 13 ।
239. मेयो से आरगाइन को, 16 मार्च 1869, मेयो कागजात, बडल 34, सख्या 102 । मेयो की सूचना बहुत सही होती थी । एत० सी० जैन 'इंडिजिनस बैंकिंग इन इंडिया', लंदन, 1929, पृ० 250) के अनुसार स्वदेशी बैंकरो की ग्याज दरे प्रतिभूतियों के स्वरूप के अनुमार 6 से 18 प्रतिशत के बीच मे रहती थी ।
240. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 149, 24 जून, 1870 ।
241. वही, वित्त (गोपनीय), सख्या 130, 16 जून, 1871 ।
242. वही, वित्त सख्या 16, 5 फरवरी, 1861,  
वही, वित्त सख्या 37, 13 मार्च, 1861,  
वही, वित्त सख्या 258, 20 दिसंबर, 1866 ।
243. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1867 । लेखा शाखा सख्या 106, बवई की सरकार से भारत मंत्री को, 8 अक्टूबर, 1866 ।
244. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1867 । लेखा शाखा सख्या 108, वित्त सचिव, भारत सरकार से सचिव, लोक निर्माण विभाग, बवई सरकार को, 21 जनवरी, 1867 ।

## राजस्व की मदें : नीति संबंधी कुछ प्रश्न

जिस समय सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ उस समय तक ब्रिटिश भारत के विभिन्न भागों में भूधृति प्रणाली, 1765 से धीरे-धीरे आकार ग्रहण करती हुई, जमींदारी, रंगत-वाड़ी तथा महालवाड़ी नामक व्यवस्थाओं में ढलकर ठोस हो चुकी थी। इन सभी प्रणालियों पर उन ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों की सतही छाप थी जिनके शब्दों को भारत में तात्त्विक रूप से व्यावहारिक निर्णय प्रक्रिया को कुछ बौद्धिक तत्व प्रदान करने के लिए कांफ़ी उद्धृत किया जाता था। भूधृति प्रणाली, जो सैन्य विद्रोह के बाद लगभग अपरिवर्तित रही, तथा भूमि संबंध जिन्हें उत्तर सैन्य विद्रोह काल के विधान द्वारा नियमित करने का प्रयास किया गया था, स्पष्ट रूप से इस अध्ययन क्षेत्र के बाहर है। यहाँ पर भूमि में हमारी दिलचस्पी केवल राजस्व के साधन के रूप में अथवा भूमि कर (मालगुजारी) की दृष्टि से है। मालगुजारी के संबंध में हमारे अध्ययन की अवधि का सबसे महत्वपूर्ण नीति विषयक मामला स्थाई बंदोबस्त का उन क्षेत्रों में विस्तार का प्रश्न था जो उस वक्त समय-समय पर संशोधित अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत थे। इस प्रकार के स्थाई बंदोबस्त द्वारा मालगुजारी में सरकार की आय में उत्तरोत्तर होने वाली वृद्धि रुक जानी थी। चूंकि सरकार की आय का 40 प्रतिशत से अधिक भाग मालगुजारी से आता था, इसलिए यह प्रश्न निर्णायक महत्व का था।

उन्नीसवीं सदी के भारत में स्थाई बंदोबस्त राजस्व विधान का एक शब्द मात्र न होकर एक सामाजिक दर्शन था। स्थाई बंदोबस्त ने स्थिरता एवं व्यवस्था के सिद्धांत को जन्म दिया था। यह सिद्धांत अति पवित्र निजी संपत्ति की प्रथा पर आधारित, भूमि तथा लाभप्रद पूंजी निवेशों से प्राप्त होने वाली अनवरत आय द्वारा संपोषित और उच्च-वर्गीय संघों द्वारा मुखरित था। ये उच्चवर्गीय संघ भूस्वामी तथा लगान जीवी (रांठिया) वर्गों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे में, उसी स्थान की मांग कर रहे थे जो 'भूमि से स्थाई रूप से संबद्ध' और (ब्रिटिश) 'राज' के प्रति वफादार 'ममाल के स्वाभाविक नेताओं' को मिलना चाहिए था। बंगाल इस सिद्धांत का घर था परंतु अन्य स्थानों पर भी इसे स्वाभाविक ढंग से अपना लिया गया था। इस सिद्धांत और ज़िह्न राजनीतिक विचारों में सादृश्य तथा उपयोगितावादी विचारधारा से इसकी भिन्नता के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मालगुजारी नीति को एक सैद्धांतिक आयाम भी मिल गया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ऐसा प्रतीत होता था कि तथाकथित बंगाल विचारधारा पर मिन के अनुयायियों की पूर्ण विजय हो गई है। फिर भी, सातवें दशक में

स्थाई बंदोबस्त के विचार को पुनः जीवन दिया गया। 1862 में भारत मन्त्री ने संपूर्ण भारत में मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त के विषय में सरकार द्वारा स्वीकृति देने के निर्णय की घोषणा की।<sup>1</sup> अगले दो दशकों में जबकि इस प्रकार के बंदोबस्त का विस्तार करने के पक्ष विपक्ष पर विचार किया जा रहा था, इस संबंध में निर्णय स्थगित कर दिया गया और 1883 में अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया।<sup>2</sup> स्थाई बंदोबस्त लागू करने और फिर इस निर्णय से धीरे-धीरे हटने के पीछे प्रयोजनों का अध्ययन उत्तर सैन्य विद्रोह काल का प्रमुख दिलचस्प विषय है।

वारेन हेस्टिंग्स पर अपने निबंध में मैकाले यों ही एक मनोरंजक बात कह गया है। ब्रिटिश भारतीय अफसरों की शब्दावली में 'राजनीतिक' शब्द 'राजनयिक' का पर्यायवाची था। सरकारी अफसर आंतरिक प्रशासन का कार्य तो योग्यतापूर्वक संपन्न करता था, परंतु वह 'राजनीतिक व्यापार से बिल्कुल अनभिज्ञ' था।<sup>3</sup> दूसरे शब्दों में, अधिकारियों के विचार से साम्राज्य के प्रशासन की कल्पना राजनीतिक पहलू से नहीं की गई थी। जिला अधिकारी तथा कलकत्ते में रहने वाले नौकरशाह प्रशासनिक निर्णयों और कार्रवाइयों की सामाजिक एवं राजनीतिक जटिलताओं की ओर ध्यान नहीं देते थे। अतः स्थाई बंदोबस्त बहुधा राजस्व संग्रह में एक विशुद्ध मुविधा के प्रश्न के रूप में लिया जाता था। तथापि निर्णय प्रक्रिया के ऊंचे स्तरों पर भ्रूति तथा बंदोबस्त व्यवस्था के सामाजिक प्रभावों के विषय में अधिक चेतना थी। गवर्नर जनरल की परिपद में वित्त सदस्य समुअल लैंग की दृष्टि में स्थाई बंदोबस्त नवीन सामाजिक-व्यवस्था का आधार था। उसके ही शब्दों में, 'हमारी सरकार का उद्देश्य इस देश से अधिकाधिक धन की प्राप्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य यहां की भारी जनसंख्या को समान रूप से निश्चेष्ट स्तर पर भी नहीं रखना है यद्यपि वह पितृवादी सरकार की छत्रछाया में भ्रूतिधारी काश्तकार के रूप में काफी प्रसन्न तथा संतुष्ट हो सकती है। यदि हम स्थाई बंदोबस्त करते हैं... तो हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नींव डालते हैं जिसकी व्यवस्था संभवतः सरल नहीं है, परंतु जो सभ्यता तथा प्रगति के तत्वों की दृष्टि से संपन्न होने के साथ-साथ विविधता भी लिए हुए है।'<sup>4</sup> स्थाई बंदोबस्त लागू होने पर 'यद्यपि कठिनाइयों, असमानताओं और टकराव में वृद्धि हो सकती है परंतु उस स्थिति की तुलना में, जहां सरकार सर्वोत्तम है, इस व्यवस्था में अधिक जीवन, क्रिया और प्रगति होगी... यदि हमें पूर्व के देशों में कुछ करना है तो वह यह है कि हम पूर्वी निरंकुशतावाद के परंपरागत स्वीकृत ढांचे के स्थान पर कोई अच्छी व्यवस्था ढोंजें।' लैंग ने माना था कि इससे समाज में श्रेणीकरण एवं असमानताएं होंगी। परंतु यह तो अपरिहार्य था चाहे मालगुजारी देने वाला व्यक्ति ज़मींदार हो अथवा जमीन को बेचने या शिकमी देने के अधिकार के साथ सांविधिक (कानूनी) काश्तकार।<sup>5</sup> तात्पर्य यह कि वर्तमान राजस्व प्रदाई रैयतों के हित वर्ग तथा स्थाई भ्रूति की स्थापना में भारी मध्यम लोग लगान देने वाले काश्तकार या मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक बनने लगेंगे। जो रैयत जमीन पर पूर्ण स्वामित्व पा जाएंगे वे उसे कई भागों में बेचेंगे अथवा शिकमी देंगे। इन प्रकार एक मध्यवर्ती वर्ग बन जाएगा। लैंग तथा सर चार्ल्स वुड के अनुसार इस



प्रकार का मध्यम वर्ग नितान्त वांछनीय था और सर जान लारेंस जिसकी सहज सहानु-भूति मध्यम वर्गों की तुलना में छोटे जमींदारों के साथ अधिक थी, इनसे सहमत था। 9 जुलाई, 1862 के अपने राजस्व प्रेषण में संपूर्ण भारत के लिए स्थाई बंदोबस्त की सिफारिश करते हुए बूड ने आशा व्यक्त की थी कि देश में 'भूमि से संबद्ध मध्यम वर्ग का धीरे-धीरे विकास होगा।' लारेंस ने भी इस प्रकार के वर्ग की जिसकी 'निश्चित रूप से सरकार के प्रति निष्ठा' होगी, वांछनीयता बतलाई।<sup>6</sup> परंतु ऐसा लगता है कि उसकी धारणाएं लैंग से भिन्न थी। लारेंस तत्कालीन 'छोटे जमींदारों तथा स्वत्वधारी किसानों को भूमि से वंचित किए बिना' भूमि से संबद्ध मध्यम वर्ग का विकास चाहता था यद्यपि, जैसा कि लैंग को अच्छी तरह पता था, स्वत्वधारी किसानों के स्वत्व का हरण नए मध्यम वर्ग के विकास की प्रक्रिया का अंग था। लारेंस अपने पंजाब के दिनों से 'लोक कल्याणवादी' हो सकता है, परंतु लैंग अथवा बूड के दृष्टिकोण में वैसा कुछ नहीं था। यह कहा जाता है कि सैन्य विद्रोह के बाद स्थाई बंदोबस्त से संबंधित प्रस्ताव का दोबारा आना जान लारेंस के प्रशासन में लोककल्याणवाद का पुनरुत्थान था।<sup>7</sup> परंतु स्थाई बंदोबस्त के अधिकांश समर्थकों का दृष्टिकोण मूलतः व्यावहारिक था, और उनके सामा-जिक दर्शन में लोककल्याणवाद की ओर प्रत्यावर्तन का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

स्थाई बंदोबस्त की समस्या को सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में समझने के लिए इस विषय में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर गौर करना भी आवश्यक है। स्थाई बंदोबस्त उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के दशकों के राष्ट्रवादियों के आर्थिक कार्यक्रमों का अनिवार्य अंग था। इनमें रमेश दत्त स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत के प्रधान समर्थक थे। 1875 में रमेश दत्त जमींदार और रैयत के बीच में ठीक उसी प्रकार के स्थाई बंदोबस्त का समर्थन कर रहे थे जैसा कि जमींदार और सरकार के बीच था।<sup>8</sup> 1793 के विनियम (रेग्यु-लेशन)। द्वारा रैयत को जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया था। बाद के काश्त-कारी कानूनों ने रैयत को कुछ विधिक अधिकार दिए, परंतु नविया तथा पाबना में हुए उसी समय के उपद्रवों से कृषकों में असंतोष की तीव्रता एवं मात्रा का पता चला। रमेश दत्त ने सरकार में ऐसा उपाय करने के लिए कहा जिससे कि जमींदारों तथा रैयतों के वर्गों के बीच 'दुर्भाग्यना दूर हो सके'। उन्होंने तर्क दिया कि इस दिशा में पहला उपाय रैयत द्वारा दिए जाने वाले लगान की दरों का स्थाई बंदोबस्त है। रमेश दत्त के सिविल सेवा के साथी अफमरो ने सावधान करते हुए उनसे कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना से सिविल सेवा में उसकी पदोन्नति की संभावनाएं नष्ट हो सकती हैं। इस पर दत्त ने अपने भाई को लिखा कि 'नौकरी में मैं पदोन्नति की अधिक चिंता नहीं करता, परंतु सीमाव्यवस्था अन्य पुस्तकें जो मैं लिखना चाहता हूँ भारत की राजनीति के विषय में नहीं है।'<sup>9</sup> जमींदारों के हितों के मुखपत्र 'हिंदू पेट्रिअट' ने 'इंग्लैंड में कुछ वर्षों तक रह कर नए विचारों के साथ भारत लौटने वाले युवकों में' 'क्रांतिकारी भावना' की स्पष्ट शब्दों में निंदा की। इस कटु निंदा के लेखक क्रिस्टोदास पाल का विचार था कि 'उम्र बढ़ने के साथ तृणाई का असंयम दूर होकर इन युवकों में गंभीरता आ जाएगी।' दत्त के दामाद और जीवनी लेखक जे० एन० गुप्ता ने भी उनकी 'जमींदारों

के दावों के प्रति पर्याप्त न्याय' करने में असफलता के कारण 'तरुणाई का जोश और अपरिपक्वता' बतलाए हैं। ऐसा लगता है कि दत्त पर विभिन्न दिशाओं से दबाव था और यह उनकी वाद की लिखी गई चीजों से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने विचारों में काफी संशोधन कर लिए थे।<sup>10</sup> दत्त की रचनाएं, विशेष रूप से 'दि पीजेंट्री आफ बंगाल (1875) तथा फेमीस इन इंडिया, (1900) रैयत के प्रति गहरी सहानुभूति से ओत प्रोत थी और इन्होंने भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में ए० पी० मैकडोनल तथा एच० जे० रेनोल्ड्स जैसे ब्रिटिश प्रशासकों, दादाभाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादियों तथा भारतीय घटना स्थल से दूर प्रिंस क्रोपोटकिन जैसे लोगों को प्रभावित किया।<sup>11</sup> परंतु दत्त की वाद की रचनाओं में 'उग्रवाद की भावना' जिसकी 'हिंदू पेड्रिगट' ने 1875 में निंदा की थी साफ तौर पर गायब थी। बंबई और मद्रास की स्थाई रैयतवादी प्रणाली के साथ बंगाल के राजस्व बंदोबस्त की तुलना करते हुए जहां दत्त उसका गुणगान करते हैं वहां वह जमींदारी प्रथा के शोषणकारी तत्व को कम बताते हैं। दत्त ने पदस्थितिजन्य यह निर्णायक कमजोरी 1900 में ग्रहण की जिसका लार्ड कर्जन ने पूरा लाभ उठाया। लार्ड कर्जन ने स्पष्ट किया कि दत्त की विचारधारा में रैयत के ऊपर जमींदारों के दावों की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। रैयत के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और यह संरक्षण उस समय की तुलना में जब भुगतान मालगुजारी के रूप में ब्रिटिश सरकार के होते थे, रैयत द्वारा जमींदार को लगान के भुगतान के समय कम आवश्यक नहीं थे। तथापि रमेश दत्त और राष्ट्रवादी खेमे के उनके अन्य मित्रों ने संपूर्ण भारत में बंगाल की तरह का स्थाई बंदोबस्त का समर्थन नहीं किया। यह स्पष्ट अनुभव हो गया था कि जिस प्रकार की जमींदारी प्रथा बंगाल में विकसित हुई थी वह स्थाई बंदोबस्त का अनिवार्य अंग नहीं थी। माना यह था कि रैयत पर मालगुजारी संबंधी दावे का स्थाई बंदोबस्त होना चाहिए। रैयत साविधिक (कानूनी) काश्तकार था। उसके और सरकार के बीच में स्थाई बंदोबस्त से उसके हितों की तो रक्षा होती थी, परंतु भूमि पर किसानों का अधीनस्थ अधिकार होने या कोई भी अधिकार न होने के कारण उन्हें स्थाई बंदोबस्त से कोई लाभ नहीं होना था। एक आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार 'यह तर्क कि बंदोबस्त रैयत के साथ होना चाहिए उस समाज में अर्थहीन होगा जिसमें रैयत को दर रैयत बनाने की स्वतंत्रता है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें शोषित शोषक बन बैठते हैं।'<sup>12</sup> समस्या के इस पहलू पर दत्त ने ध्यान नहीं दिया था। उस दृष्टिकोण को जिसके रमेश दत्त के विचार प्रतीक हैं, उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के दशकों में विशिष्ट वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि की सहायता से स्पष्ट कर सकना संभव है। यह दृष्टिकोण आंशिक रूप से राष्ट्रवादी नेताओं की सामाजिक न्याय की तुलना में जिसे वे महान उद्देश्य (अर्थात्) साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष) कहते थे से प्रतिबद्धता का परिणाम था।

स्थायी बंदोबस्त के इस पंथ का सैद्धांतिक आधार क्या था? वस्तुतः कुछ भी नहीं। एक अस्पष्ट मान्यता थी कि स्थाई बंदोबस्त के द्वारा लगान में राज्य का भाग कम हो जाने से कृषि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा और कृषि विकास के लिए पूंजी के निवेश को

प्रोत्साहन मिलेगा। न केवल दत्त और उसकी ही विचारधारा के अन्य लोग बल्कि अनेक ब्रिटिश अफसर, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस मान्यता को सही माने बैठे थे। यह मान्यता टॉर्गेट तथा स्मिथ के पूँजी निवेश प्रक्रिया के सिद्धांत का स्मरण कराती है जिसके अनुसार यदि किसी के पास निवेश्य पूँजी है तो निवेश स्वाभाविक रूप से होगा और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा। परंतु वचन और निवेश में बाधाएं जैसे विस्तृत अथवा मंयुक्त परिवार प्रणाली के माध्यम से साधनों का निकास, 'सामंती' अतीत से मिली या यूरोपीय लोगों के साथ नए संपर्कों से प्राप्त उपभोग संबंधी आदतों के अधिब्ययी प्रभाव, अग्रजवासी जमींदारों के नए वर्ग द्वारा जिसके पास पंतुक संपत्ति एकत्रित करने की परंपरा नहीं थी, प्रदर्शन उपभोग एवं अव्यय, आदि कृषि विकास के लिए भी सीमाएं थी और ये बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान थी। स्थाई बंदोबस्त के आलोचक यह बता सकते थे। वे उपयोगितावादी विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत भी प्रस्तुत कर सकते थे। मिल के लगान सिद्धांत में कहा गया था कि राज्य को अनर्जित आय का एक भाग लेना ही चाहिए और स्याई बंदोबस्त द्वारा इस पर रोक लग जानी थी। यह तर्क दिया गया कि राज्य लाभकारी लगान का एक छोटा भाग ही मालगुजारी के रूप में ले रहा है। भारत का लघु किंतु वर्धनशील वाणिज्यिक समुदाय सरकार से अपग्रह कर रहा था कि और अधिक लगान लिया जाए। कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 1867 में भारत मंत्री को अपने स्मरण पत्र में लिखा कि जे० एस० मिल ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी प्रकार के करों में मालगुजारी सबसे कम हानिकारक है, फिर भी सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों पर लाइसेंस कर लगा कर 'देश की संपत्ति और समृद्धि में योगदान देने' वाली एवं उत्पादक कार्यों में लगी पूँजी पर कराधान कर रही है जबकि अचल संपत्ति और निष्क्रिय पूँजी पर वस्तुतः कोई कर नहीं है।<sup>14</sup> बंगाल चैंबर आफ कामर्स ने शिकायत की कि यदि प्रत्यक्ष कर 'भू संपत्ति और सरकारी प्रतिभूतियों' पर न लगा कर व्यापारियों और कारीगरों पर लगाए गए तो 'राष्ट्रीय उद्योगों पर अनुचित भार पड़ेगा।'<sup>15</sup> 1859 में ही बंबई के हिंदुस्तानी व्यापारियों ने सरकार से यह अनुरोध किया कि 'वह निष्क्रिय तथा संपन्न वर्गों के लाभ के लिए औद्योगिक वर्गों पर कर न लगाए... श्रम से उत्पन्न आय और व्यापार तथा व्यवसायों से प्राप्त आयों पर संपत्ति से मिलने वाली आय की तुलना में हलके कर होने चाहिए...'<sup>16</sup> कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद तथा मद्रास से सरकार के पास इस प्रकार के कई स्मरण पत्र भेजे गए।<sup>17</sup> इस प्रकार के प्रतिवादों का अर्थ स्पष्ट है कि वणिज्य, व्यापारियों, तथा कारीगरों की अर्जित आय की तुलना में जमींदारों तथा लगानजीवियों की आयों पर भारी कर लगाए जाने चाहिए। मिल ने आय के स्रोत के आधार पर कराधान में विभेदीकरण का सुझाव दिया था तथा हाउस आफ कॉमंस की ह्यूबार्ड समिति (1861) द्वारा विचार विमर्श में भी अर्जित और अनर्जित आय में विभेदीकरण के औचित्य पर ध्यान आकर्षित किया गया था।<sup>18</sup> भारत सरकार ने विभेदीकरण सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, परंतु किसी न किसी प्रकार के संपत्तिकर की भारी आवश्यकता अनुभव की गई।<sup>19</sup> सरकार इस प्रकार का कर गोज पाने में असफल रही और छठे दशक में आय पर संशुधी

प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि स्थाई बंदोबस्त हो जाने के बाद कृषि आय में होने वाली वृद्धि पर लगा सकना कठिन कार्य था।<sup>19</sup> इस संदर्भ में स्थाई बंदोबस्त के विरुद्ध उपयोगितावादी तर्क को केवल सैद्धांतिक बता कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सातवे और आठवें दशक के राजस्व संबंधी विवाद में जे० एस० मिल का कोई प्रमुख स्थान नहीं है परंतु पृष्ठभूमि में उसकी अस्पष्ट छाया बराबर दिखाई देती है। सर एच० एस० मेन तथा डब्ल्यू० टी० थोर्नटन के साथ निजी पत्र व्यवहार में जे० एस० मिल ने उन्हें 'वर्तमान अंग्रेजी ढंग के जमींदारवाद के प्रति प्रतिक्रिया (सैन्य विद्रोह के बाद)' के विरुद्ध चेतावनी दी थी और अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मालगुजारी का स्थाई परिशोधन 'सरकार के लिए घटिया सौदा' सिद्ध होगा।<sup>20</sup>

संक्षेप में, स्थाई बंदोबस्त का विचार भिन्न-भिन्न लोगों के लिए अलग-अलग चीज था। समुच्चल लैंग की दृष्टि में यह एक ऐसे श्रेणीबद्ध एवं विकासशील समाज का आधार था जिसमें सक्रिय एवं प्रगतिशील मध्यम वर्ग को भी रहना था। रमेश दत्त के लिए इसका अर्थ कृषि आय पर विदेशी सरकार की भाग का अंतिम रूप से सीमांकन था, जिससे कृषि संपत्ति का विकास हो सकता था। जमींदारों की दृष्टि में यह उनका स्थाईकरण था। मिल तथा उसके अनुयायियों के लिए यह एक घटिया सौदा था।

1862 में भारत सरकार द्वारा स्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत स्वीकार करने के पीछे क्या प्रयोजन था? कर्नल बायर्ड स्मिथ ने स्पष्ट किया कि हमें दुर्भिक्ष की समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसका राजस्व प्रणाली के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस समय बायर्ड स्मिथ दुर्भिक्ष समस्या में उलझ पड़ा था, उस समय वह अपने कार्य में नया था। वह ख्याति प्राप्त इंजीनियर था परंतु राजस्व प्रशासन तथा दुर्भिक्ष से संबंधित अन्य बातों में उसका अनुभव सीमित था। संभवतः यह उसके लिए एक सुविधाजनक बात थी क्योंकि जब लार्ड कैनिंग ने उससे उत्तरी भारत में 1860 के दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए कहा तो समस्या के बारे में उसने नए विचार दिए। भई तथा अगस्त में प्रस्तुत की गई अपनी तीन रिपोर्टों में उसने स्पष्ट किया कि बंभाव तथा दुर्भिक्ष का सामना कर सकने की लोगों की सामर्थ्य 'बंदोबस्त प्रणाली की, जिसके अंतर्गत रहते हुए वे उत्पादन करते हैं, पूर्णता के ठीक अनुपात में या मैं कहना चाहूंगा कि ठीक ज्यामितिक अनुपात में होता है।'<sup>21</sup> उसने पाया कि सरकार की भूमि संबंधी मांग दीर्घकाल के लिए निर्धारित हो जाने और अधिकारों के सतर्कता के साथ दर्ज किए जाने से कृषि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है। निस्मदेह 1837-38 और 1860 के दुर्भिक्ष के वर्षों के बीच में भूमि प्रणाली में इतना सुधार हो गया था कि दुर्भिक्ष की स्थिति में उसका सामना कर सकने की लोगों की सामर्थ्य भी बढ़ गई। इस सुधार का श्रेय दीर्घकालीन बंदोबस्त को देते हुए बायर्ड स्मिथ ने तर्क दिया कि इस सिद्धांत के और अधिक प्रयोग द्वारा, अर्थात् 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में स्थाई बंदोबस्त लागू करके लोगों की स्थिति में और अधिक सुधार किया जा सकता है और इस प्रकार दुर्भिक्ष के समय कृषक वर्ग के पूर्णतया बरबाद हो जाने का भय भी कम हो सकता है। तथापि कृषकों की वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत थोड़ा मालूम था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बायर्ड स्मिथ

के जाच परिणामों पर आपत्ति की और दावा किया कि 'पश्चिमोत्तर प्रांत का कृषक कम से कम बंगाल के कृषक के बराबर की स्थिति में ही है' यद्यपि वहां भू स्वामी वर्ग बंगाल के भू स्वामी वर्ग की भांति संपन्न नहीं था।<sup>23</sup> तथापि यह बात तर्कमग्न निर्विवाद थी कि आबधिक बंदोबस्त की तुलना में स्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कृषि आय का अल्प भाग सरकार द्वारा लिया जाता था (और बड़ा भाग भू स्वामियों के पास छोड़ दिया जाता था)। परंतु साथ ही, स्थाई बंदोबस्त को किसानों के संपत्तीकरण के बराबर समझना बेतुकी सी बात होगी। यह बात इंडिया काउंसिल के सदस्य रोस डी० मैग्स ने बुड के स्थाई बंदोबस्त पर 1862 के प्रेषण पर अपनी विसम्मति टिप्पणी में स्पष्ट की।<sup>24</sup> उसने बुडता के साथ कहा कि स्थाई बंदोबस्त से केवल उन लोगों को लाभ होना है जो राज्य को सीधी मालगुजारी देते हैं न कि अधिकांश कृषि जनसंख्या को जिसके भूमि पर अधीनस्थ के अधिकार हैं। अस्तु, स्थाई बंदोबस्त का अर्थ 'कृपापात्र वर्ग के लिए राज्य द्वारा अपने अधिकारों तथा हितों का परित्याग' भी हो सकता है। तथापि जैसा कि वामर्ड स्मिथ ने सिफारिश की थी यदि मालगुजारी के स्थाई निर्धारण के साथ अधिकार भी दर्ज किए जाते तो इस दोष से बचा जा सकता था। ऐसा लगता है कि मर सी० बुड वामर्ड स्मिथ की रिपोर्ट से बहुत प्रभावित था और उसने जुलाई, 1862 के अपने राजस्व प्रेषण में स्थाई बंदोबस्त के पक्ष को सहारा देने के लिए रिपोर्ट से उद्धरण लिए थे।<sup>24</sup>

स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क राजनीतिक था। तर्क यह दिया गया था कि स्थाई बंदोबस्त से भू स्वामी वर्ग सरकार के पक्ष में आ जाएगा। भारत मंत्री लार्ड मंटेग ने 31 दिसंबर, 1858 के अपने राजस्व प्रेषण में लिखा था कि स्थाई बंदोबस्त के बाद जमींदार अपना सरकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेगा और 'उसकी निष्ठा उसकी अपनी बुद्धिमानी तथा स्वार्थ का सामला' बन जाएगी।<sup>25</sup> मर सी० बुड भी सदा के लिए जमीन के मालिकों के साथ बंदोबस्त के राजनीतिक लाभों से अवगत था। उसे आशा थी कि 'जमीन में संपत्ति के पूर्ण सृजन' से सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ जाएगी।<sup>26</sup> यह स्थाई बंदोबस्त के कट्टर हिमायती सर जान लारेंस का भी मत था।<sup>27</sup> उसने लिखा, 'कृषक जो देश की वास्तविक भौतिक शक्ति होते हैं, उनके ही संतोष पर ब्रिटिश शासन की सुरक्षा बहुत कुछ निर्भर है। यदि वे संपन्न हों तो सैनिक शक्ति कम हो सकती है, अन्यथा नहीं।' इस प्रकार का तर्क लारेंस जैसे अधिकारी द्वारा, और वह भी सैन्य विद्रोह के ठीक बाद, दिए जाने पर उसको काफी महत्वपूर्ण समझा जाना ही था। तथापि यह संभव है कि स्थाई बंदोबस्त का राजनीतिक लाभ बहुत बड़ा-चढ़ा कर बताया गया था। जैसा कि एक अफसर ने, जिसके पास व्यावहारिक प्रशासनिक अनुभव था, बतलाया कि भारतीय कृषकों की स्थाई बंदोबस्त के परिशोधन सबधी प्रस्ताव के ऊपर जिस प्रतिक्रिया की आशा की जा रही थी, वह उससे भिन्न भी हो सकती है। 'स्थाई बंदोबस्त करने के समय मालगुजारी की दर इतनी ऊंची निर्धारित की जानी थी जितनी भूमि के लिए सहन कर पाना संभव था, यह दर उससे अधिक रहनी थी जिसे देने की पिछली दो पीढ़ियों की आदत पड़ चुकी थी।' बड़ी हुई मालगुजारी किसानों पर भारी बोझ बन जानी थी। किसान इसके दीर्घकालीन लाभों के

समझ पाने में असमर्थ था क्योंकि वह 'इतना आगे नहीं देख सकता कि उसे भूमि के मूल्य में सामान्य वृद्धि की संभावना का बोध हो सके।'<sup>28</sup> जैसा कि पश्चिमोत्तर प्रांत के राजस्व बोर्ड से 'संबद्ध अधिकारी डब्ल्यू. म्योर ने बताया, 1857 के सैन्य विद्रोह से बंगाल की निरापदता के कारण एक गलत धारणा बन गई और इसी कारण से लोगों ने स्थाई बंदो-बस्त के लाभों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से रखा। वास्तव में जिन कारणों ने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया था (म्योर यह नहीं बतलाता है कि वे कारण क्या थे) वे बंगाल के किसी भी भाग में पूरी तरह सक्रिय नहीं थे, परंतु जहां पर वे उपस्थित और सक्रिय थे जैसे कि शाहाबाद में वहां स्थाई बंदोबस्त भी उन्हें रोक पाने में इतना ही अशक्त सिद्ध हुआ जितना कि अरथाई बंदोबस्त।'<sup>29</sup> स्थाई बंदोबस्त और राजनैतिक सुरक्षा में गलत सादात्म्य स्थापित करने का एक उदाहरण सेमुअल लैंग का यह कथन है कि स्थाई बंदोबस्त ने 'सैन्य विद्रोह के समय साम्राज्य के सबसे बड़े भाग (बंगाल अथवा निचले प्रान्तों से तात्पर्य है) ने अपने आपको हमसे संबद्ध रखा'।<sup>30</sup> कुछ भी हो, ठीक प्रकार से अथवा भूल से, यह समझा जाता था कि मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त के रूप में रियायत से लोगों की सरकार के प्रति निष्ठा में वृद्धि होगी और एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जो अपने हितों और विदेशी सरकार में सादात्म्य देखेगा।

स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में एक अन्य बात यह थी कि इसके द्वारा प्रशासन के निचले स्तरों पर प्रशासनिक कार्य तथा व्यय में कमी कर सकने की संभावना थी। यह सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता था कि समय-समय पर किया जाने वाला बंदोबस्त यूरोपीय अधिकारियों के लिए जिनका काम निरीक्षण था, एक भारी कार्य था और छोटे अधिकारियों के लिए यह मालगुजारी अदा करने वालों को लूटने का अवसर था। कर-दाता को इससे बहुत खीझ होती थी और प्रत्येक बंदोबस्त से संबंधित कार्य की लागत बहुत होती थी।<sup>31</sup> व्यावहारिक प्रशासकों को स्थाई बंदोबस्त के तथाकथित राजनीतिक लाभ संबंधी तर्क अथवा स्थाई बंदोबस्त और किसानों की दुर्भिक्ष का सामना कर सकने की क्षमता में कल्पित संबंध की तुलना में ये प्रशासनिक कारण अधिक महत्वपूर्ण लगे।

उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में त्रीमियाई युद्ध तथा अमरीकी गृहयुद्ध के समय भारतीय कच्चे माल के बाजार के विस्तार, 1861 से 1864 तक लंकाशायर में पपास के अकाल के समय भारत के कपास बाजार में तेजवाजारी, कुछ खनिज तथा वागान उद्योगों के विस्तार, रेलवे तथा अंतर्देशीय जहाजरानी के विकास से व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन, भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेशों की मात्रा में वृद्धि इत्यादि के साथ भारत के आर्थिक जीवन में आर्थिक विकास का नया चरण प्रारंभ होता है। भारत अब 'कुबेर का खजाना' नहीं रहा था 'जिससे इंग्लैंड के नई पीढ़ी के लोग आकर मनचाहा धन उठा कर ले जाते।'<sup>32</sup> भारत का पूंजी निवेश तथा व्यापार क्षेत्र के रूप में विकास किया जाना था। भारत की बेकार भूमि को ब्रिटेन के प्रवासी श्रमिकों की सहायता से उत्पादक बनाने की व्यावहारिक योजनाओं से लेकर<sup>33</sup> पैट्रोलियम के स्रोतों के विकास की प्रगतिशील योजनाओं<sup>34</sup> तक कोई भी कार्यक्रम यदि निवेश के लिए अवसर प्रदान करता था तो इंग्लैंड की जनता की उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती थी और कभी-कभी तो

इन योजनाओं को सरकार से भी सहायता मिलती थी। भारत में निवेश और व्यापार की संभावनाओं को खोजने की उत्कंठा कुछ तो संरक्षणात्मक टैरिफ के फलस्वरूप यूरोप में इंग्लैंड का बाजार सीमित हो जाने के कारण और कुछ 1857 के बाद भारत पर इंग्लैंड का पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाने और सरकार को ससदीय दबाव गुटों तथा व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्रभावित कर पाने की संभावनाओं के कारण थी। अस्थाई बंदोबस्त और मालगुजारी में समय-समय पर वृद्धि भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने वाले तत्वों में से एक तत्व थी। 'ब्रिटिश' अधिकारी भारत में इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए इच्छुक थे। लोगों का यह विश्वास था कि स्थाई बंदोबस्त, पूर्ण स्वामित्व की भूधृति, और मालगुजारी परिशोधन से भारत में ब्रिटिश पूंजी और उद्यम के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत में ब्रिटिश पूंजी आकर्षित करने के लिए 1857 में कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने भारत सरकार से आजमायशी सौदा पर अपने स्वामित्व की भूमि कुछ ऐसे संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्थाई रूप से इस शर्त पर हस्तांतरित करने का आग्रह किया कि वे जमीन में सबसे अधिक भूम्यवान फसलें उगाने के लिए कुछ पूंजी लगाएं।<sup>25</sup> कोर्ट तथा भारत मंत्री के पास खाली भूमि प्रदान करने के लिए अनेक आवेदन आए। आवेदक इस भूमि पर 'कपास और इन्डो के उत्पादकों के लिए अन्य निर्यात योग्य पदार्थों की खेती करना चाहते थे।'<sup>26</sup> मैनचेस्टर का मिलों की संयुक्त राज्य अमरीका पर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निर्भरता इनके मालिकों के लिए बिता का विषय बनी हुई थी और उनके काटन सप्लाई एसोसिएशन ने सरकार पर साम्राज्य में ही आपूर्ति के दूसरे स्रोतों को विकसित करने में सहायता देने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। इस एसोसिएशन ने एक प्रतिनिधि मंडल फरवरी, 1859 में भारत मंत्री लार्ड स्टेनले के पास, एक अन्य प्रतिनिधि मंडल अक्टूबर, 1861 में सेमुअल लैंग के पास, तथा जुलाई, 1859 तथा अप्रैल, 1860 में दो स्मरण पत्र सर चार्ल्स वुड के पास भेजे।<sup>27</sup> इसने सूती वस्त्र उद्योग के हितों के तथाकथित समर्थक सदसद सदस्यों (काटन एम० पी०) की सहायता से अपने प्रचार पत्र काटन सप्लाई रिपोर्टर के माध्यम से तीव्र प्रचार किया। यद्यपि इस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर ऊपर लिखा रहता था कपास राजनीति नहीं जानती, फिर भी उसमें काफी चालाकी से भरी राजनीति रहती थी। अमरीका में गृहयुद्ध छिड़ जाने से दक्षिणी राज्यों से कपास की आपूर्ति रुक गई और इसके साथ ही काटन सप्लाई एसोसिएशन ने अपने प्रयत्न तेज कर दिए। इंडिया आफिस के पास भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों तथा स्मरण पत्रों से संतुष्ट न रह कर इस एसोसिएशन ने भारत सरकार के साथ सीधा पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया। इसके सदस्यों ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि 'पुरानी, कष्टकर, जटिल तथा अत्याचारी भूधृति प्रणाली को बनाए रख कर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ घोर अन्याय किया गया है।'<sup>28</sup> कच्ची कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार को चाहिए कि वह मालगुजारी के परिशोधन तथा भूमि पर पूर्ण स्वामित्व और भूधृति को स्वीकार करे। काटन सप्लाई एसोसिएशन ने माग की कि 'यूरोपीय पूंजी निवेश के लिए पूरे अवसर' देने के लिए भूमि

संबंधी नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।<sup>39</sup> इस मामले में भारत के ब्रिटिश व्यापारी संघ भी मैनचेस्टर गुट के साथ हो गए। इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन, चाय तथा कहवा बागानों के मालिकों, तथा लैंडहोल्डर्स एंड कर्मशियल एसोसिएशन की संयुक्त समिति ने इस मामले पर भारत सरकार के पास स्मरण पत्र भेजे। लैंडहोल्डर्स एंड कर्मशियल एसोसिएशन ने लिखा कि 'भारत के उत्पादक स्रोतों के ऊपर काम करने के लिए इंग्लैंड से जो पूँजी, उद्यम तथा शक्ति यहाँ आ सकती है वह भूधृति प्रणाली के असुरक्षित तथा पुनर्ग्रहणीय होने के कारण आ नहीं पाती।' <sup>40</sup>

इन प्रयत्नों का 1861 में कुछ परिणाम निकला। इस वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार ने घोषित किया कि 'इंग्लैंड में भारतीय कपास की माँग काफी व आकस्मिक वृद्धि की संभावना' को देखते हुए भूमि संबंधी विनियमों में परिवर्तन करने के लिए उपाय किए जाएंगे। अक्टूबर, 1861 में मालगुजारी के परिशोधन तथा साधारण शुल्क पर भूमि देने की व्यवस्था करने के लिए विनियम बनाए गए।<sup>41</sup> इस निर्णय तक पहुँचने में सरकार न केवल मैनचेस्टर के सूती वस्त्र उत्पादकों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के दबाव से प्रभावित हुई थी, वरन् उस पर उसके अपने ही अधिकारियों कपास की खेती के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कमिश्नर आर० सांडर्स तथा रिचर्स थापसन जो बंगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू से संबद्ध था, का असर था। थापसन का मत था कि जब तक साम्राज्य के दूसरे देशों की भाँति भारत में साधारण शुल्क पर भूधृति नहीं दी जाती तब तक यूरोपीय पूँजी भारत में जोखिम नहीं उठाएगी।<sup>42</sup> पी० सांडर्स ने न केवल मालगुजारी के परिशोधन की अपितु स्थाई बंदोबस्त की भी सिफारिश की। उसने लिखा कि 'लोग इतने अधिक हतोत्साहित किसी अन्य बात से नहीं होते जितना कि यह जानकर कि सुधार के आधार पर कर में बराबर वृद्धि हो रही है और उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम और सुधारों का केवल यही परिणाम होता है कि लचीला फीता जिससे वे बंधे हैं उन्हें और अधिक कस लेता है।' <sup>43</sup>

पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुसार सांडर्स ने अस्थाई बंदोबस्त के विकास में बाधक प्रभावों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया था। परंतु वह इस बात पर सहमत था कि सरकार यूरोपीय लोगों की महानगरों के बाहर देश के भीतरी भागों में भी बसने का प्रोत्साहन देने के लिए यथाशक्ति प्रयास करे भले ही वे 'जमींदार, बागान मालिक अथवा व्यापारी के रूप में' आएँ।<sup>44</sup> जनसाधारण को 'उनके पड़ोस में ही यूरोपीय पूँजी निवेश से, जिसके द्वारा मुद्रा प्रवाह में निश्चय ही वृद्धि होगी, कमोवेश लाभ' पहुँचेगा।<sup>45</sup> जुलाई, 1862 के विख्यात राजस्व प्रेषण में, जिसमें स्थाई बंदोबस्त की सिफारिश की गई थी, सर सी० वुड ने घोषित किया (पैरा 24) कि भारत सरकार का उद्देश्य यूरोपीय लोगों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहन देना है।<sup>46</sup> उन दिनों इंग्लैंड में वेकफील्ड की रचनाओं में प्रवास तथा अन्य देशों में जाकर बड़े पैमाने पर बस जाने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई।<sup>47</sup> जलवायु, उपयोग लायक खाली भूमि के अभाव, जनसंख्या के दबाव इत्यादि अनेक कारणों से जो बहुत स्पष्ट भी थे, भारत यूरोपीय लोगों के आवास की दृष्टि से उपयुक्त स्थान नहीं था। बंबई का गवर्नर एल्फिंस्टन बहुत सही था जब उसने



साधारण शुल्क के आधार पर बेकार भूमि देने के विषय में अपेक्षित विनियमों के संबंध में एक कार्यवृत्त में लिखा : 'इस देश में यूरोपीय लोगों का इतनी बड़ी संख्या में अधिवास, जिसके आधार पर इसे हम भारत उपनिवेश कह सकें, मुझे तो कल्पना मात्र ही लगता है।' <sup>47</sup> साधारण शुल्क पर बेकार भूमि देने तथा मालगुजारी परिशोधन विषयक विनियमों की मांग व्यापारिक हितों ने की थी और इन मांगों को सरकार ने इस आशा के साथ पूरा भी कर दिया था कि भूमि में यूरोपीय पूँजी का भारी निवेश होगा, विदेशी सुविज्ञता तथा तकनीकों का आयात होगा और भारत में यूरोपीय उद्यमी आकर बसेंगे। व्यवहार में ये विनियम आ जाने पर उपर्युक्त आशाएं पूरी नहीं हुईं। बागान उद्योगों में लगे हुए यूरोपीयों को छोड़ कर बहुत थोड़े लोगों ने बेकार भूमि संबंधी विनियमों का लाभ उठाया और भारतीय जमींदार, जिन्होंने मालगुजारी परिशोधन की आवश्यकता समझी, संख्या में और भी कम थे।

यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था कि अस्थाई बंदोबस्त जिसके साथ संशोधन की शर्तें लगी रहती थीं, भूमि में यूरोपीय तथा हिंदुस्तानी दोनों ही तरह के पूँजी निवेश को हतोत्साहित करता था और स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में यह सबसे प्रबल तर्क था। यह प्रायः देखा गया था कि जब भी मालगुजारी का वार्षिक अथवा नियतकालिक निर्धारण होता था तो अगले बंदोबस्त के समय मालगुजारी की राशि में वृद्धि की निश्चित संभावना के कारण भूमि सुधार तथा उसमें पूँजी निवेश में बाधा पड़ती थी। अतः लोग नियतकालिक बंदोबस्त के क्षेत्रों में, जहाँ भूमि के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ कर भी बढ़ता चलता था, भूमि में पूँजी लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे। <sup>48</sup> यह स्वस्पष्ट था कि 'राजस्व मांग का स्थिरीकरण', संसिल बीडन के शब्दों में 'अपनी संपत्ति का मूल्य बढ़ाने के लिए मनुष्य की सभी प्रेरक शक्तियों में,' जिनसे वह परिचित है, सबसे सबल है। <sup>49</sup> निस्संदेह यह तर्क दिया जा सकता था कि नियतकालिक बंदोबस्त के क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ था। यह पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ था। उदाहरण के लिए इस प्रांत के गवर्नर ने कहा था कि '1809 की अपेक्षा यह प्रांत अब उद्यान हो गया है।' <sup>50</sup> यह ठीक है कि पश्चिमोत्तर प्रांत में बंदोबस्त नियमावली (1854) के नियम 37 के अनुसार जुम्मा में सुधारों की प्रोत्साहन देने के लिए पूँजी निवेशार्थ कुछ रियायत दी गई थी। फिर भी अल्पकालिक बंदोबस्त के क्षेत्रों में पूँजी का निवेश बहुत अनिच्छापूर्वक किया जाता था। <sup>51</sup> यह देखा गया था कि बंदोबस्त की अवधि जब समाप्त होने लगती थी और नए बंदोबस्त का समय पास आने लगता था तो कृषि सुधार का कार्य रुक जाता था क्योंकि प्रत्येक जमींदार का यह उद्देश्य होता था कि उसके ऊपर यथासंभव कम मालगुजारी निर्धारित हो कृषि सुधारों से कृषि क्षेत्र का मूल्य तथा विस्तार बढ़ जाता था और नए बंदोबस्त में मालगुजारी का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता था। <sup>52</sup> मद्रास के राजस्व अधिकारियों ने भी यह तथ्य स्वीकार किया। <sup>53</sup> इसके विपरीत लोगों का यह विश्वास था कि बंगाल में स्थाई बंदोबस्त से 'अपार संपत्ति का उत्पादन हुआ है।' <sup>54</sup> कुछ भी हो, यह गदम्य से भुलल लंग का मत था यद्यपि यह निश्चित नहीं था कि क्या अथवा कहा तक संपत्ति के मंचय से भूमि सुधार हुए। फिर भी यह धारणा कि

मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त से पूजी के संचय और निवेश में सहायता मिलती है, बहुत प्रचलित हो गई थी और स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में तर्कों के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। सर सी० वुड ने जुलाई, 1862 के अपने प्रेषण में संपूर्ण भारत के लिए स्थाई बंदोबस्त की सिफारिश करते हुए इसका प्रयोग किया था।<sup>55</sup>

सातवें दशक के मध्य तक स्थाई बंदोबस्त के समर्थकों का अधिक जोर रहा। फिर भी काफी लोग इसके विषय में संदेह करते थे। छठे दशक के मध्य से यद्यपि सरकार ने स्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत शासकीय तौर पर स्वीकार कर लिया था, तथापि अधिकारी इस बारे में पुनर्विचार करने लगे। 1864 में वुड ने लारेंस को एक व्यक्तिगत पत्र में लिखा कि 'मैं स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत से पीछे नहीं हटता, परंतु जब मालगुजारी में वृद्धि की संभावना अच्छी हो तो स्थाई बंदोबस्त करने की जल्दी न करो'।<sup>56</sup> 1865 में वुड ने पुनः अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'यदि मालगुजारी में वृद्धि कर सकना संभव हो तो वह आपत्तिजनक नहीं है'।<sup>57</sup> वुड के उत्तराधिकारी फ्रेनबोर्न ने लारेंस से 'स्थाई बंदोबस्त के मामले में सावधानी के साथ चलने के लिए' कहा। उसके शब्दों में, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और भारत में संपत्ति का हर तत्व द्रुत विकास की स्थिति में है, मैं स्थाई बंदोबस्त के प्रभावों को भयभीत होकर देख रहा हूँ'।<sup>58</sup> लारेंस उत्साहपूर्वक स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में था।<sup>59</sup> परंतु उसका उत्तराधिकारी मेयो दूसरी तरफ था। उसने आरगाइल को सुझाव दिया कि पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थाई बंदोबस्त करने के बारे में जल्दबाजी के साथ निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि 'जिस समय 1862 में सर सी० वुड ने इस संबंध में लिखा था उस समय जो भी लोग स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में थे उन सभी ने इस संबंध में अपने विचार बदल लिए थे'।<sup>60</sup> 'इस समय यह एक महत्वहीन प्रश्न है। अब से 25 अथवा 30 वर्ष बाद यह हमारे शासन के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है'।<sup>61</sup> मेयो का यह विश्वास कि स्थाई बंदोबस्त से 'मुघारों के लिए अतिरिक्त कराधान का रास्ता बंद हो जाएगा, बगाल के जमींदारों द्वारा स्थानीय उपकरणों (सेस), सड़क कर, शिक्षा उपकरण तथा ऐसे ही कुछ अन्य करों के विरोध से दृढ़ हो गया। उसने फ्रेर को लिखा कि 'जमींदार, निस्संदेह, उस हर प्रस्ताव का विरोध करेंगे जिसका उनकी जेब पर असर पड़ता है और प्रस्ताव कुछ भी क्यों न हो वे 'संविदा की शर्तों के उल्लंघन' की रट पपीहे की तरह लगाने लगेंगे... उन्हें इस बात की घेले भर चिंता नहीं है कि निर्धन व्यक्ति नमक और तबाकू के लिए भी कितना फर देने के लिए बाध्य हैं परंतु यदि उनकी मोटी आमदनी से आधा प्रतिशत भी लिया जाए तो वे चीखने लगते हैं'।<sup>62</sup> आरगाइल ने यह स्वीकार किया था कि 'स्थाई बंदोबस्त उस निजी उद्यम तथा ऐसे कृषि वर्गों के लिए जो इस विश्वास के साथ पूजी लगा सकते हैं कि वे अपनी प्रवीणता एवं उद्यम का लाभ उठा सकेंगे, एक महान प्रेरणा है।' परंतु मालगुजारी के बंदोबस्त से कराधान पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसने मेयो को लिखा कि 'मुझे आशा है कि आप ये बंदोबस्त करते समय ध्यान रखेंगे कि परस्पर यह समझौता होना चाहिए (या सूचना भी दी जा सकती है) कि साम्राज्यिक कर अथवा मालगुजारी संबंधी स्थाई बंदोबस्त से स्थानीय कार्यों के लिए और अधिक कराधान

पर कोई प्रतिवध नहीं होगा। आपको मालूम है कि उच्च अधिकारियों के पास भूमि के बढ़ते हुए मूल्य के अनुसार कर अथवा लगान का ठीक-ठीक ममायोजन करने के विषय में राज्य के अधिकार के स्याई परित्याग के संबंध में भारी एतराज आए हैं। मेरे विचार में केवल इस शर्त पर स्याई बंदोबस्त अच्छी चीज है कि इससे लोगों के पास रह जाने वाली बड़ी हुई गंपत्ति दूसरे रूप में कराधान के लिए उपलब्ध होगी। ऐसे बंदोबस्त के विरुद्ध तर्क की बहुत सारी शक्ति सदैव ही इस विश्वास पर निर्भर होती है कि भारत में राजस्व के नए स्रोत खोज पाना यदि असंभव नहीं तो काफी कठिन अवश्य है।<sup>63</sup>

इस प्रकार अपने व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के द्वारा अधिकारी अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे थे, तथापि स्याई बंदोबस्त लागू करने के विषय में 1862 के निर्णय के बारे में शासकीय रूप से कभी भी सदेह व्यक्त नहीं किया गया। इसके विपरीत 1862 के नीति संबंधी निर्णय से पीछे हटने की इच्छा की सार्वजनिक अभिव्यक्ति उन एक के बाद एक अधिसूचनाओं तथा विनियमों में दिखाई देती है जिनमें स्याई बंदोबस्त के पहले पूरी की जाने वाली शर्तें निर्धारित की गई थी। वास्तव में सर सी० वुड ने पहले ही कुछ शर्तें लगाई थी जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि स्याई बंदोबस्त उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर एक जायदाद में खेती के लायक समस्त भूमि के तीन चौथाई भाग पर पहले से ही कृषि हो रही हो।<sup>64</sup> 1793 में बंगाल के बंदोबस्त में गलती हो गई थी। वहां सभी भूमि पर राजस्व में संभाव्य वृद्धि को छोड़ दिया गया था। उपर्युक्त शर्त का सुझाव सेसिल बीडन ने इसी भूल से बचने के लिए दिया था। इस शर्त का अर्थ था कि पंजाब और मध्य प्रान्त के बहुत सारे भाग तथा बंबई व पश्चिमोत्तर प्रांत के कुछ भाग स्याई बंदोबस्त के लिए उपयुक्त नहीं थे।<sup>65</sup> 1865 में भारत मंत्री ने इस शर्त को इस प्रकार प्रतिपादित किया कि स्याई बंदोबस्त का अर्थ संशोधन के बाद उन सभी जायदादों के लिए जिनमें कृषि योग्य अथवा मालगुजारी क्षेत्र के 80 प्रतिशत भाग पर वास्तव में खेती होती है, तत्काल स्याई बंदोबस्त कर दिया जाएगा।<sup>66</sup> अन्य क्षेत्रों को अपने स्रोतों के भावी विकास तक रुकना पड़ेगा और वहां पर अस्याई बंदोबस्त रहेगा।

1866 में एक अन्य शर्त लगाई गई। यह निर्धारित किया गया कि सरकारी नहरों से लाभान्वित भूमि पर तथा ऐसी भूमि पर जिसे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना हो, कर बढ़ाए जा सकेंगे। भारत मंत्री ने इस संबंध में निर्णय देते हुए कहा कि 'ऐसी जायदाद के लिए स्याई बंदोबस्त नहीं किया जाना चाहिए जिसकी आस्तिया (ऐसेट) अपेक्षित नहर सिंचाई व्यवस्था पूर्ण हो जाने पर 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ सकती है।' इस प्रकार की जायदादों पर उन सभी जायदादों की भांति, जिन पर पूरी तरह खेती नहीं होती अथवा जो अविकसित हैं, बंदोबस्त अस्याई रूप से ही किया जाना था।<sup>67</sup> यह बहुत ही अस्पष्ट ढंग से प्रतिपादित शर्त थी और इसके आधार पर वे बहुत सारी जायदादें छोड़ी जा सकती थीं जिन पर भविष्य में सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना थी।<sup>68</sup> भारत सरकार के अनुरोध पर नोर्थकोट ने इस नियम को इस प्रकार पुनः परिभाषित किया, 'ऐसी किसी भी जायदाद का स्याई बंदोबस्त किया जाएगा जिसे सपरिपद गवर्नर जनरल की राय में अगले बीस वर्षों के भीतर नहर से सिंचाई की सुविधा मिल

सकती है और जिसकी भौज्दा आस्तियों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।<sup>69</sup>

भारत सरकार ने दावा किया कि ये शर्तें भी उसके हितों की सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अपर्याप्त थी। वस्तुतः यह कहा गया कि जब तक किसी भी जायदाद का विकास हो रहा है और उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है तब तक कोई स्थाई बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने अपने मई, 1871<sup>70</sup> के राजस्व प्रेषण में यह मत व्यक्त किया कि पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थाई बंदोबस्त लागू करने का निर्णय स्थगित रखना चाहिए। इनसे सारा मामला यथार्थ में ताक पर रख दिया गया और 1883 के राजस्व प्रेषण, संख्या 24 के द्वारा स्थाई बंदोबस्त की योजना को आखिरी झटका लगा और योजना समाप्त कर दी गई।<sup>71</sup> वस्तुतः 1883 का यह निर्णय भारत मंत्री के 1871 के प्रेषण में ही प्रत्याक्षित था। इस प्रेषण में भारतीय वित्त पर हाउस ऑफ कामंस की प्रवर समिति के विचारों के बारे में लिखा गया था कि 'वे भारत मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना ठीक समझते हैं... जिससे कि वह इस विषय पर पुनर्विचार कर सके और इस बीच यह भी निर्धारित कर सके कि अपने पूर्वाधिकारी के प्रेषण के अनुसार अगली कार्यवाही स्थगित करने के लिए कोई कदम उठाने हैं या नहीं।'<sup>72</sup>

ऐसा लगता है कि सर सी० वुड ने स्थाई बंदोबस्त लागू करने में दो समस्याओं की गंभीरता को कम समझा। उसने भूमि के मूल्य में वृद्धि का अनुमान कम लगाया और चांदी के मूल्य ह्रास की संभावना को भी कम समझा। उसने भारत सरकार को लिखा कि 'महा-महिषी की सरकार को मुद्रा के सापेक्षिक मूल्य में संभाव्य कमी की आशंका इस समय अधिक नहीं लगती...'<sup>73</sup> उसी प्रेषण में एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि 'एक बार जब लगान ठीक से निर्धारित हो जाएगा तो समाज की स्वाभाविक वृद्धि के परिणामस्वरूप उसमें कोई भी वृद्धि क्यों न हो उसके धीरे-धीरे ही होने की संभावना है और बहुत अधिक समय बीतने तक यह राशि बढी नहीं होगी...'<sup>74</sup> दोनों ही के बारे में वुड गलत था और यह जितना अधिक स्पष्ट होता गया, स्थाई बंदोबस्त के प्रति उत्साह भी घटता गया। इसका अर्थ था कि जो भाग विकसित नहीं थे उनमें स्थाई बंदोबस्त नहीं किया गया, जबकि स्थाई बंदोबस्त वास्तव में भूमि में पूजी निवेश और उसके विकास के लिए किया जाना था। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी।

एक अन्य समस्या सातवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों में नहीं देखी जा सकी थी। यह समस्या थी ऐसी कर प्रणाली का निर्माण जिससे स्थाई बंदोबस्त हो जाने पर सरकार की छूटने वाली आय दूसरे करों के द्वारा पुनः मिल सके। आयकरों तथा परोक्ष करों से प्रत्याशित आय न हो पाने से सरकार के मस्तिष्क में आय के प्रधान तथा बढ़ते हुए स्रोत के रूप में मालगुजारी का महत्व बैठ गया। स्थाई बंदोबस्त के लाभ उस समय स्वीकार कर लिए गए थे जब यह विश्वास किया जाता था कि इस प्रकार के बंदोबस्त से उत्पन्न होने वाली संपत्ति पर कराधान की प्रणाली सहज ही खोज निकाली जाएगी। केनवोर्न ने लिखा है 'कराधान की प्रणाली भारतीय वित्त विशेषज्ञों के लिए अब भी पारसमणि लगती है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि जो लोग पहले स्थाई बंदोबस्त के लिए उत्साही थे वे अब मालगुजारी में संभावित वृद्धि को छोड़ने के लिए अनिच्छुक होने लगे

हैं।<sup>175</sup> पारसमणि की खोज में चकराई हुई सरकार ने अंत में संपूर्ण भारत में स्थाई बंदोबस्त लागू करने का विचार ही त्याग दिया।

## II

बाजार में काफी उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत सरकार की अफीम से आय में अनवरत वृद्धि हुई। इस शताब्दी के प्रारंभ में यह लगभग 3.3 लाख पौंड थी। परंतु 1810 में यह बढ़कर 10 लाख पौंड हो गई थी। 1830 में अफीम से आय 15 लाख पौंड और 1850 में 35 लाख पौंड से भी अधिक हो गई थी।<sup>176</sup> 1856-57 में इस मद के अंतर्गत कुल प्राप्तियां 5 करोड़ रुपये से भी अधिक थीं। 1857-58 में जो सैन्य विद्रोह के साथ-साथ गंभीर वित्तीय अभाव का वर्ष भी था, अफीम से सरकारी आय 6.8 करोड़ रुपये हुई जो आधा से कहीं अधिक थी और इससे सरकार को वित्तीय संकट पर विजय पाने में सहायता मिली। अफीम से आय उतार-चढ़ाव के बावजूद बराबर बढ़ती गई। 1858-61 की अवधि में अफीम से वार्षिक औसत आय 7 करोड़ रुपये थी। 1862-66 के पांच वर्षों में इसका वार्षिक औसत बढ़कर 7.5 करोड़ रुपये और 1867-71 में 8.5 करोड़ रुपये हो गया।

पोस्ट की खेती प्रधान रूप से भारत के दो क्षेत्रों में होती थी। एक क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी के आगगा, अवध तथा बिहार में था और दूसरा ब्रिटिश भारत के बाहर (जिसमें मध्य भारत की अनेक रियासतें, राजपूताना और गायकवाड के अधिकार का प्रवेश था)। यह दूसरा मालवा अफीम के प्रजातिगत नाम से जाना जाता था। इन दोनों में उत्पादन तथा राजस्व संग्रह की रीतियाँ भिन्न-भिन्न थीं।

बंगाल में सरकार ने अफीम पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। अतः पोस्ट की खेती और इसका अफीम के रूप में प्रशोधन सरकार के लिए ही किया जा सकता था। पटना और गाजीपुर में रहने वाले अफीम एजेंट बंगाल राजस्व बोर्ड की ओर से अफीम के व्यापार का प्रबंध करते थे।<sup>177</sup> पोस्ट का उत्पादन करने वाले किसानों को, जो इसकी खेती स्वेच्छा से करते थे, भारी अग्रिम दिए जाते थे। ये अग्रिम अगली फसल पर उत्पादित होने वाली अफीम के आंशिक भुगतान के रूप में देखे जाते थे। कच्ची अफीम का प्रशोधन सरकारी कारखानों में होता था और यह कलकत्ता भेजी जाती थी। स्थानीय उपभोग के लिए अफीम विभाग आदकारी विभाग को अफीम देता था।<sup>178</sup> बंगाल में उत्पादित अधिकांश अफीम कलकत्ते में मासिक नीलामी द्वारा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेची जाती थी। अफीम की लागत कीमत और नीलाम कीमत का अंतर सरकार को प्राप्त होने वाला लाभ अथवा राजस्व था।<sup>179</sup> जैसा कि 1871 में अफीम प्रशासन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त समिति ने इस विषय में टिप्पणी करते हुए कहा कि संभवतः इस प्रणाली को 'जानबूझ कर खोजा नहीं गया बल्कि यह अपने आप विकसित हो गई थी।'<sup>180</sup> यह प्रणाली संतोषजनक नहीं थी। एक स्पष्ट कठिनाई जिससे इस प्रणाली से असंगत नहीं किया जा सकता था, आपूर्ति के प्रबंध की समस्या थी। आपूर्ति की मात्रा सरकार द्वारा कृपको को दी जाने वाली कीमत पर निर्भर होती थी। सरकार द्वारा

कीमत निर्धारण से संबद्ध बहुत सारी समस्याएँ थीं। अधिकारी पोस्त की इस प्रकार लेते थे मानो उस पर मांग और पूर्ति का सहज नियम लागू नहीं होता हो।<sup>80</sup> 1859-60 के वित्तीय वर्ष में अफीम की कीमत 3 रुपये 4 आने प्रति सेर से बढ़ाकर 3 रुपये 8 आने प्रति सेर कर दी गई। 1860-61 में इसमें और अधिक वृद्धि कर से 4 रुपये कर दिया गया; 1861-62 में इसमें पुनः वृद्धि की गई और इसे 5 रुपये प्रति सेर कर दिया गया।<sup>81</sup> सरकार इस बात से बहुत चिंतित थी कि 1861 तक सरकार द्वारा दी गई कीमतें पोस्त की खेती को प्रोत्साहन देने में असफल रही।<sup>82</sup> 1853-54 से 1858-59 तक पांच वर्षों में बिहार एजेंसी में 1,08,627 बीघा तथा बनारस एजेंसी में 28,056 बीघा भूमि पर अफीम की खेती कम हो गई।<sup>83</sup> कीमतों में वृद्धि होते हुए भी बंगाल में अफीम की खेती में कमी होती गई।<sup>84</sup> कृषि उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि, अफीम के उत्पादन में भूमि के अधिक प्रयोग से उसकी उर्वरता की हानि, तथा बंगाल में पोस्त का मुकाबला करने वाली अन्य वाणिज्यिक फसलों का प्रचलन अफीम के उत्पादन में कमी के कारण थे। जून, 1861 में अफीम की कीमत बढ़ाकर 5 रुपये प्रति सेर कर दिए जाने पर पोस्त की खेती फिर से कुछ बढ़ी। कुछ वर्षों में यह पता चला कि रैयतों को ऊंची दर से भुगतान करने का परिणाम यह हुआ कि इसकी खेती उन क्षेत्रों में भी फैल गई जहाँ पर अधिक लागत पर घटिया किस्म की अफीम का उत्पादन होता था। अतः 1865 में कीमत घटाकर 4 रुपये 8 आने प्रति सेर कर देने और बनारस एजेंसी में इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।<sup>85</sup>

एकाधिकार प्रणाली और सरकार द्वारा कीमत निर्धारण से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ विकट थीं। इन समस्याओं का अहस्तक्षेपी नीति पर आधारित समाधान यह था कि सरकार एकाधिकार प्रणाली को त्याग दे। 1858 में मालवा के अफीम एजेंट सर राबर्ट हैमिल्टन ने बंगाल की एकाधिकार प्रणाली का स्थान लेने के लिए एक नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इस नई व्यवस्था में पोस्त की स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित खेती करने और एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अफीम का उत्पादन तथा निर्यात कर देने का आयोजन था। सुझाव यह था कि नई प्रणाली द्वारा दिए जाने वाली अग्रिम राशियों में कमी करके तथा अफीम के उत्पादन के लिए लाइसेंस देकर धीरे-धीरे व्यवहार में लाई जानी चाहिए।<sup>86</sup> पश्चिमोत्तर प्रांत की सरकार ने इस योजना को अपना समर्थन दिया। इस योजना का औचित्य सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए गए थे वे निम्नलिखित हैं : (क) इसमें सरकार के नाम पर यह कलंक कि वह अफीम के व्यापार में एकाधिकार की हैसियत से लगी हुई है, दूर हो जाना था। (ख) एकाधिकार की समाप्ति से कोई वित्तीय हानि नहीं होनी थी, क्योंकि आवश्यकता तथा निर्यात शुल्क के रूप में आय घनी रहनी थी। (ग) अफीम विभाग अथवा अफीम एजेंसियाँ रखने का खर्च समाप्त कर बचत हो सकती थी। (घ) स्वतंत्र खेती प्रारंभ हो जाने पर कृषि कार्य में कष्टदायक हस्तक्षेप नहीं रह सकते थे।

बंगाल सरकार ने प्रस्तावित परिवर्तनों का डटकर विरोध किया। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावे के साथ कहा कि 'नैतिकता के प्रश्न के रूप में अफीम में आय

चाहे वह उपभोग पर आबकारी शुल्क तथा निर्यात शुल्क से अथवा उसके उत्पादन पर एकाधिकार द्वारा, उसमें अंतर काल्पनिक और झूठा है" <sup>87</sup> बंगाल में स्वतंत्र कृषि की प्रणाली में शुल्क के अपवंचन के द्वारा भारी हानि होनी थी। इसमें भौगोलिक कारणों की उपेक्षा नहीं की जानी थी। मालवा की अफीम पर लगाया जाने वाला पारगमन शुल्क (पास ड्यूटी) नियमित रूप से वसूल हो जाता था क्योंकि पश्चिमी घाट से होकर बंबई जाने वाले गिने-चुने रास्तों की निगरानी सहज थी परंतु बंगाल में समुद्र तक पहुंचने वाले ढेर सारे जलमार्गों के द्वारा हो सकने वाले अफीम के तत्त्वर व्यापार को रोक सकना असंभव था। बंगाल सरकार ने हेमिल्टन के इस आरोप का खंडन किया कि किसानों पर पोस्ट की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था। सरकारी एजेंसी के साथ समझौते स्वीच्छक होते थे और किसान जब चाहें सब इन्हें समाप्त कर सकते थे, अग्रिम राशियाँ व्याज सहित दी जाती थीं, यूरोपीय अधिकारियों के व्यक्तिगत निरीक्षण के कारण भ्रष्टाचार का क्षेत्र सीमित था, और खराब मौसमों में फसलों के नुकसान के लिए काफी पैसा दिया जाता था। बंगाल सरकार का यह दावा कि अफीम का उत्पादन करने वाले असामी प्रचलित व्यवस्था से संतुष्ट थे, इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि सैन्य विद्रोह के समय भी उपद्रवग्रस्त जिलों के किसान, जो अग्रिम (दादन) से चुके थे, अफीम लेकर सरकारी एजेंटों के साथ अपना हिसाब-किताब साफ करने के लिए आए। <sup>88</sup> यह भी स्पष्ट किया गया कि पोस्ट की स्वतंत्र खेती से भारत में ही अफीम खाने और दम लगाने की आदत फैल सकती थी, विशेष रूप से उस समय जबकि बंगाल में पोस्ट हर जगह पैदा किया जा सकता था। <sup>89</sup> इसके अलावा इससे अति उत्पादन भी हो सकता था जिससे चीन में इसके बाजार पर असर होता और कीमतें नीचे आ सकती थी जिससे सकट उत्पन्न हो जाता। <sup>90</sup> एकाधिकार प्रणाली के पक्ष में निर्णायक तर्क यह था कि यह सरकार के लिए मालवा अफीम पर लगाए जाने वाले पारगमन शुल्क की तुलना में अधिक लाभदायक था। यह स्पष्ट है कि मालवा अफीम के निर्यात से पश्चिम तथा मध्य भारत के व्यापारी तथा देशी राज्य (विशेष रूप से महाराजा होल्कर) संपन्न हो गए थे। <sup>91</sup>

1871 में सर सेसिल बीडन ने हिसाब लगाया था कि यदि एकाधिकार प्रणाली को आबकारी शुल्क प्रणाली में बदल दिया जाता है तो प्रति पेटो सरकार को 200 रुपये से 250 रुपये तक की हानि हो सकती है। <sup>92</sup> अफीम के व्यापार का स्वरूप असाधारण था। अतः इस पर नियंत्रण की आवश्यकता थी। इस पर 'मुक्त व्यापार के सामान्य सिद्धांत के द्वारा विचार न करके किसी अधिक स्पष्ट माध्यम की सहायता से गौर किया जाना चाहिए।' <sup>93</sup> पोस्ट की खेती बिना अग्रिमों के असंभव थी और यह संदेहजनक था कि इस प्रकार के जोखिम वाले व्यवसाय में सटोरिये और पूंजीपति अपनी पूंजी लगाएंगे। <sup>94</sup> यदि पूंजी उपलब्ध भी होती तो यह निश्चित था कि किसानों का महाजन शोषण करेंगे। यदि सरकार के साथ परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता तो 'असामी सामूहिक रूप से अफीम की खेती छोड़ देते।' <sup>95</sup> ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि जमींदार अफीम के व्यवसाय में आ जाएंगे। 'सरकार द्वारा छोड़ा गया क्षेत्र लगभग पूरी तरह से यूरोपीय लोगों के ही हाथ में आना था।' <sup>96</sup> जो यूरोपीय नील की फैक्ट्रियों का प्रबंध कर रहे

ये, वे संभवतः अफीम की फैक्ट्रिया स्थापित कर उनका प्रबन्ध कर सकते थे। बिहार के एक स्थानीय अफीम एजेंट ने लिखा था कि 'मेरे विचार में इस प्रकार के उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिभा भारत के मूल निवासियों में नहीं है।'<sup>97</sup> भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों के पास व्यवसाय में लगाने के लिए पूँजी है और नील की फैक्ट्रियों के प्रबन्ध से प्राप्त सुविज्ञता है। ये लोग अफीम के व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों से भी अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अफीम पर सरकारी एकाधिकार के विरुद्ध और मुक्त उत्पादन की व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन का यह एक मुख्य कारण था। 1871-72 में भारतीय वित्त के बारे में हाउस आफ कॉमंस की प्रवर समिति द्वारा जांच के समय यह प्रश्न उठाया गया था। सर आर० हैमिल्टन तथा बहुत सारे अन्य लोग सरकारी एकाधिकार समाप्त करने के पक्ष में बोले थे।<sup>98</sup> परंतु बंगाल प्रणाली<sup>99</sup> के समर्थक मुक्त खेती की व्यवस्था लागू करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का सफलतापूर्वक विरोध कर सके।

मालवा अफीम पर निर्यात शुल्क लगता था। मध्य भारत, विशेष रूप से देशी रियासतों, में उत्पादित अफीम इंदौर लाई जाती थी, और मध्य भारत के अफीम एजेंट के कार्यालय में उसका वजन होता था। वह अफीम की प्रत्येक पेट्टी पर एक निश्चित शुल्क लगाता था और बंबई बंदरगाह तक अफीम, जिस पर शुल्क अदा कर दिया गया होता था, ले जाने के लिए एक पास देता था। ब्रिटिश सरकार का अफीम की खेती, निर्यात तथा यातायात से कोई संबंध नहीं था। वह केवल पास शुल्क ही वसूल करती थी।<sup>100</sup> 1845 तक यह शुल्क केवल 200 रुपये प्रति पेट्टी था। इस वर्ष इसे बढ़ा कर 300 रुपये और 1847-48 में 400 रुपये कर दिया गया। 1859 में भारत सरकार ने शुल्क को बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया, परन्तु जब 1860 में शुल्क में फिर वृद्धि की गई और वह 600 रुपये कर दिया गया तो काफी विरोध हुआ।<sup>101</sup> बंबई सरकार ने स्पष्ट किया कि बंगाल अफीम के विपरीत मालवा अफीम से कम से कम चार पक्षों को लाभ मिलना ही चाहिए : कृषक, पहला खरीदार जो कृषकों को अग्रिम रूप में रुपया उधार देता है, दूसरा खरीदार जो अफीम का प्रशोधन कर उसे बंबई भेजता है और अफीम की पेट्टियों का निर्यातक। बंबई सरकार ने दृढ़तापूर्वक कहा कि 600 रुपये प्रति पेट्टी शुल्क से लाभ की समुचित मात्रा नहीं बचेगी। इंदौर के अफीम एजेंट का भी यही मत था। परंतु भारत सरकार ने इस विश्वास के साथ कि विचौलिये और निर्यातक 'काफी मुनाफा' बना रहे हैं इन आपत्तियों को अस्वीकृत कर दिया।<sup>102</sup> बंबई में सरकार को (पारगमन शुल्क के रूप में) अफीम की प्रति पेट्टी से केवल 500 रुपये मिल रहे थे, जबकि बंगाल में एकाधिकार प्रणाली के अंतर्गत प्रति पेट्टी शुद्ध लाभ 1,200 रुपये था।<sup>103</sup> ऊँचे शुल्क के विरोध में बंबई सरकार की चेतावनी तथा बंबई के अफीम व्यापारियों के स्मरण पत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।<sup>104</sup> अप्रैल, 1861 में भारत सरकार ने शुल्क को बढ़ाकर 700 रुपये प्रति पेट्टी कर देने की सूचना दी।<sup>105</sup> ऐसा व्यापारिक संकट के समय हुआ। तीन माह के भीतर कीमत 1,850 रुपये प्रति पेट्टी (अप्रैल) से घट कर 1,350 रुपये प्रति पेट्टी (जुलाई) हो गई। अफीम के छः व्यापारी दिवानिया हो गए, बाढ़ के सौदे करने वाले



20 दलाल फरार हो गए और बहुत सारे सटोरिये बरबाद हो गए।<sup>106</sup> इस स्थिति में मालवा के अफीम एजेंट कर्नल आर० शेक्सपियर ने निवेदन किया कि 700 रुपये शुल्क से व्यापार को भारी आघात पहुंचेगा। अफीम के व्यवसाय से संबंधित डेविड सेसन एंड कंपनी, हस्तमजी जमशेदजी जोशी भाई एंड कंपनी, तथा दूसरी फर्मों ने सरकार के पास शुल्क कम करने के लिए स्मरण पत्र भेजे।<sup>107</sup> इस पर भारत सरकार ने अपनी पहली अधिसूचना रद्द करने का निर्णय लिया। निर्णय यह हुआ कि शुल्क बढ़ाकर 700 रुपये नहीं किया जाएगा।<sup>108</sup>

मालवा अफीम तथा बंगाल अफीम दोनों से ही होने वाली आय में काफी घट बढ होती रहती थी। परिशिष्ट में दिए हुए आकड़ों पर दृष्टिपात से स्पष्ट हो जाएगा कि आय में इस उतार-चढ़ाव की मात्रा तथा आवृत्ति इतनी थी कि इससे 1861 से 1871 तक के दशक में कम से कम तीन बार आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। राजस्व में आकस्मिक कमी से वित्त सदस्य के, जो वर्ष की आय का सही-सही अनुमान लगाना और बजट को 'संतुलित रखना' चाहता था, सभी परिकलन तथा अनुमान गड़बड़ हो जाते थे।

विभिन्न वर्षों में अफीम से होने वाली आय में घट-बढ की प्रवृत्ति के कारण इसे सामान्य राजस्व का अनिश्चित स्रोत माना जाता था। ये प्राप्तिया कुछ ऐसी बातों पर निर्भर होती थी जो सरकार के नियंत्रण के बाहर होती थी। 'फसलों के सयोग तथा बाजारों में अवसर' के अनुसार अफीम से आय में परिवर्तन बड़े स्वाभाविक ढंग से होते थे।<sup>109</sup> इन दो कारणों के अतिरिक्त बंगाल में सरकार का शुद्ध लाभ निर्धारित करने वाला एक सीसरा भी कारण अफीम प्रभार (अर्थात् पोस्त की खेती करने वाले कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों से संबंधित वार्षिक प्रभार, सरकार द्वारा निर्धारित कीमत दर, बंगाल अफीम एजेंसियों का व्यवस्था संबंधी खर्च, इत्यादि) था। अफीम की लागत कीमत तथा कलकत्ते में नीलाम से मिलने वाली कीमत का अंतर बंगाल अफीम से मिलने वाला शुद्ध लाभ होता था।<sup>110</sup> जहां तक मालवा अफीम का प्रश्न था, उसके लाभ के निर्धारण की दृष्टि से फसल की स्थिति, चीन में माग तथा बंबई मुद्रा बाजार की स्थिति महत्वपूर्ण घटक थे। मालवा अफीम की कीमत बंगाल अफीम के साथ घटने बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाती थी।<sup>111</sup> सातवें दशक में कृषकों द्वारा अफीम के बदले कपास की खेती (अमरीकी गृह युद्ध के कारण लकाशावर में कपास की अल्प आपूर्ति के फल-स्वरूप भारतीय कपास की भारी माग थी) के परिणामस्वरूप अफीम का उत्पादन प्रभावित हुआ।<sup>112</sup> संचार व्यवस्था घराब होने से भी मालवा अफीम के व्यापार में कमी बेशी होती रहती थी। दरसाती महीनों में जब मालवा के भीतरी प्रदेशों तक सड़क व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने से गाड़ियों का आना-जाना हफ्तों तक संभव नहीं हो पाता था तो इसका अफीम के आयात पर प्रभाव पड़ता था।<sup>113</sup> ऐसे अवसरों पर अफीम का निर्यात और फलतः पारगमन शुल्को (पास ड्यूटी) से आय कम हो जाती थी। अफीम के व्यापारी जो चीन को आर्डर मिलते ही निर्यात करने के उद्देश्य से बंबई नगर के भंडार गृहों में अफीम नहीं रख पाते थे और ऐसे भी व्यापारी जो चीनी माग की आशा में अफीम ले आते थे, प्रायः भारी हानि उठाते थे। इस हानि का कारण होता था बाजार

सूचना और माल यातायात का घीमा होना।<sup>114</sup> मालवा और बंगाल दोनों ही स्थानों के अफीम व्यापार में अस्थिरता इसलिए भी थी क्योंकि भारत के बाहर अफीम के बाजार का विशेष अनुमान लोगों को नहीं था। डब्ल्यू एन० मैसी ने कहा था कि 'अफीम ऐसा स्रोत है जो अधिक स्पष्ट नहीं है। यह ऐसे बाजार पर निर्भर है जिसके विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। इसके व्यवसाय में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हैं'।<sup>115</sup> अंत में, अफीम से आय की तथाकथित अनिश्चितता का कारण बंगाल अफीम का कुप्रबंध ठहराया जा सकता था। 1867-68 तक निर्यात व्यापार में निरंतर तथा जोर-दार सट्टा होता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि सरकार की प्रति वर्ष बिन्ही के लिए बाजार में लाई जाने वाली मात्रा के विषय में कोई निश्चित नीति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अफीम से आय में बहुत अधिक कमीवेशी होती रहती थी।<sup>116</sup>

इन सभी कारणों से अफीम को राजस्व का जोखिम भरा स्रोत माना जाता था और वजत तैयार करते समय सावधानी के पक्ष में भूल करने और अफीम से आय का कम अंदाजा लगाने का रिवाज बन गया था। गृह अधिकारी अफीम से आय के संयत प्राक्कलनों की प्रथा को प्रोत्साहन देते थे। भारत में यह नीति अधिक लोकप्रिय नहीं थी क्योंकि जानबूझ कर अफीम के अल्पीकृत प्राक्कलन बहुधा प्रत्यक्ष करों को कसने का बहाना होते थे। सरकार ने समस्या से काफी समय तक संघर्ष किया और अंततः दो योजनाएं बनीं। एक योजना सदस्य सर रिचर्ड टैपिल ने तैयार की थी जिसके अनुसार अफीम (आरक्षित) निधि का निर्माण किया जाना था। दूसरी योजना का सुझाव बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेसिल बीडन ने दिया जिसमें अफीम का आरक्षित (रिजर्व) भंडार रखने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष बिन्ही के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा निर्धारित करने की भी योजना थी।

1868 में आर० टैपिल ने सांडे लारेंस के समर्थन से विभिन्न वर्षों में अफीम से होने वाली आय में कमीवेशी के निराकरण की अनोखी प्रणाली का प्रस्ताव रखा। यह योजना मूल रूप से सांडे स्टेनले ने पेश की थी। नोर्थकोट ने लारेंस को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र में स्टेनले द्वारा प्रस्तावित योजना 'कि आपको प्रति वर्ष एक निश्चित राशि राजस्व खाते में जमा करनी चाहिए, अच्छे वर्षों में उसे आधिक्य बीमा निधि में ले जाना चाहिए और बुरे वर्षों में इस निधि से रुपया निकालना चाहिए', की रूपरेखा दी थी।<sup>117</sup> किन्हीं-किन्हीं वर्षों में अफीम से आय आशा से अधिक हो जाती थी। टैपिल ने प्रस्ताव रखा कि यह आधिक्य आरक्षित अफीम निधि के रूप में अलग नकद रखा जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर रोकड़ दोष की कमी को पूरा करने, अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने या अस्थायी रूप से पुनरुत्पादी लोक निर्माणों में लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। यदि अफीम से आय में कमी हो जाए तो घाटा पूरा करने के लिए आरक्षित निधि का प्रयोग किया जाए।<sup>118</sup> परन्तु गवर्नर जनरल की परिपद के अधिकांश सदस्यों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया।<sup>119</sup> मेन तथा स्ट्रैचो योजना को अपना समर्थन नहीं दे सके, ड्यूरेड इसकी उपयोगिता को नहीं समझ सका और मैसफील्ड ने सोचा कि यह योजना शीघ्र ही 'विस्मृति के गर्भ में समा जाएगी'।<sup>120</sup>

अतः, योजना का परित्याग कर दिया गया।

अफीम से आय में तीव्र उतार-चढ़ावों से भारतीय वित्त की रक्षा करने के लिए एक अपेक्षाकृत श्रेष्ठ योजना का प्रस्ताव पहले ही आ चुका था। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेसिल बीडन ने 18 अप्रैल, 1867 के कार्यवृत्त में दृढ़ता के साथ कहा था कि इन उतार-चढ़ावों का मूल कारण सरकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली बंगाली अफीम की मात्रा में कमीबेशी है।<sup>121</sup> जान स्ट्रैची का भी यही मत था जो अफीम के आरक्षित भंडार एकत्रित करने की आवश्यकता का कायल था।<sup>122</sup> यदि उत्पादन अधिक होता तो अतिरिक्त उत्पादन को आरक्षित भंडार में जमा करना था, जिसका उपयोग अगली फसलें खराब होने के समय हो सकता था। हर वर्ष सरकार द्वारा पहले से घोषित एक निर्धारित मात्रा बेची जानी थी। यह मात्रा अफीम की 'मानक' आपूर्ति के नाम से ज्ञात थी।<sup>123</sup> यदि उत्पादन इस 'मानक' से अधिक होता था, तो अतिरिक्त मात्रा बाजार में न ले जाकर, आरक्षित भंडार में रखनी होती थी। यह योजना स्वीकार कर ली गई, यद्यपि योजना लागू होने की प्रारंभिक अवस्था में फसलें खराब हो जाने के कारण अफीम का समुचित भंडार नहीं बन सका। ब्रिटिश व्यापारिक हित इस योजना के विरुद्ध नहीं थे। मैसर्स जार्ज इन, स्किनर एंड कंपनी तथा कुछ दूसरों ने भारत सरकार के वित्तीय सचिव को लिखा, 'ऐसे व्यापार के ढंग को नियमित करने के लिए पूर्वापार किए जाने चाहिए जिसके मूल्य में बराबर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। हम सरकार से अप्रह्न करने का साहस करते हैं कि प्रत्येक वर्ष बिक्री के लिए रखी जाने वाली मात्रा में समानता लाना पहला कार्य होना चाहिए'।<sup>124</sup> व्यापारिक कंपनियों ने भारत सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह जितनी मात्रा बिक्री के लिए अगले वर्ष प्रस्तुत करना चाहती है उसे पहले ही घोषित करे। सामान्यतः मानक 48,000 पेटी या और यही लक्ष्य भी हुआ करता था। परंतु प्रारंभिक अवस्था में इसमें कमीबेशी हुई। 1879 तक निश्चित मात्रा की जो प्रत्येक माह बेची जानी थी और जिसे सरकार बिना पूर्व सूचना के न बदलने के लिए बचनबद्ध होती थी, पहले में घोषणा कर पाना संभव नहीं हो सका था।<sup>125</sup> 1871-72 के वर्ष के अनुभव से योजना के लाभ प्रकट हो गए। यद्यपि फसल की प्रत्याशित उपज का एक चौथाई भाग नष्ट हो गया था, तथापि पिछले वर्ष संकथ किए गए भंडार से मातृ निकास कर सरकार 'बढ़ी हुई कीमतों पर पूरी आपूर्ति का पूरा फायदा उठा सकी'।<sup>126</sup>

प्राप्ति में उतार-चढ़ाव ही अफीम में संबंधित समस्या नहीं थे क्योंकि आय का यह स्रोत समाप्त हो जाने का डर था और बिना यह कहीं अधिक बड़ा कारण था। यह आशंका चीन तथा फारस की शाही के क्षेत्र में अपेक्षाकृत मस्ती किस्मों की अफीम के उत्पादन में पैदा हो गई थी। फारस में यज्द तथा इस्फहान में पैदा किए जाने वाले पोता में पैदा हुई अफीम बंगाल और बंदर अम्बास होनी हुई मस्ती पहुंचती थी, जहाँ से अरब और भारतीय मण्डोदाग यह शब्द नाखुदा (Nakhudas) होनी चाहिए। नाखुदा का अर्थ है मन्नाह भारतीय और अरब मन्नाह अफीम साने में जाने का काम करते रहें होंगे। निगापुर तथा चीन की अफीम का निर्यात करने में। कभी-कभी तस्कर व्यापारी इन मन्नाहों द्वारा कराची बंदरगाहों के रास्ते भारत में आने में।<sup>127</sup> कुछ घटिया किस्म

की अफीम शीराज के आसपास, करमान, काजरन के निकट मुरमेसीर तथा उसके निकटवर्ती जिलों में पैदा की जाती थी। परंतु फारस की अफीम की कुल मात्रा लगभग 10,000 शाहमुन (एक शाहमुन = 14 पौंड) होती थी, जो अधिक नहीं थी। इसकी औसत कीमत भारतीय अफीम से कम होती थी, जिससे सुदूर पूर्व के बाजारों तक इसके यातायात की लागत निकल आती थी।<sup>128</sup> अफीम के संपूर्ण बाजार को प्रभावित करने की दृष्टि से फारस के उत्पादन की मात्रा बहुत कम थी। 1868 में एक अनोखा प्रस्ताव रखा गया कि भारत सरकार को फारस की खाड़ी में होने वाले व्यापार को राजस्व का स्रोत बना लेना चाहिए और इसके लिए फारस और टर्की के अफीम के समस्त उत्पादन को खरीद लेने के बाद उचित कीमत पर बेचना चाहिए।<sup>129</sup> यह व्यावहारिक नहीं समझा गया। यद्यपि पश्चिम एशियाई अफीम का उत्पादन तथा निर्यात नगण्य था, तथापि भविष्य में उत्पादन में वृद्धि की संभावना के कारण भारतीय अधिकारी चिंतित थे।<sup>130</sup> फारस की खाड़ी के पोलिटिकल रेजिडेंट जुई पैली की एक रिपोर्ट के अनुसार आठवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में कुल उत्पादन 2,500 पेटो था। फारस तथा तुर्की की अफीम चीन, सिंगापुर तथा लंदन भेजी जाती थी।<sup>131</sup>

भारतीय अफीम से प्रतिस्पर्धा करने वाली चीनी अफीम की किस्में नांतू (यूनान प्रांत की अफीम), चेंगटू (सेचुएन प्रांत की), और क्वीचाउटू (क्वीचाउ प्रांत की) थी। दक्षिण पश्चिम चीन के यन्नान प्रांत में 1736 के लगभग अफीम का उत्पादन होता था, और 1840 में उसका उत्पादन निकटवर्ती सेचुएन तथा क्वीचाउ प्रांतों में फैल गया।<sup>132</sup> चीनी सरकार द्वारा अफीम की खेती को हतोत्साहित करने के लिए किए प्रयत्नों के बावजूद इसका उत्पादन तेजी के साथ फैल रहा था। 1859-60 में यन्नान, सेचुएन तथा कांग्सू का उत्पादन स्थानीय उपभोग को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था और थोड़ी सी मात्रा दूसरे राज्यों को भी भेजी जाती थी। 1859-60 में अफीम का उत्पादन करने वाले प्रांतों के सबसे निकट हाकाउ का बंदरगाह केवल स्वदेशी अफीम का आयात करता था। विदेशी अफीम का आयात बिल्कुल नहीं था। परंतु यह चरम सीमा थी। इसके बाद धरेलू उत्पादन गिर गया और अगले कुछ वर्षों में विदेशी अफीम पुनः आ गई। 1861 में कैंटन में रहने वाले ब्रिटिश वाणिज्य दूत (कॉन्सुल) ने सूचना दी कि चीनी अफीम घटिया किस्म की होते हुए भी सस्ती होने के कारण से निम्न स्तर के वर्गों में लोकप्रिय थी। 'अफीम का दम लगाने वाले लोगों की नई पीढ़ी' स्वदेशी अफीम को अधिक पसंद करती थी। महंगी भारतीय अफीम में मिलावट के लिए भी चीनी अफीम का प्रयोग किया जाता था।<sup>133</sup> ब्रिटिश राजनयिक प्रतिनिधियों को चीन के भीतरी प्रदेशों में अफीम की खेती के विस्तार की डराने वाली सूचनाएं मिल रही थी।<sup>134</sup> 1861 में यांग्तिसी क्वांग नदी तक पहुँचने वाले यात्री ने देखा था कि संपूर्ण पश्चिमी चीन अफीम की दृष्टि से लगभग आत्म-निर्भर था। पूर्वी और तटीय प्रांत तब भी विदेशी अफीम पर पूर्णतया निर्भर थे।<sup>135</sup> वास्तव में चीनी उत्पादन इतना बढ़ गया था कि ब्रिटिश बर्मा को निर्यात प्रारंभ हो गया था जिससे भारतीय अधिकारी भयभीत हो उठे। काफिलों के द्वारा यन्नान की अफीम को माडले लाया जाता था और व्यापारी रगून के बंदरगाह से खाड़ी उपनिवेशों को अफीम

का निर्यात करते थे (अब तक यहाँ पर केवल बनारस की अफीम आती थी)।<sup>136</sup> उस समय उपर्युक्त स्थिति थी जिसके बारे में 1863 में ए० पी० फायरे ने अपनी रिपोर्ट दी थी।<sup>137</sup>

1864 से चीन में अफीम का उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा। चीन में व्यवसाय करने वाले अफीम के ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा दी गई सूचना से ऐसा लगता है कि 1864 से 1869 तक पांच वर्षों में अफीम का उत्पादन न केवल पश्चिम के यन्नान, सेचुएन तथा क्वीचाउ प्रांतों में बढ़ा, अपितु यह पूर्व में क्वागतुंग, होनाग, हूवे, कियान्गसिन, चेकियांग में तथा मंचूरिया और मंगोलिया में भी फैल गया। शंघाई चेंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों तथा सर आर० आल्काक ने 1869 में सूचना दी कि सेचुएन में लगभग दो तिहाई तथा यन्नान में लगभग एक तिहाई कुपि योग्य भूमि पर अफीम की खेती हो रही थी।<sup>138</sup> अफीम की खेती के बारे में राजाज्ञा प्रभावहीन थी और स्थानीय गवर्नरों को राजस्व के स्रोत के रूप में अफीम के प्रति कोई आपत्ति नहीं थी। यह संभव है कि चीनी स्थानीय अधिकारी स्वदेशी उत्पादन की स्वीकृति देकर विदेशी अफीम का आना रोकने की दिशा में प्रयत्न कर रहे थे।<sup>139</sup> सर आर० आल्काक तथा सर एफ० जे० हाली डे को संदेह था कि भारतीय व्यापार को नष्ट करने के उद्देश्य से चीनी अधिकारियों ने अफीम की खेती को हतोत्साहित करने की नीति दीखी कर दी थी।<sup>140</sup> आल्काक ने मेयो को लिखा कि चीनी सरकार भारतीय अफीम का दाम गिराने और फिर उसे चीनी बाजार से निकाल देने और कुछ समय बाद चीन में अफीम का उत्पादन ही बंद कर देने के इरादे से इसके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। मेयो ने इस पर टीका करते हुए कहा था कि 'इससे अधिक हास्यास्पद एवं बेतुकी नीति की कल्पना कर पाना भी कठिन है और ऐसी बात चीनी मस्तिष्क में ही आ सकती है।' <sup>141</sup> चीनी नीति में परिवर्तन और वहाँ पर अफीम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के कुछ भी प्रयोजन क्यों न हों, इससे भारतीय अफीम का भविष्य निराशाजनक हो गया था। कलकत्ता के प्रमुख अफीम व्यापारियों को बाजार में मंदी आने की आशंका हो गई थी।<sup>142</sup> यद्यपि अफीम की बिक्री में भारी कमी नहीं हुई थी फिर भी कलकत्ता के व्यापारिक स्रोतों में आतंक के लक्षण दिखाई देते थे। <sup>143</sup> मेयो ने आरगाइल को लिखा कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी अफीम से संबंधित बातें बिलकुल नई हैं और इस संबंध में पुरानी भारतीय कहावत कि अफीम संबंधी घनरे आवर्ती होते हैं, चरितार्थ नहीं होती।' <sup>144</sup> ऐसा लगता था कि भारत सरकार को 'आगे आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वित्त में अफीम की स्थिति इतनी निराशाजनक कभी भी नहीं दिखाई दी थी।' <sup>145</sup>

चीनी अफीम का सस्ता होना इसके इतने अधिक लोकप्रिय होने का प्रधान कारण था। भीतरी क्षेत्रों में अफीम के उत्पादन क्षेत्रों के आस-पास विदेशी अफीम काफी अधिक महंगी थी, क्योंकि इस पर बंदरगाह से भीतरी प्रदेशों तक यातायात के विविध खर्च पड़ जाते थे। 'अफीम व्यवसाय संबंधी मंथि में शामिल बंदरगाहों पर स्वदेशी अफीम की कीमत विदेशी अफीम की दो तिहाई है और इन कीमतों पर इनमें ठीक प्रतियोगिता रहनी है। हाराव में कीमतों का अंतर स्वदेशी अफीम के पक्ष में एक तिहाई में



मिलने के लिए तत्पर है।<sup>155</sup> इसके अलावा भारतीय अधिकारियों को डर था यदि भारत से अफीम के निर्यात में कमी कर दी गई तो रिक्त स्थान दूसरे देशों के उत्पादों से, जो अब तक भारतीय अफीम के साथ असफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर रहे थे, भरा जा सकता है। यदि भारत अपने निर्यात में कमी कर दे अथवा उसे पूरी तरह बंद कर दे तो वह वस्तुतः 'वे लाखों रुपये जो मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं, फारस वालों या अमरीकी लोगों को अथवा अन्य किसी को सौंप देगा।'<sup>156</sup> अतः, मेयो हड़बड़ाहट में कोई भी समझौता करने के लिए अनिच्छुक था। इस सबके अलावा वह इस मामले में 'भावुकता' के विरुद्ध था। उसने फ्रेर को लिखा, 'यदि हम चीनियों को विष देने के अपराध से बचना चाहते हैं तो यह बहुत धीरे-धीरे हो सकता है।'<sup>157</sup> अस्तु, समझौता करने के विषय में चीनियों के प्रति संदेह, चीन की साम्राज्यिक सरकार की अपनी ही घोषित नीतियों को कार्यान्वित करने में असमर्थता तथा चीनी बाजार को भारत के प्रतिस्पर्धियों को समर्पित करने के विषय में अनिच्छा वे कारण थे जिनकी वजह से आल्काक की योजना रद्द कर दी गई। इसके अलावा यह अनुभव किया गया कि आगे आने वाले वर्षों में भारतीय अफीम चीन के बाजार में अपनी ही सामर्थ्य पर विकसित रहेगी। क्योंकि भारतीय अफीम अच्छी किस्म की थी, कुल चीनी उपभोग तेजी के साथ बढ़ रहा था और चीन की सरकार भारतीय अफीम को चीन से बाहर कर पाने में उसनी ही असमर्थ थी जितनी कि धरेलू उत्पादन पर रोक लगा पाने में थी। सचमुच उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक की यह घबराहट कि अफीम से होने वाली आय को तत्काल खतरा है, यदि गलत नहीं तो समय से पहले अवश्य थी।

### III

टैरिफ नीति के पीछे निर्देशक सिद्धांत यह था कि कराधान केवल राजस्व की दृष्टि से होना चाहिए और इसलिए टैरिफ का स्वरूप संरक्षणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसा कि सेमुअल लैंग ने कपास की गांठों तथा घागे पर आयात शुल्क में कमी की घोषणा करते हुए कहा था कि 'मुक्त व्यापार का सिद्धांत केवल राजस्व के निमित्त कर लगाना है' और किसी भी सीमा शुल्क के द्वारा 'संरक्षित हितों के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।'<sup>158</sup> वास्तव में लैंग इस समाचार से कि भारत में 'ऊँचे शुल्क (सीमा शुल्क) के बल पर' सूती मिलें स्थापित हो रही हैं, इतना भयभीत हो गया कि उसने घोषणा की कि यदि 'सूत कराधान के लिए उपयुक्त पदार्थ है तो इसके देशी उत्पादन पर भी निमित्त पदार्थों पर लगाए गए सीमा शुल्क के द्वारा ही उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) लगाया जाना चाहिए। जूट के बने हुए माल पर शुल्क के विषय में भारत मंत्री को भारत सरकार के प्रेषण में इस सिद्धांत को पुनः स्पष्ट रूप से घोषित किया गया। प्रेषण में लिखा गया था कि 'भारत में कोई भी आयात कर नितात राजकोपीय प्रयोजन को छोड़ कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं लगाए जाते। आयात सीमा शुल्क टैरिफ निर्धारित करते समय हम स्वदेशी उत्पादन को चाहे वह जूट, कपास अथवा किसी अन्य पदार्थ का हो, संरक्षण देने की इच्छा से विलकुल प्रभावित नहीं हुए हैं।'<sup>159</sup> ब्रिटेन

के औद्योगिक हित इस सिद्धांत का अनुमोदन करते थे परंतु उन्हें सदैव यह विश्वास नहीं था कि भारत सरकार इनका पालन कर रही है। वे बड़े अधीर होकर सभी शुल्कों को हटाने का आग्रह कर रहे थे। 1862 में मैनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स तथा 1869 में इंडी चेंबर आफ कामर्स ने भारत में विना शुल्क दिए ही आयात करने का विशेषाधिकार मांगा।<sup>160</sup> तथापि सभी भारतीय आयात शुल्कों को हटाने के लिए चलाए गए आंदोलन को 1882 तक सफलता नहीं मिली क्योंकि 1882 तक भारतीय वित्त की स्थिति ऐसी नहीं थी कि भारत सरकार सीमा शुल्क में होने वाली भारी आय को छोड़ सकती।

ब्रिटिश औद्योगिक हितों द्वारा भारतीय टैरिफ नीति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखने की बात समझ में आती है। लंकाशायर के उद्योगपतियों के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण बाजार था। इंग्लैंड से लंकाशायर के माल के निर्यात में 1860 में 29.7 प्रतिशत और 1870 में लगभग 28.4 प्रतिशत निर्यात भारत को हुआ।<sup>161</sup> जिस अवधि का हमने अध्ययन किया है उसमें बहुत अल्प समय के लिए उत्तर संन्य विद्रोह काल के वित्तीय संकट की स्थिति को छोड़कर ब्रिटिश सूती वस्त्रों पर 5 प्रतिशत का बहुत मामूली सीमा शुल्क रहा था। 1859-60 से 1861-62 तक की अल्प अवधि में शुल्क बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। सूती वस्त्रों के आयात में निरंतर वृद्धि होती गई। 1858-59 से 1861-62 तक भारत में सूती वस्त्रों का औसत वार्षिक आयात 89.5 लाख पौंड के मूल्य का था। 1862-63 से 1866-67 के वर्षों का औसत 108.4 लाख पौंड तथा 1867-68 से 1871-72 तक की अवधि का औसत 105.6 लाख पौंड था।<sup>162</sup> कपास की गांठों और सूत पर 1859-60 में शुल्क 5 प्रतिशत, 1860-61 में 10 प्रतिशत, 1861-62 में 5 प्रतिशत तथा 1862-63 के बाद 3½ प्रतिशत था। 1858-59 से 1862-63 तक के काल में कपास की गांठों, सूत तथा धागे के वार्षिक आयात का औसत मूल्य 16.5 लाख पौंड (भार 253.6 लाख पौंड) था। 1867-68 से 1871-72 की अवधि में इसमें वृद्धि हुई और वार्षिक औसत 28.1 लाख पौंड (314.1 लाख पौंड) हो गया। भारत में लंकाशायर के व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही थी और सीमा शुल्क मामूली थे जिसका श्रेय मैनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स को है जो इस संबंध में सतर्क था।

रैंडफोर्ड ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि '1858 से लगभग अब तक भारतीय आयात शुल्क भारत के साथ लंकाशायर के व्यापार के लिए भारी खतरा (कम से कम मैनचेस्टर चेंबर के अनुसार) बने रहे हैं।'<sup>163</sup> परंतु जिस आशंका से लंकाशायर के हितों को सबसे अधिक डर था, भारत सरकार की टैरिफ नीति से भी अधिक, और जिसे मैनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स प्रभावित कर पाने में अथवा रोक पाने में बहुत कठिनाई अनुभव करता रहा वह था भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास। 1859 में बंबई प्रेसीडेंसी में दो सूती मिलें थी जिनमें पहली 1853 में और दूसरी 1854 में प्रारंभ हुई थी। 1874 तक बंबई प्रेसीडेंसी में 14 मिलें हो गई थी जिनमें 197.75 लाख रुपये की पूंजी लगी थी; इनमें 4 लाख 35 हजार से अधिक तकुए तथा 4,883 करघे थे; इनका मासिक उत्पादन 26,14,000 पौंड सूत तथा 12,30,000 पौंड कपड़े से अधिक रहता था।<sup>164</sup> कलकत्ते में छः मिलें (1,07,130 तकुए और 200 करघे) और देश के भीतरी भागों में



चार मिलें (58,882 तकुए और 387 करघे) थी। अतः कुल मिलाकर 24 मिलें थी और उनके बीच 6,01,738 तकुए और 5,460 करघे थे तथापि सूती मिल उद्योग शिथिल उद्योग था और इससे अब तक मैनचेस्टर के भारत तथा अन्य बाजारों के साथ व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

परंपरागत कुटीर उद्योग जो उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक तक बहुत अशक्त हो गया था, अब भी ग्रामीण जनता के बड़े अंश को वस्त्रों का संभरण कर रहा था। 1863 में कलकत्ता के चेंबर आफ कामर्स ने सरकार से उत्तरी भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति का एक सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया। यह आशंका थी कि कपास से कपड़ा अपेक्षाकृत उस मूल्य से कम लागत पर तैयार किया जा सकेगा जो मैनचेस्टर के माल के लिए दिया जाता था और स्थानीय उत्पादक अधिक बड़े पैमाने पर उत्तरी तथा पश्चिमोत्तर प्रांत की थोड़ी सी मांग को हथियाने का प्रयास करेंगे।<sup>128</sup> 1863-64 में पश्चिमोत्तर प्रांत, अवध, बंगाल तथा मध्य प्रांत के जिला अधिकारियों ने एक व्यापक जांच की। इस जांच से पता चला कि कपास की कीमतों में वृद्धि के कारण (अमरीकी गृह युद्ध के समय जब इसके कारण लंकाशायर में कपास का 'दुर्भिक्ष' था और भारत से कच्ची कपास के निर्यात में तेज बाजारी थी) भारतीय बुनकर कच्चा माल नहीं खरीद पाते और अपने माल को आयात किए हुए कपड़े के मूल्य से कम पर बेच पाने में असमर्थ हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत में देशी सूती वस्त्र उद्योग का 'निरंतर पतन हो रहा था। जो लोग अब तक इस उद्योग में लगे थे वे अन्य उद्योगों में मजदूरी की ऊंची दरों से आकर्षित होकर उधर जा रहे हैं।' देश में तैयार किए जाने वाले मोटे कपड़े का मूल्य ब्रिटिश कपड़े की तुलना में अधिक बढ़ा है। जहां देशी वस्त्रों के मूल्य में 200 या 300 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहां इंग्लैंड के वस्त्रों के मूल्य में केवल 150 से 200 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।<sup>129</sup> पश्चिमोत्तर प्रांत के पश्चिमी जिलों में 16 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत करघों पर काम बंद हो गया जबकि पूर्वी जिलों में 'व्यापार पूरी तरह ठप्प हो गया' और एक तिहाई अथवा आधे करघों पर काम बंद हो गया।<sup>130</sup> बुनकरों ने या तो कृषि मजदूरों के रूप में अथवा फिर किसी दूसरे प्रकार का काम ले लिया, कुछ ने घरेलू नौकर का काम कर लिया, कुछ मारीनम तथा दूसरे स्थानों पर चले गए और कुछ भीष मांगने लगे।<sup>131</sup> अवध, बिहार तथा बंगाल के जिलों और मध्य प्रांत में भी ऐसी ही स्थिति थी। कपड़ा बुनने का काम (कपास उत्पादन के सपन्न क्षेत्रों में घरेलू उपभोग को छोड़ कर) कम हो गया था, क्योंकि बुनकर प्रचलित ऊंची कीमत पर कपास खरीद पाने और कपड़े की लागत के साथ बेच पाने में असमर्थ थे।<sup>132</sup> प्रतिकूल स्थितियों के होते हुए भी कुटीर उद्योग क्यों जीवित था इसका कारण यह था कि कुटीर उद्योगों का उत्पादन ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त होता था। '(किस प्रकार स्वदेशी वस्त्र उद्योग जीवित बना हुआ था) इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वदेशी वस्त्र इस देश को इंग्लैंड से निर्यात किए जाने वाले कपड़े की तुलना में मोटा, मजबूत और अधिक टिकाऊ होता है और इस प्रकार यह मजदूर वर्ग के कपड़े और शूने स्थानों पर काम के लिए अधिक उपयुक्त है। श्रमिक..... इंग्लैंड के मशीन निर्मित हुनके और उत्तम श्रेणी के वस्त्रों की तुलना में स्वदेशी वस्त्र को

अधिक सस्ता पाता है ।<sup>170</sup> तथापि, यह आशा की जाती थी कि 'लोगों की उपभोग संबंधी आदतें बदल जाएंगी और लकाशायर की मिलें स्वदेशी कपड़े की तरह का वस्त्र बनाने लगेंगी और उसे कम कीमत पर बेच सकेंगी । सर चार्ल्स ट्रैवोलियन ने भविष्यवाणी की कि 'जब मैनचेस्टर की मिलें पुनः अच्छे ढंग से चालू हो जाएंगी तो वे देखेंगी कि उनके स्थानीय प्रतिस्पर्धी उत्पादक अप्रत्याशित हद तक परिवर्तित हो कर उनके माल के नकदी ग्राहक बन गए हैं ।' अधिकांश बुनकर कृषि कार्य में पुनः लग गए थे । 'हमारे अपने हाथकरघा बुनकरी की भांति काफी बड़ी संख्या में यहाँ के बुनकर भी पहले से ही अर्ध कृषक थे और उनका कृषक वर्ग में विलयन इंग्लैंड और भारत दोनों ही के लिए लाभप्रद है । भारत की आश्चर्यजनक उत्पादक शक्तियाँ हैं और कृषि कार्य सदैव ही यहाँ का प्रधान उद्योग रहना चाहिए । इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा चुका है ।'<sup>171</sup>

उपर्युक्त अंतिम कथन परिचित विचारधारा का प्रतिनिधि है जो कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत और निमित्त माल के उत्पादक के रूप में इंग्लैंड के मध्य 'साधारण श्रम विभाजन' के आधार पर निर्भर है । व्यापार का यह स्वरूप जो ब्रिटिश व्यापारिक वर्ग के अधिकांश लोगों को स्वाभाविक लगता था,<sup>172</sup> बंगाल चेम्बर आफ कामर्स द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए स्मरण पत्र में इस प्रकार था 'इन देशों (इंग्लैंड इत्यादि) की मिट्टी, जलवायु, पूँजी तथा उद्योगों के द्वारा कम लागत पर तैयार होने वाले माल का इस देश के कच्चे माल के साथ, जिसके उत्पादन में इसे विशिष्ट सुविधा प्राप्त है, लाभ के साथ विनिमय करने के लिए प्रतिबद्धों से पूर्ण स्वतंत्रता है ।'<sup>173</sup> इंग्लैंड के औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों के लिए भारत, बाजार की दृष्टि से भी, उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि कुछ आवश्यक कच्चे मालों के आपूर्ति स्रोत की दृष्टि से । उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में सूती वस्त्र उद्योग के हित समर्थक ससद सदस्यों (काटन एम० पी०) की सहायता में मैनचेस्टर चेम्बर आफ कामर्स तथा काटन सप्लाइ एसोसिएशन ने भारत सरकार पर कच्ची कपास की आपूर्ति बढ़ाने तथा लकाशाय को, जिसे कपास के अभाव का सामना करना पड़ रहा था, (विशेष रूप से अमरीकी गृह युद्ध के समय) कपास की आपूर्ति में आने वाली बाधाएँ दूर करने के लिए दबाव डाला । वस्त्र उत्पादकों की दिलचस्पी कच्चे जूट, फ्लैक्स तथा सन की आपूर्ति बढ़ाने में भी थी । जेम्स विल्सन ने अपने प्रथम वजट विवरण (1860) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जिन मालों का उपयोग इंग्लैंड में होता है और जिन्हें अन्य देशों के उत्पादनों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है उन पर यथासंभव थोड़े कर लगाए जाने चाहिए ।<sup>174</sup> 'जहाँ तक आयात शुल्क का प्रश्न है सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि इसमें लागत में वृद्धि होती जाती है, और इस प्रकार यह उपभोक्ता पर कर है । परंतु जहाँ तक निर्यात शुल्क का प्रश्न है आपका यह शुल्क वस्तु को विदेशी बाजार से ही बिलकुल बाहर कर सकता है ।' इससे भारी हानि हो जानी थी क्योंकि जूट, कपास, सन, खाल, ऊन इत्यादि 'यूरोप के महान उत्पादक देशों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल थे और इनकी माँग में असीमित विस्तार की संभावना थी ।' विल्सन ने घोषित किया कि 'अपने आंतरिक



कुछ वस्तुओं के ऊपर टैरिफ नीति पर विशेष टिप्पणी आवश्यक है। सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारी शुल्क से भारत का शोरा व्यापार वस्तुतः नष्ट हो गया था। निर्यात शुल्क के कारण यूरोप में भारतीय शोरे को प्रतियोगी मूल्य पर बेच पाना असंभव हो गया था और कृत्रिम शोरे के उत्पादन से संबंधित तकनीक के विकास ने इसके व्यापार पर सांघातिक प्रहार किया। शोरे का निर्यात 1862-63 में 20,253 टन था। 1863-64 में यह कम होकर 16,805 टन और 1864-65 में यह केवल 11,043 टन रह गया। 1865 में शुल्क में कमी हो जाने के बावजूद निर्यात में कमी हुई। भारत मंत्री का अनुमान था कि 'भारतीय पदार्थों की भारी शुल्क के कारण यूरोप के नव निमित्त पदार्थ के साथ प्रतियोगिता कर सकने की असमर्थता' के कारण ऐसा हुआ।<sup>181</sup>

कच्ची कपास जिसका अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों को बंगाल तथा मद्रास से निर्यात होता था और जिस पर मामूली सा निर्यात शुल्क था, 1859 में कर मुक्त पदार्थों की सूची में आ गई। 1856-57 से 1860-61 तक की अवधि में औसतन 30 करोड़ पाँड कपास का निर्यात हुआ और औसत कीमत 5 पैसे प्रति पाँड से कम थी। अमरीकी गृह युद्ध के समय कीमतों में तेजी के साथ वृद्धि हुई (1864-65 में 17 पैसे प्रति पाँड हो गई) और निर्यात में निरंतर वृद्धि के बाद 1865-66 में निर्यात 80 करोड़ पाँड तक पहुँच गया। 1865 से कीमतों में कमी होने लगी। 1866-67 में यह 9½ पैसे और 1870-71 में 6½ पैसे प्रति पाँड थी। कपास में तेजबाजारी अस्थायी घटना थी और जैसे ही अमरीकी गृह-युद्ध समाप्त हुआ लकाशायर में भारतीय कपास की भाँग कम हो गई और बाजार में भारी मंदी आ गई। वास्तव में 50 वर्षों तक भारतीय कपास की किस्म में सुधार करने के प्रयत्नों के बावजूद वह अमरीकी कपास से, जो लम्बे रेशे वाली थी, बहुत नीची श्रेणी की थी। जहाँ तक जूट के निर्यात का प्रश्न है, क्रिमियन युद्ध के समय रूसी सन (हेम्प) की आपूर्ति में कमी हो जाने के कारण, इसे अपना बाजार विकसित करने का अवसर मिला। निर्यात जो 1860-61 में 4,09,000 पाँड का था, 1870-71 में बढ़ कर 25,77,000 पाँड हो गया। कलकत्ते के पास स्कॉटिश प्रबंध में जूट उद्योग का विकास हुआ जो आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अफ्रीका के विदेशी बाजारों में डडी के उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने लगा।<sup>182</sup>

1869 में डंडी चेंबर आफ कामर्स ने भारत उपमंत्रि से जूट माल के मामले पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जिस पर 7½ प्रतिशत आयात शुल्क था, '7½ प्रतिशत आयात कर केवल राजस्व की दृष्टि से नहीं लगाया गया है, अपितु यह तो स्वदेशी उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है और डंडी के उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता करने से रोकता है। साथ ही, यह भारतीय उत्पादकों को आस्ट्रेलिया में डंडी के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता करने के अवसर प्रदान करता है। (डंडी चेंबर आफ कामर्स के) निदेशकों का विश्वास है कि भारत में जूट उत्पादों पर से आयात कर हटा दिया जाएगा।'<sup>183</sup> भारत सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसका इरादा भारतीय जूट उद्योग को संरक्षण देने का है किंतु यह माना कि जूट उत्पादकों को सूती वस्त्रों की श्रेणी में रखना न्यायसंगत होगा और उन पर कराधान के लिए 5 प्रतिशत की नीची दर

रखी जा सकती है। सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री को अपने उत्तर में लिखा कि अगली बार जब टैरिफ में संशोधन होगा सब 'जूट उत्पादों पर आयात कर को सूती वस्त्रों पर कर की कोटि में लाने के औचित्य' पर विचार किया जाएगा।<sup>184</sup> 1870 में (अधिनियम XVII) जूट उत्पादों पर से शुल्क हटा दिया गया।

1867 तक खाद्यान्नों पर निर्यात शुल्क 2 आने प्रति मन था। इसमें वृद्धि दो आधारों पर उचित ठहराई जा सकती थी। प्रथम, इससे राजस्व में वृद्धि होगी, तथा द्वितीय, यह लोगों के मुख्य खाद्य के निर्यात को रोकने में सहायक होगी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस विषय पर एक सराहनीय कार्यवृत्त में लिखा, 'यह एक यथार्थ एवं अकाट्य तथ्य है कि जब बंगाल और उड़ीसा के हजारों निर्धन व्यक्ति पिछले कुछ महीनों में क्षुधापीडित रहे हैं नाखो मन (खाद्यान्न) मुनाफे के साथ विदेशों को निर्यात कर दिया गया है—यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत एक निर्धन देश है जबकि वे देश संपन्न हैं जिन्हें भारतीय खाद्यान्न का निर्यात होता है। वे भारत के चावल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में ही नहीं बल्कि कला के लिए और अनेक वस्तुएं तैयार करने के लिए करते हैं। वे इसके लिए एक विलासिता की वस्तु की भांति वह कीमत दे सकते हैं जो भारत के निर्धन वर्गों के लिए, जिनकी यह अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है, दे सकना असंभव है।'<sup>185</sup> बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 6 आने प्रति मन शुल्क का प्रस्ताव रखा। वास्तव में इससे कम शुल्क का निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव न पड़ता और वह खाद्यान्नों के निर्यात को नहीं रोक सकता था। सपरिषद गवर्नर जनरल ने शुल्कों में बहुत थोड़ी वृद्धि का निर्णय लिया (2 से 3 आने तक)। ऐसा लगता है कि निर्णय केवल वित्त संबंधी बातों से प्रभावित था और निर्यात को हतोत्साहित करने के पक्ष में दिए गए तर्कों को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। भारत सरकार की आशा थी कि शुल्क में वृद्धि से राजस्व में 16 लाख रुपये की वृद्धि होगी। उसने भारत मंत्री को आश्वासन दिया कि 'इस माम्यता के लिए कोई कारण नहीं कि शुल्क में इतनी थोड़ी वृद्धि से निर्यात के लिए उपलब्ध होने वाले खाद्यान्न की मात्रा पर थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है।'<sup>186</sup> खाद्यान्नों का निर्यात करने वाली व्यावसायिक फर्मों के दबाव पर भारत सरकार को, शुल्क में वृद्धि करने के तत्काल बाद ही, उस पर पुनर्विचार करना पड़ा। लिवरपूल के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा भारत के व्यापारियों ने अधिकारियों के पास प्रतिवेदन भेजे।<sup>187</sup> भारत सरकार का ध्यान खाद्यान्न शुल्कों को समाप्त करने के लिए चलाए गए आंदोलनों की ओर आकर्षित करते हुए भारत मंत्री ने कहा कि देश के सामान्य हितों में व्यापार की रक्षा राजस्व की वृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है चाहे दोनों उद्देश्यों में परस्पर विरोध न भी हो।<sup>188</sup> 1873 में गेहूँ पर निर्यात कर हटा दिया गया।<sup>189</sup>

1860-61 में भारत का 28.1 प्रतिशत निर्यात (सूती, रेशमी, ऊनी और जूट) बपड़ा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का था। 1870-71 में यह अनुपात बढ़कर 43.3 प्रतिशत हो गया। चावल, दूधरे खाद्यान्न तथा बीज निर्यात की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं (1860-61 में कुल निर्यात का 15.57 प्रतिशत और 1870-71 में 14.43 प्रतिशत)। बागान उत्पाद जैसे नीम, चाय, बहवा इत्यादि 1860-61 में कुल निर्यातों का

7.2 प्रतिशत, और 1870-71 में 9.23 प्रतिशत था। 1860-61 में जूट की वस्तुएं (1.09 प्रतिशत), शोरा (2.01 प्रतिशत), चीनी (2.99 प्रतिशत) तथा तेल (0.75 प्रतिशत) जैसे निमित्त माल का कुल निर्यात में अंश बहुत थोड़ा था। 1870-71 में इस स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

आयात की महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंधित 1860-61 तथा 1870-71 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश आयात निमित्त माल का था। 1860-61 सूती वस्त्रों का अंश कुल आयात में 39.63 प्रतिशत और 1870-71 में 46.82 प्रतिशत था। 1860-61 में सूती वस्त्र, कपास की गांठें, धागा व सूत, रेशमी तथा ऊनी माल मिलाकर कुल आयात के 49.13 प्रतिशत तथा 1870-71 में 60 प्रतिशत थे। मशीनें, रेल उपकरण, तथा धातुएं (निमित्त तथा अनिमित्त) मिलाकर 1860-61 में कुल आयात की 20.81 प्रतिशत और 1870-71 में 11.31 प्रतिशत थीं। रेल निर्माण की पहली लहर के बाद उसकी गति धीमी पड़ जाना इसमें कमी होने का कारण था। मादक पेय जैसे बियर, मदिरा, स्पिरिट इत्यादि का 1860-61 में कुल निर्यात में अंश 15.3 प्रतिशत और 1870-71 में 6.93 प्रतिशत था। 1870 में भारत का 50 प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को होता था और वह भारत के 80 प्रतिशत आयातों की पूर्ति करता था।<sup>190</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के नौवें दशक में सरकार सदा की तुलना में ब्रिटिश उत्पादक हितों के दबाव से उनके उत्पादों पर लगे हुए आयात शुल्क को कम करने या पूरी तरह हटाने के लिए कभी अधिक तत्पर थी। कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना टैरिफ नीति का आधारभूत सिद्धांत रहा था। निस्संदेह, केवल टैरिफ सिद्धांत से ही इंग्लैंड और भारतीय साम्राज्य के बीच वांछित, 'श्रम विभाजन' की व्यवस्था, जिसमें इंग्लैंड औद्योगिक माल और भारत कच्चे माल का उत्पादक होता, कर पाना संभव नहीं था। परंतु जैसा कि जेम्स विल्सन और सेमुअल लैंग ने निर्धारित किया था, यह समझा जाता था कि यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस प्रकार के टैरिफ न लगाए जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वदेशी उद्योग को संरक्षण मिलता है। इस नीति के बीसवीं सदी के तीसरे दशक तक निरंतर पालन तथा टैरिफ नीति के कुछ अन्य पहलुओं पर अन्यत्र विचार किया गया है।

## IV

नमक शुल्क उन परोक्ष करों में से था जिनका भार प्रधानतः निर्धन वर्गों पर पड़ता था। भारत सरकार के अधिकारी प्रवक्ताओं का प्रायः दावा रहता था कि मालगुजारी के अलावा केवल यही ऐसा कर है जो विशाल जनसाधारण द्वारा सरकार को अदा किया जाता है। हमारे इस अध्ययन से संबंधित काल में नमक शुल्क उपर्युक्त आधार पर धीरे-धीरे इतना बढ़ाया गया कि वह असह्य हो गया और उसके कारण नमक के उपभोग में कमी हो गई। 1858-59 से 1862-63 की अवधि में इस स्रोत से औसत वार्षिक आय लगभग 3.8 करोड़ रुपये थी। यह भारत के कुल राजस्व की 10 प्रतिशत थी। 1866-67 से 1871-72 के काल में नमक शुल्क से राजस्व का वार्षिक औसत बढ़कर 5.8 करोड़ रुपये हो गया जो सभी स्रोतों से कुल वार्षिक राजस्व का 12 प्रतिशत था।

विभिन्न प्रांतों में नमक शुल्क भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा वसूल किया जाता था। बंगाल में नमक राजस्व के दो स्रोत थे। प्रथम, बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा नमक की विक्री (बंगाल सरकार के प्रत्यक्ष निरीक्षण में तैयार किया जाने वाला नमक); तथा द्वितीय, नमक पर आयात शुल्क। नमक जलवायु और नदियों द्वारा शुद्ध जल के निकास के कारण बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन नहीं होता था। तथापि मिदनापुर और चोवीस परगना में कुछ उत्पादक थे जिनका उत्पादन सरकारी भंडार गृहों में रखा जाता था और उत्पादन लागत तथा आयात शुल्क की प्रचलित दर के आधार पर निर्धारित कीमत पर बंगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा बेचा जाता था।<sup>181</sup> 1863 में बंगाल में सरकारी नियंत्रण में नमक के उत्पादन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। नमक उत्पादकों को दिए जाने वाले अग्रिम (दादन) बढ़ कर दिए गए और बंगाल में नमक का उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया।<sup>182</sup> इस परिवर्तन से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ क्योंकि नमक की थोक कीमतों में 50 प्रतिशत की कमी हो गई। आयातित विदेशी नमक बहुत सस्ता था; परंतु जो लोग अपनी जीविका के लिए नमक के उत्पादन पर निर्भर थे, उन्हें बहुत फट्टा हुआ।<sup>183</sup> 1857-58 में नमक पर आयात शुल्क 2 रुपये 8 आना प्रति मन था। 1859 में सरकार ने संपूर्ण भारत में नमक पर शुल्क बढ़ा दिया। बंगाल में शुल्क 3 रुपये प्रति मन कर दिया गया था। 1861 में शुल्क में पुनः वृद्धि हुई और यह 3 रुपये 4 आना प्रति मन कर दिया गया।<sup>184</sup> जैसा कि फासेट ने स्पष्ट किया, 1870 में आयात शुल्क नमक की प्रधान लागत पर लगभग 700 प्रतिशत था। परंतु जैसा कि सर सेसिल बीडन ने कहा था कि सरकारी दृष्टिकोण यह था, 'कर का औचित्य सोमो की उसे दे सकने और उसे सह सकने की क्षमता द्वारा मापा जाना चाहिए' न कि वस्तु की मूल लागत पर प्रतिशत निकाल कर।<sup>185</sup> संभवतः सरकार इंग्लैंड के उद्योगपतियों से प्रभावित थी। नॉर्थविक के नमक चेंबर आफ कामर्स ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह उन्हें इंग्लैंड से होने वाले नमक के निर्यात के साथ तरजीही सलूक कर उन्हें प्रोत्साहन दे।<sup>186</sup> नॉर्थविक चेंबर ने भारत मंत्री से अपने प्रतिवेदन में आग्रह किया कि भारत में वैश्याय से नमक के आयात में तथाकथित बाधाएं दूर की जाएं।<sup>187</sup> यद्यपि सरकार ने बंगाल में नमक का निर्माण बंद कर दिया था तथापि भारत के लोगों में विदेशी नमक के प्रति पूर्वग्रह था और कुछ समय तक वे 'इंग्लैंड के नमक से संतुष्ट' नहीं थे।<sup>188</sup> 1862 तक भारत सरकार के लिए संतोष के साथ भारत मंत्री को यह सूचना भेज पाना संभव हो सका कि ब्रिटिश नमक के प्रति पूर्वग्रह समाप्त हो रहा है।<sup>189</sup> सरकार को इस बात से कोई मतलब न था कि राजस्व की प्राप्ति स्वदेशी नमक की विक्री से होती है अथवा विदेशी नमक पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क से, परंतु सरकार की नमक एजेंसी का बंद हो जाना बंगाल के स्थानीय उत्पादकों के लिए विनाशकारी था।<sup>190</sup>

बंदई में नमक शुल्क की प्रणाली बंगाल प्रणाली से बहुत भिन्न थी। समुद्र के किनारे-किनारे सूर्य की किरणों से होने वाले वाष्पीकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले नमक पर उत्पाद शुल्क (एक्ससाइज ड्यूटी) लगाया गया था। प्रेंसीडेंसी के उत्तरी भागों में सरकारी स्वामित्व में नमक का उत्पादन करने वाली कुछ इकाइयां थी जो उत्पादन

लागत व उत्पाद शुल्क के आधार पर निर्धारित कीमत पर नमक बेचती थीं। परंतु बंबई में अधिकांश नमक लाइसेंस प्राप्त निजी उत्पादकों द्वारा तैयार किया जाता था जिन पर आंतरिक सीमा शुल्क विभाग का निरीक्षण रहता था। अन्य प्रांतों की तुलना में बंबई में उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) काफी नीचा था। 1857-59 में इसकी दर 12 आना प्रति मन थी। अगस्त, 1859 में इसे बढ़ा कर 1 रुपया प्रति मन कर दिया गया और अप्रैल, 1861 में इसमें पुनः 4 आने की वृद्धि हुई। 1865 में भारत सरकार ने इस प्रश्न पर सलाह मांगी कि नमक पर उत्पाद शुल्क में और अधिक वृद्धि कर पाना व्यवहार्य है अथवा नहीं। बंबई सरकार का विचार था कि शुल्क में वृद्धि की जा सकती है और ऐसा करने पर 'विरोध भड़कने की अधिक जोखिम नहीं है', यद्यपि धनी व्यक्तियों पर किसी भी रूप में आय कर लगाना 'निर्धन व्यक्तियों पर और अधिक कर भार बढ़ाने से कहीं अच्छा है।' भारत सरकार ने नमक शुल्क बढ़ा कर डेढ़ रुपया प्रति मन करने का निर्णय लिया। अक्टूबर, 1869 में शुल्क दर में पुनः संशोधन कर उसे 5 आना प्रति मन बढ़ा दिया गया। अंतः 10 वर्षों में बंबई में नमक शुल्क में 80 प्रतिशत वृद्धि हो गई।<sup>201</sup>

मद्रास की प्रणाली सरकारी एकाधिकार की प्रणाली थी। स्थानीय उत्पादकों द्वारा समुद्र तट पर वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाने वाला नमक सविदा व्यवस्था के आधार पर सरकार को दिया जाता था। सरकार निर्धारित कीमत पर नमक बेचती थी और नमक पर 'शुल्क' वास्तव में नमक की बिक्री द्वारा एकाधिकारी को प्राप्त होने वाला लाभ था।<sup>202</sup> नमक की बिक्री कीमत धीरे-धीरे बढ़ाई गई। 1857-58 में यह 1 रुपया 1859-60 में 1 रुपया 2 आना, 1860-61 में 1 रुपया 6 आना, 1861-64 में डेढ़ रुपया 1865-69 में 1 रुपया 11 आना और अंत में 1869 में 2 रुपया हो गई। शुल्क में तेजी के साथ वृद्धि करने की समझदारी संदेहजनक थी, क्योंकि नमक राजस्व में वृद्धि संभवतः इसे कम कीमत पर भारी संख्या में उपभोक्ताओं को बेचकर हो सकती थी, न कि ऊंची कीमत पर एक संकुचित बाजार में ही बेचकर। भारत सरकार ने मद्रास में नमक की कीमत में वृद्धि को इस आधार पर उचित ठहराया कि यह सभी प्रांतों में नमक शुल्कों के समानीकरण की दिशा में प्रयास था।<sup>203</sup>

पंजाब की अपनी नमक खानें थीं। सरकारी नमक की खानों से बिक्री के लिए 1857-59 में कीमत 2 रुपया, 1860-61 में 2 रुपया 2 आना, 1861-69 की अवधि में 3 रुपया और जुलाई 1870 से 3 रुपया 1 आना थी। सांभर झील को नमक के स्रोत के रूप में विकसित किया गया। मेयो ने सांभर की नमक की झील को पट्टे पर लिया, जोधपुर के राजा पर इस संबंध में समझौते के लिए राजी होने के लिए दबाव डाला गया।<sup>204</sup>

चूंकि नमक शुल्क विभिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न था, इसलिए अंतर्देशीय तत्कर व्यापार एक समस्या बन गया। नमक विभाग में राजस्व संग्रह और नमक के तत्कर व्यापार व अवैध उत्पादन को रोकने के लिए काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी रखे गए थे। आंतरिक सीमा शुल्क आयुक्त के अतर्गत यूरोपीय सहायक आयुक्त तथा सीर कारकून (जो नमक के उत्पादकों के लेखों की जांच करने के अलावा उत्पाद कर लेता था), साक्षे-दार (जो नमक तोलता और स्टॉक लेता था) दरोगा (तत्करी रोकने वाली पुलिस



टुकड़ी का प्रधान), नाकेशर (दरोगा का सहायक चपरासी) इत्यादि हिंदुस्तानी कर्मचारी होते थे। अंतर्देशीय सीमा शुल्क घेरों की निगरानी करने के लिए काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी रखे गए थे। प्रत्येक सीमा शुल्क चौकी पर निरीक्षक तथा संग्राहक, सीमा की निगरानी के लिए दरोगा, कोटगश्न तथा जमादार, और पास अथवा रबन्ना देने के लिए क्लर्क और मुन्शी होते थे। 1869 में एक 2,300 मील लम्बा सीमा शुल्क घेरा सिंधु नदी से लेकर मद्रास में महानदी तक था, एक दूसरा 280 मील लंबा सीमा शुल्क घेरा बर्बई में दोहद से कच्छ की खाड़ी तक फैला था। सीमा शुल्क के लिए निर्धारित सीमाओं पर 12,000 पहरेदार और छोटे अफसर लगे हुए थे।<sup>205</sup>

यह अनुभव किया गया था कि अंतर्देशीय सीमा शुल्क घेरा आंतरिक वाणिज्य में बाधक है और इस पर होने वाला व्यय सरकार पर भार है। परंतु जब तक विभिन्न राज्यों में शुल्क की दरों में काफी स्पष्ट अंतर था तब तक तत्काल व्यापार लाभप्रद था और शुल्क अपवंचन रोक पाना कठिन था। अतः सभी प्रांतों में नमक शुल्कों को बढ़ा कर धीरे-धीरे एक ही स्तर पर ले आना सरकार की नीति थी। केवल नमक शुल्कों को समान बनाकर ही सरकार निरोधक अधिकारियों की अंतर्देशीय सीमा को हटा सकती थी। जयपुर तथा जोधपुर की रियासतों के साथ भारत सरकार का सांभर झील पट्टे पर लेने की सविदा हो जाने पर इन क्षेत्रों से ब्रिटिश भारत में नमक आने पर रोक रखने के लिए बनाया गया 800 मील लंबा सीमा शुल्क घेरा कम किया जा सका।<sup>206</sup> 1877-79 में राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों (अलवर, भवालपुर, झालावाड़, फोटा, नरसिंहगढ़, राजगढ़, रतलाम, खवात, टोंक, भोपाल, बड़ौदा, खालियर इत्यादि) के साथ वहां पर नमक के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक के बाद एक सविदा की गई।<sup>207</sup> जब तक यह हो सका तब तक इन रियासतों से ब्रिटिश भारत में तत्कालीन रोकने के लिए सीमा शुल्क घेरे को बनाए रखना पड़ा। चूंकि भारत सरकार के लिए राजस्व में कमी कर पाना संभव नहीं था, इसलिए नमक शुल्कों को समान करने के लिए जब भी उनमें संशोधन हुआ तो वे बढ़ा दिए गए। वस्तुतः, राजस्व में वृद्धि उतना ही सबल प्रयोजन था, जितना कि नमक शुल्कों को समान करने की इच्छा।<sup>208</sup>

नमक शुल्क ही एकमात्र परोक्ष कर था जो भारी संख्या में जनसाधारण को प्रभावित करता था। वास्तव में यह व्यक्ति कर था। सरकारी मत था कि नमक व्यापार उपभोग की वस्तु होने के कारण कराधान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था। इसके अलावा चूंकि नमक लागत मूल्य में जुड़ जाता था इसलिए लोग इसका उतना क्षिरोर्ध नहीं करते थे जितना कि किसी प्रत्यक्ष कर का कर सकते थे। संग्रह की सुविधा निश्चय ही परोक्ष कराधान के पक्ष में सबसे सबल तर्क था। नमक ही नहीं, बल्कि देश के कुछ भागों में तो चीनी पर भी शुल्क था। 1861-63 में सरकार द्वारा तंबाकू पर शुल्क लगाने के विषय में विचार किया गया परंतु अफीम की भांति सरकारी एकाधिकार, अथवा तंबाकू के व्यापारियों या इसका उत्पादन करने वाले कृषकों पर लाइसेंस कर व्यावहारिक नहीं समझा गया और इसलिए इस योजना को छोड़ दिया गया।<sup>209</sup>

नमक शुल्क जैसे परोक्ष कर का आगामी से संग्रह ही, वह कारण था जिसकी

वजह से भारत सरकार को नमक शुल्क बढ़ाने में सतर्कता की आवश्यकता थी। भारत मंत्री आरगाइल ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि नमक शुल्क 'बहुत भारी और अन्यायपूर्ण हो सकते हैं भले ही वे लोग जिन पर भार पड़ रहा है उस तथ्य को न समझें अथवा अनुभव न करें।' <sup>210</sup> ऐसा लगता है कि नमक शुल्क का नमक के उपभोग पर प्रभाव पड़ा था। 1870 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार बंगाल में नमक का औसत उपभोग 9 पौंड से कम, मद्रास में लगभग 12 पौंड और बंबई में लगभग 15 पौंड था। इन आकड़ों की तुलना ब्रिटेन तथा फ्रांस के आकड़ों से की जा सकती है जहां औसत वार्षिक उपभोग क्रमशः 22 और 18 पौंड था। <sup>211</sup>

नमक कर से संपन्न वर्ग उतने प्रभावित नहीं हुए थे जितना कि जनसाधारण। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह नमक कर में वृद्धि करे और आय कर को कम कर दे अथवा बिलकुल हटा दे। <sup>212</sup> बंगाल चेंबर आफ कामर्स का मत था कि नमक शुल्क को बढ़ाकर आय कर को हटा सकना संभव है। नमक शुल्क में वृद्धि से बंगाल चेंबर के अनुसार कृषक तथा श्रमिक वर्गों की वार्षिक आय में बहुत थोड़ी कटौती होनी थी। <sup>213</sup> जैसा कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया, इस समस्या के बारे में उपर्युक्त दृष्टिकोण वर्ग हितों से बहुत अधिक प्रभावित था। 'यह कराधान मुक्त वर्ग पर से एक बहुत हलके कर को हटाकर एक ऐसे अन्य वर्ग पर डालने का प्रस्ताव था जिस पर पहले से ही यदि असह्य भार नहीं तो, प्रचलित वितरण को देखते हुए, सार्वजनिक भार के न्यायोचित अंश से कहीं अधिक भार था।' <sup>214</sup> रिचर्ड टैपिल ने लिखा कि 'मैं एक क्षीर तो संपूर्ण भारत के संपन्न लोगों को प्रभावित करने वाले आय कर और (दूसरी ओर) निर्धन लोगों को प्रभावित करने वाले नमक कर में कोई वास्तविकता अथवा न्यायोचित संबंध नहीं देख पाता हूँ "संपूर्ण भारत के संपन्न आय कर दाताओं को बचाने के लिए बंबई और मद्रास के निर्धन व्यक्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता।' <sup>215</sup>

## V

भारत सरकार द्वारा लगाए गए आय कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों का कुछ राजस्व में बहुत थोड़ा अनुपात (5 प्रतिशत से भी कम) था। तथापि आय कर नीति श्रद्धांश में एक दिलचस्पी की चीज थी क्योंकि यह कर इस देश में एक अग्रगण्य था। इसके अलावा आय कर संबंधी प्रश्न के साथ महत्वपूर्ण राजकोपीय तथा आर्थिक नीति का उल्लंघन था।

जब जेम्स विलसन भारत आया तो अधिकारी प्रत्यक्ष करों के विचार के पक्ष में थे। मद्रास के लाइसेंस कर मोहलुरफा के अलावा अन्य राजस्व का भी ध्यान था। पिछले कुछ वर्षों से लाइसेंस कर की चर्चा चल रही थी। ई. जे. जे. 1859 के हेनरी हेरिंगटन ने भारत में व्यापार करने तथा विभिन्न राजस्वों के लिए लाइसेंसों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया, जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापारियों को बाहर काफी विरोध हुआ और जब तक जेम्स विलसन भारत नहीं आया तब तक अंतिम और स्वीकृत स्वरूप नहीं ले सका। यह विधेयक अंत में निम्न प्रकार का था—

कर विधेयक 'अब तक ठीक स्वरूप नहीं ले सका है' और विल्सन ने आने पर उसे पूर्ण रूप से रद्द करने और नए सिरे से लाइसेंस कर तथा आय कर से संबंधित दो पृथक् विधेयकों को पेश करने का निर्णय लिया।<sup>216</sup>

विल्सन के लाइसेंस कर विधेयक में दो विशेषताएं थी। प्रथम, यह उस वर्ग के लोगों पर कर था जो अब तक करों से बचे हुए थे। कारीगर, खुदरा व्यापारी, वैकर, लघु उत्पादक, व्यवसायी इत्यादि इसी वर्ग में आते थे। विल्सन का विचार था कि राजस्व का बड़ा अंश भूमि से ही प्राप्त होता था और जो वर्ग ब्रिटिश शासन में स्थापित शांति से आर्थिक लाभ उठा रहे थे, वे राजस्व में अपना पूर्ण अंश नहीं दे रहे थे।<sup>217</sup> लाइसेंस कर लगाने की कल्पना इस प्रकार से की गई थी, कि इसका भार ऐसे वर्गों पर पड़े जो कृषकों के विपरीत किसी भी प्रकार के कर भार से मुक्त थे। जिन पर यह कर लगाया जाना था, उनमें से अधिकांश आय कम होने के कारण, आय कर से मुक्त रहते थे।

द्वितीय, विल्सन ने आरोही कराधान के विचार को अस्वीकार कर दिया। अपने वित्तीय विवरण में उसने स्पष्ट किया कि 'प्रत्येक बड़े छोटे वर्ग के व्यापारियों पर छोटा सा समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाना चाहिए, परंतु इसमें क्रमिक वृद्धि का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।'<sup>218</sup> तीन वर्गों पर यह कर लगाया गया। प्रथम वर्ग में थोक व्यापारी, वैकर, बड़े उत्पादक, तथा व्यवसायी वर्ग के लोग थे जिन पर कर 1॥ रुपया वार्षिक था। दूसरे वर्ग में खुदरा व्यापारी, छोटे उत्पादक जो स्थानीय खुदरा विक्री के लिए माल बनाते थे, आदि थे जिन पर कर की दर 4 रुपया वार्षिक थी। शेष जैसे बुनकर, चमंकार, इत्यादि पर दर 1 रुपया वार्षिक थी। विल्सन ने इस बात के स्पष्टीकरण का ध्यान रखा कि यह आरोही कराधान नहीं था, क्योंकि कर की राशि प्रत्येक वर्ग के सभी लोगों के लिए समान थी, चाहे उनकी आय, अथवा व्यापार या उत्पादन की मात्रा कुछ भी क्यों न हो।

लाइसेंस कर विधेयक परिपद में 4 मार्च, 1860 को पेश किया गया। परंतु इसके प्रथम पठन से लेकर इसके अधिनियमन तक लगभग डेढ़ वर्ष लगा। जुलाई, 1861 में पारित अधिनियम XVIII विल्सन के मूल विधेयक से कई दृष्टियों से भिन्न था। विधेयक के विपरीत लाइसेंस अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से अस्थाई कर लगाया गया। विधान में कर की दरें (विभिन्न अनुसूचित वर्गों के लिए 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया) भी बहुत नीची थी। अपनी योजना के इस अंश के कार्यान्वयन को देखने के लिए विल्सन जीवित नहीं रहा।

आय कर विधेयक, जो लाइसेंस कर विधेयक के साथ ही पेश किया गया था, पारित हो गया और जनता का पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित हो गया। विवाद के प्रश्न ये थे : कराधान योग्य आय की न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए ? क्या आरोही कराधान का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए ? क्या कुछ सुविधाभोगी वर्गों को आय कर से मुक्त रखना चाहिए ? कराधान की रीति कैसी बनाई जानी चाहिए कि वह लोगों को स्वीकार्य हो ? और अंत में, क्या उत्तर संन्य विद्रोह काल की राजनीतिक स्थिति में यह प्रयोग करना उचित था अथवा एंग्लो इंडियन की आलोचना और हिंदुस्तानियों की शत्रुता

का सामना के बजाए इसे स्थागित करना अधिक सुरक्षापूर्ण था ?

कराधेय आय की उचित न्यूनतम सीमा निर्धारित करने में विल्सन को कठिनाई का सामना करना पड़ा। कैनिंग के साथ पत्र व्यवहार से ऐसा लगता है कि पहले उसका विचार था कि 100 रुपये वार्षिक से अधिक आय पर कर लगाया जाना चाहिए। कैनिंग को इस बात में संदेह था कि यह उचित सीमा है। उसने यह मालूम करने के लिए कि यह सीमा किस प्रकार कार्य करेगी, कुछ चुने हुए जिलों का नमूना सर्वेक्षण (सैंपल सर्वे) करने के लिए कहा। उसने विल्सन को लिखा, 'मेरे विचार से आय कर के लिए 100 रुपये जैसी नीची सीमा के पक्ष समर्थन के लिए, जिसके निम्न वर्गों को छोड़ देने का दावा किया गया है, और कर द्वारा लोगों में जाग्रत हो सकने वाली विद्वेष भावना का अनुमान लगाने के लिए यह सूचना आवश्यक है।' <sup>219</sup> अन्त में कैनिंग ने 100 रुपये की सीमा के विरुद्ध अपना निर्णय दे दिया, और विल्सन द्वारा वित्तीय विवरण पेश करने के एक सप्ताह पहले कैनिंग ने सुझाव दिया कि 200 रुपये की सीमा ठीक रहेगी और 'कराधान की दृष्टि से प्रभावोत्पादक होगी।' <sup>220</sup> विल्सन ने अपने वित्तीय विवरण (18 फरवरी, 1860) में घोषणा की कि 200 रुपये से कम वार्षिक आय कर मुक्त होगी। आय कर विधेयक जब 4 मार्च, 1860 को विधान परिषद में पेश किया गया तो इस आधार पर कि 200 रुपये की न्यूनतम सीमा बहुत नीची है इसका व्यापक विरोध हुआ। सर सी० वुड ने पहले से ही भारत सरकार को चेतावनी दी थी कि 'बहुत कम आय पर कर लगाने के विषय में सावधान रहना चाहिए। प्रस्तावित योजना के आधार पर निचले वर्गों पर, जिनमें अनायुक्त (नान कमीशंड) यूरोपीय अफसर, तथा सेना और पुलिस के हिंदुस्तानी अफसर भी सम्मिलित थे, कराधान की व्यवस्था होगी। मुझे आशंका है कि जो कर इन वर्गों तक लाया गया है, उसे इतना नीचे ले जाया जाएगा, जितना सही नीति की दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं है।' <sup>221</sup> वुड ने जिन वर्गों का उल्लेख किया था जैसे कि सेना, नी सेना, तथा पुलिस के निचले अधिकारी, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से कर से मुक्त कर दिया गया। यह निर्णय असंतुष्ट अधिकारियों द्वारा 'बैरकों में क्री गई फुसफुसाहट से' प्रभावित था जिसकी ओर कैनिंग का ध्यान संतुष्ट होकर गया। <sup>222</sup> कैनिंग ने विल्सन को सुझाव दिया कि कर से मुक्ति सभी अनायुक्त सैनिकों को दी जानी चाहिए। <sup>223</sup>

लाइमेंस कर की भांति ही आय कर विधेयक में भी आरोही कराधान के विचार को दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया गया। विधेयक के द्वितीय पठन (14 अप्रैल) के समय विधान परिषद के सामने एक याचिका (अर्जी) आई। सरकारी तथा वाणिज्यिक दफ्तरों के क्लर्कों द्वारा भेजी गई इस याचिका में सुझाव दिया गया था कि कराधान के लिए समान दर के स्थान पर आरोही दर (आय के अनुसार 1 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक) होनी चाहिए। जैसी कि आशा की जा सकती थी विल्सन का उत्तर था कि 'लोगों की स्थितियों को समान बनाना' कराधान का उद्देश्य नहीं है। <sup>224</sup> आय कर विधेयक में दो दरों का प्रस्ताव रखा गया था : 500 रुपये से कम वार्षिक आय के लिए 2 प्रतिशत, और इससे अधिक आय के लिए 4 प्रतिशत। परंतु यह आरोही कराधान के समर्थकों के

साथ कोई रियायत नहीं थी। विल्सन ने अपने वित्तीय विवरण में कहा 'ऐसा यदि हम एक ही दर पर करते हैं तो लाइसेंस शुल्क तथा इस (निम्न) वर्ग की आय पर आय कर द्वारा द्वैध कराधान होगा जो दूसरे वर्गों की तुलना में अधिक भारी होगा।' <sup>225</sup>

आय कर विधेयक से एक विवादास्पद प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मह दावा किया गया कि 1793 के स्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार, किसी भी रूप में कराधान क्यों न हो, मुक्ति पाने के अधिकारी हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, जिसमें जमींदारों के हितों की प्रधानता थी, भारत मंत्री तथा भारत सरकार को भेजी गई याचिकाओं (अर्जियों) में उपर्युक्त विचार रखा। <sup>226</sup> परंतु भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और भारत मंत्री ने भारत सरकार की इस कार्रवाई पर अपनी सहमति दे दी। <sup>227</sup> विल्सन ने कहा कि स्थाई बंदोबस्त के संस्थापक कानूनालिस को मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त और जमींदार पर कर लगने के संबंध में दायित्व के बीच कोई भ्रांति नहीं थी। <sup>228</sup> विल्सन ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जब इंग्लैंड में पिट ने प्रथम बार आय कर लगाया तो यह निर्णय हुआ था कि पूजा निवेशक (फंड होल्डर) को कर से मुक्ति देने के पक्ष में कोई आधार नहीं था। उस स्थिति में भी कर मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता जब मालगुजारी को एक निश्चित कर में रूपांतरित कर दिया गया हो अथवा उसका परिशोधन हो गया हो। 'जमींदारों के दावों' के विरुद्ध विल्सन का तर्क और अधिक सबल हो गया जब उसे जमींदारों में से ही एक मित्र मिल गया। वह था बंदेवान का महाराजा जिसने विल्सन की 'कराधान की सराहनीय प्रणाली' का समर्थन किया। अपने को उन लोगों से अलग करते हुए जो आय कर का विरोध कर रहे थे उसने लिखा, 'यह विरोध इस गलत मान्यता पर आधारित है कि यह स्थाई बंदोबस्त का उल्लंघन (है)।' <sup>229</sup> सर चार्ल्स वुड तथा जेम्स विल्सन ने इस पत्र को विशेष महत्व दिया, यद्यपि यह जमींदार वर्ग के सामान्य मत का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता था। <sup>230</sup>

जमींदार तथा मध्यवर्ती वर्ग प्रभावशाली थे। कैनिंग ने विल्सन को लिखा कि 'हम' शहरों को लाइसेंस कर से तंग करने ही वाले हैं। इसलिए हमें इस बात में दुगुना सावधान होना चाहिए कि न केवल बड़े पैमाने पर कृषक ही अपितु जिनका कृषकों से थोड़ा ऊंचा होने के कारण अपने गांवों में काफी प्रभाव है, उनमें भी हमारे विरुद्ध हो जाने की प्रवृत्ति न उभर आए।' <sup>231</sup> विल्सन ने कर का ऐसा स्वरूप खोजने का प्रयास किया जिससे भारतीय संवेदनशीलता को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे। यह आशंका थी कि हिंदुस्तानी लोग 'खोजी कार्यवाही' का विरोध करेंगे। इंग्लैंड के अधिनियम की भांति ही विल्सन के विधेयक में गोपनीयता के पक्ष में नियंत्रण लगाए गए, अधिकारियों के लिए गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक कर दिया गया, और एक विशेष आयोग की व्यवस्था की गई जिसके पास करदाता कर निर्धारण के लिए आवेदन भेज सकते थे। सरकार कर की व्यावहारिक कार्य प्रणाली को पंचायतों तथा 'कस्बों और व्यवसायों के मुखिया लोगों' की सहायता से निश्चित स्वरूप देना चाहती थी। वार्षिक कर निर्धारण से होने वाली घीस को दूर करने के लिए कमिशनरों को अधिकार था कि वे पूरे पांच वर्षों के लिए एक मोटी राशि निर्धारित कर सकेंगे। अधिनियम के इन उपबंधों के अतिरिक्त आय कर का

प्रबंध, निर्धारण एवं संग्रह करने वाले कमिश्नरों को दिए गए आदेशों में 'खीझ उत्पन्न करने वाले परीक्षणों, अमुविधाजनक रहस्योद्घाटनों तथा परिणामी भ्रष्टाचारों' के विषय में प्रचलित आशंका को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।<sup>232</sup> चार्ल्स वुड ने विल्सन को 'अप्रिय चीज को इतना कम अप्रिय' बनाने में मिली सफलता के लिए बधाई दी।<sup>233</sup> विल्सन को संभवतः मालूम था कि इस नए कर के विरोध में सबसे अधिक रोप बैंकरों में होगा, परंतु उसे पूर्ण विश्वास था कि 'भारत में बड़े पूजीपति बैंकरों के प्रति जितनी ही कम सहानुभूति थी जितनी कम सहानुभूति लंदन में लॉन्ग स्ट्रीट के लॉन्ग स्ट्रीट यहुदियों के प्रति उस समय थी जब उन्हें राज्य की आर्थिक योगदान करने के लिए बाध्य किया गया था।'<sup>234</sup> बैंकरों और व्यापारियों की सुविधा के लिए आय कर विवरणी के फारम में संशोधन किए गए (जैसा कि विशिष्ट समिति ने जिसके सदस्य है रिगटन, टैपिल तथा प्रसन्न कुमार टैगोर थे, सुझाव दिया था)।<sup>235</sup> परंतु यह उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बंबई से भेजी गई एक याचिका (अर्जी) द्वारा भारतीय बैंकरों की भागी और उनके समर्थन में तर्कों को स्पष्ट किया गया था। याचिका में कहा गया था कि 'एक ओर आय और साख में और दूसरी ओर बकाया दावों और दायित्वों में गहरा संबंध है। बैंकर इस प्रकार की एक दूसरे के विषय में जानकारी रखने के लिए बहुत इच्छुक है।'<sup>236</sup> इस प्रकार की जानकारी यदि प्रकट हो जाए तो इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे बैंक असफल हो सकते हैं। कमकते में भी इस प्रकार की शिकायतें की गई थी। मारवाड़ी व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बंगाल सरकार से मिला और उसने निवेदन किया यदि वे इस तथ्य को कि 'व्यापार में कितना रुपया उनका अपना लगा हुआ है और कितना दूसरों का है' प्रकट कर दें तो इससे उनकी साख में कमी होगी।<sup>237</sup> आय कर आयोग के अध्यक्ष श्री ए० प्रोट ने स्वीकार किया कि 'उनकी (मारवाड़ियों की) कोठियों (व्यापार गृहों) की सस्तेदारियों का स्वरूप बहुत जटिल है' और इनके विषय में सार्वजनिक जांच खतरनाक है।<sup>238</sup> आय कर के विरोध में बंबई के बैंकर तथा व्यापारी उतने मुखर नहीं थे जितने कि जमींदार। उनकी आत्मरक्षण की विचक्षण तथा अनैतिक रीतियां थीं। बंबई के बैंकरों ने अपनी याचिका में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'स्वार्थी प्रयोजनों से प्रेरित होकर लोग आगे झूठे लेखे रखना सीख लेंगे'।<sup>239</sup>

भारत की लगभग 13 करोड़ जनसंख्या में से विल्सन के आय कर के अंतर्गत 1,000 रुपये अथवा इससे अधिक आय वाली 53,000, 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में आय वाली 1,41,500, तथा 200 रुपये से 500 रुपये तक आय वाली 5 लाख विवरणियां थी। बंगाल की 4 करोड़ जनसंख्या में केवल 21,000 व्यक्तियों की आय 1,000 रुपये के ऊपर थी। यह तर्क दिया जा सकता था कि भारत जैसे निर्धन देश में यदि आय कर की बाध्यता का कम आय वाले वर्गों पर विस्तार होता तो उसका उन पर बहुत अधिक भार पड़ता और यदि इसे ऊंची आय पाने वालों के एक छोटे से वर्ग तक सीमित रखा जाता तो, कर के संग्रह एवं निर्धारण की लागत को देखते हुए, वह अलाभकारी था।<sup>240</sup>

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि 200 रुपये से 500 रुपये तक वार्षिक

आय पर कराधान २ प्रतिशत और 500 रुपये से अधिक आय होने पर 4 प्रतिशत या और इस सीमा के ऊपर आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। शीघ्र ही यह अनुभव हुआ कि 200 रुपये जितनी कम आय पर कर लगाना निरर्थक था क्योंकि संग्रह पर होने वाला खर्च कर से प्राप्ति के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त थोड़ी आय पर कर लगाने पर अपवंचन की संभावना अधिक थी। आय कर देने वालों में दो तिहाई इसी श्रेणी (अर्थात् 200 से 500 रुपये के आय वर्ग) में थे और इस कर से कुल प्राप्ति में उनका योगदान केवल 20 प्रतिशत था। करदाताओं के निम्न वर्ग को इस कर से मुक्त कर देने का सरकार का निर्णय इन्हीं बातों से प्रभावित था और कर की दर भी घटाकर 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत कर दी गई।<sup>241</sup> यह निर्णय सेमुअल लैंग के अनुरोध पर लिया गया। उसे सभी समस्याओं के वित्तीय समाधान के निमित्त आय कर की क्षमता के बारे में सदैव ही संदेह था। विल्सन (जिसकी कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी) द्वारा बनाए गए आय कर विधान के लागू हो जाने के कुछ समय बाद ही अपने 1861-62 के वित्त विवरण में सेमुअल लैंग ने कहा कि आय कर से उतने अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है जितनी कि विल्सन को आशा थी।<sup>242</sup> अगले वर्ष लैंग ने 200 रुपये से 500 रुपये तक के आय वर्ग को आय कर से मुक्त कर दिया। उसका उत्तराधिकारी सर चार्ल्स ट्रिबोलियन आय कर का सदैव ही कटु आलोचक रहा और 1860 में जेम्स विल्सन के साथ उसके विवाद का यह भी एक विषय था जिसके परिणामस्वरूप उसे भारत से वापस बुला लिया गया था। उसे कुछ समय तक अपयश भी मिला। ट्रिबोलियन ने पहले तो दर में कमी कर दी<sup>243</sup> और तत्पश्चात् 1864-65 के वित्त विवरण में भारत सरकार के इस दृढ़ निश्चय की घोषणा की कि पांच वर्ष बाद आय कर समाप्त कर दिया जाएगा।<sup>244</sup> सरकार के कुछ सदस्य और कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी इस योजना के पक्ष में नहीं थे। वास्तविकता यह है कि गवर्नर जनरल लार्ड लारेंस को इस बारे में संदेह था कि सरकार वास्तव में राजस्व के इस स्रोत को छोड़ सकने की स्थिति में है।<sup>245</sup> सर वार्टन फ़ोर ने एक बहुत सीधा-सादा तर्क दिया (इस सामान्य राय के विपरीत कि विल्सन का आय कर केवल पांच वर्षों के लिए ही लगाया गया था) कि 3 प्रतिशत कर 5 वर्ष की अल्प अवधि के लिए लगाया गया था और इस अवधि की समाप्ति के बाद 1 प्रतिशत स्थाई रूप से रहना था और उसे स्थानीय लोक निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना था।<sup>246</sup> परंतु स्थाई आय कर के समर्थक भी प्रत्यक्ष कराधान के विरुद्ध जनसाधारण की भावना की शक्ति और इस प्रकार के कराधान से जुड़े दोषों, जैसे खोजी जाच-पड़ताल तथा मनमाने कर निर्धारण की उपेक्षा नहीं कर सके। अतः कर को 29 जुलाई, 1865 को समाप्त हो जाने दिया गया। पांच वर्षों में आय कर व प्राप्त होने वाली कुल राशि लगभग 8 करोड़ रुपये थी और संग्रह की स्थापन व्यवस्था का खर्च निकाल देने पर कर से शुद्ध प्राप्ति 7.5 करोड़ रुपये थी।

आय कर का एक दोष यह था कि इसके निर्धारण की प्रणाली अक्षम थी। 1869 अधिनियम में वार्षिक कर निर्धारण की व्यवस्था की गई थी। परंतु कर लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही एक अन्य अधिनियम पारित करके गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे

दिया गया कि वह पहले वर्ष के कर निर्धारणों को अगले एक वर्ष के लिए भी उपयोग कर सकता है। मई, 1862 में उसके इस अधिकार की अवधि 1 से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई। कर निर्धारण की प्रक्रिया बहुत अधिक कष्टप्रद थी, इसलिए उपर्युक्त निर्णय लेना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया।<sup>247</sup> परिणाम यह हुआ कि 1865 में भी करदाताओं ने पुराने निर्धारण के आधार पर ही कर दिए, जबकि ये निर्धारण हर दृष्टि से पुराने होकर अर्थ-हीन बन गए थे।<sup>248</sup>

प्रथम भारतीय आय कर के अनुभव से स्पष्ट हो गया कि कुछ अधिकारियों और समाचार पत्रों की अशुभ भविष्यवाणी के विपरीत भारत में प्रत्यक्ष कराधान असंभव नहीं था। साथ ही, अनुभव द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि आय कर के विरुद्ध लोकमत इतना प्रबल था कि असाधारण परिस्थितियों के अलावा इस उपाय का सहारा लेना अबुद्धिमत्तापूर्ण था। इसके अलावा आय कर के कुशल निर्धारण एवं संग्रह के लिए वुनियादी प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता थी। सरकार का विश्वास था<sup>249</sup> कि जनसाधारण की कर विरोधी प्रतिक्रिया कर के सहज रूप के कारण न होकर अल्प वेतन भोगी उन निम्नवर्गीय हिंदुस्तानी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार<sup>250</sup> के विरुद्ध थी जो, अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए, अतिश्रमी ब्रिटिश अधिकारियों के अपर्याप्त निरीक्षण में कर प्रशासन का कार्य संभालते थे। समाचार पत्र आय कर के विरुद्ध थे। अखबारों में वाणिज्यिक, व्यावसायिक तथा संपत्तिवान वर्गों के विचारों के अनुरूप लिखा जाता था। इन वर्गों पर पहली बार प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत कराधान की ऊँची दर रखी गई थी।<sup>251</sup> यह वर्ग कर के विरुद्ध सबसे अधिक मुखर था। विशेष रूप से नीची आय वाले वर्ग (200 रुपये से 500 रुपये तक की आय वाले वर्ग) को कर से मुक्त कर देने के बाद अधिकांश व्यक्ति आय कर की पहुँच से बाहर ही थे।

आय कर के कुछ भी दोष क्यों न रहे हों, यह बहुत स्पष्ट था कि सरकार के लिए किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष कर लगाए बिना घाटे को पूरा कर सकना संभव नहीं था। सरकार ने अनुभव किया कि उसके लिए लाइसेंस कर (1867) तथा सर्टिफिकेट कर (1868) के रूप में प्रत्यक्ष कर लगाना और अंत में पुनः आय कर (1869) लगाना आवश्यक था। आय कर के अंतिम वर्ष में वित्त सदस्य ने कहा था कि 'इस (आय कर को) देश की महान वित्तीय आरक्षित निधि के रूप में लिया जाना चाहिए, और अब इसे पूरी तैयारी के साथ सहज ही उपलब्ध हो सकने की स्थिति में रखा जाएगा जिससे जब भी कोई नई संकटकालीन स्थिति पैदा हो तो इसे लगाया जा सके।'<sup>252</sup>

विभिन्न निर्धारित करों जैसे आय कर, लाइसेंस कर तथा सर्टिफिकेट कर से सरकार को बहुत थोड़े राजस्व की प्राप्ति हुई।



निर्धारित करों द्वारा प्राप्त राजस्व  
1858-59 से 1872-73 तक

वर्ष प्रारंभ	राशि (लाख रुपयों में)
1858 मोहतुरफा	1.1
1859        "          "	2.2
1860 आय कर (1860 का अधिनियम XXXII) दर 3 प्रतिशत	11.0
1861 आय कर (1860 का अधिनियम XXXII तथा 1861 का अधिनियम XVIII) दर 3 प्रतिशत तथा लाइसेंस कर	20.5
1862 आय कर (1860 का अधिनियम XXXII) दर 3 प्रतिशत	18.8
1863 आय कर (1863 का अधिनियम XXVII) दर 2 प्रतिशत	14.8
1864        "          "	12.8
1865        "          "	6.9
1866 आय कर निरस्त कर दिया गया	0.2
1867 लाइसेंस कर (1867 का अधिनियम XXI) (क)	6.5
1868 लाइसेंस कर (1868 का अधिनियम IX) (ख)	5.1
1869 आरोही आय कर (1869 का अधिनियम IX) (ग)	11.1
1870 आय कर (1870 का अधिनियम XVI) (घ) रुपये में 6 पाई	20.7
1871 आय कर (1871 का अधिनियम XII) (ङ) रुपये में 2 पाई (क) 200 रुपये न्यूनतम (ख) 500 रुपये न्यूनतम (ग) 500 रुपये न्यूनतम, 1 प्रतिशत वेतन पर, उसके ऊपर 2½ प्रतिशत हो जाता था (घ) 600 रुपये न्यूनतम, रुपये में 6 पाई (ङ) 750 रुपये न्यूनतम	8.2

निर्धारित करों से बहुत थोड़े राजस्व की प्राप्ति के अतिरिक्त तथ्य ध्यान आकर्षित करता है वह है कर के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होना। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस काल में अन्वेषित विभिन्न करों से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थी।

यद्यपि सरकार ने आरोही कराधान का सिद्धांत दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया था, तथापि न्यायमंगल कराधान के सिद्धांतों की पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकी। सरकार ने जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम आय को कर मुक्त रखने का सिद्धांत स्वीकार किया था। विल्सन के 1860 के अधिनियम (XXXII) के अंतर्गत न्यूनतम आय जिस पर कर लगाया गया था, 200 रुपये थी। लैंग ने 500 रुपये से कम आय को कर मुक्त कर दिया था (1862)। उसने पाया था कि 1861-62 में लगभग 6 लाख व्यक्तियों पर जिनकी आय 200 रुपये से 500 रुपये तक थी, कर निर्धारित हुआ था और इस वर्ग से कुल प्राप्ति केवल 35 लाख रुपये थी जिसमें से कम से कम 10 लाख रुपया कर संग्रह की लागत के रूप में व्यय हो गया। कर संग्रह की भारी लागत और कम आय वाले बड़े वर्ग पर कर निर्धारण से थोड़ी प्राप्ति के प्रशासनिक आधार थे जिनके कारण 200 रुपये वार्षिक से कम आय वाले व्यक्तियों को कर मुक्त रखना ही उपयुक्त था। बाद के निर्धारित करों में (1867 के लाइसेंस शुल्क को छोड़ कर) कोई भी कर 500 रुपये से कम आय वाले वर्ग पर नहीं लगाया गया। 1870 में (1870 के अधिनियम XVI द्वारा) इस सीमा को ऊंचा उठा कर 600 रुपये कर दिया गया और 1871 में (अधिनियम XII द्वारा) इसे पुनः बढ़ा कर 750 रुपये कर दिया गया।

न्यायशीलता के सिद्धांत का यह भी अर्थ था कि वर्ग विशेष के साथ भेद भाव नहीं बरता जाना चाहिए। यही कारण था जिसके आधार पर टैपिल ने (वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक वर्गों पर) लाइसेंस कर को आय कर में समाविष्ट करने का समर्थन किया था।<sup>263</sup> इस संदर्भ में कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन द्वारा भारत मंत्री के पास भेजे गए एक स्मरण पत्र में उनके द्वारा दिए गए एक तर्क पर ध्यान दिया जा सकता है। तर्क था कि 'जो आय कर स्मरण पत्र से प्राप्त होने वाली आय, अस्थिर स्रोतों से होने वाली आय और व्यावसायिक आय पर समान रूप से दबाव डालता है उसे उचित एवं समान कर नहीं कहा जा सकता'। याचिका (अर्जी) में कहा गया था कि यह अनुचित है कि लगान जीवी (राटिया) वर्ग के लिए कर की वही दर है जो कारीगरों और व्यापारियों के लिए है, जबकि अर्थव्यवस्था में लगान जीवी वर्ग का योगदान अल्पतम है।<sup>264</sup> कलकत्ता से भेजे गए एक अन्य स्मरण पत्र में भी यही प्रधान तर्क दिया गया था। स्मरणपत्र में कहा गया था कि श्रम से आय प्राप्त करने वालों पर कर का भार अधिक है, और यह मांग की गई थी कि इस वर्ग और संपत्तिवान वर्ग में कराधान की दृष्टि से भेद किया जाना चाहिए।<sup>265</sup> बंगाल चैंबर आफ कामर्स ने बहुत कुछ इसी आधार पर अपनी वैचारिक स्थिति निर्धारित की थी।<sup>266</sup> परंतु आय के स्रोत के आधार पर विभेदीकरण परंपरागत वित्तीय सिद्धांतों के प्रतिकूल था।

## संदर्भ

1. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण संध्या, 14, 9 जुलाई, 1862 ।
2. वही, 24, 28 मार्च, 1883 ।
3. थोमस देविगटन मैकाले, 'क्रिटिकल एंड हिस्टारिकल एस्सेज', (संदन, 1867) जिल्द I, पृ० 56 ।
4. गृह (राजस्व) कार्यविवरण, सितंबर, 1862, संख्या 29, एम० लैंग का मेमो०, 7 अप्रैल, 1862 ।
5. पूर्वोक्त स्थल ।
6. सर जे० लारेंस द्वारा प्रस्तुत विचार, 6 जुलाई, 1862, ससदीय कागजात, हाऊस आफ लार्ड्स, 1863, जिल्द 22, पत्रक 87, पृ० 187 और आगे ।
7. तुलनीय एरिक स्टोबम, 'दि इंग्लिश यूटीलिटेरियस एंड इंडिया' (आक्सफोर्ड, 1959), पृ० 117 ।
8. आर० सी० दत्त, 'दि पीजेंट्री आफ बंगाल' (कलकत्ता, 1875) ।
9. आर० सी० दत्त से जे० सी० दत्त को (दिनांक नहीं दिया है), जे० एन० गुप्ता 'लाइफ एंड वर्क आफ रमेश चंद्र दत्त' (सी० आई० ई० (सदन, 1911), पृ० 56 ।
10. वही, पृ० 58 । 1884 में जब बंगाल काश्तकारी कानून बनाया जा रहा था तो इसी प्रकार के दबावों का परिणाम यह हुआ कि रमेश चंद्र दत्त के भूधृति धारी (टेम्पोर होल्डर) की स्थिति और उनके अधिकारों में सुधार के विषय में विविध सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया । देखें रमेश दत्त से जे० सी० दत्त को, 16 अक्तूबर, 1884 ए० पी० मैकडोनाल्ड से आर० दत्त को, दिसंबर, 1884, वही, पृ० 101-103 ।
11. जे० एन० गुप्ता पूर्वोद्धृत, पृ० 285-87, 289, 291-92 । देखें क्रोपोटकिन से पत्र, वही, पृ० 285 ।
12. भगवतोप दत्त, 'दि एकोनॉमिकल एंड इकानॉमिक थिंकिंग इन इंडिया' (कलकत्ता, 1962) ।
13. राजस्व कार्यविवरण अप्रैल, 1867, संख्या 20, कलकत्ता ट्रेडिंग एसोसिएशन के मास्टर, सर्जिंट और सदस्यों द्वारा भारत मंत्री को याचिका, (अर्जी) 22 अप्रैल, 1867, वही मार्च, 1867, संख्या 35, कलकत्ता ट्रेडिंग एसोसिएशन द्वारा वामसराय को याचिका, 15 मार्च, 1867 ।
14. राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 1867, संख्या 7, एच० डब्ल्यू० आई० बुड, सचिव, बंगाल बैंक आफ कामर्स से सचिव, गृहविभाग, भारत सरकार, 22 मार्च, 1867 ।
15. बर्दई शहर और द्वीप के 3, 646 हिंदुस्तानी व्यापारियों द्वारा याचिका, 12 अक्तूबर, 1859 'वारेमपाडेंस आन टायरेबट टैक्सेशन' (कलकत्ता, 1882) जिल्द I, पृ० 30 ।
16. देखें, याचिकाएँ कलकत्ता में (1859 व 1867), बर्दई से (17 अक्तूबर, 1859), मद्रास से (22 सितंबर, 1859), अहमदाबाद से (31 अक्तूबर, 1859), वही, I, पृ० 25-33 ।
17. तुलनीय एफ० शहाब 'प्रोग्रेसिव टैक्सेशन' . ए स्टडी इन दि डेवलपमेंट आफ दि प्रोग्रेसिव थिंकिंग इन दि ब्रिटिश इनकम टैक्स' (आक्सफोर्ड, 1953) पृ० 104, 115 और आगे ।
18. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 144, 29 जून, 1860 । फेनवीन से जे० लारेंस को, 3 नवंबर, 1866, भारत मंत्री के पत्र जिल्द III संख्या 39 । मेयो ने आरगाइन को

8 मार्च, 1869, वृत्त 34, सध्या 76 मेयो बागजात ।

19. जे० पी० नियोगी 'एबोन्यूशन आफ इडियन इनकम टैक्स' (सदन, 1929), अध्याय 1, 2 ।
20. जे० एम० मिन से डब्ल्यू० टी० चोर्नटन, 28 जनवरी, 1862 'दि सैटर्स आफ जान स्टुअर्ट मिल' (मपादक एच० एम० आर० इनियट, सदन 1910), जिल्द I, पृ० 258 । जे० एम० मिल से एच० एम० मेन बने, 1 जनवरी, 1869, वही, जिल्द II, पृ० 169 । उन्नीसवीं शताब्दी में उपयोगितावादी अर्थशास्त्रियों का प्रभाव वैसा ही था जैसा कि अठारहवीं शताब्दी में प्रकृतिवादियों का था । वस उसकी व्यापकता अधिक थी । सुसनीय रजीत गुप्ता 'ए स्ल आफ प्रापटी फार बगाल', (पेरिस, 1963) ।
21. बायर्ड रिमथ की रिपोर्टें दिनांक 16 अगस्त, 1861 । पी० पी० एच० सी० जिल्द 40, पत्रक 29, पृ० 301 । गृह कार्यविवरण, 7 अक्तूबर, 1861 । लोक भाषा सध्या 20-26 । लार्ड कैनिंग का शापन दिनांक 3 अक्तूबर, 1861 (के० डब्ल्यू०) जिनमें बायर्ड रिमथ की रिपोर्टें नै पैरा 62-82 की ओर ध्यान आरपित किया गया है । रिपोर्टें में राजस्व के स्थाई बदोयस्त की मिकारिश की गई है ।
22. गृह राजस्व कार्यविवरण, फरवरी, 1862, मध्या 2, मर जी० सुपर, सचिव, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सरकार से डब्ल्यू० प्रे, सचिव, भारत सरकार को, 27 जनवरी, 1862 ।
23. आर० बी० मैंगल्ट द्वारा अग्रहमति का मेमो०, 3 जुलाई, 1862, पी० पी० एच० एल० 1863, जिल्द 22, कालम 87, पृ० 181-86 ।
24. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण, सध्या 14, 9 जुलाई, 1862 ।
25. वही, 2, 31 दिसंबर 1858 ।
26. वही 14, 9 जुलाई, 1862 ।
27. सर जे० लारें द्वारा अभिलिखित विचार, 5 जुलाई, 1862, पी० पी० एच० एल० 1853, जिल्द 22, पत्रक 97, पृ० 187-92 । कैनिंग ने स्थाई बदोयस्त के विषय में बुड को इस आधार पर सिकारिश की कि इसके द्वारा जमींदार ब्रिटिश सरकार के साथ बंध जाएंगे । उसके शब्दों में 'इसका महत्व यूरोपीय सैनिकों की फौज जैसा ही होगा । कैनिंग से बुड को, 8 अक्तूबर, 1861, बुड कागजात, पद । एस० गोपाल, 'ब्रिटिश पालिसी इन इंडिया', 1858-1905 (कैन्नज, 1965) पृ० 11 ।
28. एस० मैमफील्ड, शिंदे के कमिशनर द्वारा रिपोर्टें, सध्या 188, 3 जुलाई, 1863, एच० सी० 1863, जिल्द 43, पत्रक 164, पृ० 617-19 ।
29. गृह राजस्व कार्यविवरण, सितंबर, 1862, सध्या 37, डब्ल्यू० म्योर द्वारा मेमो०, 5 दिसंबर, 1862 ।
30. वही, 29, एस० सैंग द्वारा मेमो०, 7 अप्रैल, 1862 ।
31. वही, 22, सचिव, फोर्ट, सेंट जार्ज की सरकार से भारत सरकार को, 8 फरवरी 1862, वही, सध्या 37 डब्ल्यू० म्योर, वार्ड आफ रेवेन्यू एस० डब्ल्यू० पी० का मेमो०, 3 दिसंबर, 1861 ।
32. टी० जे० होवेलथॉर्न 'दि कपनी एंड दि फ्राउन' (सदन, 1866) पृ० 239 ।
33. एडवर्ड वेस्ट 'एमीग्रेशन टु ब्रिटिश इंडिया' : 'प्राफिटेबल इन्वेस्टमेंट फार ज्वाइंट स्टॉक कपनीज एंड फार एमीग्रेंट्स हू पजैस कैपिटल' (सदन, 1857) । ई० जी० वेकफील्ड के उपनिवेशीकरण

के माध्यम से विकास सबधी कार्यक्रम के प्रभाव के लिए देखें, ब्रिसे बामन, 'माइग्रेशन एंड इनामिक डेवलपमेंट' (केंब्रिज, 1954), पृ० 1-14 ।

34. पैट्रोलिएम के स्रोतों के उपयोग के विषय में योजनाओं के प्रारम्भिक उल्लेखों में से एक में से द्वारा आरणाइन को लिखे गए पत्र में भी है, पत्र का दिनांक 8 अगस्त, 1869 । मेमो बागमत बटल 36, सध्या 192 ।
35. कोर्ट आफ डायरेक्टर्स से भारत सरकार को, सध्या 6. 6 मई, 1857 ।
36. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण सध्या 2, 31 दिसम्बर, 1858 ।
37. 'एनुअल रिपोर्ट्स आफ काउन्सिलर्स एमोसिएशन,' सध्या 2, 1859 और सध्या 5, मिनवर, 1862 । आइजक यादग, 'दि आरिजिन एंड प्रोग्रेस आफ दि काउन्सिलर्स एमोसिएशन,' (मैनचेस्टर, 1871) पृ० 119, 125, 131 ।
38. गृह राजस्व कार्यविवरण, 6 जुलाई, 1861, सध्या 7, सचिव, काउन्सिलर्स एमोसिएशन से सचिव, भारत सरकार को, 15 मई 1861 ।
39. गृह राजस्व कार्यविवरण, 9 दिसम्बर, 1861, सध्या 2, ठीक वही, 3 सितम्बर, 1861 ।
40. सुरमीपुर टी कंपनी, कछार के संचालकों द्वारा स्मरण पत्र, 9 फरवरी, 1861; इडिंगो प्लांटर्स एसोसिएशन 20 नवम्बर, 1860, काफी प्लांटर्स आफ कुर्ग, 25 जून, 1862; पी० पी० एच० एल० 1863, जिल्द 22, पन्ना 87, पृ० 160-61, वही पृ० 162 । जेड होल्डर्स एंड कमिशियर्स एसोसिएशन द्वारा स्मरण पत्र, 31 मई, 1861 ।
41. गृह राजस्व कार्यविवरण 28 फरवरी, 1861, सध्या 26 । भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, वही अगस्त, 1862, सध्या 12-15 ।
- 41 ए. गृह राजस्व कार्यविवरण, 26 जुलाई, 1861, सध्या 2 । 'आर० थापसन, वाई आफ रेवेन्यू से सचिव, बंगाल सरकार को, 31 मई, 1861 ।
42. गृह राजस्व कार्यविवरण, 1 अक्तूबर, 1861, सध्या 1, पी० साइर्स की रिपोर्ट, 1 मिनवर, 1861 ।
43. गृह राजस्व कार्यविवरण, फरवरी, 1862, सध्या 2, सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार से सचिव, भारत सरकार 27 जनवरी, 1862 ।
44. वही ।
45. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण, सध्या 14, 9 जुलाई, 1862 ।
46. एडवर्ड वेस्ट, 'एमीग्रेशन टु ब्रिटिश इंडिया' (मदन, 1857) ।
47. ववई के गवर्नर द्वारा मेमो०, 23 फरवरी, 1860 । पी० पी० एच० एल० 1863, जिल्द 22, पन्ना 87, पृ० 32 ।
48. गृह राजस्व कार्यविवरण, 1 अक्तूबर, 1861, सध्या 1, पी० साइर्स, कमिश्नर द्वारा कपास की खेती के विषय में रिपोर्ट, 1 सितम्बर, 1861 ।
49. गृह राजस्व कार्यविवरण, सितम्बर, 1862, सध्या 28 । सी० बीडन द्वारा मेमो०, 13 मार्च, 1862 ।
50. गृह राजस्व कार्यविवरण, फरवरी, 1862, सध्या 2 । सर जी० कूपर, सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार से डब्ल्यू० ब्रे, सचिव, भारत सरकार को, 27 जनवरी, 1862 ।

51. गृह राजस्व कार्यविवरण, सितंबर, 1862, मध्या 37 । डब्ल्यू म्योर द्वारा कार्यवृत्त, 5 दिसंबर, 1861 ।
52. वही ।
53. गृह राजस्व कार्यविवरण, सितंबर, 1862, मध्या 24 । ई० पाल्टवी द्वारा मेमो०, 24 दिसंबर, 1861, और मध्या 22, सचिव, फोर्ट सेंट जार्ज की सरकार से डब्ल्यू० ये, सचिव, भारत सरकार को, 8 फरवरी, 1862 ।
54. गृह राजस्व कार्यविवरण, सितंबर, 1862, सध्या 29 । एम० लैंग द्वारा मेमो० 7 अप्रैल, 1862 ।
55. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण सध्या 14, 9 जुलाई, 1862 ।
56. सी० बुड से जे० सार्रेम को, 15 अक्तूबर, 1864, सार्रेम कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द I, सध्या 55 ।
57. सी० बुड से जे० सार्रेम को, 12 अगस्त, 1865, वही जिल्द II, सध्या 43 ।
58. फ्रेनबोर्न से सार्रेम को, 3 नवंबर, 1866, सार्रेम कागजात, भारत मंत्री को पत्र, जिल्द III, सध्या 39 ।
59. सार्रेम से सी० बुड को, 4 फरवरी, 1865, सार्रेम कागजात, भारत मंत्री की पत्र, जिल्द IV, सध्या 45 ।
60. मेयो से आरगाहल को, 2 जून, 1871, मेयो कागजात, बडल 43, सध्या 125 ।
61. पूर्वोक्त स्थल ।
62. मेयो से बी० फेर को, 3 जून, 1870, बडल 39, मेयो कागजात, सध्या 156 ।
63. आरगाहल से मेयो को, 28 अप्रैल, 1871 । मेयो कागजात, बडल 49, सध्या 9 । मूल में तिरछे टाइट हैं ।
64. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण, सध्या 14, 9 जुलाई, 1863 ।
65. गृह राजस्व कार्यविवरण, सितंबर, 1862, सध्या 28, सी० बीडन द्वारा मेमो०, 13 मार्च, 1862 ।
66. भारत मंत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण, सध्या 11, 24 मार्च, 1865 ।
67. वही, 17, 17 मार्च, 1866 ।
68. वही, 29 20 नवंबर 1866 ।
69. वही, 15, 23 मार्च, 1867 ।
70. वही, 7, 26 मई, 1871 ।
71. वही, 24, 28 मार्च, 1883 ।
72. वही, 26, 27 जुलाई, 1871 ।
73. वही, 14, 9 जुलाई, 1862 ।
74. पूर्वोक्त स्थल ।
75. फ्रेनबोर्न से सार्रेम को, 2 जनवरी, 1867, सार्रेम कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द IV, सध्या 2 ।
- 75-ए हाउस आफ कामंस में 14 फरवरी, 1859 के अपने वित्तीय विवरण में लार्ड स्टैनले में 1800

से 1859 तक की अवधि के अफ़ीम राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। देखें, 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 'रिलेटिंग टु इंडिया'—रिप्रिंटेड फ़ॉर्म हसार्दम पालियामेन्टरी डिबेट्स' (कलकत्ता, 1871) पृ० 136-37। सकल अफ़ीम राजस्व 1810 में 9,35,996 पौंड, 1820 में 14,36,432 पौंड, 1830 में 12,53,895 पौंड, 1840 में 13,41,093 पौंड तथा 1850 में 35,58,094 पौंड था।

76. सेसिल बीडन का प्रवर समिति (1871) के सामने साक्ष्य, प्रश्न 3138, 3199 (पटना एजेंसी) में बिहार के सभी जिले और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से शामिल थे। बनारस एजेंसी में बनारस और इलाहाबाद डिवीजन तथा अवध आते थे।
77. वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1864, लेखा शाखा, सख्या 105, परिशिष्ट ए। एम० एच० फास्टर तथा एच० डब्ल्यू० ह्विफ़िन की रिपोर्ट (7 सितंबर, 1864), पृ० 22।
78. जे० स्ट्रैची व आर० स्ट्रैची पूर्वोद्धृत, पृ० 242।
79. वित्त कार्यविवरण, सितंबर, 1871, पृथक राजस्व सख्या 11, अफ़ीम विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के औचित्य पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट।
80. गृह कार्यविवरण, 21 अक्तूबर, 1861, पृथक राजस्व सख्या 3, ई० एच० लॉसिंगटन, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, 12 सितंबर, 1861।
81. गृह कार्यविवरण, 1 जुलाई, 1861, पृथक राजस्व सख्या 1, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, भारत सरकार को, गृह विभाग, 25 जून, 1861। वही सख्या 4। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव, 29 जून, 1861।
82. वित्त कार्यविवरण, लेखा शाखा, मार्च, 1860, सख्या 4, वित्त सचिव, भारत सरकार से सचिव, बंगाल सरकार को, 7 मार्च, 1860।
83. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व 1 जुलाई, 1871, सख्या 1, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, भारत सरकार को, 25 जून, 1861।
84. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व सख्या 2, अफ़ीम एजेंट बिहार से सचिव, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, निम्नलिखित प्रांत, 15 फरवरी, 1861। बंगाल में पोस्ट की खेती के अंतर्गत 1857-58 में 3,44,650 बीघा, 1858-59 में 3,41,498 बीघा, 1859-60 में 3,12,707 बीघा और 1860-61 में 2,81,126 बीघा भूमि थी।
85. विधान परिषद कार्यविवरण (सारांश) 1865, जिल्ड IV (नई सीरीज), पृ० 164।
86. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, 27 जुलाई, 1860, सख्या 28, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, भारत सरकार (गृह) को, 14 जुलाई, 1860। सर राबर्ट हैमिल्टन से सचिव, भारत सरकार को, सख्या 460, 4 अक्तूबर, 1858; अफ़ीम के संबंध में सर आर० हैमिल्टन की टिप्पणी, 13 दिसंबर, 1858।
87. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, 27 जुलाई, 1860, सख्या 58, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव भारत सरकार (गृह) को, 14 जुलाई, 1860।
88. पूर्वोक्त स्थल।
89. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, सख्या 29, ए० ईडन, कार्यवाहक सचिव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सचिव, बंगाल सरकार को, 21 नवंबर, 1859।

90 पूर्वोक्त स्थान ।

91. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व 15 मितवर, 1860 । आर० एन० फरवैहर्सेन । बिहार के अफीम एजेंट से सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू, निचले प्रांत को, 14 अप्रैल, 1859 ।

92. प्रवर समिति (1871) के मामले सी० बीडन का साक्ष्य, प्रश्न 3414-18 ।

93. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 15 मितवर, 1880 । बिहार के अफीम एजेंट से सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू, निचले प्रांत को, 14 अप्रैल, 1859 ।

94. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, 27 जुलाई, 1860 । सख्या 29, सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू से सचिव, बंगाल सरकार को, 21 नवंबर, 1859 ।

95. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, सख्या 26 । जे० जी० पछे, अवर उप अफीम एजेंट, मौलीगज से अफीम एजेंट, बिहार को, 10 मार्च, 1859 ।

96. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 15 मितवर, 1860, सख्या 23 । आर० किंग, अवर उप अफीम एजेंट, पटना से अफीम एजेंट बिहार को, 10 मार्च, 1859 ।

97. पूर्वोक्त स्थान ।

98. प्रवर समिति (1971) के मामले सर आर० हैमिल्टन का साक्ष्य, प्रश्न 5008-24 ।

99. सर सी० बीडन का साक्ष्य, पूर्वोक्त, प्रश्न 3314-21, 3516-34, 3573-75 । सर एफ० हालीडे का साक्ष्य, पूर्वोक्त, प्रश्न 5125-32, 5290-92 ।

100. प्रवर समिति (1861) के मामले आर० एन० हैमिल्टन का साक्ष्य प्रश्न 4889-4909, 4886-87, 4898-4903 ।

101. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 4 जून, 1860, सख्या 4, सचिव, बंबई सरकार से सचिव, भारत सरकार (गृह) को 16 मई, 1860 ।

102. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 4 जून, 1860, सख्या 8, सचिव (गृह), भारत सरकार से सचिव, बंबई सरकार को, 4 जून, 1860 ।

103. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 4 जून, 1860, सख्या 1, भारत सरकार से बंबई सरकार को, 10 मई, 1860 ।

104. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 14 सितंबर, 1860, सख्या 18, डेविड सेसून एंड कंपनी तथा दूसरे अफीम व्यापारियों से सपरिषद गवर्नर बंबई को, स्मरणपत्र, 15 अगस्त, 1860 ।

105. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 22 अक्तूबर, 1861, सख्या 11 । भारत सरकार से बंबई सरकार को तार, 22 अगस्त, 1861 । गृह कार्य विवरण पृथक राजस्व, अप्रैल, 1861, सख्या 1-3 ।

106. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, अक्तूबर 1861, सख्या 10 । भारत सरकार के एजेंट से नमक व अफीम कमिशनर बंबई को, 8 जुलाई, 1861 व 11 जुलाई, 1861 ।

107. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 22 अक्तूबर, 1861, सख्या 10 । फोर्क्स एंड कंपनी से सीमा शुल्क कमिशनर को, 17 जुलाई, 1861, सख्या 16 । डी० सेसून एंड कंपनी तथा बंबई के दूसरे अफीम के व्यापारियों से बंबई के गवर्नर सर सी० आर० बलकं को, 16 सितंबर, 1861 ।

108. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, अक्तूबर, 1861, सख्या 17 । सचिव, भारत सरकार से



सचिव, बंबई सरकार को, 22 अक्तूबर, 1861 ।

109. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 144, 22 जून, 1860 ।
110. देखें, जे स्ट्रैची व आर० स्ट्रैची, पूर्वोद्धृत, पृ० 240 ।
111. विधान परिषद कार्यविवरण (माराश) 1870, जिल्द IX (नई सीरीज), पृ० 207 ।
112. वही, 1866, जिल्द V (नई सीरीज), पृ० 133 ।
113. वित्त कार्यविवरण मई, 1871, पुष्पक राजस्व सख्या 16 । मेजर जनरल एच० डी० ईतो, गृह विभाग, सरकार (4 अप्रैल, 1871) ।
114. पूर्वोक्त स्थल ।
115. विधान परिषद कार्य विवरण (माराश) 1868, जिल्द VII (नई सीरीज), पृ० 149 ।
116. जे० स्ट्रैची व आर० स्ट्रैची, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 245 ।
117. नोर्थकोट से जे० सारेम को, 26 मार्च, 1868 । (सारेम कागजात, भारत मंत्री से सारेम को पत्नी की जिल्द V, सख्या 15) । और भी, नार्थकोट से सारेम को, 8 मई, 1868 (पूर्वोक्त स्थल सख्या 23) और 30 सितंबर, 1868 (पूर्वोक्त स्थल सख्या 47) ।
118. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 245, 22 सितंबर, 1868 ।
119. वित्त कार्यविवरण सितंबर, 1868, मेधा शाखा सख्या 166-85 । अफीम आरक्षित निधि के संबंध में भारत सरकार के विचार ।
120. वित्त कार्यविवरण सितंबर, 1868, मेधा शाखा सख्या 163 । एच० एम० इयूरेट व मेमो० (17 अगस्त, 1868) । वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 1858 पुष्पक राजस्व सख्या 32 । इन्स्प० आर० मैसफील्ड का मेमो० (28 अगस्त, 1868) ।
121. प्रवर समिति (1871) के सामने सर सी० बीडन का साक्ष्य पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पृष्ठ 263, प्रश्न 3240-45, 3253-69 ।
122. जे० स्ट्रैची व आर० स्ट्रैची, पूर्वोद्धृत, पृ० 245-47 ।
123. विधान परिषद कार्यविवरण 1869, जिल्द VIII, पृ० 119 ।
124. वित्त कार्य विवरण अप्रैल, 1868, पुष्पक राजस्व सख्या 6 । मैगसे बार्डहैन रिक्तर एंड कंपनी तथा कुछ दूसरी वगणियां ने मजिब, वित्त विभाग, भारत सरकार को (3 अप्रैल, 1862) ।
125. जे० स्ट्रैची व आर० स्ट्रैची, पूर्वोद्धृत, पृ० 247 ।
126. विधान परिषद कार्यविवरण (माराश) जिल्द XI (नई सीरीज), पृ० 263 ।
127. गृह कार्यविवरण पुष्पक राजस्व 21 अक्तूबर, 1861, सख्या 2, कप्तान एफ० जोन, राज० नीतिक रेजीडेंट, पारम को खासी ने मजिब, बंबई सरकार को (16 जून 1861) ।
128. गृह कार्यविवरण पुष्पक राजस्व, 10 फरवरी, 1862, सख्या 2, कप्तान एफ० जोन ने मजिब, बंबई सरकार को (9 दिसंबर, 1861) ।
129. वित्त कार्यविवरण पुष्पक राजस्व, फरवरी, 1868, सख्या 101-10 टर्फी और पारम को खासी के क्षेत्रों में वेदा को जाने वाली अफीम को सरकारी राजस्व का स्रोत बनाने के प्रश्न के संबंध में ।
130. मैगिब बीडन व समुदाय प्रवर समिति (1871) के सामने साक्ष्य, प्रश्न 334-51 ।
131. वित्त कार्यविवरण पुष्पक राजस्व, अक्तूबर, 1871, सख्या 41 । मैगिबोर्ड बर्नड स्प्रिंग रॉने,

राजनैतिक रेजीडेंट, फारम की छाड़ी से सचिव, बंबई सरकार को (17 जुलाई, 1871) ।

132. वित्त कार्यविवरण जुलाई, 1871, परिशिष्ट, चीन में अफ्रीम की छेती के बारे में वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया आपन ।
133. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व 19 अगस्त, 1861, सध्या 21, औपनिवेशिक सचिव, हागकाग से सचिव, भारत सरकार को (17 जुलाई, 1861), डब्ल्यू० एम० एफ० मेयर्स, ब्रिटिश वाणिज्य दूत, कंटन ।
134. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, 21 अक्तूबर, 1861, सध्या 6, औपनिवेशिक सचिव, हागकाग से सचिव, भारत सरकार को (10 सितंबर, 1861) । सेप्टिमेंट कर्नल सरेल की रिपोर्टें ।
135. वित्त कार्यविवरण, जुलाई 1871 । 23 फरवरी, 1871 का आपन ।
136. गृह पृथक राजस्व 22 जुलाई, 1863 । विदेशी (राजनीतिक) कार्यविवरण से 30 जून, 1863, सध्या 319 से उद्धरण, ए० पी० फायरे, बर्मा के चीफ कमिश्नर हैं सचिव विदेश विभाग, भारत सरकार को, पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1863; 1 मई, 1863; 20 नवंबर, 1862, 12 दिसंबर, 1862 ।
137. जार्जटाइन स्किनर एंड कंपनी के श्री एजरा, जार्जटाइन मैथेमन एंड कंपनी के कैमब्रिज तथा एप्कार एंड कंपनी, देखें वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1871, दिनांक 23 फरवरी, 1871 का आपन ।
138. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1871, परिशिष्ट, वित्त विभाग का आपन, 23 फरवरी, 1871 ।
139. यह सर आर० आलकाक का मत था । प्रवर समिति (1871) के सामने साक्ष्य, प्रश्न 5696 ।
140. एफ० जे० हालीडे का प्रवर समिति (1871) के सामने साक्ष्य, प्रश्न 3660-61; 3677-79 ।
141. मेयो से आरगाहल को, 17 अक्तूबर, 1869 (मेयो कागजात, बडल 37, सध्या 285) ।
142. 'फ्रीड आफ इंडिया', संपादकीय, 16 दिसंबर, 1869, वही 'औपियम रेवेन्यू इन बेंजर', 30 दिसंबर, 1869 । मेयो से आर्बुथनाट को, 23 अगस्त, 1869 (मेयो कागजात), बडल 36, सध्या 210) मैसर्स जार्जटाइन स्किनर कंपनी के स्किनर का मत उद्धृत ।
143. मेयो से आर० आलकाक को, 17 अक्तूबर, 1869 (मेयो कागजात, बडल 37, सध्या 286) ।
144. मेयो से आरगाहल को, 23 जनवरी, 1870 (मेयो कागजात, बडल 35, सध्या 28) ।
145. मेयो से डर्वी के अर्स को, 30 जनवरी, 1870 (मेयो कागजात, बडल 35, सध्या 40) ।
146. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1871, परिशिष्ट, वित्त विभाग का आपन, 23 फरवरी, 1871 ।
147. वही, पृथक राजस्व सध्या 21 । अफ्रीम परीक्षक, निचले प्रांत से अवर सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू की, 20 फरवरी, 1870, सध्या 25 । सेपार्ड से बनारस के अफ्रीम एजेंट को, 23 सितंबर, 1870 ।
148. वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 1871, पृथक राजस्व सध्या 39 । जी० डब्ल्यू० केन, हाकाउ स्थिति वाणिज्य दूत से सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार को, 31 जुलाई, 1871 ।
149. वही जेचुएन, यनान तथा कैरीचाउ में 1869 में क्रमशः 6,000; 20,000 तथा 15000 पिकल उत्पादन हुआ ।

150. वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 1871, पृथक राजस्व सख्या 29। हांकाउ स्थित वाणिज्य दूत से सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार, 31 जुलाई, 1871।
151. पूर्वोक्त स्थल।
152. मेयो से ओरगाइल को, 31 जनवरी, 1870 (मेयो कागजात, बंडल 35, सख्या 41)।
153. मेयो से वी० फेर को, 3 जून, 1870 (मेयो कागजात, बंडल 39, सख्या 156)।
154. आरगाइल से मेयो को, 5 मई, 1870 (मेयो कागजात, बंडल 48, सख्या 14)।
155. वही, 1 जुलाई, 1870 (मेयो कागजात, बंडल 48, सख्या 19)।
156. मेयो से वी० फेर को, 3 जून, 1870 (मेयो कागजात, बंडल 39, सख्या 156)।
157. पूर्वोक्त स्थल।
158. विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) जिल्द VII, पृ० 351-52, एस० सी० का वित्तीय विवरण।
159. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1869, पृथक राजस्व सख्या 54, भारत सरकार से भारत मंत्री को, 22 जुलाई, 1869।
160. मैनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स कार्यविवरण, 13 मार्च 1862, रेडफोर्ड द्वारा उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 25। वित्त कार्यविवरण जुलाई, 1869, पृथक राजस्व सख्या 51, सचिव, चेंबर आफ कामर्स, इंडी, से भारत उपमंत्री को, 5 मार्च, 1869।
161. इंग्लैंड से वस्त्रों का निर्यात (करोड़ गज)

	कुल	भारत
1850	135.8	31.4 (23.1 प्रतिशत)
1860	277.9	82.5 (29.7 " )
1870	325.3	92.3 (28.4 " )
1880	449.6	181.3 (40.3 " )

(कालम 3 का कालम 2 के साथ अनुपात कोष्ठक में दिया गया है) देखें रेडफोर्ड, पूर्वोद्धृत, पृ० 22। यह स्मरणीय है कि ये आंकड़े मात्रा को प्रकट करते हैं न कि मूल्य को। अच्छी किस्म के कीमती वस्त्रों का निर्यात यूरोपीय और अमरीकी बाजारों को होता था।

162. इन आंकड़ों में 'विदेशी' अर्थात् गैर ब्रिटिश माल भी सम्मिलित है लेकिन इस अवधि में 'विदेशी' कपड़े का आयात नगण्य था। उपनिवेशों को ब्रिटिश सूती वस्त्रों के निर्यात के बारे में देखें, डब्ल्यू० ग्लोड, 'ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेड 1870-1930' पृ० 97 ब सारणी 25, पृ० 172-74 (अनुवाद डब्ल्यू० ओ० हेडरसन तथा डब्ल्यू० एच० गोलनर द्वारा)।
163. रेडफोर्ड, पूर्वोद्धृत, पृ० 26।
164. वित्त कार्यविवरण अगस्त, 1875, सख्या 19-27 (के० डब्ल्यू०) पृ० 20-21। रेडफोर्ड, पूर्वोद्धृत, पृ० 29 पर मैनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स के कार्यविवरण से उद्धरण : 'ब्रब (1874) बर्बर्ड और उसके आमपास भीतरी प्रदेश में 20 सूती मिलें हैं।' यह गलत मान्यता है। उस समय बर्बर्ड में 14 से अधिक मिलें नहीं थीं।
165. राजस्व कार्यविवरण, 1 दिसंबर, 1863, सख्या 2।
166. वही, 1 जून, 1864, सख्या 22, जो० एम० चैटन, सचिव, मदर बोर्ड आफ रेवेन्यू में सचिव,

एन० डब्ल्यू० पी० सरकार को, 6 जनवरी, 1864।

167. राजस्व कार्यविवरण जून, 1864, सख्या 23, ठीक वही दिनांक 16 मार्च, 1864।
168. वही, अंग्रेजी कपड़े की माग में 1862-64 की अवधि में कमों के विविध कारण थे। ये कारण थे—आंतरिक मुद्रा बाजार में तंगी 'उपलब्ध पूँजी को अधिक लाभदायक कपास के निर्यात संबंधी सट्टे में लगाना', और सूती कपड़ों का ऊनी व सन के कपड़ों से प्रतिस्थापन। पूर्वोक्त स्थल, पश्चिमोत्तर प्रांत के बोर्ड आफ रेवेन्यू की टिप्पणी जिलों से मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित हैं। राजस्व कार्यविवरण, जनवरी, 1864, सख्या 23 (सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू के परिपत्र आदेश ए, दिनांक 12 जनवरी, के प्राप्त होने वाले उत्तरो का कारण) और राजस्व कार्यविवरण, नवंबर, 1864, सख्या 24, डब्ल्यू० सी० प्लोडन, सचिव बोर्ड आफ रेवेन्यू, एन० डब्ल्यू० पी० से सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार को, 24 नवंबर, 1864।
169. वित्त कार्यविवरण, दिसंबर, 1864, पृथक राजस्व प्रकीर्ण सख्या 574, सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू, निचले प्रांत से अवर सचिव, बंगाल सरकार, 28 नवंबर, 1864। वही सख्या 575, अवध के चीफ कमिशनर के सचिव से सचिव, भारत सरकार को, 22 दिसंबर, 1864। वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1865, पृथक राजस्व, प्रकीर्ण सख्या 53, मध्य प्रांत के चीफ कमिशनर के सचिव से सचिव, भारत सरकार को, 21 दिसंबर, 1864।
170. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1865, पृथक राजस्व (प्रकीर्ण) सख्या 53, मध्य प्रांत के चीफ कमिशनर के सचिव से सचिव, भारत सरकार को, 21 दिसंबर, 1864।
171. विधान परिषद कार्यविवरण, 1863, जिल्द II (नई सीरीज) पृ० 82।
172. बोर्ड से उद्यमकर्ताओं जैसे कि कलकत्ते के पास के बूट के कारखानों को चलाने वाले स्काटिश लोगों के भिन्न विचार हो सकते हैं।
173. गृह पृथक राजस्व, 31 मार्च, 1862 सख्या 7, डब्ल्यू० एस० फिट्ज विलियम, अध्यक्ष, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सपरिषद गवर्नर जनरल को, 27 मार्च, 1862।
174. विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) जिल्द VI, 1860, पृ० 115-17।
175. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 65, II अप्रैल, 1865। भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त सख्या 114, 9 मई, 1865।
176. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 114, 9 मई, 1865। जब स्वयं भारत सरकार ने निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया तो भारत मंत्री ने बहुत ही आश्चर्य व्यक्त किया। बुड से लारेंस को, 16 सितंबर, 1865। लारेंस कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द II, सख्या 50।
177. बुड से लारेंस को, 12 अगस्त, 1865, लारेंस कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द II, सख्या 45। बुड ने लिखा कि वह सिद्धांत रूप में निर्यात शुल्क के विरोध में नहीं था, लेकिन आय-कर हटाकर उमसे होने वाली हानि को पूरा करने के लिए निर्यात शुल्क को लगाना भूल था।
178. 1860 का एक्ट X, 1862 के एक्ट XI व XXIII।
179. गृह पृथक राजस्व 18 सितंबर, 1862। भारत सरकार की वित्त विभाग द्वारा टिप्पणी, 9 अप्रैल, 1861। मशीनों के आयात के संबंध में टेरिफ नीति का पुनरावलोकन करते हुए भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया कि क्या मशीनों को पूर्ण रूप में शुल्क मुक्त

कर दिया जाना चाहिए (1845 के निर्णय के अनुसार) या फिर कुछ विशेष प्रकार की मशीनों को शुल्क से मुक्त रखना चाहिए (जैसा कि 1859 के एक्ट XII के अनुसार था)। 1860 के एक्ट X के अनुसार सभी मशीनें शुल्क मुक्त थी और स्टीमर का तना बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली चादरें जुलाई, 1860 की विज्ञप्ति के अनुसार शुल्क से मुक्त थी। परंतु स्पूनर टैरिफ समिति (गृह पृथक राजस्व, सितंबर, 1862, सध्या 13, आर० स्पूनर से सचिव, भारत सरकार को, 10 जनवरी, 1861) ने सुझाव दिया था कि कुछ विशेष प्रकार की मशीनों को ही शुल्क से मुक्त रखना चाहिए। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया (गृह पृथक राजस्व अप्रैल, 1861, सध्या 14, भारत सरकार का वित्त विभाग में प्रस्ताव, 9 अप्रैल, 1861) और 1862 के एक्ट XI में केवल कृषि, नौ परिवहन, जनन निर्माण और रेल परिवहन के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनों को शुल्क मुक्त करने के लिए सशोधन किया गया (गृह पृथक राजस्व, अगस्त, 1862, सध्या 26, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 18 अगस्त, 1862)।

180. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सध्या 73, 8 मार्च, 1867। 1875 में टैरिफ समिति ने सुझाव दिया कि मशीनों पर शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस सबब में बहुत मतों-रजक विवाद हुआ। टैरिफ समिति ने तर्क दिया कि यूरोपीय मशीनों के आयात को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए 'अनुग्रह' को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत मत था कि 'जनाधिक्य के कारण सम्भावित सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने के साधनों के रूप में यदि हमें किसी एक बात पर अन्य बातों से अधिक ध्यान देना चाहिए तो वह औद्योगिक वर्ग का निर्माण और भूमि पर जन भार को आघात करके इतना कर देना है कि लोग उस पर ठीक प्रकार से जीवन-यापन कर सकें।' (वित्त कार्यविवरण, अगस्त, 1875, सध्या 20, सचिव, टैरिफ समिति से सचिव, भारत सरकार को, 27 फरवरी, 1875 और एथले ईडन की टिप्पणी, दिनांक नहीं दिया है, के० डब्ल्यू०, पृ० 9, वित्त कार्यविवरण, अगस्त, 1875, सध्या 19-27)।
181. वित्त कार्यविवरण, 1867, सीमा शुल्क समिति की रिपोर्टें, 7 जनवरी, 1867, जे० एम० ब्राफोर्ड की विसम्मति टिप्पणी, वित्त कार्यविवरण, पृथक राजस्व, मार्च 1866, सध्या 482। भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त पृथक राजस्व, सध्या 15, सितंबर, 1865।
182. एस० बी० साउम, 'स्टडीज इन ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेड 1870-1914' (लंदन, 1960) पृ० 192।
183. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1869, पृथक राजस्व सध्या 51। आर० स्ट्रोक, सचिव, बैंक आफ कामर्स, इंडी, से भारत उपमंत्री को, 5 मार्च, 1869।
184. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1869, पृथक राजस्व सध्या 54, भारत सरकार से भारत मंत्री को 22 जुलाई, 1869।
185. वित्त कार्यविवरण, पृथक राजस्व, जनवरी, 1867, सध्या 11। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिनांक 28 नवंबर, 1866 का कार्यवृत्त जो भारत सरकार को दिनांक 16 जनवरी, 1867 को भेजा गया था। वित्त कार्यविवरण पृथक राजस्व, मार्च, 1867, सध्या 10, अवर सचिव बंगाल सरकार से वित्त सचिव, भारत सरकार को, 18 फरवरी, 1867।

186. वित्त कार्यविवरण, पृथक राजस्व मार्च, 1867, सध्या 4, भारत सरकार से भारत मंत्री को, 21 दिसंबर, 1866 ।
187. वित्त कार्यविवरण पृथक राजस्व, अप्रैल, 1867, सध्या 26, ब्रिटिश बर्मा के व्यापारियों से चीफ कमिशनर, ब्रिटिश बर्मा को, 20 मार्च, 1867 । वही सध्या 27, मोनमोन के व्यापारियों से कमिशनर, टिनेगिरि डिप्टीजन को, वित्त कार्यविवरण, पृथक, राजस्व, मार्च, 1871, सध्या 25, सचिव, ईस्ट इंडिया एगोमिएशन, तिवरपुल, से भारत मंत्री को, 1 फरवरी, 1871 ।
188. वित्त कार्यविवरण, पृथक राजस्व, मार्च, 1871, सध्या 23 । भारत मंत्री से भारत सरकार को, 10 मार्च, 1870 ।
- 189 वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1873, सध्या 4, सपरिपद गवर्नर जनरल का आदेश, 4 जनवरी, 1873 ।
- 190 एस० बी० साउल, पूर्वोद्धृत, पृ० 197-98 ।
191. सर सेसिल बीडन का भारतीय वित्त से संबंधित प्रवर समिति के सामने साक्ष्य, पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, 2874-2901 ।
- 192 वही, 2904-08, गृह कार्यविवरण 10 जून, 1863, पृथक राजस्व सध्या 8, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू को, 16 अप्रैल, 1863 ।
- 193 पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पृथक 363, 2926-28 ।
- 194 गृह कार्यविवरण, 18 मार्च 1861, पृथक राजस्व सध्या 20, डब्ल्यू० ए० सचिव, भारत सरकार से सचिव, बंगाल सरकार को, 18 मार्च, 1861 ।
- 195 पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363 2981-99 ।
- 196 भारत सरकार से भारत मंत्री को, पृथक राजस्व, प्रेषण सध्या 20, 15 अगस्त, 1859 ।
197. गृह कार्यविवरण, 3 फरवरी 1860, पृथक राजस्व, सध्या 2, भारत मंत्री से भारत सरकार को, पृथक राजस्व, प्रेषण सध्या 16, 19 दिसंबर, 1859 ।
198. गृह पृथक राजस्व कार्यविवरण, 11 अप्रैल, 1862, सध्या 6 । ए० ईडन, सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू, से सचिव, बंगाल सरकार को, 27 फरवरी, 1862 ।
- 199 भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 38, 7 मार्च, 1862 ।
200. पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, 3170-75 ।
- 201 भारतीय वित्त से संबंधित प्रवर समिति के सामने डब्ल्यू० जी० पैडर का साक्ष्य, पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, 4140-47 । गृह कार्यविवरण, 20 अप्रैल, 1861, पृथक राजस्व सध्या 20, सचिव, भारत सरकार से सचिव, बर्मा सरकार को, 20 अप्रैल, 1861 । वित्त कार्यविवरण, जून, 1865, पृथक राजस्व सध्या 309, सचिव, बर्मा सरकार से सचिव, वित्त सचिव, भारत सरकार को, 7 जनवरी, 1865 । वित्त कार्य विवरण, अक्तूबर, 1859 । पृथक राजस्व सध्या 36, वही सध्या 38 । भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त सध्या 243, 4 अक्तूबर, 1869 ।
202. भारतीय वित्त से संबंधित प्रवर समिति के सामने सर टी० पाइकोफ्ट का साक्ष्य, पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द 8, पत्रक 363, 3689-97 ।
203. गृह कार्यविवरण 23 सितंबर, 1869, पृथक राजस्व सध्या 29 । महास बोर्ड आफ रेवेन्यू के

कार्यविवरण से उद्धरण, 27 मार्च, 1863। वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 1869, पृथक राजस्व सख्या 33, सचिव, मद्रास सरकार से सचिव, भारत सरकार, 17 सितंबर, 1869। वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 1869, पृथक राजस्व सख्या 38, भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त 249, 4 अक्तूबर, 1868।

204. मेयो से जे० स्ट्रैची को, 10 जनवरी, 1860, मेयो कामजात, बंडल 35, सख्या 10, मेयो ने जोधपुर के महाराजा पर राजनीतिक दबाव डालने के विषय में विचार किया और सोचा कि उसके नमक के लिए ब्रिटिश इंडियन रेलों के द्वारा यातायात की सुविधा न देकर उसकी जड़ नीचे से काटी जा सकेगी। नमक की भीलों से संबंधित पट्टे की व्यवस्था करने में ए० ओ० ह्यूम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1870, व्यय की शाखा सख्या 4, ए० ओ० ह्यूम, आंतरिक सीमा शुल्क कमिशनर से सचिव, भारत सरकार को।

205. देखें, डब्ल्यू० जी० पैडर की नमक विभाग प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट, दिनांक 30 जुलाई, 1870। वित्त कार्यविवरण जून, 1871, पृथक राजस्व सख्या 80। वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1866, सख्या 45, नमक तथा चीनी शुल्कों की संधि के संबंध में अधिनियम। जे० स्ट्रैची तथा आर० स्ट्रैची 'दि फाइनेंस एंड पब्लिक वर्क्स ऑफ इंडिया 1869-81' (लंदन, 1881) पृ० 219।

206. वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1868, पृथक राजस्व सख्या 19। आर० टैपिल का मेमो०, 11 अगस्त, 1868। मैसफील्ड, ह्यूरेड, मेन और स्ट्रैची टैपिल के प्रस्ताव के विरोध में थे और तारें उसके पक्ष में थे। भारत सरकार ने भारत मंत्री को, पृथक राजस्व प्रेषण सख्या 25, 29 सितंबर, 1868। टैपिल की योजना के अनुसार बंगाल में शुल्कों में कमी की जाती थी और इससे राजस्व की हानि होती थी। यह सच्य टैपिल की योजना के विरुद्ध एक प्रबल तर्क था। वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1868, पृथक राजस्व सख्या 21, एच० एम० ह्यूरेड का, मेमो०, 17 अगस्त, 1868; वही सख्या 27, एच० एस० मेन का मेमो०, 19 सितंबर 1868।

207. वित्त कार्यविवरण, सख्या 1878, पृथक राजस्व सख्या 350-77, खंड बी, वित्त कार्यविवरण फरवरी, 1879, व्यय शाखा 292-93।

208. देखें जे० स्ट्रैची से मेयो को, 3 जुलाई, 1869, मेयो कामजात, बंडल 36, सख्या 14 (संलग्न-पत्र)।

209. वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 1868, सख्या 23, पश्चिमोत्तर प्रांत से राजपूताना को अपना ब्रिटिश क्षेत्र की सीमा शुल्क की सीमा के बाहर चीनी के निर्यात के विषय में जे० स्ट्रैची का कार्यवृत्त 8 सितंबर, 1868। वित्त कार्यविवरण मार्च, 1871, पृथक राजस्व सख्या 14-22 तथा कृषि, राजस्व एवं वाणिज्य विभाग कार्यविवरण, नवंबर, 1871, सख्या 1-3 पंजाब में चीनी पर शुल्क के विषय में गृह कार्यविवरण, 11 अक्तूबर, 1861, पृथक राजस्व सख्या 41 सी० वीडन का सभी प्रांतीय सरकारों को परिपत्र, 21 मार्च, 1859। वित्त कार्यविवरण फरवरी, 1863, लेखा शाखा सख्या 2। भारत सरकार का प्रस्ताव, 3 फरवरी, 1863, इस प्रस्ताव द्वारा तबाकू पर शुल्क लगाने की योजना को रद्द कर दिया गया। वित्त कार्यविवरण फरवरी, 1868, पृथक राजस्व सख्या 26। तबाकू पर कर के विरोध में जे० स्ट्रैची का

ज्ञापन, 21 अक्टूबर, 1865 ।

- 210 भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सध्या 2, 21 जनवरी, 1869 ।
211. वित्त कार्यविवरण, जून, 1871 पृथक राजस्व सध्या 80, डब्ल्यू० जी० पैडर से सचिव, बवई सरकार को, (नमक विभाग के विषय में रिपोर्ट), 30 जुलाई, 1870 ।
- 212 वित्त कार्यविवरण जून, 1861, सेखा शाखा सध्या 61, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, कलकत्ता के सदस्यों से गवर्नर जनरल को, 5 जून, 1861 ।
- 213 राजस्व कार्यविवरण, जून, 1867, सध्या 50, एच० डब्ल्यू० आई० वुड, सचिव, बंगाल चैंबर आफ कामर्स से सचिव, वित्त विभाग को, 31 मई, 1867 ।
214. वित्त पृथक राजस्व कार्यविवरण, सध्या 21; भारत सरकार से भारत मंत्री को, 20 अप्रैल, 1867 ।
215. आर० टैपिल से मेयो को, 20 अक्टूबर, 1871, मेयो कागजात, बडल 61 (सध्या नहीं दी गई है) ।
- 216 लार्ड कैनिंग से जेम्स विल्सन को (22 नवंबर, 1859), बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत, II, पृ० 206 जे० विल्सन से वाल्टर बेर्जहाट को (15 नवंबर, 1859) बैरिंगटन, II, पृ० 194-95 ।
217. जे० विल्सन, स्टेटमेंट (कलकत्ता, 1860), पृ० 15 ।
- 218 वही, पृ० 31 ।
- 219 कैनिंग से जे० विल्सन को 31 जनवरी, 1860, बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत, II पृ०-223-24 ।
220. वही, 10 फरवरी, 1860, वही, पृ० 225-27 ।
221. भारत मंत्री से भारत सरकार को, 3 अप्रैल, 1860, वित्त सध्या 55 ।
- 222 वही, 18 मार्च, 1860, बैरिंगटन, पूर्वोद्धृत II पृ० 274-75 ।
223. लार्ड कैनिंग से जे० विल्सन को, 13 मार्च, 1860, बैरिंगटन II पृ० 272 । कैनिंग से जे० विल्सन को तार, दिनांक 13 मार्च । इस बात की बहुत संभावना है कि आप कर का सेना पर प्रभाव एक गंभीर प्रश्न बन जाएगा । इस समय में सरकार के व्यवहार के विषय में आप सावधान रहें । वही, पृ० 272 ।
- 224 विधान परिषद कार्यविवरण, 14 अप्रैल, 1860 जिल्द VI (पुरानी सीरीज) ।
225. जे० विल्सन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट (कलकत्ता 1860) पृ० 20 ।
226. 'पेट्रीशन अगेस्ट इनकम टैक्स आफ दि जमीदासं आफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा द्यु पार्लियामेंटस, (कलकत्ता, 1861) । भारत मंत्री से भारत मंत्री से भारत सरकार को, 2 अगस्त, 1861 । वित्त सध्या 121 । भारत सरकार से भारत मंत्री को, 6 जून, 1861; वित्त सध्या 106 ।
227. भारत मंत्री से भारत सरकार को, 2 अगस्त, 1861, वित्त सध्या 121 ।
228. 1793 के विनियम XIX का पहला वाक्य इस प्रकार था : 'देस के प्राचीन विधान के अनुसार सत्ताधारी शक्ति को भूमि के प्रत्येक बोधे पर किए गए उत्पादन का एक निश्चित अनुपात, स्थानीय प्रथा के अनुसार, नकदी या पदार्थ में प्राप्त करने का अधिकार है ।' 1793 के विनियम VIII में एक धारा (75 थी) थी जिसके अनुसार मासगुजारी निर्माण इस प्रकार विनियमित होना चाहिए कि स्वत्वाधिकारियों (भूस्वामियों) के पाम सरकार को दी जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत बच रहे । इन उपबन्धों और विवरणों की व्याख्या इस प्रकार



की गई कि भूमि से राजस्व पाने का अधिकार राज्य की सत्ता में निहित है। तात्पर्य यह है कि मालगुजारी कोई कर नहीं है।

229. गृह राजस्व कार्यविवरण 1860, जुलाई, 24, संख्या 41, बर्दवान के महाराजा से पत्र दिनांक 3 मई, 1860। राजस्व कार्यविवरण, 18 मई, 1860, संख्या 6, बर्दवान के महाराजा को धन्यवाद देते हुए भारत सरकार का प्रस्ताव। भारत मंत्री से भारत सरकार को प्रेषण, 26 जुलाई, 1860। वित्त संख्या 115 में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बर्दवान के महाराजा को धन्यवाद पत्र दे।
230. विल्लम अधिक आभाववादी था और उसने विरोध को कम समझा था। विल्लम से डब्ल्यू. बेजहाट को, 20 फरवरी, 1860, बैरिंगटन, II, पृ० 225-27।
231. सार्जेंट कोनिंग से जे० विल्लम को, 10 फरवरी, 1860, बैरिंगटन, II, पृ० 225-27।
232. गृह राजस्व कार्यविवरण, अगस्त, 10, 1860, संख्या 9।
233. थॉर्न वुड से जेम्स विल्लम को, 26 मार्च, 1860, बैरिंगटन, II, पृ० 23।
234. जेम्स विल्लम से वास्टर बेजहाट को 15 नवंबर, 1859, वही, II, पृ० 194-95।
235. गृह राजस्व कार्यविवरण, मिनबर, 23, 1860, संख्या 39, समिति की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार का प्रस्ताव। राजस्व कार्यविवरण, 20 अक्तूबर, 1860, संख्या 35। समिति की रिपोर्ट।
236. गृह राजस्व कार्यविवरण, 6 नितंबर, 1860, संख्या 15 : (फारमो विभाग) नारिवाट, बिना कैला के निवासियों द्वारा भारत की विधान परिषद के सदस्यों को भेजी गई याचिका, (मंजी) दिनांक 15 जून, 1860।
237. गृह राजस्व कार्यविवरण, 20 अक्तूबर, 1860, संख्या 42। सचिव, बंगाल सरकार ने भारत सरकार को, 2 अक्तूबर, 1860।
238. गृह राजस्व कार्यविवरण, 20 अक्तूबर, 1860, संख्या 44।
239. वही, 6 मिनबर, 1860, संख्या 15।
240. रोबर्ट माइट ए० एम० ए०, 'रिपब्लिक माइंस इन इंडिया ऐंड द्युमेट्रेस बाई दि इनकम टैक्स' (बर्मी, 1870)।
241. वित्त कार्यविवरण, 9 मई, 1863, मेधा माथा, संख्या 265।
242. ए०।। मैक, 'प्राइमरियल इंडस्ट्रिय' (कम्पेन्स, 1861)।
243. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1864, मेधा माथा संख्या 164।
244. 'दिवी वीटिज' 20 जुलाई, 1864।
245. बर्नर डायरन द्वारा कार्यविवरण (दिया है)। वित्त कार्यविवरण मई, 1864, मेधा माथा संख्या 56।
246. सी०।। डोर द्वारा मेयो०, 8 मिनबर, 1864, वित्त कार्यविवरण मिनबर, 1864, मेधा माथा संख्या 4।
247. हर रिपोर्ट की प्रतियां कब्रिनी की: देखें, सी०।। पृ० 212।
248. राज बर्न डोर [FEO] के बिना क्या हर रिपोर्ट कब्रिनी की बात। इनका विवेक भारत सरकार के [1861] में [1864] तक की मेजर-जारी की।

249. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1865, लेखा शाखा सख्या 67 I
250. मेयो से नैपियर को, 16 जनवरी, 1870, मेयो कागजात, बडल 39, सख्या 234 ।
251. मेयो से आरगाइल को, 5 जुलाई, 1870, मेयो कागजात, बडल 39, सख्या 453 ।
252. वित्तीय विवरण, विधान परिषद कार्यविवरण (सारांश) 1865, जिल्द I (नई सीरीज), पृ० 169 । चार्ल्स वुड आय कर समाप्त करने के विरुद्ध था, परंतु उसका तार कलकत्ते में समय पर नहीं पहुँचा । सी० वुड से जे० सार्वेस को, 10 अप्रैल, 1865 । भारत मंत्री से पत्र, जिल्द II, सख्या 27 ए ।
253. विधान परिषद कार्यविवरण (सारांश), जिल्द VIII (नई सीरीज), पृ० 105 ।
254. गृह राजस्व कार्यविवरण अप्रैल, 1867, सख्या 20 । कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन से भारत मंत्री को याचिका (अर्जी), 22 अप्रैल, 1867 ।
255. गृह राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 1867, सख्या 19 । कलकत्ता के निवासियों का भारत मंत्री को स्मरणपत्र, (दिनांक नहीं है) ।
256. गृह राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 1867, सख्या 7, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, गृह विभाग को, 22 मार्च, 1867 ।

## समृद्धि का लीला-रूपक

‘राष्ट्र का हाल है क्या ?  
 कौन सा है इसका कारोबार  
 ए दोस्ती, बड़ो और बढ़ते ही चलो—  
 और, भेजो हमें इसकी खबर……’

रुडयार्ड किपलिंग  
 ‘दि मस्क आव प्लेटो’

डिपार्टमेंटल डिटिज एंड धैरकरूम बैलाइस

सार्वजनिक व्यक्तियों के वक्तव्यों तथा रचनाओं से इक्के-दुक्के अंश तथा समाचार पत्रों से कहीं-कहीं से कुछ उद्धरण निकालकर उनके आधार पर बननेवाली विचारधारा को ‘लोकमत’ अथवा ‘राष्ट्रीय विचारधारा’ के नाम से प्रस्तुत करना बहुत सहज होने के साथ-साथ खतरनाक भी है। यह प्रयास इस दृष्टि से खतरनाक है कि हम मिली-जुली धारणाओं तथा विचारों में झूठी तालमेल बैठाने की भूल कर सकते हैं। जिस काल का हमने अध्ययन किया है उसके बारे में यह युक्तियुक्त परिकल्पना की जा सकती है कि उसमें कोई ऐसी सुसंगत विचारधारा नहीं थी जिसे राष्ट्रीय कहा जा सके। फिर भी, हमारे लिए ‘हिंदुस्तानी’ अथवा भारतीय स्वामित्व के अंतर्गत आनेवाले समाचारपत्रों में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसी सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संगठित परिचर्याओं तथा सभाओं में, जनता द्वारा शासकों के पास समय-समय पर भेजे गए स्मरणपत्रों एवं याचिकाओं (अर्जियो) में, और दादाभाई नौरोजी, त्रिस्टोदास पाल, हरीश मुकर्जी जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की रचनाओं में अभिव्यक्ति पानेवाली धारणाओं तथा विचारों के उभरते स्वरूप की उपेक्षा कर पाना संभव नहीं है। उस समय जानकारी लोकमत का विकास प्रारंभिक व्यवस्था में था। बंगाल और बंबई की कुछ पत्रिकाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीय समाचार पत्र प्रबुद्ध एवं जानकारी पर आधारित आलोचना कर पाने में असमर्थ थे। यह लोकवित्त जैसे तकनीकी एवं गूढ़ विषय के बारे में विशेष रूप से सत्य था। तथापि विचारों की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी जिन्होंने भिन्न-भिन्न अंशों में समाचारपत्रों को प्रभावित किया था और वित्तीय एवं आर्थिक नीति के संबंध में कुछ धारणाएँ निश्चित स्वरूप धारण करने लगी थी। इन विचारों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षों में उसके विचारों में बहुत सादृश्य दिखाई देता है।

जिस काल का यह अध्ययन है, उसमें वित्तीय प्रश्नों पर होनेवाले विवाद कुछ विशेष महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में ही रहते थे। प्रथम प्रश्न कराधान के भार से सबद्ध था और फिर कुछ इससे घनिष्ठ रूप से संबद्ध अन्य प्रश्न भी थे जैसे जीवन-स्तर, कर चुकाने की क्षमता, कर-संपात इत्यादि थे। दूसरी श्रेणी में व्यापक राजनीतिक प्रश्न जिन्हें 'प्रतिनिधित्व के साथ कराधान' के नारे से संबद्ध करके संक्षेप में व्यक्त किया जाता था, आते थे।

यद्यपि समसामयिक राजनीतिक एवं आर्थिक साहित्य में लोगों की कर चुकाने की क्षमता, जनसाधारण के जीवन-स्तर, करों के भारी बोझ इत्यादि के विषय में अनेक सामान्य बातें देखने को मिलती हैं, तथापि सांख्यिकीय आधार पर इनकी सत्यता सिद्ध करने की दिशा में बहुत थोड़े प्रयास किए गए। राष्ट्रीय आय के एक भी निश्चित प्राक्कलन उपलब्ध होने से लोगों की कर चुकाने की क्षमता क्या थी इसका (औसत प्रति व्यक्ति आय और कराधान के औसत भार में तुलना के आधार पर) निर्धारण करने में अटकलपच्चू ही रहना था। इस काल में औसत राष्ट्रीय आय के बारे में एकमात्र सरकारी विवरण भारत उपमन्त्री श्री ग्राट डफ से प्राप्त हुआ था। 24 फरवरी 1871 को हाउस आफ कॉमंस में प्रस्तुत किए गए वित्त विवरण में उसने कहा था कि 'अनुमान है कि ब्रिटिश भारत की आय 30 करोड़ रुपये वार्षिक है।' इस प्रकार औसत वार्षिक आय 2 पौंड (= 20 रुपये) प्रति व्यक्ति थी।<sup>1</sup> लगभग दो वर्ष बाद 1867-68 के आंकड़ों के आधार पर दादाभाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया।<sup>2</sup> नौरोजी ने प्रत्येक प्रांत के वार्षिक कृषि उत्पादनों का हिसाब किया और फिर प्रचलित कीमतों के आधार पर उनका मूल्य निकाला। इसमें उन्होंने अटकलपच्चू ढंग से अनुमानित गैर कृषि आय को जोड़ दिया। उन्होंने न्यून प्रकरलन से बचने के लिए द्रुति की भारी गुजाइश भी रहने दी। उन्होंने सेवाओं को कोई मूल्य नहीं दिया, क्योंकि उनका तर्क था कि सेवाएं वास्तविक आय न होकर पहले से उत्पादित आय का विनियोग मात्र होती हैं। उनका निष्कर्ष था कि ब्रिटिश भारत की 17 करोड़ जनसंख्या की आय 3 अरब 46 करोड़ रुपये थी। तात्पर्य यह है कि औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये थी। यद्यपि दादाभाई नौरोजी की रीति परिष्कृत नहीं थी और उनकी राष्ट्रीय आय की परिभाषा में वैचारिक विचित्रता थी (उदाहरणार्थ, सेवाओं को अलग रखना) तथापि उनका अनुमान सर्वाधिक विश्वसनीय है।<sup>3</sup> 1871 में डडियन इकानामिस्ट के संपादक राबर्ट नार्डन ने दावा किया था कि औसत राष्ट्रीय आय लगभग 6 पौंड (= 60 रुपये) वार्षिक है।<sup>4</sup> परंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह राशि उसने किस प्रकार निकाली थी। जाने-माने उग्र ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हिडमैन का, जिसने अनुमान लगाया था कि 1886 में 5 व्यक्तियों के परिवार में वार्षिक आय 8 पौंड थी, आधार भी इतना ही अनिश्चित था।<sup>5</sup>

प्रति व्यक्ति कराधान के औसत भार संबंधी परिकल्पनों में भारी अंतर है। 'टाइम्स आफ इंडिया' के अनुसार 1863 में प्रति व्यक्ति वार्षिक कर लगभग 10 या 12 आने था।<sup>6</sup> 'फ्रैंड आफ इंडिया' द्वारा किए गए परिकलन के आधार पर 1861 में संपूर्ण

भारत में प्रति व्यक्ति कर का औसत भार 5 शिलिंग 3 पैसे ( $= 2$  रुपये 10 आने) था। अनुपात विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग था। बंगाल में कर भार 3 शिलिंग 6 पैसे ( $= 1$  रुपया 12 आने) था जो सबसे कम और पेगू में 9 शिलिंग ( $= 4$  रुपये 8 आने) था जो सर्वाधिक था।<sup>7</sup> 1868 में इसी पत्रिका के अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक कर भार 6 शिलिंग ( $= 3$  रुपये) था।<sup>8</sup> बंबई से निकलने वाले 'इंडियन इकोनामिस्ट' की अटकल-बाजी थी कि 1871 में प्रति व्यक्ति कर भार केवल 1 शिलिंग 10 पैसे ( $= 15$  आने) था।<sup>9</sup> इसके एक दशक बाद हिंडमैन ने ऐसा ही अटकलपच्चू अनुमान लगाया कि औसतन 5 व्यक्तियों के भारतीय परिवार का सरकारी व्यय के लिए कर एवं राजस्व में लगभग 2 पौंड ( $= 20$  रुपये) का योगदान था।<sup>10</sup> वैचारिक अंतरों के कारण यह अनुमान एक दूसरे से इतने अधिक भिन्न हैं कि वास्तव में इनमें से एक भी विश्वमनीय नहीं लगता। कुछ लोग मालगुजारी को लगान मानकर उसे सरकारी आय का गैर कर स्रोत स्वीकार करते थे। दूसरी ओर, कुछ अन्य लोग कराधान को सरकार के लिए वार्षिक राष्ट्रीय आय से की जाने वाली प्रत्येक कटौती के रूप में परिभाषित करते थे। इस परिभाषा के आधार पर मालगुजारी को कर माना जाएगा। अतः मालगुजारी के स्वरूप की परिभाषा के विषय में मतभेद से इन परिकलनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई, क्योंकि इसको कर भार के अनुमान में सम्मिलित न करने का (अथवा सम्मिलित करने पर) प्राक्कलित भार काफी कम (अथवा अधिक) हो जाता था।

औसत राष्ट्रीय आय के मुकाबले कराधान के औसत भार के विश्वसनीय प्राक्कलन के अभाव में समसामयिक वृत्तकारों को जीवन स्तर, जन साधारण की आर्थिक स्थिति, और विभिन्न वर्गों पर पड़नेवाले राजकोपीय बोझ के संवध में उपलब्ध सामान्य प्रमाणों पर ही निर्भर होना पड़ा। सरकारी मत था कि देश तेजी के साथ आर्थिक विकास के दौर से गुजर रहा है और इसलिए राष्ट्रीय आय में राज्य का भाग स्वाभाविक ढंग से बढ़ता है। 1860 में भारत मंत्री की अपने प्रेषण में भारत सरकार ने दावा किया कि घरेलू तथा विदेशी व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि, सावजनिक कंपनियों में हिंदुस्तानी तथा यूरोपीय पूंजी के भारी निवेश, कृषि उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य में वृद्धि, मजदूरी की दर में वृद्धि इत्यादि से 'अभूतपूर्व समृद्धि की स्थिति' का पता चलता है।<sup>11</sup> परंतु ब्रिटिश संरक्षण में इस नवीन समृद्धि से जो वर्ग मुख्यतः लाभान्वित हुए थे, उनके ऊपर कर भार का उमका अंश नहीं पड़ रहा था। 1860 में जेम्स विल्सन ने निर्भीकतापूर्वक भारत मंत्री की अपने प्रेषण में निंदा कि 'निस्संदेह सभी वर्गों को लाभ हुआ है परंतु पूंजीपति और व्यापारी वर्गों को मिलनेवाला लाभ अनुत्तरीय है। शेष में कृषि से संबंधित वर्गों को विशेष फायदा पहुंचा है। और यदि ऐसा है तो अन्याय की बात छोड़ भी दें तो भी हमारी प्रणाली में बहुत बड़ी अमंगलित व्याप्त है। न केवल इन वर्गों ने राज्य को उन फायदों के लिए बहुत थोड़ा योगदान किया है जो सरकार ने भारी लागत पर इन्हें प्रदान किए हैं, अपितु इन्हें किसी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत लाने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया गया है जिसमें इन फायदों के लिए ये लागत के प्रति न्यायोचित योगदान करेंगे।' सरकार ने एक ऐसी राजकोपीय प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की, जिसके द्वारा 'राज्य का

के संपूर्ण (ममाज) पर समान रूप से डाला जा सके और राजस्व का ऐसा स्वरूप बन सके कि देश की मंपत्ति और समृद्धि में वृद्धि के साथ वह भी बढ़े।<sup>12</sup> यह 1860 में लिखा गया जिसका मसौदा जेम्स विल्सन ने स्वयं निर्भीकतापूर्वक तैयार किया था। 1869 में भारत सरकार ने इसी प्रकार के विचार पुनः व्यस्त किए। भारत सरकार ने भारत मंत्री को प्रेषण में लिखा कि 'साम्राज्य का भव्य राजस्व ऐसे जनसमुदाय से प्राप्त होता है जिस पर अन्य देशों की तुलना में कर भार हल्का है... पिछले बीस वर्षों में रेल तथा सिंचाई संबंधी बड़े निर्माण-कार्यों द्वारा सभ्यता एवं संपन्नता बढ़ाने वाले प्रभावों का आभास पूरे देश में मिलने लगा है... श्रम के मूल्य में निरंतर होने वाली वृद्धि से शीघ्र ही लोगों की संपत्ति तथा मनुष्य में समुचित वृद्धि होनी ही चाहिए...'<sup>13</sup> 'वित्त विवरणों' तथा 'नैतिक एवं भौतिक प्रगति संबंधी रिपोर्टों' में की गई इन घोषणाओं से अगणित बार दोहराई गई कुछ बातें बहुत साफ हो जाती हैं अर्थात् (क) 1860-70 के दशकों में भारत की राष्ट्रीय मंपत्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, और इस प्रकार का विकास केवल ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित शांति की अवस्था में ही संभव था, (ख) तुलनात्मक दृष्टि से भारत में कर भार हल्का था। विशेष रूप से ऐसे वर्ग जिन्हें व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से लाभ हुआ था अपने अंश का कर भार अपने ऊपर लेने से बच रहे थे।

अंग्रेजी के समाचार पत्र स्थिति के विषय में इस सरकारी मत को जगभग स्वीकार करते थे। 'फ्रैंड आफ इंडिया' का अनुमान था कि भारत में कर बहुत हल्का है। इस पत्रिका के अनुसार तो समस्त संसार की तुलना में भारत में ही कर सबसे कम थे।<sup>14</sup> परन्तु 'फ्रैंड आफ इंडिया' ने स्पष्ट किया कि यद्यपि औसत भार कम है, तथापि एक वर्ग के लोगों पर कष्टप्रद भार है। पत्र में लिखा गया था कि 'साम्राज्य का भार संपत्तिशाली वर्गों पर न होकर लगभग एकमात्र श्रमिकों पर ही पड़ता है।' श्रमिक वर्ग भूमि कर, आवश्यक, मोहुरका तथा 90 प्रतिशत नमक कर देता था जबकि संपत्तिशाली वर्गों पर सीमा शुल्क, अदालती शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के रूप में कर लगाए गए थे। संपत्ति-वान एवं व्यापारिक वर्गों पर कर भार का अंश छोटा था।<sup>15</sup> वास्तव में 'फ्रैंड आफ इंडिया' अलोकप्रिय धार्य कर से संतुष्ट था क्योंकि इसके द्वारा आशा थी कि कराधान का भार 'परिश्रमी एवं किसी तरह चल रहे मध्यम वर्ग' तथा निर्धन व्यक्तियों पर से हटाकर सराफों, महाजनों व बंमियों पर डाला जा सकेगा जो करों से या तो पूरी तरह मुक्त थे या फिर जिन पर करदेय क्षमता की तुलना में बहुत थोड़े कर थे।<sup>16</sup> इस अवधार ने फिर लिखा कि ये वर्ग 'अपनी संपत्ति और मंख्या के लिए हमारे ऋणी हैं' परन्तु कराधान की प्रणाली में उन्हें हल्के कर लगा कर ही छोड़ दिया जाता है जबकि हम सभी रैयत के बल पर करो से बचे हुए हैं और ये रैयत उत्पादन शुल्कों, सीमा शुल्क तथा नमक शुल्क का भार हम सबसे कहीं अधिक अनुभव करते हैं।<sup>17</sup> 'टाइम्स आफ इंडिया' का विचार था कि 'सकल भारतीय संपत्ति में वृद्धि' तो हुई थी, परन्तु लोगों के सभी वर्गों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ था।<sup>18</sup> कृषि उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि से जमींदारों को तो फायदा हुआ था, परन्तु श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि मजदूरियों में कीमतों की समानुपाती वृद्धि नहीं हुई थी। अतः 'भारतीय जनता का भूमिहीन वर्ग अधिकाधिक फटेहाल वर्ग बन

गया है।<sup>19</sup> यद्यपि 'फ्रैंड आफ इंडिया' का दावा था कि उद्योग एवं वाणिज्य की तुलना में कृषि क्षेत्र पर कर अधिक थे,<sup>20</sup> तथापि 'टाइम्स आफ इंडिया' का मत था कि कृषि आय पर भी वास्तव में भारी कर नहीं थे। बरवई में निकलने वाले इम दैनिक पत्र का तर्क था कि मालगुजारी कर नहीं थी, अतः वास्तविक कर की राशि प्रति व्यक्ति लगभग 10 या 12 आने वापिक थी जो बहुत थोड़ी थी।<sup>21</sup> 'दि मंड्रिंग टाइम्स' कलकत्ता की पत्रिका से सहमत था। उसने लिखा कि भूमि कर, नमक शुल्क, आवकारी, (विलासिता पर कर जो भारत में अत्यंत निर्धन वर्ग की ही विलासिता पर कर था), स्टाम्प तथा सीमा शुल्क ये सभी निर्धनों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दिए जाते थे जबकि मंषन्न स्वदेशी व्यापारिक पूजीपति वर्ग को 'कराधान से अनुचित उन्मुक्ति' मिली हुई थी।<sup>22</sup> इस प्रकार सभी ऐंग्लो इंडियन अखबार दृढ़ता के साथ, लगभग पूर्ण सहमति से, यह कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति औसत कराधान कम था। जेम्स विल्सन द्वारा बतलाई गई समस्या कि भूमिधारी वर्ग को छोड़कर अन्य मंषन्न हिंदुस्तानी अपने हिस्से का कर भार नहीं उठा रहे हैं, के बारे में बहुत कुछ सहमति थी। अंत में, यह भी अस्पष्ट बोध हो रहा था कि निर्धन वर्ग को के भार से कुछ कष्ट का अनुभव कर रहे थे। परन्तु इस वर्ग की वास्तविक स्थिति के बारे में ठीक-ठीक नहीं पता था। ऐसा समझा जाता था कि कराधान के दबाव से ही दुर्भिक्ष पड़ा था। हाउस आफ कॉमंस की प्रवर समिति के सामने लोक मेवा के एक अधिकारी ने दावा किया था कि कराधान के दबाव से ही उड़ीसा का दुर्भिक्ष पड़ा था। 'करों के भुगतान के लिए जोड़कर रखे गए खाद्य पदार्थ दे दिए गए थे' और कराधान के दबाववश सभी खाद्य फसलों का निर्यात किया गया था जिससे दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई।<sup>23</sup> कुछ वर्ष बाद हिंडमैन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। उसने लिखा 'दुर्भिक्ष जो भारत का सर्वनाश करते रहे है, मुख्य रूप से वित्तीय दुर्भिक्ष है। शीघ्र खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने में इसलिए असमर्थ हैं, क्योंकि वे 'कराधान के दबाव के कारण, बचत कर पाने में असमर्थ हैं।'<sup>24</sup> परन्तु ये उग्रवादी विचार थे जिन्हें एंग्लो इंडियन अखबार केवल खंडन करने के लिए ही छापते थे।

भारतीय समाचार पत्रों ने राजकोपीय (फिस्कल) भार का सांख्यिकीय प्राक्कलन लगाने जैसा कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने लिखा कि करों का भार 'असह्य'<sup>25</sup> हो गया है, करों की अनेकरूपता तथा भार से स्पष्ट है कि अंग्रेजों की पराधीन जातियों के प्रति उत्कण्ठा पाखंडपूर्ण है,<sup>26</sup> कराधान अपनी न्यायोचित सीमा<sup>27</sup> पर पहुँच गया है, कर 'बूई की तरह चुभते हैं और हल के फात की तरह लगते हैं',<sup>28</sup> देशी राजाओं के शासन की तुलना में ब्रिटिश शासन में रहने वाले लोगों पर कर भारी है,<sup>29</sup> अंग्रेज जिस अनुपात में चाहते हैं, कर भार अन्यायपूर्वक बढ़ा देते हैं,<sup>30</sup> इत्यादि। परन्तु इन्होंने कोई भी परिमाणात्मक विवरण नहीं दिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने सामान्य ढंग से सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग हथिया लेने की निंदा की। एक स्मरण पत्र में संघ ने कहा कि 'पिछले दस वर्षों में राजस्व में जो भारी वृद्धि हुई है... उसका अर्थ है कि लोगों पर इसी अनुपात में भार बढ़ा है... यह वृद्धि चाहे भारतीय राजस्व के कुछ स्रोतों में स्वाभाविक लवच के कारण हुई हो अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष नए करों को लगाने में,

इसका प्रभाव यह पड़ा है कि 'राष्ट्र के सकल लाभ में इतनी ही कमी हो गई है' और इसके परिणामस्वरूप जीवन निर्वाह के साधनों अथवा आराम में भी कमी हुई है।<sup>31</sup>

1880 में वित्त आयोग को भेजे गए एक स्मरण पत्र में दादाभाई नौरोजी ने भी यही बात कही।<sup>32</sup> उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की कुल आय लगभग 34 करोड़ पौंड थी जबकि सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 6.5 करोड़ पौंड था।<sup>33</sup> उनके ही शब्दों में 'इंग्लैंड में सरकार के कार्यों के लिए (करो के रूप में राष्ट्रीय आय का) केवल 8 प्रतिशत लिया जाता है... जबकि भारत में इसी उद्देश्य के लिए 22 प्रतिशत लिया जाता है फिर भी लोग घृण्डता एवं निर्भरता के साथ लिखते हैं कि भारत में हुनके कर लगाए गए हैं।'<sup>34</sup> नौरोजी ने यह स्वीकार किया था कि ये अनुमान पूर्णरूप से विश्वसनीय नहीं हैं परंतु उन्हें इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि भारत में सरकार द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय संपत्ति का अनुपात इंग्लैंड के अनुपात से कहीं अधिक था।<sup>35</sup> नौरोजी भारत की राजनीतिक निर्भरता और निर्णयकारी संस्थाओं में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अभाव इस समस्या का कारण समझते थे।

'दृढ़तापूर्वक चलाए गए अनेक संघर्षों के बाद इंग्लैंड की राजनीति में स्थाई रूप से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई है कि प्रतिनिधित्व रहित कराधान विकृत होकर निरंकुशता में परिणत हो जाता है। यही सिद्धांत शक्ति के दुरुपयोग से विश्वसनीय बचाव है... भारत में कराधान की अविवेचित योजनाएं, इनके विषय में केवल सरकारी भावनाओं के आधार पर या तो अज्ञानतावश या फिर लोकमत की उपेक्षा करते हुए बनाई जाती हैं और उन्हें कार्यान्वित भी किया जाता है।'<sup>36</sup> 5 सितंबर, 1860 के 'हिंदू पेट्रिट' की इस संपादनीय टिप्पणी से ब्रिटिश प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रशंसा और भारत में इस प्रकार की संस्थाओं के अभाव के प्रति धैर्यरहित आक्रोश दोनों ही विशेष रूप से प्रकट होते हैं। तथापि उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय मत को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई सुनिश्चित योजना (सिवाय विधान परिषद में 'अतिरिक्त सदस्यों' के रूप में कुछ प्रमुख व धनी-मानी व्यक्तियों के मनोनयन के) प्रस्तुत नहीं की गई थी !

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अपने आपको कुछ सामान्य बातों तक ही सीमित रखा था। जैसे इन्होंने कहा कि सरकार लोकमत की ओर ध्यान देने में असफल रही है; सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय जानकारी अपूर्ण एवं विलंबित रहती है, इत्यादि।<sup>37</sup> 1868 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में बैठक हुई जिसका उद्देश्य भारत मंत्री के सामने स्मरणपत्र के रूप में एक सुनिश्चित योजना प्रस्तुत करना था। स्मरणपत्र में एसोसिएशन ने इस बात की निंदा की कि 'भारत की जनता की वित्त के प्रबंध में यथार्थ में कोई आवाज नहीं है। यही नहीं, उसे वित्तीय उपायों के बारे में विचार विमर्श करने के पर्याप्त अवसर समय पर नहीं प्रदान किए जाते।'<sup>38</sup> कराधान संबंधी उपायों को अजट पेश होने के लगभग साय-प्राय ही पारित कर दिया जाता था। इससे लोकमत की अभिव्यक्ति के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता था। एक अन्य स्थान पर स्मरण पत्र में कहा गया कि 'तथापि, भारत के करदाताओं को इससे कुछ संतोष मिलेगा यदि



राज्य की अर्थोपाय व्यवस्था में उनकी भी कुछ आवाज हो। सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में कराधान और प्रतिनिधित्व सहगामी हैं, परंतु इंग्लैंड के भारत के साथ विशिष्ट संबंधों को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि यदि अन्य परिस्थितियों को छोड़ भी दिया जाए तो राजनीतिक कारणों से सपरिपद गवर्नर जनरल को वित्तीय मामलों में पूर्ण अधिकार होने चाहिए। यह व्यवस्था उस नीति की विरोधी नहीं... कि वित्त के नियमन और नए कर लगाने के बारे में जनता का विश्वास प्राप्त करना और उनके विचारों एवं भावनाओं को पता करना चाहिए।<sup>39</sup> स्मरणपत्र में एक बड़े परामर्श परिपद जिसके सदस्यों में साम्राज्य के विविध भागों से हिंदुस्तानी तथा अंग्रेज भद्र पुरुष हों... के गठन का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित परिपद को अधिकार दिया जाना था कि वह वित्तीय मामलों से संबंधित कागजात और कोई भी सूचना माग सके और बजट पास होने से पहले उसका पुनर्विलोकन कर सके। परंतु यह परिपद केवल विचार विमर्श के लिए ही बनाई जानी थी। इसे मत देने का अधिकार नहीं भी दिया जा सकता था। इसके सभी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। यह प्रस्ताव सरकार को स्वीकार्य नहीं था। सरकार की राय में इस प्रकार की परिपद 'जनता की आकांक्षाओं का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी।'<sup>40</sup> 'हिंदू पेट्रिअट' ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'हमें विश्वास हो चला है कि सरकार अब अधिक समय तक काल की गति को जो उसके विरुद्ध बढ़ रही है, पीछे नहीं धकेल सकती।'<sup>41</sup> कुछ अन्य हिंदुस्तानी समाचारपत्रों ने भी कर दाता को प्रतिनिधित्व देने की मांग का समर्थन किया। बंगाल के 'सोम प्रकाश' तथा बंबई के 'जामे जमशेद' ने इस मांग को अपना समर्थन प्रदान किया।<sup>42</sup> ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सरकार के पास स्मरणपत्र भेजता रहा। 1869 में भारत मंत्री के पास भेजे गए एक स्मरणपत्र में मांग की गई कि गृह खर्चों का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए (जिससे करदाताओं के लिए अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकना संभव हो)।<sup>43</sup> 1871 में मांग की गई कि वित्त का विकेंद्रीकरण किए जाने पर स्थानीय प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।<sup>44</sup> इस समस्या पर मेयो ने गोपनीय ढंग से विलकुल ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। उसने नैपियर को लिखा था कि 'लोग कहते हैं कि यह प्रक्रिया लंबी होगी। यह हो भी सकता है। मेरे विचार से यह उससे छोटी होगी जितनी कि लोग समझते हैं। जो भी हो, यह प्रशासन की नई प्रणाली प्रारंभ करने का समय है जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन में भारत के मूल निवासियों के हमारे साथ संबंध बढ़ाने के लिए रास्ता खुलेगा।'<sup>45</sup> परंतु शिक्षित और राजनीतिक दृष्टि से सचेतन वर्ग वित्तीय नियंत्रण की दिशा में घीमी प्रगति और मबंधानिक व्यवस्थाओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट था। 'हिंदू पेट्रिअट' ने लिखा कि 'ब्रिटिश संबंधानिक व्यवस्थाओं की सकल कर लेना, विधान परिपद में बजट प्रस्तुत करना, और उस पर कृत्रिम विचार विमर्श करना बहुत अच्छा है, परंतु यह अर्थहीन तमाशाबाजी है... यद्यपि मिस्र राजाओं महाराजाओं तथा सरदारों की अपने ढंग से उपयोगिता है, तथापि वे महामहिपी (महारानी) की भारतीय प्रजा का उससे अधिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जितना कि ब्रिटिश मंसद में इंग्लैंड की जनता की प्रतिनिधित्व सुई नेपोनियन अथवा विक्टर एमन्यूअल

करते थे।<sup>46</sup> सरकार को शासन का उत्तरदायित्व 'जनता के सहज नेताओं के साथ वांटने के लिए तत्पर रहना चाहिए।'<sup>47</sup> यह स्वीकार किया गया कि 'व्यक्ति, विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता' ब्रिटिश शासन में ही प्राप्त हुई थी। 'हिंदू पेट्रिअट' ने फिर लिखा 'परंतु इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता है कि विधान परिषद स्वांग है, उसके सरकारी और गैर सरकारी अतिरिक्त सदस्य प्रभावशून्य हैं और यद्यपि कानून के अनुसार हिंदुस्तानियों को परिषद की सदस्यता देने की व्यवस्था की गई है तथापि शिक्षित वर्गों की लगातार उपेक्षा की जाती है....'<sup>48</sup>

यह मान लेना भूल होगी कि सरकार लोकमत की बढ़ती हुई शक्ति को पूरी तरह से भुलाकर घंटी थी। यद्यपि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विविध आवेदनों (भारतीय समाज के विविध वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था करना, जो विधान परिषद में अतिरिक्त हिंदुस्तानी सदस्यों के मनोनयन की प्रचलित व्यवस्था में संभव नहीं था) को सरकार द्वारा बार-बार अस्वीकार कर दिया गया, तथापि समझदार नौकरशाह लोकमत की पूरी तरह उपेक्षा नहीं कर सके। उदाहरणार्थ, बार्टल फ़ेरे लोकमत की प्रवृत्ति के अध्ययन की आवश्यकता के विषय में बहुत सजग था। फ़ेरे ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक (9 जून, 1871) में कहा था कि 'कभी-कभी लोग भारत में लोकमत की उपेक्षा करते हैं अथवा उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं, परंतु पुराने दिनों में भारत आने वाले अंग्रेजों जैसे माल्कम, मुनरो, मंटकाफ तथा एल्फिंस्टन ने 'लोगों के विचारों और भावनाओं को महसूस किया था और वे लोकमत के बारे में उपर्युक्त विचार से प्रेरित नहीं थे।'<sup>49</sup> वित्तीय कठिनाई एक अन्य कारण थी जिसकी वजह से भी सरकार को हिंदुस्तानियों की भावनात्मक स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए था। लार्ड मेयो ने भी पाया कि 'व्यय की विविध मदों के बारे में भारत के लोग काफी सचेत हो रहे हैं।'<sup>50</sup> एक अन्य प्रेक्षक ने लिखा कि 'लोगों के पास संपत्ति और शिक्षा में वृद्धि से स्वतंत्रता की भावना तथा बुद्धिमत्ता आ गई है। समझदारी की बात यह है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारी प्रजा के अधिकाधिक लोग अब सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का रुचि लेकर सूक्ष्म परीक्षण करते हैं और उस पर बड़ी समझदारी के साथ बहस करते हैं। लोग अब तेजी से अज्ञानी अविवेकी समूह की स्थिति से, जिसे अपने शासकों की बुद्धिमत्ता में आस्था होती थी, ऊपर उठ रहे हैं।'<sup>51</sup>

प्रश्न उठता है कि यदि सरकार भारत में विकसित हो रहे लोकमत के बारे में जानकारी रखती थी तो इसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तथा दूसरों की मांगों को पूरा क्यों नहीं किया। प्रथम कारण यह है कि अंग्रेजी अर्थ में 'लोकमत' भारत में नई चीज था। यह विकास की प्रारंभिक अवस्था में था। सरकार का दावा था कि वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों की तथ्यों पर आधारित एवं जानकार आलोचना बिलकुल नहीं की जाती थी। द्वितीय, सरकार का विचार था कि समाचारपत्रों में जो कुछ लिखा जाता था वह लोकमत को ठीक-ठीक भी नहीं व्यक्त करता था। जैसा कि बार्टल फ़ेरे ने लिखा कि प्रकाशित मत सदैव ही लोकमत नहीं होता। अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों ही समाचार पत्र जनता के बहुत छोटे से वर्ग के विचार प्रतिबिंबित करते थे।<sup>52</sup> मेयो के अनुसार समाचार

राज्य की अर्थोपाय व्यवस्था में उनकी भी कुछ आवाज हो। सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में कराधान और प्रतिनिधित्व सहगामी है, परंतु इंग्लैंड के भारत के साथ विशिष्ट संबंधों को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि यदि अन्य परिस्थितियों को छोड़ भी दिया जाए तो राजनीतिक कारणों से सपरिषद गवर्नर जनरल को वित्तीय मामलों में पूर्ण अधिकार होने चाहिए। यह व्यवस्था उस नीति की विरोधी नहीं... कि वित्त के नियमन और नए कर लगाने के बारे में जनता का विश्वास प्राप्त करना और उनके विचारों एवं भावनाओं को पता करना चाहिए।<sup>139</sup> स्मरणपत्र में एक बड़ी परामर्श परिषद जिसके सदस्यों में साम्राज्य के विविध भागों में हिंदुस्तानी तथा अंग्रेज भद्र पुरुष हों... के गठन का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित परिषद को अधिकार दिया जाना था कि वह वित्तीय मामलों से संबंधित कागजात और कोई भी सूचना मांग सके और बजट पास होने से पहले उसका पुनर्विलोकन कर सके। परंतु यह परिषद केवल विचार विमर्श के लिए ही बनाई जानी थी। इसे मत देने का अधिकार नहीं भी दिया जा सकता था। इसके सभी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। यह प्रस्ताव सरकार को स्वीकार्य नहीं था। सरकार की राय में इस प्रकार की परिषद 'जनता की आकांक्षाओं का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी।'<sup>140</sup> 'हिंदू पेट्रिअट' ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'हमें विश्वास हो चला है कि सरकार अब अधिक समय तक काल की गति को जो उसके विरुद्ध बढ़ रही है, पीछे नहीं धकेल सकती।'<sup>141</sup> कुछ अन्य हिंदुस्तानी समाचारपत्रों ने भी कर दाता को प्रतिनिधित्व देने की मांग का समर्थन किया। बंगाल के 'सौम प्रकाश' तथा बंबई के 'जामे जमशेद' ने इस मांग को अपना समर्थन प्रदान किया।<sup>142</sup> ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सरकार के पास स्मरणपत्र भेजता रहा। 1869 में भारत मंत्री के पास भेजे गए एक स्मरणपत्र में मांग की गई कि गृह खर्चों का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए (जिससे करदाताओं के लिए अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकना संभव हो)।<sup>143</sup> 1871 में मांग की गई कि वित्त का विकेंद्रीकरण किए जाने पर स्थानीय प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।<sup>144</sup> इस समस्या पर मेयो ने गोपनीय ढंग से बिलकुल ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। उसने नैपियर को लिखा था कि 'लोग कहते हैं कि यह प्रक्रिया लंबी होगी। यह हो भी सकता है। मेरे विचार से यह उससे छोटी होगी जितनी कि लोग समझते हैं। जो भी हो, यह प्रशासन की नई प्रणाली प्रारंभ करने का समय है जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन में भारत के मूल निवासियों के हमारे साथ संबंध बढ़ने के लिए रास्ता खुलेगा।'<sup>145</sup> परंतु शिक्षित और राजनीतिक दृष्टि से सचेतन वर्ग वित्तीय नियंत्रण की दिशा में घीमी प्रगति और संवैधानिक व्यवस्थाओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट था। 'हिंदू पेट्रिअट' ने लिखा कि 'ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्थाओं की नकल कर लेना, विधान परिषद में बजट प्रस्तुत करना, और उस पर कृत्रिम विचार विमर्श करना बहुत अच्छा है, परंतु यह अर्थहीन तमाशावाजी है... यद्यपि मित्त राजाओं महाराजाओं तथा सरदारों की अपने ढंग से उपयोगिता है, तथापि वे महामहिषी (महारानी) की भारतीय प्रजा का उससे अधिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जितना कि ब्रिटिश मंसद में इंग्लैंड की जनता की प्रतिनिधित्व लुई नेपोनियन अथवा चिकटर एर्मनूअल



पत्रों में कुछ मुखर व्यक्तियों के विचार ही प्रकट होते थे और 'बहुत सारे खामोश व्यक्तियों के विचार मालूम करने का कोई साधन नहीं था। मेयो अंग्रेजों के स्वामित्व में निकलने वाले समाचारपत्रों को जो गैर सरकारी यूरोपियनों (व्यापार तथा उद्योग में लगे हुए यूरोपियन जो 'यहां पर काले लोगों से यथासंभव रूपया ऐंठने के लिए आए थे') के हितों का ही समर्थन करते थे और बाबुओं के द्वारा निकाले जाने वाले हिंदुस्तानी अखबारों का जो जनसाधारण के हितों की ओर ध्यान न देकर अपने ही हित साधन में लगे हुए थे, घृणामिश्रित तिरस्कार के साथ देखता था।<sup>53</sup> गवर्नर जनरल लारेंस ने भी अनुभव किया था कि 'जिस वर्ग की आवाजें सुनाई पड़ती हैं उसके और जनसाधारण के बीच जो मुश्किल से जीविका ही चला पाता है, खाई है।'<sup>54</sup> भारत मंत्री को भेजे जाने वाले अपने एक प्रेषण में भारत सरकार ने 'वर्गीयमत' और 'लोकमत' में भेद किया था। लोकमत 'केवल सार्वजनिक गोष्ठियों में एकत्रित होने वाले वर्गों का ही मत नहीं होना चाहिए, अपितु महामहिषी (महारानी) की प्रजा में से उन लाखों लोगों का मत होना चाहिए जो राजकोप में अपना योगदान करते हैं ...'<sup>55</sup> जब 1868 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने एक परामर्श परिपद 'जिसके सदस्य योग्य हिंदुस्तानी और यूरोपियन भद्र पुरुष होते थे, के गठन का सुझाव दिया था तो भारत सरकार ने इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की संस्था केवल 'उन थोड़े से वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी जिनका स्पष्ट उद्देश्य अपने आपको करो से बचाना होगा।'<sup>56</sup> भारत भ्रमण के लिए आए हुए एक अंग्रेज पत्रकार के सशक्त शब्दों में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सामान्यतः 'संगठित स्वार्थपरता की एक व्यवस्था' माना जाता था।<sup>57</sup> यह सत्य है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का यथार्थ में जमींदारों का संघ होने के कारण, यूरोपियन चैम्बर आफ कामर्स की भांति ही एक सुसज्जित वर्ग चरित था। यह भी सत्य है कि यह संघ और हिंदुस्तानी समाचारपत्र सामान्य लोगों के हितों की तुलना में जमींदारों, संपन्न व्यवसायिक वर्गों, दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों इत्यादि के हितों के प्रति अधिक सजग थे। उदाहरण के लिए यह बात जनसाधारण पर पड़ने वाले नमक शुल्क तथा दूसरे अप्रत्यक्ष कर कि ऊंची दरों को इनके द्वारा समर्थन से प्रकट होती है, क्योंकि इससे संपन्न वर्गों के लिए आय कर, व्यवसायो पर लाइसेंस कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों से, जो संपत्तिवान एवं व्यवसायी वर्गों को ही प्रभावित करते थे, बच सकना संभव हो सकता था। तथापि भारत में एकमात्र राजनीतिक चेतना संपन्न और मुखर वर्ग को प्रतिनिधित्व न देना, स्पष्टतया नीति विरुद्ध होता जा रहा था।

इस बारे में केवल अटकलवाजी ही संभव है कि यदि इस वर्ग का निर्णय प्रक्रिया पर प्रधान असर होता तो वित्तीय नीतियां क्या होती। यहां पर कुछ नीति विषयक मामलों पर भारत में 'लोकमत' की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण कर लेना अधिक उपयोगी होगा।

हिंदुस्तानी और एंग्लो इंडियन समाचारपत्र, आश्चर्यजनक पूर्ण सहमति से, हर प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान के विरोध में थे। दूसरी ओर उनका सुझाव था कि नमक शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए। सभी परोक्ष करों में नमक कर सबसे निर्धन वर्गों को प्रभावित करता था और प्रत्यक्ष कर केवल मध्यम और ऊंची आय वाले वर्गों पर होते थे। जेम्स विल्सन

के आय कर अधिनियम विवाद से, जिसके विषय में हम पहले लिख आए हैं, प्रत्यक्ष कराधान के पक्ष और विपक्ष में बार-बार दिए गए सारे तर्क उभरकर सामने आ गए थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की प्रतिक्रिया ठीक वही थी जो 'संपत्तिवान' एवं 'प्रबुद्ध' वर्ग की होती है। इसकी राय में नमक शुल्क कराधान का 'सबसे कम आपत्ति जनक' रूप था। इस प्रकार के कराधान के विपरीत कुछ भी आपत्ति क्यों न हो, इसके बड़े से बड़े दोष आय कर अथवा प्रत्यक्ष कराधान की ऐसी ही किसी अन्य प्रणाली के अत्याचार, खतरे और उत्साह भंग करने वाले प्रभावों की तुलना में वरदान ही सिद्ध होंगे।<sup>57A</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में एंग्लो इंडियन पत्रिकाओं और चेंबर आफ कामर्स ने निरंतर इसी प्रकार के तर्क दिए। कुछ उदाहरण हैं, जनता 'प्रसन्नतापूर्वक' परोक्ष करों को सहन करेगी। (मद्रास एक्जामिनर); जहां आय कर 'बहुत अग्रिय' है, वही नमक शुल्क 'कृपि तथा श्रम जीवी वर्गों की वार्षिक आय में से बहुत थोड़ी कटौती है' (बंगाल चेंबर आफ कामर्स); आय कर ने ब्रिटिश भारत के उन 'सभी वर्गों तथा जातियों' को एकता के सूत्र में बांध दिया है जो सबके साथ हुए अन्याय के बारे में सहमत है (पायनिर); 'निर्धन वर्गों पर' भूमि कर और शुल्क के रूप में कर भार नाम मात्र है (टाइम्स आफ इंडिया); लाइसेंस शुल्क और आय कर द्वारा अधिक उद्यमशील वर्ग 'अपने परिश्रम के फल' से वंचित किया जाता है (कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन); आय कर से निष्ठावान वर्ग के साथ 'अधिकतम अन्याय करने के बाद अल्पतम राजस्व' की प्राप्ति हो रही है (इग्लिसमैन)।<sup>58</sup> इस प्रकार के निरर्थक तर्कों के पीछे प्रयोजन स्पष्ट है। मेयो ने यूरोपीय अधिकारियों, जो भारत को अपनी दुधारू गाय समझते थे, अंग्रेज व्यापारियों, 'जिनका कम से कम समय में अधिकाधिक धन कमाकर इंग्लैंड में निष्क्रिय जीवन बिताने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं था'; और 'संपन्न हिंदुस्तानियों जिनकी कराधान के संबंध में एकमात्र धारणा निर्धन की आय का अपहरण ही है' की अज्ञानता, स्वार्थपरता तथा दुर्भाव के विषय में काफ़ी घृणा के साथ लिखा है।<sup>59</sup> कौनिंग ने संपन्न हिंदुस्तानियों की स्वार्थी प्रकृति और एंग्लो इंडियन वर्गों के प्रत्यक्ष कराधान पर संगठित प्रहारों की पील खोलने के अवसर से लाभ उठाया। उसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबद्ध राजा राधाकांत देव को लिखा कि 'आय कर के स्थान पर नमक पर कर लगाने का अर्थ है निर्धन के बल पर धनी व्यक्तियों को छूट देना'।<sup>60</sup> बंबई के इंडियन इकानामिस्ट तथा सीरामपुर के फ्रैंड आफ इंडिया के अतिरिक्त किन्हीं भी समाचारपत्रों ने नीची आय वाले वर्गों पर विभिन्न प्रकार के परोक्ष करों का भार हलका करने के लिए प्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता को कभी भी स्वीकार नहीं किया।<sup>61</sup> प्रत्यक्ष कराधान के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया थी क्योंकि सरकार ने सातवें दशक में पहली बार 'खामोश जनसाधारण के स्थान पर चीख पुकार मचाने वाले थोड़े से लोग' पर कर लगाया था।<sup>62</sup>

प्रत्यक्ष करों के विरुद्ध एक हो जाने वाले सभी वर्गों के हित एक सद्दृश नहीं थे। प्रत्यक्ष कराधान की निंदा करते समय एक होते हुए भी प्रत्येक गुट अपने हितों की रक्षा करता था। नीची आय वाले वर्ग ने आरोही कराधान का सुझाव दिया था। सरकारी तथा वाणिज्यिक दफ्तरों में नौकरी करने वाले क्लर्कों ने समान दर के स्थान पर क्रमवद्ध

पत्रों में कुछ मुखर व्यक्तियों के विचार ही प्रकट होते थे और 'बहुत सारे खामोश व्यक्तियों के विचार मालूम करने का कोई साधन नहीं था। मेथी अंग्रेजों के स्वामित्व में निकलने वाले समाचारपत्रों को जो गैर सरकारी यूरोपियनों (व्यापार तथा उद्योग में लगे हुए यूरोपियन जो 'यहां पर काले लोगों से यथासंभव रुपया ऐंठने के लिए आए थे') के हितों का ही समर्थन करते थे और वायुओं के द्वारा निकाले जाने वाले हिंदुस्तानी अखबारों का जो जनसाधारण के हितों की ओर ध्यान न देकर अपने ही हित साधन में लगे हुए थे, घुणामिश्रित तिरस्कार के साथ देखता था।<sup>53</sup> गवर्नर जनरल लारेंस ने भी अनुभव किया था कि 'जिस वर्ग की आवाजें सुनाई पड़ती हैं उसके और जनसाधारण के बीच जो मुश्किल से जीविका ही चला पाता है, ग्राई है।'<sup>54</sup> भारत मंत्री को भेजे जाने वाले अपने एक प्रेषण में भारत सरकार ने 'वर्गीयमत' और 'लोकमत' में भेद किया था। लोकमत 'केवल सार्वजनिक गोष्ठियों में एकत्रित होने वाले वर्गों का ही मत नहीं होना चाहिए, अपितु महामहिषी (महारानी) की प्रजा में से उन लोगों लोगों का मत होना चाहिए जो राजकोष में अपना योगदान करते हैं'।<sup>55</sup> जब 1868 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने एक परामर्श परिषद 'जिसके सदस्य योग्य हिंदुस्तानी और यूरोपियन भद्र पुरुष होते थे, के गठन का सुझाव दिया था तो भारत सरकार ने इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की संस्था केवल 'उन थोड़े से वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी जिनका स्पष्ट उद्देश्य अपने आपको करों से बचाना होगा।'<sup>56</sup> 'भारत भ्रमण के लिए आए हुए एक अंग्रेज पत्रकार के सशक्त शब्दों में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सामान्यतः 'संगठित स्वायंभूतता की एक व्यवस्था' माना जाता था।<sup>57</sup> यह सत्य है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का यथार्थ में जमींदारों का संघ होने के कारण, यूरोपियन चेंबर्स आफ कामर्स की भांति ही एक सुस्पष्ट वर्ग चरित्र था। यह भी सत्य है कि यह संघ और हिंदुस्तानी समाचारपत्र सामान्य लोगों के हितों की तुलना में जमींदारों, संपन्न व्यवसायिक वर्गों, दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों इत्यादि के हितों के प्रति अधिक सजग थे। उदाहरण के लिए यह बात जनसाधारण पर पड़ने वाले नमक शुल्क तथा दूसरे अप्रत्यक्ष कर कि ऊंची दरों की इनके द्वारा समर्थन से प्रकट होती है, क्योंकि इससे संपन्न वर्गों के लिए आय कर, व्यवसायों पर लाइसेंस कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों से, जो संपत्तिवान एवं व्यवसायी वर्गों को ही प्रभावित करते थे, बच सकना संभव हो सकता था। तथापि भारत में एकमात्र राजनीतिक चेतना संपन्न और मुखर वर्ग को प्रतिनिधित्व न देना, स्पष्टतया नीति विरुद्ध होता जा रहा था।

इस बारे में केवल अटकलबाजी ही संभव है कि यदि इस वर्ग का निर्णय प्रक्रिया पर प्रधान असर होता तो वित्तीय नीतियां क्या होती। यहां पर कुछ नीति विषयक मामलों पर भारत में 'लोकमत' की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण कर लेना अधिक उपयोगी होगा।

हिंदुस्तानी और एंग्लो इंडियन समाचारपत्र, आश्चर्यजनक पूर्ण सहमति से, हर प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान के विरोध में थे। दूसरी ओर उनका सुझाव था कि नमक शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए। सभी परोक्ष करों में नमक कर सबसे निर्धन वर्गों को प्रभावित करता था और प्रत्यक्ष कर केवल मध्यम और ऊंची आय वाले वर्गों पर होते थे। जेम्स विल्सन

के आय कर अधिनियम विवाद से, जिसके विषय में हम पहले लिख आए हैं, प्रत्यक्ष कराधान के पक्ष और विपक्ष में बार-बार दिए गए सारे तर्क उभरकर सामने आ गए थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की प्रतिक्रिया ठीक वही थी जो 'संपत्तिवान' एवं 'प्रबुद्ध' वर्ग की होती है। इसकी राय में नमक शुल्क कराधान का 'सबसे कम आपत्ति जनक' रूप था। इस प्रकार के कराधान के विपरीत कुछ भी आपत्ति क्यों न हो, इसके बड़े से बड़े दोष आय कर अथवा प्रत्यक्ष कराधान की ऐसी ही किसी अन्य प्रणाली के अत्याचार, खतरे और उत्साह भंग करने वाले प्रभावों की तुलना में बरदान ही सिद्ध होंगे।<sup>57A</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में एंग्लो इंडियन पत्रिकाओं और चेंबर आफ कामर्स ने निरंतर इसी प्रकार के तर्क दिए। कुछ उदाहरण हैं, जनता 'प्रसन्नतापूर्वक' परोक्ष करों को सहन करेगी। (मद्रास एक्जामिनर); जहां आय कर 'बहुत अप्रिय' है, वही नमक शुल्क 'कृपि तथा श्रम जीवी वर्गों की वार्षिक आय में से बहुत थोड़ी कटौती है' (बंगाल चेंबर आफ कामर्स); आय कर ने ब्रिटिश भारत के उन 'सभी वर्गों तथा जातियों' को एकता के सूत्र में बांध दिया है जो सबके साथ हुए अन्याय के बारे में सहमत हैं (पायनिर); 'निधन वर्गों पर' भूमि कर और शुल्क के रूप में कर भार नाम मात्र है (टाइम्स आफ इंडिया); साइसेंस शुल्क और आय कर द्वारा अधिक उद्यमशील वर्ग 'अपने परिश्रम के फल' से वंचित किया जाता है (कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन); आय कर से निष्ठावान वर्ग के साथ 'अधिकतम अन्याय करने के बाद अल्पतम राजस्व' की प्राप्ति हो रही है (इंग्लिसमैन)।<sup>58</sup> इस प्रकार के निरर्थक तर्कों के पीछे प्रयोजन स्पष्ट है। मेयो ने यूरोपीय अधिकारियों, जो भारत को अपनी दुधारू गाय समझते थे, अंग्रेज व्यापारियों, 'जिनका कम से कम समय में अधिकाधिक धन कमाकर इंग्लैंड में निष्क्रिय जीवन बिताने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं था'; और 'संपन्न हिंदुस्तानियों जिनकी कराधान के संबंध में एकमात्र धारणा निधन की आय का अपहरण ही है' की अज्ञानता, स्वार्थपरता तथा दुर्भाव के विषय में काफी घृणा के साथ लिखा है।<sup>59</sup> कनिंग ने संपन्न हिंदुस्तानियों की स्वार्थी प्रकृति और एंग्लो इंडियन वर्गों के प्रत्यक्ष कराधान पर संगठित प्रहारों की पोल खोलने के अवसर से लाभ उठाया। उसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबद्ध राजा राधाकांत देव को लिखा कि 'आय कर के स्थान पर नमक पर कर लगाने का अर्थ है निधन के बल पर धनी व्यक्तियों को छूट देना।'<sup>60</sup> बंबई के इंडियन इकानामिस्ट तथा सीरामपुर के फ्रीड आफ इंडिया के अतिरिक्त किन्हीं भी समाचारपत्रों ने नीची आय वाले वर्गों पर विभिन्न प्रकार के परोक्ष करों का भार हलका करने के लिए प्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता को कभी भी स्वीकार नहीं किया।<sup>61</sup> प्रत्यक्ष कराधान के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया थी क्योंकि सरकार ने सातवें दशक में पहली बार 'खामोश जनसाधारण के स्थान पर चीख पुकार मचाने वाले थोड़े से लोगो' पर कर लगाया था।<sup>62</sup>

प्रत्यक्ष करों के विरुद्ध एक हो जाने वाले सभी वर्गों के हित एक सदृश नहीं थे। प्रत्यक्ष कराधान की निंदा करते समय एक होते हुए भी प्रत्येक गुट अपने हितों की रक्षा करता था। नीची आय वाले वर्ग ने आरोही कराधान का सुझाव दिया था। सरकारी तथा वाणिज्यिक दफतरो में नौकरी करने वाले क्लर्कों ने समान दर के स्थान पर क्रमबद्ध



मान की आवश्यकता के बारे में सरकार के पास स्मरणपत्र भेजा।<sup>63</sup> बेतन भोगी वर्ग, जिन पर भारी कर लगाए गए थे, 'बनियो, साहूकार तथा पारसी करोड़पतियों की ओर, जो ब्रिटिश शासन के लाभ उठाते हुए भी करों से बचे हुए थे, ईर्ष्या के साथ देखते थे।'<sup>64</sup> व्यवसायी तथा उद्यमी वर्ग कर के अनौचित्य पर रुष्ट थे, क्योंकि वह उनकी अपनी आय जो 'परिश्रम का फल' थी और लगान निष्क्रिय जीवियों, पूँजी निवेशकों, जमींदारों तथा संपत्तिधारी की निष्क्रिय व्यक्तियों की आय में अंतर नहीं करता था।<sup>65</sup> व्यापारी इसलिए क्रुद्ध थे कि 'संपत्ति जब निष्क्रिय पड़ी रहकर स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य का भला नहीं करती तब तो वह कर मुक्त होती है, परंतु जैसे ही उसे उत्पादन कार्य में लगाया जाता है और वह देश के साथ-साथ संपत्ति के स्वामी के धन और समृद्धि में वृद्धि करने लगती है, उस पर कर लगा दिया जाता है।'<sup>66</sup> एंग्लो इंडियन मत आय कर के स्थान पर अथवा उसके अलावा भी, उत्तराधिकार कर के पक्ष में था, क्योंकि उत्तराधिकार कर मुख्य रूप से वास्तविक संपत्ति के मालिक भारतीयों पर ही पड़ना था, और अंग्रेज जो धन कमा लेने के बाद स्वदेश लौट जाते थे, इस कर से बचे रह सकते थे।<sup>67</sup> इन सभी बद्धिंत गुटों द्वारा दिए गए अलग-अलग तर्कों एक बिंदु पर पहुंच कर मिल जाते थे कि उनकी आय पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर, जैसा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा था 'अनुपयुक्त और अनैतिक' थे।

यह ध्यान देना बड़ा ही कौतूहलपूर्ण होगा कि इस काल में सार्वजनिक विवादों में नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न बहुधा मिल जाते थे और फिर इन्हें एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता था। इसका एक अच्छा उदाहरण अफीम का प्रश्न है। इंग्लैंड और भारत में बहुत बड़ा मत नैतिक व अन्य आधारों पर अफीम के व्यापार के विरुद्ध था। एक अवसर पर श्री ग्राइट ने कहा था कि इससे अधिक बुरा व्यापार अथवा यों कहें कि ऐसा व्यापार जिसके परिणाम इससे अधिक घृणित हों संभवतः अफ्रीकियों को उनके देश से अमरीकी महाद्वीप ले जाने के अतिरिक्त दूसरा नहीं रहा है।<sup>68</sup> कई वर्षों तक निरंतर अनेक संसद सदस्यों ने जिनमें कर्नल साइक्स, किर्नैंड, आर० एन० फाउलर, सर डब्ल्यू० लाउसन, स्टीफन केव, एम० फाउलर आदि थे, विशेष रूप से अफीम के व्यापार के साथ सरकार के प्रत्यक्ष संबंध के कारण उसके नैतिक दृष्टि से निंदनीय स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित किया।<sup>69</sup> भारतीय विषयो पर लिखी गई पुस्तकों में से दो पर यहाँ विचार किया जा सकता है। इनमें से एक डोनाल्ड मैथेसन द्वारा लिखित 'व्हाट इज ओपियम ट्रेड' है। इस पुस्तक में दावा किया गया था कि 'अफीम द्वारा किया गया अनर्थ चीन में ईसाई धर्म की स्वीकृति में एक सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुआ।'<sup>70</sup> कभी-कभी यह तर्क दिया जाता था कि अफीम पर एकाधिकार ब्रिटेन के मदिरा पर कर से बुरा नहीं है। मैथेसन लिखता है 'परंतु यह तुलना पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार भी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, मदिरा से प्राप्त होने वाला राजस्व उसमें सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि एक ओर तो इससे सरकार की आय में वृद्धि होती है और दूसरी ओर यह लागत को बढ़ाकर इस हानिकार पदार्थ के उपभोग को कम करता है। सरकार को अफीम से राजस्व पहूँचे तो इस विनाशकारी पदार्थ के उत्पादन से और फिर निपेधाज्ञाओं और निर्बल एवं गैर ईसाई राष्ट्र, जिसकी

नैतिक भावनाओं को हमारे कार्य से धक्का पहुंचता है, के विरोध के बावजूद उपभोग को प्रोत्साहन देकर प्राप्त होता है।<sup>71</sup> 'दि गवर्नमेंट आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स मोनोपलीज और दि यंग इंडिया पार्टी एंड फ्री ट्रेड' नामक पैफलेट में अफीम के एकाधिकार को अतीत का कालदोषयुक्त अवशेष कहकर इसकी निंदा की गई। लेखक माल्कम लेविन का कहना था कि सभी एकाधिकार बुरे हैं, परंतु अफीम पर एकाधिकार इन सबमें बुरा है।<sup>72</sup> उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में सरकार द्वारा अफीम के व्यापार के विरोध में मत बहुत सबल हो गया और 1874 में अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन पूर्ण रूप से संगठित था। इसी वर्ष भारत में अफीम विरोधी समाज की स्थापना की गई।<sup>73</sup>

भारत में ऐंग्लो इंडियन समुदाय के एक वर्ग का मत सरकार के अफीम पर एकाधिकार के विरुद्ध था। 'फ्रीड आफ इंडिया' ने लिखा कि इस प्रकार का एकाधिकार उतना ही अशोभनीय था जितना कि महामहिपी (महारानी) के स्वामित्व में मदिरा की दुकानें चलाना।<sup>74</sup> एकाधिकारों में अंतिम अफीम का एकाधिकार तो 'हमारे प्रशासन के लिए कलक' है।<sup>75</sup> यह अकारण ही आरोप नहीं लगाया गया था कि सरकार न केवल अफीम का उत्पादन ही, अपितु उसमें सट्टेबाजी भी कर रही है।<sup>76</sup> यह एकाधिकार 'पुराने दिनों के वाणिज्यिक भ्रष्टाचार' की अप्रिय विरासत है।<sup>77</sup> नैतिक तर्कों के अलावा आर्थिक तर्क भी दिए गए। मुक्त व्यापार के संबंध में दिए जाने वाले सामान्य तर्क भी दिए गए और यह सुझाव दिया गया कि एकाधिकार के स्थान पर उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) प्रणाली उतनी ही लाभप्रद होगी।<sup>78</sup> बंगाल की एकाधिकार प्रणाली कृत्रिम थी और उसकी अपनी कठिन समस्याएं थी। 'फ्रीड आफ इंडिया' ने लिखा कि प्रत्यक्ष उत्पादन प्रणाली में मांग और पूर्ति के बीच ऐसा कोई सहज संबंध नहीं होता जिसकी समाज के नियमों की आवश्यकता पड़ती है और जो हस्तक्षेप न होने पर, प्राप्त हो जाता है।<sup>79</sup> परंतु अफीम के व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क का मर्म आर्थिक न होकर नैतिक था। समस्या के नैतिक पक्ष के विषय में अधिकांश ऐंग्लो इंडियन पत्रिकाओं के साथ-साथ भारतीयों के स्वामित्व में निकलने वाली पत्रिकाएं भी उदासीन थीं। यह नहीं भूलना चाहिए कि अफीम का दम लगाने के हानिकारक प्रभाव भारत की तुलना में चीन में अधिक देखे गए। 'इंडियन इकानामिस्ट' ने लिखा कि 'भारत सरकार एकाधिकार अपने पास इसलिए रखे हुए है क्योंकि कोई भी इसके परित्याग के बारे में योजना दे पाने में समर्थ नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक नेता यह देख सकता है कि वह अपने पास एकाधिकार अफीम का उपभोग मंजूर देश में फैलने से रोकने की विशुद्ध तथा सच्ची अकांक्षा से रखता है। साथ ही इससे यथासंभव कम उत्पादन से अधिक से अधिक संभव राजस्व की प्राप्ति होती है।'<sup>80</sup> दादाभाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से अफीम विरोधी समिति को कहा था कि अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में 'आपके साथ सभी हिंदुस्तानियों की सहानुभूति नहीं है।' वे जानते थे कि अनेक भारतीय समाचार पत्रों की राय में अफीम से प्राप्त होने वाला राजस्व छोड़ा नहीं जा सकता था।<sup>81</sup> व्यक्तिगत रूप से नौरोजी अफीम के व्यापार को नैतिक दृष्टि से घृणास्पद मानते थे। 1855 में

जब वे बंबई की एक फर्म से संबद्ध हुए तो उनकी एक स्पष्ट शक्त यह थी कि उन्हें अफीम से संबंधित कोई कार्य नहीं दिया जाएगा।<sup>82</sup> परंतु सारे भारतीयों का यह मत नहीं था।<sup>83</sup> कुछ विरले अपवादों को छोड़कर भारतीयों के स्वामित्व में निकलले वाले समाचारपत्र अफीम के प्रश्न से संबंधित नैतिक पहलू पर चुप थे।<sup>84</sup>

अधिकारी अफीम व्यापार विरोधी आंदोलन के विषय में अनभिज्ञ नहीं थे। इस पदार्थ की खेती और बिक्री अनंतिक है, इस तर्क के विषय में लार्ड स्टैनले ने सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा कि 'मैं इस तर्क को अयुक्तियुक्त और सरकार के कार्यों के विषय में गलत सिद्धांत पर आधारित मानता हूँ...'<sup>85</sup> अफीम विरोधी आंदोलनकारियों के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए थे। किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक 'दि ओपियम रेवेन्यू आफ इंडिया' में आर्थिक आधार पर अफीम के एकाधिकार को बनाए रखने के समर्थन में तर्क दिए गए थे। पुस्तक में दावा किया गया था कि अफीम के उपभोग के हानिकार दोषों को बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया गया है।<sup>86</sup> एक अन्य पैफलेट लेखक ने अफीम से प्राप्त होने वाले राजस्व को इस आधार पर ठीक बताया कि इससे भारतीयों को कर भार से कुछ मुक्ति मिलती थी।<sup>87</sup> एक तीसरे लेखक ने प्रश्न किया कि 'यदि इन निस्तेज उपदेशकों की वन आए तो अफीम से प्राप्त होने वाले राजस्व के बिना भारत क्या करेगा?'<sup>88</sup> एस० लैंग ने तर्क दिया कि इंग्लैंड में मदिरा के कराधान से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में अफीम से राजस्व न तो अच्छा है और न ही अधिक खराब है।<sup>89</sup> चार्ल्स ट्रैवीलियन ने भी ठीक इसी तर्क का प्रयोग किया। उसने लिखा कि 'अफीम से राजस्व का नैतिक औचित्य ठीक वही है जो इंग्लैंड में मदिरा पर उत्पादन शुल्क का है। क्या अफीम पर यथासंभव ऊंचा कर लगाकर उसके उपभोग को रोकना अधिक अच्छा है अथवा उसकी खेती और निर्यात को पूर्ण रूप से मुक्त छोड़कर चीनियों को अपने प्रिय स्वापक में लीन रहने के साधन तैयार करना ठीक है?'<sup>90</sup> यह केवल आर्द्धवर्णपूर्ण प्रश्न था और ट्रैवीलियन के विचार से इसका स्पष्ट उत्तर यही था कि हर दृष्टि से पहला विकल्प ही श्रेष्ठ है।<sup>91</sup> यदि यह वाछनीय भी हो तो भी अफीम की खेती और उपभोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा पाना असंभव था। सर जान स्ट्रैची तथा कर्नल रिचर्ड स्ट्रैची ने निश्चयात्मक ढंग से कहा कि न केवल अफीम का उपभोग कुछ लोगों की पक्की आदत है, बल्कि यदि यह थोड़ी मात्रा में ली जाए जैसा कि सिख और राजपूत करते हैं (ये पोस्त के काढ़े के रूप में अफीम का सेवन करते थे) तो यह लाभप्रद भी हो सकती है।<sup>92</sup> उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि अफीम की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत भारत नहीं है इसलिए अफीम का निर्यात बंद कर देने पर भी चीनियों को इससे अनिवार्य रूप से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में चीन के भीतरी प्रदेशों के सामान्य लोग स्वदेश में उत्पादित अफीम पर निर्भर थे, केवल तटीय प्रांतों के सम्पन्न लोग ही उत्तम श्रेणी की भारतीय अफीम खरीद पाने में समर्थ थे।<sup>93</sup> इसके अतिरिक्त भारतीय हितों को भी तो ध्यान में रखना था। भारत का यह विरला सौभाग्य था कि वह अपने एक ही उत्पाद से और अपने लोगों पर कर लगाए बिना भारी राजस्व प्राप्त करने में समर्थ था। स्ट्रैची को इस आशा से कि चीनियों को उनकी इच्छा

के विरुद्ध अफीम के उपभोग से रोका जा सकेगा, उस लोगों के प्रकट एवं महत्वपूर्ण हितों के त्याग के लिए जिनके कल्याण के लिए भारत सरकार महानतम कर्तव्यपालन की दृष्टि से प्रतिज्ञाबद्ध थी, कोई कारण दिखाई नहीं दिया।<sup>94</sup> जो लोग अफीम के व्यापार को नैतिक दृष्टि से गलत मानते थे, उन्हें भी यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के इतने अधिक लाभप्रद और अपरिहार्य स्रोत को किस प्रकार छोड़ा जा सकता है। मेयो ने जिसे अफीम के प्रश्न पर 'लोकोपकारकों की बकवाद'<sup>95</sup> के प्रति गहरी तिरस्कारपूर्ण घृणा थी, स्वीकार किया कि 'अफीम संबंधी स्थिति... हमारे यश पर सबसे गहरा कलंक है।'<sup>96</sup> परंतु क्या बंगाल की एकाधिकार प्रणाली का उत्पाद शुल्क प्रणाली में परिवर्तन 'हमारे कुछ दुर्बल भाइयों के अंतःकरण पर भरहम का कार्य करने के अतिरिक्त कुछ और ही सकेगी।'<sup>97</sup> मेयो ने फेर को लिखा कि 'प्रत्यक्ष क्रय विक्रय न करके पारगमन और आवकारी कर द्वारा राजस्व उगाह कर हम इस संबंध में उत्तरदायित्व से बच सकते हैं, यह मेरे विचार से भ्रम है। कोनिश तथा आयरिश तटों के पुराने जमींदार कभी-कभार ही स्वयं तस्कर व्यापार करते थे। परंतु वे उसे प्रोत्साहन देते थे और अपने काश्तकारों द्वारा चोरी से लाए गए माल पर भारी महमूल लगाते थे। हम अपनी प्रजा को (अफीम का) व्यापार करने की छूट व प्रोत्साहन देकर भारी कराधान द्वारा बहुत अधिक लाभ अर्जित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के विरुद्ध है। यह व्यवस्था एक मिनट भी नहीं चलनी है। मैं भारी राजस्व के त्याग को, जो हमें बंगाल प्रणाली के स्थान पर पश्चिमी (बंबई की) प्रणाली के अपनाने पर करना होगा, मान उस नैतिक श्रेष्ठता के लिए वाछनीय नहीं समझता जिसे समझने के लिए भी मेरे जैसे सामान्य प्राणियों की बुद्धि से कहीं अधिक प्रखर बुद्धि होनी चाहिए।'<sup>98</sup>

सरकार की अफीम विरोधी नीति को पंशाचिक बताना, जैसा कि अफीम विरोधी आंदोलनकारियों की आदत थी, अत्युक्ति होगा। धर्मोपदेशकों के दृष्टिकोण से यह नीति असमर्थनीय थी, परंतु भारत के व्यावहारिक प्रशासक केवल 'भावुकता' के बहाव में नहीं आए।<sup>99</sup> इस प्रश्न पर सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण का सारांश निम्नलिखित उद्धरण में आ जाता है। 'इस देश को अच्छी और सस्ती अफीम में स्वाभाविक एकाधिकार प्राप्त है। यदि कोई भी गंभीरतापूर्वक यह तर्क देता है कि यह स्वभाविक लाभ जो भारत को विधाता से मिला है, चीनियों के कारण पोस्त की खेती निषिद्ध करके कृत्रिम रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो इस तर्क को उसके ही भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए... यह भारत सरकार की नीति है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे यथासंभव सहज ढंग से होने दे। राजकोष को इस एकाधिकार से लाभ मिलता है और साथ ही इतनी ही राशि के किसी अधिक असुविधाजनक कराधान से बच पाना भी सम्भव होता है।'<sup>100</sup>

कराधान संबंधी ये दो मत थे : पहला, कराधान का उद्देश्य राजस्व की प्राप्ति है। दूसरा, कर का प्रयोग समाजिक और नैतिक दृष्टि से अवाछनीय वस्तुओं का उपभोग रोकने के लिए नैतिक अनुशासन के रूप में किया जा सकता है। इन दो मतों के बीच टकराव उत्पाद शुल्क संबंधी विचार विमर्श में भी लक्षित होता है।

उत्पाद शुल्क (क) गांजा और अफीम जैसे स्वापकों से; (ख) भारत में यूरोपीय ढंग से तैयार की जाने वाली शराब पर शुल्क के रूप में; तथा (ग) 'देशी शराब' पर शुल्क के रूप में संग्रह किया जाता था। जैसा कि हम अन्यत्र वर्णन कर चुके हैं मालवा और बंगाल की अफीम एजेंसियों के नियंत्रण में अफीम का व्यापार था। बंगाल में अफीम पर सरकार का एकाधिकार था। मालवा बंदई में होकर जाने वाली अफीम पर पार-गमन शुल्क लगता था। बंगाल में नमक पर एकाधिकार की भांति ही भारत में अफीम के होने वाले उपभोग पर उत्पाद शुल्क राजस्व वस्तुतः एकाधिकारी का लाभ ही था। सरकार लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से जनता को अफीम बेचती थी और सीमा शुल्क राजस्व में लाइसेंस शुल्क जुड़ जाता था। गांजे की विक्री पर लाइसेंस शुल्क था और उसकी खेती के लिए भी लाइसेंस लेना आवश्यक था। स्वापकों की कृपि के निषेध तथा इस संबंध में लाइसेंस प्रणाली से इनके उपभोग की आदत को बढ़ने से रोकने में सहायता मिलती थी। 1871 में कृपि, राजस्व, तथा वाणिज्य विभाग ने इन स्वापकों के हानिकार प्रभावों के बारे में एक सर्वेक्षण किया और पाया इनके प्रभाव बहुत ही खतरनाक होते हैं जिनमें पागलपन भी था।<sup>101</sup> यूरोपीय ढंगों से बनाई जाने वाली शराबों पर विदेश से आयातित ऐसी ही शराबों पर लगनेवाले सीमा शुल्क के बराबर ही शुल्क था।

देशी शराबों पर शुल्क संग्रह की दो प्रणालियाँ थी। एक भभका शुल्क प्रणाली (आउट स्टिल सिस्टम) के नाम से ज्ञात थी। इस प्रणाली के अंतर्गत शराब बनाने के भभकों पर स्थित दैनिक कर था और शराब के खुदरा विक्रेता को लाइसेंस शुल्क देना होता था जिसका समय विशेष में शराब की विक्री की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता था।<sup>102</sup> जिला अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले नीलाम में विक्रेता एकाधिकार गपूर्ण अधिकार) खरीदता था। वस्तुतः यह शराब बेचने का अधिकार इजारा करने की प्रणाली थी। इजारेदार उसी कस्बे अथवा शहर में दुकानें खोल सकता था जिसके लिए उसे इजारा मिला होता था। यह विश्वास किया जाता था कि इस प्रणाली में भारी संख्या में शराब, पानों और शराब की दूकानों के खुलने पर रोक रहेगी। इस प्रणाली का दोष था कि इसमें लाइसेंस पा जाने वाले व्यक्ति को यथासंभव भारी मात्रा में शराब बेचने की प्रेरणा मिलती थी क्योंकि लाइसेंस शुल्क पहले ही निर्धारित हो जाता था और इसका शराब की बेची जाने वाली मात्रा से कोई संबंध नहीं होता था। इसलिए विक्रेता का स्वाभाविक प्रयत्न यही होता था कि वह अधिक से अधिक मात्रा में शराब बेचकर यथासंभव अधिक लाभ अर्जित करे। बंगाल सरकार ने संतुष्ट होकर देखा कि लोगो में शराब पीने की आदत बढ़ रही है। इसके लिए शराब के व्यापारी ही उत्तरदाई थे। ('जिनका लाभ केवल इस बात पर ही निर्भर होता था कि वे शराब के उपभोग को कितना बढ़ा सकते हैं')।<sup>103</sup> बंगाल सरकार के अनुसार यह 'इस देश में हमारे प्रशासन के लिए सबसे बड़े कलंक की बात है।'<sup>104</sup> उत्पादन शुल्क की दूसरी प्रणाली मदर शराब कारखाना प्रणाली के नाम से थी।<sup>105</sup> इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत शुल्क की राशि वास्तविक उपभोग के लिए उपलब्ध होने वाली मात्रा पर निर्भर होती थी।<sup>106</sup>

इस प्रणाली को सदर शराब कारखाना प्रणाली (सदर डिस्टिलरी सिस्टम) इसलिए कहा जाता था क्योंकि सरकार ने केंद्रीय शराब कारखाना स्थापित कर दिया था जिसमें वे लोग शराब का उत्पादन करते थे जो इसकी उत्पादित मात्रा पर शुल्क देते थे। इस प्रकार उत्पादित शराब को ये विक्रेताओं को दे देते थे जिन्हें एक लाइसेंस शुल्क देना होता था।<sup>107</sup> भारत सरकार 'आवकारी प्रशासन पर लगाए गए इस आरोप का निराकरण करने के लिए उत्तुंग थी' कि भभका शुल्क (आउट स्टिल सिस्टम) प्रणाली के अंतर्गत 'आवकारी विभाग ने शराब के उपभोग को थोपकर राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास किया है।'<sup>108</sup> परंतु सदर शराब कारखाना प्रणाली लागू करने के लिए इमारतों और व्यवस्था पर भारी व्यय करना आवश्यक था। इसलिए इस प्रणाली को बहुत धीरे-धीरे ही लागू किया जा सकता। हिंदुस्तानी समाचारपत्र लोगों में शराब पीने की आदत फैलाने से न रोक पाने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे थे। धर्म प्रचार का पूर्वगृह रखने वाले समाचारपत्र भी 'सरकार द्वारा नसेबाजी के विस्तार' की आलोचना करते थे।<sup>109</sup>

इस संबंध में सरकारी अधिकारियों की घोषणाएं यदि मनोरंजक नहीं तो उलझन में डालने वाली अवश्य थी। 'ऐसा विश्वास है कि (आवकारी) प्रशासन की उपयुक्त प्रणाली में राजस्व और नैतिकता के उद्देश्य समान होंगे।'<sup>110</sup> सरकार का लक्ष्य 'उत्पादन-शुल्क के रूप में इतना अधिक राजस्व एकत्रित करना था जिससे स्वापक तथा शराब का उपभोग करने वाले हतोत्साहित हो जाएं।'<sup>111</sup> इन आदर्शों को व्यावहारिक नीति में परिणत कर पाना कठिन था।

सरकार के अधिकारी प्रवक्ताओं की राय में स्टांप कर 'विशिष्ट लाभकारी राजस्व' का स्रोत था। विल्सन का विचार था कि दुकानदारों, व्यापारियों तथा बैंकरो पर, जो न्याय एवं व्यवस्था की प्रणाली का लाभ उठा रहे थे, इस सर्चीली प्रणाली का ध्येय पूरा करने के लिए न्यायोचित ढंग से कर लगाए जा सकते थे।<sup>112</sup> अतः 1860 में स्टांप कर में 100 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई, और 1861 में इसमें पुनः थोड़ी सी वृद्धि की गई। इस प्रकार स्टांप राजस्व जो 1857-58 में केवल 45.6 लाख रुपये था, 1860-61 में बढ़कर 1.18 करोड़ रुपये हो गया। सरकार के लिए वाणिज्यिक मध्यवहार (लेन-देन संबंधी कागजात (जैसे हंडी, बोड, विनिमय बिल) पर स्टांप शुल्क लगाकर राजस्व में वृद्धि करना उचित था, पर अदासती एवं विधिक कागजात (जैसे वादपत्र, याचिका, जमीन रजिस्ट्री की दस्तावेज इत्यादि) पर स्टांप शुल्क लगाना वस्तुतः 'न्याय पर कर' था।<sup>113</sup> दस्तावेजों की सरकारी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए मंजूर व्यापारी तथा बैंकर उन पर लगाए जाने वाले स्टांपों के लिए सहर्ष भुगतान करते थे, परंतु जो लोग न्याय पाने के लिए न्यायालयों की शरण में पहुंचते थे उन पर कर लगाना उचित माना जा सकता था। सरकारी मत था कि इससे अत्यधिक मुकदमेबाजी पर रोक लगेगी। यह समझा जाता था कि लोगों को मुकदमेबाजी अत्यधिक प्रिय है।<sup>114</sup>

भारतीय समाचारपत्र भारत सरकार के भारी मैन्युव्यय की निंदा करने में लगभग एकमत थे। 'भारतीय राजनीतिज्ञों की एक विचारधारा के अनुसार सरकार



किया गया वही यूरोपीय रेजिमेंटों को अछूता छोड़ दिया गया।<sup>120</sup> यह विदित था कि अधिकांश सैन्य व्यय यूरोपीय सैनिकों पर होता था, जिनकी भर्ती, परिदहन, आपत्ति, भोजन और सेवा की समाप्ति पर दी जाने वाली पेंशन पर भारी खर्च जाता था।<sup>121</sup> यह हिंदुस्तानी समाचारपत्र ने एक दिलचस्प सुझाव दिया। सुझाव यह था कि यूरोपीय अफसरों से कम वेतन पर नियुक्त हिंदुस्तानी अफसरों को रेजिमेंटों का कमान करना चाहिए।<sup>122</sup> परन्तु उन दिनों इस प्रकार के विचार को सरकार का अस्वीकार करने की संभावना नहीं थी। सैन्य विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में हिंदुस्तानी सैनिकों के प्रति गहरा अविश्वास और सेना में यूरोपीय लोगों की बहुमता के अभाव को झलकाने का काम बैठा दिया था। जब 1871 में भारतीय वित्त के संबंध में जांच करने के लिए कृष्ण कान्धलकर की प्रवर समिति का गठन हुआ, तब सैन्य व्यय के अभाव में भारतीय सैनिकों के अभाव में आया। बंबई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने भारत मंत्री के एक प्रश्न (बर्क) में पूछा कि सैन्य व्यय को जो इतना बढ़ गया था कि राजस्व का दस प्रतिशत मन से बढ़ गया था, प्रवर समिति की जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। प्रवर समिति के जांच-परिणाम से भारतीय समाचार पत्रों में व्यक्त इस तरह की अपेक्षाएँ हुईं कि कुछ खर्च, जो इंग्लैंड द्वारा उठाए जाने चाहिए थे, भारत पर अंग्रेजों द्वारा उठाए जायें।<sup>123</sup>

इंडिया आफिस का खर्च भी आलोचना का शिकार था। 1869 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने निवेदन किया कि 'यद्यपि इंग्लैंड प्रवर समिति की यह नहीं है कि भारत सरकार भारत मंत्री और उसकी परिषद के विचारों के निर्धार के अन्तर्गत इसके बजट में सशोधन करे, तथापि यदि भारत मंत्री और विप्रसन्न के बजट एक माय प्रकाशित हो तो करदाता को वित्तीय स्थिति को नहीं देखेंगे बल्कि प्रवर समिति में गंभीरता।'<sup>124</sup> सरकार सुझाव पर अमल करने का कोई उत्तर नहीं दी। कुछ हिंदुस्तानी समाचारपत्रों की भावों की तुलना में यह बहुत ही दूर था। बंबई की एक प्रमुख पत्रिका 'जा मेजमदोद' ने मांग की कि भारतीय सैन्य के मंत्रियों में भारत मंत्री का अधिकार निश्चित होने के साथ-साथ सैन्य का निर्माण भी होना चाहिए।<sup>125</sup> 'राम गोपतार' सहमत था कि ये अधिकार मिलने ही चाहिए।<sup>126</sup> 'हिंदू पैट्रियट' का भी विचार था कि 'गृह खर्चों' में होने वाली निरंतर वृद्धि का शीघ्र उपचार होना आवश्यक है।<sup>127</sup> सरकार के गृह खर्चों के अधिक विस्तृत विवरण की मांग की गई थी।<sup>128</sup>

दादाभाई नौरोजी ने 1867 में सदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए अपने लेख में प्रकाशन प्रस्तुत किया कि 1829 में 36 वर्षों में गृह खर्चों के रूप में इंग्लैंड को दस करोड़ पाउंड का हस्तांतरण हुआ है। नौरोजी के अनुसार भारत का एकत्रित राजस्व का एक चौथाई भाग देश से बाहर इंग्लैंड भेजा गया।<sup>129</sup> इन व्ययों का वास्तविक महत्व कुछ भी क्यों न हो इनका भारतीय लोकमान पर भार पड़ा। बंबई के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने भारत मंत्री ने हाउस आफ कॉमन्स के द्वारा 'गृह खर्चों' के बारे में जांच कराने की मांग की।<sup>130</sup> हेनरी फास्ट ने बार० सी० दत्त तथा वैसे दूसरे लोगों से, जिन्होंने बार० सी० दत्त को आंकड़ों की सहायता से 'संपत्ति-विकास' के सिद्धांत की पुष्टि करने में मदद की,



था, पहले ही 'संपत्ति-निकास' पर ध्यान दिया था। फास्ट ने भारतीय लोकमत को बहुत प्रभावित किया।<sup>111</sup> उसने लिखा कि यह जानकारी मन में शंका उत्पन्न होती है कि भारत के राजस्व का बढ़ता हुआ अनुपात भारत में खर्च नहीं हो रहा है।<sup>112</sup>

उन्नीसवीं शताब्दी के भारत की विशिष्ट सरकारी शब्दावली में 'गृह खर्च' से तात्पर्य उन विदेशी खर्चों से होता था जो इंग्लैंड भारत मंत्री के कार्यालय द्वारा ब्रिटिश मुद्रा में किए जाते थे। 1860-65 की अवधि में इंग्लैंड में शुद्ध भुगतान का वार्षिक औसत 94 लाख पाउंड था और इसी दशक के उत्तरार्द्ध का औसत 95 लाख पाउंड। भारत मंत्री द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले इन गृह खर्चों पर भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। जिस अवधि का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है, उसमें भारत मंत्री द्वारा तैयार किए गए इंग्लैंड में प्रत्याशित व्यय प्रावकलनों को भारतीय वजट में दो बार कम किया गया था। दोनों बार भारत मंत्री ने भारत सरकार और वित्त सदस्य को इस संबंध में जोरदार शब्दों में फटकारा था और गृह खर्चों के वजट में संशोधन करके उन्हें बढ़ा दिया गया था। भारत मंत्री ने वे आर्थिक नीतियां निर्धारित कीं जिनके द्वारा इंग्लैंड में भुगतान होने थे। इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित रीतियां थीं। इंग्लैंड में भारत पर लिखे गए विनिमय बिल तथा तार द्वारा हस्तांतरण, भारत से सोने चांदी का प्रेषण, इंग्लैंड में जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूत (गारंटीमुदा) रेल कंपनियों से हुई प्राप्तियों का उपयोग इत्यादि।

गृह खर्चों की मुख्य मदें निम्नलिखित थीं :

(1) ऋण पर व्याज : इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेरधारियों को दिया जाने वाला लाभांश सम्मिलित था। 1834 से 1874 तक इन्हें 6,29,970 पाउंड दिया गया था (1874 में इन शेयरों का परिशोधन हो गया)। इंग्लैंड में लिए गए ऋणों तथा खंडन पर काटे गए बिलों के द्वारा शोधित भारतीय ऋणों पर व्याज एक बहुत बड़ी मद था। हम देख चुके हैं कि भारत का लोक ऋण हमारे इस अध्ययन की अवधि में किस प्रकार बढ़ा है। 1856-57 में इंग्लैंड में व्याज का भुगतान केवल 8,89,000 पाउंड था। 1860-65 में औसत वार्षिक व्याज भार 20.3 लाख पाउंड और 1865-70 में 20.8 लाख पाउंड था।

(2) भारत के निमित्त भंडार : भारत पर इंग्लैंड में सिविल विभागों (जिनमें लोक निर्माण विभाग, टकसाल, तथा डाक व तार विभाग सम्मिलित थे), सेना तथा नौ सेना के लिए खरीदे गए मंडारों की लागत प्रायः 10 लाख पाउंड से अधिक आती थी और बिकने ही 15 लाख पाउंड से अधिक होती थी। इंग्लैंड से मंडारों की प्राप्ति पर नियंत्रण एक गंभीर समस्या था। 1862 में सरकार के विभिन्न विभागों को आदेश दिया गया कि वे इंग्लैंड से मंडारों की सीधी मांग न करें। मंडार संबंधी मांगें भारत मंत्री के पास भेजने से पहले वित्त विभाग उनकी जांच पड़ताल करता था।<sup>113</sup> भारत सरकार के अनुरोध पर भारत मंत्री ने इंडिया आफिश में मंडार संबंधी सभी मांग पत्रों की जांच-पड़ताल और उन पर अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पूर्व उनकी पिछले वर्षों में सामग्री के इस्तेमाल की मात्रा से तुलना करने का नियम बना दिया था।<sup>114</sup> सैन्य वित्त विभाग से

संबद्ध कर्नल वाल्फ सैन्य खर्चों में कमी करने का प्रयास कर रहा था, उसने सैन्य भंडारों को की जाने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए।<sup>145</sup> भारत मंत्री ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यदि भारत में कामज तथा लेखन सामग्री कम कीमत पर मिलना संभव हो तो उसे प्राप्त कर इंग्लैंड में भंडार पर खर्चों में कमी की जाए।<sup>146</sup> 1866 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में भंडारों पर खर्चों में कमी करे। यह स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च, जिसमें माल भाड़ा भी सम्मिलित था 1864 से 1866 तक के तीन वर्षों में तीन गुना हो गया है।<sup>147</sup> भंडार खर्च की पूर्ण योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही मांग पत्रों के प्रावकलन भेजने का निश्चय किया।<sup>148</sup> कम से कम कीमत पर भंडारों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के लिए भारत मंत्री ने टेंडर मंगाना प्रारंभ कर दिया। यह प्रणाली पहले भी प्रचलित थी, परंतु अब 'सार्वजनिक प्रतियोगिता का सिद्धांत' अधिक संगत ढंग से लागू किया गया।<sup>149</sup> ये सब उपाय भंडार पर व्यय में वृद्धि को रोक पाने में असफल रहे थे। 1869 में भारत मंत्री ने पुनः भंडारों के बढ़ते हुए व्यय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मांग पत्रों पर अपर्याप्त नियंत्रण के लिए उसे दोषी ठहराया।<sup>150</sup> मेयो ने भंडार संबंधी एक ऐसी 'मांग पत्र समिति' (इंडेंट कमेटी) की स्थापना के संबंध में सोचा जिसमें लोक निर्माण, सैन्य तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधि हों।<sup>151</sup> ऐसी समिति नियुक्त की गई और 'भंडार व्यय के वार्षिक पुनर्विलोकन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू हुई।<sup>152</sup> इन उपायों से सरकार के लिए भंडार पर अपव्यय रोक सकना संभव हुआ, परंतु जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है भंडार खर्च बढ़ता ही गया। डाक व तार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यों में विस्तार तथा रेलों के निर्माण के कारण इंग्लैंड से माल तथा विविध उपकरणों के आयात की आवश्यकता हुई।

(3) भारत स्थित ब्रिटिश सेना व्यवस्था पर गृह खर्च एक महत्वपूर्ण मद थी। हमने पिछले अध्याय में भारतीय राजस्व पर पड़ने वाले नियमित और गैर नियमित सैन्य व्यय की व्याख्या की है।

(4) गृह खर्चों में शामिल होनेवाला एक अन्य व्यय भारत जाने वाली और वहां से इंग्लैंड लौटने वाली सेनाओं पर परिवहन व्यय था। 1900 तक, जब बेलबी आयोग ने सिफारिश की कि परिवहन का आधा परिव्यय ब्रिटिश राजकोष से किया जाना चाहिए, इंग्लैंड में सेना के पोतारोहण के दिन से भारत पहुंचने तक का संपूर्ण मार्ग व्यय भारत से ही वसूल किया जाता था। अल्पकालीन सेवा प्रणाली के कारण परिवहन खर्च अधिक हो गया था। इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय की राशि हर वर्ष बदलती रहती थी।

(5) सेवा निवृत्त होने वाले सिविल सेवा अधिकारियों की पेंशन, वार्षिक अनुदानों तथा और छुट्टी पर जाने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों के कारण गृह खर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी। ये व्यय गैर नियमित प्रभार कहलाते थे।

(6) रेलों पर प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) व्याज बहुत बड़ी मद था। प्रत्याभूत

था, पहले ही 'संपत्ति-निकास' पर ध्यान दिया था। फास्ट ने भारतीय लोकमत को बहुत प्रभावित किया।<sup>141</sup> उसने लिखा कि यह जानकर मन में शंका उत्पन्न होती है कि भारत के राजस्व का बढ़ता हुआ अनुपात भारत में खर्च नहीं हो रहा है।<sup>142</sup>

उन्नीसवीं शताब्दी के भारत की विशिष्ट सरकारी शब्दावली में 'गृह खर्च' से तात्पर्य उन विदेशी खर्चों से होता था जो इंग्लैंड भारत मंत्री के कार्यालय द्वारा ब्रिटिश मुद्रा में किए जाते थे। 1860-65 की अवधि में इंग्लैंड में शुद्ध भुगतान का वार्षिक औसत 94 लाख पौंड था और इसी दशक के उत्तरार्द्ध का औसत 95 लाख पौंड। भारत मंत्री द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले इन गृह खर्चों पर भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। जिस अवधि का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है, उसमें भारत मंत्री द्वारा तैयार किए गए इंग्लैंड में प्रत्याशित व्यय प्राक्कलनों को भारतीय बजट में दो बार कम किया गया था। दोनों बार भारत मंत्री ने भारत सरकार और वित्त सदस्य को इस संबंध में जोरदार शब्दों में फटकारा था और गृह खर्चों के बजट में संशोधन करके उन्हें बढ़ा दिया गया था। भारत मंत्री ने वे आर्थिक नीतियां निर्धारित की जिनके द्वारा इंग्लैंड में भुगतान होने थे। इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित रीतियां थी। इंग्लैंड में भारत पर लिले गए विनिमय बिल तथा तार द्वारा हस्तांतरण, भारत से सोने चांदी का प्रेषण, इंग्लैंड में जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूत (गारंटीयुदा) रेल कंपनियों से हुई प्राप्तियों का उपयोग इत्यादि।

गृह खर्चों की मुख्य मदें निम्नलिखित थीं :

(1) ऋण पर व्याज : इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारियों को दिया जाने वाला लाभांश सम्मिलित था। 1834 से 1874 तक इन्हें 6,29,970 पौंड दिया गया था (1874 में इन शेयरों का परिशोधन हो गया)। इंग्लैंड में लिए गए ऋणों तथा खंडन पर काटे गए बिलों के द्वारा शोधित भारतीय ऋणों पर व्याज एक बहुत बड़ी मद था। हम देख चुके हैं कि भारत का लोक ऋण हमारे इस अध्ययन की अवधि में कितना प्रचुर बढ़ा है। 1856-57 में इंग्लैंड में व्याज का भुगतान केवल 8,89,000 पौंड था। 1860-65 में औसत वार्षिक व्याज भार 20.3 लाख पौंड और 1865-70 में 20.8 लाख पौंड था।

(2) भारत के निमित्त भंडार : भारत पर इंग्लैंड में सिविल विभागों (जिनमें लोक निर्माण विभाग, टकसाल, तथा डाक व तार विभाग सम्मिलित थे), सेना तथा नौ सेना के लिए खरीदे गए भंडारों की लागत प्रायः 10 लाख पौंड से अधिक आती थी और विरले ही 15 लाख पौंड से अधिक होती थी। इंग्लैंड से भंडारों की प्राप्ति पर नियंत्रण एक गंभीर समस्या था। 1862 में सरकार के विभिन्न विभागों को आदेश दिया गया कि वे इंग्लैंड से भंडारों की सीधी भाग न करें। भंडार संबंधी भागें भारत मंत्री के पास भेजने से पहले वित्त विभाग उनकी जाच पड़ताल करता था।<sup>143</sup> भारत सरकार के अनुरोध पर भारत मंत्री ने इंडिया आफिस में भंडार संबंधी सभी मांग पत्रों की जाच-पड़ताल और उन पर अंतिम रूप में स्वीकृति देने से पूर्व उनकी पिछले वर्षों में सामग्री के इस्तेमाल के बारे में जाच-पड़ताल करने का नियम बना दिया था।<sup>144</sup> सैन्य वित्त विभाग

संबद्ध कर्नल वाल्फ सैन्य खर्चों में कमी करने का प्रयास कर रहा था, उसने सैन्य भंडारों को की जाने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए।<sup>145</sup> भारत मंत्री ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यदि भारत में कागज तथा लेखन सामग्री कम कीमत पर मिलना संभव हो तो उसे प्राप्त कर इंग्लैंड में भंडार पर खर्चों में कमी की जाए।<sup>146</sup> 1866 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च में कमी करे। यह स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च, जिसमें माल भाड़ा भी सम्मिलित था 1864 से 1866 तक के तीन वर्षों में तीन गुना हो गया है।<sup>147</sup> भंडार खर्च की पूर्ण योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही मांग पत्रों के प्राक्कलन भेजने का निश्चय किया।<sup>148</sup> कम से कम कीमत पर भंडारों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के लिए भारत मंत्री ने टेंडर मगाना प्रारंभ कर दिया। यह प्रणाली पहले भी प्रचलित थी, परंतु अब 'सार्वजनिक प्रतियोगिता का सिद्धांत' अधिक संगत ढंग से लागू किया गया।<sup>149</sup> ये सब उपाय भंडार पर व्यय में वृद्धि को रोक पाने में असफल रहे थे। 1869 में भारत मंत्री ने पुनः भंडारों के बढ़ते हुए व्यय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मांग पत्रों पर अपर्याप्त नियंत्रण के लिए उसे दोषी ठहराया।<sup>150</sup> मेयो ने भंडार संबंधी एक ऐसी 'मांग पत्र समिति' (इंडेंट कमेटी) की स्थापना के संबंध में सोचा जिसमें लोक निर्माण, सैन्य तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधि हों।<sup>151</sup> ऐसी समिति नियुक्त की गई और भंडार व्यय के वार्षिक पुनर्विलोकन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू हुई।<sup>152</sup> इन उपायों से सरकार के लिए भंडार पर अपव्यय रोक सकना संभव हुआ, परंतु जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है भंडार खर्च बढ़ता ही गया। डाक व तार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यों में विस्तार तथा रेलों के निर्माण के कारण इंग्लैंड से माल तथा विविध उपकरणों के आयात की आवश्यकता हुई।

(3) भारत स्थित ब्रिटिश सेना व्यवस्था पर गृह खर्च एक महत्वपूर्ण मद थी। हमने पिछले अध्याय में भारतीय राजस्व पर पड़ने वाले नियमित और गैर नियमित सैन्य व्यय की व्याख्या की है।

(4) गृह खर्चों में शामिल होनेवाला एक अन्य व्यय भारत जाने वाली और वहां से इंग्लैंड लौटने वाली सेनाओं पर परिवहन व्यय था। 1900 तक, जब वैंलबी आयोग ने सिफारिश की कि परिवहन का आधा परिव्यय ब्रिटिश राजकोष से किया जाना चाहिए, इंग्लैंड में सेना के पोता रोहण के दिन से भारत पहुंचने तक का संपूर्ण मार्ग व्यय भारत से ही वसूल किया जाता था। अल्पकालीन सेवा प्रणाली के कारण परिवहन खर्च अधिक हो गया था। इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय की राशि हर वर्ष बदलती रहती थी।

(5) सेवा निवृत्त होने वाले सिविल सेवा अधिकारियों की पेंशन, वार्षिक अनुदानों तथा और छुट्टी पर जाने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों के कारण गृह खर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी। ये व्यय गैर नियमित प्रभार कहलाते थे।

(6) रेलों पर प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) ब्याज बहुत बढ़ी मद था। प्रत्याभूत

था, पहले ही 'संपत्ति-निकाम' पर ध्यान दिया था। फास्ट ने भारतीय लोकमत को बहुत प्रभावित किया।<sup>111</sup> उसने लिखा कि यह जानकारी मन में शंका उत्पन्न होती है कि भारत के राजस्व का बढ़ता हुआ अनुपात भारत में खर्च नहीं हो रहा है।<sup>112</sup>

उन्नीसवीं शताब्दी के भारत की विशिष्ट सरकारी शब्दावली में 'गृह खर्च' से तात्पर्य उन विदेशी खर्चों से होता था जो इंग्लैंड भारत मंत्री के कार्यालय द्वारा ब्रिटिश मुद्रा में किए जाते थे। 1860-65 की अवधि में इंग्लैंड में शुद्ध भुगतान का वार्षिक औसत 94 लाख पाँड था और इसी दशक के उत्तरार्द्ध का औसत 95 लाख पाँड। भारत मंत्री द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले इन गृह खर्चों पर भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। जिस अवधि का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है, उसमें भारत मंत्री द्वारा तैयार किए गए इंग्लैंड में प्रत्याशित व्यय प्राक्कलनों को भारतीय बजट में दो बार कम किया गया था। दोनों बार भारत मंत्री ने भारत सरकार और वित्त मन्त्रालय को इस संबंध में जोरदार शब्दों में फटकारा था और गृह खर्चों के बजट में संशोधन करके उन्हें बढ़ा दिया गया था। भारत मंत्री ने वे आर्थिक नीतियाँ निर्धारित की जिनके द्वारा इंग्लैंड में भुगतान होते थे। इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित रीतियाँ थीं। इंग्लैंड में भारत पर लिये गए विनिमय विल तथा तार द्वारा हस्तांतरण, भारत से सोने काँदी का प्रेषण, इंग्लैंड में जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) रेल कंपनियों से हुई प्राप्तियों का उपयोग इत्यादि।

गृह खर्चों की मुख्य मदें निम्नलिखित थीं :

(1) ऋण पर व्याज : इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारियों को दिया जाने वाला लाभांश सम्मिलित था। 1834 से 1874 तक इन्हें 6,29,970 पाँड दिया गया था (1874 में इन शेयरों का परिशोधन हो गया)। इंग्लैंड में लिए गए ऋणों तथा लंदन पर काटे गए विलों के द्वारा शोधित भारतीय ऋणों पर व्याज एक बहुत बड़ी मद था। हम देख चुके हैं कि भारत का लोक ऋण हमारे इस अध्ययन की अवधि में किन प्रकार बढ़ा है। 1856-57 में इंग्लैंड में व्याज का भुगतान केवल 8,89,000 पाँड था। 1860-65 में औसत वार्षिक व्याज भार 20.3 लाख पाँड और 1865-70 में 20.8 लाख पाँड था।

(2) भारत के निमित्त भंडार : भारत पर इंग्लैंड में सिविल विभागों (जिनमें लोक निर्माण विभाग, टकसाल, तथा डाक व तार विभाग सम्मिलित थे), सेना तथा नौ सेना के लिए खरीदे गए भंडारों की लागत प्रायः 10 लाख पाँड से अधिक आती थी और विरले ही 15 लाख पाँड से अधिक होती थी। इंग्लैंड से भंडारों की प्राप्ति पर नियंत्रण एक गंभीर समस्या था। 1862 में सरकार के विभिन्न विभागों को आदेश दिया गया कि वे इंग्लैंड से भंडारों की सीधी मांग न करें। भंडार संबंधी मांगें भारत मंत्री के पास भेजने से पहले वित्त विभाग उनकी जाँच पड़ताल करता था।<sup>113</sup> भारत सरकार के अनुरोध पर भारत मंत्री ने इंडिया आफिस में भंडार संबंधी सभी मांग पत्रों की जाच-पड़ताल और उन पर अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पूर्व उनकी पिछले वर्षों में सामग्री के इस्तेमाल की मात्रा से तुलना करने का नियम बना दिया था।<sup>114</sup> सैन्य वित्त विभाग से

संबद्ध कर्नल बाल्फ सैन्य खर्चों में कमी करने का प्रयास कर रहा था, उसने सैन्य भंडारों को भी जाने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए।<sup>145</sup> भारत मंत्री ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यदि भारत में कागज तथा लेखन सामग्री कम कीमत पर मिलना संभव हो तो उसे प्राप्त कर इंग्लैंड में भंडार पर खर्चों में कमी की जाए।<sup>146</sup> 1866 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च में कमी करे। यह स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च, जिसमें माल ढाढ़ा भी सम्मिलित था 1864 से 1866 तक के तीन वर्षों में तीन गुना हो गया है।<sup>147</sup> भंडार खर्च की पूर्ण योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही मांग पत्रों के प्राक्कलन भेजने का निश्चय किया।<sup>148</sup> कम से कम कीमत पर भंडारों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के लिए भारत मंत्री ने टेंडर मंगाना प्रारंभ कर दिया। यह प्रणाली पहले भी प्रचलित थी, परंतु अब 'सार्वजनिक प्रतियोगिता का सिद्धांत' अधिक संगत ढंग से लागू किया गया।<sup>149</sup> ये सब उपाय भंडार पर व्यय में वृद्धि को रोक पाने में असफल रहे थे। 1869 में भारत मंत्री ने पुनः भंडारों के बढ़ते हुए व्यय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मांग पत्रों पर अपर्याप्त नियंत्रण के लिए उसे दोषी ठहराया।<sup>150</sup> मेयो ने भंडार संबंधी एक ऐसी 'मांग पत्र समिति' (इंडेंट कमेटी) की स्थापना के संबंध में सोचा जिसमें लोक निर्माण, सैन्य तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधि हों।<sup>151</sup> ऐसी समिति नियुक्त की गई और भंडार व्यय के वार्षिक पुनर्विलोकन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू हुई।<sup>152</sup> इन उपायों से सरकार के लिए भंडार पर अपव्यय रोक सकना संभव हुआ, परंतु जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है भंडार खर्च बढ़ता ही गया। डाक व तार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यों में विस्तार तथा रेलों के निर्माण के कारण इंग्लैंड से माल तथा विविध उपकरणों के आयात की आवश्यकता हुई।

(3) भारत स्थित ब्रिटिश सेना व्यवस्था पर गृह खर्च एक महत्वपूर्ण मद थी। हमने पिछले अध्याय में भारतीय राजस्व पर पड़ने वाले नियमित और गैर नियमित सैन्य व्यय की व्याख्या की है।

(4) गृह खर्चों में शामिल होनेवाला एक अन्य व्यय भारत जाने वाली और वहां से इंग्लैंड लौटने वाली सेनाओं पर परिवहन व्यय था। 1900 तक, जब वेलबी आयोग ने सिफारिश की कि परिवहन का आधा परिव्यय ब्रिटिश राजकोष से किया जाना चाहिए, इंग्लैंड में सेना के पोता रोहण के दिन से भारत पहुंचने तक का संपूर्ण मार्ग व्यय भारत से ही वसूल किया जाता था। अल्पकालीन सेवा प्रणाली के कारण परिवहन खर्च अधिक हो गया था। इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय की राशि हर वर्ष बदलती रहती थी।

(5) सेवा निवृत्त होने वाले सिविल सेवा अधिकारियों की पेंशन, वार्षिक अनुदानों तथा और छुट्टी पर जाने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों के कारण गृह खर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी। ये व्यय गैर नियमित प्रभार कहलाते थे।

(6) रेलों पर प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) व्याज बहुत बढ़ी मद था। प्रत्याभूत

कंपनियों को दिया जानेवाला औसत वार्षिक व्याज 1860-65 में 20 लाख पौंड था। यह इसी दशक के उत्तरार्द्ध में 35 लाख पौंड वार्षिक हो गया।

1861 में भारत मंत्री ने इस स्थिति का बहुत अच्छा चित्रण किया। उसने लिखा कि 'रेल पूजा पर प्रत्याभूत व्याज में वृद्धि की आशा की जानी चाहिए। रेलें जब धीरे-धीरे पूरी हो चलेगी, तो यातायात से शुद्ध प्राप्ति में वृद्धि होगी और व्याज प्रभार में थोड़ी कमी होगी। परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अब भी 2 करोड़ पौंड से अधिक की राशि जुटाने की आवश्यकता है, आगे आने वाले कुछ वर्षों में व्याज प्रभार में वृद्धि की आशा की जानी चाहिए। निस्संदेह व्याज का स्वरूप अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अंततः यह सरकार को परिशोष्य है। जैसे ही रेलें लाभप्रद हो जाएंगी और लाभ 5 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा कुछ-कुछ परिशोधन होने लगेगा, परंतु यह जाहिर है कि परिशोधन का समय अभी दूर है'।<sup>133</sup> एक पिछले अध्याय में हमने प्रत्याभूत संविदाओं की व्याख्या की है जिनके अंतर्गत व्याज प्रभारों का भुगतान होता था। हमें गौर करना चाहिए कि न केवल व्याज प्रभार भारी बोझ था, वरन् रेल कंपनियों से प्राप्तियों और उन्हें किए जाने वाले भुगतानों में अनिश्चितता और इन कंपनियों की अपने खातों से अपने ही द्वारा जमा किए गए रुपये से अधिक रुपया निकालने की आदत सरकार के लिए वित्त संकट का अतिरिक्त कारण थी।<sup>134</sup>

(7) 'गृह प्रशासन की मद में भारत मंत्री, भारत उपमंत्री तथा इंडिया काउंसिल के सदस्यों के वेतन, इंडिया आफिस का स्थापन खर्च, ऋण प्रवन्ध के लिए बैंक आफ इंग्लैंड को भुगतान, लेखा परीक्षक को भुगतान (एक्ट 21 और 22 विक्ट० सी० 106 की धारा 52 के अंतर्गत) डाक खर्च इत्यादि सम्मिलित थे। इस शीर्षक के अंतर्गत 1860-61 में व्यय की राशि 1, 75, 000 पौंड थी। 1968-69 तक यह 2, 00, 000 पौंड से अधिक नहीं हुई थी और 1870-71 में यह 2, 16, 000 पौंड थी। इस व्यय की ओर विदेशी वाणिज्य दूतावासों को स्थापन पर होनेवाले व्यय की भारत में काफी छानबीन की जाती थी और ये खर्च आलोचना के विषय थे। उदाहरणार्थ, टर्की के सुल्तान के स्वागत में भारत मंत्री द्वारा की गई नाच व्यवस्था भारतीय कर दाताओं के रुपये के अपभ्रम का, कुछसात उदाहरण बन गई। नोर्थकोट ने लार्सेंस को निजी पत्र में लिखा कि 'सुल्तान के लिए आयोजित नृत्य ने बहुत सारे लोगों को कलंकित किया है'।<sup>135</sup> 1834 में हुए एक करार के अनुसार चीन में स्थापित वाणिज्य दूतावास के स्थापन खर्च का एक तिहाई खर्च भारत सरकार देती थी। ये खर्च 1860-61 में लगभग 23, 000 पौंड, 1861-63 में 14, 000 पौंड, 1863-65 में 17, 000 पौंड और 1865-67 में 19, 000 पौंड थे। इन खर्चों में कमी करने के लिए 1860, 1862 और 1866 में राजकोष के लाहों के समक्ष प्रतिवेदन पेश किए गए; परंतु उन्होंने 1834 के करार में संशोधन करना स्वीकार नहीं किया।<sup>136</sup> 1860 में भारत सरकार ने अदन में सबधित खर्च को भारत पर से हटाने अथवा उसमें कमी करने का प्रयत्न किया। यह स्पष्ट किया गया कि अदन के ही नहीं आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के रास्ते में भी पड़ता है अदन

मे किए जाने वाले सैन्य एवं राजनीतिक खर्च केवल भारत को देने पड़ते हैं।<sup>157</sup> इसी प्रेषण में यह भी स्पष्ट किया गया कि खाड़ी उपनिवेशों के प्रशासन का बोझ भारत पर 5 लाख रुपए (50,000 पाँड) वार्षिक पड़ रहा है। प्रेषण में इस बात का आग्रह किया गया कि उपनिवेश संबंधी खर्च भारत पर से हटा दिए जाने चाहिए।<sup>158</sup> भारत सरकार ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि भारत का राजस्व केवल इसी देश के कार्यों पर खर्च होना चाहिए, और भारत को 'बाहरी खर्चों' से मुक्त कर देना चाहिए।<sup>159</sup> सरकार के प्रयत्नों का कुछ परिणाम निकला। इंग्लैंड ने अदन संबंधी व्यय का आधा भाग अपने ऊपर लेकर इस खर्च को भारत के साथ बांट लिया, और 1867 में खाड़ी उपनिवेशों को भारत से अलग कर दिया गया। इस प्रकार बाहरी खर्चों में कुछ कमी हो गई।<sup>160</sup>

गृह खर्चों के अतिरिक्त भारत सरकार को 'गृह' संव्यवहारों (आदान-प्रदान) के लिए भी बड़ी राशि देनी होती थी। इसे 'गृह राजकोष' के लिए विप्रेषण पर विनिमय द्वारा हानि' कहा जाता था। सरकारी तौर पर विनिमय दर दो शिलिंग प्रति रुपया थी, परंतु बाजार की दर घटती बढ़ती रहती थी। जब भी रुपये का विनिमय मूल्य दो शिलिंग से कम हो जाता था, तो गृह राजकोष से भुगतान होने वाले स्टिलिंगों के लिए अधिक रुपयों की आवश्यकता पड़ती थी। हम अन्यत्र विवेचना कर चुके हैं कि किस प्रकार प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) रेल कंपनियों के साथ दोषपूर्ण संधिदाओं के कारण विनिमय पर हानि उठानी पड़ी। निस्संदेह यह खर्च विनिमय दर और भारत से इंग्लैंड को विप्रेषित होने वाली रकम के अनुसार काफी घटता बढ़ता रहता था।

सेना, गृह विभाग संबंधी स्थापन, इंग्लैंड से प्राप्त होने वाले भंडार आदि पर भारी व्यय की तुलना में शिक्षा के लिए नियत अनुदान कम थे। 1857-58 और 1871-72 के बीच शिक्षा पर व्यय तीन गुना हो गया। इसी अवधि में शिक्षा संस्थाएं पांच गुने से भी अधिक हो गईं और इनमें विद्यार्थियों की औसत संख्या छः गुना बढ़ गई। विकास की यह दर आशाजनक लगती है। शिक्षा न केवल सरकारी दफ्तर रूपी पौराणिक आनंदधाम के लिए अनिवार्य थी, अपितु वह बढ़ते हुए मध्यम वर्ग के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों के रूप में नए क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए भी आवश्यक थी। शिक्षा संबंधी अवसरों के लिए लालायित तथा होहल्ला मचाने वाला मध्यम वर्ग विकास की दर के प्रति सरकारी संतोष से असहमत था। शिक्षा संस्थाओं पर विद्यार्थियों की संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों के आधार पर सरकारी क्षेत्रों में अपने आपको बहुत बढ़ाई दी गई। परंतु इस प्रकार के आंकड़ों का अर्थ बहुत सावधानी के साथ लगाना चाहिए। यह बहुत संभव है कि प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संस्थाएं कम बताई गई हों जिससे सातवें दशक के अंतिम वर्षों और आठवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में तेजी से विकास का अति-शयोक्तिपूर्ण आभास मिला हो। 1857-60 में सरकार शिक्षा पर औसतन 24 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रही थी। 1861-65 में औसत व्यय की राशि 29 लाख रुपये और दशक के उत्तरार्द्ध में 53 लाख रुपए थी। जिसकी तुलना उत्तर सैन्य विद्रोह काल में इस मद पर होने वाले व्यय की राशि के साथ की जा सकती है, परंतु सातवें दशक के अंतिम



वर्षों में भी शिक्षा की मदद पर होने वाला व्यय भारत सरकार के कुल व्यय का केवल 1 प्रतिशत था। भारत सरकार शिक्षा संबंधी अनुदानों की अपर्याप्तता से अवगत थी अतः उसने प्रांतीय सरकारों से स्थानीय उपकर (सेस) लगाकर शिक्षा के लिए साधन जुटाने का आग्रह किया। इन साधनों का उपयोग विशेष रूप से देशी भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा पर किया जाना था क्योंकि इसके लिए सामान्य राजस्व से धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था नहीं थी।<sup>181</sup>

जिस अवधि का अध्ययन हम यहां कर रहे हैं उसमें शिक्षा के लिए अन्य प्रांतों की तुलना में बंगाल की अपेक्षाकृत अधिक अनुदान मिला।<sup>182</sup> परंतु सरकार परिणाम से विलकुल संतुष्ट नहीं थी। मेयो ने सर ई.० पैरी को लिखा था कि 'सब यह है कि बंगाल में शिक्षा उन लोगों के निर्देशन में है जो इस विचार के समर्थक हैं कि यदि उच्च वर्ग के लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी देखा देखी नीचे के वर्गों में भी शिक्षा का प्रसार होगा।' 'मेरे विचार से यह सिद्धांत निरा मूर्खतापूर्ण है यदि लोगों को शिक्षित किया जाना है तो नीचे से प्रारंभ करके ऊपर उठना होगा।'<sup>183</sup> यह अनुभव किया गया कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है और नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षा संबंधी वित्त काफ़ी भार डालते जा रहे हैं। मेयो ने पैरी को आगे लिखा कि 'बंगाल में आप अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं और राज्य के भारी खर्च पर कुछ सौ बाबू तैयार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश का उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करना मात्र है। परंतु इस बीच लाखों लोगों तक ज्ञान के विस्तार के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।'<sup>184</sup> मेयो का अनुमान था कि अंग्रेजी शिक्षा 'हमारे और हमारे शासन के प्रति लोगों की अज्ञाति में कमी नहीं ला रही है।' 'हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उस बाबू से अधिक असंतुष्ट व्यक्ति और कोई नहीं है जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी है।'<sup>185</sup> जो भी हो, चूंकि भारत सरकार जनसाधारण के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रणाली लागू नहीं कर सकी थी, इसलिए यह कार्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाना था। 1871 की वित्त विकेंद्रीकरण योजना में प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किए जाने वाले विषयों में शिक्षा भी एक थी।

दादाभाई नौरोजी तथा इंडियन इकानामिस्ट के संपादक राबर्ट नाइट ने अपनी रचनाओं में वे सारे बहुत तर्क पहले ही दिए थे जिन्हें बाद में रमेश दत्त तथा दूसरे राष्ट्रवादी विचारकों ने प्रयोग किया। 1869-71 में एक के बाद एक कई लेखों में राबर्ट नाइट ने तर्क दिया कि भारत अंग्रेज पूंजी निवेशकों को बहुत ऊंची ब्याज की दर पर भुगतान कर रहा है और उनको जितना लाभ मिलता है भारत को उतने ही परिमाण में हानि होती है।<sup>186</sup> उन्होंने आलोचना की दिशा में आगे जाकर भारतीय ऋण की निंदा की<sup>187</sup> और कहा कि वह 'आदि से अंत तक अंग्रेजों का दायित्व है'<sup>188</sup> जो भारतीय राजकोष के साथ अन्यायपूर्वक बांध दिया गया है।<sup>189</sup> नाइट ने महमूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूंजी (स्टॉक) तथा सैन्य विद्रोह संबंधी ऋणों के कारण उत्पन्न ब्याज प्रभार विशेष रूप से अनुचित थे। नौरोजी के अनुसार ब्याज प्रभार 'राजनीतिक बोझ थे... जो व्यय के दोषपूर्ण प्रशासन से उत्पन्न होते थे।'<sup>190</sup> और भारत के साधनों के विकास में सहायक

थे। नाइट और नौरोजी दोनों ने ही राजनीतिक ऋणों और लोक निर्माण के निमित्त ऋणों में भेद किया था। यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह लोक निर्माण जैसे उत्पादी पूँजी निवेश के लिए भी पूँजी की व्यवस्था नहीं कर सका। दादाभाई नौरोजी ने लिखा कि 'भारत को ब्रिटिश पूँजी की बुरी तरह आवश्यकता है' परंतु 'ऐसे ब्रिटिश आक्रमण की जरूरत नहीं है जो आकर यहाँ की पूँजी और उत्पादन दोनों ही को खा जाए।' <sup>171</sup>

'इंडियन इकानामिस्ट' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में व्याज की दर 20 से 50 प्रतिशत के बीच और प्रेसीडेंसी नगरों में वाणिज्यिक दर 9 प्रतिशत थी। <sup>172</sup> अतः सरकार के लिए लंदन में ऋण लेना अधिक सस्ता था। जैसा हम पहले बता आए हैं, भारत सरकार ने दूसरे देशों से ऋण लेने की नीति को इसी आधार पर युक्तिसंगत ठहराने का प्रयास किया था। देश के भीतर ऋण ले सकने का क्षेत्र बहुत सीमित था और विदेशी ऋणदाताओं से उधार पा सकना मुविघाजनक था। नौरोजी इस बात को सही मानते थे। परंतु वे सरकार पर बढते हुए स्टलिंग ऋणभार के आलोचक थे। इनके दो कारण थे। प्रथम, क्योंकि यह मुख्यतः 'राजनीतिक ऋणों' के कारण उत्पन्न हुआ था और द्वितीय, क्योंकि देश के बाहर ऋणदाताओं को व्याज का भुगतान होता था।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में टैरिफ नीति विवाद का सजीव विषय थी और 'राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की निंदा में 'औद्योगिक शिशु वध' का स्थान महत्वपूर्ण होता था।' सातवें दशक में टैरिफ समस्या का भारतीयों की दृष्टि में यह महत्व नहीं था। सीमा शुल्क प्रशामन में संगठनात्मक सुधारों का वस्तुतः अनुमोदन किया जाता था। ये सुधार थे, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के बंदरगाहों के बीच होने वाले व्यापार पर राजकोपीय प्रतिबंधों को हटाना, संपूर्ण भारत में मूल्यांकन में समानता लाने की दृष्टि से सीमा शुल्क मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना; और सीमा शुल्क संग्रह की रीति का वैज्ञानिक पुनर्गठन। देशी रियासतों के साथ भारत सरकार का उद्देश्य स्ट्रैची के शब्दों में 'एक प्रकार की जोखरीन व्यवस्था' स्थापित करना था। <sup>173</sup> देशी रियासतों के साथ किए गए विविध समझौतों के द्वारा गृह व्यापार पर से राजकोपीय प्रतिबंध हटा लिए गए, यद्यपि इस बात का ध्यान रखा गया कि देशी रियासतें 'भारत सरकार की तुलना में कम शुल्क' लगाकर ब्रिटिश भारत के बंदरगाहों से होने वाले व्यापार को आकर्षित न कर लें। <sup>174</sup> विल्सन के अनुरोध पर सीमा शुल्क मूल्यांकन में संशोधन प्रारंभ हुआ। उसने भारत आने पर पाया कि भिन्न-भिन्न बंदरगाहों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से मूल्यांकन करके मूल्यानुसारी शुल्क लागू किए जाते थे। <sup>175</sup> 1860 में प्रथम बार समस्त भारत के लिए एक तरह का मूल्यांकन लागू किया गया। <sup>176</sup> एक वर्ष पहले 1859 के एक्ट VII द्वारा पहली बार समस्त भारत के लिए एक समान टैरिफ शुल्क निर्धारित किया गया था। 1876 में 'निःशुल्क सूची' समाप्त कर दी गई। यह उन वस्तुओं की सूची थी जो सीमा शुल्क से मुक्त थी। प्रत्येक कल्पनीय पदार्थ की जो सूची में नहीं था, जांच होती थी और उस पर शुल्क लगाया जाता था। इस असंगत पद्धति के स्थान पर, नवीन ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया गया। ऐसी वस्तुओं की सूची, जिस पर शुल्क लगाया गया था

घोषित होने के साथ ही अन्य वस्तुएं शुल्क मुक्त घोषित की गईं।

निस्संदेह, प्रणाली के वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए इस प्रकार के प्रयत्नों के महत्व को जनता ने समझा था, परंतु टैरिफ के पीछे निहित सिद्धांतों को अविश्वास एवं संदेह की दृष्टि से देखा गया। प्रमुख हिंदुस्तानी पत्रिका 'हिंदू पेट्रिएट' ने लिखा कि 'निर्बाध व्यापार अच्छी चीज है,' परंतु सभी देशों के लिए नहीं। 'जहां भारत के आयात शुल्कों को पूरी तरह हटा देना इंग्लैंड के हित में है, वहां भारत का हित इसमें है कि इनका इस प्रकार नियमन हो जिससे गृह उद्योगों के विकास और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन का तालमेल बैठ सके।' <sup>177</sup> भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा डाले गए दबाव का विरोध केवल ब्रिटिश सरकार के समर्थन से ही किया जा सकता था और इस प्रकार का समर्थन केवल वित्तीय संकट के समय इस आधार पर मिलता था कि टैरिफ राजस्व वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ, 1859 में उत्तर सैन्य विद्रोह काल के वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए कैंनिंग ने आयात शुल्क में वृद्धि की थी और वाणिज्यिक समुदाय के रोष का सामना किया था, परंतु वह इस पर भी बच निकला था। कलकत्ता के व्यापारियों के इस विरोध का कि 'नवीन शुल्कों का स्वरूप पश्चिमी है और ये इंग्लैंड में हाल में पारित वाणिज्यिक विधान की विवेकपूर्ण भावना के विरुद्ध है, और बंबई के व्यापारियों की याचिकाओं का कोई लाभ नहीं हुआ।' <sup>178</sup> स्वयं कैंनिंग ने विधान परिषद में विधेयक पेश किया था और उसे दो दिनों में पास करवा लिया था। भारत मंत्री साइड स्टेनली ने कैंनिंग का समर्थन किया और वित्तीय संकट को देखते हुए सीमा शुल्कों में और अधिक वृद्धि का सुझाव दिया। जब चार्ल्स ट्रेवीलियन ने खाल, चीनी, चाय, जूट तथा ज्ञाद्यान पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो चेंबर आफ कॉमर्स की ओर से पुनः विरोध हुआ। <sup>179</sup> ट्रेवीलियन को परिषद के अपने सहयोगियों का तो समर्थन मिला, परंतु उसे भारत मंत्री की स्वीकृति नहीं मिल सकी। भारत मंत्री ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले व्यापार का हित है कि नए निर्यात शुल्कों की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। <sup>180</sup> भारत सरकार को बदनाम होकर पीछे हटना पड़ा और 1865 के सीमा शुल्क एक्ट XVIII की निर्यात शुल्कों से संबंधित कुछ धाराएं रद्द कर दी गईं। जो लोग भारत की टैरिफ नीति को नियंत्रित करते थे वे भारत में ब्रिटिश वाणिज्यिक समुदाय के दबाव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थे, परंतु उनके बीच घुनिट गठबंधन नहीं था। वे लोग कुछ सीमाओं के भीतर सहानुभूति दिखलाते थे। ये सीमाएं सामान्य वित्तीय स्थिति, गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण, हितबद्ध गुटों के द्वारा डाले जाने वाले दबाव की मात्रा तथा सरकारी निर्णयों के हिंदुस्तानी पर संभावित प्रभाव के अनुमान द्वारा निर्धारित होती थी।

के लिए छोड़ दी जानी चाहिए...<sup>181</sup> यह भी दावा किया गया कि हिंदू और मुगल वित्तीय प्रणालियों का प्रशासन सघातमक आधार पर होता था।<sup>182</sup> चूंकि मद्रास का गवर्नर ट्रैवोलियन जेम्स विल्सन के केंद्रीकरण नीति का विरोध कर रहा था, इसलिए उसे पूरा समर्थन दिया गया।<sup>183</sup> 'हिंदू पेट्रिअट' को विकेंद्रीकरण के प्रति इसलिए आकर्षण था क्योंकि उसका विद्वानस था कि बंगाल से साम्राज्य के प्रयोजनार्थ उसके न्याय-पूर्ण अंश से वहीं अधिक बगून किया जाता था। उसने लिखा कि बंगाल के साथ सदैव ही समस्त साम्राज्य के लाभ के लिए दुधारू गाय की भांति व्यवहार किया गया है।<sup>184</sup> पत्रिका की राय में विकेंद्रीकरण योजना का प्रमुख आकर्षण यह था कि इससे समस्त प्रांतों के बीच वितरण न्यायपूर्ण हो जाएगा।<sup>185</sup> द्वितीय, विकेंद्रीकरण का स्वागत इस लिए भी हुआ क्योंकि इसे 'भारतीयों को स्थानीय सरकार से संबद्ध करने' की दिशा में एक कदम माना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की थी कि स्थानीय सरकारों को 'राज्य विधेय के अनुसार करों को बढ़ाने का अधिकार होगा' और 'लोगों को प्रशासन में व्यावहारिक स्तर पर यथासंभव भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए'।<sup>186</sup> 'हिंदू पेट्रिअट' के अनुसार मेयो की योजना सही दिशा में कदम थी, परंतु 'बहुत आगे नहीं जाती थी'।<sup>187</sup> पत्रिका की कल्पना में अंतिम लक्ष्य संघीय राज्य था... 'जो एक राज्यमंडल होगा जिसमें प्रत्येक राज्य का अपना विधानांग और कार्यांग होगा, प्रत्येक राज्य अपने ही साधनों पर निर्भर होगा...'।<sup>188</sup> इन मापदंडों के आधार पर मेयो की योजना में वस्तुतः बहुत थोड़े विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने इसे 'अनिच्छापूर्वक दी गई रियायत' माना था जिसे सरकार से लोक मत के दबाव से छीन लिया गया था, परंतु वह अन्य दृष्टियों से महत्वहीन थी।<sup>189</sup>

विकेंद्रीकरण की योजना इसलिए आकर्षक थी क्योंकि इसके अंतर्गत स्थानीय वित्त के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी अधिक होने की संभावना थी। यह योजना प्रांतीय अथवा जिसे बहुधा 'वर्गीय भावना' कहा जाता था, को आंकषित करती थी। प्रति वर्ष बजट के प्रकाशन के बाद भारतीय तथा ऐंग्लो इंडियन समाचारपत्र एक कार्य करते थे। यह था प्रत्येक राज्य का राजस्व में योगदान और उसकी 'प्राप्तियों' का परिकलन। लोक निर्माण पर निवेश के असंतुलित क्षेत्रीय वितरण से आपस में बहुत ईर्ष्या थी। उदाहरण के लिए बंगाल की पत्रिकाओं की शिकायत थी कि बंगाल और मद्रास के साथ अधिमान्य व्यवहार (सरजोही सलूक) किया जाता था जबकि 'सभी प्रेसीडेंसियों में सर्वाधिक संपन्न प्रेसीडेंसी (बंगाल) दीपक के इतने निकट है कि उसे प्रकाश का न्यायोचित अंश नहीं मिल पाता'।<sup>190</sup> तथ्य क्या थे? 1862 तक बंगाल को लोक निर्माण पर निवेश का 15 प्रतिशत मिलता था जो बंबई को मिलने वाले अंश के बराबर था परंतु पश्चिमोत्तर प्रांत और मद्रास के अंशों से काफी कम था। सैन्य विद्रोह के काल में सैनिक कार्यवाही तथा सैन्य विद्रोह के बाद समुत्थान की अवधि में अन्य निर्माण कार्यों की आवश्यकताओं के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत तथा अवध में कुछ असाधारण व्ययों की आवश्यकता थी। संभवतः इस तथ्य ने सरकार के सिचाई नहरों और बांधों के अनुरक्षण में पूंजी निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित किया कि बंगाल

घोषित होने के साथ ही अन्य वस्तुएं शुल्क मुक्त घोषित की गईं।

निस्संदेह, प्रणासी के वैज्ञानिक पुनर्मंडन के लिए इस प्रकार के प्रयत्नों के महत्व को जनता ने समझा था, परंतु टैरिफ के पीछे निहित मिद्धातों को अविश्वाम एवं संदेह की दृष्टि से देखा गया। प्रमुख हिंदुस्तानी पत्रिका 'हिंदू पेट्रिएट' ने लिखा कि 'निर्वाध व्यापार अच्छी चीज है,' परंतु सभी देशों के लिए नहीं। 'जहां भारत के आयात शुल्कों को पूरी तरह हटा देना इंग्लैंड के हित में है, वहां भारत का हित इसमें है कि इनका इस प्रकार नियमन हो जिससे गृह उद्योगों के निकास और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन का तालमेल बैठ सके।'<sup>177</sup> भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा डाले गए दबाव का विरोध केवल ब्रिटिश सरकार के समर्थन से ही किया जा सकता था और इस प्रकार का समर्थन केवल वित्तीय संकट के समय ही आधार पर मिलता था कि टैरिफ राजस्व वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ, 1859 में उत्तर मैन्य विद्रोह काल के वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए कनिंग ने आयात शुल्क में वृद्धि की थी और वाणिज्यिक समुदाय के रोष का सामना किया था, परंतु वह इस पर भी बच निकला था। कलकत्ता के व्यापारियों के इस विरोध का कि 'नवीन शुल्कों का स्वरूप पश्चिमी है और ये इंग्लैंड में हाल में पारित वाणिज्यिक विधान की विवेकपूर्ण भावना के विरुद्ध है, और बंबई के व्यापारियों की माचिकाओं का कोई लाभ नहीं हुआ।'<sup>178</sup> स्वयं कनिंग ने विधान परिषद में विधेयक पेश किया था और उसे दो दिनों में पास करवा लिया था। भारत मंत्री लार्ड स्टेनली ने कनिंग का समर्थन किया और वित्तीय संकट को देखते हुए सीमा शुल्कों में और अधिक वृद्धि का सुझाव दिया। जब चार्ल्स ट्रेवीलिमन ने लाल, चीनी, चाय, जूट तथा खाद्यान्न पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो चेंबर आफ कॉमर्स की ओर से पुनः विरोध हुआ।<sup>179</sup> ट्रेवीलियन को परिषद के अपने सहयोगियों का तो समर्थन मिला, परंतु उसे भारत मंत्री की स्वीकृति नहीं मिल सकी। भारत मंत्री ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले व्यापार का हित है कि नए निर्यात शुल्कों की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।<sup>180</sup> भारत सरकार को बदनाम होकर पीछे हटना पड़ा और 1865 के सीमा शुल्क एक्ट XVIII की निर्यात शुल्कों से संबंधित कुछ धाराएं रद्द कर दी गईं। जो लोग भारत की टैरिफ नीति को नियंत्रित करते थे वे भारत में ब्रिटिश वाणिज्यिक समुदाय के दबाव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थे, परंतु उनके बीच घृणित गठ-बंधन नहीं था। वे लोग कुछ सीमाओं के भीतर सहानुभूति दिखलाते थे। ये सीमाएं समग्र वित्तीय स्थिति, गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण, हितबद्ध गुटों के द्वारा डाले जाने वाले दबाव की मात्रा तथा सरकारी निर्णयों के हिंदुस्तानी लोकमत पर संभावित प्रभाव के अनुमान द्वारा निर्धारित होती थी।

भारतीय समाचारपत्र परवर्ती राष्ट्रवादियों की भांति वित्त के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। मेयो की वित्तीय अंतरण विख्यात योजना के एक दशक पूर्व 'हिंदू पेट्रिएट' लिख रहा था कि हमारे विचार में सही उपाय वित्त का विकेंद्रीकरण है... पहले साम्राज्यिक प्रभार तय हो जाने चाहिए और प्रत्येक प्रांत का यथानुपात योगदान निर्धारित हो जाना चाहिए। शेष रकम प्रांतों के पास स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति

जो कुछ छोड़ दिया था, उसे किस प्रकार पुनः प्राप्त किया जाए यह एक समस्या थी। हम देख चुके हैं कि स्थाई बंदोबस्त के लाभभोगी जमींदार वर्ग ने बावजूद इसके कि मालगुजारी स्थाई रूप से निर्धारित हो चुकी थी, अपनी आय पर करों का कितना विरोध किया था।

सरकारी सिद्धांत के अनुसार मालगुजारी कर न होकर लगान थी। जान स्ट्रुची ने एक प्रसिद्ध जापन पत्र में लिखा था कि 'अति प्राचीन काल से भारत में अधिकांश भू संपत्ति, सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही में, राज्य के पास रही है और राज्य लगान का वह अंश लेता रहा है जो उसके लिए संभव अथवा समीचीन था। भारत की मालगुजारी भूमि पर लगान का बस यही भाग है।'<sup>196</sup> मालगुजारी को कर से भिन्न मानना सिद्धांत मात्र नहीं था। इस प्रकार की व्याख्या का अर्थ था कि मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त के द्वारा राज्य ने प्रजा पर कर लगाने के अधिकार का परित्याग नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, मालगुजारी निर्धारित हो गई थी और सरकार पर मालगुजारी पर उप कर (सेस) लगाने अथवा कृषि आय पर आय कर लेने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं था। बंगाल से भू स्वामी वर्गों ने आय कर अथवा स्थानीय करों के प्रति कभी भी सतोष व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे इन करों को स्थाई बंदोबस्त का उल्लंघन मानते थे। जेम्स विल्सन के समय से सरकारी मत यह था कि जमींदारों ने राजस्व की स्थिरता को सभी करों से मुक्ति समझकर कानून का गलत अर्थ लगा लिया है। 'यह कहना कि चूंकि सरकार ने लगभग सौ वर्ष पहले बंगाल में कतिपय व्यवस्थाएं की थीं, इसलिए बंगाल के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र का सबसे संपन्न वर्ग सदा के लिए कर से मुक्त है', 'एक स्पष्ट असंगत बात' थी।<sup>197</sup> बंगाल के जमींदार वर्ग द्वारा 'दावों' की यह अधीरता बंगाल चेंबर आफ कामर्स अथवा अंग्रेजी बहुमत वाले कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन (जिनका जमींदारी व्यवस्था में कोई हित निहित नहीं था) जैसे भारत में अंग्रेज व्यापारी गुटों में तो स्वाभाविक थी ही, बंगाल के बाहर करदाताओं की भी यही स्थिति थी। बंबई, अहमदाबाद, मद्रास से भेजे गए स्मरण पत्रों में बार-बार यही विषय रहता था कि भूमि के रूप में संपत्ति रखने वाले सभी व्यक्ति राष्ट्रीय राजस्व में यथोचित अंशदान नहीं कर रहे हैं जबकि व्यापारिक एवं व्यावसायिक आय पर भारी कर लगाए जा रहे हैं।<sup>198</sup> बंबई के हिंदुस्तानी व्यापारियों की याचिका में स्वार्थों में टकराव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इन्होंने सरकार से याचिका में आग्रह किया था कि 'निष्क्रिय और संपन्न वर्गों के लाभ के लिए औद्योगिक वर्गों पर कर न लगाया जाए...संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में श्रम से आय तथा व्यापार और व्यवसायों से आय पर हलके कर लगाए जाएं...'<sup>199</sup>

इस लेख सर्वेक्षण से भारत की जिन समस्याओं के बारे में 'लोकमत' की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं वे हैं: प्रथम, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कर भार संबंधी प्रश्न तथा करदाताओं का प्रतिनिधित्व; द्वितीय, वित्तीय नीति के वे अंगभूत तत्व जिन्होंने जनता का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया था और जो राष्ट्रीय आलोचना

स्वाई बंदोबस्त के अंतर्गत था और कृषि आय में वृद्धि से राज्य की तुलना में भू स्वामी वर्गों को अधिक लाभ मिलने की संभावना थी। 1861-62 से परिस्थितियों में अतिरिक्त तत्त्व जुड़े। वे थे पश्चिमी भारत में कपास में तेजबाजारी का प्रभाव और अमरीका में गृह युद्ध के कारण कपास के अभाव से संतुष्ट लंकाशायर को कपास की आपूर्ति के लिए कपास क्षेत्र से बदरगाहों तक सड़कों के निर्माण की लिए सहज प्रेरणा।<sup>191</sup> इसके बाद से वित्त के आवंटन में बंबई के साथ अधिमान्य व्यवहार (तरजीही सलूक) होने लगा। इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित हितों ने इस बात के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला। 1863-66 की अवधि में बंबई को औसतन प्रति वर्ग 1 करोड़ रुपये से अधिक दिया गया (सामान्य लोक निर्माण कार्यों पर व्यय का 24 प्रतिशत), जबकि बंगाल में औसतन 81 लाख रुपये प्रति वर्ग (कुल का 27 प्रतिशत), मद्रास में 66 लाख रुपये (13.9 प्रतिशत), तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में 61 लाख रुपये (12.9 प्रतिशत) व्यय किए गए।<sup>192</sup> अगले पांच वर्षों में बंबई प्रेसीडेंसी का भाग कुछ कम हो गया और पंजाब का बढ़ गया। तथापि 1863-72 में लोक निर्माण पर औसत वार्षिक व्यय मद्रास (प्रति वर्गमील 45 रुपये) और बंगाल (34 रुपये) की तुलना में बंबई (प्रति वर्गमील 79 रुपये) और पश्चिमोत्तर प्रांत (79 रुपये) में बहुत अधिक था।<sup>193</sup> हम एक पिछले अध्याय में बतला चुके हैं कि 1971 में लोक निर्माण पर प्रति व्यक्ति व्यय (साधारण) बंबई में 0.53 रुपया और मद्रास व बंगाल में महज 0.1 रुपया था। बंबई नगर और उसके भीतरी प्रदेश के द्रुत आर्थिक विकास का आंशिक कारण यह था कि कुछेक आधार-भूत आर्थिक संरचनाओं में सार्वजनिक पूंजी निवेशों के वितरण में बंबई प्रेसीडेंसी के प्रति अधिमान्य व्यवहार (तरजीही सलूक) किया गया था।

इस प्रश्न के साथ मालगुजारी अथवा करो के रूप में प्रत्येक प्रेसीडेंसी अथवा प्रांत के अंशदान का प्रश्न भी जुड़ा हुआ था। यद्यपि बंगाल प्रत्यक्ष करो और वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों की दृष्टि से अन्य प्रेसीडेंसियों से आगे था, तथापि 1793 के स्वाई बंदोबस्त के कारण इसमें मालगुजारी प्रायः स्थिर रही। 1856-57 से 1870-71 की अवधि में भारत में मालगुजारी में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस अवधि में बंबई में 37 प्रतिशत, अवध में 36 प्रतिशत, मद्रास में 16 प्रतिशत, पंजाब में 7 प्रतिशत और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, बंगाल तथा मध्य प्रांत में 6 प्रतिशत या इससे कम वृद्धि हुई।<sup>194</sup> इस अवधि में भूमि के मूल्यों में घीमी किंतु नियमित वृद्धि, अवध और उड़ीसा में बंदोबस्त और मालगुजारी के पुनर्निर्धारण, सैन्य विद्रोह के बाद राज्य द्वारा अधिहरण, आबादी के क्षेत्र में वृद्धि, 1861-64 में पश्चिमी भारत में कपास की तेजबाजारी इत्यादि के कारण कुल मिलाकर वृद्धि की दर पर्याप्त ऊंची थी। 1871 में प्रति वर्गमील मालगुजारी बंगाल (177 रुपये) में बंबई (200 रुपये) अथवा पश्चिमोत्तर प्रांत (452 रुपये) की अपेक्षा बहुत कम थी।<sup>195</sup> स्वाई बंदोबस्त के क्षेत्र में सरकार की मांग निर्धारित हो जाने का परिणाम यह हुआ कि उस पर ऐसी आय के लिए दावा करने पर रोक लग गई, जो उसे अस्वाई बंदोबस्त के क्षेत्र में मालगुजारी के पुनर्निर्धारण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा मिल सकती थी। स्वाई बंदोबस्त हो जाने पर सरकार ने मालगुजारी के रूप में





के स्थाई विषय थे : आय कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष कर और अफीम, उत्पाद शुल्क (आवकारी) तथा स्टाप से प्राप्त राजस्व जिनके कारण 'नैतिकता संबंधी टेढ़े-मेढ़े प्रश्न उठाए गए, सैन्य एवं गृह खर्च जो सदा राष्ट्रवादियों के अभियोग पत्र में तगड़े दंग से रखे जाते थे और ब्रिटिश पूँजी तथा निर्मित माल के आयात से संबंधित प्रश्न; और तृतीय, लोक निर्माण कार्यों में पूँजीनिवेश, विभिन्न क्षेत्रों में भूमि कर के प्रति व्यक्ति भार इत्यादि के आधार पर भारतीय साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों के बीच लाभों का वितरण तथा उनके अंशदान। इस संबंध में हम दो समस्याओं का उत्तेजक पहले ही कर आए हैं। प्रथम तो समाचार पत्रों, पॉपुलैटो, स्मरण पत्रों तथा सार्वजनिक संघों के वक्तव्यों से लिए गए उद्धरणों के आधार पर इतिहास रचना के प्रयोग में, दूसरे प्रयोगों की तुलना में, संभवतः पूर्व धारणाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक है।

द्वितीय, 'राष्ट्रवादी मत' और 'लोकमत' शब्दों के प्रयोग से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्या इस काल में ऐसे सशक्त विचार थे कि जिन्हें राष्ट्रवादी सिद्धांत अथवा मत कहा जा सकता है? जैसा कि बार्टल फोर ने प्रश्न उठाया था, क्या प्रकाशित मत ही लोकमत है? प्रकाशित मत को जनता में से अन्य लोग कहां तक स्वीकार करते हैं? क्या लोकमत को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि विशिष्ट मत देश की संपूर्ण जनता में किस हद तक प्रचलित है, अथवा केवल राजनीतिक दृष्टि से सगत 'विशिष्ट वर्ग' के आधार पर निर्णय कर लेना चाहिए? ये शब्द कितने ही अस्पष्ट क्यों न हों, हमने इन्हें उन स्थितियों में प्रयोग करना उपयोगी पाया है जब विशिष्ट संदर्भ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मत की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का स्रोत क्या है। संभवतः 'लोक (जनता)' संबंधी धारणा को अवखंडित करके वर्गों के अर्थ में सोचना, और 'सामान्य अभिलाषा' की रहस्यमय अभिव्यक्तियों को खोजने के स्थान पर विचारों और मतों में विविधता का अध्ययन उपयोगी है। हमने बहुधा देखा है कि न केवल एक ओर 'साहबों' और दूसरी ओर 'जमींदारों', धनियों तथा शिक्षित 'बाबुओं' में विरोध था, वरन् शासित प्रजाति के विभिन्न वर्गों में भी परस्पर विरोध था। शहरी व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्ग की लगानभोगी जमींदार वर्ग (जो लाइसेंस कर से मुक्त था और जिसे अपनी अनर्जित आय पर उसी दर से आय कर देना होता था जिस दर से व्यापार अथवा उच्च शिक्षा वाले व्यवसायों में लगे हुए व्यक्ति आय कर देते थे) के प्रति नाराजगी, ऊंची आय पाने वाले वर्गों के सरकार को अवरोही परीक्षा कर (विशेष रूप से नमक शुल्क को वस्तुतः जन साधारण पर व्यक्ति कर था) लगान के लिए राजी करने के लिए प्रयास, ताकि वे आय करों के भार से मुक्त हो सकें, सरकारी पूँजीनिवेशों के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष एतत्संबंधी कुछ उदाहरण हैं। प्रस्तावना वाले अध्याय में हमने हितवद् मुद्दों में विरोध का अध्ययन किया है और देखा है कि प्रत्येक मुद्दे वित्तीय नीति निर्णयों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विकास काल के प्रारंभिक वर्षों में इस समस्या की ओर ध्यान दिया था कि किस प्रकार प्रमुख हितों के प्रतिनिधित्व की स्थाई व्यवस्था हो सके। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में के० टी० सेलंग ने विधान मंडल में चैवर्म आफ काममें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, विश्व-

विद्यालयों तथा स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। दूसरे अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्रलाल मित्र ने कहा कि विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य 'अपने हितों' के अलावा किसी अन्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कांग्रेस ने 'वर्गीय हितों' को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा। कलकत्ता कांग्रेस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो इस बात के लिए उत्सुक थे कि सभी वर्गों, समुदायों और 'सभी प्रधान हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए', तेलंग की रूपरेखा के आधार पर एक योजना प्रस्तुत की। इसके कुछ समय बाद ही, 1888 में विधान परिषद सुधार समिति ने, जिसे डफरिन ने नियुक्त किया था वशानुगत अभिजात वर्ग एवं भू स्वामी वर्गों, व्यापारी, व्यावसायिक एवं कृषक वर्गों और यूरोपीय बागान एवं वाणिज्यिक हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विविध उपायों की सिफारिश की। अंततोगत्वा 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के पारित हो जाने पर इनमें से कुछ हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर पाना संभव हो सका।<sup>200</sup>

इसी समय आर्थिक राष्ट्रवाद के कुछ तत्व 'वर्गीय' सिद्धांतों से आगे बढ़कर अंकुरित हो रहे थे। भिन्न-भिन्न हितों के परस्पर विरोधी दबावों के बीच, किन्हीं-किन्हीं समस्याओं पर कुछ एक सी भावनाएं उभरीं जैसे नौकरशाही में अपव्ययी ब्रिटिश कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारियों को रखने की इच्छा, बढ़ते हुए सैन्य एवं गृह खर्चों के प्रति असंतोष, सामान्य रूप से लोक व्यय में कमी की मांग जिससे कर भार को कम किया जा सके, टैरिफ नीति के संबंध में परंपरागत ज्ञान की प्रेरणा के विषय में नदेह, कराधान के साथ प्रतिनिधित्व पाने की आकांक्षा और कुछ ऐसी ही अन्य समस्याएं थी जो शासित देश की आम शिकायतों से उत्पन्न हुई थी। इस काल में जो विचार प्रकट किए गए थे उनमें और कांग्रेस के अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षों के उसके प्रस्तावों में समानता दिखाई देती है। नौरोजी की प्रधान उपलब्धि थी इन विचारों की सघट अभिव्यक्ति, इनका गुंफन और निर्णायक महत्व की कुछ समस्याओं पर जोर देना। ये समस्याएं थी, क्या भारत में कराधान का प्रभाव लोक व्यय के आय एवं रोजगार उत्पादन करने वाले प्रभाव द्वारा प्रति संतुलन होता है, स्टलिंग के रूप में ऋण भार तथा भारत के बाहर सरकारी व्यय में वृद्धि द्वारा गृह खर्चों में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, करदेय क्षमता और प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कर भार की स्थिति है, और सबके ऊपर यह कि 'जो कुछ भी जनसाधारण से किया जाता है वह उसे किस प्रकार वापस किया जा सकता है।' नौरोजी की जांच लोक वित्त के क्षेत्र से बाहर संसदीय बागजात से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भुगतान संतुलनों के व्यापक अध्ययन तक विस्तृत थी। इसके आधार पर उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में 'आर्थिक विकास' की समस्या की विस्तृत व्याख्या की थी। नौरोजी के कोषों के स्थानांतरण के सभी संभव माध्यमों पर विचार किया। हमने अपने को लोक वित्त के प्रश्नों तक सीमित रखते हुए केवल उन्हीं समस्याओं पर विचार किया है (अध्याय III और V में) जो नौरोजी की भाषा में सरकारी संव्यवहार में उत्पन्न होती है, जैसे राजनीतिक ऋणों के लिए स्टलिंग ऋण प्रभार, रेल, लोह निर्माण, इंग्लैंड में किए जाने

के स्थाई विषय थे: आय कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष कर और अफीम, उत्पाद शुल्क (आवकारी) तथा स्टॉपसे प्राप्त राजस्व जिनके कारण 'नैतिकता संबंधी टेढ़े-मेढ़े प्रश्न उठाए गए, सैन्य एवं गृह खर्च जो सदा राष्ट्रवादियों के अभियोग पत्र में तगड़े ढंग से रखे जाते थे और ब्रिटिश पूँजी तथा निर्मित माल के आयात से संबंधित प्रश्न; और तृतीय, लोक निर्माण कार्यों में पूँजीनिवेश, विभिन्न क्षेत्रों में भूमि कर के प्रति व्यक्ति भार इत्यादि के आधार पर भारतीय साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों के बीच लाभों का वितरण तथा उनके अंशदान। इस संबंध में हम दो समस्याओं का उल्लेख पहले ही कर आए हैं। प्रथम तो समाचार पत्रों, पैंफलेटों, स्मरण पत्रों तथा सार्वजनिक संघों के वक्तव्यों से लिए गए उद्धरणों के आधार पर इतिहास रचना के प्रयोग में, दूसरे प्रयोगों की तुलना में, संभवतः पूर्व धारणाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक है।

द्वितीय, 'राष्ट्रवादी मत' और 'लोकमत' शब्दों के प्रयोग में प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्या इस काल में ऐसे सशक्त विचार थे कि जिन्हें राष्ट्रवादी सिद्धांत अथवा मत कहा जा सकता है? जैसा कि बार्टन फ़ोर ने प्रश्न उठाया था, क्या प्रकाशित मत ही लोकमत है? प्रकाशित मत को जनता में से अन्य लोग कहा तक स्वीकार करते हैं? क्या लोकमत को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि विशिष्ट मत देश की संपूर्ण जनता में किस हद तक प्रचलित है, अथवा केवल राजनीतिक दृष्टि से संगत 'विशिष्ट वर्ग' के आधार पर निर्णय कर लेना चाहिए? ये शब्द कितने ही अस्पष्ट क्यों न हों, हमने इन्हें उन स्थितियों में प्रयोग करना उपयोगी पाया है जब विशिष्ट संदर्भ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मत की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का स्रोत क्या है। संभवतः 'लोक (जनता)' संबंधी धारणा को अव्यक्तित्व करके वर्गों के अर्थ में सोचना, और 'सामान्य अभिलाषा' की रहस्यमय अभिव्यक्तियों को खोजने के स्थान पर विचारों और मतों में विविधता का अध्ययन उपयोगी है। हमने बहुधा देखा है कि न केवल एक ओर 'साहबों' और दूसरी ओर 'जमींदारों', 'बनियों' तथा शिक्षित 'बाबुओं' में विरोध था, वरन् शासित प्रजाति के विभिन्न वर्गों में भी परस्पर विरोध था। शहरी व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्ग की लगानभोगी जमींदार वर्ग (जो लाइसेंस कर से मुक्त था और जिसे अपनी अनर्जित आय पर उसी दर से आय कर देना होता था जिस दर से व्यापार अथवा उच्च शिक्षा वाले व्यवसायी में लगे हुए व्यक्ति आय कर देते थे) के प्रति नाराजगी, ऊँची आय पाने वाले वर्गों के सरकार की अवरोही परीक्षा कर (विशेष रूप से नमक शुल्क को वस्तुतः जन साधारण पर व्यक्ति कर था) लगान के लिए राजी करने के लिए प्रयास, ताकि वे आय करों के भार से मुक्त हो सकें, सरकारी पूँजीनिवेशों के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष एतत्संबंधी कुछ उदाहरण हैं। प्रस्तावना वाले अध्याय में हमने हितबद्ध गुटों में विरोध का अध्ययन किया है और देखा है कि प्रत्येक गुट वित्तीय नीति निर्णयों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विकास काल के प्रारंभिक वर्षों में इस समस्या की ओर ध्यान दिया था कि किस प्रकार प्रमुख हितों के प्रतिनिधित्व की स्थाई व्यवस्था हो सके। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में के० टी० तैलंग ने विधान मंडल में चेंबर आफ कामर्स, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, विश्व-

बहुत दूर तक फैले थे। कार्यवाही की तात्कालिक उपलब्धियां थोड़ी ही थी। परंतु एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के आविर्भाव में सुविधा हो गई थी। शीघ्र (ही राजनीति के क्षेत्र में) नया खेल प्रारंभ होना था जिसके दांव ऊंचे थे।

## संदर्भ

1. 'फाइनेंशल स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग टु इंडिया' रिप्रिंटेड फ्रॉम हंसार्ड्स पार्लियामेन्टरी डिबेट्स, पृ० 680। ग्रैंट हफ ने भारत की राशि की तुलना इंग्लैंड की राशि से की है, जो प्रति वर्ष 30 पौंड प्रति व्यक्ति थी।
2. दादाभाई नौरोजी 'दि पावर्टी आफ इंडिया' (बवई 1876) पृ० 1-142।
3. डी० थोर्नर के अनुसार पिछड़ी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के परिकलन में सेवाओं के क्षेत्र में सम्मिलित न करना बहुत युक्तिसंगत है। एम० एस० कुजनेत्स, 'इकानामिक प्रोय' (1955) पृ० 10। देखें मुर्रे जे० पटेल 'लाग टर्म चेंजेज इन आउटपुट एंड इनकम इन इंडिया' 1866-1960 'दि इंडियन इकानामिक जर्नल', जनवरी, 1958, वॉल्यूम V, संख्या 3, पृ० 233-46।
4. 'इंडियन इकानामिस्ट' 21 अक्टूबर, 1871।
5. एम० ए० हिडमैन, 'बैंकरप्सी आफ इंडिया,' (सदन, 1886), पृ० 157।
6. 'टाइम्स आफ इंडिया' 13 नवंबर, 1863।
7. 'फ्रीड आफ इंडिया' 27 जून, 1861।
8. 'फ्रीड आफ इंडिया' 4 फरवरी, 1868। बगाल चेंबर आफ कामर्स के अनुसार राशि केवल 2 शिलिंग थी। राजस्व कार्यविवरण जून, 1867, संख्या 50।
9. 'इंडियन इकानामिस्ट' 21 अक्टूबर, 1871।
10. एच० एम० हिडमैन, 'बैंकरप्सी आफ इंडिया' (सदन, 1866) पृ० 157।
11. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 144, 29 जून, 1860।
12. वही।
13. वही, 240, 20 सितंबर, 1869।
14. 1868 में 'फ्रीड आफ इंडिया' (27 जून, 1861 तथा 4 फरवरी, 1868) ने प्राक्कलित किया कि भारत में प्रति व्यक्ति कर भार 6 शिलिंग या जबकि इंग्लैंड में 2 पौंड 16 शिलिंग 3 पेंस सयुक्त राज्य अमरीका से 2 पौंड 16 शिलिंग 1 पेंस और फ्रांस से 1 पौंड 19 शिलिंग 1 पेंस था। 31 अक्टूबर, 1873 के 'दि इंडियन इकानामिस्ट' ने दावा किया था कि 1 शिलिंग 6 पेंस प्रति व्यक्ति कराधान की स्थिति में 'इस देश में कर भार विश्व भर में सब से कम था।'
15. 'फ्रीड आफ इंडिया,' 22 मार्च, 1860।
16. वही 26 मार्च, 1861।
17. वही 13 दिसंबर, 1866।
18. 'टाइम्स आफ इंडिया' 15 अगस्त, 1865।
19. वही।

वाले प्रशासनिक एवं सैन्य खर्च, सरकार द्वारा भंडार संबंधी खरीद इत्यादि। यहाँ पर हम यह उल्लेख मात्र कर देना चाहेंगे कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने राजनीति के लिए नौरोजी के विचारों को अपनाने में विसंशय ढंग से चुनाव किया था। गांगुली ने स्पष्ट किया है कि नौरोजी के सिद्धांत में कुछ प्रगतिशील तत्व थे जैसे अवरोही कृषि व्यवस्था की निंदा; 'साधारण कुली मजदूर' के हितों का उत्साहपूर्ण समर्थन जिन पर कि ऊँची आय पाने वाले वर्गों की तुलना में नमक शुल्क का भार कहीं अधिक था; यह संकेत कि 'धूँक संपन्न वर्ग आंदोलन कर सकते हैं और अपनी बात सुनने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं जबकि निर्धन श्रमिकों और कृषकों के लिए यह संभव नहीं है' अतः उन्हीं का कराधान के माध्यम से शोषण होना; आंतरिक 'आर्थिक विकास' की धारणा अर्थात् कराधान द्वारा ग्रामीण जनता की संपत्ति के हस्तांतरण एवं शहरी पूँजीपति वर्ग के पक्ष में आय के पुनर्वितरण के विषय में विचार।<sup>201</sup> यह महत्वपूर्ण बात है कि नौरोजी के सिद्धांत के इन तत्वों को ('बाहरी आर्थिक विकास' से संबंधित विचारों के विपरीत) उत्साहपूर्ण समर्थन मिलना तो दूर रहा, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। वस्तुतः स्वयं नौरोजी ने भी 'आंतरिक विकास' के बारे में अपने विचारों को विशिष्टता प्रदान नहीं की। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार रमेश चंद्र दत्त ने, जिन्होंने 1875 में रयत की उपज पर जमींदार के दाये को स्थाई रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता के विषय में साहस के साथ लिखा था और जिनकी 'हिंदू पैट्रियट' ने 'उग्रवादी भावना' के लिए अच्छी तरह भर्त्सना की थी, अपनी परिपक्व तथा सुप्रचारित रचनाओं में जमींदार रयत संबंध के शोषणकारी पहलुओं से अपना ध्यान हटा लिया था।<sup>202</sup> संभवतः नौरोजी तथा दत्त जैसे वैचारिक क्षेत्र के नेताओं का खयाल था कि उन्हें पहले स्वकल्पित 'विदेशी शोषण' के विरुद्ध संघर्ष करना है। बंगाल के जमींदार, बंबई के बनिये अथवा शहरों के शिक्षित व्यावसायिक वर्गों के लोग अन्य प्रकार के शोषणों को जिनमें उनके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग और भागीदारी का संदेह किया जाता था, छोड़कर केवल उपर्युक्त शोषण के बारे में संदेश ग्रहण करने के लिए तत्पर थे।

निष्कर्ष के रूप में, यह कहा जा सकता है कि एक ओर विरोधी प्रतिबद्धताओं के एक दूसरे के प्रतिकूल दबाव तथा हितों और निष्ठाओं के बंधन थे और दूसरी ओर विचारधारा का एक स्वरूप उभर रहा था जो राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुआ। दबाव गुटों के कार्य कलाप का महत्व बाद के ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही स्पष्ट होता है। जिस काल का हमने अध्ययन किया है, उसमें (दबाव गुटों) का कार्य कलाप अधो-राजनीतिक स्तर पर चालबाजी का खेल मात्र था। इस खेल में शिक्षित शहरी व्यावसायिक वर्गों को, विरोधी आर्थिक हितों के बीच विरोध की उग्रता का आभास होने लगा था। राष्ट्रीय स्तर पर बंधे हुए हितों के एकत्रीकरण की इस धारणा से ही आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। विचारों के आधार पर बने संगठन शिकायतों अथवा मार्गों के प्रचार के लिए प्रयत्न, लाञ्छनकरण इत्यादि ऐसी रीतियाँ हैं जो राजनीतिक मस्तिष्क को लचीला बनाती हैं। इस प्रकार की कार्यवाही के परिणाम निकटतम कार्यक्षेत्र के बाहर

बहुत दूर तक फैले थे। कार्यवाही की तात्कालिक उपलब्धिया थोड़ी ही थी। परंतु एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के आविर्भाव में सुविधा हो गई थी। शीघ्र (ही राजनीति के क्षेत्र में) नया खेल प्रारंभ होना था जिसके दाव ऊंचे थे।

## संदर्भ

1. 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टु इंडिया' रिप्रिंटेड फ्रॉम हंसाईंस पार्लियामेन्टरी डिबेट्स, पृ० 680। ग्रैंड ब्रिटेन ने भारत की राशि की तुलना इंग्लैंड की राशि से की है, जो प्रति वर्ष 30 पौंड प्रति व्यक्ति थी।
2. दादाभाई नौरोजी 'दि पावर्टी आफ इंडिया' (बंबई 1876) पृ० 1-142।
3. डी० थोर्नर के अनुसार पिछड़ी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के परिकलन में सेवाओं के क्षेत्र में सम्मिलित न करना बहुत युक्तिसंगत है। एम० एस० कुजनेत्स, 'इकानामिक प्रोग्रेस' (1955) पृ० 10। देखें सुरेंद्र जे० पटेल 'लाग टर्म बेंजेज इन आउटपुट एंड इनकम इन इंडिया' 1866-1960 'दि इंडियन इकानामिस्ट' जनवरी, 1958, खंड V, संख्या 3, पृ० 233-46।
4. 'इंडियन इकानामिस्ट' 21 अक्टूबर, 1871।
5. एम० ए० हिंडमैन, 'बैंकरप्सी आफ इंडिया,' (लंदन, 1886), पृ० 157।
6. 'टाइम्स आफ इंडिया' 13 नवंबर, 1863।
7. 'फ्रीड आफ इंडिया' 27 जून, 1861।
8. 'फ्रीड आफ इंडिया' 4 फरवरी, 1868। बंगाल बैंकर आफ कामर्स के अनुसार राशि केवल 2 शिलिंग थी। राजस्व कार्यविवरण जून, 1867, संख्या 50।
9. 'इंडियन इकानामिस्ट' 21 अक्टूबर, 1871।
10. एच० एम० हिंडमैन, 'बैंकरप्सी आफ इंडिया' (लंदन, 1866) पृ० 157।
11. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संख्या 144, 29 जून, 1860।
12. वही।
13. वही, 240, 20 सितंबर, 1869।
14. 1868 में 'फ्रीड आफ इंडिया' (27 जून, 1861 तथा 4 फरवरी, 1868) ने प्रावकलित किया कि भारत में प्रति व्यक्ति कर भार 6 शिलिंग था जबकि इंग्लैंड में 2 पौंड 16 शिलिंग 3 पेंस समुक्त राज्य अमरीका से 2 पौंड 16 शिलिंग 1 पेंस और फ्रांस में 1 पौंड 19 शिलिंग 1 पेंस था। 31 अक्टूबर, 1873 के 'दि इंडियन इकानामिस्ट' ने दावा किया था कि 1 शिलिंग 6 पेंस प्रति व्यक्ति कराधान की स्थिति में 'इस देश में कर भार विश्व भर में सब से कम था।'
15. 'फ्रीड आफ इंडिया,' 22 मार्च, 1860।
16. वही 26 मार्च, 1861।
17. वही 13 दिसंबर, 1866।
18. 'टाइम्स आफ इंडिया' 15 अगस्त, 1865।
19. वही।

20. 'फ्रैंड आफ इंडिया' 13 दिसंबर, 1866 ।
21. 'टाइम आफ इंडिया' 13 नवंबर, 1863 ।
22. 'मद्रास टाइम्स,' 24 अक्टूबर, 1863, 'टाइम आफ इंडिया,' 23 अक्टूबर, 1863 में उद्धृत ।
23. जे० सी० गैडस का साक्ष्य, 'ईस्टर्न इकानामिस्ट,' 21 अगस्त, 1871 में उद्धृत । संपादक राबर्ट नाइट के मतानुसार यह सिद्धांत पूर्ण रूप से गलत था ।
24. एच० एम० हिंडमैन, 'दि बैंकरप्सी आफ इंडिया' (मदन, 1886) पृ० 41 ।
25. 'बेलगांव समाचार,' 20 अप्रैल, 1868, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 21 ।
26. 'रास्त गोप्तार,' 24 मई, 1868, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 79 ।
27. 'हिंदू हितैषिणी,' 28 मार्च, 1868, आर० एन० पी० (बंगाल), पृ० 150 ।
28. 'सुधावर्धन गजद,' 14 मार्च, 1868, आर० एन० पी० (बंगाल), पृ० 130 ।
29. 'सोमप्रकाश,' 23 दिसंबर, 1867, आर० एन० पी० (बंगाल), पृ० 5 ।
30. 'खानदेश बैभव,' 4 मार्च, 1870, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 133 ।
31. वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1868, सध्या 35 । भारत मंत्री सर स्टेफर्ड नोर्थकोट को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में हुई बैठक में प्रेषित विनम्र स्मरण पत्र, फरवरी, 1868 ।
32. डी० गौरीजी, 'पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (दिल्ली, 1962) पृ० 193 और उसके आगे ।
33. वही, पृ० 195 ।
34. वही ।
35. वही, पृ० 194 ।
36. 'हिंदू पेट्रिअट,' 5 सितंबर, 1860 ।
37. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1850 । लेखा शाखा सध्या 26 । बाबू ईसर चंदर सिंह, सचिव, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारा सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार को प्रेषित, 22 मई, 1860 (राजस्व प्रेषण सध्या 21, 20 अप्रैल, 1867) भारत सरकार से भारत मंत्री को ।
38. वित्त कार्यविवरण अप्रैल, 1868, सध्या 34, बाबू जतींद्र मोहन टैगोर, सचिव, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारा सचिव, बंगाल सरकार को प्रेषित, 3 फरवरी, 1868; सध्या 35 । ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की कलकत्ता से हुई बैठक सर स्टेफर्ड नोर्थकोट को प्रेषित विनम्र स्मरण पत्र दिनांक 1 फरवरी 1868 । और भी देखिए 'हिंदू पेट्रिअट' 23 मार्च, 1868 जिसमें परिषद में होने वाली बहसों को 'ग्रहसन' कहा गया था ।
39. वही ।
40. भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त प्रेषण, सध्या 86, दिनांक 3 अप्रैल, 1878 ।
41. 'हिंदू पेट्रिअट,' 6 अप्रैल, 1868, वही, 6 मार्च, 1868 ।
42. 'सोमप्रकाश,' 9 मार्च, 1868, आर० एन० पी० (बंगाल), पृ० 107 । 'जामे जमोद,' 15 फरवरी, 1869, 10 मार्च, 1869, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 94, 133; 15 सितंबर, 1870, आर० एन० पी० (बंबई) पृ० 442 ।
43. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1868, पृथक् राजस्व सध्या 14 । ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की कलकत्ता में हुई बैठक में भारत मंत्री को प्रेषित विनम्र स्मरण पत्र, 31 मई, 1869 ।

44. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1871, लेखा शाखा सख्या 90, जतींद्र मोहन ठाकुर, सचिव, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारा सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार को प्रेषित, 10 मार्च, 1871 ।
45. मेयो से नेपियर को, 20 नवंबर, 1870, संख्या 325, मेयो कागजात, बडल 41 ।
46. 'हिंदू पेट्रिअट,' 21 फरवरी, 1870 ।
47. 'हिंदू पेट्रिअट,' 11 जुलाई, 1870 ।
48. 'हिंदू पेट्रिअट,' 10 अप्रैल 1870 ।
49. सर बार्टल फेर 'दि मीम आफ अमर्टैनिंग पब्लिक ओपीनियन इन इंडिया', (1871) 'जनरल आफ इंडिया एसोसिएशन,' जिल्द V, खंड IV, पृ० 102 172 ।
50. मेयो से डब्ल्यू० आर्बुथनाट को, 15 मार्च, 1871, मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 68 ।
51. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1868, सख्या 48, सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू से सचिव, फोर्ट सेंट जार्ज की सरकार को, 27 जनवरी, 1868 ।
52. बी० फेर, पूर्वोद्धृत ।
53. मेयो से आरगाइल को, 7 नवंबर, 1870, मेयो कागजात, बडल 41, सख्या 300 ।
54. जे० लारेंस से फ्रेनबोर्न को, 16 सितंबर, 1866, लारेंस कागजात, भारत मंत्री को प्रेषित पत्र, 1866, जिल्द, 3, सख्या 35 ।
55. राजस्व प्रेषण 1867, संख्या 21 । भारत सरकार से भारत मंत्री को प्रेषण, 20 अप्रैल, 1867 ।
56. भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त प्रेषण, संख्या 86, दिनांक 3 अप्रैल, 1868 ।
57. जेम्स स्टलेज 'इंग्लिश क्ल एंड मेटिव ओपीनियन इन इंडिया' (लंदन, 1278) पृ० 219-20 ।
- 57-ए वित्त कार्यविवरण (लेखा शाखा) जून, 1861, सख्या 61, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेषित स्मरण पत्र, 5 जून, 1861 ।
58. 'मद्रास एक्जामिनेर,' 5 फरवरी, 1863, राजस्व कार्यविवरण, जून, 1867, सख्या 50, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामर्स से सचिव, वित्त विभाग, 31 मई, 1867 । वही अगस्त, 1867, सख्या 20, कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा भारत मंत्री को प्रेषित स्मरण पत्र, 22 अप्रैल, 1867 । 'पायनिअर' 2 जनवरी, 1871 । 'इंग्लिशमैन' 11 अप्रैल, 1866 ।
59. मेयो से नेपियर को, 6 अगस्त, 1870, बडल 40, सख्या 225 ।
60. वित्त कार्यविवरण, (लेखा शाखा) जून, 1861, सख्या 62, गवर्नर जनरल से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को ।
61. 'फ्रीड आफ इंडिया,' 26 जून, 16 मार्च, 24 अगस्त, 1865 । 'इंडियन इकानामिस्ट, 21 नवंबर, 1871, 10 सितंबर, 1867 ।
62. मेयो से नेपियर को, 15 मई, 1870, बडल 39, संख्या 119 ।
63. विधान परिषद कार्यविवरण, 14 अप्रैल, 1860, जिल्द VI, पुरानी सीरीज ।
64. 'टाइम्स आफ इंडिया' 13 नवंबर, 1863 ।
65. राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 1867, सख्या 19, कलकत्ता के निवासियों द्वारा स्मरण पत्र ।
66. राजस्व कार्यविवरण, मार्च 1867, सख्या 35 कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका, (जर्जी) 15 मार्च, 1867 ।
67. 'फ्रीड आफ इंडिया' 16 मार्च, 1865 । देखिए राजस्व कार्यविवरण नवंबर, 1880, सख्या



प्रणाली को लागू करने की नीति स्वीकार कर ली गई थी 'फंड ऑफ इंडिया,' 30 सितंबर, 1869 ।

110. वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1871, पृथक राजस्व संख्या 12, ज० वेस्टमिड वित्त अवर सचिव, भारत सरकार से सचिव, बंगाल सरकार को, 14 अक्तूबर, 1871 ।
111. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1866, पृथक राजस्व संख्या 482, चीफ कमिशनर, ब्रिटिश बर्मा से वित्त सचिव, भारत सरकार को, 26 नवंबर, 1864 ।
112. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 144, 29 जून, 1860 ।
113. देखें, सी० एन० वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 484 ।
114. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1868, संख्या 39 । वित्त सचिव, द्वारा टिप्पणी, दिनांक 14 फरवरी, 1868 । वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 483 । गृह कार्यविवरण, लोक शाखा, अप्रैल, 1871, संख्या 13 । गृह सचिव, द्वारा ज्ञापन, दिनांक 14 मार्च, 1870 ।
115. 'हिंदू पेट्रिअट', 115 मई, 1871 ।
116. वही ।
117. 'हिंदू पेट्रिअट', 17 अप्रैल, 1871 ।
118. वही, 15 मई, 1871 ।
119. वही, 11 अप्रैल, 1870; 5 जून, 1871; 'रास्त गोफ्तार', 13 नवंबर, 1870, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 544 ।
120. 'हिंदू पेट्रिअट', 12 दिसंबर, 1860; 30 जून, 1860, 11 जुलाई 1860 ।
121. 'पंजाब अखबार', 8 जून, 1871, एस० बी० एन० (पश्चिमोत्तर प्रांत), 'प्रयाग हूत', आर० एन० पी० (बंगाल), 15 जुलाई, 1868 ।
122. 'रुई नू माई पंजाब', 8 फरवरी, 1867, एस० बी० एन० (पश्चिमोत्तर प्रांत); पृ० 102 ।
123. 'मास्कर', 28 मार्च, 1868, नार० एन० बी० (बंगाल), 1868, पृ० 153 ।
124. वही, 4 जून, 1868, वही, पृ० 21; 'राजशाही पत्रिका', जनवरी, 1868, वही, पृ० 59; 'अवध अखबार', जून, 1868, वही, पृ० 298 ।
125. बादामाई नीरोजी, 'एसेज, स्पीचज, एड्रिसेज एटसट्रा' (बंबई, 1887), पृ० 54 ।
126. 'हिंदू पेट्रिअट', 13 जनवरी, 1868 ।
127. वित्त कार्यविवरण, फरवरी, 1868. लेखा शाखा संख्या 67, गवर्नर जनरल का मेमो०, 20 जनवरी, 1868 ।
128. 'बंबई समाचार', 8 व 9 फरवरी, 1870, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 82 ।
129. 'जामे जमशेद', 23 नवंबर, 1869, वही, पृ० 586 ।
130. वही, 10 मार्च, 1869, वही, पृ० 133 ।
131. 'मुकीर्नबखानी', इन्क्यू० एक० राइट द्वारा मार्च, 1873 के तमिल समाचार पत्रों के विषय में रिपोर्ट (17 मार्च, 1873) ।
132. ईस्ट इंडिया एनोमिएशन की बंबई शाखा द्वारा याचिका (अर्जी), 'जनरल आफ दि ईस्ट इंडिया एनोमिएशन', बिल्ड V, खंड II (1871), पृ० 130-32 ।
133. देखें पीछे अध्याय 3 ।

134. वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 1869, पृथक राजस्व संख्या 14, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में हुई बैठक में पारित विनम्र स्मरण पत्र, भारत मंत्री को प्रेषित, दिनांक 31 मई, 1869 ।
135. 'जामे जमशेद', 4 अगस्त, 1868 को आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 230, 15 मार्च, 1869 आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 144 ।
136. 'रास्त गोस्तार', 30 मई, 1869, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 273, 17 अक्तूबर, 1869, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 525 ।
137. 'हिंदू पेडिगट', 11 अप्रैल, 1870 ।
138. 'पंजाब अखबार', 10 जून 1871, एस० बी० एन० (पश्चिमोत्तर प्रांत) पृ० 303 ।
139. दादाभाई नौरोजी, 'एमेज, स्पीचेज एटसेट्टा' (बंबई, 1887), पृ० 26-30 ।
140. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा द्वारा याचिका 'जर्नल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', जिल्द V, खंड II (1871), पृ० 130-32 ।
141. देखें, 2 सितंबर, 1885 को बंबई में हुई फासट मेमोरियल बैठक में नौरोजी का भाषण, 'स्पीचेज एंड राइटिंग आफ दादाभाई नौरोजी' (मद्रास दिनांक नहीं दिया है), पृ० 171-74 ।
142. एच० फासट, 'इंडियन फाइनेंस' (सदन, 1880), पृ०-52 ।
143. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 149, 22 नवंबर, 1862 ।
144. वही, वित्त संख्या 37, 13 मार्च, 1861 । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 53, 8 अप्रैल, 1861 ।
145. वित्त कार्यविवरण सितंबर, 1861, लेखा शाखा (मदर) सख्या 67, सचिव, सैन्य वित्त विभाग से वित्त सचिव, भारत सरकार को, 23 अगस्त, 1861 ।
146. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 218, 27 दिसंबर, 1862 ।
147. वही, 7 और 27, दिनांक 16 जनवरी, 1866 और 8 फरवरी, 1866 ।
148. वही, 221, 4 अक्तूबर, 1867 । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 464, 23 दिसंबर, 1867 ।
149. वही, वित्त संख्या 8, 11 जनवरी, 1870 ।
150. वही, 114, 18 मार्च 1869 ।
151. जे० स्ट्रैची से मेयो को, 4 अगस्त, 1869, मेयो कागजात, बंडल 60 । मेयो से आरगाइल को, 8 फरवरी, 1870, मेयो कागजात, बंडल 35, संख्या 53 ।
152. वित्त कार्यविवरण, अगस्त, 1871, संख्या 73 । भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 21 जुलाई, 1871 । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 422, 16 नवंबर, 1871 ।
153. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 136, 22 अगस्त, 1860 ।
154. वही, वित्त संख्या 4, 16 जनवरी, 1865 ।
155. नोर्थकोट ने सुल्तान के लिए व्यवस्थित नृत्य पर व्यय को उचित मिद्ध करने का प्रयास किया । उसने लिखा कि 'यद्यपि हम बात की स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं दिखाई देता, तथापि नृत्य पूर्ण रूप से एकमात्र इंडिया आफिस का ही मामला था' एस० नोर्थकोट

से जे० लारेंस को, 1 अक्तूबर, 1867। लारेंस कागजात, भारत मंत्री से पत्र, जिल्द IV, सख्या 41।

156. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 191, 27 अगस्त, 1866; भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 25, फरवरी, 1867।
157. वही, वित्त सख्या 30, 28 फरवरी, 1867।
158. वही।
159. वही।
160. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 73, 8 मार्च, 1867।
161. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 1867, लेखा शाखा, सख्या 70, वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 26 जनवरी, 1867। वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 1869, लेखा शाखा सख्या 63। वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 6 अक्तूबर, 1863।
162. बंगाल में शिक्षा विभाग में अन्य स्थानों की तुलना में वेतनमान ऊंचे थे। भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या 119, 14 जुलाई, 1865। वित्त कार्यविवरण, मार्च, 1868, लेखा शाखा सख्या 111-13। बाद के कार्यविवरण में बंगाल में बर्नाकुलर शिक्षा की स्थिति के विषय में व्यापक प्राप्त लेखक भूदेव मुकर्जी की मनोरंजक रिपोर्ट सम्मिलित है।
163. मेयो से अस्किन पेरी को, 23 मार्च, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 85।
164. मेयो से ई० पेरी को, 26 जुलाई, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 213।
165. मेयो से सर विलियम म्योर को, 4 अगस्त, 1870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 222। मेयो से आरपगाइल को, 17 अक्तूबर, 1869। मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 285।
166. 'इंडियन इकानामिस्ट', 10 सितंबर, 1869, वही, 21 अगस्त, 1871, 21 सितंबर, 1871, डी० नीरोजी, पूर्वोद्धृत, पृ० 294, 295, 201।
167. राबर्ट नाइट एक अर्धशास्त्री और 'एफ० एस० एस०' था।
168. नाइट केवल 'राजनीतिक क्रान्तियों' की बात कर रहा था।
169. 'इंडियन इकानामिस्ट', 21 अगस्त, 1871; 21 सितंबर, 1871।
170. डी० नीरोजी, पूर्वोद्धृत, पृ० 295।
171. वही, पृ० 201, 294।
172. 'इंडियन इकानामिस्ट', 30 अगस्त, 1873।
173. जे० स्ट्रुची से मेयो को, 18 अक्तूबर, 1869 को, मेयो कागजात, 60।
174. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 1865, पृथक राजस्व सख्या 302, सचिव, भारत सरकार से सचिव, बंबई सरकार को, 19 अप्रैल, 1865।
175. विधान परिषद कार्यविवरण, 1860, जिल्द VI (पुरानी सिलेज), पृ० 122।
176. गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व सख्या 7-8।
177. 'हिंदू पेडिगट', 4 जुलाई, 1870।
178. गृह (लोक शाखा) परामर्श, 15 अप्रैल, 1859, सख्या 20, 5 अप्रैल, 1859, को एक सार्वजनिक सभा में कलकत्ता के व्यापारियों के द्वारा याचिका (अर्जी)। भारत मंत्री का प्रेषण पृथक राजस्व सख्या 4, 7 अप्रैल, 1859। गृह, पृथक राजस्व सख्या 3, 1 अक्तूबर, 1860।

179. वित्त कार्यनिवहरण, अप्रैल, 1865, पृथक राजस्व संध्या 35 ।
180. वही, जून, 1865, पृथक राजस्व संध्या 244-45 ।
181. 'हिंदू पेट्रिअट', 21 मार्च, 1860 ।
182. वही, 29 मई, 1866 ।
183. वही, 21 अप्रैल, 1860 ।
184. वही, 11 जुलाई, 1870 ।
185. वही, 9 जनवरी, 1871 ।
186. वित्त कार्यनिवहरण, मार्च, 1871, लेखा शाखा संध्या 90, सचिव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से वित्त सचिव, भारत सरकार को, 11 मार्च 1871 ।
187. 'हिंदू पेट्रिअट', 9 जनवरी, 1871 ।
188. वही 6 मार्च, 1871 ।
189. बंबई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा याचिका, 'जनरल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', जिल्द V, खंड II, 1871, पृ० 130-32 ।
190. 'फ्रीड आफ इंडिया', 24 दिसंबर, 1863 ।
191. एम० भट्टाचार्य, 'लेसे केअर इन इंडिया', 'इंडियन इकानामिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू', जनवरी, 1965, जिल्द II, पृ० 1-22 ।
192. सांख्यिकीय परिशिष्ट में माधारण शौक निर्माण व्यय से संबद्ध सारणी तथा पृ० 116-120 पर आधारित ।
193. प्रत्येक प्रांत अथवा प्रेसीडेंसी का क्षेत्र, एम० एम० पी० आर०, 1871-72 तथा पी० पी० एच० सी०, 1873, जिल्द 50, पृ० 147 में दिए गए स्थूल प्राक्कलनों के आधार पर निकाला गया ।
194. 'गजट आफ इंडिया', 31 मार्च, 1888 (पूरक) ।
195. सर लुई सैलट्स द्वारा 1875 में किए गए प्राक्कलन 1871 के आकड़ों पर आधारित थे । 'रिपोर्ट आफ दि पैमोन कमिशन' (1880) परिशिष्ट एल, पृ० 143 ।
196. जान स्ट्रैची का ज्ञापन, 1874, पी० पी० एच० सी०, 1874, पृथक 326, पृ० 16-17 ।
197. वही, पृ० 18 ।
198. देखें, अध्याय IV, पृ० 157 और आगे ।
199. बंबई के 3646 हिंदुस्तानी व्यापारियों द्वारा याचिका (अर्जी); 12 अक्तूबर, 1859, 'कारेस्पॉडेंस आन टायरेक्ट टैक्मज' (कलकत्ता, 1882), जिल्द I पृ० 30 ।
200. बी० बी० मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ० 320, 339, 344-45 ।
201. बी० एन० शागुली, 'दादाभाई नौरोजी एंड दि ड्रेन विथरी', (बंबई, 1965), पृ० 80, 93-93 ।
202. देखें, ऊपर 155-57 ।

## सांख्यिकीय परिशिष्ट

यह सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के सामने प्रधान समस्या परिमाणात्मक सामग्री का अभाव है। जब मैंने यह अध्ययन प्रारंभ किया था तो मैं प्रकाशित सामग्री में और विशेष रूप से 'स्टैटिकल ऐब्स्ट्रैक्ट रिलेटिंग टु ब्रिटिश इंडिया' में भारतीय वित्त के बारे में बहुत अधिक 'प्रभावोत्पादक आंकड़े पाकर बहुत आश्चर्य हुआ था। जैसे-जैसे यह कार्य आगे बढ़ा मुझे प्रकाशित आंकड़ों की सीमाएं स्पष्ट होने लगी। जैसा कि मिचेल तथा डीन ने 'ऐब्स्ट्रैक्ट आफ ब्रिटिश हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स' की अपनी भूमिका में लिखा है, 'सांख्यिकीय श्रेणी की सीमाएं उसी समय प्रकट होती हैं जब विश्लेषण के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि मेरा प्रयास विस्तार की दृष्टि से प्रारंभिक एवं सीमित था, तथापि जो दोष मेरे सामने आए उनकी ओर मैं पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जहां तक दीर्घकालिक समयानुक्रम का प्रश्न है उनसे संबद्ध समस्याएं निम्नलिखित हैं: संसदीय कागजात में उपलब्ध अनेक सांख्यिकीय श्रेणियां और विशेष रूप से प्रवर समितियों के सामने प्रस्तुत साक्ष्यों और इन प्रवर समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में मिलने वाली सांख्यिकीय श्रेणियां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तैयार की गई थीं। बुनियादी आंकड़ों के स्थान पर संक्षिप्त लेख प्रकाशित किए गए थे। समय-समय पर परिभाषात्मक और भाषात्मक परिवर्तनों, राजस्व (व्यय) की एक मद से दूसरी मद में घटकों के अंतरण, भूतलक्षी प्रभाव से अनेक मदों के चालू आय खाते से पूंजी खाते में अंतरण, परिवर्ती सिद्धांतों के अनुसार एक ही राजस्व (व्यय) शीर्षक के अंतर्गत अनेक मदों का समुच्चय इत्यादि के कारण ये तुलनीय नहीं हैं। यह 'स्टैटिस्टिकल ऐब्स्ट्रैक्ट' के विषय में भी सत्य है जिसके स्वरूप और आकार में बिना किसी स्पष्टीकरण के परिवर्तन कर दिए जाते थे और पुराने 'ऐब्स्ट्रैक्ट्स' में प्रकाशित आंकड़ों को कोई भी स्पष्टीकरण दिए बिना ही संशोधित कर पुनः प्रकाशित किया जाता था। इन सब कारणों से दीर्घकालीन तुल्य कालानुक्रम का निर्माण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। आगे दो गई सारणियों में नवीनतम संशोधनों को लिया गया है जब तक कि परिभाषात्मक परिवर्तनों अथवा घटकों के एक मद से दूसरी मद में अंतरणों से कालानुक्रम की तुल्यता में व्यवधान न पड़ता हो, और प्रकाशित तथ्यों की वार्षिक वित्त विवरणों तथा अप्रकाशित अभिलेखों के साथ तुलना करके जांच की गई है। जहां कोई भी तथ्य बीच में टूटा हुआ है वहां संशोधित सारणी के नीचे टिप्पणी में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। किसी खास राजस्व अथवा

व्यय शीर्षक के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त घटकों को सामान्यतः संपूर्ण अवधि में उसी शीर्षक में रखा गया है। जहाँ उपलब्ध लेखों में किसी घटक का एक मद से दूसरे में अंतरण हुआ है और राशियों को अलग-अलग कर पाना संभव नहीं है, वहाँ इसे पाद टिप्पणी (फुटनोट) में स्पष्ट कर दिया गया है।

वित्त विभाग के अभिलेख बहुत विस्तृत एवं अधिक हैं (देखिए ग्रंथ सूची से संबद्ध टिप्पणी)। व्यय लेखा कार्यालय (1843) से वित्तीय नियंत्रण के माध्यम के रूप में, जिसका प्रधान सदस्य (1859) होता था, इस विभाग का क्रमिक विकास, वित्तीय सेवा के प्रारंभ 1857 तथा वित्त विभाग के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में ट्रैवीलियन के प्रयत्नों का हम पीछे वर्णन कर चुके हैं। जब वित्त विभाग का पुनर्निर्माण हो रहा था, उसी समय लेखा प्रणाली का भी, ईस्ट इंडिया कंपनी की 'वाणिज्यिक लेखा प्रणाली' से सरकारी वित्त के लिए उपयुक्त प्रणाली के रूप में तेजी के साथ विकास हो रहा था। 1860 में बजट प्रणाली प्रारंभ की गई और लेखा तथा लेखा परीक्षण पद्धतियों में लगातार अनेक सुधारों के चरम परिणाम के रूप में, फास्टर तथा ब्रिफिन के सुझावों के अनुरूप इनका पुनर्गठन किया गया। फास्टर तथा ब्रिफिन इंग्लैंड में ट्रैवीलियन तथा ग्लैडस्टन द्वारा चुने गए परामर्शदाता थे। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से वित्त संबंधी आंकड़ों के संग्रह में काफी सुधार हुआ। परंतु लेखा पद्धति के सिद्धांतों, उनके स्वरूप, मदों के वर्गीकरण इत्यादि में परिवर्तनों के कारण उत्तर पुनर्गठन काल के आंकड़ों की तुलना इससे पहले की अवधि के आंकड़ों के साथ करना कठिन हो गया। यही कारण है कि सांख्यिकीय श्रेणियाँ कहीं-कहीं टूटी हुई हैं। पूर्वानुमान रूपरेखा तथा नियमित प्रावकलन से संबंधित सपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा भारत मंत्री वित्त प्रेषण, 1860 के बाद वित्त सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष बनाए जाने वाले वित्त विवरण (विधान परिपद की कार्यवाही संबंधी विवरण, पुरानी श्रेणी जिल्दे VI VII, तथा नई श्रेणी जिल्दे I-XI), तथा भारत के गजट में वित्त संबंधी सारांश संक्षेप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा प्रस्तुत करते हैं।

कहीं-कहीं एक मद के अंतर्गत कुल सकल राजस्व तथा व्यय के आंकड़े तो उपलब्ध हैं परंतु पूरी अवधि के लिए मद विशेष में आने वाले विभिन्न मदों की राशियाँ अलग-अलग प्राप्त नहीं हैं। उदाहरणार्थ, सेना तथा लोकनिर्माण के अंतर्गत व्यय की विभिन्न मदों की राशियाँ केवल सातवें दशक के मध्य से ही उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में नीचे दी गई सारणियों में श्रेणी उसी बिंदु से प्रारंभ होती है, जहाँ से प्रकाशित श्रेणी और वार्षिक लेखों के आधार पर अविच्छिन्न श्रेणी का निर्माण किया जा सकता है। जहाँ पर आंकड़े विच्छिन्न हैं और उपलब्ध मुख्य श्रेणी के साथ तुलनीय नहीं हैं, वहाँ उन्हें नीचे दी गई सारणियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं तो इन्हें संबंधित सारणी के अंत में पाद टिप्पणी (फुटनोट) में दिया गया है।

आंकड़ों की अपर्याप्तता उस समय बहुत अधिक खलती है जबकि राष्ट्रीय आय अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित बढ़ते हुए साहित्य से वह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि राष्ट्रीय आय

के बारे में अटकलपन्चू प्राक्कलनों से सर्ववृद्ध अनिश्चितता और संभावित द्रुति का अंश बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भी कम नहीं है और जितना हम पीछे जाते हैं, इसमें वृद्धि होती जाती है। इसके अन्वावा, उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश भाग के लिए जो आंकड़े हमारे पास हैं वे आयात और निर्यात के केवल सरकारी मूल्य को प्रदर्शित करते हैं जिनसे व्यापार की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बहुत अपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। भारत की राष्ट्रीय आय के दादाभाई नौरोजी द्वारा प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा उन्नीसवीं शताब्दी में विदेशी व्यापार की मात्रा की अनुक्रमणी का निर्माण किसी अन्य शोध कार्य के अंतर्गत गौण प्रयास के रूप से हलके फुल्के ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। इन महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले शोध कार्यों (उदाहरणार्थ, भारत के विदेशी व्यापार पर डा० के० एन० चौधरी का कार्य) की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश भारत के वित्त विषयक आंकड़ों से संबंधित एक समस्या यह है कि राज्य क्षेत्र के द्रुत विस्तार के कारण विभिन्न अवधियों की कुल राशियों और प्रशासनिक प्रभागों के, जिनके आकार में निरंतर परिवर्तन हो रहे थे, आंकड़ों की तुलना श्रमसाध्य है। 1858-72 की अवधि में बहुत मामूली क्षेत्रीय परिवर्तन हुए थे। 1866-67 तक खाड़ी उपनिवेशों (जो 1941 तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहे) के लेखे भारत सरकार के लेखे से पृथक नहीं किए गए थे। यही हैदराबाद के अभ्यर्पित जिलों की स्थिति थी। इन अपवादों के अलावा किसी अन्य परिवर्तन ने प्रशासनिक प्रभागों के लेखे को, जो नीचे सारणी के रूप में दिए गए हैं, प्रभावित नहीं किया। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस काल के भारत सरकार के लेखे में भारत में दक्षिणी बर्मा सम्मिलित था। बंबई में सिंध, बगाल और (सारणी 4 को छोड़कर जो 1888 में तैयार किए गए विवरण पर आधारित है) असम सम्मिलित थे।<sup>1</sup> इस काल के आंकड़े अपने प्रकाशित रूप में (जैसे, भारत मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले विवरण, सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा भारत मंत्री को प्रेषित विवरण, और वित्त सदस्य द्वारा विधान परिषद में रखे जाने वाले विवरण) सर्वैव पीड स्टलिंग में ही होते थे। तथापि भारत में रखे जाने वाले लेखे रुपये में होते थे। सार्वजनिक विवरणों के लिए रुपये को 'स्टलिंग' (10 रुपये = 1 पौंड) में बदल लिया जाता था, और सरकारी कार्यों के लिए संकेत रूप में R + प्रयोग किया जाता था (R + का अर्थ रुपीज टैन दस रुपये होता था)। समानता की दृष्टि से नीचे सारणियों में दिए गए आंकड़े रुपये में हैं (केवल इंग्लैंड में व्यय, ब्रिटिश प्रत्याभूत कंपनियों को दिए जाने वाले ध्याज प्रभार तथा लोक ऋण से संबंधित सारणियाँ अपवादस्वरूप हैं)। यद्यपि संपूर्ण अवधि में सरकारी दर स्थिर (10 रुपये = 1 पौंड) थी, तथापि बाजार में प्रचलित दर में उतार चढ़ाव होते रहे और इसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड को भेजी जाने वाली राशियों पर 'विनिमय द्वारा हानि' हुई।

अंत में, वित्तीय वर्ष के विषय में यह लिखना आवश्यक है वह निस्संदेह पंचांग वर्ष के अनुरूप नहीं था। 1858-66 की अवधि में वित्तीय वर्ष 1 मई से और 1867 से 1 अप्रैल से प्रारंभ होता था (इसका आनुमणिक परिणाम यह हुआ कि 1866-67 के

वित्तीय वर्ष के आंकड़े केवल 11 महीने की अवधि के हैं)। वित्तीय वर्ष और भी पहले प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रस्ताव रखे गए थे ताकि संसद को भारतीय लेखे कुछ पहले मिल सकें और यदि संभव हो तो यह 1 जनवरी से प्रारंभ किया जाए परंतु भारत में फसलों की कटाई के मौसम, राजस्व संग्रह का कार्य, तथा भुद्रा बाजार की स्थिति में अनिष्ट संबंधों के कारण यह प्रस्ताव अव्यावहारिक पाया गया। भारतीय वित्तीय लेखे की भांति ही, नीचे की सारणियों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का समाप्तिकाल दिया गया है। अतः 1860 का अर्थ है '1860 में समाप्त होने वाला वर्ष' अर्थात् 1859-60 का वित्तीय वर्ष।

प्रकाशित स्रोत और प्रमुख अप्रकाशित स्रोत नीचे टिप्पणियों में बतलाए गए हैं।

मैं श्री एच० सान्याल का आभारी हूँ जिन्होंने संपूर्ण सांख्यिकीय परिशिष्ट के मुद्रण ग्रंथों को देखने और सारणियों की जांच करने की कृपा की है।

## संदर्भ

- 1-1.3 पी० पी० एच० सी० 1868-69, जिल्द 7०, पृ० 8, सारणी 7, पी० पी० एच० सी० 1870, जिल्द 68, पृ० 255, सारणी 9, पी० पी० एच० सी० 1877, जिल्द 85, पृ० 247, विधान परिषद कार्यविवरण VI-VII (पुरानी सीरीज), I-XI (नई सीरीज) के साथ सलग्न वित्तीय सारांश।
2. पी० पी० एच० सी० 1876, जिल्द पृ० 264, सारणी 21, पी० पी० एच० सी० 1874, जिल्द 70, पृ० 4, सारणी 5, पी० पी० एच० सी० 1870, जिल्द 68, पृ० 225, सारणी 9, 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स' (कलकत्ता) 1860-61। 1871-72, विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) VII, पृ० 561 और परिशिष्ट।
3. पी० पी० एच० सी० 1875, पत्रक 406, एम० एम० पी० आर० 1873-74, पृ० 65, सारणी 36, विधान परिषद कार्य विवरण (पुरानी सीरीज), जिल्द VII, पृ० 209, 354; विधान परिषद कार्यविवरण (नई सीरीज) जिल्द II, पृ० 76, III, पृ० 129, IV, पृ० 150-151, VI, पृ० 171, VII, पृ० 145।
4. 'गजट आफ इंडिया' 31 मार्च, 1888 (पूरक), पी० पी० I, पृ० 378।
5. पी० पी० एच० सी० 1875, पत्रक 406, पृ० 64, सारणी 35; वित्त कार्यविवरण जून, 1871, पृथक राजस्व 80, पी० पी० एच० सी० 1871, जिल्द, पत्रक 263।
6. पी० पी० एच० सी० 1875, पत्रक 406, पृ० 49, सारणी 4; वार्षिक वित्तीय सारांश, विधान परिषद कार्यविवरण (नई सीरीज) I-XI।
- 7-8. विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) VI-VII और विधान परिषद कार्यविवरण (नई सीरीज) I-XI, वित्तीय सारांश; वित्त कार्य विवरण अगस्त, 1875, सख्या 19-27, पी० पी० एच० सी० 1875, पत्रक 406; एम० एम० पी० आर० 1873-74, पृ० 49-50, 'पेटेंटस्टोकर एंड एक्स्ट्रेक्ट आफ ब्रिटिश इंडिया' (सदन, 1873)।



- 9-11. पी० पी० एच० सी० 1876, जिल्द 77, पृ० 265, सारणी 22; पी० पी० एच० सी० 1874, जिल्द 70, पृ० 11, सारणी 6; पी० पी० एच० सी० 1870, जिल्द 68, पृ० 225 ।
- 12-14. पी० पी० एच० सी० 1868-69, जिल्द 63, पृ० 38, सारणी 41; वही 1870, जिल्द 68, पृ० 44, सारणी 49; वही 1873, जिल्द 69, पृ० 290, सारणी 55; क्षेत्र व जनसंख्या के संबंध में आकड़े पी० पी० एच० सी० 1873 जिल्द 50, पृष्ठक 172, पृ० 147 पर आधारित । एम० एम० पी० आर० 1871-72 ।
15. पी० पी० एच० सी० 1876, जिल्द 77, पृ० 342-43, सारणी 82 ।
- 16-17. पी० पी० एच० सी० 1868-69, जिल्द 63, पृ० 34, सारणी 32-33; वही 1870, जिल्द 68, पृ० 256, सारणी 40-41, वही 1871, जिल्द 69, पृ० 158, सारणी 28; वही 1873, जिल्द 69, पृ० 55-56, सारणी 45, पृ० 277-78; वही 1874, जिल्द 70, पृ० 70, सारणी 57; वही 1876, जिल्द 77, पृ० 340, सारणी 81; पूर्वोक्त स्पष्ट, पृ० 342-43, सारणी 82 ।
- 18-20. पी० पी० एच० सी० 1860, जिल्द 49, पृष्ठक 339, पृ० 99; वही 1885, पृष्ठक 352, पृ० 212-16 और आगे, वित्तीय सारांश (वार्षिक), विधान परिषद कार्यविवरण (नई सीरीज), I-XI; 'स्टैटिस्टिकल एम्ब्रैक्चर्स' ।
21. पी० पी० एच० सी० 1873, जिल्द 69, पृ० 283, सारणी 56; वही 1871, जिल्द 69, पृ० 163, सारणी 32, वही 1870, जिल्द 68, पृ० 261, सारणी 45, वही 1868-69, जिल्द 63, पृ० 39, सारणी 37 ।

सारणी 1:1

सोव राजस्व : भारत सरकार के समग्र राज्य राजस्व के प्रतिगत रूप में  
प्रमुख घरे : बाल 1855-59 से 1871-72

	1855-59	1860-61	1865-66	1869-70	1870-71
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
मालमुजारी	50.3	43.1	41.8	41.4	40.1
अरीय	17.0	16.6	17.4	15.6	15.7
ममर	7.2	8.9	10.9	11.6	11.9
मीमा दुम्ह	8.0	9.7	4.7	4.8	5.1
उत्पादन दुम्ह	4.1	4.1	5.3	5.4	5.5
आय/नारंगीय वर	0.3	2.6	1.4	2.2	4.0
स्टाम्प दुम्ह	1.6	2.8	4.1	4.7	4.9
राकषर	1.6	1.4	0.8	1.4	1.6
सोव निर्माण प्राणियां	1.8	2.0	1.9	1.9	1.8
विशय	1.6	1.8	1.5	1.5	1.4
अन्य घरे	6.5	8.0	10.2	9.5	8.0

टिप्पणी : आधे से कई मापनी 2 वर आयातित ; राज्य की घरे का एक से दूसरी में अंतर  
नहीं है ।

## सारणी 1.2

लोक व्यय : भारत सरकार के समग्र सकल व्यय के प्रतिशत रूप में  
प्रमुख मदें

	काल			
	1863-64	1865-66	1869-70	1871-72
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
सेना	32.6	36.3	30.6	32.3
राजस्व संग्रह प्रभार	21.1	18.5	17.3	17.5
विधि एवं न्याय	4.8	5.3	5.4	4.7
सामान्य प्रशासन	2.2	2.7	2.7	3.7
अधिवार्षिकी (सुपरएनुएशन)				
भत्ता	2.1	2.0	2.5	2.9
अवकाश भत्ता	0.2	0.2	0.3	0.4
लोक निर्माण (सामान्य)	12.0	10.9	10.0	5.3
राजनीतिक एजेंसिया	0.5	0.5	0.8	0.7
श्रद्धा प्रभार	11.2	11.1	11.5	12.2
अन्य मदें	13.3	12.5	18.9	20.2

टिप्पणी आगे दी गई सारणी 11 पर आधारित। 1869-70 से लोक निर्माण 'सामान्य' से लोक निर्माण 'अमाधारण' के पुनर्गठन (सारणी 11 का कालम 12-14 द्रष्टव्य) के अतिरिक्त व्यय की मदों में एक से दूसरी में अंतरण नहीं है।

### सारणी 1.3

भारत सरकार का भारत और इंग्लैंड में सकल राजस्व और व्यय  
1858-59 से 1871-72 तक

	सकल राजस्व	सकल व्यय	वित्त सदस्य	वजट विवरण पेश करने की तारीख
1859	36.06	51.06	—	—
1860	39.71	51.86	—	—
1861	42.09	48.15	जेम्स विल्सन	18 फरवरी, 1860
1862	43.83	44.87	सेमुअल लैंग	27 अप्रैल, 1861
1863	45.14	44.05	सेमुअल लैंग	16 अप्रैल, 1862
1864	44.61	44.53	सी० ई० ट्रैवीलियन	30 अप्रैल, 1863
1865	45.65	45.85	सी० ई० ट्रैवीलियन	7 अप्रैल, 1864
1866	48.94	46.17	सी० ई० ट्रैवीलियन	1 अप्रैल, 1865
1867	42.12	44.64	डब्ल्यू० एन० मैसी	24 मार्च, 1866
1868	48.53	50.14	डब्ल्यू० एन० मैसी	5 मार्च, 1867
1869	49.26	53.41	डब्ल्यू० एन० मैसी	14 मार्च, 1868
1870	50.09	53.38	रिचर्ड टैपिल	6 मार्च, 1869
1871	51.41	51.01	रिचर्ड टैपिल	2 अप्रैल, 1870
1872	50.11	48.61	रिचर्ड टैपिल	9 मार्च, 1871

टिप्पणी भारत सरकार के व्यय संबंधी प्रकाशित विवरणों में त्रुटियाँ हैं। इन त्रुटियों के कारण हैं (क) 'पेट्रिस्टिकल ऐम्ब्रूवट' के विभिन्न संस्करणों के आकार में अंतर, (ख) ससद में आकड़े पेश करने के लिए इंडिया ऑफिस के सक्लनकर्ताओं द्वारा विभिन्न अर्थों में सांख्यिकी के अलग-अलग सिद्धांतों को अपनाना तथा (ग) आधिक्य न होने पर भी उसे दिखाने के लिए वित्त सदस्यों द्वारा की जाने वाली अद्भुत वाजीबरी। विल्सन तथा लैंग द्वारा प्रकाशित नियमित एवं वास्तविक प्राक्कथनों में बाद में पुनरीक्षण किए गए थे। इस प्रकार का पुनरीक्षण क्षेत्रीय परिवर्तनों (उदाहरणार्थ, 1866-67 के बाद खाड़ी उपनिवेशों और हैदराबाद को मिलने वाले जिलों के लेखों का पृथक्करण), व्यय के एक शीर्षक से दूसरे में मदों का अंतरण अथवा असाधारण लोक निर्माण पर व्यय के राजस्व लेखों से पूँजी लेखों में अंतरण (1868 से) के मामलों में समान रूप से नहीं किया गया। एकतपता की दृष्टि में मशोधन विशेष रूप से 1866-67 से पहले किए गए। यह वह काल था जब लेखा सिद्धांतों में तेजी के माप परिवर्तन हो रहे थे।

## सारणी 2

भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड में सकल राजस्व और प्राप्तियां  
(1857-58 से 1872-73 तक) : प्रमुख मदें

	(करोड़ रुपयों में)					
	2	3	4	5	6	7
	मालगुजारी	खिराज	उत्पाद-शुल्क एवं वन	आय एवं अनु- भत्ति कर (लाइ- सेंस टैक्स)	सीमा-शुल्क	नमक
1858	15.32	0.58	1.22	0.11	2.15	2.13
1859	18.12	0.56	1.47	0.11	2.87	2.60
1860	18.76	0.79	1.07	0.22	3.87	2.93
1861	18.51	0.78	1.78	1.01	4.16	3.81
1862	19.68	0.78	2.25	2.05	2.88	4.56
1863	19.57	0.73	2.47	1.88	2.46	5.24
1864	20.30	0.72	2.36	1.48	2.38	5.03
1865	20.09	0.68	2.58	1.28	2.29	5.52
1866	20.47	0.71	2.61	0.69	2.28	5.34
1867	19.14	0.63	2.43	0.02	2.03	5.35
1868	19.99	0.69	2.57	0.65	2.58	5.73
1869	19.93	0.69	2.69	0.51	2.69	5.59
1870	21.09	0.76	2.72	1.11	2.43	5.89
1871	20.62	0.72	2.83	2.07	2.61	6.11
1872	20.52	0.74	2.87	0.82	2.58	5.97
1873	21.35	0.74	2.89	0.58	2.65	6.17

## सारणी 2

(गत पृष्ठ से आगे)

	8 अफीम	9 स्टाम्प शुल्क	10 टकसाल	11 डाक	12 तार	13 विधि (अदालत शुल्क, जुमाना इत्यादि)
1858	6.86	0.45	0.36	0.39	—	0.03
1859	6.15	0.59	0.25	0.59	—	0.04
1860	5.59	0.74	0.39	0.66	—	0.44
1861	6.68	1.18	0.29	0.61	0.05	0.42
1862	6.36	1.17	0.38	0.04	0.07	0.51
1863	8.06	1.49	0.37	0.43	0.08	0.49
1864	6.83	1.74	0.37	0.46	0.09	0.63
1865	7.36	1.97	0.38	0.36	0.01	0.68
1866	8.52	1.99	0.49	0.41	0.19	0.79
1867	6.08	1.08	0.24	0.05	0.22	0.82
1868	8.92	2.19	0.12	0.66	0.24	0.95
1669	8.45	2.31	0.19	0.71	0.27	1.17
1870	7.95	2.38	0.16	0.71	2.25	1.09
1871	8.04	2.51	0.03	0.81	0.24	1.02
1872	9.25	2.48	0.09	0.82	0.23	0.04
1873	8.68	2.61	0.05	0.58	0.25	0.04



## सारणी 3

## अफीम राजस्व

औसत कीमत, शुल्क दर तथा व्यापार की मात्रा 1857-72

	2	3	4	5	6
	बंगाल अफीम की औसत कीमत (रुपये)	बंगाल अफीम की पेटियां हजारों में	मालवा अफीम पर शुल्क की दर (रुपये)	मालवा अफीम की पेटियां हजारों में	सकल अफीम राजस्व (करोड़ रुपयों में)
1857	890	42.3	400	29.2	5.00
1858	1,290	40.1	400	39.7	6.86
1859	1,490	30.9	400	36.4	6.15
1860	1,670	25.3	500	32.9	5.89
1861	1,920	21.4	600	46.1	6.68
1862	1,610	24.1	700	37.0	6.36
1863	1,430	32.8	600	51.2	8.06
1864	1,220	42.6	600	25.7	6.83
1865	1,940	54.5	600	32.6	7.36
1866	1,120	56.0	600	36.1	8.52
1867	1,250	38.7	600	30.6	6.08
1868	1,330	48.0	600	39.1	8.92
1869	1,380	47.2	600	31.0	8.45
1870	1,200	45.7	600	39.4	7.95
1871	1,120	49.0	600	39.5	8.04
1872	1,390	49.7	600	38.8	9.25
1873	1,390	42.7	600	44.0	8.68

टिप्पणी : बालम 2 में बंगाल अफीम की कलकत्ता में प्रति पेटो वाणिज्य कीमत और बालम 4 में मालवा अफीम पर इंदौर में प्रति पेटो शुल्क (बर्दा जाने वाली अफीम पर शुल्क) दिखाया गया है। शुल्क की नई दरें 1859-60 में 1 जुलाई, 1859, 1860-61 में 1 गिनवर, 1860, 1861-62 में 1 अक्टूबर तथा 1862-63 में 1 अक्टूबर, 1862 से लागू हुईं।



## सारणी 4

प्रमुख प्रांतों/प्रेसीडेंसियों में सकल मालगुजारी  
1856-57 से 1870-71 तक

	1856-57	1870-71	(करोट रुपयों में) प्रतिशत वृद्धि
बंगाल	3.54	3.76	6
बम्बई	2.15	2.95	37
मद्रास	3.8	4.4	16
पंजाब	1.84	1.97	7
पश्चिमोत्तर प्रांत	3.92	4.13	5
अय्यर	0.97	1.32	36
मध्यप्रांत	0.57	0.6	5

टिप्पणी इस सारणी में आगाम, दक्षिण बर्मा तथा छोटे प्रांतों के आबरे सम्मिलित नहीं किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 1888 में प्रकाशित यह प्राचक्रनन अगिष्टृत था, परंतु इसके भी अने उपयोग थे। समस्त लोकनिर्माण में पूजीनिवेश के आबटन के मामले में सरकारी नीति कुछ क्षेत्रों से अधिक आय प्राप्त होने के अनुभव तथा प्रत्याशा द्वारा प्रभावित थी।

## सारणी 5

नमक से प्राप्त-सकल राजस्व : आयात शुल्क, अंतर्देशीय सीमा शुल्क तथा

विक्रय मूल्य 1856-57 से 1871-72 तक

1 रुपया=16 आने=2 शिलिंग

कालम 7 करोड़ रुपये में

	2	3	4	5	6	7
	बंगाल	मद्रास	बंबई	पंजाब की	अंतर्देशीय	भारत
	सीमा शुल्क	विक्रय मूल्य	शुल्क	खाने	सीमा शुल्क	का सकल
	प्रति मन	प्रति मन	प्रति मन	प्रति मन	प्रति मन	राजस्व
	र० आने	र० आने	र० आने	र० आने	र० आने	करोड़
						रुपये
1858	2-8	1-0	0-12	2-0	2-0	2.13
1859	"	"	"	"	"	2.60
1960	3-0	1-2	1-0	2-2	2-8	2.93
1861	3-4	1-6	1-4	"	3-0	3.81
1862	"	1-8	"	3-0	"	4.56
1863	"	"	"	"	"	5.24
1864	"	"	"	"	"	5.03
1865	"	1-11	1-8	"	"	5.52
1866	"	"	"	"	"	5.34
1867	"	"	"	"	"	5.35
1868	"	"	"	"	"	5.73
1869	"	"	"	"	"	5.59
1870	"	2-0	1-13	"	"	5.89
1871	"	"	"	3-1	"	6-11
1872	"	"	"	"	"	5.97

टिप्पणी (क) : कालम 2 : शुल्क की गई दर दिगंबर, 1859 और मार्च, 1861 में लागू हुई।

(ख) कालम 3 में अंकित गए विषय मुख्य अग्रस्त, 1859; अर्द्ध, 1861, जून, 1861, जनवरी, 1865 तथा अक्टूबर, 1869 में लागू हुए। (ग) कालम 4 : शुल्क की पुनरीक्षण दरें अग्रस्त, 1859, अर्द्ध, 1861, जनवरी, 1865 तथा अक्टूबर, 1869 में लागू हुईं (घ) कालम 5 :

पंजाब नमक के विषय मूल्यों में उपर्युक्त वित्तीय वर्षों में अर्द्ध, 1860, दिगंबर, 1861, तथा जुलाई, 1870 में पुनरीक्षण किए गए। (ङ) कालम 6 : इस काल में नमक पर अंतर्देशीय सीमा शुल्क में दिगंबर, 1859 और मार्च, 1861 में समायोजन किए गए।

## सारणी 6

विदेशी व्यापार और सीमा शुल्क : 1857-58 से 1871-72 तक

(करोड़ रुपयों में)

	2	3	4	5
	आयातित वस्तुओं के शासकीय मूल्य	आयात शुल्क से सकल आय	निर्यातित वस्तुओं के शासकीय मूल्य	निर्यात शुल्क से सकल आय
1858	15.28	0.74	27.46	0.29
1859	21.73	1.21	29.86	0.03
1855-59	15.58	—	24.92	—
1860	24.26	2.28	27.96	0.36
1861	23.49	2.48	32.97	0.54
1862	22.32	1.93	36.32	0.56
1863	22.63	1.54	47.86	0.61
1864	27.15	1.47	65.63	0.06
1860-64	23.97	—	42.15	—
1865	28.15	1.41	68.03	0.59
1866	29.6	1.48	65.49	0.49
1867	29.04	1.51	41.86	0.34
1868	35.71	1.83	50.87	0.52
1869	35.99	1.9	53.06	0.06
1865-69	31.7	—	55.86	—
1870	32.93	1.75	52.47	0.48
1971	33.41	1.76	55.33	0.64
1872	31.08	1.65	63.19	0.69
1870-74	32.26	—	56.24	—

टिप्पणी : सामान्य प्रवृत्ति दिखाने के लिए ऊपर 1854-55, 1858-59, 1859-60, 1863-64, 1864-65, 1868-68 तथा 1869-70, 1873-74 पंचवार्षिक अवधियों के वार्षिक औसत दिए गए हैं। बाक्य 3 और 5 में अंतर्देशीय सीमा शुल्क से भारी लाभ को सम्मिलित नहीं किया गया है।

# सारणी 7.1

कुछ मुख्य निर्यातों के शासकीय मूल्य : 1860-61 तथा 1870-71

1860-61

1870-71

	मूल्य करोड़ रुपयों में	कुल निर्यात वस्तुओं के मूल्य के साथ अनुपात का प्रतिशत	मूल्य करोड़ रुपयों में	कुल निर्यात वस्तुओं के मूल्य के साथ अनुपात का प्रतिशत
कपास	7.34	22.3	19.46	36.2
कच्चा जूट	0.41	1.2	2.58	4.7
कच्चा रेशम	1.04	3.1	1.26	2.3
कच्चा ऊन	0.48	1.5	0.66	1.2
घावल	2.96	9.0	4.15	7.5
अन्य खाद्यान्न	0.36	1.2	0.32	0.6
बीज	1.79	5.4	3.52	6.4
खाल	0.66	2.0	2.02	3.7
तेल	0.25	0.8	0.18	0.3
नील	1.89	5.7	3.19	5.7
चीनी	0.99	3.0	0.24	0.4
कहुवा	0.34	1.0	0.8	1.4
चाय	0.15	0.5	1.12	2.0
शोरा	0.66	2.0	0.54	0.8
निर्मित जट	0.36	1.1	0.34	0.6

## सारणी 7.2

कुछ मुख्य आयातों का शासकीय मूल्य : 1860-61 तथा 1870-71

	1860-61		1870-71	
	मूल्य करोड़ रुपयों में	कुल आयात वस्तुओं के मूल्य के साथ अनुपात का प्रतिशत	मूल्य करोड़ रुपयों में	कुल आयात वस्तुओं से मूल्य के साथ अनुपात का प्रतिशत
सूती वस्त्र	9.31	39.6	15.64	46.8
सूती लच्छा घागा				
व सूत	1.75	7.4	3.4	10.2
रेशमी वस्त्र	0.46	1.1	0.43	1.3
ऊनी वस्तुएं	0.22	1.0	0.58	1.7
मशीनें	0.87	3.7	0.45	1.3
रेल उपकरण	1.09	8.1	1.47	4.4
वस्तुएं (निर्मित और कच्ची)	2.12	9.0	1.86	5.6
माल्ट लिक्वर	2.89	12.3	1.37	4.1
स्प्रिट	0.41	1.7	0.46	1.4
दराब	0.35	1.5	0.49	1.5
चीनी	0.22	1.0	3.36	1.7

### सारणी 8.1

सूती लच्छों, घागों और सूत का आयात 1857-58 से 1871-72 तक

	मात्रा (लाख पौंडो में)	शासकीय मूल्य (करोड़ रुपयों में)	शुल्क दर	राजस्व (लाख रुपयों में)
1858	17.7	0.94	अंग्रेजी माल 3½ प्रतिशत, विदेशी 7 प्रतिशत	3.7
1859	31.1	1.71	" " "	6.6
1860	31.5	2.05	" 5 प्रतिशत " "	11.8
1861	20.9	1.75	" 10 प्रतिशत " "	17.8
1862	23.9	1.47	" 5 प्रतिशत " "	7.5
1863	19.5	1.27	लच्छों पर 3½ प्रतिशत, घागों आदि पर 10 प्रतिशत	4.6
1864	19.6	1.53	" " "	4.5
1865	17.9	2.19	लच्छों पर 3½ प्रतिशत, घागों आदि पर 7½ प्रतिशत	7.2
1866	16.9	1.66	" " "	6.8
1867	30.9	2.57	" " "	9.1
1868	26.7	2.07	" " "	9.6
1869	29.0	2.78	" " "	10.0
1870	32.0	2.72	" " "	9.5
1871	40.4	3.04	" " "	10.2
1872	28.9	2.47	" " "	18.6

टिप्पणी : कालम 5 में 'अन्य प्रकार' के निर्मित सूती माल पर, जो सीमा शुल्क के लिए निर्धारित श्रेणियों जैसे, सूती वस्त्र, लच्छा, घागा, सूत इत्यादि में नहीं आता था, दिया जाने वाला शुल्क सम्मिलित है।

## सारणी 8.2

सूती वस्त्र के आयात : शासकीय मूल्य तथा सीमा शुल्क  
1857-58 से 1871-72 तक

शासकीय मूल्य (करोड़ रुपयों में)		सीमा शुल्क दर		राजस्व (लाख रुपयों में)
1858	4.78	अंग्रेजी माल 5 प्रतिशत, विदेशी 10 प्रतिशत		24.2
1859	8.09	"		46.7
1860	9.65	10 प्रतिशत		96.1
1861	9.31	"		92.8
1862	8.77	"		85.9
1863	8.36	5 प्रतिशत		42.7
1864	10.42	"		41.2
1865	11.04	"		50.4
1866	11.85	"		57.8
1867	12.52	"		63.6
1868	15.00	"		75.2
1869	16.07	"		80.1
1870	13.65	"		67.7
1871	15.64	"		79.6
1872	15.01	"		75.4

टिप्पणी - (क) कालम 4 1869-70 में सीमा शुल्क-राजस्व में आकस्मिक कमी का कारण यह था कि वस्तुओं का मूल्यांकन घटा कर किया गया था। (ख) कालम 2 : शासकीय मूल्य मात्रा का अपूर्ण सूचक है। चूंकि माल का आयात विविध नामों से किया गया था इसलिए सूती वस्त्रों की कुल आयातित मात्रा के संबंध में तथ्य उपलब्ध नहीं हैं।





## सारणी 10

भारत सरकार का प्रमुख प्रांतों : प्रेसीडेंसियों में सकल व्यय  
(1858-59 से 1871-72 तक)

	(करोड़ रुपये में)					
	2	3	4	5	6	7
	बंगाल	पश्चिमोत्तर प्रांत	पंजाब	मद्रास	बंबई	भारत में कुल सकल व्यय
1859	4.31	2.69	2.03	7.51	8.16	43.59
1860	4.3	3.16	2.12	8.05	9.51	44.62
1861	4.53	3.41	2.15	7.25	7.71	40.41
1862	4.84	2.47	1.68	7.06	6.31	37.25
1863	4.94	2.06	1.62	6.58	6.67	36.8
1864	5.87	2.09	1.55	6.28	7.26	38.09
1865	6.03	2.24	1.8	6.46	7.69	39.45
1866	5.32	2.13	1.65	6.71	7.92	41.12
1867	4.99	2.35	1.89	6.18	7.52	37.09
1868	6.21	2.57	2.11	6.73	8.52	41.65
1869	6.34	2.95	2.37	6.6	8.44	43.23
1870	6.89	2.95	2.22	6.6	8.29	42.79
1871	6.31	2.68	2.13	6.15	8.15	41.02
1872	5.66	2.45	2.06	5.83	7.23	38.76

टिप्पणी . कालम 7 में भारत में किया गया सकल व्यय दिखाया गया है और इसमें इंग्लैंड में हुआ व्यय सम्मिलित नहीं है। प्रकाशित लेखे कुछ विलक्षण थे क्योंकि उनमें 1865-66 तक केवल भारत के कुल व्यय की राशियाँ दिखाई गई थी जबकि इंग्लैंड में प्राप्तियाँ वहाँ के खर्चों से घटाकर दिखाई जाती थी। आगे सारणी में इंग्लैंड में किए गए भुगतानों को देखा। इस काल से अवध, ब्रिटिश बर्मा, मध्य प्रांत, स्ट्रेट्स सेटिलमेंट्स तथा सीधे भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों में व्यय को लेखे में अविच्छिन्न और तुलनीय ढंग से नहीं दिखाया गया है।

सारणी 11

भारत सरकार का भारत और इंग्लैंड में सकल व्यय : प्रमुख भवें  
(1863-64 से 1872-73 तक)

(करोड़ रुपये में)

	2	3	4	5	6	7
	सेना	राजस्व सग्रह आदि	सामान्य प्रशासन	विधि एवं न्याय	अधि-वार्षिकी भत्ते	सिविल अवकाश
1864	14.51	9.38	0.98	2.12	0.9	0.07
1865	15.77	9.05	0.97	2.26	1.27	0.07
1866	16.75	8.53	1.25	2.42	0.91	0.08
1867	15.83	7.64	1.27	2.39	0.77	0.08
1868	16.0	8.96	1.32	2.54	1.16	0.1
1869	16.27	9.25	1.04	2.85	1.75	0.12
1870	16.33	9.23	1.43	2.9	1.33	0.16
1871	16.07	9.27	1.57	2.99	1.45	0.18
1872	15.68	8.52	1.78	2.27	1.45	0.17
1873	15.05	8.89	1.89	2.22	1.58	0.16

टिप्पणी : (क) कालम 3 राजस्व सग्रह पर व्यय की राशि के साथ राजस्व की वापसी और देशी रियासतों के शासकों के साथ संधि के अंतर्गत मुकुंद की गई राशि जोड़ दी गई है। (ख) कालम 6 में अनुकंपा भत्ते सम्मिलित हैं।

## सारणी 11 (गत पृष्ठ से आगे)

	8 राजनीतिक एजेंसिया	9 प्रांतीय सेवाए	10 नौसेना	11 चिकित्सा	12 लोक निर्माण
1864	0.23	2.82	0.63	0.13	4.92
1865	0.29	2.97	0.64	0.13	4.61
1866	0.25	3.25	0.63	0.27	4.78
1867	0.27	3.24	0.77	0.26	6.03
1868	0.28	3.48	1.09	0.35	7.62
1869	0.35	3.71	1.14	0.38	6.27
1870	0.41	3.68	1.29	0.44	5.03
1871	0.35	3.5	0.76	0.52	3.95
1872	0.32	4.85	0.57	0.17	2.46
1873	0.39	5.22	0.55	0.18	2.53

(ग) कालम 9: मेयो की विकेंद्रीकरण योजना 1871-72 से लागू होने के बाद प्रांतीय सेवाओं, पुलिस, शिक्षा, लेखन सामग्री व छपाई, तथा सप्त चिकित्सा एवं लोक निर्माण प्रभार के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय माघनों का आबंटन किया गया था। पिछले वर्षों के लेखों में सन्दर्भित सन्तोषन किए गए। 'शिक्षा' पर व्यय के लिए आगे सारणी 20 देखिए। वित्तीय विकेंद्रीकरण से पहले काल में 'पुलिस' पर व्यय के अपरिष्कृत अनुमान संभव हैं।

( करोड़ रुपये में )

1864	2.5	1868	2.9
1865	2.6	1869	3.1
1866	2.8	1870	3.0
1867	2.8	1871	2.8

सारणी 11

(गत पृष्ठ से आगे)

	13	14	15	16	17	18
	सिंचाई	लोक निर्माण (असाधारण) राज्य रेलवे	निजी प्रत्याभूत (गारटी शुदा) रेलवे	ऋण प्रभार	विनिमय द्वारा हानि	कुल सकल व्यय
1864	—	—	2.12	4.97	0.01	44.53
1865	—	—	2.11	4.99	0.04	45.85
1866	—	—	0.34	5.13	0.08	46.17
1867	—	—	1.1	4.89	0.16	44.64
1868	0.22	—	1.8	5.73	0.12	50.14
1869	0.47	0.55	2.01	5.65	0.19	53.41
1870	2.01	0.19	1.86	5.61	0.2	53.38
1871	0.72	0.45	2.1	5.84	0.47	51.1
1872	0.98	0.64	1.85	5.97	0.4	48.61
1873	0.77	1.41	2.29	5.86	0.76	50.64

(घ) कालम 13 : 'असाधारण' शब्द अध्याय III में स्पष्ट किया गया है। (ङ) कालम 18 : कुल योग में अन्य अनेक मदें सम्मिलित हैं (जैसे, गिरजा संबंधी स्थापन, विभागीय लेखों में सम्मिलित न किए गए भंडार और 'प्रकीर्ण' जिसमें बहुधा विविध प्रकार के रिहाव छिपे हैं) इस सारणी के मुख्य प्रभार शीर्षक में मदवार उल्लेख है। (च) कालम 17 : विनिमय द्वारा हानि के बारे में शब्द जाल करर पृ० 301 पर स्पष्ट किया गया है। (छ) कालम 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वत्वाधिकारियों को दिया गया लाभांश सम्मिलित है।

## सारणी 11.1

लोक निर्माण विभाग में व्यय के कुछ प्रमुख शीर्षक : लोक निर्माण 'साधारण'  
1857-58 से 1871-72 तक

	कुल सकल व्यय	मैनिक इमारतें व सड़कें	अमैनिक इमारतें	(करोड़ रुपयों में) सड़कें, सिंचाई व सार्वजनिक सुधार	स्थापन औजार व संग्रह
1858	1.52	0.83	अनुपलब्ध	0.65	अनुपलब्ध
1859	0.41	0.33	अनुपलब्ध	0.08	अनुपलब्ध
1860	3.22	1.24	0.24	1.08	0.67
1861	3.37	0.9	0.39	1.42	0.66
1862	3.4	0.54	0.29	1.85	0.72
1863	3.93	0.61	0.42	1.62	0.74
1864	4.92	0.71	0.62	2.31	0.82
1865	4.61	0.86	0.72	2.13	प्राप्त नहीं
1866	4.78	1.08	0.74	1.86	0.99
1867	5.03	1.54	0.75	1.86	0.81
1868	5.62	1.74	0.85	1.76	1.07
1869	6.27	2.13	0.84	1.88	1.27
1870	5.03	1.45	0.68	1.55	1.12
1871	3.95	0.99	0.51	1.32	1.08
1872	2.46	0.98	0.21	0.61	0.61

टिप्पणी : इस विवरण में प्रस्ताभूत (गारंटीयुक्त) रेलों एवं राज्य रेलों और 'असाधारण लोक निर्माण', अर्थात् जिनका धन द्वारा वित्त प्रवर्धन हुआ था (देखिए सारणी 11 कालम 12-15) को सम्मिलित नहीं किया गया है। 1857-58 से 1861-62 तक के कालम 3 से 6 तक में दिए गए आंकड़े व्यय की स्वीकृत राशियों को सूचित करते हैं। ये वास्तविक व्यय की राशियों के लगभग होते हैं, परन्तु इन्हें समान नहीं माना जा सकता। 1872 के आंकड़ों में वित्तीय विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप 'प्रातीय सेवाओं' के लिए अनुदान (कालम 4 में 44 लाख रुपये, कालम 5 में 64.6 लाख रुपये तथा कालम 6 में 33 लाख रुपये) सम्मिलित नहीं हैं।

## सारणी 12.2

प्रमुख प्रांतों : प्रेसिडेंसियों में लोक निर्माण (साधारण) पर व्यय

भारत में कुल सरकारी व्यय प्रतिशत रूप में

	1864-66	1867-69	1870-72	1871-72
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	लोक निर्माण (साधारण) पर प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये में)
बंगाल	17	15.7	16.8	0 103
उत्तर-पश्चिमोत्तर प्रांत	12.9	13.3	13 5	0 19
पंजाब	11.9	14 2	13.3	0.34
मद्रास	11.9	13.8	12 2	0.106
बंबई	24	20 4	8.4	0.53

टिप्पणी - यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर सारणी में 'साधारण' लोक निर्माण के आंकड़े हैं और 'असाधारण निर्माण कार्यों' को सम्मिलित नहीं किया गया है। कालम 5 के बारे में इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह निश्चित है कि 'असाधारण' निर्माण कार्यों, प्रत्याभूत (गारंटीबुद्ध) रेलवे और राज्य रेलवे को 'साधारण' लोक निर्माण के साथ ही मिला कर देखा जाए तो अधिक अनुकूल स्थिति उभर कर आती है। परंतु स्थूल प्राक्कलनों से लगता है कि वितरण का स्वरूप (अर्थात् प्रत्येक प्रांत के व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात) लगभग वही रहेगा। इस प्रकार का प्राक्कलन स्थूल ही हो सकता है (इसलिए उसे सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है) क्योंकि बहुत सारे निर्माण कार्यों का वर्गीकरण साधारण से असाधारण में और असाधारण से साधारण में बदला गया कुछ निर्माण कार्यों पर शुद्ध व्यय के आंकड़े तो उपलब्ध हैं, परंतु सकल व्यय के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है, और 'साधारण' निर्माण कार्यों को छोड़कर हमारे किस्म के निर्माण कार्यों के बारे में प्रातवार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है कि 1871-72 के एम० एम० पी० आर० (पी० पी० एच० सी० 1873, खंडे 50, पत्रक 172, पृ० 147) में शक्ति और जनसंख्या के आंकड़े पूरी तरह सही नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लोक निर्माण में निवेश की दीर्घकालीन तुलना नहीं की गई है। (1898-1914 के काल का एम० के० थावराज ने अच्छा अध्ययन किया है, ग्रंथ सूची द्रष्टव्य)।

## सारणी 13

लोक निर्माण विभाग में व्यय के कुछ मुख्य शीर्षक : रेलवे तथा 'असाधारण' लोक निर्माण

(लाख रुपयों में)

	रेलवे (साधारण)			लोक निर्माण (असाधारण)				
	कुल योग	निरीक्षण तथा भूमि	प्रत्याभूत (गारंटी बुद्धा)	विनिमय द्वारा हानि	कुल योग	राज्य रेलवे	सिंचाई	बढ़ाई विशेष निधि
	रेलवे (साधारण)	तथा भूमि	व्याज (शुद्ध)		योग			
1866	34.3	22.5	6.7	5.1	—	—	—	—
1867	110.2	25.9	73.1	11.2	—	—	—	—
1868	179.9	15.6	154	10.2	60.2	0.01	21.9	38.3
1869	201.2	26.1	170	2.1	137.1	55.2	46.9	34.9
1870	185.7	9.1	154.7	20.5	259.9	19.1	200.7	40.1
1871	210.3	8.3	183.4	17.1	116.8	44.9	71.8	—
1872	185.1	6.6	172.3	5.3	162.8	64.4	98.3	—

टिप्पणी यह विवरण उस काल से प्रारम्भ होता है जब रेलवे और असाधारण लोक निर्माण के लेखे साधारण लोक निर्माण के लेखे से पृथक् कर फिर से दूसरे रूप में तैयार किए गए थे। कालम 3 में रेल पथों के लिए भूमि और निरीक्षण की लागत तथा कालम 4 में रेल यातायात से प्राप्तियों के ऊपर प्रत्याभूत व्याज की राशि अधिक दिखाई गई है। कालम 7 में उत्तरी बंगाल, नल्हाटी, पंजाब, उत्तरी सिंधु घाटी, राजपूताना, नोमब, होस्कर, चर्खा घाटी, हुबली तथा कोरबाड़ तथा कलकत्ता की राज्य रेलों और दक्षिण पूर्व रेलवे पर व्यय दिखाए गए हैं।

## सारणी 14

सोक निर्माण पर व्यय : क्षेत्रीय विवरण 1857-58, 1871-72 : प्रमुख प्रांतों/प्रेसीडेंसियों में 'साधारण' सोक निर्माण पर व्यय

(लागू राशियों में)

	2 कुल मूल्य रुपये	3 बंगाल	4 पश्चिमोत्तर प्रांत	5 पंजाब	6 मद्रास	7 बंबई
1858	151.9	23.5	99.4	4.1	1.5	12.3
1859	41.1	7.4	14.7	0.8	0.4	0.3
1860	322.2	39.2	62.4	39.9	65.4	47.6
1861	337.1	51.4	61	51	62	50.5
1862	339.7	51	63	54	66	52.5
1863	356.5	51.8	60.1	51	69.5	57.9
1864	492.1	96	65.8	52.5	66.2	121.9
1865	461.3	76.4	60.5	57.7	70.5	104.7
1866	478.4	72.2	59.2	57.3	63.6	118.2
1867	502.5	69.4	69	71.3	62.5	132.2
1868	562.2	86.3	62.7	78.9	82.2	105.2
1869	627.2	100.8	86	81.7	79.9	94.6
1870	503.4	86.6	65.9	60.9	65.8	84.6
1871	394.6	61.6	49.7	49.2	58.1	77.8
1872	245.9	39.7	35.4	34.4	24.3	46.4

टिप्पणी : अथवा, मध्य प्रांत, ब्रिटिश बर्मा, पूर्वी सेंट्रियल प्रोविन्स (1866-67 तक) और भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को मद्रास प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में व्यय को दूसरे काल में सम्मिलित किया गया है। 1871-72 के आंकड़ों में प्रांतीय सेवाओं के लिए आवंटन को सम्मिलित नहीं किया गया है (कुल 14,17,571 रुपये; बंगाल 2,89,528 रुपये, पश्चिमोत्तर प्रांत 2,25,600 रुपये; पंजाब 2,60,757 रुपये; मद्रास 88,858 रुपये; और बंबई 2,80,401 रुपये)। 1863 से पहले के वर्षों के विवरणों में स्वीकृत राशि दी गई है जो वास्तविक व्यय के लगभग हो है, परन्तु पूरी तरह तक़्तबदार नहीं है। 1863 से लेखे गए व्यय से तैयार किए गए और ये आंकड़े वास्तविक व्यय को दिखाते हैं। 1857-58 के आंकड़े 1 मई, 1857 से 31 दिसंबर 1858 तक और 1858-59 के आंकड़े केवल 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 1859 तक का व्यय बताते हैं।



## सारणी 15

सैन्य व्यय का विस्तृत विवरण : काल : 1865-66, 1869-70 तथा 1871-72। कुल  
सैन्य व्यय के साथ प्रत्येक मद पर व्यय का अनुपात कोष्ठकों में प्रतिशत  
(लाख रुपये में)

	1865-66		1869-70		1871-72	
	(रुपये लाख में)	कुल का प्रतिशत	(रुपये लाख में)	कुल का प्रतिशत	(रुपये लाख में)	कुल का प्रतिशत
1. सेना तथा रक्षक						
सेना स्टाफ	49	(2.9)	52	(3.2)	46	(3)
2. प्रशासनिक						
स्टाफ	20	(1.2)	20	(1.2)	20	(1.3)
3. रेजिमेंटों को वेतन	684	(40.9)	666	(40.9)	650	(41.5)
4. निम्नलिखित स्थापन खर्च :						
(क) रसद						
विभाग	313	(18.7)	243	(14.9)	193	(12.3)
(ख) घोड़े	19	(1.1)	25	(1.6)	18	(1.1)
(ग) वस्त्र	15	(0.9)	11	(0.7)	12	(0.8)
(घ) बैरक	33	(2)	35	(2.2)	34	(2.1)
(छ) सेना- शासन	4	(0.3)	4	(0.3)	5	(0.3)
(च) चिकित्सा विभाग	44	(2.6)	46	(2.8)	42	(2.7)
5. युद्ध सामग्री	45	(2.7)	54	(3.3)	60	(3.8)
6. सामुद्रिक						
यातायात	34	(2)	15	(0.9)	11	(0.7)
7. प्रकीर्ण सेवाएँ	57	(3.4)	47	(2.8)	49	(3.2)
8. पेंशन						
अनियमित	117	(7)	64	(3.9)	63	(4)
9. भारत में कुल योग	1436	(85.7)	1282	(78.6)	1203	(76.8)
10. इंग्लैंड में व्यय :						
(क) भंडार	—	—	88	(5.4)	94	(6)
(ख) नियमित व्यय	128	(7.6)	142	(8.7)	132	(8.4)
(ग) गैर निय- मित व्यय	111	(6.6)	119	(7.3)	138	(8.8)
11. इंग्लैंड में कुल व्यय	239	(14.2)	350	(21.4)	364	(23.2)

## सारणी 16.1

ब्रिटिश भारत में नियोजन : सैनिकों की संख्या

	शही सेना यूरोपीय	भारतीय सेना		कुल	कुल योग
		यूरोपीय	भारतीय		
1859	86,186	20,104	1,96,243	1,06,290	3,02,533
1860	72,158	20,708	2,13,002	92,866	3,05,868
1861	62,120	22,174	1,84,672	84,294	2,68,966
1862	67,545	10,629	1,25,913	78,174	2,04,087
1863	71,074	5,001	1,21,775	76,085	1,97,860
1864	70,674	4,287	1,21,060	74,961	1,96,021
1865	65,901	5,979	1,18,315	71,880	1,90,195
1866	62,451	4,363	1,17,095	66,814	1,83,909
1867	61,498	3,969	1,17,681	65,467	1,83,148
1868	58,2888	3,609	1,19,169	61,897	1,81,066
1869	60,969	3,889	1,20,000	64,858	1,84,858
1870	59,487	3,452	1,17,881	62,939	1,80,820

## सारणी 16.2

ब्रिटिश भारत की प्रत्येक प्रेसीडेंसी में नियोजित कुल सैनिकों की समस्या : यूथ्-यूथ् यूरोपीय और भारतीय सेना

	यंगल			मद्रास			बंबई		
	यूरोपीय	भारतीय	कुल	यूरोपीय	भारतीय	कुल	यूरोपीय	भारतीय	कुल
1859	62,167	82,687	1,44,854	17,091	67,141	84,232	27,032	46,415	73,447
1860	57,778	91,998	1,49,676	17,851	78,440	96,291	17,237	42,664	59,901
1861	51,791	86,620	1,38,411	18,257	63,727	81,984	14,246	34,325	48,571
1862	47,912	39,210	87,122	16,421	55,687	72,108	13,841	31,016	44,857
1863	46,614	40,945	87,559	15,113	50,964	66,077	14,358	28,866	43,224
1864	45,283	42,938	88,221	15,583	50,131	65,714	14,095	27,991	42,086
1865	42,128	43,796	85,924	16,002	46,693	62,695	13,750	27,826	41,576
1866	38,992	43,394	82,386	14,184	46,435	60,619	23,638	27,266	40,904
1867	38,029	44,428	83,457	13,511	46,046	59,557	12,927	27,207	40,134
1868	35,125	45,758	80,883	12,145	45,961	58,106	14,627	27,450	42,077
1869	39,249	46,112	85,361	12,939	45,681	58,620	12,670	28,207	40,877
1870	38,106	44,642	82,748	13,650	45,744	59,394	11,183	27,495	38,678
1971	40,698	63,170	1,03,868	13,471	32,434	45,905	12,506	26,764	39,270

टिप्पणी : 1870-71 के वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## सारणी 17

प्रत्येक प्रेसीडेंसी में सेना पर सकल व्यय और इंग्लैंड में भुगतान

(करोड़ रुपयों में)

	भारत सरकार	मद्रास प्रेसीडेंसी	बंबई प्रेसीडेंसी	इंग्लैंड में भुगतान	कुल सकल व्यय
1864	7.16	3.06	2.47	1.81	14.51
1865	7.49	3.26	2.75	2.28	15.77
1866	8.15	3.34	2.87	2.39	16.78
1867	6.72	3.08	2.64	3.38	15.82
1868	6.75	3.07	2.78	3.5	16.1
1879	7.01	3.02	2.96	3.28	16.27
1870	6.97	2.99	2.86	3.5	16.33
1871	6.51	2.91	3.12	3.12	16.07
1872	6.54	2.85	2.64	3.64	15.68

टिप्पणी : (क) कालम 2 इस कालम में बंगाल प्रेसीडेंसी का व्यय सम्मिलित है। (ख) कालम 5 : इंग्लैंड में प्राप्तियों की राशियां 1863-64 में 24.9 लाख रुपये, 1864-65 में 1.1 लाख रुपये और 1865-66 में 4.2 लाख रुपये थी, जो हम लेख में इंग्लैंड में उक्त वर्षों में होने वाले खर्चों को घटाकर दिखाई गई हैं।

## भारती 18

प्रदेश विभाग एवं के अंत में विद्यमान भारत के अपरिमोपित लोक-संख्या की राशियां 1858-69 से 1872-73 तक

	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	लाय पौंड में 1 पौंड = 10 रुपये
सर्ग									
समाधि									
दरिद्र में वृद्ध	1509	26.14	29.98	35.1	31.84	26.31	26.12	26.95	
कुल मात	81.17	98.11	101.88	107.51	104.5	98.52	98.48	98.38	
सर्ग समाधि	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873		
दरिद्र में वृद्ध	29.54	30.7	31.7	35.2	37.63	39.01	39.01		
कुल योग	102.06	101.99	102.87	108.19	119.0	121.77	121.5		

टिप्पणी : इस विभाग में 1 करोड़ 20 लाख लोग के ईस्ट इंडिया कंपनी के गेजर (स्टार) सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इस पर प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्टीमेट (आकलन) भाग 11 के भाग 16 में वृद्ध प्रचार गवर्नी विवरण में सम्मिलित किया गया है।

## सारणी 19

प्रत्याभूत (गारंटी शुद्धा) कंपनियों को भुगतान किया गया वार्षिक व्यय  
1860-61 से 1871-72 तक

वर्ष समाप्ति	लाख पाँड में
	1 पाँड = 10 रुपये
	राशि
1861	1.48
1862	1.78
1863	2.17
1864	2.46
1865	2.69
1866	2.90
1867	3.04
1868	3.49
1869	3.91
1870	4.13
1871	4.35
1872	4.50

## सारणी 20

भारत सरकार के इंग्लैंड में शुद्ध भुगतान : मुख्य मर्चे और भुगतान की रीति

लाग पौंड में

1 पौंड = 10 रुपये

शुद्ध भुगतान :

	2	3	4	5	6
	कुल योग	ऋण प्रभार	भारत के लिए भंडार	ब्रिटिश सेना की सेवा	ब्रिटिश सेना का परिवहन
1857	4.43	.89	1.03	.29	.05
1861	8.12	1.85	1.29	1.46	.37
1862	11.17	2.13	1.12	1.33	.15
1863	8.63	.22	.70	.92	.14
1864	11.86	2.08	.41	.58	.17
1865	7.47	1.93	.71	1.03	.18
1866	9.11	1.95	1.28	.85	.46
1867	9.20	1.97	1.16	8.9	.85
1868	8.09	2.15	1.15	.97	.58
1869	9.11	2.16	1.63	.85	.44
1870	12.01	2.21	1.67	.95	.28
1871	11.57	2.35	1.58	.90	.31
1872	12.20	2.44	1.41	1.07	.27

टिप्पणी : कालम 5 में भारत स्थिति ब्रिटिश सेना की सेवा पर और कालम 6 में इसके ब्रिटेन और भारत के बीच परिवहन पर गृह खर्चों को दिखाया गया है।

## सारणी 20

गत पृष्ठ से आगे

	7	8	9	10	11
	भारतीय अफसरों का अव- काश भत्ता	भारतीय अफसरों की पेंशन	प्रकीण पेंशन	भारतीय भविष्य निधि	गृह प्रशासन खर्च
1857	.23	.92	.3	.37	.19
1861	.3	.91	.38	.44	.18
1862	.3	.94	.4	.46	.19
1863	.27	1.13	.48	.45	.17
1864	.24	1.12	.53	.47	.17
1865	.24	1.09	.37	.48	.17
1866	.28	1.09	.37	.52	.18
1867	.3	1.06	.32	.43	.19
1868	.34	1.08	.39	.52	.2
1869	.38	1.07	.29	.56	.21
1870	.56	1.07	.44	.6	.21
1871	.65	1.06	.38	.62	.22
1872	61	1.05	.34	.66	.21

टिप्पणी : कालम 7 में छुट्टी पर इस्तेमाल में रहने वाले अफसरों के अवकाश तथा अनुपस्थिति भत्ते सम्मिलित हैं। कालम 8 में भारत सरकार के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पेंशनों और बायिकी तथा पेंशनो के बदले में उपदा (बेंचुटी) और पूंजीगत भुगतान सम्मिलित हैं। कालम 11 में भारत मंत्री, तथा भारत उपमंत्री के वेतन, इंडिया काउंसिल के सदस्यों, इंडिया आफिस के स्थापन आदि पर होने वाले खर्च दिखाए गए हैं। इस सारणी में दिखाई गई मदों के अलावा दो अन्य दिलचस्प मदें थी : 1862-64 में 'ऋण परिशोधन'—17.6 और 55.3 लाख पौंड, तथा 'प्रत्याभूत कंपनियों' को व्याज का भुगतान। ये मदें सारणी 19 में दिखाई गई हैं।



## सारणी 20

(गत पृष्ठ से आगे)  
भुगतान की रीतियाँ

	12 कुल भुगतान	13 विनिमय बिल	14 प्रत्याभूत (गारटी- शुदा) कंपनियों की शुद्ध प्राप्तिया	15 ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनर्भुग- तान	16 भारत से सोने-चांदी के रूप में भेजी गई राशि	17 लिया गया ऋण
1857	4.23	2.82	1.09	—	—	—
1861	8.12	—	1.95	9.2	—	3.71
1862	11.17	1.19	5.22	9.5	—	3.69
1863	8.63	6.64	1.26	2.4	—	—
1864	118.6	8.98	2.23	—	—	—
1865	7.47	6.79	—	—	—	—
1866	9.11	6.99	—	—	.16	.85
1867	9.2	5.61	—	—	.88	2.64
1868	8.09	4.14	1.37	0.3	—	1.16
1869	9.21	3.71	.18	4.29	—	1.03
1870	12.01	6.98	—	1.35	—	3.54
1871	11.57	8.44	—	1.3	5.7	2.42
1872	12.2	10.31	—	—	—	1.41

टिप्पणी : कालम 13 में लंदन में लिखे जाने वाले विनिमय बिल तथा सार द्वारा हस्तांतरण हैं। इसमें भारत पर चीन में काटे गए बिल और भारत में खरीदे गए और लंदन के नाम काटे गए बिल जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण थे, सम्मिलित नहीं हैं। कालम 15 में चीन और अबोसीनिया में भारतीय सेना के प्रयोग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई अदायगी को दिखाया गया है (अबोसीनिया के संबंध में इस मद में इंग्लैंड में किए गए भुगतान पर वापसी की राशि की अधिकता दिखाई गई है।) कालम 16 में भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड को सोने-चांदी के रूप में भेजी गई राशि और कालम 14 में प्रत्याभूत (गारटीशुदा) कंपनियों की शुद्ध प्राप्तिया दिखाई गई हैं।

## सारणी 21.1

शिक्षा पर व्यय 1857-58 से 1871-72 तक

	2	3	4	5
	शिक्षण संस्थाएं	छात्रों की औसत उपस्थिति (हजारों में)	सकल सरकारी व्यय (लाख रुपये)	सभी स्रोतों से कुल व्यय (लाख रुपये)
1858	8,070	151	23.15	—
1859	12,479	239	25.94	—
1860	13,550	306	23.34	31.54
1861	14,322	333	23.54	36.39
1862	13,219	351	24.83	28.41
1863	15,159	396	27.45	40.26
1864	17,058	474	31.99	49.78
1865	17,813	448	40.7	64.46
1866	19,463	593	44.56	74.42
1867	20,683	659	46.14	75.55
1868	21,549	675	53.76	89.68
1869	23,300	758	59.16	100.97
1870	24,274	789	63.75	107.07
1871	25,147	800	64.97	107.94
187	43,192	977	68.58	108.34

टिप्पणी : (क) कालम 2 में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अथवा उससे सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की संख्या और कालम 3 में इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या दिखाई गई है। (ख) कालम 5 में शिक्षा पर व्यय, निजी और सार्वजनिक दोनों ही स्रोतों से, दिखाया गया है।

## सारणी 21.2

शिक्षा पर व्यय : मुख्य प्रांतों । प्रे सीडेसियों में : सरकार व्यय (कात्म क) और सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों से कुल व्यय (कात्म ख)  
(साथ रूपों में) वर्ष

	बंगाल		पश्चिमोत्तर प्रांत		पंजाब		मद्रास		वर्ष	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1858	10.4	10.5	3.3	अनुपलब्ध	1.4	2.3	4.1	अनुपलब्ध	3.9	अनुपलब्ध
1859	10.2	10.3	4.6	"	1.7	2.9	5.1	"	4.3	"
1860	8.0	10.4	5.0	6.9	1.6	3.4	4.9	"	3.8	5.8
1861	8.1	11.0	5.0	9.5	1.5	4.2	5.3	5.6	3.7	6.1
1862	8.8	11.0	4.9	अनुपलब्ध	1.8	5.1	5.1	5.4	4.3	6.8
1863	9.9	12.3	4.9	7.5	2.6	7.3	5.6	5.6	4.4	7.5
1864	11.2	17.3	5.4	7.6	2.8	6.5	6.1	6.5	5.2	9
1865	12.6	20.3	7.3	11.2	4.1	7.9	6.7	7.1	7.1	12
1866	13.8	22.9	7.8	11.9	4.8	8.7	6.2	7.2	8.7	17.1
1867	13.9	22.9	7.7	12.3	5.6	9.5	6.2	7.3	9.2	15.2
1868	16.6	27.4	9.6	14.9	4.7	9.5	7.1	8.4	8.7	16.7
1869	17.5	29.5	9.7	18.1	6.0	9.8	8.6	10.6	8.5	17.6
1870	18.4	31.6	10.7	18.9	5.8	10.0	9.8	11.5	8.9	18.1
1871	18.7	32.0	10.5	19.4	5.9	10.2	10.2	11.7	9.5	20.9
1872	18.1	31.9	12.1	19.4	6.2	10.5	8.6	15.6	9.0	20.7

## संदर्भ ग्रंथ सूची

### 1. प्राथमिक स्रोत

- (क) सार्वजनिक अभिलेख
- (ख) निजी कागजात
- (ग) भारत सरकार के शासकीय प्रकाशन
- (घ) संसदीय कागजात
- (ङ) समकालीन पैंम्पलेट, पुस्तिका तथा विवादास्पद कृतियां
- (च) प्रकाशित पत्र व्यवहार, भाषण, वृत्त आदि
- (छ) समकालीन पत्र पत्रिकाएं

### 2. अनुपूरक स्रोत

#### 1. प्राथमिक स्रोत

##### (क) सार्वजनिक अभिलेख

भारत सरकार की वित्तीय नीतियों पर स्रोत-सामग्री के लिए खोज [यद्यपि वित्त-विभाग के अभिलेखों से प्रारंभ होनी चाहिए, परंतु यह इतने ही तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये स्रोत अनेक सिरीज में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुए सार्वजनिक अभिलेखों में फँसे हुए हैं। यदि कोई भी शोधकर्ता अपने अध्ययन को मोटी-मोटी जिल्दों में उपलब्ध वित्त-विभाग के अभिलेखों तक ही सीमित रखता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसकी जांच का क्षेत्र विगत मनमानी प्रशासनिक व्यवस्था (और अभिलेखागारीय वर्गीकरण) के द्वारा निर्धारित हो जाता है। जैसा कि ट्रैबोलियन ने कहा है 'वित्त सभी विभागों की कुंजी है।' चूँकि वित्त विभाग का साधनों पर नियंत्रण था, इसलिए सरकार का प्रत्येक दूसरा विभाग वित्त विभाग के संवीक्षण जांच-पड़ताल के अंतर्गत आ जाता था। स्पष्टतः वित्तीय दृष्टि से सभी विभाग समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण विभाग थे—सेना, लोक-निर्माण, गृह और (1869 में सृजित) नया विभाग राजस्व, कृषि और वाणिज्य। इसके अलावा जिस काल का हमने अध्ययन किया है, वह नव-प्रवर्तनों और प्रयोगों का काल था। प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न विभागों के मध्य कार्यों का विभाजन व्यवस्थित नहीं था। उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में वित्तीय व्यवसाय जिसका काफी बड़ा अंश वित्त विभाग के बाहर संपन्न किया जाता था, को प्रभावित करने वाले अनेक परिवर्तन हुए। 1843 में वित्तीय मामलों के लिए एक

सचिव की नियुक्ति की गई। यही से पृथक वित्त विभाग का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इस विभाग का प्रधान कार्य भुगतानों पर नियंत्रण रखना था। बहुत सारा वित्तीय व्यवसाय, विशेष रूप से राजस्व संग्रह के क्षेत्र में गृह-विभाग ('राजस्व' एवं 'पृथक राजस्व' शाखाएं) का उत्तरदायित्व था। गवर्नर जनरल की परिपद में वित्त सदस्य की नियुक्ति से, जो परिपद का चौथा सामान्य सदस्य था, वित्त विभाग की स्थिति मजबूत हो गई। जेम्स विल्सन द्वारा प्रवर्तित वित्तीय नियंत्रण के केंद्रीयकरण की नीति और विशेष रूप से बजट मबंधी नियंत्रण की नवीन प्रणाली से अन्य विभागों की तुलना में वित्त विभाग के उत्तरदायित्वों और शक्तियों में वृद्धि हुई। परिपद में संविभागीय प्रणाली (पोर्ट फोलियो सिस्टम) से जिसका प्रारंभ कैनिंग ने किया था और जो 1851 के इंडियन काउंसिल एक्ट (जिसके अनुसार गवर्नर जनरल को परिपद में सुविधापूर्वक कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार मिला) के बनने के बाद और भी अधिक वैज्ञानिक पुनर्गठन तथा व्यवस्थित विभाजन को प्रोत्साहन मिला। सरकार का उद्देश्य समस्त वित्तीय कामकाज को सदस्य और वित्त सचिव के नियंत्रण में लाना था। 21 मार्च, 1861 को कुछ विषय (स्टाम्प शुल्क) गृह विभाग से वित्त विभाग को अंतरित कर दिए गए। कुछ प्रशासनिक असुविधाओं के कारण अंतरण रद्द कर दिया गया और इन कार्यों के संग्रह का कार्य मार्च, 1862 में पुनः गृह विभाग के पास पहुंच गया। तथापि ये विषय तथा नमक शुल्क, अफीम राजस्व और आवश्यकी शाखाएं अंतिम रूप से अक्टूबर, 1863 में गृह विभाग से वित्त विभाग को अंतरित कर दिए गए (सितंबर, 1864 तक अवध, पंजाब, ब्रिटिश, बर्मा और मध्य प्रांत में ये परिवर्तन लागू नहीं हुए थे)। गृह-विभाग के अतिरिक्त दो अन्य विभाग वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इनमें से एक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग था जिसकी स्थापना 1855 में हुई थी। दूसरा सैन्य विभाग था। सैन्य विद्रोह के बाद सैन्य व्यय में व्यवस्थित रूप से कटौती की नीति के कारण एक सैन्य वित्त आयोग (जून, 1859) के निर्माण की आवश्यकता हुई जो कालांतर में सैन्य वित्त विभाग में बदल दिया गया। कुछ समय बाद (अप्रैल, 1864) इसका स्थान सैन्य विभाग के महालेखाकार ने ग्रहण कर लिया। जून, 1871 में राजस्व, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की मालगुजारी सर्वेक्षण बंदोबस्त, कृषि एवं वाणिज्य साक्ष्यिकी, वन, इत्यादि के कार्य गृह, वित्त, और लोक निर्माण विभागों से अंतरित कर दिए गए। थोड़े समय बाद (1872-77 में) कुछ अन्य विषय जैसे नमक, अफीम, सीमा शुल्क तथा स्टाम्प भी इस विभाग को दे दिए गए।

वित्त विभाग में सपरिपद गवर्नर जनरल का कार्य विवरण (शाखाएं : लेखा और वित्त, अनुपस्थिति के लिए अवकाश, पेंशन व ग्रेचुटी, व्यय, पृथक राजस्व और प्रकीर्ण) 1858-75। वित्त विभाग में सपरिपद गवर्नर जनरल का कार्य-विवरण (शाखा : राजस्व, पृथक राजस्व, लोक) 1858-72। सैन्य विभाग में सपरिपद गवर्नर जनरल का कार्यविवरण (शाखा : वित्त), 1858-72।

लोक निर्माण सपरिपद विभाग में गवर्नर जनरल का कार्यविवरण, 1858-72।

कृषि, राजस्व एवं वाणिज्य विभाग में सपरिपद गवर्नर जनरल का कार्यविवरण (1871-73)।

कोर्ट आफ डायरेक्टर्स से भारत सरकार को प्रेषण :

(क) वित्त प्रेषण, 1857-58।

(ख) रेल प्रेषण, 1857-58।

भारत सरकार से कोर्ट आफ डायरेक्टर्स को प्रेषण :

वित्त प्रेषण 1857-58।

भारत मंत्री से भारत सरकार (सपरिपद गवर्नर जनरल) को प्रेषण :

(क) वित्त प्रेषण, 1858-75।

(ख) राजस्व प्रेषण, 1858-75।

(ग) पृथक राजस्व (गृह) प्रेषण, 1858-60।

(घ) रेल प्रेषण, 1858-72।

(ङ) सैन्य प्रेषण, 1858-72।

भारत सरकार (सपरिपद गवर्नर जनरल) से भारत मंत्री को प्रेषण :

(क) वित्त प्रेषण, 1858-72।

(ख) राजस्व प्रेषण, 1859-72।

(ग) लोक निर्माण प्रेषण, 1859-72।

(घ) सैन्य प्रेषण, 1859-72।

### (ख) निजी कागजात

जेम्स ब्रूस, एलिन का आठवां अर्ल (1811-63), भारत का गवर्नर जनरल (1862-63), के कागजात (पाण्डुलिपियाँ यूरोप एफ० 83, इंडिया आफिस लाइब्रेरी)। उसकी कार्यावधि लघु थी और उसके कागजात का इस अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा ही महत्व है।

सर जेम्स लारेंस (प्रथम बरेन लारेंस—1811-79), भारत का गवर्नर जनरल (1864-69), कागजात (पाण्डुलिपियाँ यूरोप एफ० 90, इंडिया आफिस लाइब्रेरी तथा अमर्यांकित माइक्रो फिल्म, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार)। इसमें अधिक उपयोगी सामग्री भारत मंत्री द्वारा लिखे गए पत्रों की जिल्दों में है, ये हैं—जिल्द I व II, 1864-65 (चार्ल्स वुड); जिल्द III, 1866 (वुड, डि ग्रे तथा रिपन; क्रेनवोर्न); जिल्द IV, 1867 (क्रेनवोर्न तथा नोर्थकोट); जिल्द V, 1868 (नोर्थकोट)। लारेंस द्वारा भारत मंत्रियों और सपरिपद गवर्नर जनरल के सदस्यों को लिखे गए पत्र भी उपयोगी हैं। रिचर्ड वॉर्क, मेयो के छठे अर्ल (1822-72), भारत के गवर्नर जनरल (1869-72) के कागजात (पता—7490, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी तथा असंख्यांकित माइक्रो-फिल्म, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार)। प्रेषित पत्रों की संख्या लगभग 1,200 है जिनमें बहुत सारे वित्तीय समस्याओं के विषय में हैं। भारतमंत्री द्वारा प्रेषित 111 पत्र और एच० वार्टल फ्रेर, आर टेंपल, जे० स्ट्रेची एस० नोर्थकोट, एच०, एस० मेन, जी०

कंपबैल, एस० फिट्जजेराल्ड तथा कुछ अन्य लोगों के द्वारा लिखे गए अनेक पत्र बहुत उपयोगी तथ्य प्रकाश में लाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ बंडलों में (जो संख्यांकित हैं) पत्र न तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित है और न ही वे संख्यांकित हैं। प्रेषित पत्र अपेक्षाकृत व्यवस्थित है।

सर चार्ल्स एडवर्ड ट्रेवीनियन (1807-86), मद्रास का गवर्नर (1859-60) तथा वित्त सदस्य (1862-65), की पत्र-पंजियां। (मैंने बोडलियन लाइब्रेरी, आवसफोर्ड में इन पत्रों की 'माइक्रो फिल्म प्रति का उपयोग किया है। मूल कागजात जो पहले बोडलियन के पास थे अब टाइम पर न्यूकैसिल में हैं। मैं ट्रेवीनियन की सामग्री की प्रबंधक लेडी मेरी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये निजी कागजात देखने दिए। (इंग्लैंड में सिविल-सेवा विपयक सुधारों के बारे में ट्रेवीनियन के कार्यों से संबंधित कागजात के अतिरिक्त अब तक ट्रेवीनियन की पत्र पंजियों का उपयोग नहीं हुआ है। मैंने इन 44 संग्रहों में से बाद की जिल्दों का प्रयोग किया है। इन संग्रहों का काल 1840 से 1865 तक है।

सर चार्ल्स ब्रूड, प्रथम विसकाउंट हेलीफाक्स (1800-85), भारत मंत्री, 1859-66, के कागजात (पाण्डुलिपिया यूरोप एफ० 78 इंडिया आफिस लाइब्रेरी), पत्र-पंजियां 1859-66, 22 जिल्दें।

मेयो, जेम्स विल्सन, वार्टन फ़ैर, जार्ज कंपबैल, जान सारेंस, रिचर्ड टैपिल आदि की जीवनियां और प्रकाशित पत्रों में अनुपूरक सामग्री मिलती है (देखें, ग्रंथ सूची, एफ)।

### (ग) शासकीय प्रकाशन

'एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फार दि आफिशियल इयर्स 1860-61 टु 1971-72' (कलकत्ता, 1871)।

'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टु इंडिया डिलीवर्ड इन पार्लियामेंट बाई सभसे-सिव प्रेसीडेन्ट्स आफ दि बोर्ड आफ कंट्रोल एंड सेक्रेटरीज आफ स्टेट फार इंडिया; रिप्रिंटेड फ्रॉम हंसाइंड्स पार्लियामेन्टरी डिबेट्स (कलकत्ता, 1872)।

'डब्ल्यू० एस० मेयर, मेमोरेण्डम आन दि फाइनेंशियल पावर्स आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया दि प्राविशियल गवर्नमेंट्स फार दि रायल कमीशन आन डिमेंट्रलाइजेशन' (शिमला, 1907)।

'कारेस्पॉन्डेंस एंड डिबेट्स इन दि लॉजिस्टिकल काउंसिल एंड मिनिट्स रिलेटिंग टु डायरेक्ट टैक्सेशन इन ब्रिटिश इंडिया कपाइल्ड इन दि फाइनेंस डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया', दो जिल्दें (कलकत्ता, 1882)।

'वेपर्स रिगार्डिंग दि कलैक्शन आफ इन्लीमल सैसस एंड ड्यूटीज इन बंगाल सिलेक्शन फ्रॉम दि रेकार्ड्स आफ गवर्नमेंट आफ बंगाल', संख्या 46 (कलकत्ता, 1873)।

'जे० एफ० फिल्ले, हिस्ट्री आफ प्राविशियल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स' (कलकत्ता, 1887)।

स्टैंडिस्टीकल ऐक्स्ट्रैक्ट आफ ब्रिटिश इंडिया (कलकत्ता)।

इंडियन सैजिस्ट्रेटिव काउंसिल प्रासीडिंग्स, 1861 तक पुरानी सीरीज (जिल्दे I से VI तक) और 1862 के बाद नई सीरीज (कलकत्ता) ।

### (घ) संसदीय कागजात

(चूंकि इनमें से अधिकांश कागजात उन अभिलेखों से उदाहरण हैं जिनका हम अनुच्छेद (क) में उल्लेख कर आए हैं, इसलिए यहां पर कुछ थोड़े से मबद्ध कागजात ही नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं ।)

	जिल्द	पृष्ठ	कागजात संख्या	विषय
एच० सी० 1859 II	23	31	154	ऋण : भारत सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऋणों का विवरण पत्र ।
एच० सी० 1860	49	241	339	वित्त : भारत में प्रस्तावित वित्तीय उपायों के विषय में पत्र व्यवहार ।
एच० सी० 1862	40	7	230	सेवा निवृत्ति भत्तों और लोकनिधि व लोक वापिकी निधि से संबंधित शिकायतों के विषय में भारतीय सिविल सेवा का स्मरण पत्र ।
एच० सी० 1862	40	665	327	बेकार भूमि की बिक्री और भारतीय मालगुजारी का स्थाई परिशोधन । पत्र व्यवहार, 1859-61 ।
एच० सी० 1863	43	389	164	बेकार भूमि की बिक्री और मालगुजारी का परिशोधन : कुछ और कागजात ।
एच० सी० 1863	22	5	87	बेकार भूमि की बिक्री, मालगुजारी परिशोधन, तथा स्थाई बंदोबस्त का विस्तार ।
एच० सी० 1867	50	125	450	मालगुजारी का स्थाई बंदोबस्त (पश्चिमोत्तर प्रांत) ।
एच० सी० 1871	8	1	363	पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति की रिपोर्ट कार्यविवरण सहित ।
एच० सी० 1872	8	1	327	पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति की रिपोर्ट कार्यविवरण सहित ।
एच० सी० 1873	12	1	179	पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति की प्रथम रिपोर्ट ।



एच० सी० 1873	12	9	194-	पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति की द्वितीय रिपोर्ट ।
एच० सी० 1873	12	19	354	पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति की तृतीय रिपोर्ट ।
एच० सी० 1874	8	1	329	पूर्वी भारत का वित्त : इस देश में भारत के राजस्व से देय खर्चों के विषय में जाच करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट (सैन्य व्यय)

### (ङ) समकालीन पैपलेट, पुस्तिकाएं तथा विवादात्मक कृतियां

अलैक्जेंडर, आर०	'दि राइज एंड प्रोग्रेस आफ ब्रिटिश ओपियम स्मॉलिंग' (लंदन 1866)
" "	'कोट्टाबंड ओपियम ट्रैफिक' (कलकत्ता, 1857)
अज्ञात	'दि फाइनेंसज आफ इंडिया' (लंदन, 1853)
"	'इंडियन रेलवे एंड इंडियन फाइनेंस' (बंबई, 1869)
"	'इंडियन फाइनेंस डिफेंडिट : ए रेस्पूटेसन आफ दि ओपीनियन टू जनरली हूल्ड दैट ब्रिटिश इंडिया इज ओवर वड्डेड विद डैट एंड टैक्सेशन' (लंदन, 1878)
"	'दि इंजिस्टिस एंड अप्रेशन आफ दि आवकारी डिपार्टमेंट ऐज ऐक्जिडिटेड इन दि पैटीशंस आफ टीहुी मर्चेन्ट्स' (मद्रास, 1859)
अज्ञात	'स्कैच आफ दि कर्माशियन रिसोर्सेज एंड मोनेटरी एंड मर्कैंटाइल सिस्टम आफ ब्रिटिश इंडिया' (लंदन, 1837)
अज्ञात	'दि सेट गवर्नमेन्ट बैंक आफ बंबई : इट्स हिस्ट्री' (लंदन, 1868)
	'हाउ बी टैंक्स इंडिया' (लीड्स, 1858)
आइडाराफ, एस०	'ब्रिटिश इंडिया फ्राम फाइनेशियल प्वाइंट आफ व्यू' (शिमला, 1878)
काकवर्न, एफ० के०	'दि कस्टम्स एक्ट आफ इंडिया, चीइंग एक्ट VI आफ 1863' (कलकत्ता, 1862)
काटन, ए०	'पब्लिक ववर्म् इन इंडिया : देअर इम्पोर्टेंस विद सजैशंस फार देअर ऐक्स्टेंशन एंड इंप्रूवमेन्ट' (लंदन, 1857)
काटन, एच० जे० एस०	'टेक्नीकल एजुकेशन आर दि इंडियन रिवोल्यूशन इन इट्स इकानामिक आस्पेक्ट्स' (लंदन, 1883)
कैलेंडर, डब्ल्यू० आर०	'दि कर्माशियन फाइनेंस आफ 1857' (लंदन, 1858)
कोस्टा, जे० डा०	'दि इंडियन बजट फार 1876' (लंदन, 1876)

- कोस्टा जे० दा० 'दि गवर्नमेंट एंड दि फाइनैसज आफ इंडिया' (लंदन, 1879)
- " " " 'दि पोलिटिकल एंड फाइनैशियल रिक्वायरमेंट्स आफ ब्रिटिश इंडिया एज सैट फोरथ इन ए पेंटीशन आफ दि ब्रिटिश इंडियन एसोशिएशन' (लंदन, 1880)
- कीनल, ए० के० 'दि इकानामिक रिवोल्यूशन आफ इंडिया एंड दि पब्लिक वर्क्स पालिसी' (लंदन, 1883)
- ग्रिम्ले, डब्ल्यू० एच० 'दि सी कस्टम्स ला आफ इंडिया, एक्ट VII आफ 1878 एंड टैरिफ, एक्ट' (लंदन, 1879)
- ग्रेहम, ए० 'दि मॉस आफ एमेलिओरेटिंग इंडिया' (ग्लासगो, 1835) ।
- चंपमैन, जे० 'प्रिंसिपल्स आफ इंडियन रीफार्म बीइंग ग्रीफ हिंदुस टु गैदर विद ए प्लान फार दि इम्प्रूवमेंट आफ दि कॉन्स्टीचुएंसी आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फार दि प्रमोशन आफ इंडियन पब्लिक वर्क्स' (लंदन, 1753)
- जेफरीज, टी० डब्ल्यू० बी० 'नेशनल क्रेडिट एंड पब्लिक वर्क्स' (कराची, 1871)
- टकर, हेनरी सेंट जार्ज 'प्लास आफ फाइनैस लेटली इट्रोड्यूस्ड बाइ दि आनरेबिल कोर्ट आफ डायरेक्टर्स एंड बाइ दि सुप्रीम गवर्नमेंट आफ इंडिया' (लंदन, 1321)
- टकैट, एच० 'दि इंडियन रेवेन्यू सिस्टम ऐज इट इज' (लंदन, 1840)
- टोरेंस, राबर्ट 'लेटर टु दि राइट आनरेबिल आर० बर्नन स्मिथ विद ए रिव्यू आफ डायग्नोसिस' (लंदन, 1856)
- ट्रैवीलियन, सी० ई० 'लेटर्स आफ इंडोफिलस टु दि टाइम्स' (लंदन 1875, कृतक नाम 'इंडोफिलस')
- डिकिंसन, जे० 'इंडिया इट्स गवर्नमेंट अंडर ए व्यूरोक्रैसी' (लंदन, 1853)
- तलवार खां, दिग्गहाह आर्दशीर 'ए रिव्यू आफ दि बंबई टैक्सेशन डिस्कशन आफ 1871' (बंबई 1871)
- थोर्नटन, विलियम थामस 'इंडियन पब्लिक वर्क्स एंड कोन्नेट इंडियन टापिक्स' (लंदन, 1875)
- थोर्नबर्न, डब्ल्यू० एम० 'इंडिया सोल्वेंट' (मद्रास, 1880)
- नाइट, राबर्ट 'इंडियन एंपायर एंड अवर फाइनैशियल रिलेशंस देअर विद' (लंदन, 1866)
- नाइट, राबर्ट 'स्पीच आन इंडियन एफेयर्स ऐट दि मैनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स' (लंदन, 1866)
- नाइट, राबर्ट 'इंडिया : ए रिव्यू आफ इंग्लैंड्स फाइनैशियल रिलेशंस देअर विद' (लंदन, 1868)
- नाइट, राबर्ट 'दि फाइनैशियल स्टेटमेंट दैट शुड हैव बीन डिक्लीवर्ड एंड वाज नाट' (बंबई, 1870) अन्य नाम से प्रकाशित

- नाइट, राबर्ट 'डिसेंट्रलाइजेशन आफ दि फाइनैसेज आफ इंडिया' (बंबई, 1871)
- नाइट राबर्ट 'हाउ दि पर्मानेंट सेंटिलमेंट पेज' (बंबई, 1862)
- नाइट, राबर्ट 'मैनचेस्टर एंड इंडिया : ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर जोन स्ट्रैचीज फाइनैशियल स्टेटमेंट' (कलकत्ता, 1877)
- नोटन, जे० 'ए न्यू फाइनैशियल स्कीम फार इंडिया, ए स्टैप टु पोलिटिकल रीफार्म' (लंदन, 1857)
- नौरोजी, दादाभाई 'पोवर्टी आफ इंडिया' (बंबई, 1873)
- नौरोजी, दादाभाई 'एसेज, स्पीचेज, ऐड्मिनिस्ट्रेशन एंड राइटिंक्स आन इंडियन पालिटिक्स आफ दि आनरेबिल दादाभाई नौरोजी' (संपादक—सी० पारिख, बंबई, 1887)
- पार्कर, एच० एम० 'दि एपायर आफ दि मिडिल क्लासज' (लंदन, 1858)
- पूना सार्वजनिक सभा 'रिपोर्ट फ्रॉम सब कमिटी अप्वाइंटेड टु कर्नल इफार्मेशन टु वी लेड विफोर दि ईस्ट इंडिया फाइनैस कमिटी' (पूना, 1872)
- प्रोवीन, एल० सी० 'इज इंडिया सोल्वेंस ?' (लंदन, 1880)
- फास्ट हेनरी, (एम० पी०) 'इंडियन फाइनैस : श्री एसेज रिपब्लिशड फ्रॉम दि 'नाईटीय सेचुरी' (लंदन, 1860)
- बर्न, ओ० टी० 'ए पयू लैटर्स आन दि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि अल आफ मेयो 1869-72' (शिमला, 1877, अज्ञात नाम से कुछ खास लोगो के बीच वितरण के लिए)
- विन्नी, ए० आर० 'पब्लिक वर्क इन इंडिया : ए लैटर एड्रैस्ड टु दि राइट आनरेबिल डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन, एम० पी० एंड अवर मेम्बर्स आफ हर मंजिस्ट्रीज गवर्नमेंट' (लंदन, 1881)
- बैल, मेजर हवास 'रिट्रास्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स आफ इंडियन पालिसी' (लंदन, 1881)
- „ „ „ (संपादन) 'लास्ट कौंसिल आफ एन अननोन कौंसिलर, जोन डिकिंसन' (लंदन, 1877)
- बंगाली, सोराबजी 'ए लैटर टु दि राइट आनरेबिल लार्ड लिटन अगेंस्ट दि कोर्ट-प्लेटड रिपोल आफ दि ड्यूटीज आन दि इपोट ऑफ फारेन काउन् गुड्स इन इंडिया' (बंबई, 1877)
- ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 'कारेस्पॉडेंस विटवीन दि गवर्नमेंट आफ बंगाल एंड दि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' (कलकत्ता, 1862)
- ब्रूस्, एच० 'साल्ट सोमंज आफ इंडिया एंड दि कस्टम्स प्रिविलिज ऐस्टेब्लिशमेंट आफ दि नोथ वेस्टर्न प्राविसेज एंड दि पंजाब' (कलकत्ता, 1863)

मिल्स, ए०

'इंडिया इन 1858, ए ममरी आफ दि एक्जिस्टिंग एडमिस्ट्रेशन, पोलिटिकल, फिस्कल एंड जुडीशियल आफ ब्रिटिश इंडिया' (लंदन, 1858)

मुकर्जी, शंभू० सी०  
मैकैड्यू, आई० एफ०

'विल्सन, कॅनिंग एंड दि इनकम टैक्स' (कॅनिंग, 1860)  
'आन मम रैवेन्यू मैटर्स, चीफली इन दि प्रोविंस आफ अवध' (कलकत्ता, 1876)

मैथेसन, डोनाल्ड  
मोक्सन, थोमस बी०  
मोल्सवर्थ, सी० एल०  
रश्टन, जे०

'व्हाट इज दि ओपियम ट्रेड' (एडिनबर्ग, 1857)  
'इंडियन फाइनेंस' (मैनचेस्टर, 1881)  
'ब्रिटिश जगरनोट : फ्री एंड फेयर ट्रेड' (1884)  
'इंडियन एक्सचेज हाउ अफैक्टेट वाइ होम चार्जेज, विद टेबिल्स आफ इंडियन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, फ्राम 1837 टु 1887' (कलकत्ता, 1888)

राय, मोहिनी मोहन  
लेविन, माल्कम

'टैक्सेशन इन इंडिया' (कलकत्ता, 1889)  
'दि गवर्नमेंट आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स मोनोपलीज, और दि यंग इंडिया पार्टी एंड फ्री ट्रेड ?' (लंदन, 1857) ।

रैग, सेमुअल ।  
थाइली, एम०  
विगेट, जार्ज

'फाइनेंशियल स्टेटमेंट' (कलकत्ता, 1861)  
'इंडिया ऐज ए फील्ड फार कामर्स एंड मिशन' (लंदन, 1867) ।  
'ए पयू वर्ड्स आन अवर फाइनेंशियल रिलेशंस विद इंडिया' (लंदन, 1859)

वैस्ट, एडवर्ड

'एमीग्रेशन टु ब्रिटिश इंडिया : प्रोफिटेबल इनवेस्टमेंट्स फार ज्वाइंट स्टॉक कम्पनीज एंड फार एमीग्रेट्स हू पजेस कंवीनल : एम्प्लोयमेंट फार एंटरप्राइजिंग एंड इंटेलीजेंट मैन : एपिल सप्लाइज आफ रा काटन, सिल्क, सुगर, राइस, टुबैको, इंडिगो, एंड अदर ट्रापिकल प्राडक्शंस : इन्फ्रिग्ज डिमांड फार मैन्यू-फैक्चर्ड गुड्स : सुपरसीडिंग आफ स्लेवरी : ओपनिंग्स फार मिशनरी एंड एजुकेशनल सोसाइटीज : एम्प्लायमेंट आफ ट्वेंटी मिलियंस आफ हिंदू लेबरर्स अपान वन हंड्रेड मिलियन एक्सर्स आफ फर्टाइल लैंड इन ब्रिटिश इंडिया, विद्वज इज नाउ वेस्ट एंड अनप्राडक्टिव' (लंदन, 1857)

हाउ, मेजर

'ए रिव्यू आफ दि टैरीटोरियल एंड मिमलेनियस रेवेन्यूज आफ ब्रिटिश इंडिया फार दि फोर इयर्स ऐंडिंग 1835-36, एंड आफ दि फोर इयर्स ऐंडिंग 1839-30, टु गैदर विद दि सिविल एंड मिलिटरी चार्जेज फार दि सेम पीरियड' (कलकत्ता, 1842)

हंटर, डब्ल्यू० डब्ल्यू०

'इंग्लैंड्स वर्क्स इन इंडिया' (लंदन, 1881)

हंटर, डब्ल्यू० डब्ल्यू०	'नोट्स आफ ए स्पीच आन सम आस्पैक्ट्स आफ इंडियन फाइ- नैस' (लंदन, 1880)
" " "	'सम आस्पैक्ट्स आफ इंडियन फाइनैस' (मैनचेस्टर, 1881)।
हिडमैन, एच० एम०	'दि बैंकरप्सी आफ इंडिया : एन इक्वायरी इंटू दि एडमिनि- स्ट्रेशन आफ इंडिया अंडर दि क्राउन, इक्लूडिंग ए चैप्टर आन दि सिल्वर क्वेश्चन' (लंदन, 1886)
हैक्टर, जे०	'अंडरसाइग प्रिंसिपल्स आफ इंडियन फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन' (लंदन, 1880)
हेमिल्टन, लांडे जार्ज	'स्पीच आन दि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दि हाउस आफ कॉमंस' (लंदन, 1876)

### (च) प्रकाशित वृत्त, जीवनी, पत्र व्यवहार, भाषण

आरगाइल, ड्यूक आफ	'इंडिया अंडर डलहौजी एंड कौनिंग' (लंदन, 1867)
ऐट्किंसन, सी० यू०	'लांडे लारेंस' (लंदन, 1905)
" " "	'लांडे लारेंस एंड दि रिक्स्ट्रक्शन आफ इंडिया अंडर दि क्राउन' (लंदन, 1903)।
कनिंघम, एच० एम०	'अलं कौनिंग' (लंदन, 1903)
फेमे, जे० डब्ल्यू०	'लाइज आफ इंडियन आफिसर्स', 3 जिल्दे (लंदन, 1875)।
कैपबेल, जार्ज	'मेमाइस आफ माइ इंडियन कैरियर, (संपादक) सर सी० ई० बर्नार्ड' (लंदन, 1893)
टैपिल, रिचार्ड	'मैन एंड इवेट्स आफ माइ टाइम इन इंडिया' (लंदन, 1882)।
" " "	'लांडे लारेंस' (लंदन, 1890)
" " "	'दि स्टोरी आफ माइ लाइफ' (लंदन, 1866)
पाल, थिस्टो दास	'स्पीचेज एंड मिनट्स' (कलकत्ता, 1882)
बाल्फोर, वेटी	'लांडे सिट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन 1876-80' (लंदन, 1899)
बीम्स जीन	'मेमाइस आफ द बंगाल सिविलियन' (लंदन, 1961)
बैरिंगटन एमिली आई०	'दि सर्वेंट आफ आल : पेजज फ्रॉम दि फेमिली, सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ आफ माइ फादर जेम्स विल्सन : ट्वेंटी द्रम आफ मिड विक्टोरियन लाइफ', 2 जिल्दे (लंदन, 1927)
भाटिन्यू, जान	'दि लाइफ एंड कारेस्पॉण्डेंस आफ सर वॉट्सन फ्रैर', 2 जिल्दे (लंदन, 1895)
मिल, जान स्टुअर्ट	'दि सेंटर्न आफ जान स्टुअर्ट मिल', संपादक एच० एम० आर० इलियट, 2 जिल्दे (लंदन, 1910)
मेयो, अलं आफ	'स्पीचेज इन इंग्लैंड एंड इंडिया' (कलकत्ता, 1873)
मैक्लैगन, माइकल	बरीमेसी कौनिंग (लंदन, 1963)

मैलट, वर्नाडि	'थोमस जार्ज, अलं आफ नोर्थवुक, ए मेमोइर' (लंदन, 1908)
रिपन, मार्क्विस् आफ	'स्पोचेज', दो जिल्हे (कलकत्ता, 1883)
रोंग, जी० एम०	'दि अलं आफ एल्लिन' (लंदन, 1905)
लारेंस, जी०	'रेमिनिमेंसेज आफ फाट्टी थ्री इयर्स इन इंडिया' (लंदन, 1875)
वाचा, डी० ई०	'प्रेमचंद रायचंद . हिज अर्ली लाइफ एंड कैरियर' (बंबई, 1913)
वैस्ट, अल्जनेन	'सर चार्ल्स वुड्स एडमिनिस्ट्रेशन आफ इंडियन अफेयर्स 1859-66' (लंदन, 1867)
स्क्राइन, एफ० एच०	'एन' इंडियन जर्नलिस्ट : वीइंग दि लाइफ लैटर्स एंड कारे-स्पोंसेस आफ डाक्टर शंभू सी० मुकर्जी, लेट एडीटर आफ रईस एंड रैयत' (कलकत्ता, 1895)
स्मिथ, आर० वी०	'लाइफ आफ लार्ड लारेंस', 2 जिल्हे (लंदन, 1883)
हंटर, डब्ल्यू० डब्ल्यू०	'दि अलं आफ मेयो' (लंदन, 1892)
" "	'ए लाइफ आफ दि अलं आफ मेयो, दि फोर्थ बायसराय आफ इंडिया', 2 जिल्हे (लंदन, 1875)

## (छ) समकालीन पत्र पत्रिकाएँ

### (i) समाचारपत्र (नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता)

- 'बंगाल हरफार' (कलकत्ता)
- 'दि इंग्लिशमैन' (कलकत्ता)
- 'दि फ्रैंड आफ इंडिया' (सीरामपुर)
- 'दि हिंदू पेट्रिअट' (कलकत्ता)
- 'दि इंडियन डेली न्यूज' (कलकत्ता)
- 'दि मद्रास एक्जामिनेर' (मद्रास)
- 'दि पायनियर' (इलाहाबाद)
- 'दि टाइम्स आफ इंडिया' (बंबई)

### (ii) हिंदुस्तानी प्रेस के विषय में रिपोर्ट्स (राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली)

बंगाल, बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसियों में प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तानी समाचार पत्रों के विषय में रिपोर्ट और पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रांत, अवध तथा मध्य प्रांत में प्रकाशित होने वाले देशी भाषाओं के समाचारपत्रों से उद्धरण भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध है। ये सरकारी नौकरी में हिंदुस्तानी समाचारपत्रों के शासकीय अनुवादकों एवं परीक्षकों की साप्ताहिक (अथवा पाक्षिक) रिपोर्टें होती थी। इन रिपोर्टों में देशी भाषाओं के समाचारपत्रों में प्रकाशित सामग्री के अंग्रेजी अनुवाद जो प्रायः संक्षिप्त अंग्रेजी रूपांतर होते थे, रहते थे। इन रिपोर्टों की थोड़ी सी प्रतियाँ छापी जाती थी और गृह विभाग में 'गोपनीय' कागजात के रूप में रखी जाती थी। ये रिपोर्टें बहुत उपयोगी

हैं क्योंकि पुनर्ने देनी भाषाओं के समानास्यों की मूल फार्मों का मिलना अब अनभव है। इन रिपोर्टों का उल्लेख करने समय जार० एन० पी० (हिंदुस्तानी प्रेस के विषय में रिपोर्ट) तथा एम० बी० एन० (देनी भाषाओं के समानास्यों में उद्धरण) संकेताश्रयों का प्रयोग किया गया है। देनी भाषाओं के समानास्यों (बंगला, तमिल, मराठी, उर्दू, इत्यादि) के नाम ग सार्वजनिक तथा रिपोर्टों में अनूचित उद्धरण उपलब्ध हैं, दोनों ही हैं। उदाहरणार्थ, 'गोमप्रकाश', 24 फरवरी 1865, जार० एन० पी० (बंगाल) 1868, पृष्ठ 89

### (iii) 'प्रकीर्ण पत्रिकाएँ'

'अनुभव रजिस्टर'

'दि इकानामिस्ट' (लंदन)

'बंगाल चेंबर आफ कामर्स', मद्रास की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्टें

'बम्बई चेंबर आफ कामर्स', रिपोर्टें

'बलकला रिब्यू', (बलकला, 1844)

'बलकला ट्रेडिंग एगोमिजेशन', मद्रास की रिपोर्टें, (1862)

जनरल आफ दि इस्ट इंडिया एगोमिजेशन', (लंदन), 1867

'दि इंडियन इकानामिस्ट' (बम्बई) 1869-75

'कराची चेंबर आफ कामर्स', रिपोर्टें

'लैंड होल्डर्स एंड कमजियन एगोमिजेशन', मद्रास की रिपोर्टें, 1863

### (2) अनुपूरक कृतियाँ

आर्मीन्ड, डब्ल्यू० टी० 'ग्रांट एंजेज आन सोजग एंड इंडियन सर्वेराइन' (बलकला, 1869)

एटकिंगन, एफ० जे० 'ए स्टैटिस्टिकल रिब्यू आफ दि इन्कम एंड वैल्यू आफ ब्रिटिश इंडिया, जनरल आफ दि रायल स्टैटिस्टिकल सोसायटी', 1902, LXV, पृष्ठ 209

एल्गटैंटर, फार्म 'दि इंडियन गिरवर करेंसी, ए हिस्टोरीकल एंड इकानामिक स्टडी', (जिकापो विश्वविद्यालय 1895), अनुवादक : जे० एन० लाफलिन

ऐस्टे, वेरा 'दि इकानामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' (लंदन, तृतीय संस्करण, 1936)

काल्किंस, डब्ल्यू० एन० 'ए बिकटोरियन फ्री ट्रेड लाबी', 'इकानामिक हिस्ट्री रिब्यू', द्वितीय सीरीज, जिल्द XIII, पृष्ठ 90-113

काले, बी० जी० 'डान आफ मोटर्न फाइनेंस इंडिया' (पूना, 1929)

केंज, जान मेनार्ड 'इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस' (लंदन, 1911)

कैपे, जे० डब्ल्यू० 'दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी', (लंदन, 1853)

- कैपटेल, जी० 'मोडर्न इंडिया : ए स्कैच आफ दि सिस्टम आफ सिविल गवर्न-  
मेन्ट', (लंदन, 1852)
- कैनेक्रास, ए० ए० 'होम एंड फारेन इवेस्टमेन्ट, 1870-1913' (केंब्रिज, 1953)
- कोनल, ए० के० 'डिस्कटेंट एंड डेंजर इन इंडिया' (लंदन, 1880)
- कोयाजी, जहांगीर 'इंडियन करेंसी सिस्टम', 1835-1926 (मद्रास, 1930)
- 'इंडियन फिस्कल प्रॉब्लम' (पटना, 1924)
- काटन, आर्थर आन दि प्रपोज्ड एडीशनल एक्स्पेंडीचर आफ 100 मिलियन  
आन रेलवेज 'जनरल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', जिल्द  
4, 1870, पृष्ठ 1-6।
- क्लिग, ब्लेयर डब्ल्यू० 'दि ब्ल्यू म्यूनिटी : दि इंडिगो डिस्टर्बेंसेज इन बंगाल' (फिला-  
डेल्फिया, 1966)
- गाडगिल, डी० आर० 'इन्डस्ट्रियल एवोल्यूशन इन इंडिया' (ओ० यू० पी०, 1940)
- गागुली, बी० एन० 'दादाभाई नौरोजी एंड दि ड्रेन थिअरी बवई, 1965, 1965
- गोपाल, एस० 'ब्रिटिश पालिसी इन इंडिया 1858-1905' (केंब्रिज, 1965)
- गोपालकृष्णन, पी० के० 'डेवलपमेन्ट आफ इकानामिक आइंडियाज' 1880-1914  
(दिल्ली, 1954)
- ग्रिफिथ्स, पर्सीवल 'दि ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इंडिया' (लंदन, 1952)
- घोष, गिरीशचंद्र 'सिलेक्शन फ्रॉम दि राईटिंग्स आफ गिरीशचंद्र घोष, दि फाउं-  
डर एंड एडिटर आफ दि 'हिंदू पेट्रिअट' एंड दि 'बंगाली'।  
संपादक एम० घोष (कलकत्ता, 1912)
- चेजनी, जार्ज 'इंडियन पालिटी : ए ब्यू आफ दि सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन  
इन इंडिया' (लंदन, 1868)
- जैकस, एल० एच० 'माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल, टु 1875' (न्यूयार्क, 1927,  
लंदन 1938)
- टैमिल, रिचर्ड 'इंडिया इन 1880' (लंदन, 1880)
- ट्रैवीलियन, सी० ई० 'डिसेंट्रलाइजेशन', 'जनरल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन',  
जिल्द V, खंड 2, 1871, सख्या जी० 2, पृष्ठ 108-27।
- " " 'आन दि फाइनैसज आफ इंडिया' 'जनरल आफ दि ईस्ट इंडिया  
एसोसिएशन', जिल्द IV, सख्या 82, 1870, पृष्ठ 290-323।
- ट्रोटर, एल० जे० 'हिस्ट्री आफ इंडिया अंडर क्वीन विक्टोरिया, 1836-1880'  
(लंदन, 1886)
- डिग्वी, विलियम 'प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया : ए रिक्लेक्शन फ्रॉम आफिशियल  
रेकार्ड्स' (लंदन, 1901)
- डे, एच० एल० 'पालिसी आफ प्रोटेक्शन इन इंडिया : ए रिट्रास्पेक्ट' (पूना,  
1950)



- टे, एन० एन० 'वेड रेवेन्यू पाविगी ब्रिटिश पैरामाउंट ग्रुंड इंडियन रिनिंग' (बंबई, 1963) -
- पायराज, एम० के० 'पब्लिक इवेस्टमेंट इन इंडिया 1898-1914' 'इंडियन इकनामिक रिव्यू', जिल्द II, 1955, पृष्ठ 37-52।
- पायग, पी० जे० 'दि प्रोय आफ फेडरल फाइनेंस इन इंडिया : बीग ए सॉ आक इंडियाज पब्लिक फाइनेंस फ्राम 1833 टु 1929' (ओ० यू० पी० 1939)।
- दास, रमेश गी० 'इकनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया इन दि रिपब्लिकन एज' (संदन, 1903)
- दास, एम० एन० 'स्टडीज इन दि इकनामिक गृह मोशल डेवलपमेंट आफ माटर्न इंडिया,' 1848-56' (सत्कर्ता, 1959)
- धर्मपाल नायडिदा, मार्क 'एडमिनिस्ट्रेशन आफ सर जान सार्वेग' (निमला, 1952)
- निधोगी, जे० पी० 'जान सार्वेग एंड इनकम टैक्स', 'बंगाल पाम्ट एंड प्रेजेंट', जुलाई-दिगबर, 1900
- नीरोजी, दादाभाई पटेल सुरेन्द्र जे० 'एवोल्प्शन आफ इंडियन इनकम टैक्स' (सदन, 1929)
- 'पावर्टी ग्रुंड अन-ब्रिटिश रूत इन इंडिया' (संदन 1901)
- 'लीम टर्म नैजिज इन आउटपुट एंड इनकम इन इंडिया 1896-1960' 'दि इंडियन इकनामिक जर्नल', जनवरी, 1958, जिल्द 5, सप्ता 3, पृष्ठ 233-46
- पेअरंग, आर० 'इकनामिक फेक्टर्स इन दि हिस्ट्री आफ दि ब्रिटिश एपायर', 'इकनामिक हिस्ट्री रिव्यू', जिल्द VII, मई, 1937, पृष्ठ 119-44
- पेंश, जार्ज 'ग्रेट ब्रिटेन कंपीटल इवेस्टमेंट इन इंडीविजुअल कालोनीज एंड फोरन कंट्रीज' 'जर्नल आफ दि रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी', LXXIV (1910-11) पृष्ठ 186
- प्रियाहट, आई० टी० 'दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ इंडिया फ्राम 1859 टु 1868', 2 जिल्द, (संदन, 1869)
- फिलिप्स, सी० एच० 'ओर अन्यत्र' (मपादक) 'दि एवोल्प्शन आफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1858-1947, सिलेक्ट डाक्युमेन्ट्स, (संदन, 1962)
- फे, सी० आर० 'ग्रेट ब्रिटेन फ्राम एडम स्मिथ टु दि प्रेजेंट डे : एन इकनामिक एंड सोशल सर्वे' (सदन, 1932)
- " " 'इपीरियल इकनामी एंड इट्स प्लेस इन दि फार्मेशन आफ इकनामिक डाक्ट्रीन 1600-1932' (आक्सफोर्ड, 1934)
- फेरे, एच बार्टल 'दि मोस आफ असर्टेनिंग पब्लिक ओपीनियन इन इंडिया' 'जर्नल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', जिल्द 5, खंड IV,

1871, पृष्ठ 102-72

- वगल, जे० सी 'हिस्ट्री आफ दि इंडियन एसोसिएशन' (कलकत्ता, 1953)
- वनर्जी, प्रमयनाथ 'फिस्कल पालिसी इन इंडिया' (कलकत्ता (1922)
- " " 'ए हिस्ट्री आफ इंडियन टैक्सेशन' 1930)
- " " 'प्राविशियल फाइनैस इन इंडिया' (कलकत्ता, 1929)
- शुकानन, डी० एच० 'डेवलपमेंट आफ कैपीटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया' (न्यूयार्क, 1934)
- विपिन चंद्र 'दि राइज एंड ग्रोथ आफ इकानामिक नेशनलिज्म इन इंडिया 1880-1905, (नई दिल्ली, 1966)
- वैल, ई० 'ट्रस्ट एज दि वेसिस आफ इपीरियल पालिसी' 'जर्नल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', जिल्द 6, 1872, पृष्ठ 145
- वोड्सन, सी० ए० जी० 'स्टडीज इन मिड विक्टोरियन इंपीरियलिज्म' (1924)
- डी० सी० वौल्जर, 'इंडिया इन दि नाइंटीथ सेंचुरी' (लंदन, 1901)
- भानुव, आर० एन० 'पब्लिक फाइनैस-इट्स बिजरी एंड बकिंग इन इंडिया' (इलाहाबाद, 1954)
- मजूमदार, विमलविहारी 'हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थाट : फ्रोम राममोहन टु दयानंद 1821-84' (कलकत्ता 1934)
- मार्टिन, आर० एम० 'दि पोलिटिकल, कमर्शियल एंड फाइनैसियल कडीशन आफ दि एंग्लोईस्टर्न एपायर इन 1832' (लंदन, 1832)
- " " दि इंडियन एपायर, इट्स हिस्ट्री, टोपोग्राफी, गवर्नमेंट, फाइनैस, कामर्स एंड स्टेपिल प्राडक्ट्स' (लंदन, 1858-61)
- माल्कम, जे० 'दि गवर्नमेंट आफ इंडिया' (लंदन, 1833)
- मिश्र, बी० वी० 'दि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी' (मैनचेस्टर, 1959)
- " " 'दि इंडियन मिडिल क्लासेज : देअर ग्रोथ इन मोडर्न टाइम्स' (लंदन, 1961)
- मुकर्जी, हरीश सी० 'सिलैक्शन फ्रॉम दि 'राइटिंग्स आफ हरीश चंद्र मुकर्जी कपाइल्ड फ्रॉम दि 'हिंदू पेट्रिअट', संपादक नरेश सी० सेनगुप्ता (कलकत्ता, 1910)
- मूर०, आर० जे 'सर चार्ल्स वुड्स 'इंडियन पालिसी 1853-66' (मैनचेस्टर, 1966)
- मेहता, एस० डी० 'दि कांटेन मिल्स आफ इंडिया 1854-1954' (बंबई, 1954)
- मेटकाफ, थोमस आर० 'दि आपटरमैथ आफ रिबोल्ट्स, इंडिया 1857-1870', (प्रिस्टन, 1964)
- मैकलेगन, माइकल 'ब्लीमैसी कैनिंग' (न्यूयार्क, 1962)

- मैकफर्गन, डब्ल्यू० जे० 'इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रेलवेज' 1845-75' 'इकानामिक हिस्ट्री रिब्यू', जिल्द VII, द्वितीय सीरीज (1955)
- मोरिसन, जे० एल० 'एमीग्रेशन एंड लैंड पालिसी 1815-1873' 'कैब्रिज हिस्ट्री आफ दि ब्रिटिश एंपायर,' जिल्द II (1946)
- रटलेज, जे० 'इंग्लिश रूल एंड नेटिव ओपीनियन इन इंडिया, फ्रॉम नोट्स टेकेन 1870-74' (लंदन, 1878)
- राव, बी० के० आर० बी० 'एन एसे आन इंडियाज नेशनल इनकम 1925-29' (लंदन, 1939)
- रुद्र, ए० बी० 'दि वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल आफ इंडिया' (ओ० यू० पी०, 1940)
- रे, मरिमल 'इंडियाज फारेन ट्रेड, सिस 1870' (लंदन, 1934)
- रैंडफोर्ड, ए० 'मैनचेस्टर मर्चेंट्स एंड फारेन ट्रेड,' 2 जिल्दे (मैनचेस्टर, 1956)
- लैम, हैलन बी० 'दि स्टेट एंड इकानामिक डेवलपमेंट इन इंडिया', इकानामिक ग्रोथ : ब्राजील, इंडिया, जापान, संपादक एस० कुजेनेत्स आदि (डरहम, 1955)
- यकील, सी० एन० 'फाइनैशियल डेवलपमेंट इन माडर्न इंडिया' (बंबई, 1924) ।
- मुराजन, एव एस० के० 'करेंसी एंड प्राइसेस इन इंडिया' (बंबई, 1927)
- यडेंबर्ग, एन० पी० 'दि मनी मार्केट एंड पेपर करेंसी आफ ब्रिटिश इंडिया' (बटाविया, 1884)
- वाचा, डीनशा ई० 'ए फाइनैशियल चैप्टर इन दि हिस्ट्री आफ दि बंबई सिटी' (बंबई, 1909)
- वेंकटरंगैया, एम० 'विगनिंग आफ लोकल टैक्सेशन इन मद्रास' (मद्रास, 1928) ।
- शिरास, जी० फिडले 'इंडिया फाइनैस एंड बैंकिंग' (लंदन, 1920)
- शुम्पीटर, जोसफ ए० 'हिस्ट्री आफ इकानामिक एनालिसिस' (न्यूयार्क, 1954) ।
- शेहाब, एफ० 'प्रोग्रेसिव टैक्सेशन : ए स्टडी इन दि डेवलपमेंट आफ दि प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल इन दि ब्रिटिश इनकम टैक्स' (आक्सफोर्ड, 1963)
- श्लोट, डब्ल्यू० 'ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम 1700 टू दि 1930' (आक्सफोर्ड, 1952)
- सलीवान, एफ० जे० 'वन हंड्रेड इयर्स आफ बंबई, हिस्ट्री आफ दि बंबई चेम्बर आफ कामर्स 1836-1936' (1937)
- आर० 'स्टडीज इन ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेड' (लिवरपूल, 1960)
- साडन, एस० बी० 'इंडियन करेंसी प्रॉब्लम 1885-1900', बंगाल पास्ट एंड प्रेंट, जनवरी-जून, 1961

मिह, एम० एन०	'दि मेसेजरी भाग.स्टेट नगर इतिहास गृह लिख बालमिह' (दिम्पी, 1962)
मिलर, ए०	'मैनचेस्टर मैन गृह इतिहास बालम' (मैनचेस्टर, 1964)
मीन, मनिम,	'दि लुडवेल भाग. इतिहास मेसनरिगम : बालीटीमन गृह बोर- मोमन इन दि मेटर गार्डटीव मेधुरी' (बैजिड, 1968)
मुद्राभाष्य भाष्य, श्री०	'मन इवनामिह भाग.स्टेट भाग. इतिहास भाग इन इतिहास' (मद्रास, 1903)
मेहन, मल्लम गो० गो०	'दि इतिहास भागम' (मदन, 1924)
मेन, मुनीन के०	'गृहीत इन इतिहास भागमि गृह देवनामिह इन इतिहास' (बनरगा, 1964)
मीनर, दे० दे०	आदि (मंगर) 'इवनामिह दोष' (दरहम, 1955)
टोम, एरिक	'इमिह मुटोमिहमिह गृह इतिहास' (आमगरोह, 1959)
मृषी, जान	'इतिहास : इम गृहमिहमिह गृह मीमिह' (मदन, 1911)
मृषी, जान	'इतिहास' (मदन, 1895)
मृषी, जान व	'दि फार्मम गृह मनिह वम भाग. इतिहास 1869-81'
आर० मृषी	(मदन, 1882)
हवागृह, एम० दे०	'मो गृह गृह मनिम एमममन 1853-70' बैजिड लिखी भाग. दि इतिहास मंगर लिख II, (1940), पृष्ठ 753-805
हाडू, रोमरु भागने	'दि मैनचेस्टर पानिटीमन' 1750-1912 (मदन, 1912)
हूजेर, दे० आर० टी०	'मनमममन इन गृह, इमगृह एह फार्मम 1850-60' (आमगरोह, 1960)
हूजेर, एहम	'मन फार्मम गृहमिमन गृह मिमिह मनिम रीमम 1855-55' 'दि इमिह हिमरिहम रिमू', लिख XIV, 1949, पृष्ठ 1 व 2, पृष्ठ 53 व 206
मिनाटी, ए०	'गृहमम फार्मम इन मंगम मेसीहमी 1793-1833' (बनरगा, 1956)
मानमंद	'दा फार्ममिमन मिमम भाग. इतिहास' (मदन, 1926)



## अनुक्रमणिका

- अग्रजी शिक्षा 260  
अग्रराजनीतिक संघ 16  
अदालती शुल्क 241  
अनुत्पादक ऋण 159  
अनीचोगीकरण 31  
अपरिशोधित लोक ऋण सारिणी 310  
अफगान युद्ध (1838-48) 65  
अफीम 10, 12, 34, 35, 70, 71, 72, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 266  
तुर्की 199  
चीनी 71, 199, 200, 201, 202, 248  
फारस 199  
बंगाल 72, 193, 194, 196, 197, 201  
बनारस एजेंसी 193  
भारतीय 199, 201, 202  
मालवा 71, 193, 194, 195, 196, 197  
शिराज 199  
अफीम आरक्षित निधि 198 -  
अफीम उत्पादन 10, 199, 200, 201, 249  
अफीम एकाधिकार 249  
अफीम एजेंट 195, 196  
अफीम खेती 193, 200, 250  
अफीम निधि 197  
अफीम निर्यात 202  
अफीम प्रभार 196  
अफीम प्रशासन 192  
अफीम विरोधी आंदोलन 92, 250  
अफीम विरोधी समाज 249  
अफीम व्यापार 92, 193, 195, 196, 198, 200, 248, 251  
बंगाल प्रणाली 251  
बंबई प्रणाली 251  
अफीम राजस्व, सारिणी, 289  
अफीम शुल्क, 212  
अवीसीनिया युद्ध, 140  
अभिकर्ता गृहों, 45  
अमेरीकी गृहयुद्ध, 31, 48, 74, 185, 186, 207, 264  
अवाध व्यापार का साम्राज्यवाद, 45  
असैनिक व्यय, 135  
अस्थाई बंदोबस्त, 35, 178, 187, 188, 264  
अहस्तक्षेपी नीति, 27, 36, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 142  
आंतरिक निकास, 268  
आपतकालीन स्थिति, 65  
आयकर, 19, 81, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 241, 246, 248  
आयकर आयोग, 217  
आयकर कराधान, 218  
आयकर नीति 213  
आयकर पत्रक संशोधक समिति, (1860)

- आयकर विधेयक, 214, 215, 216  
 आयकर विवरणी, 217  
 आयकर विवरणी प्रारूप समिति, 7  
 आय की मर्दे, 71  
 आयात शुल्क, 17, 18, 20, 27, 72, 205, 209, 210, 262  
 आयात सारिणी, 295  
 आरगाइल, ह्यूक, 4, 12, 15, 20, 37, 68, 89, 91, 92, 93, 94, 114, 133, 134, 135, 137, 144, 145, 146, 147, 152, 158, 162, 189, 200, 201, 213  
 आर्थिक उदारवाद, 27, 75  
 आर्थिक विकास, 267, 268  
 आर्थिक राष्ट्रवाद, 9, 268  
 आर्थिक साम्राज्यवाद, 43  
 आर्बुथनाट, 114  
 आल्काक, रुथरफोर्ड, 200, 201  
 अंगलिशमैन, 12  
 इंडियो प्लाटम एसोसिएशन, 5, 6, 187  
 इंडियन एकनामिस्ट, 161, 239, 240, 247, 249, 260, 261  
 इंडियन एसोसिएशन, 7  
 इंडियन काउंसिल ऐक्ट, 90, 91  
 इंडियन काउंसिल ऐक्ट, (1860), 94  
 इंडियन काउंसिल ऐक्ट, (1861), 97, 107, 109  
 इंडियन काउंसिल ऐक्ट, (1892), 40, 98, 267  
 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 40, 238, 266, 267  
 इंडिया आफिस, 6, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 24, 27, 36, 48, 90, 92, 133, 136, 137, 139, 140, 143, 151, 186, 255, 258  
 इंडिया काउंसिल, 91, 134, 135, 184  
 इंडिया बोर्ड आफ कंट्रोल, 148  
 इंडिया रिफार्म सोसायटी, 8, 10  
 इम्ला, ए० एच०, 41  
 ईडन, एशले, 14  
 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 8, 10, 12, 13, 161, 208, 238, 245, 254  
 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (बंबई), 255  
 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1, 23, 69, 73, 131, 136, 139, 148, 159, 160, 254, 260  
 ईस्ट इंडिया वित्त प्रवर समिति, 153  
 उड़ीसा के दुर्मिष, 29  
 उत्तर सैन्य विद्रोह काल, 142, 159, 178, 203, 214, 254, 262  
 उत्पादक ऋण, 159  
 उत्पादन शुल्क, 18, 116, 130, 252, 266  
 उपनिवेशवाद, 41  
 उपयोगितावाद, 35, 36, 77, 182, 183  
 उपयोगितावादी विचार धारा, 178  
 उपयोगितावादी सिद्धांत, 34  
 ऋण पत्र, 160  
 ऋण शोधन नीति, 8  
 एकाधिकारी प्रणाली, 193, 174, 195  
 एलियन, 20  
 एल्फिस्टन, 187  
 एंग्लो इंडियन प्रेस, 35  
 एंग्लो इंडियन समुदाय, 14, 249  
 औद्योगिक पूंजीवाद 79  
 औद्योगीकरण, 47  
 औपनिवेशिक व्यापार, 74  
 औपनिवेशीकरण, 30  
 बंटोन्नर जनरल आफ मिनिटरो एग्ज-पेक्टिवर, 99  
 बपाग उत्पादन, 6  
 बपाग मेनो, 6  
 बपाग दुर्मिष, 29, 185, 204  
 बपाग निर्यात, 6  
 बपाग व्यवसाय, 4, 207, 264

करभार, 240

करांची चेंबर आफ कामर्स, 11

कराधान 33, 35, 78, 110, 115, 148,  
154, 182, 189, 191, 202, 215, 239,  
243, 251

कराधान, शारोही, 214, 215, 221, 247

कराधान, द्वंद्व, 216

कराधान, प्रत्यक्ष, 213, 218, 219, 247

कराधान प्रणाली, 241

कराधान भार, 241

कराधान मुक्त वर्ग 213,

कराधान विधेयक, 97

कर्जन, लाई, 181

कलकत्ता गजट, 90

कलकत्ता चेंबर आफ कामर्स, 204

कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन, 5, 6, 33,  
182, 221, 247, 265

कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन, 5, 6, 33,  
182, 221, 247, 265

कहवा बागान, 6

काप्रेव, रिचर्ड, 37

काटन, आर्थर, 161

काटन सप्लाय एसोसिएशन, 5, 6, 10, 11,  
16, 18, 29, 45, 46, 186, 205

काटन सप्लाय रिपोर्टर, 6, 11, 186

कार्डवेल, 21, 138

किर्नड, 248

किपलिंग, रुडोल्फ, 77, 238

केंद्रीयकरण, 99, 107, 263

केंद्रीय रेवेन्यू बोर्ड, 103

केंद्रीय लोक निर्माण 100

केनेक्रास, ए० के०, 25, 41

केव, स्टोफेन 12, 248

कैनिंग, लाई, 39, 90, 94, 99, 108, 144,

159, 183, 213, 215, 216, 247, 262

कैरनीज, जे० ई०, 79

कोर्ट आघ हायरेक्टर्स, 6, 29, 138, 181

क्राफोर्ड, जे० ए०, 13

क्रीमियन युद्ध, 74, 185, 207

क्रेनवोर्न, लाई, 20, 91, 148, 151, 181,  
189, 191

क्रोफोटकिन, प्रिंस 181

खाद्यान्न भत्ता 157

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, (1853),

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, (1858),  
91, 92, 140, 254

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, (1859), 2

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, (1885) 7

गांजा, 252

गारंट्री प्रणाली, 142, 143, 145, 146,  
147, 148

गालाघर, 46

गुप्ता, जे० एन०, 180

गृह कर, 116

गृह खर्च, 131, 138, 255, 258, 259

गृह खर्च मदे, 256-258

गृह प्रशासन, 258

गृह सव्यवहार, 259

गृह सचिव, 99

गैर अनुबंधित सेवा, 157

ग्रेटर ब्रिटेन, 37

ग्रोट, ए०, 217

ग्लॅडस्टन, 26, 27, 75, 106, 160

ग्लॅडस्टन युग, 65

घोष, शिशिर कुमार, 7

चासलर आफ ऐक्सचेकर, 65

चार्टर ऐक्ट, 107

चुंगी, 116

चेंबर आफ कामर्स, 5, 6, 9, 13, 16, 81,  
266

चेंबर आफ कामर्स

ग्लासगो, 7,



- डेडी, 7, 18, 203, 207  
 बंगाल, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 30, 31, 33, 295, 213, 265  
 मेनचेस्टर, 6, 7  
 लीड्स, 7  
 बंबई, 11, 161  
 चेन्नई, जी०, 144, 146  
 जमशेदजी जीजा भाई, 9  
 जमींदार एसोसिएशन आफ बंगाल, 7  
 जयपुर के महाराजा, 40  
 जामे जमशेद, 244  
 जूट, 209  
 जूट उत्पादन, 24  
 जूट उद्योग 24, 207  
 जेफीज, टी० बी०, 161  
 जैक्स, एल० एच० 41  
 टाइम्स आफ इंडिया, 161, 239, 241, 242  
 टुलाक समिति, 136  
 टैपिल रिचर्डे, 12, 13, 26, 68, 69, 93, 95, 104, 114, 159, 160, 197, 213, 217, 221  
 टैपिल योजना, 114  
 टैगोर, प्रसन्न कुमार, 7, 13, 39, 40, 217  
 टैरिफ, 6, 208, 262  
 टैरिफ नीति, 92, 202, 207, 209, 261, 267  
 टैरिफ राजस्व, 262  
 टैरिफ शुल्क, 18  
 टैरिफ समिति, 1866, 13  
 टैरिफ मिश्रित, 209  
 ट्रेडरियन, चार्ल्स, 3, 4, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 66, 67, 68, 73, 95, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 160, 205, 206, 218, 250, 262, 263  
 ट्रेडरियन, जार्ज, 73  
 ट्रेडरियन, नोर्थकोट सुधार, 101  
 डडी, 23  
 डंडी चेंबर आफ कामर्स, 7, 18, 203, 207  
 डफ ग्रैंट, 239  
 डलहौजी लार्ड, 90, 97, 100, 148  
 डिकिंसन जान, 10  
 डिजरायली, 12, 93  
 डिल्के चार्ल्स, 37, 141  
 डेनी ए०, 46  
 डेनिस, डब्ल्यू० टी०, 110  
 ड्रमंड, ई०, 104, 110  
 ड्यूरेंड, एच०, एम०, 111, 135, 155, 156  
 तंजोर श्रृण, 160  
 तंवाकू शुल्क, 212  
 सेतिंग, के० टी०, 266  
 थोर्नटन, डब्ल्यू० टी०, 35, 144, 146, 183  
 दत्त, रमेश सी०, 180, 181, 182, 183, 255, 268  
 दुर्भिक्ष, 151, 183, 252  
 देशी शराब, 252  
 नमक खाने, 211  
 नमक चेंबर आफ कामर्स, 210  
 नमक राजस्व, 210, 211  
 नमक राजस्व सारिणी, 291  
 नमक शुल्क, 72, 81, 130, 209, 210, 211, 212, 213, 241, 242, 246, 247  
 नमक शुल्क  
 बंगाल प्रणाली, 210  
 बंबई प्रणाली, 210  
 मद्रास प्रणाली, 211  
 नव वाणिज्यवाद, 31  
 नाइट, राबर्ट, 161, 239, 261  
 नाथ भाई 9

- निजी उद्यम, 29  
 नियत कालिक बंदोबस्त, 188  
 निर्यात शुल्क, 11, 18, 19, 30, 68, 205, 206, 207, 208  
 निर्यात सारिणी, 293  
 नील फैक्टरी, 194  
 नील विद्रोह, 17  
 नेपाल युद्ध, 65  
 नेपियर, लार्ड, 113, 114, 116, 134  
 नैतिक एवं भौतिक प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 25, 241  
 नोर्थकोट, स्टेफोर्ड, 12, 67, 69, 92, 96, 145, 147, 152, 155, 156, 190, 197, 254, 258  
 नोर्थकोट रिपोर्ट, 1958, 3  
 नौकरशाही, 3, 23, 24  
 नौरोजी, दादाभाई, 8, 9, 10, 13, 81, 181, 238, 239, 243, 249, 254, 255, 260, 261, 267, 268  
 पायनियर, 12  
 पारगमन शुल्क, 72, 196  
 पाल, क्रिस्टोदास, 180, 238  
 पूंजी निवेश, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 73, 74, 111, 159, 162, 181, 182, 191, 260, 265, 266  
 पूना सार्वजनिक सभा, 9  
 पूर्ण स्वामित्व पट्टेदारी, 30  
 पेंशन, 157, 158  
 पेंशन भत्ता, 158  
 पेरी, डी०, 260  
 पैली, लूई, 199  
 पेंश, जार्ज, 41  
 प्रजाति, 16, 37, 39  
 प्रतिनिधि प्रणाली, 116  
 प्रत्यक्ष कर, 19, 247  
 प्रत्याभूत कंपनियां, 142  
 प्रत्याभूत कंपनियां—व्याज सारिणी, 311  
 प्रत्याभूत व्याज, 145, 146  
 प्रवर समिति, 107, 141, 144, 148  
 प्रातीय राजस्व बोर्ड, 10  
 प्रिगिल, 35  
 प्रोटो पालिटिक्स एसोसिएशन, 16  
 प्लैट, डी० सी० एम०, 47  
 फाइनेंस सेक्रेटरी, 66  
 फाउलर, आर० एन०, 12, 248  
 फाउलर, एम०, 12, 248  
 फायरे, ए० पी०, 200  
 फासट, एफ०, 93  
 फास्ट, हेनरी, 13, 149  
 फास्टर, एम० एच०, 100, 105, 106  
 फिट्जेराल्ड, एस०, 112, 113  
 फील्ड हाउस, डी० के०, 46  
 फोर, हेनरी बार्टल, 8, 20, 48, 66, 67, 75, 94, 95, 97, 114, 202, 218, 245, 266  
 फौड आफ इंडिया, 15, 38, 68, 239, 241, 242, 247, 249  
 बंगाल चेंबर आफ कामर्स, 5, 11, 14, 18, 19, 30, 31, 33, 205, 213, 221, 265  
 बंगाल प्रणाली, 195  
 बंगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू, 187, 210  
 बंगाल राजस्व बोर्ड, 192  
 बंगाल विचारधारा, 178  
 बंगाली, सोराबजी सापूरजी, 9  
 बंदोबस्त नियमावली (1854), 188  
 बंबई एसोसिएशन, 9, 153  
 बंबई चेंबर आफ कामर्स, 11, 161  
 बंबई मुद्रा बाजार, 166  
 बंबई सरकार, 162, 195  
 बजट 1861-62, 67  
 1862-63, 67  
 1865, 15

- 1866-68, 68  
 1866-69, 96  
 बजट पद्धति, 102  
 बजट प्रणाली, 69, 89, 98, 102, 103, 104, 105, 106  
 बजट व्यय, 130, 131  
 बजट समिति, 104, 105, 107  
 बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, 40, 267  
 बर्मा युद्ध (द्वितीय), 65  
 बाबे एसोसिएशन, 8, 13  
 बागान मालिक मस, 16, 18  
 बायर्ड स्मिथ रिपोर्ट, 184  
 बालफोर, कर्नल, 132, 133  
 बीडन, सैसिल, 110, 194, 197, 198, 210  
 बुलन, एस० एन०, 13  
 बेजले, टी०, 12  
 बेजहाट, वास्टर, 25, 37, 79, 201  
 बेल, इवांग, 8  
 बैंक आफ इंग्लैंड, 143  
 बैंकिंग ऐक्ट (1844), 66  
 बैंकिंग विचारधारा, 66  
 बोर्ड आफ कट्टील, 65  
 बोर्ड आफ ट्रस्टीज, 12  
 बोर्ड आफ ट्रेड, 26, 66, 67  
 बोर्ड आफ रेवेन्यू, 20, 112  
 ब्रिटिश इन्डियन एगोसिएशन, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 39, 40, 98, 117, 213, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 263, 266  
 ब्रिटिश उत्पादक हित (और देखें हितवद्ध गुट समूह), 209  
 ब्रिटिश उपनिवेश, 244  
 ब्रिटिश व्यापक गुट, 17  
 ब्रिटिश पूंजी 42, 43, 73, 74, 142, 147, 155, 185, 186, 261 और देखें पूंजी निवेश,  
 ब्रिटिश भारत, 3, 178, 212, 261, 239  
 ब्रिटिश मुद्रा, 256  
 ब्रिटिश राज, 2  
 ब्रिटिश वित्तीय नीति, 65  
 ब्रिटिश शासन, 241  
 ब्रिटिश सरकार, 3, 21, 136, 141, 150  
 ब्रिटिश सिविल सेवा, (और देखें सिविल सेवा) 11, 67  
 ब्रिटिश सेना, 138, 140, 141, 257  
 ब्रिटिश हितवद्ध गुट (और देखें हितवद्ध गुट समूह) 18, 19, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 44, 47, 49, 81  
 ब्याज प्रभार 131, 258  
 भंडारकर, आर० जी० 9  
 भभका शुल्क प्रणाली 252, 253  
 भारत कार्यालय (देखें इंडिया आफिस)  
 भारत निधि 66  
 भारत मंत्री 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 28, 38, 68, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 116, 132, 133, 142, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 162, 163, 173, 182, 184, 186, 190, 202, 206, 208, 213, 216, 221, 240, 244, 246, 254, 256, 257  
 आरगाइन 142  
 जेनबोर्न 133  
 बुद्ध 206  
 स्टैनले 184, 186  
 भारत सरकार 5, 65, 98, 104, 109, 131, 140, 142, 143, 145, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 159, 183, 190, 191, 192, 196, 198, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 240, 241, 255, 256, 258, 260, 261, 264,

भारत सरकार, व्यय सारिणी 298, 299, 301

शुद्ध भुगतान सारिणी 312, 314,

भारतीय आयात शुल्क, 203

भारतीय उद्योग, 75

भारतीय कपास, (और देखें कपास) 207

भारतीय कुटीर उद्योग, 204

भारतीय टैरीफ नीति, 203

और देखें टैरिफ

भारतीय तार व्यवस्था, 2

भारतीय पत्र मुद्रा, 66

भारतीय पूजी, 147

भारतीय बुनकर, 31

भारतीय बैंकर 217

भारतीय राजस्व 9, 64, 74, 143, 242, 254

भारतीय राजस्व प्रणाली, 100

भारतीय राजस्व सारिणी, 297

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखें

इंडियन नेशनल कांग्रेस

भारतीय रेल 28, 44, 73, 141, 142

144, 145

भारतीय रेवेन्यू प्रणाली 108

भारतीय लेखा जाच आयोग 105

भारतीय लोक वित्त (और देखें लोक वित्त) 1

भारतीय वित्त 1, 9, 13, 92, 94, 141,

148, 191, 195, 198, 203, 255

भारतीय वित्त नीति, 38, 80

भारतीय विधान परिषद, 39

भारतीय विधान मंडल, 91

भारतीय शिक्षायातबाज, 93

भारतीय साम्राज्य, 64, 209

भारतीय सिविल सेवा (और देखें सिविल सेवा) 22, 32, 48, 68, 95

भारतीय सेना, 136, 140

भारतीय सेना मबंधी खर्च, 131

भारतीय सैन्य बजट, 138

भूटान युद्ध, 133

भूधृति नीति, 71

भूधृति प्रणाली, 178, 186, 187

भूमिकर, 241

भूस्वामी (जमीदार) संध, 15

मंगलदास, 9

मदिरा, 248, 249, 253

मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 9

मद्रास प्रेसीडेंसी, 134

मद्रास विद्रोह, 38

मराठा युद्ध, 65

मइंगाई भत्ता, 157

माग पत्र समिति, 257

मारल एंड मेटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, 25, 241

मालगुजारी, 6, 17, 34, 35, 36, 70, 71,

100, 116, 178, 179, 181, 183,

184, 185, 186, 187, 188, 189,

191, 216, 240, 242, 264, 265, 290

मालगुजारी अदायगी, 6

मालगुजारी नीति, 178, 179

मालगुजारी वृद्धि, 17

मालगुजारी सारिणी, 290

मार्क्स, कार्ल 80

मित्र, राजेंद्रलाल, 267

मिल, राजेंद्रलाल, 267

मिल, जे० एस०, 29, 32, 33, 34, 35, 76, 183

मिलिटरी होम चार्जस, 131

मुकर्जी, हरीश, 238

मुक्त व्यापार, 80, 202

मुख्य वित्त सचिव, 98

मुद्रा बाजार, 112, 150, 162

मेन, एच० एस०, 35, 37, 79, 183, 197

मेनचेस्टर, 23, 24

- मेनचेस्टर काटन स्प्लाइ एसोसिएशन, 28, 81
- मेनचेस्टर गुट, 187
- मेनचेस्टर चेंबर आफ कामर्स (और देखें चेंबर आफ कामर्स), 16, 203, 205
- मेनचेस्टर मंकट, 29
- मेयो, लार्ड 1, 4, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 68, 69, 70, 89, 91, 92, 93, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 152, 158, 159, 161, 162, 189, 200, 201, 202, 211, 245, 251, 254, 257, 260, 262, 263
- मेयो जाच 93
- मेयो योजना, 114, 116, 117
- मैकडोनल, ए० पी०, 181
- मैकाले, लार्ड, 67, 179
- मंगलम, रोस डी०, 184
- मैड्रास टाइम्स, 242
- मैपसन डोनेल्ड, 248
- मैसफील्ड, डब्ल्यू० थार० 155, 156, 197
- मैसफील्ड, विलियम, 96
- मैसी, डब्ल्यू० एन०, 15, 32, 68, 109, 111, 112, 114, 144, 155, 156, 197
- मैसी योजना, 69, 110
- माचिका (देखें स्मरण पत्र)
- यूरोपियन चेंबर आफ कामर्स, 246
- यूरोपियन पूजी, 187, 188, 206, 240
- राजकोष पत्र, 159
- राजस्व 209, 213, 214, 218, 241
- राजस्व और प्राप्तिर्मा, मारणी 286-288
- राजस्व और व्यय, सारणी 285
- राजस्व प्रबंध, 64
- राजस्व विकेंटीकरण, 69
- राजस्व विवरण, 220
- रानाडे, ए० जी०, 80
- राव, दिनकर 39
- राष्ट्रीय आय, 239, 240
- रास्तगोफ्तार, 12
- रिगटन, 217
- रिजर्व सेना, 137, 138
- रेनोल्ड्स, एच० जे०, 181
- रेल उद्योग, 4
- रेल कंपनी, 100, 131, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 256, 259
- रेलवे कंपनी (देखें रेल कंपनी)
- रैयत, 179, 180, 181, 168
- रैयतवाड़ी प्रणाली, 181
- रोबिसन, आर० ई० 46
- लशिगटन, सी० एच० 104
- लाइसेंस अधिनियम, 214
- लाइसेंस कर, (और देखें लाइसेंस शुल्क) 32, 215, 216, 219, 221, 246
- लाइसेंस कर विधेयक, 214
- लाइसेंस व्यवस्था, 213
- लाइसेंस शुल्क, (और देखें लाइसेंस शुल्क) 221, 247
- लाउसन, डब्ल्यू 248
- मारेस, जान, 20, 21, 22, 92, 96, 112, 133, 140, 141, 146, 151, 156, 157, 162, 180, 189, 197, 218, 254, 258
- लामन, डब्ल्यू०, 12
- लिवरपूल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 208
- लिस्ट, फ्रेडरिक 80
- लेखा पद्धति, 104, 105
- लेखा परीक्षण एवं लेखा प्रणाली, 106
- लेखा प्ररीक्षण प्रणाली, 104
- लेजली, टी० ई० सी०, 37
- लेजली, थामस, 80
- मेविन, माल्कम, 249
- मंग, मंगुजम, 20, 22, 27, 32, 67, 70

- 90, 94, 95, 100, 104, 109, 114,  
179, 185, 188, 202, 209, 218, 221  
250
- लैंडहोल्डर्स एंड कमर्शियल एसोसिएशन,  
187
- लैंडहोल्डर्स सोसायटी, 7
- लैम, चार्ल्स, 1
- लोक ऋण, 107, 161, 162
- लोक कल्याणवाद, 180
- लोक निर्माण, 148, 149, 151, 154, 155;  
156, 261, 163, 264
- लोक निर्माण अनुदान, 149
- लोक निर्माण कार्य, 161
- लोक निर्माण नीति, 149
- लोक निर्माण विभाग, 148, 152, 153
- लोक निर्माण व्यय सारिणी 302-305
- लोक राजस्व सारिणी, 283
- लोक वित्त, 65, 267  
(और देखें वित्त.)
- लोक व्यय सारिणी 284
- ल्यूइस, जार्ज, 106
- वार्षिक आय, 239
- वार्षिक कर, 239
- वार्षिक बजट, 98
- विकेंद्रित वित्त योजना (1871-72), 115
- विकेंद्रिकरण, 1, 70, 110, 263
- विकेंद्रिकरण योजना, 109, 111
- विकटोरिया युग, 150
- वित्त आयोग, 159, 243
- वित्त मंत्री, 65, 89,
- वित्त विभाग, 98, 99, 100, 101, 103,  
136
- वित्त विवरण, 218, 241
- वित्त सचिव, 99, 101, 114, 198
- विन सदस्य, 26, 32, 66, 67, 68, 69,  
94, 109, 143, 256
- वित्त सिद्धांत, 26
- वित्तीय आरक्षित निधि, 219
- वित्तीय केंद्रीकरण, 3, 38, 108
- वित्तीय नियंत्रण, 89, 90, 91
- वित्तीय निरीक्षण, 91
- वित्तीय नीति, 5, 7, 8, 25, 26, 27, 81
- वित्तीय प्रणाली, 64, 110
- वित्तीय प्रशासन, 89
- वित्तीय वर्ष, 105,
- वित्तीय विकेंद्रीकरण, 68, 69, 106, 109,  
111, 112, 113, 114, 115, 116, 260,  
262, 263
- वित्तीय संकट, 1, 20, 65, 89, 97, 203
- वित्तीय मंथीकरण, 112
- वित्तीय सिद्धांत, 221
- वित्तीय हस्तांतरण योजना, 70
- विदेश नीति (ब्रिटिश), 47
- विदेशी व्यापार, 240
- विदेशी व्यापार सारणी, 292
- विद्रोह  
बंगाल 1857, 17  
दक्षिण 1875, 17
- विधान परिषद, 96, 97, 98
- विधान परिषद सुधार समिति, 67
- विभाग प्रणाली, 99
- विल्सन, जेम्स, 18, 20, 22, 23, 25, 26,  
27, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 65, 66,  
67, 68, 70, 74, 90, 93, 94, 95,  
97, 99, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 107, 108, 148, 160, 205, 209  
213, 214, 215, 216, 217, 218, 221  
240, 241, 242, 253, 261, 263
- वुड चार्ल्स, 21, 35, 66, 90, 91, 94, 95  
97, 99, 108, 132, 137, 143, 145,  
162, 179, 184, 186, 187, 189, 190  
191, 215, 217

- बेकफील योजना, 30  
 बैस्ट, एडवर्ड, 26, 30  
 व्यक्ति कर, 72  
 व्यय संबंधी नीति, 131  
 बिल्फन, 105, 106  
 शंघाई चेंबर आफ कामर्स, 200  
 शराब, 248, 252, 253,  
 शासन पत्र (चार्टर), 93  
 शाही आयोग 153,  
 शिक्षा पर व्यय, 160  
 शिक्षा व्यय सारणी, 315, 316  
 शुल्क प्रणाली 194  
 शूपीटर, जे० ए०, 25, 79  
 शोरा, 23, 209  
 संचार प्रणाली, 2, 3  
 संयुक्त परिवार प्रणाली, 182  
 ससदीय प्रवर समिति, 9, 10, 13  
 सत्तावादी प्रणाली, 16  
 सदर शराब कारखाना प्रणाली, 252, 253  
 सदाचरण काल, 91  
 समुद्री केबिल, 91  
 सार्टिफिकेट कर, 219  
 सांडर्स, आर० 187  
 साभर फील, 212  
 साइमन, कर्नल, 12  
 साइमन, मेथ्यू, 41, 42, 248  
 साम्राजिक लेखा परीक्षण विभाग, 103  
 सिविल प्रशासन, 130  
 सिविल सेवा, 2, 3, 9, 15, 94, 158, 180,  
 257  
 सिविल सेवा आयोग, 100  
 सीकोंव समिति, 139  
 सीमा शुल्क, 6, 14, 18, 19, 30, 38, 45,  
 72, 99, 107, 130, 202, 206, 211,  
 212, 241, 252  
 सीमा शुल्क ऐक्ट (1865), 262  
 सीमा शुल्क सारिणी, 292  
 सूत आयात सारिणी, 295  
 सूती वस्त्र, 209  
 सूती वस्त्र आयात सारिणी, 296  
 सूती वस्त्र उद्योग, 31, 78, 92, 203, 204,  
 264  
 सेगल, हावे, 48  
 सेना रसद विभाग, 132  
 सेना विभाग, 21, 136, 137, 138, 139  
 सेलिसबरी, मार्क्विंस आफ, 141  
 सैन्य निर्माण, 154, 155, 156  
 सैन्य बोर्ड, 148  
 सैन्य वित्त आयोग, 26, 28, 67, 132, 133  
 सैन्य वित्त विभाग, 99  
 सैन्य विद्रोह, 1, 21, 23, 29, 35, 36, 39,  
 48, 65, 69, 72, 73, 89, 93, 96, 97,  
 99, 102, 106, 130, 131, 132, 133,  
 135, 138, 149, 153, 160, 178, 180,  
 184, 185, 255, 260, 263, 264  
 सैन्य व्यय, 15, 135, 136, 139, 141,  
 253, 254  
 सैन्य व्यय सारिणी, 306, 309  
 सैन्य मंडया सारिणी, 307-308  
 सोम प्रकाश, 244  
 स्टलिंग, 1, 150, 261, 167, 280  
 स्टॉप बिक्री, 130  
 स्टॉप राजस्व, 253  
 स्टॉप शुल्क, 33, 241  
 स्टीफन, एफ० जे० 36, 37, 77  
 स्टेनले, लार्ड, 197  
 स्ट्रैची, जान, 34, 37, 68, 69, 76, 77,  
 112, 114, 156, 157, 197, 198, 250,  
 261, 265  
 स्ट्रैची, रिचर्ड, 69, 70, 110, 111, 146,  
 152, 250  
 स्थलीय केबिल, 91

- स्याई बंदोबस्त, 7, 20, 32, 35, 36, 71, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 216, 264, 265  
 स्याई बंदोबस्त (1705), 7  
 स्याई बंदोबस्त (1862), 20  
 स्याई बजट, 113  
 स्थानीय बोर्ड, 116  
 स्थानीय वित्त, 114  
 स्थानीय स्वावलंबन, 109  
 स्मरण पत्र एवं याचिका, 5, 9, 10, 11, 17, 217, 221, 238, 262, 365  
 स्मिथ, एडम, 32  
 स्मिथ, जे० बी०, 12  
 स्मिथ, वायडें रिपोर्ट, 184  
 स्मिथवाद, 79  
 स्वीफ्ट, डीन, 47  
 स्वेज नहर, 91  
 स्वेज मार्ग, 3  
 हंटर, डब्ल्यू० यम्ल्यू०, 75  
 हस्तक्षेपवाद, 46  
 हाउस आफ कामस, 97, 141, 161, 182, 191, 195, 239, 242, 255  
 हाउस आफ कामस प्रवर समिति, 242, 255  
 हाल, ए० आर०, 42  
 हालीडे, एफ० जे०, 200  
 हान्सन, सी० के०, 41  
 हान्सवादी समीक्षा, 46  
 हितवद्ध गुट समूह, (और देखें ब्रिटिश हितवद्ध गुट) 3, 4, 8, 10, 16, 25, 262, 266  
 हिडमैन, हैनरी, 13, 239, 240, 242  
 हिंदू पैट्रियट, 12, 40, 95, 180, 181, 243, 244, 245, 454, 255, 262, 263, 268  
 हेरिंगटन, हेनरी, 213  
 हेस्टिंग्स, वारेन, 179  
 हैमिल्टन, आर०, 195  
 होम चांजेस देखें गृह खर्च  
 ह्यू बांडें समिति (1861), 182  
 ह्यूम, जोसेफ, 28





